विदेश मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2004 – 2005

यह वार्षिक रिपोर्ट इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है:
www.meaindia.nic.in

आवरण:
श्री काशी नाथ दास द्वारा पानी के रंगों से चित्रित केन्द्रीय सचिवालय के भवन

रूपरेखा एवं मुद्रण:
साइबरआर्ट इनफारमेशंस प्रा. लि.
कनु चेम्बर्स, सी-2, सांवल नगर, नई दिल्ली 110 049
टेलीफैक्स: 26256148/26250700
ईमेल: cyberart@vsnl.com

विषय सूची

कार्यकारिणी सार

1. पड़ोसी देश 1
2. दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत 23
3. पूर्वी एशिया 39
4. मध्य एशिया 46
5. खाड़ी क्षेत्र, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका 52
6. अफ्रीका (दक्षिण सहारा) 61
7. यूरोप 79
8. अमरीका 95
9. संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन 106
10. विदेश आर्थिक संबंध 125
11. तकनीकी सहयोग 131
12. निवेश और व्यापार संवर्द्धन 133
13. नीति नियोजन एवं अनुसंधान 134
14. विदेश प्रचार 135
15. प्रोतोकोल 139
16. पासपोर्ट, वीजा और कौंसली सेवाएं 145
17. प्रशासन और संगठन 148
18. समन्वयन 151
19. प्रवासी भारतीय और विदेशों में भारतीय मूल के लोग 152
20. विदेश सेवा संस्थान 153
21. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार 155
22. लिंग संबंधी मसले 157
23. सांस्कृतिक संबंध 158
24. इण्डियन काउन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स 163
25. विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आर आई एस) 165
26. पुस्तकालय 170
27. कल्याण 171

कार्यकारी सार

भारत की विदेश नीति के संचालन में राष्ट्रीय सहमति की एक स्वस्थ परम्परा रही है । प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू पी ए) सरकार ने, मई, 2004 में सत्ता में आने के बाद, विदेश विभाग श्री नटवर सिंह को सौंपा, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति के संचालन में एक पेशेवर राजनयिक और दिग्गज हैं । उनके सहयोग में दो राज्य मंत्री, श्री ई0 अहमद और श्री राव इन्द्रजीत सिंह हैं । श्री श्याम सरन ने 1 अगस्त 2004 को श्री शशांक से विदेश सचिव का कार्यभार ग्रहण किया।

भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शी सिद्धांत पंचशील, व्यावहारिकता और राष्ट्रीय हित के लक्ष्य पर आधारित है । तीव्र और निर्बाध परिवर्तन के दौर में, विदेश नीति को नई चुनौतियों एवं अवसरों के साथ बेहतर ढंग से प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम होना चाहिए । आर्थिक विकास, सामाजिक तानाबाना और जनता की बेहतरी के सुदृढ़ीकरण तथा भारत की संप्रभुता एवं प्रादेशिक अखण्डता के संरक्षण के माध्यम से राष्ट्र की क्षमताओं का निर्माण करने में इसे बृहत्तर प्रयासों का एक अभिन्न अंग होना चाहिए । भारत की विदेश नीति शेष विश्व के साथ प्रगतिशील विचारों के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीतिक समसामयिक आकलन पर आधारित हो ।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त वार्त्ता को जारी रखने तथा पड़ोसी देशों एवं भारत के विस्तारित पड़ोस के साथ पहले से विद्यमान निकट संबंधों को आगे भी सुदृढ़ बनाने को उच्च प्राथमिकता दी है । विश्व की बड़ी ताकतों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, ब्राजील, मिस्र, जर्मनी, जापान, मॉरीशस, नाईजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और आसियान देशों ने मंत्रालय का अत्यधिक ध्यान आकृष्ट किया है । परन्तु सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया तथा विश्व शांति के सृजन की ओर योगदान देकर आपसी हित की नई साझेदारी का निर्माण करने के भारत के प्रयत्न में अफ्रीका, लातीन अमरीका और छोटे द्वीप के देशों को और अधिक प्राथमिकता तथा केन्द्रीकरण हासिल हुई थी ।

हालांकि, भारत कोई परम्परागत दाता देश नहीं है, फिर भी मित्र देशों को बाहरी विकास सहायता देने के लिए लगभग 1300 करोड़ रूपए खर्च किए गए थे ।

पड़ोसी

एक देश द्वारा सामना की जा रही राजनयिक चुनौतियों में भूगोल का तर्क अविरल और सान्निध्य अत्यन्त कठिन एवं कसौटीपूर्ण है । जबकि वैश्विकरण से विकास के लिए तथा हमारे जीवन की संपन्नता के लिए कई लाभ और अवसर हासिल हुए हैं, वहीं इससे एक की पहचान के खोने तथा शक्तिशाली एवं प्रौद्योगिकीय उन्नत समाजों द्वारा दबाए जाने का भी खतरा है ।

भारत आज विश्व के अत्यन्त गतिशील और तीव्र प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है । यह न केवल व्यापक और बढ़ता हुआ बाजार तैयार कर रहा है, वरन् प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकीय स्त्रोत और ज्ञान-आधारित सेवाएं भी प्रदान कर रहा है । विश्व में फैले देशों ने भारत को एक अपरिहार्य आर्थिक साझेदार के रूप में देखना शुरू कर दिया है तथा हमारी उभरती अर्थव्यवस्था के साथ आपसी लाभप्रद आर्थिक और व्यावसायिक संबंध कायम करना चाहते हैं । क्या हमारे पड़ोसी भी आपसी संपन्नता के अवसरों में योगदान करना नहीं चाहेंगे जैसा कि भारत उनके साथ कर रहा है ? क्या हमारे पड़ोसी देश भारत के साथ सहयोग कर या भारत से शत्रुता कर या हमारे भूगोल के तर्क के विरूद्ध भारत से अपने-आप को अलग रखकर अपनी स्वयं की सुरक्षा और विकास पर बल देते हैं ? कुछ पड़ोसियों ने भारत की ताकतों का फायदा उठाया है और परिणामस्वरूप आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों लाभ हासिल कर रहे हैं । अन्य ऐसा नहीं कर रहे हैं । यदि वैश्वीकरण में कहा गया है कि कोई भी देश तानाशाही वातावरण में विकास नहीं कर सकता है, तो क्या यह एक क्षेत्र के अंदर के देशों के लिए और अधिक सत्य नहीं है ? यदि सार्क को दक्षिण एशिया की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप एक संगठन के रूप में खड़ा किया गया है, तो इन प्रश्नों पर गहन विचार-विमर्श करने तथा इसका ईमानदारीपूर्ण उत्तर देने की आवश्यकता होगी ।

भारत चाहेगा कि संपूर्ण दक्षिण एशिया एक उभरते लोकतांत्रिक समुदाय के रूप में सामने आए । हम विश्वास करते हैं कि लोकतंत्र हमारे उप-महाद्वीप में सहयोग तथा शांति की स्थापना के लिए एक अत्यन्त टिकाऊ और व्यापक आधार वाली नींव प्रदान करेगा । दक्षिण एशिया में अर्द्धशताब्दी में हासिल राजनीतिक अनुभव से यह स्पष्ट सीख मिली है कि जबकि स्वार्थपरायणता से अल्पकालीन लाभ हासिल होता है, यह मानव अधिकारों और सर्वसाधारण के आदर के हमारे मर्म-मूल्यों को अलाभकारी क्षति भी पहुंचाता है । एक समान इतिहास और भाग्य को संजोने वाली दक्षिण एशिया की जनता के हितों के लिए आवश्यक है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने वाले प्रयासों या आतंकवादी एवं साम्प्रदायिक ताकतों से उभरने वाले संभावित खतरों से सावधान रहें । जबकि लोकतंत्र भारत की चिरस्थायी दृढ़ धारणा है, हमारे पड़ोस की महत्ता के लिए आवश्यक है कि हम सरकार द्वारा अपने पड़ोस के किसी भी देश में किए जा रहे कार्यों से संबद्ध रहें ।

भारत समस्त पड़ोसियों के लिए अपना बाजार खोलने के लिए तैयार है

। भारत अपने प्रत्येक पड़ोसी के साथ सीमा पर अवसंरचना के पुनर्निर्माण और सुधार में पूंजी निवेश के लिए तैयार है । एकशब्द में, भारत अपने पड़ोसियों को भारत की आर्थिक निर्यात में तथा, ऐसे सहयोग के माध्यम से, सच्ची गतियमान और वैश्विक प्रतिस्पर्धी दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय के सृजन में पूर्ण साझेदारी देने को तैयार है ।

अफगानिस्तानःभारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों ने गहनता और सहयोग की एक नई ऊंचाई हासिल कर ली है । दोनों देशों के बीच निरन्तर राजनीतिक संपर्क होते रहे हैं । प्रधानमंत्री ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयार्क में राष्ट्रपति करजई के साथ अपनी बैठक में, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की भारत की वचनबद्धता को ईंगित किया तथा अफगानिस्तान में आर्थिक पुनर्निर्माण प्रयास के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया । भारत की वर्तमान वचनबद्धता 2002-2008 की अवधि के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर तक है, जो एक गैर-परम्परागत दाता के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि है ।

बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंकाः भारत ने बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के साथ निकट संबंध बनाए रखा । 26 दिसम्बर 2004 की सुनामी विनाश की त्रासदी से जूझने के लिए भारत द्वारा दी गई तत्काल राहत सहायता को बड़े पैमाने पर सराहा गया ।

भूटानः आपसी समझ, विश्वास, आस्था और नियमित रूप से हो रहे उच्चस्तरीय दौरे भूटान के साथ भारत के आपसी लाभप्रद संबंधों को ईंगित करते हैं । भूटान के शाही राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक 26 जनवरी, 2005 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे ।

म्यामांः म्यामां के साथ सृजनात्मक गठजोड़ की भारत की नीति 2004-05 के दौरान भी जारी रही । सीनियर जनरल थान स्वे, म्यामां के स्टेट पीस एण्ड डेवलपमेंट कॉऊन्सिल (एस पी डी सी) के अध्यक्ष ने 24-29 अक्टूबर 2004 तक भारत का राजकीय दौरा किया । उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि म्यामां भारत के विरूद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधि के लिए अपने क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देगा । भारत आपसी हित की सीमापार परियोजनाओं को विकसित कर म्यामां के साथ उत्तर-पूर्वी राज्यों को जोड़ने तथा आर्थिक विकास करने के लिए कार्यरत है । इनमें सड़क, रेलवे, बिजली, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं । म्यामां भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है।

नेपालः बहुदलीय सरकार की बर्खास्तगी, आपातकाल की घोषणा तथा 1 फरवरी, 2005 को नेपाल के राजा द्वारा राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी से उत्पन्न नेपाल की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति से भारत काफी अधिक चिंतित है। नेपाल की ऐसी प्रगति से लोकतंत्र के मकसद को काफी क्षति पहुँची है, जिससे मात्र संविधान-विरोधी ताकतों को लाभ हासिल होगा । भारत का सदैव यह विश्वास रहा है कि नेपाल में उत्पन्न चुनौतियों का सामना मात्र राष्ट्रीय जनमत से प्रभावी ढंग से किया जा सकता है । इस परिप्रेक्ष्य में, हमने नेपाल में यथाशीघ्र सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए आह्वान किया है । अपनी ओर से, भारत नेपाल में राजनीतिक स्थायित्व की बहाली और आर्थिक सम्पन्नता के समस्त प्रयासों को समर्थन देना जारी रखेगा ।

पाकिस्तानः दक्षिण एशिया में व्यवहार्य शांति एवं स्थायित्व की स्थिति तैयार करने के वृहत्तर उद्देश्य के साथ पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, दोस्ताना और सहयोगी संबंध स्थापित करने हेतु सरकार ने रचनात्मक गठजोड़ की एक सकारात्मक नीति अपनाई है। इस्लामाबाद में 6 जनवरी, 2004 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दी गई औपचारिक वचनबद्धता, कि पाकिस्तान के नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र को आतंकवाद के समर्थन के लिए प्रयोग में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, के आधार पर दोनों देशों ने 2004-05 में अपनी संयुक्त वार्त्ता को जारी रखा। इस गठजोड़ से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जैसे कि उच्चायुक्तों के स्तर पर संबंधों की बहाली, लोगों -से- लोगों और संस्थागत सम्पर्कों में वृद्धि तथा संचार सम्पर्कों में सुधार हुआ है । विशेष तौर पर नवम्बर 2003 से युद्ध-विराम हो गया है । दोनों देश इस समय विभिन्न प्रस्तावों पर समझौता कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी, आर्थिक सहयोग सुधरेगा और द्विपक्षीय सम्पर्क संस्थापित होंगे । वर्ष 2004-05 में उच्चस्तरीय सम्पर्क भी हुए, जैसे कि 21 सितम्बर, 2004 को न्यूयार्क में राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ और प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह के बीच बैठक हुई तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शौकत अजीज ने 22-23 नवम्बर, 2004 को भारत का दौरा किया । विदेश मंत्री ने दिल्ली में 5-6 सितम्बर 2004 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री से संयुक्त वार्त्ता में समग्र प्रगति की समीक्षा करने के लिए मुलाकात की तथा 15-17 फरवरी, 2005 तक पाकिस्तान का द्विपक्षीय दौरा किया, जहां यह सहमति हुई थी कि 7 अप्रैल 2005 से मुजफ्फराबाद - श्रीनगर बस सेवा चालू की जाए और ननकाना साहिब जैसे धार्मिक स्थलों सहित अमृतसर से लाहौर तक एक बस सेवा शुरू की जाए ।

ईरानः वर्ष 2004-05 में भारत-ईरान संबंधों को और अधिक गहराते एवं सुदृढ़ होते देखा गया । उच्चस्तरीय विनिमयों, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच संस्थागत संपर्कों तथा संयुक्त आयोग बैठक की बढ़ती गतिमात्रा 2004-05 की मुख्य घटनाएं थीं । संबंध को एक सामरिक स्वरूप प्रदान करने वाले सामान्य संकल्प को जनवरी 2003 में हस्ताक्षरित नई दिल्ली घोषणा में संकल्पित और प्रतिपादित किया गया था जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं के साथ-साथ आपसी महत्व के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मामलों को शामिल किया गया है।

दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशान्त महासागर

वर्ष के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशान्त महासागर के देशों के साथ भारत के संबंध व्यापक और गहन हुए हैं । इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण आगन्तुकों में सिंगापुर, न्यूजीलैण्ड और मलेशिया के प्रधानमंत्री शामिल थे । सोलोमन द्वीपसमूह के विदेश मंत्री ने जनवरी 2005 में भारत का दौरा किया । विदेश मंत्री ने सुनामी आपदा की विभीषिका के बाद जकार्ता में विशेष आसियान नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया । विदेश मंत्री ने 11वीं ए आर एफ बैठक में हिस्सा लेने के लए ईण्डोनेशिया का दौरा किया और इस दौरे के दौरान ईण्डोनेशिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग संबंधी एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था । इसने लाओस, म्यामां और वियतनाम के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किया, जो तीनों देशों की राजधानियों में उद्यमवृत्ति विकास केन्द्रों की स्थापना करने से संबंधित था। इस तरह के पहले केन्द्र का उद्घाटन 27 नवम्बर 2004 को वियतनाम में विदेश मंत्री द्वारा किया गया था ।

पूर्व एशिया

चीनः भारत ने चीन के साथ एक-दूसरे की समस्याओं और अपेक्षाओं के प्रति शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं आपसी भावुकता के पांच सिद्धांतों के आधार पर दोस्ताना, सहयोगी, अच्छे पड़ोस तथा आपसी तौर पर लाभप्रद संबंधों की ईच्छा रखते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखा। भारत ने चीन के साथ पिछले मतभेदों को सुलझाने और दीर्घकालीन रचनात्मक तथा सहयोगी संबंध बनाने के लिए वार्त्ता की प्रक्रिया को जारी रखने की वचनबद्धता को भी निभाया, जिसमें उच्चस्तरीय वार्ता की निरंतरता, सुदृढ़ीकरण और स्थायी गतिशीलता भी शामिल थी । प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने वियनताने, लाओस में तीसरे भारत-आसियान सम्मेलन की तर्ज पर 30 नवम्बर 2004 को चीनी प्रीमियर वेन जिबाओ से मुलाकात की । द्विपक्षीय वार्त्ता तंत्र को उस सामरिक वार्त्ता को शुरू कर सुदृढ़ बनाया गया था, जो 24 जनवरी 2005 को नई दिल्ली में चीनी उप विदेश मंत्री तथा विदेशी सचिव के बीच हुई थी । विभिन्न स्तरों पर विनिमयों/ अंतर्सम्पर्कों के माध्यम से दोनों सेनाओं के बीच क्षमता-निर्माण प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया था । भारत- चीन व्यापार की प्रगति को बनाए रखा गया और इसने 2004 में 13 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा को पार कर लिया । वर्ष के दौरान घटित मुख्य घटना पंचशील की पचासवीं वर्षगांठ को मनाना था, जिसे भारत और चीन द्वारा संयुक्त रूप से दोनों देशों की राजधानियों में कार्यक्रम को आयोजित कर मनाया गया ।

जापानः भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए 2004-05 की अवधि एक सक्रिय वर्ष के रूप में थी । द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक और गहन बनाने के लिए 2000 में भारत तथा जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित 21वीं सदी की वैश्विक साझेदारी के अनुसरण में वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच विनिमयों का दौर जारी रहा । प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 29 नवम्बर 2004 को वियनताने, लाओस में आसियान सम्मेलन के तर्ज पर जापान के प्रधानमंत्री श्री जुनिचिरो कोजुमी से मुलाकात की, जिसके अंतर्गत दोनों नेताओं ने आपसी हित के मामलों पर चर्चा की । दोनों पक्ष विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की एक-दूसरे की दावेदारी को समर्थन देने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार को हासिल करने हेतु एकजुट होकर काम करने के लिए सहमत हुए ।

कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्यः दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं जयंती मनाने के लिए, भारत ने जुलाई 2004 में कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य को 1000 मी0 टन चावल की आपूर्ति की । भारत ने सितम्बर 2004 में गुट-निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के 9वें पोंगयांग फिल्म समारोह में भाग लिया ।

मंगोलियाः भारत और मंगोलिया ने उत्साहवर्द्धक मैत्रीपूर्ण राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई । दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच कार्यस्तरीय परामर्शों का प्रथम दौर नई दिल्ली में अक्टूबर 2004 में सम्पन्न हुआ । सर्वप्रथम भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया में अक्टूबर 2004 में किया गया ।

कोरिया गणराज्यः वर्ष 2004-05 को भारत और कोरिया गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं जयन्ती के रूप में मनाया गया । राष्ट्रपति श्री रोह मूहयुन के 4-6 अक्टूबर 2004 के भारत के दौरे में द्विपक्षीय संबंधों पर और अधिक बल दिया गया । विदेश मंत्री ने भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए 14-16 दिसम्बर 2004 तक कोरिया गणराज्य का दौरा किया ।

यूरेशिया

स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण, जोशपूर्ण और आपसी सहयोग वाले संबंध में वर्ष के दौरान और अधिक मजबूती आई है । आर्थिक एवं व्यापार संबंधों को गति प्रदान करने के लिए "फोकस सी आई एस" कार्यक्रम शुरु किया गया था । क्षेत्र के देशों के साथ नियमित आधार पर उच्च स्तरीय दौरा का विनिमय हुआ । इसमें व्यापार शिष्टमंडलों के दौरे के साथ-साथ औद्योगिक एवं उपभोक्ता सामान प्रदर्शनियों में भागीदारी से समर्थन मिला है। भारतीय सांस्कृतिक पर्वो और मीडिया विनिमयों ने इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को और अधिक बढ़ाया है।

भारत-रुस संबंध दोनों देशों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इस वर्ष दोनों पक्षों द्वारा सहयोग को घोषणा स्तर से बदलकर रचनात्मक चरण तक लाने में भगीरथ प्रयास किया गया। पाँचवी भारत-रुस बैठक के लिए 3-5 दिसम्बर, 2004 तक राष्ट्रपति व्लादिमीर वी पुतिन द्वारा भारत के दौरे से अपने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा करने, आपसी हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा करने तथा ऊर्जा, आई टी, बैंकिग एवं उच्च प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों पर द्विपक्षीय ध्यान केन्द्रित करने का अवसर हासिल हुआ । सी आई सी ए विदेश मंत्रियों की बैठक के तर्ज पर अलमाटी में 21 अक्तूबर 2004 को भारत रुस एवं चीन के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक हुई । उन्होंने क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हित के मामलों पर विचार-विनिमय किया तथा त्रिपक्षीय आर्थिक सहयोग की संभावना तलाशने पर सहमत हुए ।

रूसः भारत-रूस संबंध दोनों देशों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है । अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए भारत-रूस संयुक्त कार्यदल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 8 अप्रैल 2004 को हुई थी । इसमें विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, आतंकवाद वित्तपोषक स्त्रोतों और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अनुभव का आदान-प्रदान करने तथा जानकारी विनिमय करने हेतु द्विपक्षीय तंत्रों को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया । सी आई सी ए विदेश मंत्रियों की बैठक के तर्ज पर भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की तीसरी त्रिपक्षीय बैठक 21 अक्टूबर 2004 को अलमाटी में हुई । उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई और इराक में शांति व्यवस्था कायम करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सहित, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय हित के मसलों पर विचार-विनिमय किया । उन्होंने त्रिपक्षीय आर्थिक सहयोग की संभावनाओं को तलाशने पर भी सहमति जताई ।

(कई मंत्रीस्तरीय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं तकनीकी स्तरीय दौरों के अतिरिक्त राष्ट्रपति पुतिन के दौरे की कोई चर्चा नहीं की गई ।)

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की 10वीं बैठक 18-19 नवम्बर 2004 को नई दिल्ली में हुई थी । वर्तमान सहयोग के अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने संभावित विकास के नए क्षेत्रों के रूप में ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, संचार, जैव-प्रौद्योगिकी का पता लगाया ।

यूरोप

यूरोपीय संघ और यूरोप के प्रत्येक देशों के साथ भारत का संबंध वर्ष के दौरान निरन्तर बढ़ता रहा । इन सम्पर्कों में उच्चस्तरीय दौरों सहित दौरों का निरन्तर विनिमय, द्विपक्षीय संबंधों को गहरा और विस्तारित करने की आपसी ईच्छा का प्रदर्शन शामिल था । भारत ने फ्रांस, जर्मनी और ईंग्लैण्ड के साथ सामरिक साझेदारी कायम की तथा यूरोप के कई अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ाए, जो व्यापक क्षेत्रों में अत्यंत गहन द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रति लक्षित थे । नवम्बर 2004 में हेग में हुई 5वीं भारत-यूरोपीय संघ बैठक भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें मुख्य क्षेत्रीय एवं वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत की बढ़ती हस्ती को समझते हुए भारत-यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी की शुरूआत हुई । यूरोप के प्रत्येक सदस्य देशों के साथ सम्पर्कों से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आपसी समझदारी झलकती रही । संयुक्त राष्ट्र सुधारों संबंधी चर्चा में, भारत विभिन्न यूरोपीय संघ सदस्य देशों से महत्वपूर्ण समर्थन हासिल करने में समर्थ रहा । भारत और जर्मनी ने एक सामरिक नीति के तहत विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन देने पर सहमति जताई।

यूरोप के देशों के साथ भारत का मजबूत संबंध कायम करने के लिए आर्थिक विचार हो रहा है । प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती पहचान को दर्शाने के लिए प्रौद्योगिकी के आला क्षेत्रों में संवर्द्धित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु द्विपक्षीय संधि/समझौता ज्ञापन करने के लिए यूरोपीय संघ के सदस्य देश इच्छुक हैं । विभिन्न प्रख्यात व्यक्तियों के समूह के प्रतिनिधित्व में, मुख्य यूरोपीय देशों के साथ वार्त्ताओं से बहुआयामी संबंध को सुदृढ़ बनाने में योगदान मिला।

मंत्रालय में मार्च 2004 में सृजित यूरोप-II प्रभाग के 29 देशों के साथ भारत ने मैत्रीपूर्ण एवं व्यापक संबंधों का परम्परागत लाभ उठाया । समीक्षाधीन वर्ष में क्षेत्र के आर्थिक-राजनीतिक परिदृश्य में युगान्तकारी परिवर्तन देखा गया । 2 अप्रैल 2004 को सात पूर्वी यूरोपीय देश यथा बुल्गारिया, ईस्तोनिया, लातिविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल हो गए । एक महीने बाद, यूरोपीय संघ को विस्तारित किया गया जिससे दस अधिक सदस्य देशों को शामिल किया जा सके । वर्ष के अंत तक, यूरोपीय संघ ने निर्णय लिया कि बुल्गारिया और रोमानिया 2007/2008 में इस निकाय में शामिल होने के लिए सक्षम थे । यूरोपीय संघ ने क्रोएशिया तथा तुर्की के साथ सहमति वार्त्ताएं शुरू करने का भी निर्णय लिया । यूरोपीय संघ, जो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निवेश का स्त्रोत है, में हो रहे परिवर्तनों का भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव है । मंत्रालय ने उच्च-स्तरीय राजनीतिक सम्पर्कों को बढ़ावा और संरक्षण प्रदान किया है तथा समस्त देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाया है ।

खाड़ी देश

वर्ष 2004-05 में खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें विदेश मंत्री का दिसम्बर 2004 में ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात दौरा, कुवैती विदेश मंत्री का अगस्त, 2004 में भारत दौरा, राज्य मंत्री श्री ई. अहमद का सऊदी अरब(जून एवं नवम्बर, 2004), बहरीन (अगस्त, 2004), कतर(अक्तूबर 2004), ओमान (नवम्बर, 2004) और यमन एवं कुवैत (फरवरी, 2005) दौरा शामिल है । भारत और जी सी सी के बीच आर्थिक सहयोग संबंधी रुपरेखा करार पर हस्ताक्षर होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । भारत के राष्ट्रपति ने नवम्बर 2004 में राष्ट्रपति शेख जईद की मृत्यु पर शोक जताने के लिए आबूधाबी का दौरा किया । क्षेत्र में हमारे राजनयिक प्रयासों को नई दिशा और बल प्रदान करने के लिए विदेश मंत्री की अध्यक्षता में दुबई में पश्चिम एशिया के मिशन प्रमुखों का सम्मेलन हुआ । भारत ने दोहा (मई 2004), टोक्यो (अक्टूबर, 2004) में इराक दानदाता सम्मेलन में हिस्सा लिया । तीन भारतीय राष्ट्रिकों, जिन्हें जुलाई 2004 में इराकी आतंकवादी दल द्वारा बंदी बना लिया गया था, को निरंतर राजनयिक प्रयासों के बाद हानिरहित छुड़ा लिया गया था । कुवैत एवं ओमान के साथ प्रत्यर्पण संधियां हस्ताक्षरित हुई थी। जी सी सी देशों ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी का पुरजोर समर्थन किया ।

पश्चिम एशिया एवं उत्तर अफ्रीका

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (वाना) क्षेत्र के साथ भारत के संबंध को इस वर्ष के दौरान और अधिक गति हासिल हुई । उच्च स्तरीय दौरों में मोरक्को प्रधान मंत्री तथा इसराइली उप प्रधान मंत्री का भारत दौरा शामिल था । मोरक्को प्रधानमंत्री का भारत दौरा जून 2005 से अरब क्षेत्र की ओर से प्रथम उच्च स्तरीय दौरा था । विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक काबीना मंत्री सहित एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने 12 नवम्बर, 2004 को कायरो में राष्ट्रपति अराफात की अन्त्येष्टी में हिस्सा लिया । भारत और वाना क्षेत्र विशेषकर लिबिया और इसरायल के बीच आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई । भारत तेल निष्कासन और गैस वितरण में हिस्सेदारी हासिल कर सूडान, लिबिया, मिस्त्र और साईरिया में हाईड्राकार्बन क्षेत्र में प्रवेश कर गया है । राष्ट्रपति यासर अराफात की मृत्यु के बाद श्री महमूद अब्बास फिलीस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के नए राष्ट्रपति चुने गए। एक महत्वपूर्ण प्रगति इसराइल एवं फिलीस्तीनी नेतृत्व के बीच 8 फरवरी 2005 को शर्म अल शेख सम्मेलन में शांति वार्ता का फिर से बहाल होना था । भारत ने पश्चिम एशिया एवं मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में अपना विशेष दूत नियुक्त किया है ।

पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका

वर्ष के दौरान पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए । जंजीबार के राष्ट्रपति ने मार्च 2004 को भारत का दौरा किया । भारत के उपराष्ट्रपति ने दक्षिण अफ्रीका के 10वें स्वतंत्रता दिवस में हिस्सा लेने के लिए अप्रैल 2004 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया । राष्ट्रपति जी ने सितंबर 2004 में तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया । उन्हें पैन-अफ्रीकन पार्लियामेंट को संबोधित करने का सम्मान मिला था, वे ऐसा करने वाले राज्य के पहले गैर-अफ्रीकी प्रमुख थे ।

राष्ट्रपति कलाम ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान यह घोषणा की कि भारत अफ्रीका के सभी देशों में फाईबर ऑप्टिक और इलेक्ट्रानिक संपर्कता स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता और सुविज्ञता मुहैया कराएगा । यह एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे अफ्रीकी राज्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों और संचार की आधुनिक पद्धतियों को अपना सकेंगे । ऐसी उम्मीद है कि ऐसे संपर्क से अफ्रीका में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र विकास में काफी तेजी आएगी और वे ई-मेडिसीन, ई-गवर्नेंस, ई-एजूकेशन आदि पर आधारित योजनाओं को

कार्यान्वित कर पाएंगे । वर्ष के दौरान कोमोरॉस, लेसोथो और मॉरीशस के विदेश मंत्रियों ने भारत का दौरा किया ।

भारत ने अफ्रीका में अर्थात् बुरूंडी, आइवरी कॉस्ट और डी आर सी में विभिन्न शांति प्रयास वाले कार्यों में हिस्सा लिया, जो गृहयुद्ध और मानवीय हिंसा से ग्रस्त था । भारतीय सेना का एक विशाल सैन्य दल, जो संयुक्त राष्ट्र बल का अंग है, इरीट्रिया और इथोपिया के बीच शांति बहाल कर रहा है । इस बल का वर्तमान कमांडर (यूनाइटेड नेशन्स मिशन इन इथोपिया एण्ड इरीट्रिया) भारत का एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी है ।

अफ्रीका में यह सामान्य मान्यता है कि भारत विश्व में प्रत्येक मायने में अब एक शक्ति बन गया है । इसीलिए अफ्रीका के अधिकांश देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का जोरदार समर्थन किया है । विभिन्न अफ्रीकी देशों में रहने वाले भारतीय समुदायों ने हाल ही के वर्षों में यह साबित कर दिखाया है कि वे भारत और उन देशों, जहां वे रह रहे हैं, के बीच के संबंधों को मजबूत करने में एक बहुमूल्य माध्यम का कार्य कर रहे हैं ।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के उद्योगपतियों का एक संयुक्त मंच हाल ही में बनाया गया था, दोनों तरफ से जिसकी अध्यक्षता क्रमशः मि0 रतन टाटा और मि0 पेट्रीस मोट्सेप कर रहे थे । राष्ट्रपति कलाम ने दक्षिणी अफ्रीका के दौरे के दौरान यह घोषणा की कि भारत अफ्रीका के सभी देशों में फाईबर ऑप्टिक और इलेक्ट्रानिक संपर्कता स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता और सुविज्ञता मुहैया कराएगा । यह एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे अफ्रीकी राज्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों और संचार की आधुनिक पद्धतियों को अपना सकेंगे । ऐसी उम्मीद है कि ऐसे संपर्क से अफ्रीका में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र विकास में काफी तेजी आएगी और वे ई-मेडिसीन, ई-गवर्नेंस, ई-एजूकेशन आदि पर आधारित योजनाओं का कार्यान्वित कर पाएंगे ।

भारत ने अफ्रीका में अर्थात् बुरूंडी, आइवरी कॉस्ट और डी आर सी में विभिन्न शांति प्रयास वाले कार्यों में हिस्सा लिया, जो गृहयुद्ध और मानवीय हिंसा से ग्रस्त था । भारतीय सेना का एक विशाल सैन्य दल, जो संयुक्त राष्ट्र बल का अंग है, इरीट्रिया और इथोपिया के बीच शांति बहाल कर रहा है । इस बल का वर्तमान कमांडर (यूनाइटेड नेशन्स मिशन इन इथोपिया एण्ड इरीट्रिया) भारत का एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी है ।

अफ्रीका में यह सामान्य मान्यता है कि भारत विश्व में प्रत्येक मायने में अब एक शक्ति बन गया है । इसीलिए अफ्रीका के अधिकांश देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का जोरदार समर्थन किया है । विभिन्न अफ्रीकी देशों में रहने वाले भारतीय समुदायों ने हाल ही के वर्षों में यह साबित कर दिखाया है कि वे भारत और उन देशों, जहां वे रह रहे हैं, के बीच के संबंधों को मजबूत करने में एक बहुमूल्य माध्यम का कार्य कर रहे हैं ।

मारीशसः भारत पोर्ट लुईस में 15 मिलियन यू एस डालर की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय केन्द्र बना रहा है । इस राशि का आधा हिस्सा अनुदान के रूप में जबकि आधा हिस्सा ऋण के रूप में है । एविजम बैंक ऋण द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित साईबरसिटी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था । अनेक अन्य परियोजनाएं विचाराधीन हैं जिसके लिए मारीशस को पर्याप्त ऋण मुहैया कराया जाएगा । भारत अनेक अन्य क्षेत्रों में मारीशस की सहायता कर रहा है और राजनैतिक संबंध लोगों के घनिष्ठ संबंधों पर टिके हैं ।

पश्चिम अफ्रीकाः पश्चिम अफ्रीका के देशों के साथ भारत का सौहार्दपूर्ण संबंध बना हुआ है । पश्चिम अफ्रीका में भारतीय राजनयिक मिशन मजबूत हुए थे और किंशासा में भारतीय दूतावास फिर से खोलने का भी निर्णय लिया गया है । कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारतीय दूतावास फिर से खुल चुका है । इसके लिए भारत की ओर से पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है और मंत्रालय ने इस क्षेत्र में खासकर अंगोला, नाईजीरिया, कोट डी आईवरी, मौरीतानिया और विषुवतरेखीय गिनी में तेल और पेट्रोलियम क्षेत्र तक अपनी पैठ स्थापित करने की पहल की है । भारत ने इकॉनोमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स (इकावास) को अपना दृढ़ सहयोग भी दिया और नाइजीरिया में भारत के राजदूत की इकॉवास के लिए प्रत्यायित स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया । कोट डी आईवरी, और गिनी को दी जाने वाली खाद्य सहायता के साथ तकनीकी सहायता और विकास संबंधी मदद जारी रही । इस क्षेत्र के देशों को एच आई वी प्रतिरोधी दवाईयां भी भेजी गई थीं । नाईजीरिया के राष्ट्रपति ने नवम्बर 2004 में भारत का रवानगी दौरा किया और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की । नई पहल टीम 9 की शुरूआत, जो भारत और पश्चिम अफ्रीका के आठ देशों के बीच एक तकनीकी आर्थिक सहयोग प्रयत्न है, एक प्रमुख पहल थी जिसका लक्ष्य भारत द्वारा सामान्यतः अफ्रीका में और विशेष रूप से पश्चिम अफ्रीका में किए जाने वाले विशेष क्रियाकलापों को प्रदर्शित करना था ।

अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिकाः भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी अपनी प्रबल वचनबद्धता को जारी रखा जैसा कि द्विपक्षीय संपर्कों और वार्त्ताओं की बारंबारता और बहुलता से पता चलता है । दोनों पक्षों ने अपने विस्तृत संबंधों को, जिसमें सामरिक और और सुरक्षा मुद्दे, रक्षा, आतंकवाद विरोधी, हथियार उत्पादन विरोधी मुद्दे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, व्यापार, अंतरिक्ष, ऊर्जा और पर्यावरण शामिल थे, को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रबल प्रतिबद्धता दिखाई ।

प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति बुश के साथ 17 सितम्बर 2004 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उपवृत्ति के संबंध में एक बैठक हुई थी । बैठक में हमारे संबंध में भावी निर्देश जारी होने के बाद एक संयुक्त कथन"संयुक्त राज्य भारत साझेदारीः सहयोग और विश्वास" जारी किया गया और यह देखा गया कि"द्विपक्षीय संबंध इतने घनिष्ठ कभी नहीं रहे थे जितने कि वे इस समय थे "। बैठक में डब्ल्यू एम डी प्रसार, आतंकवाद की समस्या का समाधान करने और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ाने के प्रति हमारी वचनबद्धता सहित इसके सामरिक आयामों को चिन्हित करने का काम किया गया । नेताओं ने पाया कि नेकस्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (एन एस एस पी) के प्रथम चरण के कार्यान्वयन से सहयोग और विश्वास के नए युग का सूत्रपात हुआ । बहुपक्षीय संस्थाओं, डब्ल्यू टी ओ के दोहा विकास एजेंडा सहित और भारत संयुक्त राज्य आर्थिक वार्त्ता तथा द हाई टेक्नोलॉजी कोपरेशन ग्रुप (एच टी सी जी) सहित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया गया ।

वर्ष के दौरान राजनैतिक स्तर पर उच्च-स्तरीय करार जारी रहे । जून 2004 में भारत के विदेश मंत्री का वांशिगटन डी सी का दौरा और बाद में 1-2 जुलाई 2004 को ए आर एफ की उपवृति पर और फिर जनवरी 2005 में सुनामी के कहर के बाद उनके संयुक्त राष्ट्र के राज्य सचिव कोलिन पावेल के साथ हुई बैठक ने भारत में नई सरकार के गठन के बाद दोनों देशों के बीच राजनैतिक स्तर पर संबंधों को मजबूत

बनाने का काम किया। संयुक्त राज्य की तरफ से, राज्य के उप सचिव रिचर्ड आर्मिटेज ने 13-14 जुलाई 2004 को और संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया। संयुक्त राष्ट्र रक्षा सचिव डोनाल्ड एक्सफेल्ड ने 8-9 दिसंबर 2004 को भारत का दौरा किया।

कनाडाः कनाडा के प्रधानमंत्री मि0 पॉल मार्टिन ने 17-18 जनवरी 2003 को भारत का दौरा किया। दोनों नेताओं के संयुक्त कथन में भारत-कनाडा साझेदारी को सुदृढ़ बनाने एवं बढ़ाने वाली पहलों पर तथा वैश्विक चुनौतियों का कारगर ढंग से सामना करने पर सहमति हुई। दोनों प्रधानमंत्री इस बात पर सहमत थे कि भारत और कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय और वैश्विक सामरिक मुद्दों पर अपनी वार्त्ता को जारी रखना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय खतरों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्राथमिकता के रूप में एक बहुपक्षीय पहल को भभ् स्वीकार किया। भारत और कनाडा ने वर्ष के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना जारी रखा।

लेटिन अमेरिकी देश (एल ए सी)

वर्ष 2004 में भारत सरकार का लेटिन अमेरिकी देशों के साथ वचनबद्धता का स्तर मजबूत होना और विस्तृत होना जारी रहा। इस क्षेत्र के प्रति नीति का उद्देश्य मौजूदा संबध को मजबूत एवं विस्तृत करना, राजनैतिक वार्त्ता और सहयोग के लिए एक तंत्र बनाना तथा व्यापार और उद्योग को बढाना है। क्षेत्रीय समूहों अर्थात् देशों के मर्कोसर समूह के साथ फ्रेमवर्क करार किएप गए हैं, कैन (एंडीयन समुदाय) के साथ राजनैतिक वार्त्ता और सहयोग तंत्र, परामर्श के लिए एक स्थायी संयुक्त आयोग, कैरीकॉम के साथ सहयोग और समन्वय तथा देशों के केंद्रीय अमेरिकी समूहों (सीसा) के साथ राजनैतिक परामर्शों का तंत्र।

संयुक्त राष्ट्र और दीसा

प्रधानमंत्री ड0 मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 52वें सत्र में भारतीय शिष्टमंडल का नेतत्व किया और अपने संबोधन में, उन्होंने बहुपक्षीयण्वादल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुनः पएष्टि की। प्रधानमंत्री ने स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद के विस्तार के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह एक वास्तविक प्रतिनिधित्वात्मक निकाय बन सके। फिलहाल भारत संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयास कार्यों में अत्यधिक सैन्य सहायता भेजने वालों में से एक है। भारत ने अपनी नीति-निर्णयों और राजनयिक पहलों में गैर-भेदभाव मूलक और सर्वसामान्य परमाण्विक निरस्त्रीकरण और सभी जन संहारक हथियारों के बहिष्कार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी। विभिन्न बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंचों में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर देश का नजरिया भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों और इन चुनौतियों का समाधान करने में सहयोगी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंधों की परंपरा पर आधारित था।

प्रमुख देशों के साथ द्विपक्षीय वार्त्ता इस वर्ष पर भी जारी रही और हथिरोत्पादन पर रोक लगाने और निरस्त्रीकरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के साथ भारत की राष्ट्रीय अनिवार्यताओं और सुरक्षा दायित्वों का सामंजस्य भी धीरे-धीरे बढ़ता गया। आशयान क्षेत्रीय मंच (ए आर एफ) और कोन्फ्रेंश और इंटरएक्शन एंड कंफिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया (सीसा) के अंतर्गत ढांचे और विश्वास और सुरक्षा निर्माण प्रक्रिया में भारत की भागीदारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में सक्रिय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ नियमित संपर्क बहाल रखा गया ताकि निरस्त्रीकरण मुद्दे पर भारत के परिप्रेक्ष्यों का प्रसार किया जा सके।

एम ई आर प्रभाग

भारत की पूर्व की और देखो नीति को दी गई प्रमुखता के अनुसरण में, सरकार ने दक्षिण-पूर्वी और

पूर्वी एशिया के देशों के साथ, जिसके साथ भारत का सांस्कृतिक और नागरीय संबंध काफी गहरा है, नए संपर्क स्थापित करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के प्रयास जारी रखे। बैंकाक में 30-31 जुलाई 2004 को सबसे पहला बिम्सटेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तीसरा भारतीय-आशियान शिखर सम्मेलन वियंतियान, लाओ पी डी आर में 29-30 नवंबर 2004 को संपन्न हुआ था, जिस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज शांति, प्रगति और पारस्पिरक समृद्धि के लिए भारत-आशियान भागीदारी पर हस्ताक्षर हुए थे। पहला भारत-आशियान मोटर कार रैली 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक भारत में गुवाहाटी से शुरू होकर 8 आशियान देशों से गुजाने के बाद इण्डोनेशिया में बनाम द्वीप पर समाप्त हुआ। यह रैली एक महत्वपूर्ण सफलता थी

ईब्साः भारत द्विपक्षीय तथा भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (ईब्सा) वार्त्ता के त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के भीतर दक्षिण अफ्रीका की काफी अधिक सहायता कर रहा है। ईब्सा को विकासशील देश में सहयोग के एक मॉडल के रूप में देखा जाता है और इससे अन्य देशों में और अधिक हित एवं अनुराग की भावना जगी है।

निवेश एवं व्यापार को प्रोत्साहन

वैश्वीकरण के इस दौर में भारत के आर्थिक एवं वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने तथा इसे प्रोत्साहन करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तथा तीव्रता से समेकित होती हुई विश्व अर्थव्यवस्था द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ उठाने एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए मंत्रालय ने आर्थिक व्यवहार कुशलता को सर्वोच्च वरीयता दी है। इसमें व्यापार, दोहरे विदेशी निवेश, आयात और क्षेत्रीय समूहों के साथ बढ़ता हुआ करार इत्यादि को प्रोत्साहित करना शामिल है। मित्र देशों, विशेषकर विकासशील देशों के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों पर अब अधिक बल दिया जाता है। मंत्रालय निवेश और निर्यात प्रोत्साहक लक्ष्यों, तथा सामान्य आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में सरकार और व्यापार तथा उद्योग के बीच सक्रिय भगीदारी में भी विश्वास करता है।

नीतिगत आयोजना और अनुसंधान

मंत्रालय ने अनेक शैक्षणिक और गैर सरकारी संगठनों के साथ पारस्परिक संपर्क को बरकरार रखा है और विदेशी नीति के मामलों पर अनुसंधान अध्ययन शुरू कराने और संगोष्ठियां आयोजित कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। विदेश मंत्री ने विदेशी नीति सलाहकार समूह का भी गठन किया है और भारत के हित में उभरते हुए मुख्य विदेशी मुद्दों पर विदेशी नीति संबंधी विकल्पों को समझने एवं मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से बैठकें भी आयोजित की गई थी। बीजिंग में 7 नवम्बर 2004 को चीन के साथ और नई दिल्ली में 28 फरवरी 2005 को कनाडा के साथ विदेशी नीति पर बातचीत हुई थी।

विदेशी प्रचार

विदेशी प्रचार के मोरचे पर, मंत्रालय ने विदेश नीति संबंधी अलग-अलग मुद्दों पर भारत के परिप्रेक्ष्य को दर्शाना जारी रखा, जिसमें मई 2004 में यू पी ए सरकार के गठन के बाद से ही उसकी विदेशी नीति संबंधी निदेश के स्पष्ट स्वराच्चारण पर विशेष बल दिया गया था । प्रमुख शक्तियों, पड़ोसियों और पुराने मित्रों के भारत की गठन प्रतिबद्धता को काफी अधिक ख्याति प्राप्त हुई । विदेशी मोरचे पर और खासकर इराक में बंधक संकट के दौरान और सुनामी महाप्रलय के पश्चात, भारत के राहत प्रयासों के संबंध में सभी प्रमुख विकासों के बारे में मीडिया को जानकारी देने में मंत्रालय ने एक प्रमुख भूमिका अदा की । आने तथा जाने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों के दौरान मीडिया शिष्टमंडलों का कार्य आसान हो गया । मंत्रालय ने भारत की विदेश नीति प्राथमिकताओं के अनुरूप, अनेक प्रलेखन कार्यों की शुरूआत की । मंत्रालय ने एक सक्रिय वेबसाईट www.meaindia.nic.in रखने के अलावा मासिक पत्रिका "इंडिया पर्सपेक्टिव" और प्रमुख मुद्दों और घटनाओं पर अन्य विशेष प्रकाशनों का प्रकाशन किया ।

प्रोटोकॉल

मंत्रालय अनेक उच्चस्तरीय दौरों, सम्मेलनों, प्रत्यायक सम्मेलनों, सरकारी कामकाज और विविध स्वरूप वाले अनेक कार्यों में पूरी तरह व्यस्त रहा । विदेशी उच्चपदाधिकारियों के अनेक दौरों का प्रबंध करने के प्रति मंत्रालय की योग्यता से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और प्रोफाईल बेहतर हुई है । प्रोटोकॉल मानदण्डो और मानकों का सरलीकरण प्राथमिकता का मुद्दा बना रहा ।

कान्सुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं

मंत्रालय द्वारा दी गई कान्सुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं भारत और विदेशों में सर्वजनीन हैं । भारत में सभी 30 पासपोर्ट कार्यालय कम्प्यूटरीकृत हैं तथा मशीन से छपे हुए तथा मशीन द्वारा पढे जाने वाले पासपोर्ट जारी करते हैं । विकेंद्रीकरण योजना के भाग के रूप में, जिला स्तर पर 25 जिलों में लगभग 400 जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ (डी पी सी) खोले गए हैं । अतिरिक्त फीस लेकर समय से पहले पासपोर्ट जारी करने के लिए एक नवीन तत्काल योजना शुरू की गई है जिससे अत्यावश्यक मामलों में पासपोर्टों की बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने में मदद मिली है । 22 पासपोर्ट कार्यालयों में टेलीफोन पर पूछताछ की व्यवस्था है और बंगलोर पासपोर्ट कार्यालय में प्रायोगिक आधार पर टच-स्क्रीन इंक्वायरी कियोस्क शुरू किया गया है । सभी मिशन और विदेशी भारतीयों को कांसुलर जरूरतों को कारगर ढंग से पूरा कर रहे थे । नियोजित अपराध, अंतराष्ट्रीय आतंकवाद और ड्रग्स की तस्करी तथा वित्तीय अपराधों के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दायरों से निपटने के लिए एक कानूनी और संस्थागत फ्रेमवर्क मुहैया कराने के लिए अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय करार किया गया था ।

समन्वय

संसद से संबंधित समस्त कार्य तथा संघ एवं राज्य सरकार के विधायकों और सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरों की स्वीकृति के प्रस्तावों की जांच करने के लिए मंत्रालय का प्रमुख अंग समन्वय प्रभाग है । यह प्रभाग भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद आयोजनों एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन को स्वीकृति; विदेशी आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा भागीदारी के साथ-साथ समस्त अनिर्धारित उड़ानों के लिए राजनयिक स्वीकृति जैसे कार्य भी करता है । आतंकवाद - विरोधी दिवस, सदभावना दिवस और कौमी एकता दिवस / सप्ताह का आयोजन किया गया था तथा पद्म पुरस्कार देने हेतु विदेशी नागरिकों के नामांकनों के संबंध में सिफारिशी प्रक्रियाएं चलाई गईं थीं । समन्वय अनुभाग भारत में चुनिंदा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्रों के नामांकन की स्व-वित्तपोषण योजना का संचालन भी करता है ।

विदेशी सेवा संस्थान (एफ एस आई)

विदेश सेवा संस्थान ने आई एफ एस परीविक्षार्थियों एवं विदेश मंत्रालय के अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के अलावा विदेशी राजनयिकों को प्रशिक्षण देने का प्रयास जारी रखा । संस्थान द्वारा वर्ष के दौरान विदेशी राजनयिकों के लिए तीन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और दो उच्च पाठ्यक्रमों तथा फिलीस्तीनी राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था । कनाडा के राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन 21-24 मार्च 2005 को किया जाने वाला है। विदेश मंत्री द्वारा 27 जुलाई 2004 को एफ एस आई के एक प्रभावोत्पादक परिसर का उद्घाटन किया गया जिसे सेवारत भारतीय राजनयिकों को उनकी कार्यावधि के मध्य में प्रशिक्षण देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के परामर्श से स्थापित किया गया था । इस संस्थान ने उन भारतीय राजनयिकों, जिन्होंने 18-20 वर्षों की कार्यावधि पूरी कर ली है, के लिए विदेश नीति, सुरक्षा, आर्थिक एवं क्षेत्रीय मुद्दों के विषय में एक द्वि-साप्ताहिक आवासीय मध्यावधि माड्यूल का भी आयोजन किया । इस वर्ष बुल्गारिया, वेनेजुएला और अफगानिस्तान के विदेश सेवा संस्थानों के साथ सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ ।

प्रशासन

मंत्रालय ने मुख्यालय में और विदेश स्थित 162 भारतीय मिशनों/पदों में अपना कारगर कामकाज सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया । मंत्रालय में पर्याप्त संख्या में योग्य कार्मिक रखने के लिए और अधिकारियों/स्टाफों को पर्याप्त पदोन्नति देने के लिए भी, वर्ष मे दौरान भारतीय विदेश सेवा (आई एफ एस) र आई एफ एस "बी" की संवर्ग समीक्षाएं की गई थीं । आई एफ एस की चौथी संवर्ग समीक्षा का उद्देश्य वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों स्तरों पर पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को नियुक्त करना था । आई एफ एस की सबसे पहली संवर्ग समीक्षा अतिआवश्यक स्टाफिग प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए और विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति में आई स्थिरता से मुक्ति दिलाने के लिए कराई गइ थी । मंत्रालय ने प्रौद्योगिकीय संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए नए उपाय भी शुरू किए हैं । त्रुटिरहित ई-गवर्नेंस परियोजना के भाग के रूप में कार्मिक सूचना प्रणाली (पी आई एस), नाम आधारित और पदनाम आधारित ई-मूल आई डी, का विकास, ऑन-लाईन डाटाबेश का सृजन आदि जैसे उपाय किए गए थे ।

हिंदी को बढ़ावा देने और प्रचार प्रसार करने वाली सरकार की नीति के अनुरूप, मंत्रालय हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास करता रहा है । द्विपक्षीय संधि, समझौता-ज्ञापन, प्रत्यय पत्र, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषण, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और संसदीय प्रश्नों के उत्तर जैसे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज दोनों भाषाओं में जारी किए गए थे । विदेश स्थित अधिकांश मिशनों/पदों को

हिंदी में कामकाज करने में सक्षम बनाया गया है । 18 देशों के 43 छात्रों को केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में भरती किया गया था । विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए रोमानिया में एक क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था । संयुक्त राष्ट्र में एक भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई थी । मंत्रालय में सितंबर 2004 को एक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया था । विदेशी सेवा संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए हिंदी एक अनिवार्य है ।

भारतीय विदेश सेवा के प्रारंभ से ही महिलाएं इस सेवा में आ सकती हैं । मंत्रालय इसकी कार्यप्रणाली के सभी क्षेत्रों में लिंग आधारित समानता सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है और महिला अधिकारियों को चुनौतियां स्वीकारने और प्रतिष्ठापूर्ण कार्यों को करने का समान अवसर प्रदान करता है । महिला अधिकारी मुख्यालयों में और विदेश स्थित मिशनों/पदों में प्रमुख पदों पर हैं ।

इण्डिया कौंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स

द इंडियन कौंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स (आई सी सी आर), जिसकी स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी, भारतीय विदेश नीति को उद्देश्यों और अधिदेश को पूरा करने के लिए विदेश मंत्रालय के स्वायत सांस्कृतिक विंग के रूप में कार्य कर रही है । आई सी सी आर की "कल्चरल डिप्लोमेसी" राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । आई सी सी आर के क्रियाकलाप अन्य देशों के लोगों को भारत और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी देने का काम भी करते हैं । आई सी सी आर और भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों और विदेश स्थित भारतीय अध्ययनों के अध्यक्षों द्वारा किए गए क्रियाकलापों, विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं, प्रकाशनों आदि के जरिए अपने उद्देश्यों को पूरा करती है । भारत के विभिन्न राज्यों में इस परिषद् की नो क्षेत्रीय शाखाएं हैं ।

इंडियन कौंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स (आई सी डब्ल्यू ए)

इंडियन कौसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एक्ट, 2001 के उद्देश्यों के अनुरूप, आई सी डब्ल्यू ए ने विश्व के प्रमुख मामलों पर विशेष भाषण, सेमिनार और बैठकें आयोजित करते हुए अपने विभिन्न क्रियाकलापों को जारी रखा । वर्ष के दौरान सप्रू हाऊस में विशेष संबोधन करने वाले उच्च पदाधिकारियों में सम्माननीय डा0 मि0 जार्ज हैनी, चीली के राजदूत ; सम्माननीय हॉहेंगोल्लेर्न-वेटीगेन, रोमानिया के राजकुमार राधू ; सम्माननीय मि0 यसाकूनी इनोकी ; जापान के राजदूत और सम्माननीय मि0 हियो रिक्टर ; जर्मनी संघ राज्य के राजदूत शामिल थे । विदेश मंत्री श्री के0 नटवर सिंह ने "पंचशील" के पचास वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया, जिसमें अनेक विदेशी उच्चाधिकारियों ने हिस्सा लिया था । राव इंदरजीत सिंह, विदेश राज्य मंत्री ने "इमर्जिंग ट्रेन्ड्स इन इंडो-अफ्रीकन रिलेशन्स" पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया । श्री ई. अहमद, विदेश राज्य मंत्री ने इराक में सुरक्षा और राजनैतिक स्थिति पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया । विदेश सचिव, श्री शशांक ने 2 जून 2004 को तृतीय अफ्रीकी दिवस पर भाषण दिया था । धमकियों, चुनौतियों तथा परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उच्चस्तरीय पैनल की रिपोर्ट पर विदेश सचिव, श्री श्याम सरन के साथ 30 दिसम्बर 2004 को, एक पैनल चर्चा हुई थी ।

गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आर आई एस)

आर आई एस मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एक स्वायत्तशासी नीतिगत थिंकटैंक की तरह है । वर्ष 2004-05 के दौरान, आई आई सी ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत अनुसंधान करवाया और प्रमुख शिखर सम्मेलनों और अन्य महत्वपूर्ण वात्ताओं की तैयारी में विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की । आर आई एस ने आशियान-भारत शिखर सम्मेलन, बिम्सटेक मंत्रालीय बैठक, शार्क मंत्रालीय बैठक यू एन सी टी ए डी न्त चल रही डब्ल्यू टी ओ वार्त्ता और चीन, दक्षिण कोरिया के साथ विस्तृत आर्थिक वार्त्ता संबंधी द्विपक्षीय संयुक्त अध्ययन समूहों और एफ टी ए वात्ताओं में अपना समर्थन दिया । इसने एशिया में अग्रणी नीतिगत थिंकटैंकों के साथ मिलकर एशियाई आर्थिक समुदाय की प्रासंगिकता एवं इससे आगे का मार्ग तलाश करने के संबंध में एक नीतिगत वार्त्ता की और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास सहयोग के संबंध में नीतिगत संगति लाने और क्षमता निर्माण के लिए अन्य देशों में नीति थिंक-टैंकों के साथ मिलकर नेटवर्क बनाया है ।

■■

भारत के पड़ोसी देश

1

भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी है । इसने बंगलादेश, मालदीव और श्रीलंका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं । इन सभी देशों के साथ सांस्थानिक तंत्रों पर पुनः बल दिया है और आपसी लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है । उच्चस्तरीय आदान-प्रदान मित्रता को उजागर करते हैं और एक-दूसरे के हित की समझ-बूझ को बढ़ाते हैं तथा साझे लक्ष्यों को गहन बनाया गया । श्रीलंका और मालदीव के मामले में एक उल्लेखनीय घटना 26 दिसम्बर, 2004 की दुखद सुनामी तबाही के बाद आपदा सहायता के उनके अनुरोधों का तुरन्त जबाव देना था। हालांकि भारत स्वयं भी सुनामी द्वारा हुए विनाश से निपटने के लिए दबाव में था फिर भी हमने अविलम्ब कार्रवाई की । भारत ने 26 तारीख को ही तत्काल श्रीलंका तथा मालदीव को हवाई जहाज एवं समुद्री मार्ग से राहत सामग्री, चिकित्सा दल और सहायता भेजी जिससे पीड़ितों को मदद देने में सहायता मिली । भारतीय दल तब से चिकित्सा सहायता, खाद्य, पानी, कपड़े मुहैया करने, महामारी के फैलने को रोकने एवं विस्थापितों की पुनर्वास परियोजनाओं में मदद करके राहत कार्यों में लगा हुआ है । इन देशों ने तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से भारत की सहायता की व्यापक तौर पर सराहना की गई है ।

ज्भारत अपने सभी पड़ोसी देशों में कई परियोजनाओं को विकास सहायता देता रहा है जो सूचना प्रौद्योगिकी,मानव संसाधन विकास, अवसंरचनात्मक इंजीनियरी (सड़कों तथा जलमार्गों), रेलवे आदि में उसकी विशेषज्ञता का परिचायक है । अपने पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदान-प्रदान बढ़े और भारत उच्चतर अध्ययन एवं प्रशिक्षण के लिए बंग्लादेश, मालदीव तथा श्रीलंका के बड़ी संख्या में छात्रों की मेजबानी करता रहा है ।

अफगानिस्तान

भारत और अफगानिस्तान के बीच दीर्घावधिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक घनिष्ठ संबंध हैं । दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों ने प्रगाढ़ता और सहयोग के नए स्तर को प्राप्त किया है । दोनों देशों के बीच नियमित राजनीतिक अन्योन्याक्रियाएं हुई । भारत अफगानिस्तान के पुनर्वास और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के लिए अपनी आर्थिक तथा वित्तीय सहायता देता रहा और उसे मजबूती प्रदान करता रहा है ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के सिलसिले में प्रधानमंत्री की न्यूयार्क की यात्रा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति करजई से 21 सितम्बर 2004 को मुलाकात की । मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भारत की सहायता तथा अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव सहित द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की । प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की भारत की वचनबद्धता पर जोर दिया तथा अफगानिस्तान में आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रयासों में भारत द्वारा सहायता देने पर बल दिया । अफगानिस्तान के आर्थिक पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए भारत के योगदान पर आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति करजई ने प्रत्येक क्षेत्र में भारत का सहयोग जारी रखने की मांग की जिसमें राज्य की संस्थाओं का पुर्निर्माण भी शामिल है।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री डा0 अब्दुल्ला अब्दुल्ला 31 अगस्त से 3 सितम्बर 2004 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए । हमारे विदेश मंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के अलावा डा0 अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की । इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के राजनय संस्थान के बीच आपसी सहयोग से सम्बद्ध एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए । इस समझौता-ज्ञापन के तहत विदेश मंत्रालय का विदेश सेवा संस्थान अफगानिस्तान के राजनय संस्थान को मदद देगा ।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 19 अक्तूबर 2004 को काबुल की यात्रा पर गए । उन्होंने राष्ट्रपति करजई, उप-राष्ट्रपति तथा रक्षा मंत्री मार्शल फाहिम और विदेश मंत्री डा0 अब्दुल्ला से भेंट की । इससे पहले नई सरकार के साथ सम्पर्क साधने के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डा0 जाल्मी रसूल 30 मई 2004 को दिल्ली की यात्रा पर आए । उन्होंने विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भेंट की ।

भारत अफगानिस्तान के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए उसके कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए अपनी सहायता को जारी रखे हुए हैं । भारत की मौजूदा वचनबद्धताएं 2002-2008 की अवधि के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर की हो गई है जो एक गैर-पारम्परिक दाता के लिए पर्याप्त राशि है । वचनबद्धता का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

- भारत ने जनवरी, 2002 में टोक्यो दाता सम्मेलन में अफगानिस्तान के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की थी । इस सहायता में से 88.11 मिलियन अमरीकी डालर आज की तारीख तक विभिन्न परियोजनाओं में परिचालन में आ गई है/ वचनबद्ध हो गई है ।

- भारत ने अफगानिस्तान को एक मिलियन टन गेहूं (100 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य) की खाद्य सहायता की घोषणा की है । इस सहायता के एक भाग को अफगानिस्तान में स्कूली भोजन कार्यक्रम के लिए उच्च प्रोटीनयुक्त बिस्कुट में परिवर्तित किया जा रहा है और इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से भेजा जाएगा । 85517 मैट्रिक टन गेहूं की तुलना में 9526 टन बिस्कुटों की पहली खेप नवम्बर, 2002 से जून, 2003 तक अफगानिस्तान को भेज दी गई है । 76521 मैट्रिक टन गेहूं की तुलना में 7496 टन बिस्कुटों की दूसरी खेप की डिलिवरी दिसम्बर, 2003 से अगस्त, 2004 तक की गई । 1,28,856 मैट्रिक टन गेहूं की तुलना में 18000 टन बिस्कुटों की तीसरी खेप की डिलिवरी नवम्बर, 2004 से शुरू हुई । इस कार्यक्रम के फलस्वरूप, लगभग एक मिलियन अफगानी स्कूली बच्चे प्रतिदिन 100 ग्राम बिस्कुट का पैकेज प्राप्त कर रहे हैं ।
- सरकार ने अफगानिस्तान में जारंग से देलाराम तक सड़क के उन्नयन/पुनर्निर्माण के लिए 377.47 करोड़ रूपए (लगभग 84 मिलियन अमरीकी डालर) अनुमोदित किए। इस परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है ।
- मंत्रिमंडल ने अफगानिस्तान के हेरात प्रान्त में 351.87 करोड़ रूपए (जुलाई, 2004 की विनिमय दर पर लगभग 76.7 मिलियन अमरीकी डालर) की अनुमानित लागत से सल्मा बांध विद्युत परियोजना के पुनर्निर्माण और उसे पूरा करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
- भारत सरकार ने अफगानिस्तान के नए संसद भवन के निर्माण की वित्त-व्यवस्था करने की पेशकश की है ।
- भारत विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित अफगानिस्तान के पुर्ननिर्माण न्यास निधि में 200,000 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष अंशदान कर रहा है ।

2004-05 की अवधि के दौरान प्रचालन की गई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नलिखित हैं-

i) 377.47 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से जारंग-देलाराम सड़क (218 किलोमीटर) का पुनर्निर्माण/उन्नयन। सीमा सड़क संगठन द्वारा इस परियोजना का निष्पादन किया जाएगा । अफगानिस्तान में अवसंरचनात्मक पुनर्निर्माण में सहायता करने की हमारी वचनबद्धता के द्योतक के अलावा इस परियोजना से उस पारगमन समस्या का समाधान भी निकल आएगा जिसे भारतीय निर्यातक अफगानिस्तान को सामान भेजते समय महसूस करते हैं ।

ii) 351.87 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से अफगानिस्तान के हेरात प्रान्त में सल्मा बांध विद्युत परियोजना का पुनर्निर्माण और उसे पूरा करना । इस परियोजना में 52 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता से विद्युत उत्पादन के लिए पानी के बहाव हेतु 107.5 मीटर ऊंचा अर्थ तथा रोक फिल बांध का निर्माण शामिल है ।

iii) 1 मिलियन टन गेहूं की खाद्य सहायता के तहत 1,28,856 मैट्रिक टन गेहूं की तुलना मं 18,000 टन बिस्कुटों की तीसरी खेप की डिलिवरी नवम्बर 2004 से शुरू हो गई है ।

iv) काबुल, मजार-ए-शरीफ, शिबेरगन, हेरात तथा कान्धार स्थित भारतीय चिकित्सा मिशनों को लगभग 69 टन चिकित्सा स्टोर की आपूर्ति की गई है ।

v) पुनर्वास तथा इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की गई ।

vi) 19 मई 2004 से 18 अगस्त 2004 तक तीन महीने की अवधि के लिए अफगानिस्तान के 8 अर्द्ध-चिकित्सकों को इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में प्रशिक्षण दिया गया।

vii) इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान के दो चिकित्सकों ने 15 जुलाई 2004 से 13 अक्तूबर 2004 तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अपने-अपने विशेषज्ञता के क्षेत्रों में प्रशिक्षण में भाग लिया।

viii) अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के 20 अध्यापकों को 15 जुलाई 2004 से 6 अक्तूबर 2004 तक संस्कृति स्कूल, नई दिल्ली में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया।

ix) दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी ने अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के 20 अफगानी अध्यापकों को 5 फरवरी से 5 मई 2004 तक सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया ।

x) अफगानिस्तान में स्थापित सूचना को पुनः तैयार करने/बरकरार रखने से संबंधित परियोजनाओं के भाग के रूप में ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लि0 ने डी.टी.पी. सुविधा के साथ आधुनिक आफसेट प्रिटिंग मशीन स्थापित करने और काबुल में टी.वी. सेटेलाइट अपलिंक सुविधा तथा 10 स्टेशनों पर डाउनलिंक सुविधा स्थापित करने का कार्य पूरा किया । काबुल में एक नए 100 किलोवाट एस.डब्ल्यू. ट्रांसमीटर स्थापित करने तथा जलालाबाद एवं नांगरहार प्रान्त में टी.वी.हार्डवेयर कायम/बढ़ाने का काम चल रहा है 1

xi) अफगानिस्तान के मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम और चुनावों को आयोजित करने के लिए उत्तरदायी संयुक्त मतदान प्रबंध निकाय को राष्ट्रपति चुनावों में 50,000 अमिट स्याही वाले मार्कर पैन मुहैया कराए गए । कर्नाटक सरकार का एक उपक्रम मैसूर पेंट एण्ड वार्निस लि0 ने अमिट स्याही की आपूर्ति की जो भारत के निर्वाचन आयोग को अमिट स्याही का एकमात्र स्पलायर है ।

xi) अफगानिस्तान के मिल्ली बैंक की पुनर्स्थापना में सहायता करने के लिए पांच बैंकरों को भेजा गया ।

xii) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने कान्धार में 5000 टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है ।

xiii) काबुल नगरपालिका को मुहैया कराए गए 105 यूटिलिटी वाहनों/उपकरणों (वाटर टेंकर, रियर ड्राप टिप्पर्स, डम्प ट्रक, बुलडोजर, मोटर ग्रेडर तथा गारबेज टिप्पर्स) में से 94 वाहन/उपकरण अफगानिस्तान प्राधिकारियों को सौंप दिए गए हैं ।

दिसम्बर 2001के बॉन करार से अफगानिस्तान की घटनाओं को सकारात्मक आंका जा सकता है । राष्ट्रपति चुनावों का सफलतापूर्वक समापन अफगानिस्तान के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है । तथापि, अफगानिस्तान में शांति और स्थायीत्व की प्रक्रिया अभी कमजोर है । तालिबान, अलकायदा और हिज्ब-ए-इस्लामी तत्व बाह्य समर्थन से शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा करते रहते हैं । स्वापकों की खेती, उत्पादन तथा गैर-कानूनी व्यापार ने इसमें और बढ़ोतरी कर दी है जो अफगानिस्तान के राजनीतिक तथा आर्थिक पुर्निर्माण को कमजोर बना सकती हैं और इस क्षेत्र तथा इसके बाहर इसके पर्याप्त खतरनाक प्रभाव हैं ।

बंगलादेश

बंगलादेश के साथ भारत के बहुत ही घनिष्ठ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संबंध है । हमारे द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं को प्रशासित करने वाले सांस्थानिक तंत्रों में हाल के वर्षों में विविधता लाई गई है ।

यह वर्ष बंगलादेश से उच्चस्तरीय यात्राओं का द्योतक है । बंगलादेश के विदेश मंत्री श्री एम. मोरशेद खान बंगलादेश के प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में भारत की नयी सरकार द्वारा कार्यभार संभालने पर बधाई देने के सिलसिले में 31 मई से 4 जून 2004 तक भारत की यात्रा पर आए । इस यात्रा से सुरक्षा तथा द्विपक्षीय हित-चिन्ता के अन्य मसलों पर चर्चा करने का अवसर मिला । बंगलादेश के विदेशमंत्री बंगलादेश के प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में जनवरी,2004 में ढाका में सम्पन्न होने वाले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की 13वीं शिखर-सम्मेलन के सिलसिले में हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने के लिए भी भारत की यात्रा पर आए । दोनों पक्षों ने हाल के वर्षों में शुरू किए गए सहयोगी द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और उन्हें गति प्रदान करने की अपनी-अपनी वचनबद्धता को दोहराया ।

बंगलादेश के वाणिज्य मंत्री एअर वाइस मार्शल अल्ताफ हूसैन चौधरी भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के आमंत्रण पर 16-18 नवम्बर 2004 तक भारत की यात्रा पर आए । इस यात्रा के दौरान उन्होंने विदेशमंत्री तथा भारतीय उद्योग परिसंघ और फिक्की के साथ मुलाकात की । उन्होंने फिक्की द्वारा आयोजित सेमिनार में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के साथ संयुक्त रूप से भाषण दिया । इस यात्रा से दोनों देशों के बीच कई आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला।

बंगलादेश के वित्त मंत्री सैफुअर रहमान दिसम्बर 2004 में भारतीय उद्योग परिसंघ के आर्थिक शिखर-सम्मेलन के सिलसिले में भारत में थे । उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की और अपने समकक्ष वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम से बातचीत की ।

लगभग चार वर्षों के अंतराल के बाद ढाका में गृह-सचिव स्तर की बातचीत हुई । इस बातचीत से भू-सीमा, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन तथा कोंसली एवं वीजा से संबंधित अन्य मुद्दों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर मिला । बातचीत के दौरान बंगलादेश किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और/ अथवा बन्दरगाह से गुजरने वाले भारतीय नागरिकों को दोहरे प्रवेश तथा निकासी वीजा देने पर सहमत हुआ ।

दोनों देशों के जल संसाधन सचिवों की सह-अध्यक्षता में भारत-बंगलादेश विशेषज्ञ संयुक्त समिति की सातवीं बैठक सितम्बर 2004 को ढाका में सम्पन्न हुई । इस बैठक में तिस्ता नदी के जल के बंटवारे के लिए तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गठित संयुक्त तकनीकी दल की रिपोर्ट पर विचार किया गया ।

सीमा प्रबंधन से सम्बद्ध मुख्य मसलों पर संस्थागत वार्ता सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राइफल्स के बीच द्विवार्षिक तौर पर महानिदेशक स्तर पर जारी रही । सहयोग संवर्धित करने तथा विश्वासोत्पादक उपायों को बढ़ाने के लिए कई प्रचालनात्मक और फील्ड स्तर के मुद्दों पर चर्चा हुई । सीमा पार से अपराधों को रोकने के लिए समन्वित गश्त लगाने तथा शांतिपूर्ण सीमा प्रबंधन जैसे अन्य मसलों पर भी चर्चा हुई ।

जुलाई 2003 में सम्पन्न छठी संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक के दौरान जिस प्रस्ताव की पेशकश की गई थी, उसके अनुसरण में भारत सरकार ने बंगलादेश को सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत नई दिल्ली में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के सिलसिले में 250 बंगलादेशी अध्यापकों को प्रायोजित किया । इस कार्यक्रम का आयोजन टाटा इनफोटेक द्वारा किया गया और इसमें बंगलादेश सरकार द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के लिए 6 सप्ताह का प्रशिक्षण शामिल था ।

संयुक्त आर्थिक आयोग की छठी बैठक के दौरान बंगलादेश को नए संभव ऋण देने पर भी चर्चा हुई । इस समय रेल और सड़क के क्षेत्रों में अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए बंगलादेश को 150 मिलियन अमरीकी डालर के प्रस्तावित एक्जिम बैंक के ऋण की शर्तों एवं निबंधनों तथा तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए बातचीत चल रही है ।

इस वर्ष बंगलादेश में भंयकर बाढ़ आने के बाद भारत सरकार ने बंगलादेश को 100 करोड़ रूपए की बाढ़ राहत सहायता की मंजूरी दी । इस राशि का उपयोग बंगलादेश की सरकार द्वारा भारत से खाद्य अनाज, चिकित्सा आपूर्तियों एवं भवन निर्माण सामग्रियों की खरीद पर किया जा सकता है । इस

राशि का उपयोग करने के तौर-तरीकों का उल्लेख करते हुए दोनों देशों के बीच एक समझौता-ज्ञापन सम्पन्न किया जाना है।

भूटान

एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी के नाते भूटान के साथ भारत के संबंधों की विशेषता आपसी समझ-बूझ, विश्वास, आस्था और दोनों देशों के लोगों के परस्पर लाभ के विविध क्षेत्रों में बहुफलकीय सहयोग की रही है ।

इन संबंधों को नियमित यात्राओं के आदान-प्रदान से मजबूत किया गया और उसमें बढ़ोतरी की गई जिसमें दोनों देशों के बीच नियमित यात्रायों सहित उच्चतम स्तर की स्तर की यात्राएं शामिल हैं । वर्ष 2004 के दौरान महामहिम भूटान नरेश जिग्मे सिंग्वे वांगचुक गणतंत्र दिवस समारोह 2005 में मुख्य अतिथि थे। इस यात्रा के दौरान तीन समझौता-ज्ञापन सम्पन्न हुए। ये (i) भारत तथा भूटान के सीमावर्ती कस्बों के बीच रेलवे सम्पर्क स्थापित करने के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने, (ii) भूटान में दो जल-विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और (iii) कृषि तथा अनुषंगी क्षेत्रों में सहयोग करने से संबंधित हैं। भूटान नरेश के साथ शिष्टमंडल में युवराज तथा भूटान के विदेश मंत्री शामिल थे। इससे पहले भूटान नेरश 24 - 29 नवम्बर 2004 तक भारत की यात्रा पर आए। भूटान की चार साम्राज्ञियों में सबसे छोटी साम्राज्ञी महामान्या अशी संङ्ग्रेय कोदेन वांगचुक भी 6-21 फरवरी 2005 तक भारत की यात्रा पर आयीं।

इस वर्ष भूटान से जो अन्य विशिष्ट व्यक्ति भारत की यात्रा पर आए उनमें विदेश मंत्री ल्योन्पो खांडु वांगचुक, कृषि मंत्री ल्योन्पो संग्ये जेडुप तथा राष्ट्रीय असेम्बली के अध्यक्ष दाशो यूगेन दोरजी शामिल हैं । महामहिम भूटान नरेश जनवरी 2005 में भारत से विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह, पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्री एन.एन.मीणा तथा विदेश राज्य मंत्री श्री राव इन्दरजीत सिंह अक्तूबर 2004 में भूटान की यात्रा पर गए।

भूटान के साथ विकास सहयोग विशेषकर जल-विद्युत क्षेत्र में सहयोग सन्तोषजनक रूप से चलता रहा । 1020 मेगावाट की ताला परियोजना का निर्माण ठीक तरह से प्रगति कर रहा है । पुनतसांगयू चरण-। से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 2006 की पहली तिमाही में पूर्ण होने की आशा है और दो और परियोजनाओं (पुनतसांगचू चरण-।। तथा मंगडेगचू परियोजनाओं) से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र आरंभ की जाएगीं।

जनवरी 2005 में भूटान नेरश की यात्रा के दौरान भूटान की नौंवी योजना के लिए भारत सरकार के सहायता पैकेज की भी समीक्षा की गई तथा विकास राज सहायता के रूप में 280 करोड़ रू. के अतिरिक्त राशि दी गई।

इस वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में (i) परियोजना कार्यान्वयन तंत्र से सम्बद्ध एक समझौता-ज्ञापन सम्पन्न करना है। इस समझौता-ज्ञापन से भूटान में भारत सरकार की सहायता से चल रही परियोजनाओं की निगरानी कारगर होगी और परियोजनाओं को निधियां रिलीज करने के लिए क्रियाविधि सरल होगी । (ii) कुरिचू परियोजना के लिए दिए गए भारत सरकार के ऋण की अदायगी के संबंध में एक प्रोतोकोल सम्पन्न हुआ। 560 करोड़ रूपए की लागत से बने इस परियोजना में 40 प्रतिशत ऋण घटक है, जिसे भूटान की शाही सरकार द्वारा अब पुर्नभुगतान किया जा रहा है।

दोनों देशों में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए अगस्त 2004 में बाढ़ प्रबंधन से एक संयुक्त विशेषज्ञ दल का गठन किया गया । यह दल बार-बार बाढ़ आने के संभावित कारणों और उसके प्रभावों एवं भूटान के दक्षिण पहाड़ी भूभाग तथा भारत के सटे हुए मैदानों में भूमि-कटावों का जायजा लेगा । इस दल की दो बैठकें हो चुकी हैं।

भूटान ने सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषकर दिसम्बर 2003 से जनवरी 2004 की अवधि में उन भारतीय विद्रोही ग्रुपों जिन्होंने भूटान में शिविर स्थापित कर दिए थे, के विरूद्ध भूटान की शाही सेना द्वारा सफल सैन्य कार्रवाई के परिणामस्वरूप अपना सहयोग सुदृढ़ किया है । मार्च 2004 में गठित सीमा सुरक्षा तथा प्रबंधन से सम्बद्ध भारत-भूटान दल ने प्रशिक्षण, दोनों देशों के सुरक्षा तथा प्रशासनिक प्राधिकारियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान एवं बेहतर सीमावर्ती समन्वय के संबंध में कई व्यवहारिक सिफारिशें की जिनका कार्यान्वयन हो रहा है ।

चीन

भारत पंचशील के सिद्धांतों, परस्पर सम्मान तथा एक-दूसरे की हित-चिंता एवं समानता की संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ दीर्घावधिक रचनात्मक और सहयोगी भागीदारी विकसित करने के लिए वचनबद्ध है । भारत और चीन के बीच सहयोग न केवल अपने-अपने सामाजिक आर्थिक विकास तथा समृद्धि के लिए प्रेरक है बल्कि यह विश्व में बहु-ध्रुवीकरण को सुदृढ़ करने एवं वैश्विकरण के सकारात्मक कारकों को संवर्धित करने के लिए भी प्रेरक है ।

इस वर्ष के दौरान निरन्तरता तथा मजबूती भारत-चीन संबंधों का द्योतक है । उच्चस्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान तथा चर्चाओं से सहयोग के नए क्षेत्रों में विविधता लाने की दिशा में निरन्तरता आयी । इस अवधि में कार्यात्मक स्तरों पर गहन आदान-प्रदान देखा गया ।

प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 10वें आसियान शिखर-सम्मेलन के दौरान नवम्बर 2004 में वियन्ताने, लाओस में प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से मुलाकात की । दोनों नेताओं ने यह नोट किया कि भारत चीन संबंध अच्छी गति से चल रहे हैं और उनकी संबंधों के स्वरूप तथा दिशा के संबंध में विविध चर्चाएं हुई । उन्होंने आर्थिक तथा व्यापार संबंधों का और विस्तार करने के महत्व का जिक्र किया । दोनों नेताओं ने सीमा के प्रश्न पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चाओं की भी समीक्षा की । उम्मीद है कि प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ मार्च 2005 में भारत की यात्रा पर आएं ।

राजपथ, नई दिल्ली में 26 जनवरी 2005 को गणतंत्र दिवस समारोह।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा भूटान नरेश, महासचिव जिग्मे सिंघे वांगचुक के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज। महामहिम भूटान नरेश गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2005 में मुख्य अतिथी थे। चित्र में उनके दाईं ओर प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और उनके बाईं ओर भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी।

विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह ने चार अवसरों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान चीनी विदेश मंत्री लि झाओयांग से मुलाकात की । इन मुलाकातों में उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चाएं की ।

चीन से कई उच्चस्तरीय विशिष्ट व्यक्ति भारत की यात्रा पर आए जिनमें पोलिटविरो के सदस्य ही योगेंग तथा ली क्यू एवं राज्य काउंसलर यांग जियांग और चेन जिनी शामिल हैं । भारतीय पक्ष की ओर से उच्चस्तरीय यात्राओं में पूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर.नारायणन, श्रम मंत्री श्री शीश राम ओला, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्व. श्री जे.एन.दीक्षित एवं थल सेना अध्यक्ष जनरल एन.सी.विज शामिल हैं ।

चीन के राज्य काउंसलर यांग जियांग की अक्तूबर 2004 में भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री के साथ सारगर्भित चर्चा की और प्रधानमंत्री से मुलाकात की । भारत और चीन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की दीर्घावधिक एवं नीतिगत संदर्श, मौजूदा संबंधों की स्थिति द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाने और उसकी गति के बनाए रखने की पुनः पुष्टि की । वे सीमा के प्रश्न सहित सभी अनसुलझे मसलों के समाधान के लिए निष्पक्ष, युक्तिसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान ढूंढने के साथ-साथ और अधिक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने एवं उन्हें विकसित करने पर सहमत हुए । इस यात्रा के दौरान राज्य काउंसलर यांग ने यह बताया कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत द्वारा और अधिक भूमिका निभाने का समर्थन करता है ।

भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि जिन्हें समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से सीमा के समाधान की रूपरेखा की खोज-बीन करने कार्य दिया गया, ने दो दौर की चर्चाएं अर्थात जुलाई 2004 में नई दिल्ली में और नवम्बर 2004 को बीजिंग में की । उनकी बातचीत स्पष्ट, रचनात्मक तथा व्यापक रही ।

इस वर्ष के दौरान उल्लेखनीय समारोह पंचशील की 50वीं वर्षगांठ थी । इस अवसर पर नई दिल्ली और बीजिंग दोनों में कई समारोह हुए । चीनी पीपुल्स इंस्टीच्यूट आफ फारेन अफेयर्स ने जून 2004 में बीजिंग में स्मरणोत्सव मनाया जिसमें पूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर.नारायणन प्रमुख वक्त थे । दोनों पक्षों ने इस समारोह के अवसर पर विशेष डाक कवर जारी किए । उसके बाद नवम्बर 2004 में इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स ने नई दिल्ली में एक पंचशील सेमिनार का आयोजन किया जिसमें विदेश मंत्री श्री के.नटवर सिंह ने वक्तव्य दिया और इस अवसर पर एक स्मरणोत्सव खण्ड रिलीज किया गया ।

चीनी राज्य काउंसलर चेन जिली जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं संस्कृति की प्रभारी हैं, की यात्रा के दौरान उन्होंने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं समुद्री विकास राज्य मंत्री श्री कपिल सिब्बल से चर्चा की । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-चीन सहयोग के लिए समग्र दिशा-निदेश देने के लिए मंत्रियों के स्तर पर एक संचालन समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया । शिक्षा मंत्री झू जी जो इस शिष्टमंडल के एक भाग थे, ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया । इस अवधि के दौरान मौजूदा करारों के अंतर्गत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच निरन्तर आदान-प्रदान बना रहा ।

इस वर्ष के दौरान हुए अन्य आदान-प्रदानों में अक्तूबर 2004 में चीन के जिनजियांग प्रान्त के अध्यक्ष एवं हेनन प्रान्त के गर्वनर की अगस्त-सितम्बर, 2004 की यात्राएं शामिल हैं । दोनों यात्राएं विशिष्ट व्यक्तियों के यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत हुई जिसमें महत्वपूर्ण निर्णयकर्ताओं/मत निर्माताओं को भारत आमंत्रित किया गया । इन यात्राओं के दौरान आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटन एवं सांस्कृतिक संबंधों को गहन बनाने पर चर्चा हुई । चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी (सी.पी.सी. का अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क विभाग) और भारत के मुख्य मंत्रियों के बीच आदान-प्रदान के कार्यक्रम के भाग के रूप में पोलितविरो सदस्य ली क्यी दिल्ली की मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर नवम्बर 2004 में भारत की यात्रा पर आए । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की जनवरी - फरवरी 2005 में चीन की यात्रा पर जाने की संभावना है । एशियाई राजनीतिक दलों के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसकी मेजबानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सितम्बर 2004 में की, में छह भारतीय राजनीतिक दलों ने प्रतिनिधित्व किया । भारत और चीनी संगठनों जैसे इंडियन इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन और सेंट्रल पार्टी स्कूल, आई.सी.एस.एस.आर. एवं जियांग प्रोविंसियल एकेडेमी आफ सोसियल साइन्स तथा योजना आयोग एवं नेशनल डिवलपमेंट एण्ड रिफार्म कमशीन के बीच जोड़े बनाकर कार्यात्मक आदान-प्रदान और वार्ता शुरू करायी गई । यात्राओं के इन आदान-प्रदानों से न केवल संबंधों को व्यापक आधार मिलता है बल्कि ये नीतियों, चुनौतियों एवं विकास अनुभवों सहित अन्य मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए मंच भी प्रदान करती हैं ।

उपर्युक्त आदान-प्रदानों के अलावा, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता तंत्र ने मौजूदा पहकदमियों को संवर्धित करने और उनका क्रियान्वयन करने तथा नयी पहलकदमी की तलाश करने को सुविधाजनक बनाने के सुव्यवस्थित उपायों को प्रदान करना जारी रखा । सीमा के प्रश्न से सम्बद्ध विशेष प्रतिनिधियों की बैठकों के अलावा वर्ष के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच परामर्श एवं नीति आयोजना वार्ता के दूसरे दौर के परामर्श हुए । विदेश सचिव श्री श्याम सरन और चीन के उप विदेश मंत्री व्यू दावी के स्तर पर सामरिक वार्ता का पहला दौर 24 जनवरी,2005 को सम्पन्न हुआ । इस वार्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ सार्वभौम राजनैतिक एवं नीतिगत महत्व के मसलों पर ध्यान केन्द्रित किया ।

इस वर्ष भारत-चीन व्यापार में निरन्तर वृद्धि देखी गई । 1992 में 338 मिलियन अमरीकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा बढ़कर 2003 में 7.6 बिलियन अमरीकी डालर तक हो गई है । जनवरी - नवम्बर 2004 की अवधि में चीन के आंकड़ों

के अनुसार व्यापार की मात्रा 12.2 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गयी जिसमें 2003 की इसी अवधि की तुलना में 82.5% की बढ़ोतरी हुई है । इस अवधि में भारत द्वारा चीन को 6.9 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया गया (87.2 % की वर्ष-दर-वर्ष की बढ़ोतरी) जबकि चीन से भारत को 5.2 बिलियन अमरीकी डालर (76.6 % की वर्ष-दर-वर्ष की बढ़ोतरी) का आयात हुआ । भारत से चीन को हुई निर्यात की मुख्य मदें आयरन अयस्क, लोहा तथा इस्पात, प्लास्टिक, रत्न (अधिकांशतः हीरे), कपास यार्न एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन हैं। चीन से भारत को आयातित मुख्य मदों में विद्युत तथा अन्य मशीनरी, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, खनिज ईंधन, सिल्क यार्न, मनुष्य द्वारा तैयार केसर आदि हैं । भारत द्वारा चीन को हुए निर्यात में इस वर्ष तीव्र बढ़ोतरी देखी गई जिनमें लौह अयस्क, काटन यार्न, अकार्बनिक रसायन तथा मशीनरी उत्पाद शामिल हैं ।

इस वर्ष के दौरान आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को और संवर्धित करने एवं सुदृढ़ करने के प्रयास किए गए । प्रोत्साहन क्रियाकलाप शुरू किए गए । भारत के राजदूतावास के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए दिसम्बर, 2004 में बीजिंग में अपना दूसरा "मेड इन इंडिया " शो आयोजित किया । भारतीय आमों तथा चाय को संवर्धित करने के लिए उत्सव आयोजित किए गए । इसी प्रकार नवम्बर 2004 में सम्पन्न भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में चीन एक भागीदार देश था जिसमें 80 से अधिक चीनी कंपनियों ने भाग लिया । इस वर्ष के दौरान व्यापार तथा व्यवसाय शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान की गति निरन्तर बढ़ती गई ।

भारत-चीन संयुक्त अध्ययन दल जिसे दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापारिक तथा आर्थिक सहयोग के विकास की संभावित सम्पूरकताओं की जांच करने और उसके लिए एक कार्यक्रम तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, अपना कार्य करना जारी रखा एवं इस वर्ष के दौरान संयुक्त अध्ययन दल की तीन बैठकें हो चुकी हैं । दोनों देशों की सरकारों के लिए सिफारिशें देते हुए संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट मार्च, 2005 में पूरी हो जाने की संभावना है ।

थल सेनाध्यक्ष की 22-29 दिसम्बर 2004 तक चीन की यात्रा से द्विपक्षीय रक्षा आदान-प्रदानों की गति को बनाए रखा गया । दस वर्ष के बाद किसी भारतीय थल सेनाध्यक्ष की चीन की यह यात्रा थी । थल सेनाध्यक्ष ने चीन के उप राष्ट्रपति जेंग कियांग और रक्षा मंत्री जनरल काओ गुंगचुन से मुलाकात की तथा पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी से व्यापक अन्योन्यक्रिया की । दोनों पक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन कायम हो रहा है । सैन्य आदान-प्रदानों तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक संवर्धित करने पर भी सर्वसम्मति हुई । गैर-पारम्परिक खतरों विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद के विरूद्ध सहयोग पर भी चर्चा हुई । पी.एल.ए. के जनरल स्टाफ के प्रमुख ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए थल सेनाध्यक्ष का भारत की यात्रा का आमंत्रण स्वीकार किया । द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के भाग के रूप में भारत और चीन के बीच सैन्य सम्पर्कों का विस्तार थलसेनाध्यक्ष की यात्रा एक महत्वपूर्ण घटक है ।

विश्वासोत्पादक उपयों के भाग के रूप में चीनी पक्ष में संयुक्त पर्वतारोहण अभियान और भारतीय पक्ष में खेलकूद कार्यक्रमों सहित दोनों देशों के सीमा कार्मिकों के बीच अन्योन्यक्रियाएं आयोजित की गई । राष्ट्रीय दिवसों तथा महत्वपूर्ण समारोहों के दौरान सहित सीमा कार्मिकों की बैठकें तथा फ्लैग बैठकें जो विश्वासोत्पादक उपायों का एक महत्वपूर्ण भाग हैं , आयोजित की गई । एक वायु सेना प्रशिक्षण शिष्टमंडल मार्च-अप्रैल 2004 में चीन की यात्रा पर गया और अन्य भारतीय शिष्टमंडल सितम्बर 2004 में पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी के मुक्केबाजी के अभ्यास को देखने के लिए चीन की यात्रा पर गया । चीनी पक्ष की ओर से सैन्य विज्ञान अकादमी एवं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के शिष्टमंडल भारत की यात्रा पर आए । जिनजियांग सैन्य कमान्डर के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जनवरी के अंत में तथा फरवरी 2005 के शुरू में भारत की यात्रा पर आएगा ।

चीनी पक्ष ने राजनयिक माध्यमों तथा सीमा फ्लैग बैठकों के जरिए भू-स्खलनों के परिणामस्वरूप चीन के तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में पारेचू नदी पर बनी झील के बारे में डाटा और सूचना मुहैया की, जिससे हिमाचल प्रदेश के तलहटी वाले क्षेत्रों को खतरा हो गया है । अगले बरसात के मौसम से पहले ब्लाकेज के कन्ट्रोल्ड रिमूवल के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए सितम्बर तथा दिसम्बर 2004 में क्रमशः लासा और बीजिंग में तकनीकी स्तर की दो दौर की बातचीत हुई । चीन के तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में संभावित आपदा की स्थिति के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान हेतु तंत्र का भारत में न्यूनतम प्रभाव होने की संभावना है तथा कुछ साझी नदियों के जल विज्ञान संबंधी डाटे की साझेदारी पर भी चर्चा हुई ।

इस वर्ष के दौरान कार्यकारी कार्यक्रम 2003-2005 (भारत - चीन सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का) के तहत सांस्कृतिक आदान-प्रदान जारी रहे । पंचशील की 50वीं वर्षगांठ के लिए स्मरणोत्सव क्रियाकलापों के भाग के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा भारतीय और चीनी डाक टिकटों की एक संयुक्त प्रदर्शनी आयोजित की गई । जून, 2003 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय शिक्षा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत और चीन के बीच छात्रों का आदान-प्रदान जारी रहा । इस समय द्विपक्षीय शिक्षा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत 22 भारतीय शिक्षाविद चीन में हैं तथा 21 चीनी शिक्षाविद भारत में हैं । जून 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी की चीन की यात्रा के दौरान बीजिंग विश्वविद्यालय के भारतीय अध्ययन केन्द्र का उद्घाटन किया गया, इस केन्द्र ने चीन के अन्य विश्वविद्यालयों के सहयोग से अपने परिसर में शैक्षिक सेमिनारों के आयोजन सहित अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया । तान युनशान जिसे इस केन्द्र का अंतिम वर्ष का श्रेष्ठ हिंदी छात्र का पहला अवार्ड

दिया गया, नवम्बर, 2004 में भारत की यात्रा पर आया । प्रत्येक देश में दूसरे देश के सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के तौर-तरीकों पर चर्चा जारी रहीं ।

वर्ष 2004 के दौरान बीजिंग स्थित भारत के राजदूतावास ने 15359 वीजा जारी किए जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रतीक है । संघाई स्थित प्रधान कोंसलावास ने 2004 में कुल 7785 वीजा जारी किए जो पिछले वर्ष की तुलना में 110% की वृद्धि का प्रतीक है ।

कार्यात्मक आदान-प्रदान

- जल संसाधन में सहयोग तथा कृत्रिम झील बनने के फलस्वरूप तथा पारेचू नदी पर भू-स्खलन के फलस्वरूप हुई समस्या के समाधान में सहयोग करने के लिए केन्द्रीय आपदा आयोग के संयुक्त सचिव श्री आर.के.सिंह तथा गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विपदा प्रबंधन) श्री एस.के.चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडलों ने सितम्बर और दिसम्बर 2004 को क्रमशः तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र एवं बीजिंग की यात्रा की ।
- पीपुल्स आर्मड पुलिस के साथ अन्योन्यक्रिया के सिलसिले में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पुलिस) श्री ए.के.जैन के नेतृत्व में एक पांच-सदस्यीय शिष्टमंडल अगस्त 2004 में चीन की यात्रा पर गया । पी.ए.पी. का एक अन्य शिष्टमंडल का सी.पी.ए.पी.एफ. के उप सेनाध्यक्ष मेज़. जनरल वांग जियापिंग के नेतृत्व में जनवरी,2005 में भारत की यात्रा पर आने का कार्यक्रम है । चर्चाओं में प्रशिक्षण तथा आंतकवाद को रोकने में सहयोग करने का पता लगाना शामिल है ।
- भारत की कृषि अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए सी.पी.सी. के सेंट्रल पार्टी स्कूल का शिष्टमंडल प्रो0 पी. जिंगयान के नेतृत्व में अक्तूबर 2004 में भारत की यात्रा पर आया। इस शिष्टमंडल ने अन्य बातों के साथ-साथ इंडियन स्कूल आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अन्योन्यक्रिया की ।
- आई.आई.पी.ए. का एक शिष्टमंडल जिसमें उन्नत व्यवसायिक कार्यक्रम के 53 सदस्य शामिल थे, दिसम्बर, 2004 में चीन की यात्रा पर गया तथा उसने विकास, प्रशासनिक सुधार, शासन एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान किया ।
- उप-मंत्री जोह केरेन के नेतृत्व में एक सात सदस्यीय शिष्टमंडल तथा चीन लोक राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन की विदेशी मामलों से सम्बद्ध समिति के सदस्य 4-11 जनवरी,2005 तक भारत की यात्रा पर आए ।
- राष्ट्रीय विकास तथा सुधार आयोग के उपाध्यक्ष झांग जियांगक्यांग के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल नई दिल्ली में हमारे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित "क्षेत्रीय सहयोग - ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी " शीर्षक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4-10 जनवरी, 2005 तक भारत की यात्रा पर आया ।
- श्रम मंत्री के वरिष्ठ सलाहकार श्री क्यू हुली के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय शिष्टमंडल 24-29 अक्तूबर, 2004 तक भारत की यात्रा पर आया । इस शिष्टमंडल ने भारत के श्रम मंत्रालय के साथ चर्चा की ।
- चीन की सांस्कृतिक विरासत के राज्य प्रशासन के महानिदेशक श्री यान जियांग चीन में पड़े पैमाने पर होने वाली भारतीय प्रदर्शनी पर चर्चा करने तथा भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण और एस.ए.सी.एच. के बीच सहयोग संवर्धित करने के सिलसिले में जुलाई-अगस्त, 2004 में भारत की यात्रा पर आए ।
- सूचना कार्यालय के राज्य परिषद के उपमंत्री श्री वांग कियांग नवम्बर 2004 में भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने श्रव्य-दृश्य तथा प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में अन्योन्यक्रिया संवर्धित करने के लिए सचिव (सूचना तथा प्रसारण) से चर्चा की ।
- उपमंत्री मेंग जिओसी जो भारत की यात्रा (अक्तूबर 2004) पर आए राज्य काउंसलर तांग जियाक्सन के शिष्टमंडल के सदस्य थे, ने सांस्कृतिक आदान-प्रदानों को और अधिक गहन बनाने के सिलसिले में सचिव(संस्कृति) के साथ चर्चा की ।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से भारत के महा सर्वेक्षक डा0 पी. नाग के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जुलाई 2004 में चीन की यात्रा पर गया और उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों, चीन विज्ञान अकादमी, चीन के राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान फाउन्डेशन तथा विदेशी विशेषज्ञ मामलों के राज्य प्रशासन के साथ मुलाकात की । विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संयुक्त कार्यदल की बैठक में 2004-06 की अवधि के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 16 परियोजनाओं पर सहमति हुई ।
- भारत के मौसम विज्ञान विभाग और चीन के मौसम विज्ञान प्रशासन की तीसरा संयुक्त कार्यदल दोनों संगठनों के बीच सम्पन्न समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत और आगे सहयोग करने पर चर्चा करने के लिए नवम्बर 2004 में नई दिल्ली में मिले तथा उन्होंने कई संयुक्त कार्यक्रमों और 2005-07 के लिए कार्य योजना का सुझाव दिया ।
- जेनोमी सूचना-विज्ञान से सम्बद्ध भारत-चीन सेमिनार सी.एस.आई.आर. के इंस्टीच्यूट आफ जेनोमिक्स एण्ड इन्टीग्रेटिव बायलोजी तथा बीजिंग जेनोमिक्स इंस्टीच्यूट द्वारा अक्तूबर - नवम्बर 2004 में हांग झू में आयोजित किया गया । बीजिंग में अगस्त 2004 में सहयोग से सम्बद्ध एक समझौता-ज्ञापन सम्पन्न हुआ।

हांगकांग

इस अवधि में भारत-हांगकांग द्विपक्षीय व्यापार में विस्तार देखा गया । एच.के.एस.ए.आर. सांख्यिकियों के अनुसार 2004 में हांगकांग - भारत का द्विपक्षीय व्यापार 5.43 बिलियन अमरीकी डालर (2003 की तुलना में 20.3 % की बढ़ोतरी) पहुंच गया है जिसमें भारत का निर्यात 3.53 बिलियन अमरीकी डालर (24 % की वृद्धि) तथा हांगकांग का निर्यात 1.89 बिलियन अमरीकी डालर (14 % की वृद्धि) पहुंच गया है ।

लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के नेतृत्व में एक 14 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल 6-7 नवम्बर 2004 को हांगकांग की यात्रा पर गया और उन्होंने भारतीय समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों से मुलाकात की । सूचना और प्रसारण मंत्री श्री जयपाल रेड्डी पिराटेड वी.सी.डी./डी.वी.डी. की बिक्री पर रोक, वी.सी.डी./डी.वी.डी. की कापी करने के लिए लाइसेंस देने तथा इस संबंध में हांगकांग की सरकार द्वारा अधिनियमित कानूनों से संबंधित फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के मसलों पर चर्चा करने के सिलसिले में 13-14 अक्तूबर 2004 को हांगकांग की यात्रा पर गए । प्रवासी भारतीयों के मामलों के राज्य मंत्री श्री जगदीश टाइटलर प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में 27-28 सितम्बर 2004 तक हांगकांग की यात्रा पर गए ।

आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता से सम्बद्ध तीसरे दौर की बातचीत नवम्बर 2004 में सम्पन्न हुई और दोनों पक्षों ने करार के प्रारूप पर आद्याक्षर किए । नागर विमानन मंत्रालय का एक शिष्टमंडल द्विपक्षीय वायु सेवा परामर्शों के सिलसिले में जनवरी 2005 के अंत में हांगकांग की यात्रा पर जाएगा । जनवरी-दिसम्बर,2004 की अवधि के दौरान हांगकांग स्थित प्रधान कोंसलावास द्वारा जारी किए गए वीजाओं की संख्या 23719 है जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 153% की वृद्धि हुई।

ईरान

भारत और ईरान प्राचीन काल से पड़ोसी हैं । वर्ष 2004 में ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्र में पारगमन मार्गों, अफगानिस्तान से संबंधित सहयोग और उसके पुनर्निर्माण तथा द्विपक्षीय व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों में वृद्धि करने के क्षेत्रों में भारत और ईरान के बीच निरन्तर सहयोग देखा गया जिसने द्विपक्षीय संबंधों को एक सामरिक आयाम दिया ।

उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान

मई 2004 में भारत में नयी सरकार के गठन के बाद से ईरान के राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी ने टेलीफोन पर प्रधानमंत्री से बातचीत की । विदेश मंत्री डा0 खारजी 25-26 जुलाई 2004 को भारत की यात्रा पर आए । इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की ।

सुरक्षा और सामरिक परामर्श

भारत और ईरान दोनों ने शांतिपूर्ण,स्थायी तथा समृद्ध अफगानिस्तान की आवश्यकता पर बल दिया जो बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त हो । वे अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए हाथ

मिलाने पर भी सहमत हुए । भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान में मेलक-जेरांज-देलाराम सड़क के जरिए ईरान के छबाहर बन्दरगाह के रास्ते अफगानिस्तान के लिए एक वैकल्पिक पहुंच मार्ग विकसित करने के लिए अपना-अपना समर्थन व्यक्त किया । भारत ने अफगानिस्तान में सड़क निर्माण परियोजना शुरू कर दी है जिसके लिए ईरान ने वीजा सुविधा, ईरान से कच्चे माल की सोर्सिंग, बन्दरगाह और पारगमन सुविधाओं आदि की शक्ल में समर्थन देने का आश्वासन दिया है ।

ईरान के विदेश मंत्री डा0 खारजी और हमारे विदेश मंत्री इराक की उभरती स्थिति के बारे में टेलीफोन पर चर्चाओं सहित नियमित सम्पर्क में रहे । डा0 खारजी की जुलाई 2004 में भारत की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति और अफगानिस्तान एवं इराक की स्थिति की समीक्षा की ।

दोनों पक्षों ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच अन्योन्यक्रिया के स्थापित तंत्रों के जरिए नियमित सुरक्षा तथा सामरिक परामर्श भी किया । अक्तूबर 2004 में ईरान की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री जे.एन.दीक्षित ने द्विपक्षीय मसलों एवं इराक और अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में चर्चा की ।

हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग

ऊर्जा सुरक्षा भारत-ईरान के द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है । राष्ट्रपति खातमी की यात्रा और हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध समझौता-ज्ञापन सम्पन्न हो जाने के बाद भारत और ईरान ने इस क्षेत्र में अपना सहयोग और व्यापक बनाने के लिए कई कदम उठाए । दोनों पक्षों ने हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया । संयुक्त कार्यदल द्वारा की गई चर्चा के अनुसार भारत और ईरान, भारत द्वारा ईरान से एल.एन.जी. की दीर्घावधिक खरीद की दिशा में कार्य करने पर सहमत हुए । इस बात पर भी सहमति हुई कि भारत की तेल कंपनियां ईरान में प्रतियोगी आधार पर तेल अन्वेषण के क्षेत्रों में भाग लेंगी ।

सहयोग के इन पहलुओं पर दोनों पक्षों के बीच तकनीकी बातचीत जारी है । केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर 5-6 दिसम्बर, 2004 को ईरान की यात्रा पर गए । इस क्षेत्र में और आगे सहयोग के लिए उन्होंने ईरान के पेट्रोलियम मंत्री डा0 बिजान जांगनेह से मुलाकात की ।

भारत ईरान से भारत के लिए ईरानी गैस की लागत-प्रभावी, दीर्घावधिक तथा अन्तरण के सुरक्षित तरीके का सुनिश्चय करने के लिए वचनबद्ध है । भारत के लिए ईरानी गैस के अन्तरण से सम्बद्ध भारत-ईरान संयुक्त समिति को इस मसले

के सभी पहलुओं की जांच करने का काम सौंपा गया है । दोनों पक्षों ने आफशोर एवं आनशोर मार्गों का अध्ययन करने के लिए दोनों पक्षों की ओर से "गेल" तथ एन.आई.ओ.सी. के नेतृत्व में एक तकनीकी उप-समिति का गठन किया है ।

मालदीव

वर्ष 2004-05 के दौरान भारत-मालदीव के संबंध घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण बने रहे । नियमित बैठकों/यात्राओं के आदान-प्रदान के जरिए इन संबंधों में उत्साह को कायम रखा गया ।

हमारे विदेश मंत्री ने जुलाई 2004 में सार्क मंत्रियों की परिषद की बैठक के दौरान इस्लामाबाद में तथा जनवरी 2005 में जकार्त्ता में सुनामी राहत से सम्बद्ध आसियान बैठक के दौरान मालदीव के विदेश मंत्री श्री फातुला जमील से मुलाकात की । विदेश सचिव 18-19 अक्तूबर 2004 को मालदीव की यात्रा पर गए । इस यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हित के अन्य क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की । विदेश सचिव ने मालदीव के राष्ट्रपति गयूम से भेंट की।

आर्थिक और तकनीकी सहयोग की प्रक्रिया संतोषजनक बनी रही । धारूमावन्त रासगेफानू मस्जिद के संरक्षण से संबंधित कार्य के सिलसिले में सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण से सम्बद्ध राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ का एक विशेषज्ञ दल मई 2004 में मालदीव की यात्रा पर गया ।

जनता के विरोध जो 12 - 13 अगस्त 2004 को शुरू हुआ, के कारण मालदीव सरकार ने माले में तथा उसके इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में अगस्त 2004 में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी । मालदीव के राष्ट्रपति ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद अब्दुलाह को मालदीव की घटनाओं की जानकारी भारत सरकार को देने के लिए अपने विशेष दूत के रूप में भारत भेजा । श्री अब्दुलाह ने 25 जुलाई 2004 को विदेश मंत्री से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री को संबोधित राष्ट्रपति गयूम का व्यक्तिगत पत्र सौंपा। राष्ट्र में आपातकालीन स्थिति को 10 अक्तूबर 2004 को हटा लिया गया और मालदीव में स्थिति सामान्य होने लगी ।

एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में मालदीव ने नई दिल्ली में आवासी हाई कमीशन खोला तथा श्री अब्दुल सत्तार आदम को भारत में पहला आवासी हाई कमिश्नर नियुक्त किया । उन्होंने 30 नवम्बर 2004 को अपने प्रत्यय-पत्र राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए ।

एक अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय घटना हाल ही के सुनामी आपदा के परिणामस्वरूप हुई । मालदीव सरकार के अनुरोध पर राहत सामग्री, चिकित्सा दलों और विशेषज्ञों को लेकर भारतीय जहाज, हवाई जहाज तथा हेलीकेप्टर 27 दिसम्बर 2004 को मालदीव के लिए तुरन्त रवाना हुए । हमारे कार्मिक समुद्र में गए और उन्होंने अनिवार्य सेवाएं, चिकित्सा राहत प्रदान कर मदद की एवं खोज-बीन, बचाव कार्यों, राहत सामग्री को ढोने और जनरेटरों एवं संचार की बहाली कर सहायता की ।

म्यांमां

भारत -म्यांमा संबंध साझे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संबंधों पर आधारित हैं। दोनों देशों की लम्बी साझी भू-सीमा (1600 किलोमीटर) तथा बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा है। चार पूर्वोत्तर राज्य अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमा की सीमा पर हैं । भारतीय मूल की एक बड़ी जनसंख्या (लगभग 2.5 मिलियन) म्यांमा में रहती है । भौगोलिक सामरिक कारणों ने भारत और म्यांमा के घनिष्ठ संबंधों को महत्वपूर्ण बना दिया है । भारत-म्यांमा के संबंध दोनों देशों की इस साझी इच्छा के द्योतक हैं कि अपनी सीमा पर शांति तथा अमन कायम रखने के लिए, स्थायी विकास प्राप्त करने के लिए तथा लोगों से लोगों की अन्यन्योक्रिया को संपोषित करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करें। हाल के वर्षों में आदान-प्रदानों में तेजी से वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय संबंध और गहन तथा व्यापक बने ।

उच्चतर स्तर पर आदान-प्रदानों से 2004 के दौरान म्यांमा के साथ रचनात्मक भागीदारी बनाए रखने की भारत की नीति को मजबूती मिली । राज्य शांति तथा विकास परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल थान शाव राष्ट्रपति के आमंत्रण पर 24-29 अक्तूबर 2004 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए । उनके साथ उच्च अधिकार प्राप्त शिष्टमंडल भीं आया जिसमें एस.पी.डी.सी. के सचिव ले. जनरल थेन सेन, क्वॉटर मास्टर जनरल तथा म्यांमा आर्थिक सहयोग के अध्यक्ष थिहा थुरा तिन यांग मिंट ओ एवं विदेश मंत्री, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, रेल परिवहन मंत्री, संचार मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य एवं धार्मिक मामले मंत्री सहित आठ केन्द्रीय मंत्री शामिल थे । यह यात्रा ऐतिहासिक स्वरूप की थी क्योंकि 24 वर्षों के बाद म्यांमा से यह पहली राष्ट्राध्यक्ष स्तर की यात्रा थी और 17 वर्षों में दोनों देशों के बीच यह पहली राज्याध्यक्ष-शासनाध्यक्ष स्तर की अन्योन्यक्रिया थी ।

उनकी इस यात्रा के दौरान वरिष्ठ जनरल थान शाव ने राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति से मुलाकात की तथा प्रधानमंत्री के साथ आपसी हित चिन्ता के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और सार्वभौम मसलों पर व्यापक चर्चा की । एस.पी.डी.सी. के अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा कि म्यांमा भारत के विरूद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए अपने प्रदेश के प्रयोग की अनुमति नहीं देगा । दोनों देशों के बीच गैर-परम्परागत सुरक्षा मसलों के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध एक समझौता-ज्ञापन सम्पन्न हुआ । दोनों पक्षों ने अवसंरचना परियोजनाओं तथा ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपनी-अपनी मंशा भी व्यक्त की । म्यांमा में चिन्दविन नदी पर तमंथी जल विद्युत परियोजना से सम्बद्ध एक समझौता-ज्ञापन भी सम्पन्न हुआ । दोनों पक्षों ने 2004-2006 के लिए एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर भी आद्याक्षर किए । इस यात्रा के अन्त में जारी संयुक्त वक्तव्य में म्यांमा की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

राष्ट्रपति भवन के सामने का खुला क्षेत्र जँहा विभिन्न राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों का औपचारिक विधान समारोह का आयोजन किया जाता है।

राष्ट्रपति डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम और प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह, 24 अक्तूबर 2004 को म्यामां की शान्ति और विकास परिषद् के अध्यक्ष सीनियर जनरल थान स्वे का स्वागत करते हुए।

की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रयास का पूरा समर्थन किया ।

हमारे विदेश मंत्री और म्यांमा के विदेश मंत्री यू यान वी., वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ तथा म्यांमा के उद्योग मंत्री-रू यू. आंग थांग, रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव तथा म्यांमा के रेल परिवहन मंत्री मे. जनरल आंग मिन; संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन और म्यांमा के संचार, डाक तथा टेलीग्राफ मंत्री बिग्रेडियर थोइन जाव; और विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कपिल सिब्बल एवं म्यांमा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यू. थांग के साथ मंत्रिस्तर पर पांच द्विपक्षीय बैठकें हुई । यह यात्रा बहुत सफल रही तथा इससे म्यांमा के नेतृत्व में भारत के प्रति और अधिक सदभावना जागृत हुई ।

इस वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय आदान-प्रदानों में म्यांमा के विदेश मंत्री यू. विन आंग की 24 जुलाई 2004 को भारत की यात्रा शामिल है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की । विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान दोनो पक्षों ने भारत-म्यांमा-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, 2006 तक द्विपक्षीय व्यापार को 1 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई ।

इससे पहले दोनों मंत्रियों की जुलाई के शुरू में जकार्ता में सम्पन्न आसियान पश्च-मंत्रिस्तरीय सम्मेलन/आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक के दौरान मुलाकात हुई थी, जहां उन्होंने यांगेन में उद्यमशील विकास केन्द्र की स्थापना से सम्बद्ध समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । यांगोन इंस्टीच्यूट आफ इकोनोमीज के सह-प्रोफेसर डा0 सान एलविन को निदेशक के रूप में तथा म्यांमा के पांच अधिकारियों को प्रस्तावित उद्यमशील विकास केन्द्र (ई.डी.सी.) के लिए प्रशिक्षक चुना गया ।

म्यांमा के रेल परिवहन मंत्री मे. जनरल आंग मिन के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय शिष्टमंडल 26 जुलाई से 3 अगस्त 2004 तक भारत की यात्रा पर आया । इस यात्रा के दौरान म्यांमा तथा भारत ने यांगोन-मंडाले ट्रंक रोड का उन्नयन करने से संबंधित एक समझौता-ज्ञापन सम्पन्न किया । इस समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत भारत सरकार ने रोलिंग स्टाक की खरीद के साथ-साथ कार्यशालाओं, ट्रेकों तथा संचार एवं सिगनल पद्धतियों का उन्नयन के लिए मयांमा संघ की सरकार को 56.358 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण उपलब्ध कराया।

म्यांमा ने 3-5 अक्तूबर 2004 को भारत और म्यांमा के बीच विदेश कार्यलय परामर्शों की मेजबानी की । विदेश सचिव श्री श्याम सरन ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया तथा म्यांमा के विदेश उपमंत्री यू क्याव थू ने म्यांमा पक्ष का नेतृत्व किया । इस बैठक के दौरान भारत-म्यांमा संबंधों की व्यापक समीक्षा की गई । इस यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री महामान्य ले. जनरल खिन यूंत के अलावा गृह मंत्री, शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से मुलाकात की ।

दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय स्तर की 10वीं बैठक 4-7 अक्तूबर, 2004 तक नई दिल्ली में हुई । दोनों देशों के गृह सचिवों ने अपने-अपने शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया। चर्चा में सुरक्षा से संबंधित मसले, नशीली दवाइयों का गैर-कानूनी व्यापार, मुक्त आवाजाही व्यवस्था से संबंधित मसले, सीमावर्ती व्यापार तथा बैंकिंग प्रबंध शामिल थे ।

म्यांमा के विदेश उपमंत्री यू. क्याव थू ने नई दिल्ली में 19 अक्तूबर और चेन्नई में 20-21 अक्तूबर 2004 को सम्पन्न भारत-आसियान व्यवसाय शिखर-सम्मेलन में भाग लिया। ऊर्जा क्षेत्र में भारत-म्यांमा सहयोग पर चर्चा करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल जनवरी 2005 के दूसरे सप्ताह में म्यांमा की यात्रा पर गया ।

आर्थिक क्षेत्र में भारत संयुक्त व्यापार समिति द्वारा निर्धारित द्विपक्षीय व्यापार को 2006 तक 1 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृत-संकल्प है । वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है । 2003-04 के दौरान म्यांमा ने भारत को 361.38 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया और उसने भारत से 108.85 मिलियन अमरीकी डालर का आयात किया । द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए सिफारिशें करने के संबंध में एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना करने के बारे में फरवरी 2004 में भारतीय उद्योग परिसंघ तथा म्यांमा संघ के वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए । इस कार्य दल की रिपोर्ट वरिष्ठ जनरल थान शाव की भारत यात्रा के दौरान रिलीज हुई और उसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

भारत की नीति का एक मुख्य उद्धेश्य परस्पर लाभकारी सीमावर्ती परियोजनाओं का क्रियान्वयन करके पश्चिमी म्यांमा के साथ पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास एवं एकीकरण की दिशा में कार्य करना है । इनमें सड़कों, रेलवे, विद्युत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं । नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0 तमन्थी एच.ई.पी.पी. के संबंध में पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन कर रहा है । म्यांमा भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक भागीदार के रूप में उभर रहा है । ओ.एन.जी.सी. विदेश लि0 और जी.ए.आई.एल. ने राखिन तट से दूर ए-रू ब्लाक में 20% तथा 10% की भागीदारी की इच्छा अर्जित की है। ओ.एन.जी.सी. विदेश लि0 ए-रूरूरू ब्लाक में भागीदारी प्राप्त करने में सफल हो गया है जिसमें प्रमुख भूमिका कोरिया के डेबू की है ।

इस वर्ष के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत - म्यांमा सहयोग गहन हुआ है तथा उसमें विविधता आयी है । तटवर्ती म्यांमा में अप्रैल 2004 में टाइडल गौज की स्थापना से सम्बद्ध संयुक्त परियोजना फलदायी हुई है । संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ है । संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध भारत-म्यांमा संयुक्त कार्यदल

की अप्रैल 2004 में पहली बैठक के बाद टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंस इंडिया लि0 और म्यांमा संघ की सरकार के म्यांमा डाक एवं दूरसंचार के बीच यांगोन में 27 जुलाई 2004 को दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए । भारत के एक्जिम बैंक और म्यांमा के विदेश व्यापार बैंक ने यांगोन तथा मण्डाले में कोर डी.ई.सी.टी. डब्ल्यू.एल.एल. आधारित बेसिक टेलीफोन तथा इन्टरनेट नेटवर्क बिछाने के लिए 7 मिलियन अमरीकी डालर का विशेष ऋण देने के संबंध में अक्तूबर 2004 में एक करार पर हस्ताक्षर किए । इसमें मोरेह(भारत) तथा तामू (म्यांमा) के सीमावर्ती शहरों में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम भी शामिल है । भारत ने यांगोन और मण्डाले में दो ई-लर्निंग केन्द्र स्थापित करने एवं ई-गवर्नेन्स परियोजना को चलाने के लिए 3 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान की भी घोषणा की ।

पहली भारत-आसियान कार रैली जिसे प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने 22 नवम्बर को गुवाहटी ने झण्डी दिखाई, 24 से 28 नवम्बर तक म्यांमा के रास्ते गयी । म्यांमा के इलैक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया ने इस रैली को व्यापक कवरेज दिया । राज्य शांति तथा विकास परिषद के सदस्य ले. जनरल ये माइन्त के नेतृत्व में म्यांमा का एक 10 सदस्यीय उच्चस्तरीय शिष्टमंडल जिसमें खेल मंत्री ब्रिगेडियर जनरल थूरा आए माइन्त एवं उत्तर-पश्चिम कमाण्ड के कमाण्डर मे. जनरल था आए भी थे, कार रैली की शुरूआत के समारोह में भाग लेने गुवाहटी गए ।

रैली के साथ-साथ यांगोन स्थित भारत के राजदूतावास मण्डाले स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास, म्यांमा संघ के वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ ने संयुक्त रूप से मण्डाले में 25 नवम्बर 2004 को "भारत -म्यांमा व्यापार तथा आर्थिक सहयोग " से सम्बद्ध सेमिनार का आयोजन किया । इस सेमिनार के सिलसिले में भारी उद्योग तथा लोक उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष मोहन देव यांगोन तथा मण्डाले की यात्रा पर गए । म्यांमा पक्ष की ओर से वाणिज्य मंत्री ब्रिगेडियर जनरल तिन यांग थेन ने सेमिनार को संबोधित किया ।

मानव संसाधन विकास में सहयोग के अंतर्गत कोलम्बो योजना के टी.सी.एस., आइटेक तथा आई.सी.सी.आर. के जी.सी.सी.एस. जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2004-05 में म्यांमा से लगभग 200 उम्मीदवारों के भारत में प्रशिक्षण पर आने की संभावना है ।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया तथा म्यांमा न्यूज एजेन्सी के बीच द्विपक्षीय सम्पर्क भली प्रकार से कार्य कर रहे हैं । म्यांमा न्यूज एजेन्सी नियमित रूप से पी.टी.आई. के न्यूज फीड्स का उपयोग रहा है जो सरकार के दैनिक समाचार-पत्र "दि न्यू लाईट आफ म्यांमा " तथा अन्य स्थानीय भाषा के समाचार-पत्रों में प्रकाशित होती है ।

सांस्कृतिक क्षेत्र में भारतीय फिल्में विशेष रूप से वालीवूड की फिल्में म्यांमा में बहुत लोकप्रिय हैं । 20 वर्षों के अन्तराल के बाद म्यांमा सरकार के सूचना मंत्रालय के सहयोग से यांगोन स्थित भारत के राजदूतावास ने यांगोन में 18-24 अगस्त 2004 तक और मण्डाले में 1-5 सितम्बर 2004 तक भारतीय फिल्म सप्ताह का आयोजन किया । इस उत्सव में भारी भीड़ हुई और इसे इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया दोनों में पर्याप्त कवरेज मिला ।

सेना के द्विवार्षिक सीमा सम्पर्क बैठकों के तंत्र के जरिए रक्षा सहयोग भली-भांति चल रहा है । कई उच्चस्तरीय आदान-प्रदान हुए जिनमें पूर्वी कमांड के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ले. जनरल जे.एस.वर्मा की 21-24 सितम्बर 2004 तक और स्टाफ कमेटी के प्रमुखों के अध्यक्ष एवं वायु सेना अध्यक्ष एअर चीफ मार्शल एस. कृष्णास्वामी की 15-19 नवम्बर 2004 तक की म्यांमा की यात्रा शामिल है ।

नेपाल

नेपाल में राजनीतिक और सुरक्षा की स्थिति गंभीर चिंता का कारण है। 1 फरवरी 2005 को नेपाल नरेश ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की बहुदलीय सरकार को बर्खास्त कर दिया। आपातकालीन की घोषण कर दी गई और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। राजनीतिक नेता, मीडिया के व्यक्ति, बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्त्ता एवं छात्र नेता नजरबंद है। प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया दोनों पर सख्त सेंसरशिप है।

हालांकि नेपाल में सुरक्षा की स्थिति बगड़ती जा रही है। माओवादियों ने सम्पूर्ण नेपाल ने अपना जाल फैला दिया है। उन्होंने काठमाडू घाटी सहित प्रमुख शहरों में जन-जीवन को अस्त-व्यस्त करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। नेपाल में माओवादी विद्रोह की वृद्धि भारत के लिए गंभीर चिंता का मामला है क्योंकि भारत की खुली तथा अभिनियमित सीमा के साथ-साथ नेपाल के माओवादियों एवं भारत के नक्सली गुटों के बीच सम्पर्कों के कारण भारत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

नेपाल की घटनाओं से लोकतंत्र को गहरा धक्का पहुंचा है जिससे गैर-संविधानिक बलों को लाभ पहुंचेगा तथा लोकतंत्र के साथ-साथ राजतंत्र को क्षीण करेगा। भारत का हमेशा यह मानना है कि केवल राष्ट्रीय सर्वसम्मति के आधार पर नेपाल द्वारा महसूस की जा रही चनौती का प्रभावी ढंग से समाधान निकाला जा सकता है। इस संदर्भ में, हमने शीघ्र लोकतंत्र की बहाली की प्रक्रिया का आह्वान किया है। हमने गिरफ्तार किए गए सभी राजनैतिक नेताओं, मीडिया के व्यक्तियों, बुद्धिजीवियों तथा मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं की शीघ्र रिहाई का भी आह्वान किया है जिन्हें अपने सैवेधानिक अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। भारत अपनी ओर से नेपाल में राजनैतिक स्थिरता की बहाली और आर्थिक समृद्धि के सभी प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगा।

द्विपक्षीय सहयोग

वर्ष के दौरान विशेषकर नेपाल में बहु-दलीय सरकार की

बर्खास्तगी एवं आपात स्थिति लगाने से पहले द्विपक्षीय संबंध संतोषजनक ढंग से चलते रहे। नेपाल ऐसा पहले देश है जहां विदेश मंत्री अपना कार्यभार संभालने के बाद वहां की यात्रा पर गए जो इस बात को परिलक्षित करता है कि भारत नेपाल के साथ संबंधों के और अधिक विकास को प्राथमिकता देता है। नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री महामान्य शेर बहादुर देउबा 8-12 सितम्बर 2004 तक भारत की उपयोगी और रचनात्मक यात्रा पर आए। विदेश राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह 29 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2004 तक नेपाल की यात्रा पर गए। इसके अलावा मौजूदा द्विपक्षीय तंत्रों के जरिए व्यापक मसलों पर नियमित परामर्श हुए।

नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मसलों की व्यापक समीक्षा की गई । इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें हुई जिनमें गृह-सचिव स्तर की वार्ता (19-20 जनवरी 2005), सुरक्षा मसलों से सम्बद्ध भारत-नेपाल द्विपक्षीय परामर्शीय समूह की बैठक, जल संसाधनों से सम्बद्ध संयुक्त समिति (7-8 अक्तूबर 2004), पंचेश्वर परियोजना से सम्बद्ध विशेषज्ञों के संयुक्त दल की बैठक (6 अक्तूबर 2004), सचिव स्तर की दूरसंचार समन्वय बैठक (1-2 नवम्बर 2004) और संयुक्त सचिव स्तर की व्यापार बातचीत (1-2 नवम्बर 2004) शामिल है । फलस्वरूप कई द्विपक्षीय मसलों पर उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की गई ।

इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज सम्पन्न किए गए; (1) मौसम भविष्यवाणी के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध समझौता-ज्ञापन; (2) संस्कृति तथा खेलकूद के क्षेत्रों में सहयोग से सम्बद्ध करार; (3) तेल पाइपलाइन के निर्माण के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन तथा नेपाल आयल कारपोरेशन के बीच समझौता-ज्ञापन;(4)भारतीय मानक ब्यूरो तथा नेपाल मानक एवं माप-पद्धति ब्यूरो के बीच द्विपक्षीय सहयोग करार और (5) रेल सेवा करार (भारत और नेपाल के बीच जुलाई 2004 में रेल सेवा शुरू करने को सुविधाजनक बनाने के लिए)।

भारत और नेपाल के बीच सुरक्षा से सम्बद्ध सहयोग को कारगर बनाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है जिसमें सुरक्षा मसलो से सम्बद्ध द्विपक्षीय परामर्शी दल, गृह-सचिव स्तर की वार्ता एवं सीमा प्रबंधन से सम्बद्ध संयुक्त कार्यदल शामिल हैं जो आपसी सुरक्षा चिंताओं को प्रभावी रूप से हल करने में बहुत प्रभावी सिद्ध हुए है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि नेपाल में माओवादी विद्रोह की बढ़ोत्तरी एक साझी चिंता है, हमने इससे निपटने के लिए नेपाल को अपेक्षित सहायता प्रदान की है। प्रभावी सीमा प्रबंधन और आसूचना की साझेदारी के लिए नेपाल के साथ सहयोग संवर्धित करने के उपाय किए हैं। सीमा के साथ शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा सीमा पार से विद्रोही गतिविधियों को खुली सीमा का प्रयोग करने से रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के कार्मिकों को तैनात किया गया है। आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता से सम्बद्ध द्विपक्षीय करार सम्पन्न करने तथा प्रत्यर्पण संधि को अद्यतन करने के संबंध में चर्चाएं हुई जिससे अपराध एवं आतंकवाद का प्रभावी रूप से प्रतिकार करने के लिए भारत और नेपाल के बीच संस्थागत कानूनी प्रबंध सुदृढ़ होगें।

सितम्बर-अक्तूबर 2004 में द्विपक्षीय सांस्थानिक तंत्रों की कई बैठकों में जल संसाधन के क्षेत्र में भारत-नेपाल सहयोग की व्यापक समीक्षा की गई । दोनों पक्षों ने विभिन्न परियोजनाओं पर कार्रवाई करने के लिए एक तय रूपरेखा तैयार की । जल संसाधन से सम्बद्ध संयुक्त समिति बाढ़ प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक व्यापक नीति के साथ ही लघु से मध्यम अवधि में कार्यान्वित किए जाने वाले उपायों को अंतिम रूप देगी ।

भारत अवसंरचना, स्वास्थ्य, ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को शुरू करके नेपाल सरकार के विकास के प्रयासों में निरन्तर योगदान करता आ रहा है । इस वर्ष के दौरान पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पर आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाने संबंधी मुख्य सहायता प्राप्त परियोजना पूर्ण हो गई है । स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में कई छोटी-छोटी परियोजनाएं भी निष्पादित की गई ।

व्यापार और पारगमन को सुविधाजनक बनाने एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर सीमावर्ती अवसंरचना में सुधार करने के लिए कई नयी परियोजनाएं शुरू की हैं । इन परियोजनाओं में सीमा पर चौकियों के विकास, नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क अवसंरचना में सुधार और पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के साथ शहरों एवं गांवों को बेहतर जोड़ना शामिल है । उन्होंने भारतीय पक्ष की सीमा से लगे उन सड़कों तथा राजमार्गों के सुधार को भी शामिल किया है जो नेपाल के शहरों को जोड़ते हैं और भारत के सबसे नजदीक स्थान से तराई क्षेत्र के नेपाली शहरों को बड़ी रेल लाइन से जोड़ती हैं जहां बड़ी रेल लाइन पहले ही मौजूद है । वीरगंज स्थित भारत के कोंसलावास ने कार्य करना शुरू कर दिया है ।

भारत सरकार विभिन्न पाठ्यक्रमों में नेपाली छात्रों को वार्षिक रूप से 1000 से अधिक छात्रवृत्तियों की पेशकश करती है । इस वर्ष के दौरान एक नयी छात्रवृत्ति योजना अर्थात डा. होमी जे. बाबा छात्रवृत्ति योजना प्रचालन में है जिसके अंतर्गत भारत में अध्ययनरत मेधावी नेपाली छात्रों को प्रतिवर्ष 5 एम.टेक छात्रवृत्ति अवार्ड की जाएंगी । इसके अलावा, कई नेपाली छात्र अपने खर्च से भारत में अध्ययन के लिए आते हैं।

पाकिस्तान

भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंध कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है । इस लक्ष्य के अनुसरण में सरकार ने समय-समय पर कई नीतिगत पहलकमियां की । वर्ष 2004-05 में पाकिस्तान के साथ गंभीर, स्थायी और व्यापक वार्ता की शुरूआत । अच्छी सद्भावना तैयार करना जो दोनों देशों के लोगों में देखी गई है, भारत ने दक्षिण एशिया

में शांति तथा स्थायीत्व के स्थायी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के साथ रचनात्मक बातचीत की सक्रिय नीति को आगे बढ़ाया ।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा 6 जनवरी 2004 को दी इस महत्वपूर्ण सुस्पष्ट वचनबद्धता कि पाकिस्तान के नियंत्रण वाले किसी भी प्रदेश के उपयोग की अनुमति किसी भी प्रकार के आंतकवाद का समर्थन करने के लिए नहीं दी जाएगी, के आधार पर दोनो देशों के विदेश सचिवों ने संयुक्त वार्ता शुरू करने के लिए फरवरी 2004 में मुलाकात की। इन बातचीतों ने सारगर्भित वार्ता प्रक्रिया को शुरू करने का संकेत दिया जिसमें सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच 24-27 मार्च, 2004 की प्रारंभिक अन्योन्यक्रिया तथा दोनों देशों के स्वापक नियंत्रण प्राधिकारियों के बीच 15-16 जून, 2004 की बातचीत शामिल है । सीमा प्रबंधन और तस्करी तथा नशीली दवाओं के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने से संबंधित मसलों पर भी चर्चा हुई और दोनों पक्ष प्रचालन आसूचना की साझीदारी के जरिए सहित आपसी लाभ के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए ।

नाभिकीय विश्वासोत्पादक उपायों से सम्बद्ध विशेषज्ञ स्तर की बैठक(19-20 जून,2004)

फरवरी 2004 को भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच सम्पन्न बैठक के दौरान भारत ने नाभिकीय विश्वासोत्पादक उपायों के संबंध में विशेषज्ञ स्तर की वार्ता का सुझाव दिया । ये बातचीत 19-20 जून 2004 को नई दिल्ली में हुई जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच हाटलाइन स्थापित करने, दोनों देशों के डी.जी.एम.ओ. के बीच संचार सम्पर्क का उन्नयन करने, उसे समर्पित करने और प्राप्त करने से सम्बद्ध करार सम्पन्न करने एवं प्रक्षेपास्त्रों की उड़ान की जांच के पूर्व-अधिसूचना से सम्बद्ध करार की दिशा में कार्य करने पर चर्चा हुई ।

विदेश सचिव स्तर की वार्ता (27-28 जून 2004)

27-28 जून 2004 को शांति तथा सुरक्षा और जम्मू तथा कश्मीर के बारे में विदेश सचिव स्तर की बातचीत के दौरान आंतकवाद और हिंसा से मुक्त वातावरण में प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान हुआ । भारत ने विश्वासोत्पादक उपायों की व्यापक रूपरेखा का प्रस्ताव किया । अन्य बातों के साथ-साथ अपने -अपने हाई कमीशन के कर्मचारियों की संख्या 110 के मूल स्तर पर तत्काल बहाल करने; एक-दूसरे की हिरासत में पकड़े गए सभी मछुवारों को तुरन्त रिहा करने और गैर-इरादतन उल्लंघन करने वाले मछुवारों तथा गहरे समुद्र से उनकी नौकाओं को पकड़े बिना उनकी वापसी के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करने; सिविलयन कैदियों की शीघ्र रिहाई के कदम उठाने पर सहमति हुई । करांची और मुम्बई में प्रधान कोंसलावास पुनःस्थापित करने पर भी सिद्धांत रूप से सहमति हुई । दोनों विदेश सचिवों ने जम्मू तथा कश्मीर के संबंध में विचारों का विस्तृत रूप से आदान-प्रदान किया और इस मसले का शांतिपूर्ण, बातचीत के जरिए और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढ निकालने के उद्देश्य से सार्थक और उपयोगी वार्ता जारी रखने पर सहमति हुई ।

संयुक्त वार्ता की समीक्षा (4-6 सितम्बर 2004)

संयुक्त वार्ता में हुई समग्र प्रगति की समीक्षा करने के लिए हमारे विदेश मंत्री ने 5-6 सितम्बर, 2004 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की । इससे पहले दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच एक दिन की बैठक हुई ।

दोनों देशों के विदेश मंत्री विभिन्न विषयों पर कई तकनीकी बातचीतों के बारे में सहमत हुए जिनमें परम्परागत तथा नाभिकीय विश्वासोत्पादक उपायों पर विशेषज्ञ स्तर की बैठक के अलावा प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण की अग्रिम सूचना से सम्बद्ध प्रारूप करार ; मुन्नाबाओ-खोखरापार रेल सम्पर्क को प्रचालित करने के बारे में रेलवे प्राधिकारियों की बैठक; भारत सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान के रेंजर्स के बीच बैठक; स्वापक नियंत्रण प्राधिकारियों के बीच बैठक; भारतीय तटरक्षकों और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेन्सी के बीच संचार सम्पर्क स्थापित करने से सम्बद्ध समझौता-ज्ञापन पर चर्चा करने के लिए उनके बीच बैठक; और श्रीनगर तथा मुज्जफराबाद के बीच बस सेवा शुरू करने से संबंधित सभी मसलों पर बैठक शामिल है ।

व्यापार, सिरक्रीक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समस्तर खण्ड पर सीमा स्तम्भों का संयुक्त सर्वेक्षण, दोनों देशों के बीच वीजा व्यवस्था में पर्यटन वीजा की नयी श्रेणी को जोड़ना तथा समूह में पर्यटन को संवर्धित करना; नागरिक बंदियों तथा मछुवारों के मसले को निपटने के लिए तंत्र की स्थापना, धार्मिक स्थलों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए और अधिक उपाय करना एवं ऐतिहासिक स्थलों का रखरखाव; अगस्त 2004 को रक्षा सचिवों की बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन और संबंधित विदेश कार्यालयों के बीच अन्योन्यक्रिया तथा आदान-प्रदानों में बढ़ोतरी से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति की स्थापना करने पर सहमति हुई ।

तकनीकी स्तर की बातचीत (दिसम्बर 2004)

सितम्बर 2004 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के दौरान हुई सहमति के अनुसार विभिन्न विषयों पर तकनीकी स्तर की बातचीत दिसम्बर के पहले पखवाड़े में हुई। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- मुन्नावाओ और खोखरापार के बीच रेल सम्पर्क प्रचालित करने के संबंध में चर्चा करने के लिए दोनों देशों के रेलवे प्राधिकारियों के बीच 2-3 दिसम्बर 2004 को इस्लामाबाद में एक तकनीकी स्तर की बैठक हुई । दोनों पक्ष प्रस्तावित रेल सम्पर्क शीघ्र स्थापित करने पर सहमत हुए । दोनों पक्ष चर्चा को जारी रखने तथा रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिए रेलवे लाइन बिछाने एवं अपेक्षित अन्य संबंधित अवसरंचना सहित विशिष्ट

क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए आवश्यक अंतरिम उपाय शुरू करने पर भी सहमत हुए ।

- 3-4 दिसम्बर 2004 को दोनों पक्षों ने भारतीय तटरक्षकों तथा पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेन्सी के बीच संचार सम्पर्क स्थापित करने के समझौता-ज्ञापन पर प्रारंभिक विचारों का आदान-प्रदांन किया। इस चर्चा को जारी रखने पर सहमति हुई ।
- श्रीनगर और मुज्जफराबाद के बीच बस सेवा शुरू करने से संबंधित सभी मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बैठक 7-8 दिसम्बर 2004 को नई दिल्ली में हुई । दोनों पक्षों ने प्रस्तावित सम्पर्क की शीघ्र स्थापना और इसको शुरू करने के संबंधित सभी पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान करने की दिशा में अपनी-अपनी वचनबद्धता दोहरायी । दोनों पक्ष इस चर्चा को जारी रखने के संबंध में दुबारा मुलाकात करने पर सहमत हुए ।
- भारत और पाकिस्तान के स्वापक नियंत्रण प्राधिकारियों ने 13-14 दिसम्बर 2004 को नई दिल्ली में मुलाकात की । दोनों पक्षों ने नशीली दवाइयों के गैर-कानूनी व्यापार तथा सूचना एवं प्रचालन आसूचना के आदान-प्रदान के जरिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने से संबंधित मामलों पर एक-दूसरे को सकारात्मक से लगाए रखने से संबंधित समझौता-ज्ञापन का आदान-प्रदान किया ।
- सिरक्रिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समस्तर खण्ड में सीमा स्तम्भों का संयुक्त सर्वेक्षण करने के संबंध में एक तकनीकी स्तर की बैठक 14-15 दिसम्बर 2004 को इस्लामाबाद में हुई । दोनों पक्ष 3 जनवरी 2005 से सीमा स्तम्भों के संयुक्त सर्वेक्षण शुरू करने पर सहमत हुए ।
- नाभिकीय तथा परम्परागत विश्वासोत्पादक उपायों के संबंध में एक अलग बैठक 14-15 दिसम्बर 2004 को इस्लामाबाद में हुई । दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की । दोनों देशों के डी.जी.एम.ओ. के बीच सम्पर्क बढ़ाने और दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच हाटलाइन की स्थापना पर सहमति हुई ।

संयुक्त वार्ता का नया दौर

संयुक्त वार्ता का अगला दौर शुरू करने के लिए दोनों देशों के विदेश सचिवों ने इस्लामाबाद में 27-28 दिसम्बर 2004 को मुलाकात की । उन्होंने द्विपक्षीय सबंधों की समग्र प्रगति और विश्वासोत्पादक उपायों एवं जम्मू तथा कश्मीर सहित शांति और सुरक्षा पर चर्चा की । संयुक्त वार्ता के अन्य छह विषयों पर बैठकों का कार्यक्रम तय किया गया । विश्वासोत्पादक उपायों सहित शांति तथा सुरक्षा, दोनों देशों के डी.जी.एम.ओ. के बीच मौजूदा सम्पर्कों का निर्माण करने के मुद्दे पर दोनों देशों के विदेश सचिव स्थानीय स्तर पर तय स्थानों पर नियमित सम्पर्कों को संवर्धित करने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं नियंत्रण रेखा पर और अधिक विश्वासोत्पादक उपायों को खोज निकालने पर सहमत हुए । जम्मू तथा कश्मीर के संबंध में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पांच स्थानों का सुझाव दिया जहां पर दोनों पक्षों के बिछड़े परिवारों के सदस्य आ सकते हैं और संयुक्त सुरक्षा प्रबंधों के अंतर्गत मुलाकात कर सकते हैं ।

उच्च स्तरीय राजनैतिक संपर्क

उच्चस्तरीय राजनैतिक संपर्कों और यात्राओं के जरिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया । विदेश मंत्री श्री के.नटवर सिंह ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ अन्योक्रियाएं की । सार्क मंत्रीस्तरीय परिषद की बैठक के लिए 19-23 जुलाई 2004 तक की इस्लामाबाद की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ चर्चाएं की और पाकिस्तान के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री से भेंट की । इससे पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय कार्यक्रमों के दौरान 21 जून 2004 को किंगडाओ और 2 जुलाई 2004 को जकार्ता में मुलाकात की ।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 24 सितम्बर 2004 को न्यूयार्क में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की । भारत में नई सरकार के गठन के बाद उच्चतम स्तर पर यह पहली मुलाकात थी । प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वार्ता प्रक्रिया राष्ट्रपति मुर्शरफ द्वारा आंतकवाद के संबंध में दिए गए आश्वासन पर आधारित थी जैसाकि 6 जनवरी, 2004 के संयुक्त प्रेस वक्तव्य में दिया गया है। दोनों नेताओं ने सामान्य स्थिति की बहाली तथा सहयोग की द्विपक्षीय वार्ता को जारी रखने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया और दोनों देशों के बीच व्यापारिक तथा आर्थिक संबंधों के विस्तार के व्यापक संदर्भ में गैस पाईप लाइन की संभावना की जांच करने पर भी सहमति हुई । जम्मू और कश्मीर के मसले पर प्रधानमंत्री ने सीमाओं के दोबारा सीमांकन करने, अथवा देश का दोबारा विभाजन करने के सिवाय सभी विकल्पों का पता लगाने की भारत की इच्छा से अवगत कराया ।

सार्क के अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री शौकत अज़ीज की 23-24 नवम्बर 2004 की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने को सुविधाजनक बनाया । हालांकि सार्क एक यात्रा का मौका था फिर भी उस दौरान द्विपक्षीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान भी हुआ । प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने सीमा पार के आंतकवाद के संबंध में पाकिस्तान द्वारा अपनी वचनबद्धता का शब्दशः पूरा करने के महत्व पर जोर दिया । उन्होंने भी गंभीरतापूर्वक और दृढ़तापूर्वक द्विपक्षीय कार्यसूची के सभी मसलों को हल करने के भारत के दृढ़निश्चय को दोहराया ।

एक-दूसरे देश के लोगों का आदान-प्रदान - बीजा उदारीकरण के उपायः

शांतिपूर्ण और सामान्य अन्योयक्रिया के लिए लोगों की बलवती इच्छा एक दूसरे के देश के लोगों जिनमें संसद सदस्य, पत्रकार, नयायविद, खिलाड़ी, कलाकार, व्यवसायी

FINISH
1st ASEAN - INDIA CAR RALLY 2004
NETWORKING PEOPLE AND ECONOMIES
DEVELOPMENT • FRIENDSHIP • HARMONY • PEACE
BATAM ISLAND
SPONSORS
BY 5574

30 नवम्बर 2004 को वियनटाइने में लाओ पी डी आर के प्रधान मंत्री महामहिम बोनहेंग वोराचित और भारत के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह कार रैली को झंडा हिला कर रवाना करते हुए। चित्र में आसियान देशों के नेतागण भी हैं।

इंडोनेशिया के विदेश मंत्री तथा असम के मुख्यमंत्री बताम द्वीप, इंडोनेशिया में भारत-आसियान कार रैली की स्माप्ति रेखा पर झंडा गिराते हुए।

आदि शामिल है, के बढ़ते हुए आदान-प्रदानों में झलकती है । पाकिस्तान की राष्ट्र असेम्बली के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल लोक सभा के अध्यक्ष के आमंत्रण पर 18-23 दिसम्बर 2004 तक भारत की यात्रा पर आया तथा पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने भारतीय समकक्ष के आमंत्रण पर 29 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2004 तक भारत की यात्रा पर आए।

दोनों देशों के लोगों के संपर्क को और अधिक सुविधाजनक बनाने तथा भारत-पाकिस्तान संबंधों की मौजूदा प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने 18 सितम्बर 2004 को पाकस्तानी राष्ट्रिकों के लिए वीजा व्यवस्था को उदार बनाने के एकपक्षीय उपायों की घोषणा की, इनमें वे मान्यता प्राप्त पत्रकार जो राष्ट्र अथवा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ कम से कम 3 वर्ष से सम्बद्ध हों, शिक्षाविद और प्रोफेसर, कुलपति तथा वे व्यक्ति जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के आमंत्रण पर आते हैं, चिकित्सक यदि भारत में किसी प्रमुख/ प्रसिद्ध अस्पताल में इलाज के लिए रोगियों को साथ लाते हैं, 65 वर्ष की आयु से अधिक सभी पाकिस्तानी राष्ट्रिक शामिल हैं । पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को प्रत्येक यात्रा के दौरान 12 स्थानों की यात्रा करने की अनुमति देने और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वीजा के मसले को उदार बनाने का भी निर्णय लिया गया ।

दिसम्बर 2004 में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष से ऊपर), बच्चों (12 वर्ष से नीचे) और पाकिस्तान के चिकित्सा जांच करवाने वाले दल के सदस्यों को बाघा सीमा पर पहुंचने पर वीजा स्वीकृत करने का एकतरफा निर्णय लिया । इसके अलावा, सरकार ने भारत में तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों को मामला-दर-मामला आधार पर प्रवेश की अनुमति देने का भीं निर्णय लिया ।

तीर्थयात्री समूहों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान

इस वर्ष दोनों पक्षों से तीर्थयात्री समूहों द्वारा कई यात्राएं की गई। इनमें जून में गुरू अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर यात्रा, महाराजा रणजीत सिंह की बरसी, नवम्बर में गुरू नानक देव की जन्म शताब्दी और नवम्बर 2004 में कलासराज एवं हयात पिताफी की भारतीय तीर्थ यात्री समूहों की यात्रा शामिल है । इसी प्रकार पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों का दल कल्यार शरीफ, अजमेर शरीफ और सिरहिंद शरीफ की यात्रा पर भारत आए ।

इसके अलावा, भारत ने 1974 के द्विपक्षीय प्रोतोकोल से अलग जिन अन्य स्थानों की यात्रा करने की अनुमति दी उनमें अप्रैल, 2004 में 400 तीर्थ यात्रियों के खानूर सहित , प्रकाश उत्सव के दौरान अगस्त-सितम्बर 2004 में 1000 तीर्थ यात्रियों को अमृतसर स्वर्ण मंदिर, 26-31 अक्तूबर 2004 तक जम्मू तथा कश्मीर में 12 पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों क चरार-ए-शरीफ , 300वीं शहीदी दिवस के मौके पर दिसम्बर 2004 में 250 तीर्थयात्रियों को फतेहगढ़ साहिब एवं 26-28 दिसम्बर 2004 तक अहमेदिया समुदाय के 2000 यात्रियों के एक बड़े दल को कादियान (पंजाब) की यात्रा की अनुमति देना शामिल है ।

लोगों की भावना को देखते हुए भारत ने धार्मिक स्थलों की यात्रा से सम्बद्ध 1974 के प्रोतोकोल में नए तीर्थस्थलों को जोड़ने तथा विभिन्न अवसरों पर यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के समूहों के आकार को बड़ा करने एवं प्रोतोकोल के अलावा अन्य अवसरों पर अतिरिक्त दलों को भेजने के संबंध में कई प्रस्ताव दिए । अमृतसर तथा लाहौर में और उसके इर्द-गिर्द स्थित तीर्थस्थलों के बीच बस सेवा शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया । दोनों पक्षों ने गुरूद्वारा दरबार साहिब (करतारपुर) पाकिस्तान, रायपुर(एम.पी.) स्थित शादानी दरबार तथा भारत में (पानीपत, हरियाणा)हजरत बू अली शाह कलंदर तीर्थ स्थल के लिए तीर्थयात्रियों द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी ।

नागरिक बंदियों और मछुवारों से संबंधित मसले

बंदियों और मछुवारों से संबंधित मानवीय मसले सरकार की कार्य-सूची में प्राथमिकता पर हैं । इस समय पाकिस्तान की अभिरक्षा में रह रहे लगभग 900 भारतीय नागरिक बंदियों, 54 युद्धबंदियों और 974 मछुवारों की शीघ्र रिहाई एवं उनकी स्वदेश वापसी के मसले को सभी स्तरों पर पाकिस्तान के साथ लगातार उठाया गया । नवम्बर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भी इस मामले को उठाया गया था । इस प्रयास के परिणामस्वरूप पाकिस्तान ने 6 जनवरी, 2005 को 266 भारतीय मछुवारों को रिहा कर दिया। फिलहाल वर्ष 2004 के दौरान भांरत ने 135 पाकिस्तानी कैदियों को कोंसली सहायता प्रदान की और 58 कैदियों को रिहा किया । इसके अलावा 108 पाकिस्तानी मछुवारों (कुल 140 में से) को कोंसली सहायता प्रदान की गई ।

दिसम्बर 2004 में विदेश सचिव स्तर की बातचीत के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर सहमति हुई ।

द संबंधित विदेश मंत्रालयों द्वारा गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी/भारतीय राष्ट्रिकों की सूचना तत्काल संबंधित उच्चायोग को दी जाएगी ।

- पकड़े जाने के तीन महीनों के भीतर कोंसली सहायता प्रदान की जाएगी ।
- सजा पूरी हो जाने और राष्ट्रियता का सत्यापन हो जाने के तुरन्त बाद स्वदेश वापसी कर दी जाएगी ।
- किसी नागरिक द्वारा असावधानीवश सीमा पार करने पर सजा दिए बिना उसको शीघ्र स्वदेश भेजने के लिए किसी तंत्र को लागू किया जाएगा ।
- किसी भी पक्ष द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के पकड़े जाने पर उसे सजा दिए बिना उसी शीघ्र रिहाई के लिए इसी प्रकार के एक तंत्र की स्थापना की जाएगी ।

सीमा पार से आंतकवाद की स्थिति

अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा तथा वास्तविक भूमि स्थिति

रेखा पर 23 नवम्बर 2003 का युद्धविराम कायम है । हालांकि विगत में घुसपैठ के स्तर में कुछ कमी आयी थी फिर भी पाकिस्तान ने संचार सम्पर्कों, लांचिंग पेडो और प्रशिक्षण शिविरों जैसी आंतकवाद का समर्थन करने वाली अवसंरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की है। भारत निकट से स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और पाकिस्तान को आंतकवाद के संबंध में उसकी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए उस पर लगातार जोर देता रहा है ।

निष्कर्ष

अप्रैल 2003 में भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद से स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी हैं । हाई कमिश्नरों के स्तर पर संबंधों को कायम रखा गया है, परिवहन और संचार सम्पर्कों को बहाल किया गया है । तकनीकी स्तर की तथा संयुक्त वार्ता से संबंधित कई बैठकें निर्धारित समय के अनुसार हुई हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच सम्पर्कों को मजबूती मिली एवं इस प्रक्रिया को और अधिक प्रेरणा मिली । दोनों देशों के विदेश सचिवों ने वर्ष 2005 के लिए बैठकों का कार्यक्रम तय कर लिया है । सरकार का विश्वास पैदा करने, सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद एवं हिंसा से मुक्त वातावरण में वार्ता करने की मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखने का इरादा है ।

श्रीलंका

इस वर्ष के दौरान उच्चस्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान, व्यापार के विस्तार,श्रीलंका में भारतीय निवेश में बढ़ोतरी और रक्षा संबंधों में वृद्धि से भारत-श्रीलंका के संबंध और अधिक मजबूत बने हैं । द्विपक्षीय मसलों तथा परस्पर हित के अन्य मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने तथा द्विपक्षीय संबंधों को और गहन बनाने की दिशा में कार्य करने के उद्देश्य से श्रीलंका की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता सभी भारत की यात्रा पर आए । दोनों देशों के बीच घनिष्ठ राजनैतिक समझबूझ तथा द्विपक्षीय संबंधों को दिया गया महत्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को समर्थन देने से परिलक्षित होती है ।

अप्रैल, 2004 में श्रीलंका में संसदीय चुनाव सम्पन्न हुए प्रधानमंत्री महिन्द राजापाक्षा के नेतृत्व में नयी सरकार ने कार्यभार संभाला । प्रधानमंत्री राजापक्षा ने भारत को जुलाई 2004 में अपनी पहली विदेश यात्रा के गन्तव्य के रूप में चुना । श्री लंका के विदेश मंत्री लक्ष्मण कादिरगमर इससे पहले 28-29 अप्रैल 2004 तक भारत की यात्रा पर आए । राष्ट्रपति चन्द्रिका भण्डारनायके कुमारतुंग 4-7 नवम्बर 2004 तक तथा विपक्ष के नेता रानिल विक्रमसिंघे 11-14 अक्तूबर 2004 तक भारत की यात्रा पर आए ।

श्रीलंका के नेताओं ने भारत को श्रीलंका के शांति प्रक्रिया के घटनाक्रम की जानकारी दी । भारत ने व्यापक, बातचीत के जरिए श्रीलंका के सभी समुदाय को स्वीकार्य समाधान चाहने के लिए प्रक्रिया के लिए अपने समर्थन को पुनःदोहराया जो एकजुट श्रीलंका की रूपरेखा को परिलक्षित करे और लोकतंत्र के अनुरूप हो एवं व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करें। भारत श्रीलंका की सुरक्षा में स्थायी रूचि रखता है तथा उसकी एकता, सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता के प्रति वचनबद्ध है । भारत शांति प्रक्रिया से संबंधित बातचीत को शीघ्र पुनः शुरू करने के पक्ष में है । प्रशासन की कोई अन्तरिम व्यवस्था अंतिम समाधान निकालने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए जो श्रीलंका की एकता तथा क्षेत्रीय अखण्डता को बनाए रखे एवं लोगों की सुरक्षा, खुशहाली और समृद्धि को सुनिश्चित करें ।

श्रीलंका की शांति प्रक्रिया इस समय रूकी हुई है । लिट्टे ने अप्रैल, 2003 से शांति प्रक्रिया में भागीदारी को रोक दिया है । बाद में उसने उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के लिए एक अंतरिम स्व-शासन प्राधिकारी के सृजन का प्रस्ताव किया जिसमें उसे शक्तियों की सुपुर्दगी सहित विदेश व्यापार को विनियमित करने के अधिकार, समुद्र तथा पहुंच के नियंत्रण के अधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर ऋण लेने के अधिकार जैसे कुछ अर्द्ध-प्रभुसत्ता सम्पन्न कार्य सहित शक्तियों की व्यापक सुपुर्दगी दी गई है। श्रीलंका की सरकार ने संकेत दिया है वह ओस्लो घोषणा के अनुसार लिट्टे की सहमति के मुताबिक उस सीमा तक अन्तरिम स्व-शासन प्राधिकारी के बारे में बातचीत करने के लिए तैयार जहां तक यह संघीय समाधान के संदर्भ में हो । लिट्टे के भीतर मतभेद से 2004 में शांति प्रक्रिया में एक नया आयाम और जुड़ गया है । लिट्टे के श्रेष्ठ रेंक वाले सैन्य कमाण्डर करूणा के नेतृत्व में तथाकथित पूर्वी तमिलों ने प्रभाकरन के विरूद्ध विद्रोह कर दिया और 2004 में जफना के तमिलों ने "वाणी " के नेतृत्व को प्रधानता दे दी । खून-खराबे का संघर्ष तथा हत्याएं करना लिट्टे के विद्रोह का द्योतक है।

भारत और श्रीलंका के बीच मानवोचित व्यवहार के प्रति मौजूदा समझबूझ और उन मछुवारों की रिहाई जो समुद्री सीमा के लाइनों के पार भटक गए, को जारी रखा गया । इस मसले से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन करने का निर्णय लिया । यह कार्यदल भटक रहे मछुवारों से संबंधित मसले से निपटने, उनके विरूद्ध बल प्रयोग को रोकने के लिए तौर-तरीके तैयर करने एवं जब्त की गई नौकाओं की शीघ्र रिहाई तथा मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस देने के संबंध में द्विपक्षीय प्रबंधों की दिशा में काम करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कार्यदल की अक्सर बैठकें होंगी । मत्स्य से सम्बद्ध समझौता-ज्ञापन जो दोनों देशों के बीच मत्स्य के क्षेत्र में सहयोग को संस्थागत बनाएगा, भी विचाराधीन है । इस समझौता की मुख्य विशेषताएं मछली पकड़ने के लाइसेंस देने पर विचार करने, दोनों पक्षों से जालपोतों द्वारा छापा मारने की समस्या को कम करने के लिए निगरानी बढ़ाने में सहयोग करने एवं पाल्क स्ट्रीट में पारिस्थितिकी को संरक्षित करने और समुद्र में मछली के संरक्षण में सहयोग करना है ।

बड़ी संख्या में श्रीलंका के सैनिक, नाविक तथा वायुसैनिक भारतीय रक्षा संस्थापनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । चालू

वर्ष में भारत के विभिन्न रक्षा संस्थाओं में लगभग 2100 स्थानों का उपयोग श्रीलंका के सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों द्वारा किए जाने की आशा है । रक्षा सहयोग करार पर चर्चा के दौरान यह संकल्प लिया गया कि रक्षा सहयोग करार और पलाले में एअरफील्ड की पुनर्स्थापना से सम्बद्ध समझौता-ज्ञापन पर परस्पर सुविधाजनक तारीखो को दोनों देशों की सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । भारतीय पक्ष ने श्रीलंका के नौवहन पौत "सयूरा " को पुनः फिट करने एवं उसकी लागत को अपने जिम्मे लेने पर सहमति दी ।

इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में और तीव्रता देखी गई। व्यापार के विस्तार और निवेशों में वृद्धि के अलावा व्यापार को सेवाओं तथा निवेशों में शामिल करके मुक्त व्यापार करार को व्यापक आर्थिक भागीदारी करार में उन्नयन करके व्यापार की रूपरेखा को गहन तथा व्यापक बनाने के प्रयास किए गए । व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर वाणिज्य सचिव स्तर की पहले दौर की बातचीत अगस्त 2004 तथा फरवरी 2005 को कोलम्बो में हुई ।

भारत आज श्रीलंका में चौथा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है(सिंगापुर, यू.के. और आस्ट्रेलिया के बाद) । हालांकि ऐतिहासिक अन्तर्वाह कम रहा है फिर भी मुक्त व्यापार करार के बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई है । भारत के निवेशकों के लिए सबसे प्रमुख आर्कषण श्रीलंका में कच्चे माल पर कम टैरिफ का लाभ उठाते हुए भारत को पुनः निर्यात करने की क्षमता है । पूर्व प्रवृत्ति को समाप्त करके भारत 2002 तथा 2003 में श्रीलंका में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक था ।

श्रीलंका निवेश बोर्ड ने अगस्त, 2004 के अनुसार 147 परियोजनाओं का अनुमोदन दिया जिसमें कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 450 मिलियन अमरीकी डालर का था । वास्तविक अर्न्तवाह के आंकड़े उपलब्ध नहीं है फिर भी यह अनुमान है कि सार्क देशों में भारतीय निवेश का 50 % श्रीलंका में हुआ है । नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कोयले अथवा लिग्नाइट से चलाए जा रहे 300 मेगावाट के विद्युत संयंत्र से संबंधित बड़ी विद्युत परियोजना विचाराधीन है ।

भारत सरकार ने श्रीलंका को कई ऋण दिए हैं । उनमें से दो अभी भी चल रहे हैं । 100 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण पूंजीगत सामान, उपभोक्ता टिकाऊ सामान, परामर्शी सेवाओं और खाद्य मदों के लिए है तथा 31 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण श्रीलंका को 300,000 टन गेहूं की आपूर्ति के लिए है । इसके अलावा, 150 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की पेशकश श्रीलंका की सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए की गई है, 100 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए है । इस प्रकार श्रीलंका की सरकार को लगभग 381 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1700 करोड़ रूपए) उपलब्ध कराया जा रहा है । भारत सरकार श्रीलंका में लगभग 70 करोड़ रूपए की लागत से विकास परियोजनाएं निष्पादित करने की प्रक्रिया में है और उसने लगभग 87 मिलियन अमरीकी डालर की लागत की अन्य वचनबद्धताएं की है । वे परियोजनाएं जिनको कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा जिन पर विचार किया जा रहा है उनमें जनरल अस्पताल का निर्माण, कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए अनुदान, शैक्षिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रणालियों को सुदृढ़ करने से संबंधित परियोजनाएं, 1500 कैट्रेक आपरेशन करने तथा ग्रामीण विकास परियोजनाएं शामिल हैं ।

26 दिसम्बर, 2004 को सुनामी की तबाही के बाद श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर नौवहन जहाजो तथा हैलीकाप्टरों से बड़ी मात्रा में भारतीय राहत सामग्री श्रीलंका में भेजी गई । चार भारतीय नौवहन जहाज चिकित्सा दलों, चिकित्सा तथा सामान्य राहत की मदों, गोताखोर दल, 27 दिसम्बर, 2004 से श्रीलंका में हैं । एक भारतीय नौवहन डोरनियर तथा आइसलेंडर राहत सामग्री के साथ 27 दिसम्बर को रतमलाना हवाई अड्डे पर पहुंचा । हालांकि दूसरे डोरनियर ने लगभग 700 किलोग्राम आपातकालीन चिकित्सा आपूर्तियों और स्वास्थ्य अधिकारियों को लेकर अगले दिन उड़ान भरी । दक्षिणी प्रान्त में राहत कार्यवाहियों में सहायता करने के लिए तीन एम.आई.-8 हैलीकाप्टर 27 दिसम्बर से काटूनायक हवाई अड्डे पर खड़े हैं जबकि दो एम.आई.-8 और एक एम.आई.-17 हैलीकाप्टर को 28 दिसम्बर से पूर्वी प्रान्त में तैनात किया गया है । इसके अलावा, भारतीय नौवहन जहाजों पर खड़े चेतक हेलीकाप्टर चिकित्सा तथा राहत सामग्री पहुंचाने के लिए उड़ान भर रहे हैं ।

सार्क

जनवरी 2004 में हुई 12वीं शिखर बैठक में तीन दस्तावेजों, सार्क सोशल चार्टर, आतंकवाद सम्बन्धी एक अतिरिक्त प्रोटोकाल और साफ्टा पर एक ढांचागत करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने सार्क देशों में (भारत के बाहर) में गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करने की पेशकश की।

12वीं शिखर बैठक में गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी स्वतन्त्र दक्षिण एशियाई आयोग से 12वीं शिखर बैठक में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों के लिए सार्क विकास लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए अपनी भूमिका जारी रखने और 13वीं शिखर बैठक में अपनी वास्तविक तथा व्यापक रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तत्पश्चात माले तथा नई दिल्ली में हुई बैठक में आईएसएसीपीए ने 13वीं शिखर बैठक तक एक कार्य योजना की पहचान किया और यूएनडीपी जैसे बाह्य स्रोतों से वित्त-पोषण की मांग की। भारत 21 दिसम्बर 2004 को आईएसएसीपीए रिपोर्ट लांच करेगा। एक क्षेत्रीय गरीबी प्रोफाइल-2004, जो कि दूसरी ऐसी रिपोर्ट है, में सार्क के सदस्य देशों का आर्थिक

संकेतकों का ब्यौरा दिया गया है उसे ढाका में 13वीं शिखर बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

भारत द्वारा प्रस्ताव

जुलाई 2004 में इस्लामाबाद में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव (प्रत्येक प्रस्ताव की स्थिति रिपोर्ट कोष्ठक में दी गयी है) पेश किए।

i) दक्षिण एशियाई संसदीय फोरम का गठन : भारत ने सार्क के अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग के प्रयासों से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दक्षिण एशियाई संसदीय फोरम का गठन किए जाने की मांग की और फोरम की अगली बैठक की मेजबानी की पेशकश की। (भारत बजट सत्र 2005 के दौरान फोरम की बैठक की मेजबानी करेगा)

ii) अर्थव्यवस्था, व्यापार, वित्तीय और मौद्रिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से सम्बन्धित विचारों तथा पहलकदमियों का संवर्धन करने के लिए सार्क सदस्य देशों के वित्त और वाणिज्य मंत्रियों के साथ सार्क उच्च आर्थिक परिषद की स्थापना की गयी। (20-23 नवम्बर 2004 को इस्लामाबाद में हुई चौथी सार्क वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में, बांग्लादेश में होने वाले आर्थिक सहयोग सम्बन्धी समिति की 13वीं बैठक, जिसकी तारीख 2005 में तय की जाएगी, के दौरान अपनी टिप्पणियों को विचारार्थ सचिवालय को भेजने के लिए सदस्य राज्यों को कहा)।

iii) सार्क अवसंरचना कोष का गठन, जिसमें क्षेत्र की प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने के लिए लगभग 10 मिलियन अमरीकी डालर का संग्रह होगा। 20-23 नवम्बर 2004 को इस्लामाबाद में हुई चौथी सार्क वाणिज्य मंत्रियों की बैठक ने यह अनुमोदन किया कि प्रथमतया प्रस्ताव की वैचारिक व्यवहार्यता और संभाव्यता के बारे में सार्क वित्त की सलाह (केन्द्रीय बैकों में गवर्नरों का एक निकाय और सार्क के वित्त सचिव) ली जा सकती है।

iv) सदस्य देशों में राष्ट्रीय समितियों के गठन ने सार्क जिसे सामाजिक चार्टर के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के कार्यक्रमों को मानीटर तथा उनका उपाय करने और सार्क गरीबी उन्मूलन निधि की परियोजनाओं सहित सहयोगी गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं का संवर्धन करने के लिए एक-दूसरे के साथ सम्पर्क करने का प्रादेश दिया गया। (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सार्क समकक्षों के साथ सहयोग के लिए नोडल फोकल प्वाइंट के रूप में पहचान की गयी है)

v) टीबी और एचआईवी/एड्स के लिए सार्क जागरूकता वर्ष के एक भाग के तौर पर, परिषद ने टीबी और/अथवा एचआईवी/एड्स के क्षेत्र में" समर्पित सामुदायिक सेवा " के लिए सार्क युवा पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। भारत ने इस वर्ष सार्क देशों के विशेषज्ञों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं की बैठक की मेजबानी करने की पेशकश की और प्रत्येक सार्क देशों को चिकित्सा वाहन और चल जागरूकता यूनिटें भेजने की पेशकश किया। (इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विदेश मंत्रालय के परामर्श से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) द्वारा एक परियोजना तैयार की जा रही है।

vi) भारत ने सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण की पेशकश की है। (भारत ने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित के लिए प्रथम बैठक आयोजित करने के लिए सार्क सचिवालय से सार्क सदस्य देशों को उपयुक्त तारीख सुझाने (बताने) की पेशकश की है)।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (एसएएफटीए) के लिए बातचीत

साफ्टा को जनवरी से दिसम्बर 2004 के दौरान आयोजित 6 बैठकों से प्रगति देखने को मिली है। संवेदनशील सूची को स्पष्ट करने तथा मूल नियम (रूल्स ऑफ ओरिजिन) के अंतर को कम करने में प्रगति हुई है। फरवरी 2005 में होने वाली बैठक में कम विकसित कन्टैक्टिंग स्टेटों (एलडीसीएस-बांग्लादेश, भूटान, मालदीव तथा नेपाल) के लिए मुआवजे के तन्त्र पर एक वैचारिक पत्र पर चर्चा की जाएगी। तकनीकी सहयोग के लिए कम विकसित संविदाकारी राज्यों (एलडीसीएस) द्वारा किए गए अनुरोध को भारत, पाकिस्तान तथा श्री लंका द्वारा पूरा किया जाएगा। आशा है कि जनवरी 2006 तक साफ्टा को अस्तित्व में लाने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उन देशों को सक्षम बनाकर सभी मुद्दों को जनवरी 2005 तक हल कर लिया जाएगा। 1 जनवरी 2006 तक साफ्टा अस्तित्व में आ जाने से और वर्ष 2016 तक इसके पूर्ण प्रचालन से, हम 2015 तक कस्टमस यूनियन तथा 2020 तक एसएईयू को कार्यान्वित करने के मुद्देनजर सेवाओं और निवेश जैसे आर्थिक एकीकरण के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने में समर्थ होगें। सार्क उच्च आर्थिक परिषद की स्थापना के लिए जुलाई के मंत्रिस्तरीय बैठक में हमारा प्रस्ताव आर्थिक, व्यापार, वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से सम्बन्धित विचारों तथा पहलकदमियों को आगे बढ़ाने के विचार से किया गया था।

साफ्टा के सहारे 13वीं शिखर बैठक के दौरान व्यापार सुविधा उपायों पर हस्ताक्षर किए जाने की सम्भावना है। ये कस्टम मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहयोग, निवेश का संवर्धन तथा सुरक्षा, सार्क मध्यस्थता परिषद की स्थापना और दोहरे कराधान के परिहार एवं कर मामलों में पारस्पारिक प्रशासनिक सहयोग से सम्बन्धित हैं।

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

छठीं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 12-13 जून 2004 तक थिम्पू में हुई थी। वर्ष 2004-05 के थीम के तौर पर" जल प्रंबधन और संरक्षण " पर सहमति हुई थी। भारत ने भूटान में वानिकी संस्थान स्थापित किए जाने के लिए सहयोग की पेश की।

इसमें विशेष रूप से क्षेत्रीय सन्दर्भ में प्रदूषण नियन्त्रण के लिए पर्यावरण स्तर और पर्यावरण प्रबन्धन को सुव्यवस्थित बनाने वाली सार्क पर्यावरण कार्रवाई योजना का अनुसमर्थन किया गया। भारत ने " आपदा तैयारी और प्रशमन पर सूचना की साझेदारी " पर सार्क सचिवालय के माध्यम से एक संकल्पना पत्र प्रचालित किया जिस पर वर्ष 2005 में कभी-भी विशेषज्ञ दल की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा जो नवम्बर 2005 में ढाका में होने वाली सार्क पर्यावरण मंत्रियों की 7वीं बैठक में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। भारत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान, नई दिल्ली और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था के भीतर आपदा प्रबंधन के लिए सार्क केन्द्र की स्थापना करने के लिए उत्सुक हैं जो आपदा प्रबन्धन के लिए सार्क में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के तौर पर कार्य करेगा।

सार्क संचार मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 29-30 जून 2004 तक इस्लामाबाद में हुआ। इसमें डिजिटल डिवाइड को पाटने में आईसीटी की भूमिका पर जोर दिया गया। यह भी महसूस किया गया कि मानव संसाधन विकास कार्यक्रम पर क्षेत्र के भीतर प्रशिक्षण पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। दूर-संचार के क्षेत्र में उपयुक्त कार्य-निष्पादन के संकेतकों की आवश्यकता को इंगित किया गया। सम्मेलन में सूचना सोसाइटी के लिए विश्व शिखर बैठक (डब्ल्यूएसआईएस), ट्यूनिस और नवम्बर 2005 की सार्क सामान्य स्थिति अपनायी गई। सार्क संचार मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन, 2-4 फरवरी 2005 तक नई दिल्ली में, सार्क दूर-संचार विनिर्माता प्रदर्शनी-सह-फोरम (एसयूपीईआरसीओएम) के बाद आयोजित होना प्रस्तावित है।

संचार मंत्रियों की चौथी बैठक, आर्थिक सहयोग सम्बन्धी समिति (वाणिज्यि सचिवों की अगुवाई में) की 12वीं बैठक के ठीक बाद 22-23 नवम्बर 2004 तक आयोजित की गयी। बैठक में साफ्टा को 1 जनवरी 2006 तक अस्तित्व में लाने में समर्थ बनाने में साफ्टा के बकाया मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उच्च आर्थिक परिषद और सार्क आधारभूत ढांचा निधि तथा सार्क में क्षेत्रीय बहरूपात्मक परिवहन प्रणलियों पर प्रस्तावित अध्ययन के लिए भारतीय प्रस्तावों पर भी चर्चा की गयी जिसके लिए एडीबी ने वित्त-पोषण की पेशकश की है। श्री लंका की तरजीह सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) योजना के अन्तर्गत सार्क तथा आसियान देशों के सुपर रीजनल कुमुलेशन के लाभों को प्रदान करने के यूरोपीय आयोग को औपचारिक अनुरोध करने के श्री लंका के प्रस्ताव को उपयुक्त विशेषज्ञों वाली विशेष समिति को भेज दिया गया। उक्त समिति को उनकी जीएसपी योजनाओं के अन्तर्गत कुमुलेटिव रूल्स ऑफ ओरिजिन को स्वीकृत करने के लिए एक एसोसिएशन के तौर पर सार्क को मान्यता प्रदान करने के लिए यूएसए, कनाडा, जापान तथा स्विटजरलैण्ड से अपना औपचारिक अनुरोध करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए भी काम में लगाया गया था। मंत्रियों ने 13-18 दिसम्बर 2005 तक हांगकांग में होने वाले छठे डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के पूर्व मिलने की सहमति व्यक्त किया जबकि सदस्य देशों के स्थायी प्रतिनिधि साझी चिन्ता के मुद्दों पर सामंजस्यपूर्ण सार्क स्थिति को विकसित करने के लिए विचार करेगें।

तीसरी सूचना मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा, 11-12 नवम्बर 2003 तक की गयी। इस सम्मेलन में यह सहमति हुई कि मीडिया प्रोडक्सन, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण यूनिटों वाला सार्क सूचना केन्द्र, काठमान्डु में स्थापित किया जाना चाहिए। चौथी, सूचना मंत्रियों की बैठक पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, में 15-16 दिसम्बर 2004 तक आयोजित की जाएगी।

■■

दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशान्त

2

दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने महान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जुड़ावों को आगे बढ़ाते हुए भारत में अपनी पूर्वाभिमुख नीति में यथानिहित ध्येय के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया के साथ निकट संबंधों को प्रगाढ़ करने का काम जारी रखा । भारत की पूर्वाभिमुख नीति अब अपने द्वितीय चरण में प्रवेश कर गई है अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया से आगे बढ़कर प्रशांत क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। द्विपक्षीय रूप से उच्च स्तर की यात्राओं के नियमित आदान प्रदान और क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय स्तरों पर सम्पर्क समन्वय से नेताओं के बीच प्रभूत मात्रा में सहजता और परिचय बढ़ा है जिससे इन देशों के साथ हमारे संबंधों में नई गतिशीलता लाने में सहायता मिली है । इस क्षेत्र के साथ हमारे संपर्कों का चरम बिंदु तब प्राप्त किया गया जब 29-30 नवम्बर, 2004 तक आयोजित किए गए तृतीय भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह लाओ लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के वेनेशियान की यात्रा पर गए । दूसरी ओर से सिंगापुर के प्रधान मंत्री श्री गोह चोक तोंग ऐसे पहले शासन प्रमुख बने जिनका स्वागत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने किया । न्यूजीलैंड और मलेशिया के प्रधान मंत्रियों ने भी वर्ष के दौरान भारत की यात्रा की । न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री तो लगभग दो दशक के अंतराल के बाद भारत आए जबकि अन्य देशों की अपनी यात्राओं की तुलना में मलेशिया के प्रधान मंत्री सबसे लंबे समय की यात्रा पर भारत आए । भारत-आसियान तृतीय शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री सुशीलो बामबांग युधोयोनो, आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री महामहिम जॉन हावर्ड और सिंगापुर के प्रधान मंत्री महामहिम ली सिएंग लुंग के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं । भारत और आसियान देशों के विदेश मंत्री इस शिखर सम्मेलन से पहले पहली बार मिले । शिखर सम्मेलन में "भारत-आसियान शांति, प्रगति तथा साझी समृद्धि हेतु सहभागिता" पर हस्ताक्षर किए गए । 06 जनवरी, 2005 को जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा भूकंप और सूनामी की तबाही के बाद बुलाए गए आसियान के नेताओं के एक विशेष शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया । तृतीय भारत-आसियान व्यापारिक शिखर सम्मेलन 19 अक्तूबर को नई दिल्ली में और 20 से 21 अक्तूबर, 2004 तक चेन्नई में आयोजित किया गया जिसमें आसियान के सभी देशों से बड़ी संख्या में सहभागी आए । प्रधान मंत्री ने 22 नवम्बर, 2004 को भारत आसियान कार रैली को हरी झंडी दिखाई और 29 नवम्बर, 2004 को वेनेसियान में आसियान के नेताओं ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई । इस वर्ष के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के उन देशों के नेताओं के साथ नए सिरे से संपर्क बनाए गए जिनमें सत्ता परिवर्तन हुआ अर्थात इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर । इस अवधि के दौरान की गई अनेक मंत्रि स्तरीय यात्राओं से इस क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाने में और भी मदद मिली।

जहां तक प्रशांत क्षेत्र का संबंध है तो भारत ने अगस्त, 2004 में समोआ में आयोजित पी.आई.एफ. देशों के साथ वार्ता बैठकों में दूसरी बार हिस्सा लिया । भारत ने अपने इस इरादे को दोहराया कि वह आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों की अर्थ व्यवस्थाओं के विकास में सहायता देगा । इस क्षेत्र के देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूती तथा प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिला । जैसा कि हमारी पूर्वाभिमुख नीति के प्रथम एवं द्वितीय चरण में अनुध्यात है, भारत दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को उचित महत्व देता आ रहा है ।

आस्ट्रेलिया

इस वर्ष के दौरान भी भारत और आस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंध विकसित होकर मजबूत भागीदारी की दिशा में बढ़ते रहे। संघीय संसद में गठबन्धन की विजय और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड की सत्ता में वापसी से भारत और आस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ोत्तरी के लिए किए जा रहे प्रयासों में निरंतरता आई और उन्हें मजबूती मिली ।

भारत से आस्ट्रेलिया और आस्ट्रेलिया से भारत में इस अवधि के दौरान मंत्रिस्तरीय यात्राएं जारी रहीं । बिजली मंत्री श्री पी एम सईद ने सिडनी में आयोजित 19वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए 6-10 सितम्बर तक आस्ट्रेलिया की यात्रा की । विदेशों में भारतीय मामलों के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जगदीश टाइटलर ने आस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय से मुलाकात करने और जनवरी 2005 में मुम्बई में आयोजित किए जा रहे तीसरे प्रवासी भारतीय दिवस को बढ़ावा देने के लिए 26 अक्तूबर से 1 नवम्बर तक आस्ट्रेलिया की यात्रा की । श्रीमती प्रतिभा सिंह, सांसद , श्रीमती कृष्णा तीरथ, सांसद, श्रीमती जयाबेन ठक्कर, सांसद और डॉ. श्रीमती चन्द्र कला पाण्डे, सांसद की सदस्यता वाले एक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल ने 29-30 जून , 2004 तक आयोजित किए गए "द्वितीय एशियाई महिला सांसद एवं मंत्री सम्मेलन" में हिस्सा लेने के लिए केनबरा की यात्रा की । आस्ट्रेलियाई संघीय चुनावों के प्रेक्षक के रूप में चुनाव आयुक्त श्री बी बी टण्डन 3-10 अक्तूबर तक आस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए ।

आस्ट्रेलिया से क्वींसलैण्ड के प्रीमियर श्री पीटर बियेती ने एक व्यापारिक शिष्टमण्डल के साथ सितम्बर में भारत की यात्रा की । अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बंगलूर में क्वींसलैण्ड सरकार के व्यापार कार्यालय का उद्घाटन किया । दक्षिण आस्ट्रेलिया के प्रीमियर श्री माईक रेन अक्तूबर में एक व्यापारिक शिष्टमण्डल के साथ भारत की यात्रा पर आए । विक्टोरिया की राज्य सरकार की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा लघु व्यापार मंत्री सुश्री मार्था टॉमसन, अक्तूबर में भारत की यात्रा पर आईं । न्यू साऊथ वेल्स के प्रीमियर श्री बॉब कार एक विशाल व्यापारिक शिष्टमण्डल के साथ नवम्बर में भारत की यात्रा पर आए ।

इस वर्ष के दौरान भारत आस्ट्रेलिया व्यापार संबंध वृद्धि की ओर अग्रसर रहे । विशाल व्यापारिक शिष्टमण्डलों के साथ भारत की यात्रा पर आए क्वींसलैण्ड, न्यू साऊथ वेल्स और दक्षिण आस्ट्रेलिया के प्रीमियरों के दौरे के समय भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया । 21 अप्रैल, 2004 को भारतीय स्टेट बैंक के शाखा कार्यालय का उद्घाटन किया गया । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आस्ट्रेलिया में भारतीय कम्पनियों का निवेश बढ़ा । दीपक उर्वरक एवं पेट्रो रसायन निगम लि. ने एक संयुक्त उपक्रम शुरू किया और ओ एन जी सी विदेश लि. को पश्चिमी आस्ट्रेलिया में तेल एवं गैस की खोज के लिए एक संभावनापूर्ण ब्लॉक उपलब्ध कराया गया । प्रमुख आस्ट्रेलियाई बैंकों ने भारत के लिए विशेष निवेश निधियां शुरू कीं । कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव उस समय आया जब पादप संगरोध संबंधी मुद्दों पर वार्षिक विचार विमर्श शुरू किए गए क्योंकि इन विचार विमर्शों से दोनों देशों के बीच कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा ।

इस वर्ष के दौरान प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सहयोग का मुद्दा भी सक्रिय बना रहा । इस वर्ष आस्ट्रेलिया की नौ सेना, थल सेना और प्रतिरक्षा बल के प्रमुखों ने भारत की यात्रा की । दोनों देशों के रक्षा सेवाओं के बीच बढ़ रहे सहयोग का एक अन्य पक्ष यह रहा कि नौ सेना के जहाज एक दूसरे देश में गए ।

ब्रुनेई दार उस्सलाम

ब्रुनेई दार उस्सलाम के साथ द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्री पूर्ण बने रहे । राजनैतिक , वाणिज्यिक , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा खेलों के मुद्दों पर महत्वपूर्ण सम्पर्क वार्ताएं हुईं ।

मंत्रालय में अपर सचिव (आई ओ) डॉ. शील कान्त शर्मा, विदेश मंत्री के विशेष दूत के रूप में 5-7 मई , 2004 तक ब्रुनेई की यात्रा पर गए और उन्होंने ए आर एफ से जुड़े मुद्दों पर 6 मई , 2004 को ब्रुनेई के विदेश मंत्री राजकुमार मुहम्मद बोलकइया के साथ बातचीत की ।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चार बैज्ञानिकों के एक दल ने 20 सितम्बर, 2004 को ब्रुनेई दार उस्सलाम में अपने टी टी सी केन्द्र से भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जी एस एल वी) के प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक अनुवीक्षण किया । इस केन्द्र की स्थापना, भारत सरकार और ब्रुनई दार उस्सलाम की सरकार के बीच अन्तरिक्ष के क्षेत्र में अगस्त, 1997 में हस्ताक्षरित एक समझौते के अन्तर्गत की गई थी ।

ब्रुनेई के विदेश उप मंत्री पेहिन हाजी अवांग मोहम्मद अली, 19 अक्तूबर को नई दिल्ली में और 20-21 अक्तूबर तक चेन्नै में आयोजित भारत आसियान तृतीय व्यापार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चार सदस्यों के एक शिष्टमण्डल के मुखिया के रूप में भारत की यात्रा पर आए ।

गुवाहाटी से बाताम (इण्डोनेशिया) तक की प्रथम भारत आसियान मोटर कार रैली में तीन दलों ने हिस्सा लिया जिनमें कुल 12 सदस्य शामिल थे ।

कम्बोडिया

वर्ष 2004-2005 के दौरान भारत और कम्बोडिया के बीच द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत हुए तथा इनमें विविधता आई। सचिव (ए एन ए) श्री आर एम अभयंकर 6 मई , 2004 को कम्बोडिया की यात्रा पर गए और उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत के लिए विदेश मंत्री से मुलाकात की ।

100 लाख अमेरिकी डॉलर की भारत सरकार की ऋण श्रृंखला का आंशिक उपयोग करते हुए मेसर्स किरलोस्कर ब्रदर्स लि. ने कम्बोडिया के जल संसाधन एवं मौसम विज्ञान मंत्रालय को लगभग 50 लाख अमेरिकी डॉलर की कीमत के 240 सिचाई पंपों की आपूर्ति की । शेष ऋण श्रृंखला का उपयोग पश्चिमी बराई सिचाई परियोजना के लिए किया जाना है । वैपकॉस इण्डिया लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश श्री डी दत्ता ने इस परियोजना के कार्यान्वयन चरण हेतु तौर तरीकों के बारे में कम्बोडियाई प्राधिकारियों से चर्चा करने के लिए 17-19 नवम्बर, 2004 तक कम्बोडिया की यात्रा की ।

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ओडिसी नृत्यांगना सुश्री रंजना गौहर, विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग द्वारा आयोजित “पत्थर में अमृत” नामक डाक्यूमेन्टरी फिल्म को फिल्माए जाए के संबंध में एक 5 सदस्यीय समूह के साथ 16-27 अप्रैल , 2004 तक कम्बोडिया की यात्रा पर गईं । सुश्री गौहर ने कम्बोडिया की संस्कृति एवं ललित कला मंत्री एच आर एच राजकुमारी नोरोदम बूपादेवी से मुलाकात की । इस फिल्म के फिल्मांकन के एक हिस्से के रूप में सुश्री गौहर ने एक कम्बोडियाई अप्सरा नर्तकी के साथ प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर के सामने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया । कम्बोडिया के संस्कृति एवं ललित कला मंत्रालय के सहयोग से भारतीय राजदूतावास ने 19 अप्रैल, 2004 को एक संगीत एवं नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सुश्री गौहर के ओडिसी नृत्य के साथ कम्बोडियाई कलाकारों द्वारा भी नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए ।

आसियान एकीकरण कार्यक्रम के लिए पहलकदमी के अन्तर्गत भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि कम्बोडिया के नोम पेन्ह

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री हामिद करज़ई से हाथ मिलतो हुए, नई दिल्ली, 24 फरवरी 2005।

*29 नवम्बर 2004 को लाओस,
वियतनाम में आसियान-शिखर सम्मेलन
के साथ-साथ प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह
ने आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री
श्री जॉन होवर्ड
के साथ मुलाकात की।*

नगर में कम्बोडिया भारत उद्यमिता विकास केन्द्र की स्थापना की जाए । भारत उद्यमिता विकास केन्द्र, अहमदाबाद के निदेशक डॉ. दिनेश अवस्थी की अगुवाई वाले एक प्रतिनिधि मण्डल ने उद्यमिता मूल्यांकन कार्यशाला संचालित करने और कम्बोडिया भारत उद्यमिता विकास केन्द्र के लिए निदेशक/ प्रशिक्षकों तथा अन्य प्रमुख अधिकारियों के चयन के लिए 7-11 जून, 2004 तक नोम पेन्ह का दौरा किया ।

केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद से दो प्राध्यापकों के एक दल ने कम्बोडिया की शाही सरकार के अधिकारियों के लिए आधारिक अंग्रेजी भाषा एवं संप्रेषण कौशल पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए 28 जून से 23 जुलाई, 2004 तक नोम पेन्ह का दौरा किया । यह दौरा "आसियान एकीकरण कार्यक्रम हेतु पहलकदमी" नामक कार्यक्रम के अधीन भारत और सिंगापुर का एक संयुक्त प्रयास था ।

नवम्बर , 2002 में अपनी कम्बोडिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने "मीकांग गंगा सहयोग कार्यक्रम" के अन्तर्गत सीम रीप में पारम्परिक एशियाई वस्त्र म्यूजियम की स्थापना के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर की स्थापना राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की थी । कम्बोडिया सरकार ने सीम रीप में एक प्रमुख स्थान पर म्यूजियम की स्थापना के लिए एक एकड़ का एक भूखण्ड आबंटित कर दिया है । इस परियोजना का समन्वय अपसरा प्राधिकरण और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा किया जा रहा है । म्यूजियम की स्थापना के लिए विशेषज्ञों की दूसरी बैठक 29 जून, 2004 को हुई और इसमें कम्बोडिया , लाओस, म्यांमार, थाईलैण्ड और वियतनाम के शिष्टमण्डल शामिल हुए । म्यूजियम के निर्माण एवं स्थापना के लिए बैठक में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् तथा अपसरा प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

अप्रैल्, 2002 में अपनी कम्बोडिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 5 एम आई ई सूचना प्रौद्योगिकी क्योस्क कम्बोडिया को भेंट स्वरूप देने की घोषणा की थी । वर्ष 2004 के दौरान एन आई आई टी लि. ने नोम पेन्ह , सीमरीप , ताकेओ तथा कान्दाल में 5 क्योस्क स्थापित कर दिए । ये क्योस्क संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं और स्कूलों तथा जनता की ओर से इनके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ।

कम्बोडिया के पर्यटन मंत्री श्री ले प्रोहास की अगुवाई में एक शिष्टमण्डल पर्यटन राज्य मंत्री के आमंत्रण पर 19-21 अक्तूबर, 2004 तक हुए भारत आसियान तृतीय व्यापारिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा के लिए भारत की यात्रा पर आया ।

विश्वास बहाली के उपायों पर प्रथम ए आर एफ अन्तर्सत्रीय समर्थन समूह की बैठक में हिस्सा लेने के लिए तीन सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मण्डल 26-29 अक्तूबर, 2004 तक कम्बोडिया की यात्रा पर गया ।

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के उपाध्यक्ष और विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव तथा कम्बोडिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत श्री एल एल मेहरोत्रा ने नोमपेन्ह शाही विश्वविद्यालय में कम्बोडिया सामाजिक सांस्कृतिक अनुसंधान के सातवें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 14-18 नवम्बर, 2004 तक कम्बोडिया की यात्रा की और कम्बोडिया में शान्ति , लोकतंत्र तथा स्थायित्व के प्रति संयुक्त राष्ट्र के योगदान पर एक व्याख्यान दिया । उन्होंने कम्बोडिया के पितृ सम्राट महामहिम संदेश नोरोदोम सिंहानुक, सीनेट के अध्यक्ष, महामहिम श्री ची सिम, राष्ट्रीय असेम्बली के प्रथम उपाध्यक्ष महामहिम श्री हेंग सामरिन, महामहिम श्री सारखेंग तथा एच आर एच राजकुमार नोरोदोम श्रीयुध उप प्रधानमंत्री और सह गृहमंत्री , महामहिम उप प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् के प्रभारी मंत्री श्री सोक आन तथा उप प्रधानमंत्री और विदेशी मामलों और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के मंत्री महामहिम श्री होरनामहोंग से भी मुलाकात की ।

प्रथम भारत आसियान कार रैली 4-7 दिसम्बर 2004 तक कम्बोडिया से होकर गुजरी । इस रैली का कम्बोडिया के उच्चाधिकारियों ने समारोहपूर्वक स्वागत किया और इसे विदा किया । कम्बोडिया में रैली के कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण भारत आसियान पर्यटन संध्या का कार्यक्रम था जिसके बाद कम्बोडिया के पर्यटन मंत्रालय की ओर से रात्रि भोज का आयोजन किया गया । इस समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय असेम्बली के अध्यक्ष एच आर एच राजकुमार नोरोदोम रणरिद्ध ने की और उप प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय सह रक्षा मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री महामहिम श्री तिया बान ने , पर्यटन मंत्री महामहिम श्री ले प्रोहास ने इसे संबोधित किया । रैली के प्रतिभागियों के समक्ष एक भव्य सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें एच आर एच राजकुमारी बूपादेवी के नृत्य निर्देशन में अनेक नृत्य कार्यक्रम भी शामिल थे ।

बावेत से लेकर पोईपेत तक के पूरे रास्ते में इस कार रैली का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कम्बोडियाई जनता एकत्र हुई । रैली के गुजरने के रास्ते पर भारत और आसियान के देशों के झण्डे लहराते हुए विद्यार्थी कतारबद्ध खड़े थे । पर्यटन राज्य मंत्री महामहिम डॉ. तोंग खों 22 नवम्बर, 2004 को गुवाहाटी में भारत आसियान कार रैली के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए 20-23 नवम्बर, 2004 तक भारत की यात्रा पर आए ।

सी. राजगोपालाचारी द्वारा रचित रामायण के खमेर रूपान्तर (खमेर भाषा में डॉ. तोन हेन द्वारा इसका अनुवाद किया गया है) का विमोचन कम्बोडिया की शाही सरकार में उप प्रधानमंत्री एवं सह गृह मंत्री महामहिम संदेश नोरोदोम श्रीबुध द्वारा नोम पेन्ह में 16 दिसम्बर, 2004 को किया गया ।

भारत के पुरातत्व विभाग में अपर सचिव एवं महानिदेशक श्री सी बाबू राजीव यूनेस्को-आई सी सी प्लीनरी सैशन में हिस्सा लेने के लिए और सीमरीप में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण की "ता प्रोम बहाली परियोजना" के बारे में बात चीत के लिए 15-18 दिसम्बर, 2004 तक कम्बोडिया की यात्रा पर गए ।

जनवरी से मार्च , 2005 के दौरान संभावित महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

- विदेश मंत्री की कम्बोडिया यात्रा
- नोमपेन्ह में भारत कम्बोडिया संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक
- पर्यटन राज्य मंत्री की कम्बोडिया यात्रा
- पर्यटन संबंधी भारत कम्बोडिया संयुक्त कार्यदल की दूसरी बैठक कम्बोडिया के सीम रीप नगर में आयोजित की जानी है ।

फिजी

विभिन्न पहलकदमियों और उच्चस्तरीय यात्राओं के परिणामस्वरूप भारत और फिजी के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं ।

फिजी के बीमार चीनी उद्योग के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए भारत सरकार ने एक शर्करा प्रौद्योगिकी मिशन भेजा है और चार चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए भारत से मशीनरी/सेवाएं आयात करने हेतु फिजी चीनी निगम को आसान शर्तो पर ऋण श्रृंखला उपलब्ध कराने पर भी भारत सरकार विचार कर रही है । भारत सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनओं के अन्तर्गत शैक्षिक/विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए फिजी के 34 नामितियों को प्रतिनियुक्त किया गया है । भारत द्वारा दी जा रही सहायता को व्यापक तौर पर सराहा जा रहा है ।

भारत सरकार ने सूवा में अपना सांस्कृतिक केन्द्र फिर से खोल देने के साथ साथ लुआतका में एक उपकेन्द्र भी खोला है । फिजी के ये सांस्कृतिक केन्द्र सांस्कृतिक सौहार्द और क्षेत्र में समझबूझ को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे । भारत ने इस सांस्कृतिक केन्द्र में एक वर्ष की अवधि के लिए तीन कलाकारों को प्रतिनियुक्ति किया है ।

कई वर्षों के अन्तराल के बाद भारत और फिजी के बीच अनेक उच्चस्तरीय यात्राओं का आदान प्रदान हुआ है जिनसे हम दोनों देशों के बीच बेहतर समझ विकसित हुई है । भारत से की गई यात्राओं में शामिल हैं - राष्ट्रमण्डल की महिला मामलों की मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए मई में एक 2 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डल की यात्रा, पर्यावरण एवं विकास संबंधी एशिया प्रशान्त सांसद सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगस्त में एक 6 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डल की यात्रा और वर्ष, 2005 के प्रवासी भारतीय दिवस को बढ़ावा देने के लिए नवम्बर में प्रवासी भारतीय मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की यात्रा ।

फिजी से एक 7 सदस्यीय आई टी सी सहभागिता विकास मिशन ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास हेतु तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए अगस्त में भारत की यात्रा की। फिजी सशस्त्र सेनाओं के कमान्डर "प्रशान्त क्षेत्र की सेनाओं के प्रबन्धन" पर संगोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए सितम्बर में भारत की यात्रा पर आए ।

इण्डोनेशिया

इण्डोनेशिया, दक्षिणपूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है और रणनीतिक रूप से हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी भी है जिसके साथ हमारी समुद्री सीमा मिली हुई है । इण्डोनेशिया के साथ भारत के संबंध इस वर्ष के दौरान और भी व्यापक तथा सघन हुए। हमारे संबंधों का अन्तर्भूत तत्व एशिया के विशालतम बहुधर्मी लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझा मान्यताएं हैं और एक दूसरे की सफलता एवं समृद्धि में हम एक दूसरे के साझीदार हैं ।

भारत की तरह इण्डोनेशिया में भी वर्ष, 2004 चुनावी वर्ष रहा। इण्डोनेशिया में अप्रैल से सितम्बर, 2004 तक संसद के और राष्ट्रपति के सुसंठित और शान्तिपूर्ण चुनाव हुए जिसे लोकतंत्र में इण्डोनेशिया के प्रवेश को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में मान्यता मिली है । दीर्घकाल से स्थायी लोकतंत्र के रूप में भारत ने इण्डोनेशिया में एक नए नेतृत्व को सत्ता का स्थिर लोकतांत्रिक हस्तांतरण का स्वागत किया। हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने ही 20 अक्तूबर, 2004 को इण्डोनेशिया में राष्ट्रपति का पदभार संभालने वाले महामहिम सूसिलो बामबांग युधोयोनो को बधाई दी और इण्डोनेशिया के साथ हमारे साझा मूल्यों एवं चुनौतियों पर आधारित अधिक निकट संबंधों को पोषित करने की इच्छा प्रकट की ।

वर्ष 2004 में वार्षिक शिखर स्तरीय संपर्क की परम्परा इस वर्ष भी बनाए रखी गई और तदनुसार प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति डॉ. सुसिलो बामबांग युधोयोनो 28 नवम्बर, 2004 को तृतीय भारत आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर वेनेशियान में मिले । 2003-2004 के दौरान जब इस क्षेत्रीय समूह की अध्यक्षता इण्डोनेशिया के पास थी तो इस दौरान आसियान के साथ भारत के संबंधों में तेजी से प्रगति हुई जिसके परिणामस्वरूप 30 नवम्बर , 2004 को "आसियान भारत शान्ति, प्रगति एवं साझा समृद्धि हेतु साझेदारी" के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए ।

विदेश मंत्री ने 30 जून से 2 जुलाई, 2004 तक जकार्ता में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में हिस्सा लिया। 2 जुलाई, 2004 को आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक के समय ही अपने इण्डोनेशियाई समकक्ष डॉ एन हसन वीरायुध के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की गई । विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संयुक्त आयोग की अगली बैठक के लिए इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री को नई दिल्ली का दौरा करने का आमंत्रण दिया। यह बैठक 2005 के प्रारम्भ में आयोजित की जानी अपेक्षित है ।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में इण्डोनेशिया के साथ सहयोग के बारे में एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन को 2 जुलाई, 2004 को अन्तिम रूप दिया गया । इस समझौता ज्ञापन के अधीन स्थापित संयुक्त कार्यदल द्विपक्षीय संयुक्त आयोग के अधीन कार्य करेगा ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ ने जकार्ता में 5

सितम्बर, 2004 को आयोजित "तृतीय भारत आसियान आर्थिक परामर्श बैठक" में हिस्सा लिया । अपने इण्डोनेशियाई समकक्ष के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों ही पक्ष द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक एवं निवेश संबंधों में और तेजी लाने के लिए एक जुट होकर काम करने पर सहमत हुए ।

इण्डोनेशिया के एक व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल ने दिल्ली/ चेन्नै में 19 से 21 अक्तूबर, 2004 तक आयोजित तृतीय भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भागीदारी की ।

रक्षा , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी सहयोग एवं संस्कृति के क्षेत्र में भारत और आसियान के बीच में क्षैत्रीय एवं कार्यात्मक सहयोग में इस वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के एक शिष्टमण्डल ने 16 से 21 मई , 2004 तक इण्डोनेशिया की यात्रा की । इस शिष्टमण्डल ने इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री , टी एन आई चीफ , रक्षा महासचिव और एन डी सी की इण्डोनेशियाई समकक्ष संस्था लेमहेनास के गवर्नर से मुलाकात की । सितम्बर , 2004 के महीने में "इण्डोनेशिया भारत समन्वित संयुक्त नौसेना चौथी छमाही गश्त" संचालित की गई । मई से नवम्बर , 2004 तक आठ भारतीय नौसैनिक जहाजों ने इण्डोनेशियाई बंदरगाहों की सदभावना यात्रा की । इन यात्राओं ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच निकट सम्पर्क विकसित करने के साथ साथ दोनों देशों के बीच अन्तरण अभ्यास चलाए जाने के अवसर भी प्रदान किए । भारतीय सशस्त्र सेनाओं और टी एन आई के बीच सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में दोनों ओर से आदान प्रदान इस वर्ष भी जारी रहा । वर्ष 2004-2005 के दौरान आईटैक-। योजना के अन्तर्गत टी एन आई के 14 अधिकारियों के भारत में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने की संभावना है ।

आईटैक, कोलम्बो योजना तथा जी सी एस एस छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन मानव संसाधन के विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र में इण्डोनेशिया को भारतीय सहायता इस वर्ष के दौरान बढ़ाई गई और वृद्धि के रूप में आईटैक के अन्तर्गत कुल 78 प्रशिक्षण स्लॉट , कोलम्बो योजना के अन्तर्गत 38 और जी सी एस एस योजनाओं के अन्तर्गत 20 स्लॉट उपलब्ध कराए गए । इन स्लॉटों का पूरा पूरा उपयोग किया गया ।

3.08 करोड़ रूपए की एक आईटैक परियोजना के रूप में जकार्ता में निर्माण क्षेत्र के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र पर कार्य इस वर्ष के दौरान कार्यान्वयन एजेन्सी अर्थात एन एस आई सी ने शुरू किया । यह केन्द्र 2005 के प्रारम्भ में चालू हो जाएगा।

हमारे द्विपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग का एक महत्वपूर्ण घटक है - शान्तिपूर्ण उद्देश्यों हेतु अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन और इसका इण्डोनेशियाई समकक्ष संगठन लापान , उपग्रहों और भूस्थैतिक प्रक्षेपण यानों के लिए इण्डोनेशिया के पापुआ राज्य के बेआक में एक अंतरिक्ष टैलीमीटरी , ट्रैकिंग एवं कमाण्ड जमीनी स्टेशन का संयुक्त रूप से संचालन कर रहा है । इस महत्वपूर्ण केन्द्र पर भौतिक एवं प्रौद्योगिकीय अवसंरचना का विस्तार किया गया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से 8,75,000 अमेरिकी डॉलर के निवेश से इस वर्ष के दौरान एक द्वितीय जमीनी स्टेशन (बेआक टी टी एण्ड सी - ।।) की स्थापना की गई ।

जकार्ता स्थिति जवाहर लाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की एक शाखा बाली में अक्तूबर, 2004 में खोली गई जिसे इण्डोनेशिया में हमारी सांस्कृतिक मौजूदगी के प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है । भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के सहयोग से हमारे मिशन ने जवाहर लाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के क्रियाकलापों में बढ़ोत्तरी और एक ऐसे देश के साथ अपने सांस्कृतिक संपर्कों को व्यापक बनाना जारी रखा जिसके साथ हमारे संबंध एक ऐतिहासिक तथ्य हैं ।

भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष, 2004 के दौरान 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का हुआ है जिसे कि एक भारी वृद्धि समझा जाता है । वर्ष के दौरान इण्डोनेशिया में एक टोल रोड के निर्माण के लिए भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी इरकोन ने एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का ठेका प्राप्त किया और रेलवे पुनर्वास तथा लोकोमोटिव्स को पट्टे पर देने के क्षेत्रों में व्यापारिक अवसरों का पता लगाया ।

लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य

समीक्षाधीन वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण 29-30 नवम्बर, 2004 को लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के वेनेशियान शहर में आयोजित भारत आसियान तीसरा शिखर सम्मेलन रहा । यह बैठक दसवें आसियान शिखर सम्मेलन, दूसरे आसियान व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन और पहली बार आयोजित की गई भारत आसियान कार रैली के साथ ही हुई।

भारत आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 29 नवम्बर, 2004 को लाओ के राष्ट्रपति महामहिम खामते साइफानदोन से मुलाकात की और उनके साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की । इससे पहले 28 नवम्बर, 2004 को प्रधानमंत्री ने अपने लाओ समकक्ष प्रधानमंत्री महामहिम बाउनहांग वोराचित के साथ मुलाकात की । लाओ के प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के साथ विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के प्रति अपने देश का समर्थन दोहराया ।

27 नवम्बर, 2004 को भारत के विदेश मंत्री और लाओ के शिक्षा मंत्री ने "लाओ भारत उद्यमिता विकास केन्द्र" का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया । यह केन्द्र लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य में उद्यमिता विकास का अग्रदूत बनेगा और नए व्यवहार्य तथा प्रतिस्पर्धी उद्यमों के सृजन में तथा विद्यमान उद्यमों को मजबूत बनाने में सहायता करने वाला एक उत्कृष्टता केन्द्र बनेगा ।

FINISH
1st ASEAN - INDIA CAR RALLY 2004
NETWORKING PEOPLE AND ECONOMIES
DEVELOPMENT • FRIENDSHIP • HARMONY • PEACE
BATAM ISLAND
SPONSORS
BY 5574

30 नवम्बर 2004 को वियनटाइने में लाओ पी डी आर के प्रधान मंत्री महामहिम बोनहेंग वोराचित और भारत के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह कार रैली को झंडा हिला कर रवाना करते हुए। चित्र में आसियान देशों के नेतागण भी हैं।

इंडोनेशिया के विदेश मंत्री तथा असम के मुख्यमंत्री बताम द्वीप, इंडोनेशिया में भारत-आसियान कार रैली की स्माप्ति रेखा पर झंडा गिराते हुए।

भारत की ओर से विदेश मंत्री ने और लाओ पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण एजेन्सी के अध्यक्ष प्रो. डॉ. बाउनतीम फेसामे ने लाओ भारत सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का भी संयुक्त रूप से उद्घाटन 28 नवम्बर को किया । यह महत्वाकांक्षी परियोजना आर्थिक प्रगति , गरीबी घटाने, रोजगार पैदा करने, संसाधनों के सतत् उपयोग आदि के लिए डिजिटल अवसरों को मजबूत बनाने में लम्बे समय तक अपना योगदान देती रहेगी।

भारत आसियान प्रथम कार रैली को हमारे प्रधानमंत्री और लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री ने 30 नवम्बर को समारोहपूर्वक हरी झंडी दिखाई ।

जुलाई , 2003 से तीन वर्ष की अवधि के लिए आसियान में भारत के लिए समन्वयक देश के रूप में लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य ने इस क्षेत्रीय संगठन के साथ भारत के वृहत्तर एकीकरण में सक्रिय भूमिका निभाई है । लाओस ने 1 जुलाई, 2004 से आसियान की अध्यक्षता का भार भी ग्रहण कर लिया है । 38वीं आसियान स्थायी समिति के आगामी अध्यक्ष के रूप में लाओस के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री महामहिम सोमसावत लैंगसावद ने सद्भाव एवं सहयोग सन्धि में भारत के शामिल होने को महत्व दिया ।

115 केवी ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण के लिए लाओस की विद्युत कम्पनी के साथ एक भारतीय कम्पनी ने आपूर्ति के ठेके पर हस्ताक्षर किए । इस आपूर्ति का वित्तपोषण एक करोड़ अमेरिकी डॉलर की भारत सरकार की ऋण श्रृंखला के माध्यम से किया जाएगा । ऋण पत्रों की स्थापना 30 जून, 2004 की निर्धारित तिथि के अन्दर ही कर ली गई।

वेनेशियान में एक विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल के निर्माण के लिए भी भारत प्रतिबद्ध है । सितम्बर, 2004 में इस परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट का काम एच एस सी सी (इंडिया) लि. ने पूरा कर लिया है । इस प्रस्तावित विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल से हमारे पारम्परिक एवं ऐतिहासिक जुड़ावों में मजबूती आएगी और जनता का परस्पर सम्पर्क बढ़ेगा ।

मलेशिया

भारत के मलेशिया के साथ संबंधों में एक नए घटनाक्रम के रूप में सभी क्षेत्रों में और खास तौर से राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अप्रैल से नवम्बर, 2004 की अवधि के दौरान सकारात्मक गतिविधियों की प्रक्रिया शुरू हुई । मार्च , 2004 में हुए आम चुनाव में 90 प्रतिशत से अधिक संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त करके ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त करने वाले अब्दुल्ला अहमद बदावी ने दिसम्बर , 2004 में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली यात्रा पर भारत आने का निर्णय लिया। आशा है कि प्रधानमंत्री बदावी एक उच्चाधिकार-प्राप्त शिष्टमण्डल के साथ भारत आएंगे जिसमें अनेक कैबिनेट मंत्री और व्यापार क्षेत्र की हस्तियां शामिल होंगी ।

अवसंरचना के क्षेत्र में, खास तौर से सड़क निर्माण , बंदरगाह, विमानपत्तन तथा उर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग अनेक उच्चस्तरीय यात्राओं के आलोक में लगातार मजबूत हुआ है। मलेशिया के निर्माण मंत्री श्री एस सामी वेलु ने वर्ष , 2004-2005 के पहले आठ महीने के दौरान ही दो बार भारत की यात्रा की है । 20 जून, 2004 को अपनी पहली यात्रा के दौरान श्री एस सामी वेलु ने सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री श्री टी आर बालू और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्री ऑस्कर फर्नान्डीस से मुलाकात की । वे, विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह और वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम से 23-24 अगस्त, 2004 को अपनी दूसरी यात्रा के दौरान मिले । उनकी तीसरी यात्रा 1-2 दिसम्बर, 2004 को निश्चित है जिसके दौरान वे विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह और सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री श्री टी आर बालू से मिलेंगे ।

बिजली मंत्री श्री पी एम सईद ने 11-12 सितम्बर, 2004 को मलेशिया की यात्रा की और मलेशिया के निर्माण मंत्री श्री एस सामी वेलु से मुलाकात की ।

मुम्बई में 7-9 जनवरी, 2005 तक आयोजित किए जा रहे तीसरे प्रवासी भारतीय दिवस में मलेशिया से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीय मामलों के राज्य मंत्री श्री जगदीश टाइटलर ने 24-26 सितम्बर, 2004 तक क्वालालम्पुर की यात्रा की ।

आसियान के देशों में मलेशिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होने वाला है । दोनों देशों के बीच दोनों ओर से द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2004-2005 में 4.2 बिलियन अमेरीकी डॉलर का होने की संभावना है । अप्रैल-सितम्बर, 2004 की अवधि के दौरान भारत से निर्यात में 114 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2003-2004 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 297 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में बढ़कर 636 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है । इसी अवधि के दौरान मलेशिया से भारत को आयात में भी 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और यह 2004-2005 में 1481 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है जबकि वर्ष 2003-2004 में यह निर्यात 1228 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था ।

सघन द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को प्रतिबिंबित करते हुए नई दिल्ली और चेन्नै में 18-20 अक्तूबर, 2004 तक आयोजित किए गए भारत आसियान तृतीय व्यापारिक शिखर सम्मेलन में भी, पिछले दोनों शिखर सम्मेलनों की भांति आसियान के सभी देशों में से मलेशिया से सबसे बड़े शिष्टमण्डल ने हिस्सा लिया । चेन्नै में इस शिष्टमण्डल की अगुवाई मलक्का के मुख्यमंत्री दातुक सेरी मुहम्मद अली मुहम्मद रूस्तम ने की ।

भारत और मलेशिया ने विभिन्न बहु पक्षीय संस्थाओं और मंचों में एक दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करके आपसी समझबूझ और सहयोग का प्रदर्शन किया ।

इस अवधि के दौरान रक्षा संबंधों को मजबूत बनाते हुए दोनों ही देशों से उच्चस्तरीय अधिकारियों ने एक दूसरे देश का दौरा किया । भारत की ओर से उप थल सेना अध्यक्ष ले. जनरल

पी पी एस भण्डारी ने 12-16 अप्रैल , 2004 तक “रक्षा सेवा एशिया प्रदर्शनी , 2004” के संबंध में मलेशिया की यात्रा की और मलेशियाई पक्ष की ओर से शाही मलेशियाई नौसेना के प्रमुख एडमिरल दातुक मुहम्मद अनवर बेन हाजी मुहम्मद नूर 6-9 सितम्बर, 2004 तक भारत की यात्रा पर आए । भारतीय तटरक्षक बल के दो जहाजों - सी जी एस सागर और सी जी एस विवेक ने 9-13 अप्रैल, 2004 तक मलेशिया की यात्रा की जबकि मलेशिया के दो जहाजों - के डी लेक्यू और के डी कस्तूरी 8-12 सितम्बर, 2004 तक मुम्बई आए ।

श्रीमती वीरन्नला जयराम राव और श्रीमती वनश्री राव के नेतृत्व में कुचीपुड़ी नृत्य समूह और सुश्री गीताचन्द्रन के नेतृत्व में भरतनाट्यम नृत्य मण्डली द्वारा क्वालालम्पुर के साथ अन्य स्थानों पर भी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा आयोजित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए । भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के प्रायोजन में ही सुश्री सुजाता चौधरी ने दसवें क्वालालम्पुर कविता पाठ कार्यक्रम में हिस्सा लिया ।

29 अक्तूबर से मलेशिया द्वारा घोषित आम माफी योजना के अन्तर्गत लगभग 4000 अवैध भारतीय राष्ट्रकों ने मलेशिया स्थित भारतीय मिशन की सहायता से नवम्बर, 2004 तक मलेशिया छोड़ दिया ।

न्यूजीलैण्ड

प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क 16-20 अक्तूबर, 2004 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आयीं ।

अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चाएं की । वे बंगलूर, मुम्बई और आगरा भी गईं।

प्रवासी भारतीय मामलों के राज्य मंत्री श्री जगदीश टाइटलर प्रवासी भारतीय दिवस, 2005 के संबंध में 3-6 नवम्बर, 2004 तक न्यूजीलैण्ड की यात्रा पर गए और वहां उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की ।

पापुआ न्यू गिनी

पापुआ न्यू गिनी के साथ भारत के संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं । पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और बनौतू ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों अर्थात् (i) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लन्दन में हुए 23वें असेम्बली सत्र के साथ हाल ही में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की कार्यकारी परिषद् के चुनाव में भारत की उम्मीदवारी का , (ii) 28 अक्तूबर , 2004 को न्यूयार्क में 59वीं आम सभा के सत्र के दौरान 2005-2007 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के चुनाव में भारत की उम्मीदवारी का लगातार समर्थन किया है।

वर्ष, 2004-2005 के दौरान भारत ने अपने आईटैक/एस एफ टी सी/कोलम्बो योजना/विदेश सेवा संस्थान कार्यक्रमों के अधीन पापुआ न्यू गिनी को 17 सीटों की पेशकश की । जिन पाठ्यक्रमों का उपयोग किया गया, वे सांख्यिकी, पत्रकारिता, कार्यालय प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट अनुप्रयोग , सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण में लेखा परीक्षण, नेटवर्किंग डिजाइन, लघु उद्यम वित्त पोषण, शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी , उद्यमिता विकास, अनुरक्षण इंजीनियरी एवं प्रबंधन, महिलाओं के खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, पर्यटन एवं अतिथि सत्कार प्रबंधन , लघु उद्योग, विदेशी राजनयिकों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि क्षेत्रों से संबंधित थे ।

प्रशान्त द्वीप समूह मंच

प्रशान्त द्वीप समूह मंच की 35वीं बैठक 5-7 अगस्त, 2004 तक आपिया (समोआ) में संपन्न हुई । भारत ने इस मंच के बाद होने वाली भागीदारों की 16वीं वार्ता बैठक में 9 अगस्त, 2004 को दूसरी बार हिस्सा लिया ।

भारत ने प्रशान्त द्वीप समूह मंच के देशों के लिए प्रशिक्षण सीटों में काफी वृद्धि की है । हमारे आईटैक/एस एफ टी सी/कोलम्बो योजना/विदेश सेवा संस्थान कार्यक्रमों के अधीन पापुआ न्यू गिनी को 17 स्लॉट, सोलोमन द्वीप समूह को 13 स्लॉट और वनौतू को 10 स्लॉट वर्ष , 2004-2005 में आबंटित किए गए हैं ।

फिजी, पापुआ न्यू गिनी, वनौतू जैसे प्रशान्त द्वीप समूह मंच के कुछ देशों में आवश्यकता के आकलन के लिए और साथ ही आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में परामर्श वार्ताएं करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल मई-जून, 2004 में भेजा गया । इस यात्रा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में कार्यान्वयन में शामिल होने वाले भारत सरकार के भिन्न भिन्न विभागों के परामर्श से एक कार्य योजना तैयार की जा रही है ।

हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि प्रशान्त क्षेत्र के एक क्षेत्रीय पेय - कावा पर भी शोध कार्य किया जाए । इस शोध कार्य से गरीबी घटाने के संदर्भ में प्रशान्त क्षेत्र की देशी जनता पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

बैंक आफ नाउरू , राजकोष , वेतन पंजी, सरकारी खातों , भूमि एवं सर्वेक्षण, फॉस्फेट निगम आदि के कार्यालय प्रचालनों में प्रयोग की जा रही अपनी कम्प्यूटर प्रणाली को अद्यतन बनाने और इसकी मरम्मत करने में सहायता के लिए नाउरू सरकार से प्राप्त अनुरोध के जवाब में भारत सरकार ने जून, 2004 में सी एम सी लि. बंगलूर से एक कम्प्यूटर इंजीनियर को वहां तैनात किया । इस विशेषज्ञ ने उपर्युक्त कम्प्यूटर प्रणाली फिर से चालू कर दी और उसने प्रवासी भारतीय दिवस 2005 को बढ़ावा देने के लिए नवम्बर में प्रवासी भारतीय मामलों में सुधार लाने के लिए और इनमें निरन्तरता लाने के लिए तौर तरीके भी सुझाए ।

फिलीपीन्स

भारत और फिलीपीन्स के बीच संबंधों में राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अधिक गहराई आई है । विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह और फिलीपीन्स के विदेशी मामलों के मंत्री अलबर्टो जी रोमुलो ने नवम्बर , 2004 में वेनेशियान में हुए

तृतीय आसियान भारत व्यापारिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर एक द्विपक्षीय बैठक की ।

दोनों देशों के बीच विस्तारित हो रहे रक्षा संपर्क को उस समय और भी बल मिला जब पूर्वी नौसैनिक बेड़े के 5 भारतीय नौसैनिक जहाजों ने 29 अक्तूबर से 1 नवम्बर , 2004 तक मनीला की यात्रा की ।

वर्ष, 2004 के पहले 10 महीनों के दौरान कुल द्विपक्षीय व्यापार 285 मिलियन अमेरीकी डॉलर का हुआ इसमें भारत से निर्यात 207.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर का और फिलीपीन्स से आयात 78 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा ।

व्यापारिक रिश्तों में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में 6 नवम्बर 2004 को मुम्बई में फार्मेक्सिल तथा फिलीपीन्स अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिससे फिलीपीन्स को भारतीय दवाईयों के भारी मात्रा में निर्यात का मार्ग प्रशस्त हुआ है । इस समझौता ज्ञापन पर इण्डिया कैम 2004 में हिस्सा लेने के लिए पी आई टी सी के अध्यक्ष राबर्टो पगदान्गनन की अगुवाई में मुम्बई आए एक फिलीपीनी शिष्टमण्डल की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए । फिलीपीन्स भारत व्यापार परिषद् के अध्यक्ष के नेतृत्व में फिलीपीन्स का एक व्यापारिक शिष्टमण्डल दिल्ली और चेन्नै में 19-21 अक्तूबर, 2004 तक आयोजित भारत आसियान तृतीय व्यापारिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत की यात्रा पर आया ।

कृषि राज्य मंत्री श्री कान्ति लाल भूरिया एक शिष्टमण्डल का नेतृत्व करते हुए मनीला गए जहां उन्होंने 27-29 नवम्बर, 2004 तक आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय चावल उत्सव और अन्तर्राष्ट्रीय चावल मंच की बैठकों में हिस्सा लिया ।

आईटैक और कोलम्बो योजना प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बढ़ती हुई लोकप्रियता का पता इस बात से चलता है कि कुल आबंटित 68 स्लॉटों में से अभी तक 62 प्रशिक्षण स्लॉट उपयोग में लाए जा चुके हैं।

वर्ष 2004 की प्रथम तिमाही में अपेक्षित महत्वपूर्ण घटनाएं

फिलीपीन्स के व्यापार एवं उद्योग विभाग के मंत्री ने फरवरी, 2005 में आधिकारिक यात्रा पर आने का प्रस्ताव किया है । उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधि भी आएंगे ।

सिंगापुर

समीक्षाधीन अवधि के दौरान अनेक अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उच्चस्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान से भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार हुआ है और मजबूती आई है ।

12 अगस्त, 2004 को सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने वाले श्री ली सिएन लून्ग को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने बधाई संदेश भेजा । विदेश मंत्री श्री के नटवर सिंह ने सिंगापुर के नवनियुक्त विदेश मंत्री श्री जार्ज यो को बधाई संदेश भेजा । समीक्षाधीन अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखा गया ।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री गोह चोक तोंग ने 8-11 जुलाई, 2004 तक भारत की यात्रा की । उनके साथ विदेश एवं विधि मंत्री प्रो. एस जय कुमार और व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री जार्ज यो भी आए । इस यात्रा के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम, उप राष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत से मुलाकात की । वे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, विदेश मंत्री श्री के नटवर सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ और लोक सभा में विपक्ष के नेता श्री एल के आडवाणी से भी मिले । प्रधानमंत्री श्री गोह चोक तोंग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष, 2003 के जवाहर लाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया ।

विदेश मंत्री श्री के नटवर सिंह 3 जुलाई, 2004 को सिंगापुर की यात्रा पर गए । अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधान मंत्री श्री गोह चोक तोंग , वरिष्ठ मंत्री ली कुआन यू तथा वर्तमान प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन उप प्रधानमंत्री ली सियेन लून्ग से मुलाकात की ।

प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जगदीश टाइटलर , मुम्बई में आयोजित किए जाने वाले वर्ष, 2005 के प्रवासी भारतीय दिवस को बढ़ावा देने के लिए 22-24 सितम्बर, 2004 तक सिंगापुर की यात्रा पर गए । अपनी यात्रा के दौरान वे शिक्षा मंत्री डॉ. तरमन षण्मुगरत्नम, सामुदायिक विकास के कार्यकारी मंत्री डॉ. विवियन बालकृष्णन , युवा एवं खेल तथा व्यापार एवं उद्योग के वरिष्ठ राज्य मंत्री के साथ साथ सूचना, संचार कला तथा स्वास्थ्य के वरिष्ठ राज्य मंत्री डॉ. बाला जी सदाशिवन से मिले । उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित भारतीय समुदाय के एक समारोह को भी संबोधित किया ।

सूचना, प्रसारण एवं संस्कृति मंत्री श्री एस जयपाल रेड्डी 18-20 अक्तूबर, 2004 तक सिंगापुर की यात्रा पर गए । अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने समकक्ष सूचना, संचार और कला मंत्री डॉ. ली. बून यांग के साथ संस्कृति, सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के बारे में बात चीत की । उन्होंने उप प्रधानमंत्री और विधि मंत्री श्री एस जयकुमार से भी मुलाकात की । भारत और सिंगापुर के बीच कला, धरोहर, अभिलेखागार और पुस्तकालय के क्षेत्रों में सहयोग संबंधी चौथे कार्यकारी कार्यक्रम पर भारत के उच्च आयुक्त श्री आलोक प्रसाद और सूचना, संचार एवं कला मंत्रालय में स्थायी सचिव डॉ. तान चिन नाम ने 19 अक्तूबर, 2004 को हस्ताक्षर किए ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ के साथ वाणिज्य सचिव श्री एस एन मेनन, 10-12 नवम्बर, 2004 तक सिंगापुर की यात्रा पर गए । अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने समकक्ष सिंगापुर के व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री लिम हांग

मलेशिया के प्रधान मंत्री दातो सेरी अब्दुला अहमद बदावी ने तक उप-राष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत से भेंट की, 19-23 दिसम्बर 2004।

अन्तर्राष्ट्रीय समझबूझ के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार, 2003 प्राप्त करने से पूर्व सिंगापुर के प्रधान मंत्री श्री गोह चोक टोंग, भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के साथ, 9 जुलाई 2004 । चित्र में आईसीसीआर की अध्यक्ष श्रीमती नजमा हेपतुल्ला भी हैं।

कियांग से मुलाकात की । दोनों पक्षों में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधी मामलों , क्षेत्रीय घटनाओं पर विचारों का आदान प्रदान किया गया और द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता पर चल रही वार्ता की प्रगति की समीक्षा की गई ।

गुजरात के मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 13 सदस्यीय व्यापारिक शिष्टमण्डल ने अहमदाबाद में 11-14 जनवरी, 2005 तक आयोजित किए जाने वाले वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के संबंध में 27-30 नवम्बर, 2004 तक सिंगापुर की यात्रा की । अपनी यात्रा के दौरान वे सिंगापुर के समुदाय विकास, युवा मामले एवं खेल के कार्यकारी मंत्री तथा वरिष्ठ व्यापार राज्य मंत्री डॉ. विवियन बालकृष्णन से मिले । शिष्टमण्डल ने तेमसेक होल्डिंग्स , सिंगापुर चीनी वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर तथा सिंगापुर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर के साथ भी बैठकें की । श्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान और नेटवर्क इण्डिया द्वारा आयोजित "मेकिंग इनरोड्स इनटू गुजरातः अपॉरच्यूनिटीज एण्ड स्ट्रेटजीज" विषय पर एक संगोष्ठी को भी संबोधित किया ।

सिंगापुर के व्यापार एवं उद्योग मंत्री लिम हांग कियांग के नेतृत्व में 25 सदस्यीय एक व्यापारिक शिष्टमण्डल, 19 अक्तूबर, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित भारत आसियान तृतीय व्यापारिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आया । अपनी यात्रा के दौरान श्री लिम ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारान से मुलाकात की ।

सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री डॉ. टोनी तेन, 24 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 2004 तक भारत की यात्रा पर आए । अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह, विदेश मंत्री श्री के नटवर सिंह , रक्षा मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी और गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने नई दिल्ली में आब्जर्वर रिसर्च फाउन्डेशन में □ नेशनल सिक्योरिटी आफ्टर 9/11 - सिंगापुर्स पर्सपेक्टिव उु विषय पर एक व्याख्यान भी दिया ।

18 नवम्बर, 2004 को नई दिल्ली में विश्व मामलों की भारतीय परिषद् द्वारा "पंचशील के पचास वर्ष - वास्तविक बहुपक्षीयता पर आधारित एक नई विश्व व्यवस्था की ओर" विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में राजदूत किशोर महबूबानी और सिंगापुर के लोकनीति विद्यालय के डीन ली कुआन यू ने हिस्सा लिया ।

सिंगापुर के गृह मंत्री श्री वोंग कान सेंग के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने 22 नवम्बर, 2004 को गृहमंत्री श्री शिवराज पाटिल से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सुरक्षा से जुड़े द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की ।

विदेश मंत्रालय स्तर के परामर्शों का छठा चक्र 4 नवम्बर, 2004 को सिंगापुर में सम्पन्न हुआ । सचिव (पूर्व) श्री राजीव सीकरी ने भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया । अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री श्री जार्ज यो से मुलाकात की ।

विदेश सचिव श्री शशांक 29-30 अप्रैल, 2004 तक सिंगापुर की यात्रा पर गए । अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्रालय में स्थायी सचिव श्री तान चिन तियोंग से मुलाकात की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया । उन्होंने "एमर्जिंग एशिया - इण्डियाज् फारेन पालिसी पर्सपेक्टिव" विषय पर दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान में आयोजित एक संगोष्ठी को भी संबोधित किया ।

अप्रैल, 2003 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के आशय पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद से दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों के नेतृत्व में 10 वार्ता चक्र बारी बारी से नई दिल्ली और सिंगापुर में आयोजित किए गए ।

भारतीय उद्योग परिसंघ ने सिंगापुर में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मिशन भेजने का कार्य जारी रखा । भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष श्री आनन्द महेन्द्रा के नेतृत्व में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मिशन ने 15-16 अप्रैल, 2004 तक सिंगापुर की यात्रा की । अपनी यात्रा के दौरान इस शिष्टमण्डल ने राष्ट्रपति महामहिम श्री एस आर नाथन , प्रधानमंत्री श्री गोह चोक तोंग, उप प्रधानमंत्री श्री ली सियेन लून्ग , सूचना, संचार एवं कला मंत्री डॉ. ली बून यांग , स्वास्थ्य एवं परिवहन राज्य मंत्री डॉ. बाला जी सदाशिवन और व्यापार एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री रेमण्ड लिम से मुलाकात की।

भारतीय उद्योग परिसंघ के मुख्य संरक्षक श्री तरून दास को सिंगापुर सरकार द्वारा भारत सिंगापुर संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए 4 नवम्बर, 2004 को पी बी एम पुरस्कार से सम्मानित किया गया । सिंगापुर सरकार से इस प्रकार का पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय राष्ट्रिक हैं ।

इण्डियन मर्चेन्ट्स चैम्बर , मुम्बई ने सिंगापुर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर के सहयोग से 9-10 जुलाई , 2004 तक सिंगापुर में "इण्डिया कॉलिंग-2004 एशिया पैसिफिक बिजनेस समिट" का आयोजन किया । इण्डियन मर्चेन्ट्स चैम्बर द्वारा भारत से बाहर आयोजित किया गया यह अपने प्रकार का पहला शिखर सम्मेलन था और इसमें 600 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया ।

भारतीय निर्यात संगठन फेडरेशन ने स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में दो भारतीय शिष्टमण्डलों की यात्रा (19-20 अगस्त, 2004) तथा बहु उत्पादों के क्षेत्र में एक शिष्टमण्डल की यात्रा (23-25 सितम्बर , 2004) का प्रायोजन किया ।

दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और भी मजबूत हुए । रक्षा सचिव श्री अजय प्रसाद के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्ट मण्डल, सिंगापुर में 4-6 जून, 2004 तक आयोजित एशियाई

सुरक्षा सम्मेलन “शांगरी ला वार्ता” में हिस्सा लेने के लिए गया।

सिंगापुर की नौ सेना के प्रमुख रियर एडमिरल रोनी ते, 27-30 सितम्बर, 2004 तक भारत की यात्रा पर आए । अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष और नौ सेना अध्यक्ष के साथ शिष्टाचार भेंट की ।

वायु सेना प्रमुख मेजर जनरल लिम किम चून ने 24-29 अक्तूबर, 2004 तक भारत की यात्रा की । वे सिंगापुर गणराज्य की वायु सेना और भारतीय वायु सेना के बीच ग्वालियर में हो रहे सिन्डैक्स अभ्यास को देखने भी गए । दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच यह अभ्यास अपनी तरह का पहला द्विपक्षीय अभ्यास था ।

भारतीय नौ सेना के पूर्वी नौ सैनिक बेड़े के तीन जहाज - आई एन एस रणवीर , आई एन एस उदयगिरि और आई एन एस कोरा 17-18 मई, 2004 तक सिंगापुर की यात्रा पर गए।

22 मई , 2004 को सिंगापुर में पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आयोजित किए गए । इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म स्टारों ने हिस्सा लिया । सिंगापुर के राष्ट्रपति महामहिम श्री एस आर नाथन इस समारोह में मुख्य अतिथि थे ।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा प्रायोजित “श्री राम भारतीय कला केन्द्र, नई दिल्ली” की एक सांस्कृतिक मण्डली ने 14 सितम्बर, 2004 को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रामायण के व्यापक प्रभाव का चित्रण करने वाली प्रदर्शनी और विशाल सम्मेलन के एक हिस्से के रूप में अपनी प्रसिद्ध रामलीला (बैले के रूप में) का प्रदर्शन किया । इस कार्यक्रम में भी सिंगापुर के राष्ट्रपति महामहिम श्री एस आर नाथन उपस्थित रहे ।

भारत आसियान प्रथम कार रैली अपने अन्तिम चरण में 10 दिसम्बर, 2004 को सिंगापुर पहुँची । रैली का स्वागत वरिष्ठ मंत्री श्री गोह चोक तोंग और भारत से आए एक उच्चस्तरीय शिष्टमण्डल ने किया ।

थाईलैण्ड

थाईलैण्ड के साथ भारत के संबंध उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान और आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने से सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक और गहन हुए । विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की सदस्यता वाले एक उच्चस्तरीय शिष्टमण्डल के साथ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 29-31 जुलाई, 2004 तक बैंकाक में आयोजित बिम्सटैक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया । भारत ने उर्जा सहयोग संबंधी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी 2005 में करने का, आतंकवाद विरोधी उपायों पर चर्चा करने के लिए एक कार्यकारी समूह के गठन तथा पर्यटन मंत्रियों एवं पर्यटन उद्योग की एक गोलमेज वार्ता/कार्यशाला की मेजबानी करने का प्रस्ताव किया । भारत ने वर्ष, 2006 में द्वितीय बिम्सटैक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर भी अपनी सहमति जताई । अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने महामहिम सम्राट भूमिबल अदुल्यदेज से मुलाकात की । इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने समान हित के द्विपक्षीय , क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर थाईलैण्ड के प्रधानमंत्री डॉ. तक्षिन सिनवात्रा के साथ व्यापक एवं महत्वपूर्ण चर्चा की । दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने भारत और थाईलैण्ड के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए समझौते के ढांचे के अन्तर्गत “अर्ली हार्वेस्ट स्कीम” के कार्यान्वयन हेतु की जाने वाली बातचीत में तीव्र प्रगति का स्वागत किया ।

थाईलैण्ड के विदेश मंत्री डॉ. सुराकियार्त सथीरथई ने नई सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए जून में और नई दिल्ली में “भारत और विश्व” विषय पर हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नवम्बर, 2004 में पुनः दिल्ली की यात्रा की । उन्होंने, इन यात्राओं के दौरान क्षेत्रीय एवं वैश्विक संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों एवं सहयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की । भारत के विदेश मंत्री ने भी 15-16 अक्तूबर, 2004 तक की अपनी बैंकाक यात्रा के रास्ते में डॉ. सुराकियार्त सथीरथई से मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की । दोनों ही विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक के अवसर पर सितम्बर, 2004 में न्यूयार्क में और सी आई सी ए बैठक के अवसर पर अक्तूबर, 2004 में कजाखिस्तान में एक बार पुनः मिले । किंगदाओ में ए सी डी की बैठक के अवसर पर भारत के विदेश मंत्री ने जून, 2004 में थाईलैण्ड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की ।

भारत से थाईलैण्ड के बीच हुई अन्य महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय यात्राओं में शामिल हैं - (i) ब्राडबैंड तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में ए पी टी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जुलाई, 2004 में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारान की यात्रा (ii) एच आई वी/एड्स के बारे में द्वितीय एशिया प्रशान्त बैठक और पन्द्रहवें अन्तर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जुलाई, 2004 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अम्बुमणि रामदास की यात्रा (iii) 16 जुलाई को बैंकाक में पन्द्रहवें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की यात्रा । अपनी इस यात्रा के अवसर पर थाईलैण्ड के प्रधानिमंत्री तक्षिन सिनवात्रा और थाईलैण्ड के विदेश मंत्री डॉ सुराकियार्त सथीरथई ने उनसे मुलाकात की। (iv) अध्ययन दौरे के लिए अगस्त, 2004 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की यात्रा (v) आसियान के दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों की चौथी बैठक में हिस्सा लेने के लिए अगस्त में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. शकील अहमद की यात्रा, और (vi) आई यू सी एन विश्व संरक्षण की तृतीय कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए नवम्बर, 2004 में पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री नमोनारायण मीना की यात्रा ।

थाईलैण्ड की ओर की जाने वाली भारत की कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं थी। (i) व्यापार एवं निवेश, पर्यटन आदि सहित अन्य संबंधों पर चर्चा करने के लिए जून , 2004 में फुकेत प्रान्त के राज्यपाल श्री उदोमसक उस्वरंकोरा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल की पोर्ट ब्लेयर यात्रा। (ii) जुलाई , 2004

में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कोर्न तपरान्सी , की चेन्नै एवं बंगलूर की यात्रा और नवम्बर, 2004 में मैसूर में इन्फोसिस के 20 सप्ताह के सूचना प्रौद्योगिकी शिविर में हिस्सा लेने के लिए 100 विद्यार्थियों के समूह के साथ फिर से की गई यात्रा (iii) भारत-थाईलैण्ड मुक्त व्यापार समझौते के अधीन ई एच एस सूची में शामिल किए जाने वाले उत्पादों के ब्योरे को अन्तिम रूप देने के लिए भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ चर्चा के लिए उप वाणिज्य मंत्री श्री प्रानप्री बाहिद्द नुकारा की जुलाई, 2004 की यात्रा और फिक्की एवं एफ टी आई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के समय 16 दिसम्बर, 2004 को की गई पुनः यात्रा (iv) जुलाई , 2004 में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री ओथई पिम्पचैचोल के नेतृत्व में दस सदस्यीय शिष्टमण्डल ने लोक सभा के अध्यक्ष से मुलाकात की और राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति से भेंट की । (v) अगस्त, 2004 में वाणिज्य मंत्री श्री वत्तन मोंगसुक के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल ने मुक्त व्यापार समझौते के अन्तर्गत “अर्ली हार्वेस्ट स्कीम” के कार्यान्वयन के प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ से मुलाकात की । (vi) नई दिल्ली और चेन्नै में अक्तूबर, 2004 में आयोजित भारत आसियान तृतीय व्यापारिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उप वाणिज्य मंत्री श्री अनुतिन चारविराकुरल की यात्रा और (vii) दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान इंटरफेस के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नवम्बर, 2004 में राजकुमारी चुलबोन महिडोल की यात्रा ।

सुरक्षा के संबंध में तृतीय संयुक्त कार्य समूह की बैठक थाईलैण्ड में 31 अगस्त से 1 सितम्बर, 2004 तक हुई और इसमें सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया । भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व सचिव (पूर्व) श्री राजीव सीकरी ने और थाईलैण्ड के शिष्टमण्डल का नेतृत्व थाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव जनरल विनई पतियाकुल ने किया ।

अन्तरिक्ष सहयोग में संयुक्त कार्यकारी समूह की द्वितीय बैठक, सहयोग के अन्य क्षेत्रों की पहचान के लिए 20-22 अक्तूबर, 2004 तक बंगलूर में आयोजित की गई । थाईलैण्ड से आए एक 10 सदस्यीय वैज्ञानिक समूह ने भारतीय दूर संवेदी संस्थान, देहरादून में 27 नवम्बर से 31 दिसम्बर, 2004 तक एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया।

रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए दोनों ओर से उच्च स्तरीय यात्राएं की गईं । शाही थाई सेना के आयुध विभाग के महानिदेशक ले. जनरल वाईचा टैकवानिक के नेतृत्व में एक दल ने नई दिल्ली में फरवरी , 2004 में हुई “रक्षा प्रदर्शनी, 2004” में भागीदारी की । राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय और रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय में एक एक रिक्ति प्रतिवर्ष थाईलैण्ड की सशस्त्र सेनाओं को आबंटित करने की प्रथा जारी रखी गई । भारतीय तटरक्षक बल के दो जहाजों ने मार्च-अप्रैल, 2004 में बैंकाक बंदरगाह की सद्भावना यात्रा की और भारतीय नौ सेना के दो जहाज, अक्तूबर, 2004 में फुकेत बंदरगाह पर सद्भावना यात्रा पर गए ।

द्विपक्षीय व्यापार में भी तीव्र वृद्धि जारी रही । अप्रैल से अक्तूबर 2004 की अवधि के दौरान थाईलैण्ड को भारत का निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 28.7 प्रतिशत बढ़कर 666.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ । इसी अवधि के दौरान भारत को थाईलैण्ड का निर्यात 69 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 561.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया । इस वर्ष की एक प्रमुख घटना, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के ढांचे के अन्तर्गत “अर्ली हार्वेस्ट स्कीम” के बारे में प्रोतोकोल पर बातचीत पूरी होना और इस पर हस्ताक्षर होना रही । इस प्रोतोकोल में दोनों ही पक्षों की रूचि की 82 वस्तुओं को शामिल किया गया है और यह समझौता 1 सितम्बर , 2004 से लागू हो गया है ।

भारत ने थाईलैण्ड में जिन महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं आर्थिक संवर्धन गतिविधियों में हिस्सा लिया, वे इस प्रकार हैं - (i) अप्रैल, 2004 में बैंकाक अन्तर्राष्ट्रीय उपहार मेला (ii) जुलाई, 2004 में “प्रतिस्पर्द्धात्मकता-एशियाई देशों के लिए चुनौतियां एवं अवसर” विषय पर सम्मेलन जिसमें वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने प्रतिष्ठित भारतीय व्यापारियों के साथ हिस्सा लिया । (iii) जुलाई, 2004 में इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा क्रेता-विक्रेता बैठक (iv) अगस्त, 2004 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा मेड इन इण्डिया प्रदर्शनी जिसका उद्घाटन थाईलैण्ड के वाणिज्य मंत्री और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ई वी के एस एलांगोविन ने संयुक्त रूप से किया । (v) सितम्बर, 2004 में बैंकाक रत्न एवं आभूषण मेला (vi) अक्तूबर, 2004 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा प्रायोजित “अस्पताल प्रबंधन एशिया, 2004” सम्मेलन में हिस्सा लेना, और (vii) बाजार विकास के लिए भारतीय मशीन टूल्स निर्माता संघ के एक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा नवम्बर, 2004 में की गई यात्रा । इसके अलावा व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में व्यक्तिगत वाणिज्यिक शिष्टमण्डल एक दूसरे के यहां गए ।

दोनों देशों के बीच पारम्पिरक सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ़ हुए । इस क्षेत्र में हुई प्रमुख घटनाओं में शामिल हैं - (i) अगस्त, 2004 में गुरू जय राम राव द्वारा कुचीपुड़ी नृत्य (ii) सितम्बर, 2004 में “दया का मार्ग” शीर्षक से एक फोटो प्रदर्शनी, और (iii) सितम्बर, 2004 में डॉ. लीलावती अदसूले द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत ।

भारत ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत थाईलैण्ड के राष्ट्रकों को 119 छात्रवृत्तियां दीं ।

भारत आसियान प्रथम कार रैली को गुवाहाटी में 22 नवम्बर, 2004 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाई गई । यह रैली 28-30 नवम्बर, 2004 तक अपने प्रथम चरण में माए साए से नोंग खाए तक थाईलैण्ड से होकर गुजरी । अपने द्वितीय चरण में यह रैली, बैंकाक से होते हुए अरण्य प्राथेट से सेदाओ तक गई । बैंकाक में इस रैली को थाईलैण्ड के उप प्रधानमंत्री सुवत लिपतपनलोप ने दिसम्बर, 2004 में हरी झंडी दिखाई । इसके बाद यह रैली, इण्डोनेशिया के बाताम में समाप्त हुई । थाईलैण्ड से इस रैली में एक मीडिया टीम सहित कुल तीन टीमों ने हिस्सा लिया ।

अपने कार्यकाल के पूरा होने पर राजदूत एल के पुनापा, 24 दिसम्बर, 2004 को बैंकाक से वापस लौटे । अन्य लोगों के साथ साथ थाईलैण्ड के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने राजदूत के लिए अलग अलग विदाई समारोह आयोजित किए जिनमें दोपहर का भोज भी शामिल था ।

थाईलैण्ड के महामहिम सम्राट की ओर से एच आर एच राजकुमारी चुलबोन महिडोल ने 25 दिसम्बर, 2004 को बुद्ध मन्थन पार्क में भारत द्वारा भेंट स्वरूप दिए गए 'साल' के 40 पौधों में से 7 पौधे स्वयं रोपे ।

जनवरी से मार्च, 2005 के दौरान अपेक्षित महत्वपूर्ण क्रिया कलाप

(i) थाईलैण्ड में आम चुनाव 6 फरवरी , 2005 को सम्पन्न होने हैं ।

(ii) एच आर एच राजकुमारी महाचक्री सिरिन्धोर्न, 28 फरवरी से 10 मार्च, 2005 तक भारत की यात्रा पर आने वाली हैं ।

(iii) भारतीय उद्योग फेडरेशन का एक शिष्टमण्डल फरवरी, 2005 में (क) व्यक्तिगत स्तर पर व्यापारिक सम्पर्क स्थापित करने (ख) नए व्यापारिक अवसरों का पता लगाने और संयुक्त उपक्रमों की स्थापना करने तथा आर्थिक सहयोग का विस्तार करने, और (ग) जानकारी के आदान प्रदान के लिए उद्योग संघों एवं वाणिज्य चैम्बरों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए थाईलैण्ड की यात्रा पर जाने वाला है ।

(iv) भारतीय उद्योग परिसंघ, 12-14 जनवरी , 2005 तक कोलकाता में "11वें भागीदारी शिखर सम्मेलन 2005" का आयोजन करेगा । इस शिखर सम्मेलन की विषयवस्तु है - विकास के लिए भागीदारी और इसका मुख्य ध्यान सहभागी देशों के साथ निकट सम्पर्क रखते हुए व्यापार रणनीतियों के विकास का रहेगा । थाईलैण्ड को इस शिखर सम्मेलन में मंत्रिस्तर पर हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन से आसियान देशों के साथ वार्ता का एक अवसर प्राप्त होगा ।

(v) थाईलैण्ड के लिए नियुक्त राजदूत श्री विवेक काटजू के फरवरी , 2005 में पदभार ग्रहण करने की संभावना है ।

तिमोर ल ईस्ते

नए बने राष्ट्र तिमोर ल ईस्ते के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध, इस वर्ष के दौरान लगातार विकसित हुए । आईटैक प्रशिक्षण और जी सी एस एस छात्रवृत्तियों के प्रावधान के अलावा आईटैक के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण परियोजना की पहचान की गई । इस परियोजना के लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन नवम्बर, 2004 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के एक दल ने तिमोर ल ईस्ते में किया । यह परियोजना अगले वर्ष शुरू की जाने की आशा है और तिमोर ल ईस्ते की सरकार ने इसका अत्यधिक स्वागत किया है ।

वियतनाम

फ्रांसीसी कब्जे से हनोई की आजादी के बाद अक्तूबर, 1954 में प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू की हनोई यात्रा की 50वीं वर्षगांठ मनाने और 17 अक्तूबर, 1954 को राष्ट्रपति हो चि मिन्ह से उनकी मुलाकात की स्मृति के रूप में विदेश मंत्री श्री के नटवर सिंह 16-18 अक्तूबर, 2004 तक हनोई की यात्रा पर गए । वियतनाम के विदेश मंत्रालय के अन्तर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान ने इस अवसर पर एक संगोष्ठी आयोजित की जिसे भारत के विदेश मंत्री के साथ साथ वियतनाम के विदेश मंत्री श्री नोयेन दाई निएन ने संबोधित किया । उसी दिन वियतनाम मैत्री संगठन संघ ने इस घटना की स्मृति में एक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ साथ वियतनाम भारत मैत्री संघ के अध्यक्ष की हैसियत से वियतनाम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री होंग वान फोंग और वियतनाम फादरलैंड फ्रंट के अध्यक्ष श्री फाम दे दुयेत ने हिस्सा लिया । विदेश मंत्री ने वियतनाम के प्रधानमंत्री महामहिम श्री फान वान खाय और महान जनरल वो नुयेन ग्लाप से भी भेंट की ।

विदेश मंत्री ने 18 अक्तूबर, 2004 को वियतनाम के विदेश मंत्री श्री नियेन के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक की सह अध्यक्षता की । संयुक्त आयोग की बैठक से पहले 15 अक्तूबर, 2004 को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्रीमती एस त्रिपाठी , अपर सचिव (पी पी एण्ड सी पी वी) ने किया और वियतनामी पक्ष का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय में एशिया -II विभाग के महानिदेशक और सहायक मंत्री डॉ. दो नॉक सोन ने किया । दोनों पक्षों ने वियतनाम की कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव की मई, 2003 की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारत और वियतनाम के बीच व्यापक सहयोग के ढांचे संबंधी संयुक्त घोषणा को लागू करने के लिए 2004-2006 के लिए एक कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए ।

पर्यटन राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा ह्यु में आयोजित सांस्कृतिक पर्यटन एवं गरीबी उपशमन संबंधी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 11-14 जून, 2004 तक वियतनाम की यात्रा पर गईं । उन्होंने वियतनाम राष्ट्रीय पर्यटन प्रशासन की अध्यक्षा मैडम वो थाई तांग से मुलाकात करके भारत और वियतनाम के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की ।

वियतनाम राष्ट्रीय पर्यटन प्रशासन की अध्यक्षा मैडम वो थाई तांग ने नई दिल्ली में क्षेत्रीय पर्यटन मेले में हिस्सा लेने के लिए 16-21 अक्तूबर, 2004 तक भारत की यात्रा की । भारत आसियान तृतीय व्यापारिक शिखर सम्मेलन में भी उन्होंने वियतनाम का प्रतिनिधित्व किया ।

शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन राज्य मंत्री कु. शैलजा ने "शांति एवं शतत विकास के लिए संस्कृतियों एवं सभ्यताओं के बीच वार्ता" संबंधी एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 19 से 22 दिसम्बर, 2004 तक वियतनाम

की यात्रा की । इस सम्मेलन के उद्‌घाटन सत्र में उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में भाषण दिया ।

सचिव (ए एन ए) श्री आर एम अभयंकर, विदेश मंत्री के विशेष दूत के रूप में 4-5 मई, 2004 तक वियतनाम की यात्रा पर गए ।

भारत और वियतनाम के बीच में द्वितीय विदेश मंत्रालय परामर्श नई दिल्ली में 5 अगस्त, 2004 को हुआ । वियतनामी पक्ष का नेतृत्व वियतनाम के सह विदेश मंत्री श्री ली कांग फुंग ने किया जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व विशेष सचिव (पूर्व) श्री राजीव सीकरी ने किया।

वियतनाम की राष्ट्रीय असेम्बली के कार्यालय से एक 12 सदस्यीय शिष्टमण्डल, संस्कृति , युवा बाल मामले संबंधी समिति की अध्यक्षा मैडम त्रान थाई ताम दान के नेतृत्व में 3-9 जुलाई, 2004 तक भारत की यात्रा पर आया । इस शिष्टमण्डल ने लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों से भेंट की ।

भारतीय नौ सेना के तीन जहाज अर्थात आई एन एस रणविजय, आई एन एस सुकन्या और आई एन एस किर्च नवम्बर, 2004 में पूर्वी नौ सैनिक बेड़े के फ्लीट कमान अधिकारी रियर एडमिरल एस के दामले के नेतृत्व में हो चि मिन्ह सिटी की सद्‌भावना यात्रा पर गये । पूर्वी नौ सैनिक कमान के मुख्य फ्लीट कमान अधिकारी वाइस एडमिरल ओ पी बंसल भी इसी दौरान हनोई और होची मिन सिटी की यात्रा पर गए और उन्होंने उप रक्षा मंत्री तथा वियतनाम जनवादी सेना के चीफ आफ जनरल स्टाफ सीनियर ले. जनरल फोंग कुआंग तान से भेंट की।

एयर वाइस मार्शल ए के तिवारी , वी एस एम के नेतृत्व में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय से एक 15 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने मई , 2004 में वियतनाम की यात्रा की । इस शिष्टमण्डल में यूनाईटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात से भी एक एक अधिकारी अर्थात् कुल तीन विदेशी अधिकारी शामिल थे ।

सी ई पी/जी सी एस एस के अन्तर्गत वियतनाम को आबंटित सभी 20 छात्रवृत्तियों का उपयोग कर लिए जाने की संभावना है । आईटैक के अन्तर्गत वियतनाम को आबंटित 110 स्लॉट भी पूरी तरह उपयोग में लाए जाने की आशा है ।

वर्ष के दौरान सांस्कृतिक संवर्धन एवं प्रचार से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल हैं - (i) हनोई स्थित राजदूतावास में "इण्डिया पर्सपेक्टिव्स" के वियतनामी रूपान्तर का विमोचन (ii) द्विवर्षीय ह्यू समारोह 2004 में हिस्सा लेने के लिए श्री पी पी बोरा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय सात्रीय नृत्य मण्डली की 10-18 जून , 2004 तक की यात्रा, तथा (iv) अप्रैल में हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारत के प्रधान कौन्सुलावास द्वारा स्थानीय भाषा में पर्यटन विवरणिका का प्रकाशन ।

वियतनाम को भारत का निर्यात, जनवरी से नवम्बर, 2004 की अवधि के दौरान 518.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया जिससे वर्ष, 2003 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का पता चलता है । निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं - पशुचारा (सोयाबीन चारा), औषधि एवं दवाईयां, प्लास्टिक का सामान , इस्पात, कपड़ा और सिले सिलाए वस्त्रों में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री आदि । इस वर्ष के दौरान व्यापार को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में शामिल हैं - (i) मेसर्स बेसिक कैमिकल्स, फार्मास्यूटीकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल (केमेक्सिल) से एक 10 सदस्यीय शिष्टमण्डल की फरवरी , 2004 में हनोई यात्रा (ii) अक्तूबर-नवम्बर, 2004 में वियतनाम प्रतिष्ठित अन्तराष्ट्रीय औद्योगिक मेला, 2004 के अवसर पर एक कैटलॉग प्रदर्शनी का आयोजन (iii) वियतनाम अन्तराष्ट्रीय कृषि मेले में कैटलॉग आधारित सहभागिता (iv) अप्रैल, 2004 में वियतनाम 14वें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (वियतनाम एक्सपो 2004) में हिस्सा लेने के लिए भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा प्रायोजित 8 भारतीय कम्पनियों की यात्रा (v) नवम्बर, 2004 में नई दिल्ली में 24वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2004 में वियतनाम की भागीदारी (vi)10-13 दिसम्बर, 2004 तक भारतीय उद्योग परिसंघ के एक 6 सदस्यीय शिष्टमण्डल की हो चि मिन्ह सिटी की यात्रा (viii) 1-4 दिसम्बर, 2004 तक हनोई में वियतनाम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्लैक्सकौन्सिल से 6 सदस्यी शिष्टमण्डल द्वारा सहभागिता ।

वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव श्री एस एस कपूर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने "पांचवें आसियान वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों की बैठक - भारत से परामर्श" नामक बैठक में हिस्सा लेने के लिए 31 जुलाई को ह्यू की यात्रा की ।

भारत वियतनाम एकता समिति, कोलकाता के अध्यक्ष श्री गीतेश शर्मा द्वारा लिखी गई "भारत वियतनाम संबंध - पहली से इक्कीसवीं शताब्दी तक" नामक पुस्तक का विमोचन 01 दिसम्बर, 2004 को एक प्रेस सम्मेलन में किया गया । इस सम्मेलन का आयोजन, हो चि मिन्ह सिटी स्थित भारत के प्रधान कौन्सुलावास के परिसर में किया गया था।

भारत आसियान प्रथम कार रैली 1-4 दिसम्बर , 2004 तक वियतनाम से होकर गुजरी । इस रैली के मार्ग में आने वाले प्रमुख नगर थे - ह्यू, न्हा त्रांग, हो चि मिन्ह सिटी । वियतनाम की सरकार और वियतनाम के प्रान्तीय प्राधिकारियों ने इस रैली का स्वागत गर्मजोशी से किया और रैली के लिए व्यापक व्यवस्थाएं कीं । वियतनाम की सरकार ने एक विशेष मामले के तौर पर अपने देश में राइट हैंड ड्राइव वाहनों के प्रवेश की अनुमति दी ।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के एक 15 सदस्यीय शिष्ट मण्डल ने 10-14 दिसम्बर, 2004 तक वियतनाम की यात्रा की । अपने वियतनाम प्रवास के दौरान उन्होंने यूथ कल्चरल हाऊस, कू ची सुरंगों और हो चि मिन्ह सिटी स्थित युद्धावशेष म्यूजियम देखे और वियतनाम के युवा संगठनों के साथ मेल मुलाकात की ।

पूर्व एशिया

3

जापान

भारत जापान के साथ अपने निकट, सहयोगात्मक और मित्रतापूर्ण संबंधों का अत्यधिक सम्मान करता है। अगस्त, 2000 में भारत और जापान ने संयुक्त रूप से 21वीं सदी के लिए वैश्विक भागीदारी की नींव रखी थी। उक्त भागीदारी के फलस्वरूप हमारे आपसी संबंध मजबूत तो हो ही रहे हैं और साथ-ही-साथ एशिया और विश्व में स्थायित्व और सम्पन्नता में भी इज़ाफा हुआ है। वैश्विक भागीदारी होने से दोनों देश मिलजुल कर विश्वव्यापी समस्याओं से जुड़े विभिन्न मामलों को भी सुलझाते हैं। दोनों देश अपनी- अपनी समान सांस्कृतिक धरोहरों, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्धताओं, आर्थिक प्रतिपूर्तियों और नीतिगत जानकारियों को मान्यता देते हैं। दोनों देशों में उक्त समभाव से सहयोग के बहुमुखी संबंधों को एक परिवर्तनीय आधार प्रदान हुआ है। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में 2004-05 एक सक्रिय वर्ष था। वैश्विक भागीदारी को सुदृढ़ करने के हमारे सतत् प्रयासों के अनुसरण में इस वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान पर बल दिया जाता रहा।

प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 29 नवम्बर 2004 को वियनतने, लाओस में हुए आसियान शिखर-सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधान मंत्री श्री जुनीकीरो कोइज़ुमी से भेंट की। इस भेंट के दौरान दोनों नेताओं ने परस्पर महत्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

जापान की डेट के निचले सदन के अध्यक्ष और ऊपरी सदन के अध्यक्ष के निमंत्रण पर श्री सोमनाथ चटर्जी, लोक सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का एक शिष्टमंडल 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2004 तक जापान की यात्रा पर गया। अध्यक्ष ने अपनी यात्रा के दौरान जापान के सम्राट, प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से भेंट की और जापान की डेट के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

फ्रेंडशिप एक्सचेंज काउंसिल (एफ.ई.सी.) के निमंत्रण पर पूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर.नारायणन ने 18 से 24 अक्तूबर 2004 तक जापान की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान पूर्व राष्ट्रपति और श्रीमती नारायणन ने फ्रेंडशिप एक्सचेंज काउंसिल को सम्बोधित किया और उन्होंने दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों, विदेश मंत्री तथा जापान के शाही परिवार के राजकुमार और राजकुमारी अकिशीनों से भेंट की। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन ने 17 से 19 जनवरी 2005 तक जापान की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने जापान के आन्तरिक कार्य और संचार मंत्री श्री टारो असो के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के संबंध में विचार-विमर्श किया। प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री पृथ्वी राज चौहान ने समुद्री सुरक्षा पर भारत-जापान की तीसरे दौर की वार्ता में भाग लेने के लिए 24 से 26 नवम्बर 2004 तक जापान की यात्रा की।

जापान के प्रधान मंत्री योरिको क्वागुची ने 12 से 14 अगस्त 2004 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच वैश्विक भागीदारी तथा अन्य मुद्दों पर विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह से चर्चा की। दोनों पक्ष विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करने और सयुंक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के प्रति मिल कर कार्य करने के लिए सहमत थे। यह भी सहमति हुई कि आतंकवाद नियंत्रण संबंधी संयुक्त कार्य दल स्थापित किया जाए और संयुक्त राष्ट्र सुधार के संबंध में डी.जी.स्तर पर वार्ता आरम्भ की जाए। सुश्री क्वागुची ने प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी भेंट की।

जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री श्री शोइची नकागवा ने 22 से 30 अगस्त 2004 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह से भेंट की और वाणिज्य एवं उद्योग तथा वित्त मंत्रियों से चर्चा की। उन्होंने 6 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में हुई ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में गोल मेज सम्मेलन के पहले दौर की वार्ता में भाग लेने के लिए भारत की पुनः यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान, श्री नकागवा ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ से चर्चा की। जापान के वित्त मंत्री श्री सडाकाजु तनिगाकी ने 12 से 14 जनवरी 2005 तक भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान, श्री तनिगाकी ने प्रधान मंत्री से भेंट की और वित्त मंत्री श्री पी0 चिदम्बरम तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया से चर्चा की। श्री हीजो टाकेनाका, अर्थव्यवस्था और वित्तीय नीति मंत्री ने 12 से 13 जनवरी 2005 तक भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान श्री टाकेनाका ने वित्त मंत्री श्री पी0 चिदम्बरम तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया से भेंट की। वरिष्ठ कृषि, वन और मत्स्यिकी उप मंत्री श्री

टाकायोशी सुनेडा ने 11 से 13 जनवरी 2005 तक भारत की यात्रा की और कृषि राज्य मंत्री श्री कान्ति लाल भूरिया से भेंट की।

वर्ष के दौरान भारत से की गई अन्य यात्राओं में ये यात्राएं शामिल हैं - उत्तरांचल के राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल की 20 से 26 मई 2004 तक यात्रा; कनाडा में 50वें कामनवैल्थ संसदीय सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व सम्मेलन - पूर्व अध्ययन करने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की 28 - 29 अगस्त 2004 की यात्रा; कनाडा में 50वें कामनवैल्थ संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात् सम्मेलन-उपरांत अध्ययन के लिए राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह की 15 - 17 सितम्बर 2004 की यात्रा; नागोया, आइची में आई.टी.एस. संबंधी 11वीं विश्व कांग्रेस में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन और विद्युत मंत्री श्री हारून युसुफ की 17 - 22 अक्तूबर 2004 की यात्रा।

वर्ष के दौरान जापान से भारत में की गई अन्य यात्राओं में ये यात्राएं शामिल हैं - जापान के विदेश संसदीय सचिव श्री शोगो अरई की 15 - 19 जुलाई 2004 की यात्रा; संसद सदस्य एवं एशियाई जनसंख्या और विकास एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शिन सकुरई की 20 - 22 जुलाई 2004 की यात्रा; और जापान की डेमोक्रेटिक पार्टी के संसद सदस्य श्री कजुओ इनोई की 22 - 27 सितम्बर 2004 की यात्रा।

22 दिसम्बर 2004 को नई दिल्ली में जापान के साथ विदेश कार्यालय परामर्श के 11वें दौर की वार्ता की गई जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों के सबंध में विचार-विमर्श किया गया।

भारत-जापान विज्ञान परिषद् की बैठक टोक्यो में 28-29 जनवरी 2005 को सम्पन्न हुई। वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधी आदान-प्रदान नियमित रूप से होता रहा। जनरल एन.सी.विज, सेनाध्यक्ष ने 25 और 26 मार्च 2004 को टोक्यो की यात्रा की और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के सेनाध्यक्ष से चर्चा की। एयर वाइस मार्शल ए.के.तिवारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के एक शिष्टमंडल ने मई 2004 में जापान की यात्रा की। वाइस ऐडमिरल सुरेश मेहता, तटरक्षक निदेशक और कमांडेंट के.पी.एस.रघुवंशी ने एशिया की तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में भाग लेने के लिए 16 से 19 जून 2004 तक जापान की यात्रा की। एयर चीफ मार्शल एस.कृष्णास्वामी, वायु सेना अध्यक्ष ने 20 - 24 जुलाई 2004 को जापान की सद्भावना यात्रा की। यह किसी भारतीय वायु सेना अध्यक्ष की जापान की प्रथम यात्रा थी। एयर मार्शल एस.के.मलिक, वायु सेना उपाध्यक्ष ने 23 - 26 सितम्बर 2004 को जापान में वायु सेना अध्यक्षों के सम्मेलन (ए.सी.सी.जे.) में भाग लिया। वाइस ऐडमिरल संग्राम सिंह बाइसे ने रक्षा प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11 - 13 अक्तूबर 2004 को टोक्यो की यात्रा की। रियर ऐडमिरल सुनील के.दामले, फ्लैग आफीसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट की कमान में भारतीय नौ सेना के तीन पोतों रंजीत, रणविजय तथा ज्योति ने 22 - 24 अक्तूबर 2004 को टोक्यो की सद्भावना यात्रा की। एक यू.एस.आई. शिष्टमंडल ने दूसरे टोक्यो- नई दिल्ली 'एशिया में शान्ति' अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान सम्मेलन में भाग लेने के लिए 24 से 28 अक्तूबर 2004 तक टोक्यो की यात्रा की।

जापान रक्षा एजेंसी के प्रशासनिक उप मंत्री श्री टाकेमसा मोरिया ने 23 - 27 मई 2004 को भारत की यात्रा की। वाइस कमांडेंट केनजी इशी के नेतृत्व में जापान के तटरक्षक शिष्टमंडल और जापान के एक तटरक्षक पोत ने भारतीय तटरक्षक के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए 2 - 5 नवम्बर 2004 को मुम्बई की यात्रा की।

भारत-जापान मिश्रित सांस्कृतिक आयोग की बैठक 9 फरवरी 2005 को टोक्यो में सम्पन्न हुई। वर्ष के दौरान टोक्यो स्थित हमारे दूतावास ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनियां आयोजित की। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक कथकली दल और आई.सी.सी.आर. द्वारा भेजे गए एक कुचीपुड़ी दल और राजस्थानी दल द्वारा नृत्य प्रस्तुत करना शामिल है। दूतावास ने विभिन्न भारतीय प्रदर्शनियों, संगीत समारोहों तथा जापानी संगठनों द्वारा आयोजित शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रमों में सहायता दी। दूतावास ने 7 - 25 सितम्बर 2004 तक ओटानी विश्वविद्यालय में 'करूणा का पथ' शीर्षक से एक पखवाड़े तक एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जिसमें विनय के. बहल द्वारा बुद्ध स्थलों और कला के चित्रों का प्रदर्शन किया गया। 'बुद्ध परम्परा' के संबंध में एक सम्मेलन से पहले इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

2003-04 में भारत और जापान के बीच कुल 4.35 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ जिसमें जापान को 1.71 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया गया और जापान से 2.64 बिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया। 2003-04 के दौरान भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 18% की वृद्धि हुई। 1991-2004 के दौरान जापान से संचयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ए.डी.आर.एस./जी.डी.आर.एस. का निवल) 1.86 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें मौजूदा शेयरों (1999 तक) के अधिग्रहण, आर.बी.आई.- एन.आर.आई.स्कीमों, स्टॉक स्वैप्ड और शेयरों के अग्रिम लम्बित मामलों से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल नहीं है।

कार्यात्मक आदान-प्रदान

भारत से जापान

- डा. हर्ष के. गुप्ता, सचिव, महासागर विकास विभाग, नई दिल्ली ने टोक्यो में हुई राष्ट्रीय महासागर नीतियों के संबंध में अनुसंधान कार्य दल की निप्पन फाउंडेशन की पहली बैठक में भाग लेने के लिए 22 से 24 अप्रैल 2004 तक जापान की यात्रा की।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 29 नवम्बर 2004 को वियनटाइने, लाओस में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के प्रधान मंत्री श्री वेन जियाबाओ से मुलाकात करते हुए।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 29 नवम्बर 2004 को वियनटाइने लाओस में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान जापानी प्रधान मंत्री श्री जुनिचिरो कोइज़ुमी से विचार-विमर्श करते हुए।

- श्री के.एन.अग्रवाल, सदस्य सचिव और सचिव, भारत सरकार, विधि आयोग और डा. के.एन.चतुर्वेदी, सदस्य सचिव, विधि आयोग ने टोक्यो में हुई पहली ए.सी.डी. कार्यशाला में भाग लेने के लिए 19 - 22 मई 2004 को जापान की यात्रा की।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति आगामी कार्रवाई के संबंध में डा. प्रदीप्तो घोष, सचिव (पर्यावरण और वन) ने जापान और ब्राजील की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अनौपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए 14-16 सितम्बर 2004 को जापान की यात्रा की।
- राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के डा. एम.जी.के. मेनन, एम.एन.शाह, प्रतिष्ठित शिक्षावृत्ति भोगियों ने टोक्यो में 21 - 23 सितम्बर 2004 को 'सभ्यता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सभ्यता' विषय पर हुए सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा की।
- श्री राजीव सीकरी, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने 13-14 अक्तूबर 2004 को टोक्यो की यात्रा की और इराक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निधि सुविधा के संबंध में दानदाताओं के तीसरे सम्मेलन में भाग लिया।
- रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने अन्तर्राष्ट्रीय द्रुत गति रेलवे सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 - 11 नवम्बर 2004 को जापान की यात्रा की।
- सी.आई.आई. के अध्यक्ष के नेतृत्व में उसके एक शिष्टमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम में भाग लेने के लिए 14 - 18 नवम्बर 2004 को जापान की यात्रा की और जापान के व्यापार संगठनों के साथ व्यापार संबंधी बैठकें की।
- श्री ए.के.रस्तोगी, सचिव (बी.एम.), गृह मंत्रालय ने आपदाओं को कम करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18 - 22 जनवरी 2005 को कोबे, जापान की यात्रा की।
- 01 अप्रैल - 31 अक्तूबर 2004 की अवधि के दौरान टोक्यो में स्थित भारतीय दूतावास ने 29, 272 वीजा जारी किए (जिनमें से 5,645 वीजा व्यापारिक वीजा थे और 13,150 वीजा पर्यटक वीजा थे), 397 नए पासपोर्ट, 22 आपात प्रमाण-पत्र प्रदान किए तथा 964 भारतीय नागरिकों को परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान की।

कोरिया गणराज्य

भारत और कोरिया गणराज्य के बीच उच्च स्तरीय नियमित यात्राओं, आर्थिक और वाणिज्यिक सम्पर्कों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में दोनों देशों के बीच अन्योयक्रिया के साथ दोनों देशों के संबंधों में नियमित रूप प्रगति होती रही।

वर्ष 2004-05 भारत और कोरिया गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के रूप में चिह्नित है। लोकतांत्रिक आदर्शों और उनके आदान-प्रदान को समेकित करने तथा उनमें विविधता लाने की साझी इच्छा की वचनबद्धता की मजबूत नींव पर इन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच पारम्परिक मित्रता विकसित होती रही है। वर्ष 2004-05 इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्ष आर्थिक सम्पूरक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ लेते हुए, परस्पर लाभकारी सहयोग में वृद्धि करने के लिए उल्लेखनीय क्षमता और अवसरों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के उद्देश्य से □शान्ति और उन्नति के लिए दीर्घकालिक सहयोगी भागीदारी ु स्थापित करने के लिए सहमत हुए। कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री रोह मू-ह्यून ने 4 - 6 अक्तूबर 2004 को भारत की यात्रा की। उनके साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल था जिसमें चार मंत्री (विदेश और व्यापार; वाणिज्य, उद्योग और ऊर्जा; सूचना और संचार; तथा व्यापार) और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल थे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रोह ने राष्ट्रपति ए.पी.जे.अब्दुल कलाम से भेंट की और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह से द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा वैश्विक मुद्दों के संबंध में विचार-विमर्श किया। यात्रा के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जिसमें द्विपक्षीय संबंधों का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। यात्रा के दौरान एक प्रत्यर्पण संधि और आपराधिक मामलों में परस्पर विधि सहायता से संबंधित एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्ष रक्षा क्षेत्र में आदान-प्रदान और अन्योन्यक्रिया में और अधिक वृद्धि करने पर भी सहमत हुए।

राष्ट्रपति रोह के साथ एक बड़ा व्यापार शिष्टमंडल भी था जिसमें प्रमुख कोरयाई कम्पनियों के सी.ई.ओ.शामिल थे जो इस यात्रा के आर्थिक महत्व के सूचक हैं। विचार-विमर्श के दौरान, व्यापार, निवेश और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और सहक्रियाओं में सम्पूरकों का लाभ उठाते हुए, द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी को उच्च स्तर पर पहुंचाने के प्रयासों को बढ़ाने का निर्णय किया गया। दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार के लिए 2008 तक 10 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत थे। यह भी सहमति हुई कि व्यापार, निवेश और सेवाओं में द्विपक्षीय सम्पर्कों के एक व्यापक दृष्टिकोण के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल स्थापित किया जाए जिसमें सरकारी अधिकारी, अर्थशास्त्री तथा व्यापार समुदाय के प्रतिनिधि हों।

कोरिया गणराज्य के वाणिज्य, उद्योग और ऊर्जा उप मंत्री श्री चाऊ हवान-ईक ने 6 जनवरी 2005 को नई दिल्ली में ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में हुई बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

कोरिया गणराज्य की नेशनल असैम्बली के उपाध्यक्ष श्री पार्क ही-टाई के नेतृत्व में कोरिया गणराज्य के एक संसदीय शिष्टमंडल ने 30 जनवरी - 2 फरवरी 2005 को भारत की यात्रा की।

विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह ने 21 जून 2004 को क्विंगडायो, चीन में हुई ए.सी.डी. की तीसरी मंत्री स्तर की बैठक से इतर समय में कोरिया गणराज्य के विदेश और व्यापार मंत्री श्री बान की-मून से भेंट की और 1 - 2 जुलाई 2004 को जकार्ता में हुए आसियान क्षेत्रीय फोरम के विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक के इतर समय में पुनः भेंट की।

विदेश मंत्री श्री के.नटवर सिंह ने भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त आयोग के 15 दिसम्बर 2004 को सियोल में हुए तीसरे सत्र की सह-अध्यक्षता करने के लिए 14 - 16 दिसम्बर 2004 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की। दोनों पक्षों ने बैठक में द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

दोनों पक्षों ने गहन और नियमित सलाह-मश्विरा करते रहने के महत्व को दोहराया ताकि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अवसंरचना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, पेट्रोकेमिकल्स, कपड़ा, तेल और गैस क्षेत्र विकास, आटोमोबाइल्स, पोत-निर्माण, लोहा और इस्पात, औषध-निर्माण और कृषि क्षेत्र शामिल हैं, में सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी-अपनी इच्छाओं को दोहराया। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की भी सहमति व्यक्त की और आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष जारी रखने की अपनी-अपनी वचनबद्धता दोहराई। यात्रा के दौरान, भारत और कोरिया गणराज्य के बीच 2004-07 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री रोह मू-ह्यूम और कोरिया गणराज्य की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष श्री किम वॉन-की से भी भेंट की।

पोत-परिवहन, राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री श्री टी.आर.बालू ने 19 - 22 जनवरी 2005 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की। यात्रा के दौरान, श्री बालू ने कोरिया गणराज्य के वाणिज्य, उद्योग और ऊर्जा मंत्री श्री ही बियोम ली के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया। श्री बालू ने हुंडै हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा भारतीय पोत-परिवहन निगम के लिए निर्मित की जा रही एम.टी.- □ देश उजालाु के नामकरण समारोह में भी भाग लिया। कोरिया गणराज्य के विदेश और व्यापार मंत्रालय में महानिदेशक और संयुक्त सचिव, पूर्व एशिया, विदेश मंत्रालय स्तर पर 12 अप्रैल 2004 को सियोल में विदेश कार्यालय स्तर पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्रालय स्तर पर संयुक्त व्यापार समिति के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक 19 - 20 अगस्त 2004 को नई दिल्ली में की गई। भारत और कोरिया गणराज्य के बीच पहली विदेश नीति और सुरक्षा के संबंध में 20 जनवरी 2005 को नई दिल्ली में चर्चा की गई।

भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त अध्ययन दल की पहली बैठक 27 - 28 जनवरी 2005 को नई दिल्ली में हुई। कोरिया गणराज्य पक्ष का नेतृत्व श्री जाँग-की हाँग, व्यापार उप मंत्री ने किया और भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य सचिव ने किया। 2003-04 के दौरान भारत और कोरिया गणराज्य के बीच कुल 3.2 बिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया जिसमें कोरिया गणराज्य को 0.76 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात और 2.45 बिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया। भारत में कोरिया गणराज्य के निवेश की स्वीकृति 3 बिलियन अमरीकी डालर के निकट है।

1991-2004 की अवधि के लिए कोरिया गणराज्य से 657.0 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की वस्तुओं की वास्तविक रूप से आमद हुई। कोरिया व्यापार निवेश संवर्धन एजेंसी ने जून 2004 में भारत में मुम्बई में अपना तीसरा कार्यालय खोला। टाटा दक्षिणी कोरिया में निवेश करने वाली पहली भारतीय कम्पनी बनी। उन्होंने मार्च 2004 में दक्षिणी कोरिया में गुनसन में देवू कमर्शियल वीकल्स का अधिग्रहण करके 120 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया।

भारत और कोरिया गणराज्य के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने की 30वीं वर्षगांठ को मनाने के एक भाग के रूप में, सी. आई. आई. ने 8 से 10 अगस्त 2004 तक 11-सदस्यीय छोटे और मझौले उद्यमियों का एक मिशन सियोल भेजा। इस मिशन ने फेडरेशन आफ कोरियन इंडस्ट्रीज, कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन, इनकेयोन चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज और कोरिया फेडरेशन ऑफ स्माल एंड मीडियम बिजनेस (के.एफ.एस.बी.) के साथ बैठकें की। सी.आई.आई. ने के.एफ.एस.बी. के साथ सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।

भारत-कोरिया गणराज्य सांस्कृतिक समिति की छठी बैठक 13 मई 2004 को नई दिल्ली में हुई। इस समिति ने 2004 से 2007 तक के वर्षों के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सी.ई.पी.) को अन्तिम रूप दिया और इस कार्यक्रम की शुरूआत की। भारत से अभिनय कलाकारों के एक दल ने जून 2004 में गेंगनियोंग अन्तर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में भाग लिया। भारत के एक सांस्कृतिक दल ने 14 से 19 सितम्बर 2004 तक ग्याचेओन हमाडोंग महोत्सव में भाग लिया।

अनुसंधान कार्मिकों के आदान-प्रदान, तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहयोग की संभावना के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए कोरियाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष आई.आई.टी., मुम्बई और आई.आई.एस., बंगलौर आए।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त कार्य दल की तैयारी बैठक 13 दिसम्बर, 2004 को नई दिल्ली में हुई।

कार्यात्मक आदान-प्रदान

भारत से कोरिया गणराज्य को

- कोरिया के न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायालय प्रशासन मंत्री के निमंत्रण पर जस्टिस ब्रजेश कुमार, न्यायाधीश ने 10 - 15 अप्रैल 2004 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की।
- पी.ए.टी.ए. के 53वें वार्षिक सम्मेलन और निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए श्रीमती रति विनय झा, सचिव, पर्यटन विभाग ने 17 - 21 अप्रैल 2004 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की।
- श्री पी.आई. सुवरत्न, अपर सचिव, कार्मिक मंत्रालय ने आई.आई.ए.एस., प्रशासन और कार्यकारी समिति की परिषद तथा 26वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन विज्ञान कांग्रेस की बैठकों में भाग लेने के लिए 13 - 19 जुलाई 2004 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की।
- भारतीय शिष्टमंडल संबंधी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष डा. एल.एम.सिंघवी ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने हेतु 'की-नोट' सुपुर्द करने के लिए 23 - 27 जुलाई 2004 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की।
- श्री जस्टिस डी.पी.वधवा, अध्यक्ष, श्री विनोद वैश्य, सदस्य, टेलीकॉम विवाद और अपीलीय अधिकरण ने 6-11 सितम्बर 2004 और श्री प्रदीप बैजल, अध्यक्ष, भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण ने 7 - 11 सितम्बर 2004 को एशिया-प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय दूरसंचार फोरम और प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन टेलीकॉम एशिया- 2004 में भाग लेने के लिए कोरिया गणराज्य की यात्रा की।
- जस्टिस ए.एस.आनन्द, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया-प्रशांत फोरम की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 11-18 सितम्बर 2004 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की।
- श्री राकेश कुमार, महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने 20 - 22 सितम्बर 2004 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की।
- श्री के.के.चक्रवर्ती, सदस्य-सचिव, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र और महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय ने त्रैवार्षिक 20वें आम सम्मेलन और 21वीं जनरल असेम्बली ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स में भाग लेने के लिए 29 सितम्बर - 5 अक्तूबर 2004 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की।
- श्री पी.के.महन्ता, सदस्य, असम विधान सभा ने विश्व नेताओं और विश्व शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 - 5 अक्तूबर 2004 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की।
- श्री एस.सी.त्रिपाठी, सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देवू शिप बिल्डिंग एंड मेरीन इंजीनियरिंग कम्पनी, कोरिया गणराज्य में निर्माणाधीन एल.एन.जी. कैरियर के नामकरण समारोह में भाग लेने के लिए 8-9 दिसम्बर 2004 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की।
- डा0 सुभाष पाणि, मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने कोरिया गणराज्य के पी.ओ.एस.सी.ओ. द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित समन्वित इस्पात संयंत्र के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए 27 - 31 दिसम्बर 2004 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की।
- वर्ष 2004 के दौरान सियोल स्थित भारतीय दूतावास ने कुल 43,230 वीजा जारी किए और 1 - 24 जनवरी 2005 की अवधि के दौरान 4,285 वीजा जारी किए।

लोकतांत्रिक जनगणराज्य कोरिया

2004-05 के दौरान भारत और कोरिया प्रजातांत्रिक गणराज्य (डी.पी.आर.के.) में सहयोग और परस्पर लाभ के आधार पर सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर भारत ने कोरिया प्रजातांत्रिक गणराज्य को 1000 मीटरी टन चावल की आपूर्ति करने का निर्णय किया जिसकी औपचारिक रूप से 29 जुलाई 2004 को कोरिया प्रजातांत्रिक गणराज्य को सुपुर्दगी की गई। भारत ने कोरिया प्रजातांत्रिक गणराज्य को मानवीय सहायता के रूप में डेक्सामेथासोन के 100,000 टीके प्रदान किए।

मंत्रालय के आई.सी.ई.सी. कार्यक्रम के अधीन, भारत कोरिया प्रजातांत्रिक गणराज्य को प्रशिक्षण में सहायता दे रहा है। 2004-05 से आई.टी.ई.सी. स्लाट्स की संख्या 5 से बढ़ा कर 10 कर दी गई है। वर्ष के दौरान, आई.सी.सी.आर. ने प्योंगयांग में 22 अप्रैल के वसन्त मैत्री कला उत्सव के लिए 14 सदस्यीय भंगड़ा/गिद्दा नृत्य दल को प्रायोजित किया। भारत ने 12 - 20 सितम्बर 2004 को प्योंगयांग में हुए गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के नौवें प्योंगयांग फिल्म समारोह में भी भाग लिया।

कोरियन बुद्धिस्ट फेडरेशन की केन्द्रीय समिति के उपाध्यक्ष श्री ह्वांग प्योंग जुन के नेतृत्व में एक पांच-सदस्यीय डी.पी.आर.के. के शिष्टमंडल ने बौद्ध धर्म और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए 17 - 19 फरवरी 2004 को भारत की यात्रा की।

01 अप्रैल - 31 अक्तूबर 2004 की अवधि के दौरान प्योंगयांग स्थित भारत के दूतावास ने 96 वीजा जारी किए।

मंगोलिया

वर्ष के दौरान भारत और मंगोलिया के बीच पारम्परिक रूप से निकट और मित्रतापूर्ण संबंधों को मजबूत बनाया गया। 14 - 20 जनवरी 2004 को मंगोलिया के तत्कालीन प्रधान मंत्री भारत की यात्रा के दौरान किए गए करारों और समझौतों को दोनों देश कार्यान्वित करते रहे।

मंगोलिया राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के कार्यकारी सचिव डा0 डुरगेरजव गोटव के नेतृत्व में भारत आए एक शिष्टमंडल के साथ 11 - 12 अक्तूबर 2004 को नई दिल्ली में दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच कार्यात्मक स्तर पर पहले दौर का विचार-विमर्श हुआ। इसी प्रकार, 11 - 15 अक्तूबर 2004 को मंगोलिया में प्रथम भारत-मंगोलिया सुंयक्त सैन्य अभ्यास किए गए जिसके लिए भारतीय सेना के कार्मिकों के एक सैन्यदल ने मंगोलिया की यात्रा की।

इस वर्ष भारत से प्रथम व्यापार प्रदर्शनी का 30 अगस्त - 3 सितम्बर 2004 को उलनबट्टर में आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न भारतीय कम्पनियों ने भाग लिया। इसके साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी, औषध-निर्माण तथा जैवप्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के संबंध में सम्मेलन किए गए और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मई 2004 में उलनबट्टर में भारत-मंगोलिया संबंधों पर एक प्रमुख शैक्षिक सम्मेलन हुआ जिसमें मंगोलिया के कई विख्यात विद्वानों और भारत के विद्वानों ने भाग लिया। सम्मेलन में भारत-मंगोलिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। 'भारत-मंगोलिया पुस्तकालय सम्पर्को' के संबंध में एक अन्य सम्मेलन मंगोलिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में 17 जनवरी 2005 को आयोजित किया गया जिसमें मंगोलिया के कई विख्यात विद्वानों ने दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस सम्मेलन के साथ-साथ, मंगोलिया राज्य पुस्तकालय में भारत-मंगोलिया के पुस्तकालयों की पुस्तकों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई।

योग और चिंतन की कक्षाएं आरम्भ होने के साथ वर्ष के दौरान भारतीय संस्कृति केन्द्र की गतिविधियों को सुदृढ़ किया गया। हमारे 15 अगस्त 2004 के स्वतंत्रता दिवस समारोहों के अनुरूप, भारत-मंगोलिया मैत्री को समर्पित एक लम्बी दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें 250 व्यक्तियों ने भाग लिया।

मंगोलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन को दोहराया। राष्ट्र सचिव, विदेश मंत्रालय श्री आर. अलटंगेरेल ने 27 सितम्बर 2004 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में दिए गए अपने भाषण में कहा कि उनकी सरकार जापान, जर्मनी और भारत जैसे उन देशों की न्यायसंगत आकांक्षा का समर्थन करता है जो इसके इच्छुक हैं और जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा और विकास के एक बड़े उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सक्षम हैं।

दोनों देशों के विदेश अधिकारियों के बीच अप्रैल 2004 में उलनबट्टर में विचार-विमर्श हुए। वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और संस्कृति के क्षेत्र की सहयोग परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए गए। भारत और मंगोलिया दिसम्बर 2005 में राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे करेंगे। 24 दिसम्बर 2004 को दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों के 50 वर्षों के बारे में समारोह आरम्भ किए जो पूरे वर्ष विभिन्न घटनाओं/गतिविधियों का आयोजन करके किए जाएंगे।

■■

4

यूरेशिया

रूस

यूरेशिया के अनुकूल समीपवर्ती पड़ोसी देशों के संबंधों में आई तेजी बनी रही तथा इस अवधि के दौरान संबंध और घनिष्ठ हुए ।

भारत-रूस संबंध दोनों पक्षों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वर्ष 2004-2005 के दौरान सहयोग को व्यापक करने और आगे बढ़ने के संगठित प्रयास किए गए ।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष करने से सम्बद्ध भारत-रूस संयुक्त कार्यकारी ग्रुप के द्वितीय सत्र की बैठक 8 अप्रैल 2004 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। इसमें द्विपक्षीय तंत्र प्रणालियों को सुदृढ़ करने को विशेष महत्व दिया गया, विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष में सूचना का आदान-प्रदान करने और अनुभव बांटने के लिए तथा आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को एवं स्वापकों के अवैध व्यापार को समाप्त करने में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए।

विदेश मंत्री ने जकार्ता में 1 जुलाई 2004 को रूस के विदेश मंत्री श्री सेरगी लावरोव से मुलाकात की। इराक और अफगानिस्तान की स्थिति सहित अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। भारत-रूस के द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय संबंधों को और आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर बल दिया। उन्होंने ऊर्जा और अन्तरिक्ष के क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि करने के बारे में भी विचार-विमर्श किया ।

रूसी संघ के प्रथम विदेश उप-मंत्री श्री वी.आई. त्रुबनिकोव की भारत में रूसी संघ के राजदूत के रूप में नियुक्ति की गई। पूर्व विदेश सचिव श्री कंवल सिब्बल को रूसी संघ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया ।

चेचन्या में 29 अगस्त 2004 को राष्ट्रपति के चुनाव सफलतापूर्वक कराने के लिए भारत ने रूसी सरकार को बधाई दी। श्री अलु अल्खानोव ने 73.48 प्रतिशत मत प्राप्त किए और उन्हें चेचन्या गणराज्य का राष्ट्रपति घोषित किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान रूस में कई आतंकवादी आक्रमण हुए। चेचन्या के संदिग्ध आतंकवादी आक्रमण में 31 अगस्त 2004 को 10 लोग मारे गए और 51 लोग घायल हो गए। भारत ने इस आतंकवादी कार्रवाई की निन्दा की और आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष में रूस के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने 24 अगस्त 2004 को हुई विमान दुर्घटनाओं के बारे में भी रूसी सरकार को अपनी संवेदना व्यक्त की जिसमें दो रूसी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे ।

भारत ने उस आतंकवादी आक्रमण की कठोर शब्दों में निन्दा की जिसमें 1-3 सितम्बर 2004 तक चेचन्या आतंकवादियों द्वारा बेसलान में एक स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके फलस्वरूप बच्चों सहित लगभग 350 लोग मारे गए। राष्ट्रपति जी और प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को शोक संदेश भेजे। प्रधान मंत्री ने 5 सितम्बर 2004 को राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की। विदेश मंत्री ने 6 सितम्बर 2004 को दिल्ली में रूसी दूतावास में संवेदना पुस्तक पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने 50,000 अमरीकी डॉलर की भारतीय दवाएं भेजकर बेसलान त्रासदी के पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान की ।

59वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने 22 सितम्बर 2004 को रूसी संघ के विदेश मंत्री श्री सेरगी लावरोव से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हित-चिन्ता के अनेक मामलों पर विचार-विमर्श किया। रूसी विदेश मंत्री श्री सेरगी लावरोव 8-10 अक्तूबर 2004 तक भारत की यात्रा पर आए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधान मंत्री से मुलाकात की और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठकें की। विचार-विमर्श द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हित-चिन्ता के व्यापक मामलों पर केन्द्रित रहा। दोनों पक्षों ने भारत-रूस के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग में सुधार के महत्व पर भी बल दिया। इस संदर्भ में दोनों पक्ष उन सभी विषयों का पता लगाने और उनका समाधान करने पर सहमत हुए जो द्विपक्षीय संबंधों का पूरी क्षमता में लाभ उठाने में बाधा डालते हैं। विदेश मंत्री लावरोव ने 9 अक्तूबर 2004 को भारतीय उद्योग मण्डल द्वारा आयोजित एक व्यवसाय अन्योन्यक्रिया सत्र को भी संबोधित किया ।

सीआईसीए के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अल्माटी में 21 अक्तूबर 2004 को भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच तीसरी त्रिपक्षीय बैठक सम्पन्न हुई। विदेश मंत्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जिसमें इराक में शान्ति और नागरिक व्यवस्था बहाल करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष शामिल थे। उन्होंने त्रिपक्षीय आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, नई दिल्ली में मुलाकात करते हुए, 3-5 दिसम्बर 2004।

राष्ट्रपति भवन के पिछवाड़े में स्थित मुगल बगीचे में बसन्त ऋतु में रंगो का उत्सव।

पर भी सहमति व्यक्त की। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध भारत-रूस अन्तःसरकारी आयोग की 10वें सत्र की बैठक 18-19 नवम्बर 2004 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रूसी संघ के उप-प्रधान मंत्री श्री अलैक्जेण्डर जुकोव ने रूसी पक्ष का नेतृत्व किया और विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया। श्री जुकोव ने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की तथा वित्त मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मिले। बैठक के उपरान्त दोनों सह-अध्यक्षों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

अन्तःसरकारी आयोग की बैठक के दौरान लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में सॉफ्टवेयर उत्पादों के विकास के लिए परियोजनाएं तथा साथ ही रूस में सॉफ्टवेयर पार्कों की स्थापना में भारतीय सहायता, भारत में आनुषंगी फ्लीट शिप के निर्माण के लिए रूसी कंपनी सुडोइम्पोर्ट और मैगनम इन्टरनेशनल ट्रेडिंग के बीच सहयोग तथा उड़ीसा में टिटेनियम डाइऑक्साइड के उत्पादन के लिए भारत-रूस की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी का विकास शामिल है। दोनों पक्षों ने ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, संचार, जैव-प्रौद्योगिकी की विकास के नए क्षेत्रों के रूप में पहचान की। विद्युत उत्पादन के लिए ताप विद्युत, जल विद्युत और न्यूकलीय ऊर्जा में सहयोग को बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा। रूस तथा अन्य देशों में नए तेल और गैस के क्षेत्रों में भारत और रूस की कंपनियों की भागीदारी के प्रयोजन हेतु भारत एवं रूस के बीच सहयोग को बढ़ाने का भी दोनों देशों ने समर्थन किया ।

सितम्बर-अक्तूबर 2005 में रूस में 'डेज ऑफ इण्डियन कल्चर' आयोजित करने तथा 2005-2006 में 'डेज ऑफ दी सिटीज मास्को एण्ड दिल्ली' के कार्यक्रम आदान-प्रदान के ढांचे के अन्तर्गत सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर भी करार सम्पन्न हुआ।

पारस्परिक हित के विषयों पर अधिक तेजी से ध्यान केन्द्रित करने की दृष्टि से अन्तःसरकारी आयोग के कार्यकारी दलों और उप-दलों की संख्या 23 से घटाकर 5 करने का भी निर्णय लिया गया ।

रूसी संघ के रक्षा मंत्री श्री सेरगी इवनोव सैन्य तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध भारत-रूस संयुक्त के चौथे सत्र के संबंध में 30 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2004 तक भारत की यात्रा की।

प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री ब्लादिमीर पुतिन 5वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 3-5 दिसम्बर 2004 तक भारत की यात्रा पर आए। यात्रा के दौरान कुल 11 दस्तावेज सम्पन्न हुए। इनमें से शामिल थे : रूसी संघ के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किया गया संयुक्त घोषणा पत्र तथा अन्तरिक्ष, कोंसली एवं क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्रों को कवर करने वाले चार अन्तःसरकारी करार। संयुक्त घोषणा पत्र में भारत और रूस के बीच नीतिगत भागीदारी पर बल दिया गया है और हाल ही में विगत में सार्वभौम पर्यावरण में रूपान्तरण को नोट किया गया है। इसमें बहु-ध्रुवीय विश्व पर आधारित एक नई अन्तर्राष्ट्रीय संरचना की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और बैंकिंग के क्षेत्रों सहित आर्थिक संबंधों पर पर्याप्त एवं नए सिरे से बल दिया गया है। यात्रा के दौरान बैंकिंग और ऊर्जा के क्षेत्रों में छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों प्रोत्साहित करने की पारस्परिक इच्छा के अनुसरण में सुचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध पहला भारत-रूस गोलमेज सेमिनार 3-4 दिसम्बर 2004 तक बेंगलूर मे सम्पन्न हुआ तथा ऊर्जा से सम्बद्ध पहला भारत-रूस सेमिनार 15 जनवरी 2005 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ ।

सैन्य तकनीकी सहयोग के बारे में बुद्धिजीवियों के अधिकारों के पारस्परिक संरक्षण सम्बद्ध अन्तःसरकार करार के मसौदे पर भारत रूसी दल की पहली बैठक 18-19 जनवरी 2005 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने से सम्बद्ध भारत-रूस संयुक्त कार्यकारी दल की तीसरी बैठक 19-20 जनवरी 2005 को मास्को में सम्पन्न हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के सहयोग में दोनों देशों के बीच नीतिगत साझीदारी एक महत्वपूर्ण अंग है तथा आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध को शक्ति प्रदान करने के लिए दोनों देशों द्वारा देश में तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर किए गए उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इस क्षेत्र में सहयोग को व्यावहारिक आयाम प्रदान करने की दृष्टि से दोनों पक्ष निकट भविष्य में आतंकवाद की वित्त व्यवस्था को प्रतिबंधित करने पर लक्ष्यपूर्ण विचार विमर्श करने पर सहमत हुए ।

नीतिगत स्थायित्व के बारे में भारत-रूस विदेश कार्यालय परामर्श 27 जनवरी 2005 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। दोनों पक्षों ने निरस्त्रीकरण और डब्ल्यूएमडी की चोरी को रोकने से संबंधित पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया ।

राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान दिसम्बर 2004 को सम्पन्न राजनयिक एवं सरकारी पासपोर्ट धारकों की वीजा मुक्त यात्रा से सम्बद्ध भारत-रूस करार 15 फरवरी 2005 से लागू हो गया ।

सीआईएस

इस अवधि के दौरान सीआईएस देशों के साथ भारत के संबंध और अधिक मजबूत हुए। सीआईएस क्षेत्र के देशों के साथ उच्च स्तर पर यात्राओं का आदान-प्रदान नियमित रूप से चलता रहा। व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों की यात्राओं के अलावा औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं की प्रदर्शनियों से इन यात्राओं में और वृद्धि हुई। इसलिए भारत के आर्थिक संबंधों में लगातार सुधार की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है ।

सांस्कृतिक संबंधों और मीडिया संबंधी आदान-प्रदान ने इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों की गुंजाइश को और बढ़ा दिया है। तीन केन्द्रीय एशियाई देशों में ' फेस्टिवल ऑफ इण्डिया' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में समकालीन महिला पेंटरों द्वारा 'अमृता शेरगिल रिविजिटेड' नामक एक पेंटिंग प्रदर्शनी उजबेकिस्तान, कजाकस्तान और किर्गिजस्तान में आयोजित की गई। ताशकंद में 16 अगस्त 2004 को भारत और केन्द्रीय एशिया से सम्बद्ध एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ताशकंद में (20-21 अगस्त 2004 को) और अल्माटी में (25-26 अगस्त 2004 को) रॉयल प्रिंसेस द्वारा एक फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय आभूषणों और वेश-भूषाओं की परम्पराओं का प्रदर्शन किया गया।

कजाकस्तान

इस अवधि के दौरान कजाकस्तान के साथ संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बने रहे, जिसमें उच्च राजनीतिक स्तर पर यात्राओं का आदान-प्रदान शामिल है। सीआईसीए के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री 21-22 अक्तूबर 2004 तक अल्माटी की यात्रा पर गए। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने कजाकस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की और कजाकस्तान के विदेश मंत्री के साथ एक बैठक की। तेल एवं गैस तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग सहित आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया ।

कजाकस्तान के उद्योग एवं व्यापार मंत्री श्री आदिलबेक जक्सीबेकोव एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ 15-18 सितम्बर 2004 तक भारत की यात्रा पर आए। इस प्रतिनिधिमण्डल में कजाकिस्तान के विभिन्न मंत्रालयों, कजाकस्तान के मंत्री ने रक्षा मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ बैठके की। यात्रा के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी सहयोग से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास का अवलोकन करने के लिए कजाकस्तान के मंत्री बेंगलूर की संक्षिप्त यात्रा पर गए ।

भारत-कजाकस्तान संयुक्त व्यवसाय परिषद की तीसरी बैठक 6 सितम्बर 2004 को अल्माटी में सम्पन्न हुई। बैठक में भारतीय पक्ष की आरे से 'फिक्की' ने भागीदारी की तथा कजाकस्तान का प्रतिनिधित्व कजाकस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल ने किया ।

फोकस-सीआईएस कार्यक्रम के अन्तर्गत इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद ने कजाकस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल के सहयोग से 3-6 सितम्बर 2004 तक अल्माटी में इण्डियाटैक-2004 का आयोजन किया तथा केआईटीईएक्स 2004 का आयोजन किया जिसमें 66 भारतीय कंपनियों के इंजीनियरी उत्पादों को प्रदर्शित किया गया ।

सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता के संबंध में भारत और कजाकस्तान के बीच एक करार के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए कजाकस्तान के न्याय उप-मंत्री के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय दल 28-30 अक्तूबर 2004 तक भारत की यात्रा पर आया। कजाकस्तान के प्रतिनिधिमण्डल ने अपर सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय के नेतृत्व में भारतीय पक्ष के साथ विचार-विमर्श किया ।

महाभारत का कजाकस्तान की भाषा में अनुवाद करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 30 जून 2004 को कजाकस्तान के कवि ए.निलिबाएव को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया ।

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ई.वी.के.एस. इलांगोवन 12-24 जनवरी 2005 तक कजाकस्तान की यात्रा पर गए। मंत्री के साथ 50 से अधिक व्यावसायिक गए। व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल में फिक्की, सीआईआई, ईईपीसी, औषध निर्यात परिषद तथा रसायन निर्यात परिषद के प्रतिनिधि शामिल थे। राज्य मंत्री ने कजाक-भारत क्रेता-बिक्रेता मेले का उद्घाटन किया और 13 जनवरी 2005 को अल्माटी में कजाकस्तान-भारत व्यवसाय मंच को सम्बोधित किया। व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डल ने रसायन एवं अनुषंगिक उत्पादों, भेषज उत्पादन, इंजीनियरी, कपड़ा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कजाक कंपनियों के साथ एक-एक करके व्यावसायिक बैठकें आयोजित कीं। राज्य मंत्री ने भी अल्माटी में प्रमुख व्यावसायिक मण्डलों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान निर्माण सामग्री और विशिष्ट बैटरियों के खेत्रों की भारत एवं कजाक की कंपनियों के बीच दो संयुक्त उपक्रम करार सम्पन्न हुए ।

भारत-कजाक संयुक्त आयोग की पांचवीं बैठक 17-18 फरवरी 2005 को अस्ताना, कजाकस्तान में सम्पन्न हुई। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर ने किया तथा कजाक पक्ष का नेतृत्व कजाकस्तान के ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्री श्री ब्लादिमीर श्कोल्निक ने किया। श्री मणिशंकर अय्यर ने कजाक प्रधान मंत्री श्री डेनियल अखमेटोव, अर्थव्यवस्था एवं व्यापार मंत्री श्री के. केलिम्बेतोव और परिवहन एवं संचार मंत्री श्री के. नगमानोव के साथ भी बैठकें कीं। विचार विमर्श आर्थिक एवं व्यापार संबंधों पर केन्द्रित रहा ।

किर्गिजस्तान

किर्गिजस्तान के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे। सांस्कृतिक और व्यावसायिक स्तर पर आदान-प्रदान नियमित रूप से चलता रहा। भारत-किर्गिजस्तान संयुक्त व्यावसायिक परिषद के चौथे सत्र की बैठक 7-8 सितम्बर 2004 तक बिश्केक में सम्पन्न हुई। भारत की ओर से 'फिक्की' तथा किर्गिजस्तान की ओर से किर्गिजस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल ने संयुक्त व्यावसायिक परिषद की बैठक में भाग लिया ।

जुलाई 2004 में एफआईईओ का एक प्रतिनिधिमण्डल किर्गिजस्तान की यात्रा पर गया जिसमें कृषि उत्पादों, चाय, आभूषणों के निर्यात, सोने तथा हीरों के उत्खन्न, कपास प्रसंस्करण आदि में रुचि रखने वाली भारतीय कंपनियां शामिल थी। प्रतिनिधिमण्डल ने किर्गिजस्तान सरकार और विभिन्न एजेंसियों के उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकें की ।

ताजिकिस्तान

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत-ताजिकिस्तान के संबंध और घनिष्ठ हुए। एक प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें सचिव (एएनए) और संयुक्त सचिव (युरेशिया) शामिल थे, 7-9 मई 2004 तक ताजिकिस्तान की यात्रा पर गया। प्रतिनिधिमण्डल ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की। भारत के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दशान्बे शहर के लिए 10 नगर परिवहन बसें भेंट स्वरूप दी गई। ताजिकिस्तान सरकार को दी गई 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान राशि को छोड़ दिया गया तथा जो जनवरी 2005 में भारत के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ताजिकिस्तान को हस्तांतरित की गई थी। ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री कोलोनल जनरल शेरली खेरूल्लोविच खैरूलोव ने 26-27 जनवरी को भारत का दौरा किया। दशान्बे में एक फल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की परियोजना लगभग पूरी होने वाली है ।

उजबेकिस्तान

चालू अवधि के दौरान भारत-उजबेकिस्तान के संबंधों में पारम्परिक धनिष्ठता बनी रही। उजबेकिस्तान के विदेश मंत्री 29-30 अक्तूबर 2004 को भारत की यात्रा पर आए। यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधान मंत्री और लोक सभा अध्यक्ष के साथ मुलाकात की। उजबेकिस्तान के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री के साथ बैठक की। यात्रा के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भारत-उजबेकिस्तान केन्द्र स्थापत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

उजबेकिस्तान में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जन्म शताब्दी समारोहों में भाग लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री 1-4 अक्तूबर 2004 तक उजबेकिस्तान की यात्रा पर गए। अपनी यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री ने उजबेकिस्तान के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश राज्य मंत्री ने ताशकन्द में शास्त्री स्कूल का दौरा किया और स्कूल के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के लिए 25000 अमरीकी डॉलर का एक चैक सौंपा। विदेश राज्य मंत्री श्री ई.अहमद ने ताशकन्द युनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड डिप्लोमेसी एण्ड इकोनॉमी में एक भाषण दिया ।

जुलाई 2004 में एफआईईओ का एक प्रतिनिधिमण्डल उजबेकिस्तान की यात्रा पर गया जिसमें सिल्क, कपास प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों, चाय, आभूषणों के निर्यात, सोने और हीरे के उत्खनन आदि में रुचि रखने वाली भारतीय कंपनियां शामिल थी। प्रतिनिधिमण्डल ने उजबेकिस्तान सरकार और विभिन्न एजेंसियों के उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ मुलाकात की ।

9 सितम्बर 2004 को सम्पन्न हुई संयुक्त व्यवसाय परिषद की द्वितीय बैठक में भाग लेने के लिए फिक्की का एक 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल 9-10 सितम्बर 2004 को ताशकंद की यात्रा पर गया। प्रतिनिधिमण्डल ने स्वास्थ्य उप-मंत्री, विदेश आर्थिक संबंधों की एजेंसी के उपाध्यक्ष, विदेश मंत्रालय तथा अन्य वाणिज्यिक संगठनों के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। सीएमसी लिमिटेड का एक 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल अक्तूबर 2004 में ताशकंद की यात्रा पर गया और व्यावसायिक सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट उद्यमियों के साथ मुलाकात की ।

श्री ई.वी.के.एस. इलांगोवन, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भारत और उजबेकिस्तान के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग से सम्बद्ध अन्तःसरकारी आयोग के 5वें सत्र के सह-अध्यक्ष के रूप में 8-12 जनवरी 2005 तक उजबेकिस्तान की यात्रा पर गए। उजबेकिस्तान के उप प्रधान मंत्री श्री मिराबरोर उस्मानोव ने उजबेक पक्ष की ओर से सह-अध्यक्षता की। संयुक्त आयोग की बैठक (11 जनवरी को ताशकंद में सम्पन्न) में भारत और उजबेकिस्तान के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की पुनरीक्षा की। सहयोग के लिए अभिज्ञात क्षेत्र इस प्रकार हैं : परिवहन, निर्माण, सूचना, प्रौद्योगिकी, परामर्श, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, औषध उत्पादन, खनन, संयुक्त उपक्रम, संस्कृति एवं मानव संसाधन। बैठक के अन्त में दोनों पक्षों के बीच एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री ई.वी.के.एस. इलांगोवन तथा उजबेकिस्तान के उप प्रधान मंत्री श्री मिराबरारे उस्मानोव द्वारा संयुक्त रूप से एक क्रेता-बिक्रेता मेले का उद्घाटन किया जिसमें उजबेकिस्तान के व्यावसायिकों और वरिष्ठ स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया ।

भारतीय मिशनों के प्रमुखों/सीआईएस देशों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों का सम्मेलन 10 जनवरी 2005 को ताशकंद में सम्पन्न हुआ ।

उक्रेन

भारत-उक्रेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध संयुक्त समिति की चौथी बैठक 1 अप्रैल 2004 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। भारतीय उद्योग मण्डल द्वारा कीव में (8-11 जुलाई) एक 'इन्टरप्राइज इण्डिया 2004' प्रदर्शिनी का आयोजन किया गया। ऑटोमोबाइल हिस्से-पुर्जो, साइकिलों

औजारों, नकली आभूषणों तथा सौंदर्य प्रसाधनों आदि क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाली 30 से अधिक कंपनियों ने इस प्रदर्शिनी में भाग लिया। उक्रेन के वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल के सहयोग से ईईपीसी ने जून 2004 में कीव में एक 'बायर-सेलर मीट' का आयोजन किया। 'बायर-सेलर मीट' में 10 से अधिक इंजीनियरी फर्मों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया ।

अजरबैजान

अजरबैजान में एक बैंक के स्वचलन (ऑटोमेशन) के संबंध में बैंकिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए मैसर्स इनफॉसिस लिमिटेड को 900,000 अमरीकी डॉलर की एक संविदा प्रदान की गई। बाकु में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र की अध्यक्ष डा. लेयला अलियेवा 22-26 अगस्त 2004 तक भारत की यात्रा पर आई। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया तथा सेंटर फॉर कॉकेसियन स्टडीज, चण्डीगढ़ में कॉकेसस मामलों पर कई व्याख्यान दिए ।

अर्मेनिया

संयुक्त सचिव (युरेशिया) विदेश कार्यालय परामर्श के लिए 3-4 मई 2004 को अर्मेनिया की यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान संयुक्त सचिव (युरेशिया) ने अर्मेनिया के विदेश मंत्री, विज्ञान एवं शिक्षा मंत्री, वित्त एवं अर्थव्यवस्था उप-मंत्री, विदेश उप-मंत्री, कृषि उप-मंत्री तथा संस्कृति एवं युवा कार्य उप-मंत्री के साथ मुलाकात की ।

जार्जिया

संयुक्त सचिव (यूरेशिया) 15-17 दिसम्बर 2004 तक जार्जिया की यात्रा पर गए। उन्होंने जार्जिया के प्रधान मंत्री, जार्जिया संसद के अध्यक्ष तथा जार्जिया के विदेश उप मंत्री और आर्थिक विकास उप मंत्री के साथ बैठकें की। विचार विमर्श पारस्परिक हित चिन्ताओं के मामलों पर केन्द्रित रहा ।

बेलारूस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग से सम्बद्ध भारत बेलारूस संयुक्त समिति की तीसरे सत्र की बैठक में भाग लेने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कपिल सिब्बल ने नवम्बर 2004 के प्रथम सप्ताह में मिन्स्क में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। बेलारूस की स्टेट कमेटी फॉर साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी के अध्यक्ष के साथ बैठकों के अलावा उन्होंने बेलारूस के प्रधान मंत्री, बेलारूस की विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष और बेलारूस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने भारत-बेलारूस वैज्ञानिक संगोष्ठी को भी सम्बोधित किया तथा मिन्स्क में कई प्रख्यात अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का दौरा किया। वियतनाम की यात्रा पर जाते हुए बेलारूस के प्रधान मंत्री श्री सेरगी सिदोरस्की 7 नवम्बर 2004 को मार्ग में नई दिल्ली में ठहरे। अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान बेलारूस के प्रधान मंत्री का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास राज्य मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने स्वागत किया। सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संयुक्त सचिव (युरेशिया) और अन्य भारतीय अधिकारी श्री सिब्बल के साथ गए ।

■■

5

खाड़ी, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका

खाड़ी देश

वर्ष 2004-2005 के दौरान भारत और खाड़ी देशों के बीच महत्वपूर्ण यात्राओं के आदान-प्रदान और अनके करार सम्पन्न हुए। जहां तक खाड़ी प्रभाग का संबंध है, वर्ष 2004 उत्तेजनापूर्ण रहा, विशेष रूप से इराक में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण।

इराक

इराक में राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ करने के प्रथम कदम के रूप में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1946 का स्वागत किया। प्रधान मंत्री ने इराके के अंतरिम प्रधान मंत्री ईयाद अल्लावी को बधाई संदेश भेजा और इराक के लोगों की उनके पुनर्वास में सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने अपने समकक्षी होशियार जिबारी को पत्र भेजा जिसमें अन्तिरम सरकार के गठन का स्वागत किया और पुनर्निर्माण कार्यकलापों में भारत द्वारा भूमिका निभाए जाने की पेशकश की। दोहा (मई 2004), टोकिया (अक्तूबर 2004) में सम्पन्न इराक के दानदाताओं के सम्मेलनों में भारत सक्रिय भागीदार रहा। भारत ने डब्ल्यूएफबी के माध्यम से इराकी बच्चों के लिए 1.1 मिलियन डालर मूल्य का दूध पाउडर का वितरण कराया। आइटैक कार्यक्रम के तहत इराकी अधिकारियों के प्रशिक्षण सीटों की संख्या 75 से बढ़ाकर 125 प्रति वर्ष कर दी गई। इराकी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की छात्रवृत्तियों की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील समस्या तब उत्पन्न हुई जब इराक में एक आतंकवादी ग्रुप ने 21 जुलाई 2004 को चार अन्य विदेशी नागरिकों के साथ तीन भारतीयों को बंधक बना लिया। कठिन प्रयत्नों के बाद सरकार 2 सितम्बर 2004 को भारत सरकार बंधकों को मुक्त कराने में सफल हुई। इसके बाद, अस्थाई उपाय के रूप में सरकार ने इराक में यात्रा पर न जाने का परामर्श जारी किया। इराक यात्रा के लिए प्रवास नियंत्रण को और भी कड़ा कर दिया गया। भारत ने भारत में 30 इराकी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की भी पेशकश की ।

संयुक्त अरब अमीरात

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक और पारस्परिक हित के संबंध सुदृढ़ किए गए। शोक संतप्त शासक परिवार और संयुक्त अरब अमीरात नेतृत्व को सांत्वना देने के लिए भारत के राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तथा उनके साथ विदेश राज्य मंत्री श्री अहमद 3-4 नवम्बर 2004 को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए। विदेश मंत्री 27 और 28 दिसम्बर 2004 को आबुधाबी और दुबई की यात्रा पर गए। आबुधाबी में मंत्री ने माननीय राष्ट्रपति जी की ओर से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायेद अल नाहियान को भारत की यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया और आबुधाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहियान तथा उप प्रधान मंत्री एवं विदेश राज्य मंत्री शेख हमद बिना जायेद अल नाहियान के साथ राजनीतिक, सामरिक, सैन्य और आर्थिक सहयोगग के बारे में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया। संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन की घोषणा की। मंत्री ने क्षेत्र के 15 देशों के भारतीय मिशनों के प्रमुखों के सम्मेलन को भी सम्बोधित किया। विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने मिशनों के प्रमुखों के सम्मेलन में तथा विदेश मंत्री की शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम के साथ बैठक में भाग लिया। संयुक्त अरब अमीरात भारतीय निर्यात का महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। भारत ने आईडीईएक्सपीओ 2005 में भाग लिया। दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का नियमित आदान-प्रदान चला रहा, जिसमें प्रमुख व्यापार मेलों में भागीदारी भी शामिल है ।

संयुक्त अरब अमीरात भारतीय निर्यात का दूसरा सबसे बड़ा स्थान बना रहा। दोनों देशों के बीच पारस्परिक प्रतिनिधिमंडलों का आना-जाना नियमित रूप से चलता रहा, जिसमें प्रमुख व्यापार मेलों में भागीदारी भी शामिल है। दिसम्बर 2004 के अन्त में विदेशी मंत्री का संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम है ।

बहरीन

विश्व मलयाली सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद 19 से 21 अगस्त 2004 तक बहरीन की यात्रा पर गए। सचिव स्तर पर दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच परामर्श वार्ता का पहला दौर 16 से 19 नवम्बर 2004 तक नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। नई दिल्ली में 33वीं इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड एक्जीबिशन में भाग लेने के लिए बहरीन के प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री अब्दुलनबी अल शोआला के नेतृत्व में सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेंट का एक 25 संसदीय प्रतिनिधिमण्डल 22 नवम्बर से भारत की यात्रा पर

आया। 7 से 9 जनवरी 2005 तक मुम्बई में सम्पन्न प्रवासी भारतीय दिवस को बढ़ावा देने के संबंध में अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जगदीश टाइटलर एक दिन की सरकारी यात्रा पर 24 नवम्बर 2004 को बहरीन गए। भारतीय नौसेना के दो पोत - आईएनएस दिल्ली और आईएन कुलिश - 22 से 26 सितम्बर 2004 तक बहरीन की सद्भावना यात्रा पर गए। विदेश मंत्री की 29 दिसम्बर 2004 को बहरीन की अनुसूचित यात्रा सुनामी के विध्वंस के फलस्वरूप हुई घटनाओं के कारण रद्द करनी पड़ी चूंकि इसके लिए भारत में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी ।

दोहा

श्री ई. अहमद, विदेश राज्य मंत्री 15-16 सितम्बर 2004 तक कतर की यात्रा पर गए और उन्होंने कतर के विदेश राज्य मंत्री महामहिम अहमद बिन अब्दुल्ला अल महमूद से मुलाकात की। विभिन्न द्विपक्षीय, अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों के अलावा उन्होंने पश्चिम एशिया के साथ भारत के पारम्परिक संबंधों को दिए जा रहे नए बल पर प्रकाश डाला। चौथा विश्व यात्रा एवं पर्यटन शिखर सम्मेलन 1 से 3 मई 2004 तक दोहा में सम्पन्न हुआ और श्री एन.के. सिंह, सदस्य, योजना आयोग और श्री ललित सूरी, संसद सदस्य ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में भारत के संबंध में प्रस्तुति पेश की ।

कतर

श्री ई.अहमद, विदेश राज्य मंत्री 15-16 सितम्बर 2004 तक कतर की यात्रा पर गए और विदेश राज्य मंत्री अहमद बिन अब्दुल्ला अल महमूद के साथ द्विपक्षीय मामलों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न द्विपक्षीय, अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों के अलावा उन्होंने पश्चिम एशिया के साथ भारत के पारम्परिक संबंधों को दिए जा रहे नए बल पर प्रकाश डाला। श्री एन.के.सिंह, सदस्य, योजना आयोग और श्री ललित सूरी, संसद सदसय 1 से 3 मई 2004 तक दोहा में सम्पन्न चौथे विश्व यात्रा एवं पर्यटन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कतर की यात्रा पर गए। कतर भारत को एलएनजी का प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। कतर के द्वितीय प्रधान मंत्री और ऊर्जा एवं उद्योग मंत्री महामहिम अब्दुल्ला बिन हमद अल अत्तियाह 6 से 9 जनवरी 2005 तक भारत की सरकार यात्रा पर आए। यात्रा के दौरान उन्होंने 6 जनवरी को नई दिल्ली में सम्पन्न 'क्षेत्रीय सहयोग : ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी' से सम्बद्ध गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद वे दो दिन की यात्रा पर केरल गए जहां उन्होंने कोची में पेट्रोनेट के प्रस्तावित एलएनजी टर्मिनल के मॉडल का अनावरण किया जिसमें 2008 से एलएनजी की आपूर्ति प्राप्त होने की सम्भावना है ।

ओमान

विदेश मंत्री मस्कट की यात्रा पर गए (25-26 दिसम्बर 2004)। सुल्तान क्वाबूस बिन सईद ने उनका स्वागत किया जिन्हें उन्होंने प्रधान मंत्री का पत्र सौंपा। सुल्तान के हुए विचार विमर्श में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने विदेश, परम्परा एवं संस्कृति, तेल एवं प्राकृतिक गैस, रक्षा तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रियों के साथ भी विचार विमर्श किया। ओमान ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के अपने समर्थन की घोषणा की। दोनों देश 2005 में ओमान में भारत की राजनयिक उपस्थिति की 50वीं वर्षगांठ उपयुक्त ढंग से मनाने पर सहमत हुए। फरवरी/मार्च 2005 में एक बिलियन अमरीकी डॉलर की भारत-ओमान उर्वरक फैक्ट्री द्वारा उत्पादन शुरू करने तथा तत्संबंधी अन्य घटनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। यात्रा का एक महत्वपूर्ण परिणाम लंबे समय से लंबित ची आ रही प्रत्यर्पण संधि पर विदेश मंत्री तथा ओमान के विदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किया जाना था जिससे दोनों देशों के बीच लेखापरीक्षा में सहयोग से सम्बद्ध एक करार भी सम्पन्न किया तथा राजदूतावास के भवन का शिलान्यास किया ।

श्री ई. अहमद, विदेश राज्य मंत्री 4 से 7 नवम्बर 2004 तक ओमान की यात्रा पर गए और ओमान के विदेश परम्परा एवं संस्कृति, वाणिज्य एवं उद्योग तथा जनशक्ति मंत्रियों के साथ मुलाकात की। तीसरे प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जगदीश टाइटलर 28 से 30 नवम्बर 2004 तक मस्कट की यात्रा पर गए और ओमान में भारतीय कामगारों की हित-चिन्ताओं संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए ओमान के जनशक्ति मंत्री से मुलाकात की ।

नीतिगगत परामर्शदात्री ग्रुप के तीसरे सत्र में भाग लेने के लिए श्री राजीव सीकरी, सचिव (पूर्व) 12-14 फरवरी 2005 तक मस्कट की यात्रा पर गए। उन्होंने विदेश, वाणिज्य एवं उद्योग तथा तेल एवं गैस मंत्रियों के साथ मुलाकात की। भारत-ओमान राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ औपचारिक रूप से मस्कट में 13 फरवरी 2005 को शुरू हुई जब इस अवसर पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बधाई एवं प्रशंसा पत्रों का आदान प्रदानन किया गया।

भारत के सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष एडमिरल माधवेन्द्र सिंह के निमंत्रण पर आमेना के सुल्तान के सैन्य बल के अध्यक्ष ले. जनरल अहमद अल नाभानी 18 से 23 मई 2004 तक भारत की यात्रा पर आए। भारत के राष्ट्रीय रक्षा कालेज के अधिकारियों का एक दल एक सप्ताह के अध्ययन दौरे पर मस्कट की यात्रा पर गया। भारत की पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ सह नौसेनाध्यक्ष मदनजीत सिंह 12 से 15 सितम्बर 2004 तक ओमान की यात्रा पर गए। उसी दौरान भारतीय नौसेना पोत आईएनएस तलवार और आईएनएस प्रलय तथा पनडुब्बी आईएनएस सिंधुराज भी मस्कट बन्दरगाह की यात्रा पर गए। भारत, संयुक्त राज्य अमरीका और ओमान सल्तनत के वैज्ञानिकों के साथ तीन

देशों की अरब सागर अनुसंधान यात्रा के भाग के रूप में भारत का महासागर अनुसंधान जलयान सागर कन्या 12 से 14 सितम्बर तक मस्कट की यात्रा पर गया ।

सऊदी अरब

वर्ष के दौरान राजनीतिक और सरकारी दोनों स्तरों पर अन्योन्य क्रियाएं हुई। हज यात्रा की प्रबंध व्यवस्था के संबंध में विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद 13 से 16 जून 2004 तक और 9 से 10 नवम्बर 2004 तक जेद्दाह की यात्रा पर गए। उन्होंने 15 जून 2004 को हज 2005 के लिए करार पर हस्ताक्षर किए। करार के तहत 1,27,000 भारतीय मुस्लिम हज 2005 की यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने 13 जून को राजा फहद से मुलाकात की और भारत के प्रधान मंत्री का एक पत्र सौंपा। न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित 'जुडिशियरी एंड लॉज इन दी किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया' से सम्बद्ध संगोष्ठी में भाग लेने के लिए भारत के एटर्नी जनरल श्री सोली जे. सोराबजी 4 से 6 अप्रैल 2004 तक सऊदी अरब की यात्रा पर गए ।

श्री आर.एम. अभयंकर, सचिव (एएनए) और उनके साथ संयुक्त सचिव (खाड़ी) 8 से 12 अप्रैल 2004 तक सऊदी अरब की यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्रालय में स्थायी अंडर सेक्रेटरी महामहिम श्री इस्माइल शौरा के साथ विस्तृत परामर्श किया। उन्होंने सहायक विदेश मंत्री डा. निजार ओबीद मदानी तथा गृह-उपमंत्री डा. अहमद अल सलेम से भी मुलाकात की। सऊदी अरब के पेट्रोलियम एवं खनिज संसाधन मंत्री अली अल नाइमी 6 जनवरी 2005 को नई दिल्ली में आयोजित 'क्षेत्रीय सहयोग : ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी' से सम्बद्ध एक दिवसीय मंत्रीय स्तरीय पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर आए। भारत ने 5-8 फरवरी 2005 तक रियाध में आयोजित आतंकवाद विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। भारत को ग्रुप - 4 में आतंकवादी संगठनों और संरचनाओं को मात देने और विध्वंस करने वाला अग्रणी देश का दर्जा दिया ।

वर्ष 2003-04 के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ गति से बढ़ता रहा। इस अवधि के दौरान 19.41 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई। जिनेवा में 16 जून 2004 को सऊदी अरब के विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो जाने पर भारत और सऊदी अरब के बची द्विपक्षीय एक्सेशन करार सम्पन्न हुआ। इस करार में सऊदी अरब के बाजार में भारत के लिए निर्यात की रूचि की मदों पर सहमत टैरिफ की अनुसूची के साथ-साथ भारत के हित में सेवा क्षेत्रों में सऊदी अरब के बाजार में प्रवेश की प्रतिबद्धताएं शामिल थी। सांस्कृतिक क्षेत्र में अन्योयक्रिया बढ़ाने की दृष्टि से केशव चौधरी के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय वाद्य दल, जिसे भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित किया गया था, 27 से 31 मई 2004 तक सऊदी अरब के दौरे पर गया और रियाध एवं जेद्दाह में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सऊदी अरब में भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए एक 24 घंटे की हैल्पलाइन की स्थापना भारतीय मिशन, रियाध में की गई ।

कुवैत

कुवैत के विदेश मंत्री शेख (डा.) मोहम्मद सबह अल-सलेम अल-सबह 24 से 26 अगस्त 2004 तक भारत की यात्रा पर आए और राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और लोक सभा अध्यक्ष से मुलाकात की। यात्रा के दौरान प्रत्यर्पण संधि से सम्बद्ध करार, आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता से सम्बद्ध करार, भारत - कुवैत सामरिक परामर्शी ग्रुप की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन तथा आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध जीसीसी-भारत ढांचा करार सम्पन्न किए गए। अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जगदीश टाइटलर प्रवासी भारतीय दिवस 2005 को प्रोत्साहित करने के लिए 25 से 27 नवम्बर 2004 तक कुवैत की यात्रा पर गए। कुवैत के प्रधान मंत्री के सलाहकार डा. युसूफ हमद अल-इब्राहीम ने 6 जनवरी 2005 को नई दिल्ली में सम्पन्न 'क्षेत्रीय सहयोग : ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी' से सम्बद्ध गोलमेज सम्मेलन के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

श्री ई.अहमद, विदेश राज्य मंत्री 20-21 फरवरी 2005 तक कुवैत की यात्रा पर गए और भारत की यात्रा पर आने के लिए प्रधान मंत्री की ओर से कुवैत के प्रधान मंत्री को निमंत्रण पत्र दिया। श्री अहमद ने कुवैत के विदेश मंत्री और कुवैत की संसद के कार्यकारी अध्यक्ष से भी मुलाकात की तथा भारतीय समुदाय को सम्बोधित किया ।

विशेष कुवैत कक्ष

1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान जिन भारतीय नागरिकों को जान एवं माल की हानियां हुई थी उन्हें मुआवजे का भुगतान करने के लिए 1991 में विशेष कुवैत कक्ष की स्थापना की गई थी। मुआवजे का भुगतान संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग, जिनेवा द्वारा किया जा रहा है तथा खाड़ी युद्ध 1990-91 के पीड़ितों को मुआवजे देने के लिए धनराशि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 692 (1991) के द्वारा स्थापित 'ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम' के तहत इराकी तेल की बिक्री से प्राप्त राजस्व से आती है। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से प्राप्त मुआवजे की राशि का वितरण इस प्रयोजन के लिए नामित चार राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, इंडियान ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से किया जा रहा है ।

दावे के आवेदनपत्रों की जांच करना और प्रत्येक मामले में भुगतान की मात्रा तथा भुगतान की समय-सीमा निर्धारित करना (अथवा किसी दावे को पूरी तरह अस्वीकार करना) पूर्णतया संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग की शासी परिषद आयोग द्वारा अपनाई गई मुआवजा प्रक्रिया के अनन्तिम नियमों के अनुच्छेद 40(4) के तहत संयुक्त राष्ट्र मुआवजा

आयोग के निर्णय अन्तिम होते हैं तथा वास्तविक, प्रक्रियात्मक अथवा किसी अन्य आधार पर पुनरीक्षा अथवा अपील के अध्यधीन नहीं होते ।

1 अप्रैल 2004 से 15 जनवरी 2005 तक की अवधि के बीच संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने व्यक्तिगत दावों की श्रेणी में लगभग 1,350 दावों के लिए 14,141,354.01 अमरीकी डॉलर की राशि अन्तरित की है। पिछले वर्ष में प्राप्त राशि, जो विभिन्न कारणों से असंवितरित पड़ी रही, इस अवधि के दौरान संवितरित की जाती रही। चार नामित बैंकों द्वारा 1,635 दावेदारों को कुल 14,632,823.71 अमरीकी डॉलर की राशि संवितरित की गई। ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

श्रेणी	दावों की संख्या	भुगतान की गई राशि (अमरीकी डॉलर में)
क	924	240,551.21
ख	शून्य	शून्य
ग	631	2,527,660.94
घ	76	11,864,611.56
कुल	**1635**	**14,632,823.71**

यमन

दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श 3 से 5 जनवरी 2005 तक नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। यमन प्रतिनिधिमण्डल के नेता श्री हुसैन ताहिर बिन माहया, अरब, अफ्रीका और एशिया कार्यों के विदेश सचिव ने श्री राजीव सीकरी, सचिव (पूर्व) के साथ व्यापक स्तर पर द्विपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श किया तथा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की पुनरीक्षा की। उन्होंने विदेश राज्य मंत्री श्री ई.अहमद के साथ मुलाकात की और यमन के विदेश मंत्री का एक पत्र सौंपा जो यमन की यात्रा पर बुलाने के लिए विदेश मंत्री को सम्बोधित था। आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-यमन संयुक्त समिति का 5वाहं सत्र 15-17 जनवरी 2005 तक साना में सम्पन्न हुआ। श्री राजीव सीकरी, सचिव (पूर्व) ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। परामर्श में आर्थिक सहयोग, वाणिज्य, निवेश ऊर्जा, कोंसली मामले, संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग संबंधी मामलों को शामिल किया गया। श्री सीकरी ने विदेश मंत्री से मुलाकात की और उन्हें विदेश मंत्री की ओर से एक पत्र सौंपा। उन्होंने यमन के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा प्रधान मंत्री से भी मुलाकात की ।

श्री ई.अहमद, विदेश राज्य मंत्री ने 19-20 फरवरी तक यमन की यात्रा की तथा विदेश मंत्री के साथ विचार विमर्श किया तथा प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात की ।

हज

वर्ष के दौरान हज प्रबंधन में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों में 20 अक्तूबर 2004 को सरकार के निर्णय में ये शामिल थे - भारत की हज समिति के माध्यम से हज यात्रियों की संख्या 72,000 से बढ़ाकर 82,000 करना तथा हज 2005 के लिए आर्थिक सहायता प्रदत्त हवाई भाड़े का लाभ उठाने के लिए पूर्व की यथास्थिति बहाल करते हुए हज 2004 के दौरान लागू किए गए प्रतिबंधों को हटाना। 2005 में भारत से कुल लगभग 1,27,000 तीर्थ यात्रियों ने हज यात्रा की जिसमें 80,772 यात्रियों ने हज समिति द्वारा की गई प्रबंध व्यवस्था के तहत और शेष ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से यात्रा की ।

सऊदी अरब हज मंत्री श्री इयाद बिन आमीन मदानी के निमंत्रण पर विदेश राज्य मंत्री श्री ई.अहमद 13-16 जून 2004 तक सऊदी अरब की यात्रा पर गए और हज 2005 के लिए करार पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री ने दो पवित्र मस्जिदों के अभिरक्षक राजा फहदीबन अब्देल अजीज से 13 जून 2004 को जेद्दाह में मुलाकात की और उन्हें भारत के प्रधान मंत्री का पत्र सौंपा ।

श्री के.नटवर सिंह, विदेश मंत्री ने 27 अक्तूबर 2004 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय वार्षिक हज सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन में केन्द्रीय एवं राज्य हज समितियों के सदस्यों, संसद सदस्यों, धार्मिक विद्वानों एवं सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि नया हज समिति अधिनियम लागू होने के बाद तथा नई हज समिति के गठन के बाद यह प्रथम वार्षिक हज सम्मेलन था।

विदेश राज्य मंत्री श्री ई.अहमद हज 2005 के लिए की जा रही प्रबंध व्यवस्था की पुनरीक्षा करने के लिए 8-11 नवम्बर 2004 तक सऊदी अरब की यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान उन्होंने सऊदी हज मंत्री श्री ईयाद बिन अमीन मदानी, सऊदी अरब के उमराह कार्य उप मंत्री श्री ईस्सा खईस तथा भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सम्भारतांत्रिक प्रबंध व्यवस्था के लिए उत्तरदायी सऊदी एजेंसी साउथ एशियन मुस्सासाह के अध्यक्ष श्री अदन कतीब से मुलाकात की और हज 2005 के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए की जा रही विभिन्न प्रबंध व्यवस्थाओं के बारे में उनके साथ विचार विमर्श किया। विदेश राज्य मंत्री तथा सचिव (पूर्व) दिसम्बर 2004 में सऊदी अरब की यात्रा पर गए और हज 2005 की प्रबंध व्यवस्था की पुनरीक्षा की ।

हज 2005 के दौरान हज 2005 के कलिए जहाज पर चढ़ने के तीन नए स्थल अर्थात औरंगाबाद, गुवाहाटी और पटना (गया के स्थान पर) जोड़े गए जिसके फलस्वरूप जहाज पर चढ़ने के कुल स्थान 15 हो गए। भारत में जहाज पर चढ़ने के तीन स्थलों अर्थात अहमदाबाद, हैदराबाद, कालीकट से पहली बार लगभग 21000 तीर्थयात्रियों ने सीधे मदीना के लिए उड़ान भरी ।

तीर्थयात्रियों की अवस्थिति और संचलन की मानीटरिंग करने

और नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग किया। केवल हाजियों के उपयोग के लिए मक्का में तीन इन्टरनेट कैफे की व्यवस्था की गई। मक्का में मुख्य कार्यालय के अलावा सभी 9 शाखा कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस उपलब्ध था जिनमें प्रत्येक तीर्थयात्री के ठहरने के स्थान और पहुंचने/प्रस्थान के कार्यक्रम के बारे में तत्काल सूचना उपलब्ध कराई गई। हज तीर्थयात्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए सऊदी अरब प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई ।

संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में एक 34 सदस्यीय भारतीय हज सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल 16 जनवरी से 3 फरवरी 2005 तक सऊदी अरब की यात्रा पर गया। यात्रा के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता दो पवित्र मस्जिदों के अभिरक्षक महामहिम राजा फहदीबन अब्देल अजीज तथा सऊदी हज मंत्री के साथ मुलाकात की ।

मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के पंजीकरण की प्रणाली को हज 2005 के लिए भी जारी रखा, जो हज 2003 से आरम्भ की गई थी ताकि तीर्थयात्रियों के लिए निजी ऑपरेटरों द्वारा बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें ।

भारत - जीसीसी

भारत - जीसीसी राजनीतिक वार्ता 27 सितम्बर 2004 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान सम्पन्न हुई जिसमें जीसीसी के विदेश मंत्रियों और भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया। भारत और जीसीसी ने 25 अगस्त 2004 को नई दिल्ली में आर्थिक सहयोग के लिए ढांचा करार पर हस्ताक्षर किए। जीसीसी के महासचिव इस प्रयोजन के लिए नई दिल्ली की यात्रा पर आए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ के साथ जीसीसी - भारत करार पर हस्ताक्षर कुवैत के विदेश मंत्री डा. मुहम्मद सबह अल सलेम अल सबह और खाड़ी के अरब देशों की सहयोग परषिद के महासचिव श्री अब्दुल रहमान बिन अहमद अल अत्तियाह द्वारा किए गए। यात्रा के दौरान जीसीसी के महासचिव ने विदेश मंत्री और पर्यटन मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी के साथ भी विचार विमर्श किया। आर्थिक सहयोग के लिए ढांचा करार के तहत भारत और जीसीसी के बीच अधिकारी स्तर पर पहली बैठक 19 नवम्बर 2004 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई ।

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका

अल्जीरिया

अल्जीरिया के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ और हार्दिक बने रहे। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और व्यावसायिक स्तर पर अन्वेषणात्मक यात्राएं की गई। लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में स्थापित की गई संयुक्त समिति की पहली बैठक 21 से 26 नवम्बर 2004 तक नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। छठे दौर के लाइसेंस देने के तहत अल्जीरियाई अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे तेल/गैस अनुसंधान के लिए ब्लॉकों के तकनीकी आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (विदेश) लि. के एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 5 से 8 दिसम्बर 2004 तक अल्जीरिया की यात्रा की। अल्जीरिया ने आईटैक कार्यक्रम के तहत 5 स्लॉट प्राप्त किए हैं तथा सीएफवाई में 4 अतिरिक्त स्लॉटों का उपयोग किए जाने की संभावना है।

डी जिबूती

वर्ष के दौरान भारत - डी जिबूती के द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण बने रहे। डी जिबूती सरकार भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए उत्सुक है और नई दिल्ली में राजदूतावास खोलने का निर्णय लिया है और भारत के लिए अपना राजदूत नामित कर दिया है। डी जिबूती ने मुम्बई में एक (कोंसलावास) भी खोलने का निर्णय लिया है तथा श्री इदरिस साबाबन को अपना महाकोंसल नामित किया है ।

डी जिबूती अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में विभिन्न पदों के लिए भारतीय उम्मीदवारी का समर्थन करता रहा। डी जिबूती के लिए आईटैक स्लॉट 2003-04 में 2 से बढ़ाकर 2004-05 में 10 कर दिए गए हैं ।

मिस्र

द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे। चालू वर्ष के दौरान मिस्र से मंत्री स्तर की दो यात्राए की गई। भारतीय निवेशकों से आग्रह करने के लिए दिसम्बर में नई दिल्ली में भारतीय आर्थिक शिखर सम्मेलन में मिस्र के निवेश मंत्री डा. महमूद मोही एल-दिन ने पहली बार भाग लिया। इसी प्रकार अधिक भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मिस्र के पर्यटन मंत्री श्री अहमद अल मगरबी ने दिसम्बर में भारत में एक रोड शो प्रारम्भ किया। भारतीय पर्यटकों की संख्या प्रति वर्ष 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ रही है (2004 में लगभग 45,000 रही)।

वर्ष 2004 के दौरान पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में मिस्र भारत का महत्वपूर्ण वाणिज्यिक एवं आर्थिक भागीदार बना रहा। काहिरा और अल फायूम में दो गैस वितरण परियोजनाओं में अल्पांश इक्विटी और प्रबंधन में भागीदारी प्राप्त करके भारतीय गैस प्राधिकरण लि.(गेल) ने मिस्र के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में पहली बार निवेश किया है। गेल ने मिस्र की एक नई कंपनी नेटगैस में भी 15 प्रतिशत इक्विटी शेयर प्राप्त किए हैं। मिस्र के 10 शीर्ष गैस उत्पादकों और निर्यातकों में शामिल होने की संभावना को देखते हुए अर्थपूर्ण सहयोग को और अधिक बढ़ाने के हमारे प्रयासों में वृद्धि हुई है। भारत के पेट्रोल मंत्री ने भूमध्य सागर से लाल सागर तक एक नई उत्पाद लाइन स्थापित करने में मिस्र के साथ भागीदारी में भारत की

रुचि दिखाई है। हमने मिस्र से सीमित मात्रा में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदना जारी रखा, जिसका मूल्य प्रति वर्ष लगभग 350 मिलियन अमरीकी डॉलर है। एचडीएफसी ने 10 प्रतिशत इक्विटी शेयर लेकर और तकनीकी सहायता प्रदान करके इजिप्ट हाउसिंग डवलपमेंट कार्पोरेशन की स्थापना में सहायता की है। पूर्व यूएनएसजी बुतरस घाली ने फरवरी 2005 में भारत में साऊथ सेंटर बैठकों का उद्घाटन किया ।

इजरायल

इजरायल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ होते रहे। उप-प्रधान मंत्री तथा उद्योग, व्यापार और श्रम मंत्री एहद ओल्मर्ट 6 से 9 दिसम्बर 2004 तक भारत की यात्रा पर आए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कृषि मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री से मुलाकात की। भारत और इजरायल के बीच औद्योगिक अनुसंधान और विकास पहलकदमी से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन को शीघ्र अन्तिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान भारत से नियंत्रक महालेखापरीक्षक, वायुसेनाध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष इजरायल की यात्रा पर गए। भारत-इजरायल विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां दौर नई दिल्ली में 16 नवम्बर 2004 को सम्पन्न हुआ जिसके दौरान द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इजरायल के प्रतिनिधिमण्डल ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। भारत-इजरायल के आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्यकारी दल की चौथी बैठक 30 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2004 तक सम्पन्न हुई तथा इसके साथ-साथ निरस्त्रीकरण मामलों से सम्बद्ध द्विपक्षीय परामर्शों का पहला दौर भी सम्पन्न हुआ। राजनयिकों और सरकारी पासपोर्ट धारकों की वीजा मुक्त यात्रा से सम्बद्ध भारत-इजरायल करार 20 अक्तूबर 2004 से लागू हो गया ।

इजरायल के व्यापार संबंधी आंकड़ों के अनुसार जनवरी-अक्तूबर 2004 के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.144 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया। 2003 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यह पूरे 2003 में रिकार्ड व्यापार से अधिक थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध भारत-इजरायल संयुक्त समिति की छठी बैठक जुलाई 2004 में इजरायल में सम्पन्न हुई। दोनों पक्ष अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त परियोजनाओं पर, विशेष रूप से नानो-टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी और उन्नत सामग्रियों के क्षेत्र में, कार्रवाई करने पर सहमत हुए। रक्षा सहयोग से सम्बद्ध भारत-इजरायल संयुक्त कार्यकारी दल की तीसरी बैठक 21 से 23 दिसम्बर 2004 तक इजरायल में सम्पन्न हुई। इसकी सह-अध्यक्षता भारतीय पक्ष की ओर से रक्षा सचिव द्वारा और इजरायल के पक्ष की ओर से रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक एमोस यारोन द्वारा की गई ।

इजरायल की 'डिसइन्गेजमेंट प्लान' के बारे में 8 नवम्बर 2004 के भारत-यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया था कि इजरायल का समस्त गाजा उपनिवेशों और पश्चिम तट के भागों से वापस हटने का इरादा दो देशों के बीच समाधान की दिशा में एक कदम हो सकता है तथा इससे रोडमैप में पुनः प्रगति शुरू होने की संभावना है बशर्ते यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुसंगत संकल्पों के अनुसार हो और रोडमैप के संदर्भ में हो, यह दो देशों के बीच समाधान दिशा में एक कदम हो, इसमें उपनिवेशी गतिविधि पश्चिम तट की ओर स्थानांतरित करना निहित नहीं हो, सुव्यवस्थित ढंग से और बातचीत के द्वारा दायित्व फिलिस्तीनी प्राधिकारी को सौंपा गया हो और इजरायल गाजा में पुनर्वास एवं पुनर्संरचना कार्य में सहायता करे। प्रस्तावित वापस हटने का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समुचित समन्वय स्थापित करके किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके फलस्वरूप गाजा में सुव्यवस्थित स्थिति बहाल हो जिसमें सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ पुनर्वास और पुनर्संरचना की अनुमति होगी। हमने पुनः दृढ़तापूर्वक कहा कि मध्य पूर्व संघर्ष का एक औचित्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और दूरगामी समाधान अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सक्रिय सहयोग से राजनीतिक पार्टियों के बीच बातचीत के जरिए ही किया जा सकता है। उक्त व्यापक समाधान में सीरिया और लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। जुलाई 2004 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के पक्ष में मतदान किया था जिसमें इजरायल से पश्चिमी तट पर 'सैपरेशन फेंस' के बारे में इन्टरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के परामर्शी मत का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि इजरायल द्वारा सैपरेशन फेंस का निर्माण करना अन्तर्राष्ट्रीय नियम के विरूद्ध है ।

प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग करार से सम्बद्ध भारत-इजरायल संयुक्त अध्ययन दल की बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए वाणिज्य सचिव 13-14 फरवरी 2005 तक इजरायल की यात्रा पर गए ।

जोर्डन

इस अवधि के दौरान भारत और जोर्डन के संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बने रहे। विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद 16 से 18 जून 2004 तक जोर्डन की यात्रा पर गए। उन्होंने रीजेंट प्रिंस फैसल से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श किया तथा अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को नया बल देने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की नीति पर प्रकाश डाला। मंत्री महोदय ने राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की ओर से राजा अब्दुल्ला को शीघ्र ही किसी तारीख को भारत आने का निमंत्रण पत्र दिया। श्रम मंत्री श्री अमजद मजाली 27 सितम्बर से 1 अक्तूबर 2004 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए। अपने समकक्षी श्री सीसराम ओला से वार्ता के दौरान श्री मजाली ने श्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक बीमा के क्षेत्र में भारतीय अनुभव से

लाभ लेने की राजा की इच्छा व्यक्त की। जोर्डन के एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ भारत आने के लिए महामहिम श्री अब्दुलहादी मजाली, अध्यक्ष (सभापति) हाऊस ऑफ डिप्टीज को राज्य सभा अध्यक्ष और लोक सभा अध्यक्ष की ओर से एक संयुक्त निमंत्रण पत्र दिया गया है ।

विगत वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि व्यापार संतुलन विगत कुछ वर्षों से जोर्डन के पक्ष में है फिर भी भारतीय निर्यात में भी उत्साहजनक वृद्धि हुई है। गत वर्ष भारत ने जोर्डन को 141 मिलियन जेडी मूल्य का सामान निर्यात किया है जिसमें मसाले, चाय, तिल, मांस और मोटर वाहन एवं हिस्से-पुर्जे शामिल हैं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से अगस्त 2004 तक की अवधि के दौरान जार्डन से भारतीय आयात 144 मिलियन अमरीकी डॉलर था जबकि इसी अवधि में जोर्डन के लिए भारतीय निर्यात 101 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा ।

लेबनान

लेबनान के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बने रहे। फरवरी 2004 में फ्रांस के मेजर जनरल अलेन पेलेग्रिनी ने मद्रास रेजीमेंट के मेजर जनरल ललित मोहन तिवारी से कार्यभार ग्रहण किया जो 2001 से 2003 तक की अवधि के दौरान यूएनआईएफआईएल सैन्य दल के कमाण्डर थे। भारतीय सशस्त्र बल की छठी बटालियन अर्थात 10 गढवाल ने अक्तूबर 2004 में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था तथा उसके स्थान पर 15 असम रेजीमेंट को तैनात किया गया ।

कुछ भारतीय व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलों की यात्राओं के फलस्वरूप भारत-लेबनान के आर्थिक संबंधों में कुछ सुधार हुआ है जिनमें फरवरी 2004 में रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद के प्रतिनिधिमण्डल, अक्तूबर 2004 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रतिनिधिमण्डल और नवम्बर 2004 में भारतीय गैस प्राधिकरण लि.(गेल) के प्रतिनिधिमण्डल की यात्राएं शामिल हैं ।

लीबिया

चालू वर्ष के दौरान आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संयुक्त राष्ट्र, अमरीका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के हट जाने से भारतीय कंपनियों को अधिक अवसर प्राप्त होंगे और अन्य देशों से अधिक प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना होगा। हाइड्रोकार्बन और विद्युत क्षेत्र के साथ-साथ औषध निर्माण, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां हमारी कंपनियों के लिए अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। वर्तमान में भारतीय कंपनियां 600 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की परियोजनाओं का कार्य निष्पादित कर रही हैं। विद्युत के क्षेत्र में बीएचईएल इस समय 600 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए 1200 करोड़ रुपए की संविदा का कार्य निष्पादित कर रही है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो लीबिया में पहले से कार्य कर रहा है। नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, लीबिया के नए अनुसंधान और उत्पादन साझा करार राउण्ड (इपीएसए - रूज्) कुल 13 ऑयल ब्लॉक प्रस्तुत किए गए तथा वर्तमान राउण्ड में भारत तेल निगम को जनवरी 2005 में एक ब्लॉक प्राप्त हुआ ।

नेशनल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने जुलाई 2004 में भारतीय वस्तुओं से प्रतिबंध हटा लिए हैं। प्रतिबंध वर्ष 2000 से लगे हुए थे। वर्तमान वर्ष के दौरान व्यापार संबंधी आंकड़ों में कई गुणा वृद्धि होने की आशा है। व्यापार संबंधी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आरम्भ के दो महीनों (अप्रैल-मई) में भारतीय निर्यात 48.11 करोड़ रुपए (लगभग 10.7 मिलियन अमरीकी डॉलर) रहा। यह पिछले वर्ष (2003-04) के निर्यात की तुलना में है जो 86.60 करोड़ रुपए (18.73 मिलियन अमरीकी डॉलर) रहा था ।

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री ई.वी.के.एस. इलांगोवन भारत-लीबिया संयुक्त आयोग के 9वें सत्र की बैठक में भाग लेने के लिए 20 से 22 नवम्बर 2004 तक लीबिया की यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान जिन प्रमुख क्षेत्रों के बारे में विचार विमर्श किया उनमें हाइड्रोकार्बन, विद्युत, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और निवेश शामिल हैं। संयुक्त आयोग के विचार विमर्श के अलावा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने प्रधान मंत्री, अर्थव्यवस्था एवं व्यापार मंत्री, ऊर्जा मंत्री, जनशक्ति, प्रशिक्षण एवं रोजगार मंत्री के साथ मुलाकात की तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मेजबान बने। हाइड्रोकार्बन और विद्युत क्षेत्र के दो मिश्रित प्रतिनिधिमण्डल 11 से 15 जून 2004 तक लीबिया की यात्रा पर गए। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल परिसंघ (फिक्की) तथा भारतीय इलैक्ट्रिकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के दो प्रतिनिधिमण्डल जुलाई 2004 में लीबिया की यात्रा पर गए ।

संसदीय कार्य एवं शहरी विकास मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद राजनीतिक दृष्टिकोण से 27 से 29 नवम्बर 2004 तक त्रिपोली की यात्रा पर गए। अपने प्रवास के दौरान संसदीय कार्य एवं शहरी विकास मंत्री ने जनरल पीपल्स कांग्रेस (संसद) की विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष श्री शाहौमी, जनशक्ति और प्रशिक्षण मंत्री एफ.एम. शालगाम और श्री माटौग मोहम्मद माटौग के साथ मुलाकात की। यात्रा पर गए मंत्री ने लीबियाई नेता कर्नल गद्दाफी से भी मुलाकात की ।

मोरक्को

भारत और मोरक्को के बीच सभी क्षेत्रों में संबंध बढ़े और सुदृढ़ हुए तथा 6-9 दिसम्बर 2004 तक मोरक्को के प्रधान मंत्री द्रिस जेट्टू की भारत यात्रा से ये चरम बिन्दु पर पहुंच गए। उनके साथ एक विशाल प्रतिनिधिमण्डल आया जिसमें 7 मंत्री, 25 उच्चस्तर के अधिकारी और मीडिया के 20 प्रतिनिधि

एवं 20 व्यावसायिक शामिल थे। श्री जेट्टू ने हमारे राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा और विद्युत, नागरिक उड्डयन और कृषि अनुसंधान के क्षेत्रों में करार सम्पन्न हुए। इस दौरान भारत-मोरक्को संयुक्त आर्थिक परिषद की तीसरी बैठक भी सम्पन्न हुई जिसमें दोनों पक्षों के व्यावसायिक शामिल थे। प्रधान मंत्री और उनके उच्चस्तरीय प्रतिनिधमण्डल की यात्रा से और अधिक घनिष्ठ संबंधों की शुरूआत हुई। एक 14 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसमें उद्योग और वाणिज्य के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे, जून 2004 में मार्रकेच में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल की 35वीं विश्व कांग्रेस में भाग लिया ।

लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति के निमंत्रण पर मोरक्को संसद के दोनों सदनों के नेता, श्री अब्देलौहेद रादी, मोरक्को हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (निम्न सदन) के अध्यक्ष की बाद में इस वर्ष नई दिल्ली में एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किए जाने की आशा है।

फिलिस्तीन

विदेश राज्य मंत्री ई. अहमद 17-19 सितम्बर 2004 तक फिलीस्तीन की यात्रा पर गए। उनकी यात्रा के फलस्वरूप बुनियादी स्थिति में सुधार हुआ और स्वर्गीय राष्ट्रपति अराफात तथा अन्य फिलीस्तीनी नेताओं के साथ बातचीत हुई। यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री ने फिलीस्तीनी नेशनल ऑथोरिटी को दान के रूप में 2 करोड़ रुपए मूल्य की दवाएं तथा टाटा सफारी वाहन सौंपे। 22 नवम्बर से 17 दिसम्बर 2004 तक मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान द्वारा 10 फिलीस्तीनी राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठयक्रम आयोजित किया गया है ।

11 नवम्बर 2004 को राष्ट्रपति अराफात की मृत्यु के बाद भारत ने कहा कि वे बहुत महान तथा अत्यधिक सम्मानित अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे, जिसने फिलीस्तीन आन्दोलन के लिए तथा फिलीस्तीनी लोगों के लिए एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत बलिदान देकर निःस्वार्थ भाव से और साहसपूर्वक संघर्ष किया, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भारत के लोग और नेता उन्हें अत्यधिक सम्मान देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं तथा उन्हें सदैव भारत के सच्चे एवं पक्के मित्र के रूप में याद किया जाएगा। राष्ट्रपति अराफात के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री के नेतृत्व में अनेक पार्टियों का एक प्रतिनिधिमण्डल काहिरा गया। राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री की ओर से फिलीस्तीनी नेशनल ऑथोरिटी में अपने समकक्षों को शोक संदेश भेजे गए। राष्ट्रपति अराफात के सम्मान में संसद ने एक विस्तृत निधन सूचना पारित की।

राष्ट्रपति अराफात की दुःखद मृत्यु के बाद फिलीस्तीनी लोगों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय भातृत्व दिवस के अवसर पर 29 नवम्बर 2004 को जारी प्रधान मंत्री के संदेश में फिलीस्तीनी आन्दोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की ।

फिलिस्तीन में लोकतंत्र के आन्दोलन के समर्थन के रूप में तथा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत ने, फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के निमंत्रण पर, जनवरी 2005 में फिलिस्तीनी आवासीय चुनावों के पर्यवेक्षक के लिए चुनाव पर्यवेक्षणों का एक दल भेजा। भारत ने फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के नए राष्ट्रपति के रूप में श्री महमूद अब्बास का स्वागत किया। भारत ने इजरायल-फिलिस्तीन शान्ति प्रक्रिया के बहाल होने का स्वागत किया और 10 फरवरी 2005 को एक वक्तव्य जारी किया जिसमें कहा गया था कि :

'8 फरवरी 2005 को श्रम-एल शेख में शिखर सम्मेलन और लगभग चार वर्षों के अन्तराल के बाद इजरायल और फिलिस्तीन के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण बैठक इजरायल-फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा यह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन पाने का हकदार है। हमने दोनों नेताओं के उत्साहवर्द्धक वक्तव्य नोट किए हैं। तथापि अनेक महत्वपूर्ण मसलों का समाधान किया जाना शेष है। भारत ने सभी पक्षों की ओर से हिंसा को समाप्त करने का लगातार अनुरोध किया है। हम शांति प्रक्रिया में और प्रगति की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं जिससे एक उपयुक्त समय सीमा के अन्दर न्यायोजित और शांतिपूर्ण समाधान होगा और फलस्वरूप एक प्रभुतासम्पन्न स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र बनेगा जिसकी सीमाएं सुपरिभाषित एवं सुरक्षित होंगी तथा इजरायल देश के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा ।'

सूडान

वर्ष 2004-05 में द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के क्षेत्र में अनेक कार्यकलाप हुए। जून 2004 में सेंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, भारत तथा सूडान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच खारतूम के समीप सौर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) मॉड्यूल निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 'तकनीकी करार' सम्पन्न हुआ। जुलाई 2004 में टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने 'सूडान इलैक्ट्रानिक सिटी' के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की। ग्रेटर नील पेट्रोलियम ऑपरेटिंग कंपनी में अपनी 25 प्रतिशत भागीदारी के अलावा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग विदेश लि. (ओवीएल) ने मई 2004 में कुल 115 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत से आस्ट्रिया की ओएमवी से ब्लॉक 5ए और 5बी में क्रमशः 26 प्रतिशत और 24.5 प्रतिशत की भागीदारी अधिग्रहित की। सूडान के तेल ब्लॉकों में ओवीएल की भागीदारियों के अलावा ओवीएल को 1 जुलाई 2004 को खारतूम रिफाइनरी से सूडान पोर्ट तक उत्पाद पाइपलाइन के निर्माण की परियोजना का कार्य सौंपा गया। भारत पोर्ट सूडान में एक रिफाइनरी को अपग्रेड करने के लिए भी बातचीत कर रहा है। डारफुर के लोगों की सहायता के लिए भारत की सहायता हेतु सूडान की सरकार के अनुरोध के उत्तर में, भारत सरकार ने डारफुर के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में 20,000 टन गेहूं प्रदान किया। आईटैक

कार्यक्रम के तहत सूडान एक प्रमुख लाभ प्राप्तकर्ता देश है तथा वर्ष 2004-05 के दौरान इसे 60 स्लॉट आबंटित किए गए हैं ।

सीरिया

नवम्बर 2003 में प्रधान मंत्री की यात्रा के फलस्वरूप वर्ष के दौरान द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत हुए। राष्ट्रपति अस्सद ने भारत की यात्रा पर आने का निमंत्रण सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है ।

लघु और मध्यम क्षेत्र से सम्बद्ध संयुक्त कार्यकारी दल की पहली बैठक नवम्बर में नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। द्विपक्षीय व्यापार में (जिसका झुकाव भारत के पक्ष में बहुत अधिक है) वर्ष 2003-04 में तीव्र गति से वृद्धि हुई जो 205 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा तथा यह वर्ष 2002-03 की तुलना में 66 प्रतिशत अधिक था। अनेक भारतीय कंपनियों सरकारी निविदाओं में भाग लिया। ओएनजीसी (विदेश) ने एक अमरीकी कंपनी आईपीआर के साथ मिलकर सीरिया के उत्तरपूर्वी भाग में ब्लॉक न. 24 में तेल के अनुसंधान और विकास के लिए सीरिया सरकार के साथ एक अनुसंधान संविदा पर हस्ताक्षर किए। एबीबी इण्डिया को सब स्टेशन की सप्लाई के लिए दिसम्बर 2004 में 30 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की एक और संविदा प्राप्त हुई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक श्री ई. श्रीधरन के नेतृत्व में दमश्क में मैट्रो परियोजना को व्यवहार्यता अध्ययन के लिए कॉर्पोरेशन का एक दल अक्तूबर में सीरिया की यात्रा पर गया। इसका वित्त पोषण 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की क्रेडिट लाइन से किया जाएगा जिसकी घोषणा पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा की गई थी। भारत सीरिया संयुक्त हाइड्रोकार्बन समिति की बैठक 14 फरवरी 2005 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई ।

ट्यूनीशिया

भारत और ट्यूनीशिया के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण बने रहे। ट्यूनीशिया विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थक रहा है। द्विपक्षीय व्यवसाय की संभावनाओं का पता लगाया गया है और भारत में उर्वरक क्षेत्र में भारी ट्यूनीशियाई निवेश तथा ट्यूनीशिया के लिए भारत के व्यापार में वृद्धि होने के फलस्वरूप इसके लाभ प्राप्त होने आरम्भ हो गए हैं। इण्डियन इलैक्ट्रिकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन का एक छह सदस्यीय दल ट्यूनीशिया की यात्रा पर गया और अपने ट्यूनीशियाई समकक्षों के साथ लाभदायक विचार विमर्श किया। दूरसंचार उद्योगों में भारतीय सप्लाई की बहुत अधिक गुंजाइश है। जुलाई में भारत में सफलतापूर्वक सम्पन्न भेषज और औषध निर्माण से सम्बद्ध भारत-ट्यूनीशियाई संयुक्त कार्यकारी दल की दूसरी बैठक 2005 में ट्यूनीशिया में सम्पन्न हुई तथा इसे क्षेत्र में औषधियों एवं तत्संबंधी अन्य मदों के भारतीय निर्यात में और मजबूती आएगी ।

■■

अफ्रीका (दक्षिण सहारा)

6

वर्ष के दौरान अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। अफ्रीकी देश उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरूद्ध संघर्ष के दौरान भारत द्वारा उन्हें की गई सहायता को कृतज्ञतापूर्वक याद करते हैं। अधिकांश अफ्रीकी देशों के साथ हमारा सीमित द्विपक्षीय व्यापार होता है। यह सर्वविदित है कि हमारी वस्तुएं, चाहे वह उपभोक्ता या पूंजी हो, दुनिया में श्रेष्ठ हैं और कीमतें बहुत कम है। भारतीय प्रौद्योगिकी को व्यापक पहचान और प्रतिष्ठा प्राप्त है। यह गहन रूप से अनुभव किया गया है कि भारत अफ्रीका महादेश के लिए काफी मददगार हो सकता है क्योंकि यह प्रगति एवं विकास की ओर अग्रसर है।

भारत एवं अफ्रीका के बीच संबंधों की निकटता प्रदर्शित करते हुए जंजीबार के राष्ट्रपति ने मार्च में भारत की यात्रा की। नाईजीरिया के राष्ट्रपति ने नवम्बर, 2004 में भारत की संक्षिप्त यात्रा की। भारत के उप-राष्ट्रपति ने दक्षिण अफ्रीका के 10 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में वहाँ की यात्रा की। कोमोरोस, लेसोथो, मॉरीशस, सेनेगल और बुरकिना फासो के विदेश मंत्रियों ने विगत 2-3 महीनों के दौरान भारत की यात्रा की।

भारत के राष्ट्रपति ने सितम्बर में तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। हमारे राष्ट्रपति को अपनी यात्रा के दौरान पान-अफ्रीकी संसद को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। अफ्रीकी संसद को संबोधित करने वाले वे पहले गैर-अफ्रीकी राष्ट्रपति थे। कॉंग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी ने नवम्बर,2004 के अंतिम सप्ताह में मॉरीशस की यात्रा की। प्रधान मंत्री शीघ्र ही मॉरीशस की यात्रा करने वाले हैं।

भारत और अफ्रीका के बीच उच्च स्तर पर परस्पर दौरों से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष आपसी संबंध को और मजबूत करने के प्रति अत्यंत गंभीर हैं। यह एक सच्चाई है कि भारत और अफ्रीका दोनों अच्छी तरह यह स्वीकार करते हैं कि इन दोनों को एक-दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है और पिछड़ापन एवं गरीबी के विरूद्ध अपने साझे संघर्ष में वे स्वाभाविक साझेदार हैं। विगत वर्ष के दौरान क्षेत्र के देशों को कई प्रकार के ऋण दिए गए हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नेपाड को 200 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण दिया गया है। हाल ही में भारत ने मोजाम्बिक, केन्या, लेसोथो, सेनेगल, अंगोला आदि को ऋण दिया है। पहले पश्चिम अफ्रीका के 8 देशों को 500 मिलियन डॉलर ऋण देने का निर्णय लिया गया जिसे सामान्यतः टीम-9 पहल कहते हैं। इस ऋण के उपयोग के तौर-तरीकों पर आगे चर्चा करने के लिए भारत में हाल ही में इन देशों के प्रतिनिधियों (जिसमें 4 विदेश मंत्री शामिल हैं) की उच्च-स्तरीय बैठक हुई।

अब हम अफ्रीका के साथ हमारे सहयोग के कुछ बिन्दुओं पर चर्चा करें। भारत वर्तमान में मॉरीशस में 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत पर इन्टरनेशनल कन्वेंसन सेंटर का निर्माण कर रहा है। जहां आधी राशि सहायता के रूप में दी जाएगी वहीं शेष आधी राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। हाल ही में साइबर सिटी का निर्माण कार्य पूरा किया गया और यह पूर्णतः ऋण द्वारा वित्तपोषित है। अन्य विचाराधीन परियोजनाएं हैं जिसके लिए मॉरीशस को उपयुक्त ऋण दिया जाएगा। भारत मॉरीशस को अनेक क्षेत्रों में मदद कर रहा है और सघन जन-संपर्कों के द्वारा भारत के शानदार आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध में प्रगाढ़ता आई है। यह उल्लेखनीय है कि मॉरीशस की 58 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है।

जहां तक दक्षिण अफ्रीका का सवाल है, भारत द्विपक्षीय और भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका वार्ता के दायरे के अन्दर इसके साथ सक्रिय सहयोग कर रहा है। इबसा को विकासशील दुनिया में सहयोग के प्रतिरूप में देखा जाता है और अन्य देशों में रूचि बढ़ी है। हम अन्य अफ्रीकी देशों में खनिज निष्कषर्ण, तेल /गैस की खोज आदि क्षेत्र में संयुक्त उद्यम पर भी विचार कर रहे हैं। हाल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के उद्योगपतियों का संयुक्त मंच बनाया गया। भारतीय पक्ष के अध्यक्ष श्री रतन टाटा और दक्षिण अफ्रीकी पक्ष के अध्यक्ष श्री पेट्रिस मोटसेपे हैं जो उस देश में बड़े निगम के अध्यक्ष हैं। यह आशा की जाती है कि इस मंच के गठन से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आर्थिक लेन-देन में वृद्धि होगी और विशेषकर मुख्य क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम के गठन को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार की बेहतर संभावनाएं हैं।

हमारे राष्ट्रपति की दक्षिण अफ्रीका की हाल में की गई यात्रा के दौरान उनके द्वारा की गई घोषणा के बारे में विशेष उल्लेख करना आवश्यक है। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अफ्रीका के सभी देशों के बीच तंतु प्रकाशीय एवं इलेक्ट्रॉनिक संपर्क स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता एवं अनुभव मुहैया करेगा। यह एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना है और यह अफ्रीकी राज्यों को संचार की आधुनिक प्रौद्योगिकियों और विधियों को अपनाने में समर्थ बनाएगा। यह आशा की जाती है कि संपर्क शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में इससे अफ्रीका के विकास को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और वे ई-मेडिसिन, ई-गवर्नेंस और ई-एडुकेशन आदि पर आधारित योजनाएं कार्यान्वित करवाने में सक्षम हो पाएंगे।

यह स्पष्ट है कि भारत और अफ्रीका के बीच संपर्क एक मुख्य मोड़ पर है। अफ्रीका में यह आम धारणा है कि भारत ही उनकी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्षों में मददगार रहा है और पुनः भारत ही उप-निवेश काल के विरासत के रूप में गरीबी, पिछड़ापन और आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसे समस्याओं का सामना करने में उसकी मदद कर रहा है। अफ्रीका की भारत के प्रति क्या सोच है, इसे शायद, मॉरीशस के प्रधानमंत्री द्वारा वहां की संसद में दिए गए भाषण के उद्धरण से बेहतर रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है।

'मैं यह भी मानता हूँ कि हम भाग्यशाली हैं। हम भारत को 'धन्यवाद' देना कभी नहीं भूलेंगे। हर कठित स्थिति में भारत हमारे साथ रहा है। हम आई सी टी क्षेत्र को हटाना चाहता हूँ। इसमें भारत हमारे साथ है। हमें एड्स पर एक विशाल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने में समस्या है और भारत इसमें हमारे साथ है और जब हम लोकतंत्र को मजबूत करने और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढाना चाहते हैं भारत पुनः हमारे साथ है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत अर्जित अनुभव से लाभान्वित हो रहे हैं। यही कारण है कि हम केवल भाग्यवादी ही नहीं सौभाग्यशाली हैं। इस विशाल उप महाद्वीप भारत ने ऐसी परिपक्वता लोकतंत्र की ऐसी शिक्षा दी है। पहली बार इस विशाल संपूर्ण महाद्वीप में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया। आश्चर्य की बात है कि जिसने सोचा कि हम जीतेंगे, वे हार गए। अध्यक्ष महोदय, यह परिपक्वता की मिशाल है। यह साधारण चुनौती नहीं है। वाह ! उन्होंने एक शानदार इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई है, उन्होंने इसका उपयोग किया है और यह साधारण काम नहीं है। कैसी सबक है। उन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय, हम इन सभी मामलों में लाभान्वित हो रहे हैं’।

आई टी सी और अन्य ऐसी योजनाओं के अंतर्गत मानव श्रम प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत 1960 के दशक की शुरूआत से ही अफ्रीका के देशों को वृहत् स्तर पर प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है। यह आई टी ई सी के अंतर्गत दिए जाने वाले उच्च स्तर के प्रशिक्षण के प्रति श्रद्धांजलि है क्योंकि इनके तत्त्वावधान में दिए जा रहे प्रशिक्षण पाठयक्रम के लिए चयन किए जाने हेतु बहुत स्पर्द्धा है। प्रशिक्षित मानव श्रमिकों की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने आई टी ई सी के कार्य क्षेत्र में काफी हद तक विस्तार किया है और अफ्रीका को आंबटित की जाने वाली सीटों की संख्या में वर्षों से निरन्तर वृद्धि होती रही है। यहां अफ्रीका में शॉति स्थापना के विभिन्न कार्यों में हमारी भागीदारी का उल्लेख करना आवश्यक होगा। अफ्रीका के विभिन्न देशों, जैसे-बुरूंडी, आइवरी कोस्ट, डी आर सी आदि, जो गृह युद्ध, जातीय हिंसा आदि से जूस रहे थे, में शांति स्थापना के कार्यों में भाग लेते समय हमारी सुरक्षा सेना द्वारा निभाई गई साहसिक भूमिका का उल्लेख करना आवश्यक होगा। वहां भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र की सेना का बड़ा हिस्सा है, जो इरीट्रिया और इथोपिया के बीच शांति की रक्षा कर रहा है। भारत के एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी इस सेना (यू.एन.एम.ई.ई.- यूनाईटेट नेशंस मिशन इन इथोपिया एण्ड इरीट्रिया) के सेनापति हैं। अफ्रीकी देश भारत द्वारा इस महादेश के विभिन्न भागों में स्थायित्व एवं शॉंति को पुनः कायम करने में दिए जा रहे योगदान की काफी प्रशंसा करते हैं। इन कार्यों में भाग ले रहे हमारे सुरक्षाकर्मियों ने अपनी व्यावसायिक दक्षता और मानवीय दृष्टिकोण से प्रतिष्ठा प्राप्त की है जिससे अफ्रीका के आम लोगों को यह मालूम हो रहा है कि भारत के लोग अफ्रीका के लोगों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के बारे में सचमुच चिन्तित हैं।

अफ्रीका में यह आम सहमति है कि भारत अब हर दृष्टि से मुख्य शक्ति बन गया है। यही कारण है कि अफ्रीका के अधिकाँश देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारतीय उम्मीदवारी का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। जहां तक अफ्रीका के विभिन्न देशों में बसे भारतीय समुदायों की बात है उन्होंने भारत और प्रवासी देशों के बीच संबंध को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण माध्यम का काम किया है। इन समुदायों में अधिकाँश भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनके पूर्वज 19 वीं शताब्दी में अफ्रीका आए थे। अधिकाँश अफ्रीकी देशों में भारतीय समुदायों के लोग सामान्यतः व्यापार करने में लगे हुए हैं और वे अपने देश में फुटकर व्यापार करते हैं। लालची एवं दुराचारी भारतीय व्यापारी, जिसने स्थानीय लोगों का शोषण किया और काफी लाभ कमाया, की छवि बीती बात बन गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि अफ्रीका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग स्थानीय उद्योगों में निवेश करने लगे हैं और वे इस प्रकार

यह साबित कर रहे हैं कि उनका पहला संपर्क एवं लगाव अफ्रीका में रहने वाले लोगों के साथ है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय समुदाय के अनेक लोग विभिन्न अफ्रीकी देशों के संसद सदस्य बन गए हैं। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अफ्रीका में भारतीय मूल के लोग पुराने निवासी हो गए हैं और उनकी अपनी भारतीय संस्कृति और पहचान अफ्रीका के मूल लोगों की संस्कृति में सद्भावनापूर्ण ढ़ग से मिल गई है।

भविष्य के बारे में विचार करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग के व्यापक अवसर हमारे सामने मौजूद हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी और पूँजीसहित अपना कुशल मानवश्रम अफ्रीका को, भारत और अफ्रीका दोनों देशों के लोगों के लिए परस्पर लाभप्रद ढंग से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में सक्षम बनाएगा। अफ्रीकी देशों में हुए विकासों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है।

बोत्सवाना

वर्ष के दौरान अत्यधिक सौहार्द और पारस्परिक लाभ भारत और बोत्सवाना के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को उजागर करता है। बोत्सवाना ने अनेक मुद्दों पर भारत का समर्थन किया है और अंतराष्ट्रीय चुनावों में भारत के पक्ष में मत दिया तथा अनेक मामलों में भारत का सहयोग किया। बोत्सवाना एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (बेडिया) के शीर्षस्थ अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने नए निवेशकों की तलाश में मई 2004 को भारत का दौरा किया। टेलीकम्यूनिकेशन कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री जी0डी0 गैहा ने जुलाई 2004 में बोत्सवाना का दौरा किया। वे बॉयसी सबीटैला, विज्ञान संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले। साथ ही, उन्होंने बोत्सवाना टेलीकम्यूनिकेशन कॉरपोरेशन (बी टी सी) और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी भेंट की। बोत्सवाना एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट अथॉरिटी (बेडिया) के आमंत्रण पर 11 भारतीय व्यवसायियों के दल ने, जिसमें मैसर्स लार्सन एंड टॉब्रो (कोलकाता) और टाटा इनफोकॉम के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जुलाई 2004 को बोत्सवाना का दौरा किया। ई ई पी सी द्वारा समर्थित एक 9-सदस्यीय शिष्टमंडल ने अगस्त, 2004 में बोत्सवाना का दौरा किया और निर्यात संबंधी संभावनाओं पर चर्चा की। बोत्सवाना डिफेंस फोर्स के कमांडर लेफ्टि. जनरल एल.एम. फिशर, ने सैन्यस्टाफ के प्रमुख जनरल एन.सी.विज के निजी आमंत्रण पर अगस्त, 2004 में भारत का दौरा किया। बेडिया के अनुसार भारत 2002 से अब तक 31 ऽ कुल निवेश के साथ बोत्सवाना में सबसे बड़ा निवेशक था। वर्ष के दौरान बोत्सवाना में भारतीय निर्यात में भी 54% की वृद्धि हुई।

बुरूंडी

दोनों देशों के बीच के संबंध अभी भी मैत्रीपूर्ण हैं।

कोमोरोस

यूनियन ऑफ कोमोरोस के विदेश मंत्री महामहिम श्री सोएफ मोहम्मद अल-अमीन विदेश मंत्री के आमंत्रण पर 23-27 अगस्त, 2004 को भारत के सरकारी दौरे पर आए थे। दोनों पक्षों की ओर से यह पहला उच्च-स्तरीय दौरा था। द्विपक्षी वार्ता में भारत तथा कोमोरोस विविध क्षेत्रों में संबंधों को मधुर बनाने पर सहमत हुए। यू एन जी ए कोमोरोस के 59 वें सत्र में कोमोरोस ने सुरक्षा परिषद तथा ईकोसोक की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

मालावी

नए भारतीय उच्चायुक्त ने 12 अक्टूबर, 2004 को मालावी के राष्ट्रपति को अपना प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत किया। इस बैठक के दौरान मालावी के राष्ट्रपति ने भारत के साथ राजनैतिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी संबंधों को और अधिक मजबूत करने की इच्छा जताई। मालावी के उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री जान ब्राइट खुमबो चिरवा 12 नवम्बर से 19 नवम्बर, 2004 तक भारत के दौरे पर आए थे। नई दिल्ली में रहते समय उन्होंने आई टी पी ओ व्यापार मेला देखा तथा स्थानीय रूप में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके मालावी में लघु तथा मध्यम उद्यमों को लगाने की संभावना पर चर्चा की। अनेक मालावी छात्रों ने हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा दी गई आई टी ई सी/स्कैप छात्रवृत्तियां प्राप्त की हैं।

नामीबिया

भारत और नामीबिया के बीच द्विपक्षीय संबंध काफी सौहार्दपूर्ण रहे हैं और इन संबंधों का वर्णन 1990 में नामीबिया के स्वतंत्र होने से पहले तथा बाद में सहयोग की एक सशक्त परंपरा के पास्परिक मूल्यांकन से किया जाता है। नामीबिया संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का लगातार समर्थन करता रहा है। इसने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए किए गए भारत के दावे का समर्थन किया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशासन के वरिष्ठ उप-निदेशक, श्री एस. कृष्णन ने आई टी ई सी कार्यक्रम के अंतर्गत नामीबिया में सिविल सेवा संस्थान स्थापित करने के संबंध में नामीबिया की सरकार से सलाह-मशविरा करने के लिए 12-18 अप्रैल 2004 को नामीबिया का दौरा किया। नामीबिया के राष्ट्रपति की फरवरी 2003 में भारत दौरे के दौरान, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा

की गई घोषणा के अनुसार 5000 टन चावल दान के रूप में 3 मई 2004 को नामीबिया सरकार को औपचारिक रूप से दे दिया गया था। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के एक छः- सदस्यीय शिष्टमंडल ने 20-23 जून 2004 को नामीबिया का दौरा किया। यह दौरा नामीबिया के खान एवं ऊर्जा मंत्री के आमंत्रण पर था। वैयक्तिक व्यवसायियों के दौरों के अलावा, सी आई आई के एक छः-सदस्यीय शिष्टमंडल ने अफ्रीका एशिया इनवेस्टमेंट एंड ट्रेड प्रोमोशन सेंटर के यूनिडो कार्यक्रम के अंतर्गत 4-7 जुलाई 2004 को नामीबिया का दौरा किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एस.रामासुंदरम ने एस ए सी यू के साथ विचार-विमर्श करने की दृष्टि से नामीबिया के लिए एक आधिकारिक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया ताकि एक ऐसी रूपरेखा पर सहमति बन सके, जो भारत और एस ए सी यू के बीच मुक्त व्यापार समझौता संबंधी बातचीत के लिए एक आधार के रूप में काम करे। दोनों पक्ष, रूपरेखा संबंधी समझौते पर सहमत थे जिस पर दो चरणों में बातचीत की जाएगी। आई सी सी आर द्वारा प्रायोजित मेरी भूमि मेरे लोग नामक फोटो प्रदर्शनी का आयेजन नामीबिया के विन्डहोक में 21 से 28 अक्तूबर, 2004 तक किया गया था। नामीबिया के मुख्य न्यायाधीश ने दिसम्बर में एक निजी संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। नामीबियाई नेतृत्व द्वारा मानव संसाधन विकास के प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय सहायता की सराहना की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 13 नामीबियाई उम्मीदवारों ने एस सी ए ए पी/आईटेक की छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त की है। चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षण हेतु 13 अभ्यर्थियों का अनुमोदन किया गया है। छः नामीबियाई छात्रों को आई सी सी आर छात्रवृत्ति मिली है।

जाम्बिया

इस अवधि के दौरान जाम्बिया के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ होते गए हैं। भारत ने एक सौ हजार डॉलर मूल्य के एण्टी-टिट्रोवायरल ड्रग्स दान में दिए। इन दवाओं की एक खेप भारतीय उच्चायुक्त द्वारा औपचारिक रूप से 8 अप्रैल 2004 को जाम्बिया के स्वास्थ्य मंत्री के सुपुर्द की गई थी। भारत सरकार ने जाम्बिया को 1979 में दिए गए ऋण और उस पर आए ब्याज को मिलाकर लगभग 3 मिलियन डॉलर की बकाया देयताओं को माफ करने का निर्णय लिया। जाम्बिया के वित्त मंत्री और भारतीय उच्चायुक्त के बीच 9 जुलाई 2004 को आस्थगन करार संपन्न हुआ था। भारतीय संसद के अधिष्ठाताओं ने जाम्बिया नेशनल एसेंबली के वक्ता को संसदीय शिष्टमंडल के साथ भारत आने का आमंत्रण दिया। इस आमंत्रण को स्वीकार किया गया तथा यह दौरा 2005 के पूर्वार्द्ध में होने की संभावना है।

जाम्बिया में भारत की आर्थिक मौजूदगी भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए नए निवेशों और उन्हें दिए गए ठेकों से संभली हुई है। जाम्बिया सरकार ने जाम्बिया की सबसे बड़ी कोंकोला तांबे की खानों के पुनरूर्द्धार के लिए मैसर्स वेदांत रिसोर्सेज, मैसर्स स्टर्लाईट इण्डस्ट्रीज ऑफ इंडिया की मूल कंपनी को प्रमुख इक्विटी साझेदार के रूप में चुना है। एक अन्य भारतीय कंपनी, मैसर्स कमानी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को जाम्बिया और नामीबिया के सीमावर्ती शहरों के बीच एक पावर ट्रांसमिशन लाईन लगाने के लिए 11 मिलियन डॉलर का ठेका मिला है। टाटा समूह के अध्यक्ष मि0 रतन टाटा ने लुसाका का दौरा किया और 26 अक्तूबर, 2004 को राष्ट्रपति से मुलाकात की तथा खनन, विद्युत उत्पादन और अंतरण, पर्यटन और ऑटोमोबाईल क्षेत्रों में नए निवेश पर विचार करने पर अपनी सहमति जताई। टाटा समूह ने लुसाका में ताज पामोदजी होटल के नवीकरण में 8 मिलियन यू एस डॉलर का निवेश किया जो कि इस समूह और जाम्बिया सरकार के बीच संयुक्त प्रयत्न है। मैसर्स वाटर एंड पावर कन्सल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (वैपकोस) के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दो-सदस्यीय दल ने सिंचाई क्षेत्र में कॉमेसा सचिवालय के साथ भारतीय सहयोग के तौर-तरीके पर चर्चा करने के लिए 15-17 अगस्त,2004 को जाम्बिया का दौरा किया।

मोजाम्बिक

मोजाम्बिक के साथ पहले से ही विद्यमान नजदीकी संबंध वर्ष के दौरान और अधिक मजबूत हो गया। श्रम में सहयोग के लिए संपन्न समझौता ज्ञापन के तहत गठित संयुक्त कार्य समूह (जे डब्ल्यू जी) की पहली बैठक 12-16 अप्रैल 2004 के दौरान मापूटो में हुई। डा0 पी.डी. सेनोय, सचिव (श्रम) के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने मोजाम्बिक के श्रम मंत्री और श्रम मंत्रालय में उच्च स्तर के अन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। भारतीय पक्ष मोजाम्बिक के अनुदेशकों को रोजगार और पेशेवर प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और श्रम सांख्यिकी के क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने पर सहमत था।

एच आई पी सी पहलों के तहत, भारत सरकार ने मोजाम्बिक को सरकार-दर- सरकार दिए गए सभी बकाया ऋणों को माफ कर दिया है। राष्ट्रपति चिसानों की मई 2003 में भारत के दौरे के दौरान मोजाम्बिक को भारत द्वारा दिए गए 20 मिलियन यू एस डॉलर के ऋण के उपयोग के लिए भारत के एक्जिम बैन और मोजाम्बिक के प्राधिकारियों के बीच

फिलीस्तीन नेता यासर अराफात, विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद का स्वागत करते हुए, रामल्ला का वैस्ट बैंक टाऊन, 17 सितम्बर 2004।

अपनी दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थाबो म्बेकी के साथ, 14 से 18 सितम्बर 2004।

एक करार संपन्न हुआ था। एशिया पैसिफिक उद्यमियों के एक यूनिडो प्रायोजित शिष्टमंडल के दौरे के दौरान, जिसमें विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय उद्योगपति शामिल थे, सी आई आई ने मोजाम्बिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए। राईट्स और ईरकॉन लिमिटेड के संकाय को 600 कि0मी0 लम्बी बेरा रेलवे प्रणाली, जो संपूर्ण जाम्बेजी घाटी की जीवन रेखा है और जो मोजाम्बिक के पश्चिम में स्थल-रूद्ध पेशों के लिए हिन्द महासागर तक पहुंचाने का एक प्रमुख मार्ग है, को पुनः प्रतिष्ठापित करने और इसका प्रबंध करने के लिए रियायत दी गई थी। मोजाम्बिक सरकार, और राईट्स तथा ईरकॉन लिमिटेड के संकाय एवं सी एफ एम, मोजाम्बिक रेलवे अथॉरिटी के बीच यह रियायत करारनामा राष्ट्रपति चिसानो और मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों की मौजूदगी में 5 अक्तूबर 2004 को संपन्न हुआ।

मोजाम्बिक सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने दो भारतीय सैन्य पोतों, आई एन एस सुजाता और आई एन एस सावित्री को 30 मई से 27 जून,2004 की अवधि के दौरान मोजाम्बिक के जल क्षेत्र में लगाया। इन दोनों पोतों ने 2-4 जून 2004 तक विश्व आर्थिक मंच के अफ्रीका आर्थिक शिखर सम्मेलन और 23-24 जून 2004 को चौथे ए सी पी शिखर सम्मेलन के दौरान तटीय सुरक्षा प्रदान की। समुद्री उड़ान और तटीय गश्त लगाने के अलावा इन दोनों पोतों ने उक्त अवधि के दौरान मोजाम्बिक के नौ सैनिकों को प्रशिक्षण भी दिया। मोजाम्बिक के रक्षा मंत्री ने दो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के दौरान मोजाम्बिक के समुद्री तट पर सुरक्षा और जांच की क्षमता को सुदृढ़ करने में अपना योगदान करने के लिए भारत के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति के आग्रह पर, भारत ने वर्ष 2004-05 से मोजाम्बिक के लिए एस सी ए ए पी स्लॉटों की संख्या को 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया है। भारत ने कृषि विज्ञान में डिग्री पाठ्यक्रम के लिए मोजाम्बिक के 9 छात्रों के नामांकन को भी स्वीकार किया। भारत द्वारा दी गई प्रशिक्षण सुविधाओं की मोजाम्बिक के प्राधिकारियों द्वारा जमकर सराहना की गई।

स्वाजीलैंड

मापुटो में हमारा मिशन उस देश में स्वामी प्राधिकरणों और भारतीय समुदायों के साथ आपसी संबंध बहाल रखने में जारी रहा।

दक्षिण अफ्रीका

वर्तमान वर्ष के दौरान भारत और दक्षिण अफ्रीकी संबंधों के बीच सामरिक महत्व की साझेदारी के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को और अधिक गति मिली। भारत के राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की 14-18 सितम्बर, 2004 को दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान इन दोनों देशों के बीच राजनैतिक स्तर पर सर्वोच्च वार्ता जारी रही थी। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति के लिए दक्षिण अफ्रीका का पहला दौरा था और इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए मील का पत्थर माना जाता है। द्विपक्षीय संबंधों की उत्कृष्ट अवस्था, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका मंच और धार्मिक एवं वैश्विक महत्व के मुद्दों पर दोनों राष्ट्रपतियों ने अपने विचार रखे। इस दौरे के दौरान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। राष्ट्रपति ने पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट को संबोधित किया, वे ऐसा करने वाले राज्य के पहले गैर-अफ्रीकी प्रमुख थे। राष्ट्रपति ने डरबन का भी दौरा किया, जहां उनका नागरिक सत्कार किया गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 2004 को न्यूयार्क में यू एन जी ए की उपजीविकाओं पर द्विपक्षीय चर्चा की। दक्षिण अफ्रीकी विदेश मंत्री और विदेशी मामले मंत्री की बैठक भी हुई थी। भारत के उपराष्ट्रपति श्री भैरोसिंह शेखावत ने ताबोम्बेकी के दूसरे कार्यकाल के शुभारंभ समारोह में और दक्षिणी अफ्रीका में लोकतंत्र के एक दशक पूर्ण होने के अवसर पर हुए समारोह में भाग लेने के लिए 26 अप्रैल से 2 मई, 2004 तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। भारत के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि की इस समारोह में मौजूदगी द्विपक्षीय संबंधों की निकटता का एक प्रमाण थी।

अन्य महत्वपूर्ण मंत्रीपदीय दौरों में विदेश राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह का 14वें नाम मंत्रीपदीय सम्मेलन और दूसरे आसरौक (एशियन अफ्रीकन सब-रिजनल ऑर्गेनाइजेशन्स कॉन्फ्रेश) में भाग लेने के लिए 19-20 अगस्त, 2004 को किया गया दौरा शामिल था। उन्होंने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की। रक्षा राज्य मंत्री श्री बी.के. हांडिक ने 21-25 सितम्बर तक बड़े शिष्टमंडल के प्रमुख के रूप में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया, इस शिष्टमंडल ने प्रीटोरिया में संपन्न अफ्रीकन एरो डिफेंस प्रदर्शनी में भी भाग लिया। नवम्बर में, ओवरसीज इंडियन्स के राज्य मंत्री मि0 जगदीश टायटलर ने अन्य बातों के साथ-साथ तृतीय प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। दक्षिण अफ्रीकी पक्ष की ओर से, महाप्रांत मंत्री डा0 एसोप पहाद, संचार मंत्री मिस मत्सेपी कसाबकुरी और लोक सेवा एवं प्रशासन मंत्री, मिस जी. जे.फ्रेज मोलेकेटी के संयुक्त शिष्टमंडल द्वारा 6-11 सितम्बर, 2004 को किया गया भारत का दौरा सबसे महत्वपूर्ण दौरा था। दौरे के महत्वपूर्ण परिणामों में लोक सेवा और प्रशिक्षण के विकास में द्विपक्षीय सहयोग का एक कार्यक्रम शामिल

है। दक्षिण अफ्रीका के विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपमंत्री मि0 डेरेक हनीकॉम ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आई बी एस ए मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अक्टूबर में भारत का दौरा किया। दक्षिण अफ्रीका के उद्योग एवं व्यापार मंत्री मि0 माहलवा विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए 6-7 दिसम्बर को भारत का दौरा कर रहे हैं और वे अपने सहयोगी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्र स्तर के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका के अनेक उपप्रांतों ने भी सहयोग के विभिन्न पहलूओं का अध्ययन करने के लिए अपने-अपने शिष्टमंडल भारत भेजे हैं।

उपर्युक्त महत्वपूर्ण राजनैतिक आदान-प्रदान के अलावा, दोनों पक्षों की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर सक्रिय संपर्क भी थे। इनमें से 25 अक्टूबर, 2004 को भारत दक्षिण अफ्रीका वाणिज्य सहयोग के संबंध में हुई बैठक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव श्री एस.एन.मेनन ने किया। वे दक्षिण अफ्रीका में बसे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों से भी मिले। इससे पहले, लद्यु उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री बी.एस.मिन्हास ने 2-8 सितम्बर,2004 को दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। दूसरी महत्वपूर्ण प्रगति भारत दक्षिण अफ्रीकी सी इ ओ मंच पर 25 अक्टूबर को हुई पहली बैठक थी। राष्ट्रपति थाबो म्बेकी भारतीय शिष्टमंडल से मिले और उन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के निजी क्षेत्रों को एक अभिनव तरीके से एकजुट करने के लिए, ताकि वैश्विक ढंग से उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन के लिए दोनों देशों की पूरक शक्तियों को बढ़ाया जा सके, मंच के संकल्प का स्वागत किया।

राजनैतिक और संचालन दोनों स्तरों पर रक्षा सहयोग को बढ़ाना जारी रहा। महत्वपूर्ण उपलब्धियों में आइ एन एस तबार का जुलाई 2004 में किया गया केप टाउन का दौरा शामिल था। भारतीय वायु सेना और दक्षिण अफ्रीकी वायु सेना ने सितम्बर, 2004 में एक संयुक्त वायु सेना रक्षा अभ्यास, गोल्डन ईगल किया, जिसमें भारतीय वायु सेना के छः मिराजों ने हिस्सा लिया। दक्षिण अफ्रीका में किसी संयुक्त अभ्यास में इतने बड़े पैमाने पर आई ए एफ वायुयान की यह पहला तैनाती था।

वर्ष के दौरान सांस्कृतिक मेलजोल भी काफी महत्वपूर्ण रहा। आई सी सी आर के तत्वाधान में अनेक संगीत/नृत्य समूहों ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। एक लोकप्रिय भारतीय थियेटर समूह ने भी पहली बार अफ्रीका का दौरा किया। केप टाउन में 31 अक्टूबर से 7 नवम्बर,2004 तक दूसरी बार इंडियन एक्सपेरिएन्स 2004 का आयोजन किया गया। इसमें एक फैशन शो, खाद्य समारोह, लोकनृत्य प्रदर्शन, दीवाली मनाने के लिए मशाल जुलूस और व्यापार मेले में भारतीय कंपनियों की भागीदारी शामिल थी। इसके जरिए भारतीय संस्कृति के अनेक पहलूओं को दर्शाया गया। यह एक भारी सफलता थी , जिसमें दर्शकों ने यह आग्रह किया कि इसे वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के अन्य शहरों में भी किया जाना चाहिए।

लिसोथो

लिसोथो के विदेशी मामले मंत्री के प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 1-7 अगस्त, 2004 को भारत का दौरा किया, ताकि नई दिल्ली में लिसोथो उच्चायोग की स्थापना को अंतिम रूप दिया जा सके। यह उच्चायोग आगामी माहों में अपना कार्य शुरू कर सकता है। भारतीय लघु उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री बी.एस.मिन्हास ने 9-10 अक्टूबर, 2004 को लिसोथो का दौरा किया। इस दौरे के दौरान दोनों सरकारों ने लघु उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लिसोथो के विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक तीन-सदस्यीय मंत्रीपदीय शिष्टमंडल ने 10-16 अक्टूबर, 2004 को भारत का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य लिसोथो सरकार और एकसपोर्ट इम्पोर्ट बैंक आँफ इण्डिया के बीच 5 मिलियन यू. एस डॉलर का एक ऋण करार संपन्न करना था। लिसोथो सरकार अपने देश में कृषि आधारभूत सुविधा को बेहतर बनाने के लिए इस ऋण का उपयोग करना चाहती है। लिसोथो के प्रधानमंत्री की पिछले वर्ष भारत दौरे के दौरान किए गए वायदे के अनुसार गेहूँ और चावल 5000-5000 टन खाद्यान्न की आपूर्ति जून, 2004 में की गई। लिसोथो सरकार ने इस उदारता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

जिम्बावे

जिम्बावे की अर्थव्यवस्था में गिरावट जारी रहने के बावजूद, जिम्बावे के साथ भारत का मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संबंध वर्ष के दौरान और अधिक प्रगाढ़ हो गया। जिम्बावे ने यू.एन. इकॉनोमिक एण्ड सोशल काउंसिल (इकोसॉक) और इन्टरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आई सी ए ओ) में भारत की अभ्यर्थिता का समर्थन करते हुए बहुपक्षीय मंचों पर भारत का समर्थन किया। भारत ने मानवाधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग और संयुक्त राष्ट्र की तृतीय समिति में जिम्बावे का समर्थन किया था। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष व्यापार और संस्कृति सहित अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत हुए हैं।

लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, जिम्बावे सरकार के स्थायी सचिव मिसेज ई. नदलोवू के नेतृत्व में एक व्यापार शिष्टमंडल

ने भारतीय उद्योग महासंघ के साथ पारस्परिक वार्ता करने के लिए जुलाई में भारत का दौरा किया। इस शिष्टमंडल में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अथॉरिटी (ई पी जेड ए) के अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस दौरे के प्रति भारतीय उद्योगपतियों ने अत्यधिक दिलचस्पी दिखाई और इससे उत्साहित होकर भारत के इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (ई ई पी सी) के शिष्टमंडल ने अगस्त में जिम्बावे का दौरा किया। नौ-सदस्यीय ई ई पी सी शिष्टमंडल ने हरारे में एक व्यावसायिक सेमिनार का आयोजन किया तथा कृषि मशीनरी, टैक्टर्स, टैक्सगईल मशीनरी, ऑटोमोबाईल्स, कृषि प्रसंस्करण मशीनरी आदि सहित अनेक क्षेत्रों में व्यापार करने के संबंध में चर्चा की। अगस्त में सितार वादक, सुजात हुसैन खान और उसके साथ कलाकारों के दौरे से भी यह द्विपक्षीय संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो गया। इन्होंने विख्यात हरारे इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंश सेंटर में जोरदार प्रदर्शन किया। हरारे की नेशनल ऑर्ट गैलरी में 8-24 सितम्बर, 2004 तक भारतीय संस्कृति की एक फोटो प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया गया था।

इथोपिया

इस अवधि के दौरान भारत और इथोपिया में मैत्री एवं सौहादपूर्ण संबंध बना रहा और विशेषकर क्षमता निर्माण और मानववे संसाधन विकास के क्षेत्रों में यह संबंध और मजबूत हो गया। इथोपिया सरकार ने अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट में इसे स्वीकार किया है जिसमें यह बताया गया है कि स्वास्थ्य विस्तरण कामगरों के प्रशिक्षण में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं और ऐसा भारत से पेशवरों की सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने की वजह से संभव हुआ है। भारत और इथोपिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ा था। तथापि, शेष व्यापार भारत के पक्ष में ही रहे थे। इथोपिया ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विभिन्न पदों के लिए भारत की अभ्यर्थिता का समर्थन भी किया है। भारत भी यूनाईटेड नेशन्स मिशन फॉर इथोपिया एण्ड इरीट्रिया के लिए शांति सैन्य दल भेजता रहा था। उक्त अवधि के दौरान किसी भी पक्ष से किसी अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति का दौरा नहीं हुआ। तथापि आधिकारिक स्तर पर कुछ दौरे हुए थे। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण इथोपिया हाउस ऑफ फेडेरेशन के स्पीकर, डा. मुलाटू तेसोम का भारत दौरा था। उन्होंने इथोपिया, अम्हारा और टिग्रे के दो संघ राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों (मुख्य मंत्रियों) के साथ 25 अक्टूबर से 2 नवम्बर,2004 तक भारत का दौरा किया। एक जर्मन गैर-सरकारी संगठन, जी टी जेड ने इस दौरे का खर्च वहन किया। दौरे के दौरान डा. तेसोम और उसके शिष्टमंडल राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के गृह मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और राजस्थान के मुख्य मंत्री से मिले। इसके अलावा, यू एन डी पी इथोपिया ने सितम्बर, 2004 में राजस्थान के लिए 15-सदस्यीय शिष्टमंडल के अध्ययन भ्रमण का आयोजन किया। शिष्टमंडल में इथोपिया, बेनिशाँगुल- गोमूज और गैम्बीला संघ राज्यों के अध्यक्ष (मुख्य मंत्री) भी शामिल थे।

भारत ने अफ्रीकन यूनियन (ए यू) कार्यकारी परिषद् के 5 वें साधारण सत्र में और अदिस अबाबा में जुलाई,2004 को हुए राज्य और सरकार के प्रमुखों के तीसरे अफ्रीकन यूनियन (ए यू) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवधि के दौरान भारत और इथोपिया के पुलिस बलों के बीच सहयोग की भावना भी पनपती हुई दिखी। भारतीय पुलिस के एक दो-सदस्यीय शिष्टमंडल, जिसमें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एण्ड डी), नई दिल्ली के महानिदेशक श्री सरबजीत सिंह और डाइरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साईंस के निदेशक एवं मुख्य फारेंसिक वैज्ञानिक डा. एम.एस. राव शामिल थे, ने 5-11 अप्रैल , 2004 को इथोपिया का दौरा किया। इस दौरे के बाद पुलिस प्रशिक्षकों के कई शिष्टमंडलों ने इथोपिया का दौरा किया। इन दौरों से दोनों मित्र देशों के पुलिस बलों के बीच सहयोग की भावना बढ़ी। उक्त अवधि के दौरान उन्नत नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी की, सॉफ्टवेयर विकास, मल्टीमीडिया और वेब डिजाइन में उन्नत पाठ्यक्रम, सामाजिक क्षेत्रों की लेखा-परीक्षा और बैंकिंग तथा वित्त में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे विविध क्षेत्रों में आईटेक के अंतर्गत 15 इथोपिया-वासियों को भारत में प्रशिक्षण दिया गया।

भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) और इथोपिया की फेडेरल एण्ड स्मॉल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एजेंसी ने 12 जुलाई,2004 को माइक्रो और लघु उद्योग विकास के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन में विकासीय योजनाएं तैयार करके और रोजगार एवं स्वरोजगार सृजित करने के लिए परियोजनाओं की पहचान करके इथोपिया में संगठित माइक्रो एवं लघु उद्योग विकास का प्रावधान है। इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिडेड को जून, 2004 में इथोपिया में 120 कि.मी. रोड़ी वाली सड़क के निर्माण के लिए 31 मिलियन यू एस डॉलर का ठेका मिला था। यह पहला मौका था जब इथोपिया में किसी भारतीय कम्पनी को सड़क निर्माण की परियोजना सौंपी गई थी। एक भारतीय कम्पनी, के ई सी इन्टरनेशनल लिमिटेड को सितंबर, 2004 में 132 कि.वा. पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 40 मिलियन यू. एस डॉलर का ढेका दिया गया था। द नार्दर्न इण्डिया टेक्सटाईल रिसर्च एसोसिएशन को वेस्त्र एवं परिधान उद्योग सहायक संस्थान स्थापित करने के लिए परामर्शदात्री सेवा संविदा दी गई। द वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेंसी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (वैपकॉश) को, जो पिछले कई वर्षों से इथोपिया में जल

क्षेत्र में परियोजनाओं का कार्यान्वित करता रहा है, सितम्बर, 2004 में चार अतिरिक्त परियोजनाएं भी दी गई थीं। यू.जी.सी. और फिक्की द्वारा आदिस अबाबा में 10 और 11 जून, 2004 को एक दो-दिवसीय शैक्षिक मेले का आयोजन किया गया था। यह मेला यू जी सी के प्रोमोशन ऑफ इंडियन हायर एडूकेशन एब्रोड (पीहेड) कार्यक्रम का एक हिस्सा था। सोलह भारतीय विश्व विद्यालयों और मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थानों ने मेले में हिस्सा लिया और इसमें इथोपिया एवं अन्य राष्ट्रों के सैकड़ों छात्रों को आकर्षित किया जो भारत में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते थे।

मैडागैस्कर

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59 वें सत्र में, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए मैडागैस्कर ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया और इकॉसॉक में भारत की अभ्यार्थिता के पक्ष में मत दिया। मैडागैस्कर के विदेश मंत्री जन. मार्शल रंजेवा का भारत दौरा 2005 के पूर्वार्द्ध में होने वाला है।

तंजानिया

राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 11-14 सितम्बर, 2004 को दार-ए-सलाम और जंजीबार राज्यों के दौरे से तंजानिया और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध और अधिक मधुर हो गए। यह 15 वर्ष के अंतराल के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति का पहला दौरा था। दौरे के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी और तंजानिया के ऋण को माफ करने के संबंध में दो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते सपन्न हुए थे। तंजानिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का खुलकर समर्थन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुरक्षा परिषद् की अस्थायी सदस्यता के लिए तंजानिया की दावेदारी का समर्थन किया। भारत ने तंजानिया को सूखा एवं अकाल की स्थिति से निपटने के लिए 4 जून,2004 को 5000 टन गेहूं और 5000 टन चावल दान के रूप में दिया। तंजानिया आईटेक कार्यक्रम के विशालतम लाभार्थियों में से एक रहा है। तंजानिया के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भारत आ रहे हैं। उनकी सहायता करने के लिए दार-ए-सलाम में 7-8 जून को एक मेले का आयोजन किया गया था जिसमें 25 भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य शैक्षणिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया। अप्रैल में दिल्ली के कव्वाल गुलाम कादिर नियाजी के नेतृत्व में 8-सदस्यीय कव्वाली दल के गायन से भारत और तंजानिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को एक नई दिशा मिली। इसके बाद मई में अभिमन्यू लाल के नेतृत्व में 6-सदस्यीय कत्थक दल ने यहां का दौरा किया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, 33 वर्ष के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड ने व्यापक भारतीय प्रसार और व्यवसायियों एवं स्थानीय तंजानिया वासियों की सुविधा के लिए 13 अक्टूबर को दार-ए-सलाम में अपनी शाखा खोली है।

यूगांडा

यूगांडा सरकार के साथ कम्पाला में 30 अप्रैल, 2004 को दोहरा करारोपण निषेध करार संपन्न हुआ था। यूगांडा के वित्त, योजना और आर्थिक विकास मंत्री माननीय गेराल्ड सेन्डौला और भारत सरकार की ओर से भारत के उच्चायुक्त ने इस करार पर हस्ताक्षर किए। श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं महासागर विकास राज्य मंत्री ने इन्टरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिसिएटिव (आई ए वी आई) की बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए 16-17 जून,2004 को कांपला का दौरा किया। वे 17 जून को सुश्री नामूयांगु जनात ब्याकाहोंडा, उद्योग और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा मंत्रालय एवं यूगांडा नेशनल काउंसिल फांर साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले। श्री कपिल सिब्बल ने यूगांडा और भारत के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में एक समझौते का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। भारत सरकार ने उत्तरी यूगांडा के विस्थापित लोगों के लिए 5 जूलाई 2004 को 16,69,747 रू0 (लगभग 38,000 यू.एस. डॉलर) की दवाईयां दान में दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सड़क एवं भवन, पूंजी परियोजना, शहरी विकास व शहरी आवास मंत्री, श्री इन्द्रविजय सिंह जदेजा के नेतृत्व में गुजरात सरकार के एक शिष्टमंडल ने 21 से 24 नवम्बर, 2004 तक यूगांडा का दौरा किया जिसका लक्ष्य यूगाँडा में बसे हुए अप्रवासी भारतीयों द्वारा गुजरात में निवेश करने की संभावना तलाश करना और ग्लोबल इनवेस्टर समिट 2005 में हिस्सा लेना था।

रवांडा

दोनों देशों के बीच का संबंध मैत्रीपूर्ण रहा। रवांडा जल्द ही अपने रेजिडेंट राजदूत के साथ नई दिल्ली में अपना दूतावास खोलने वाला है। एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का मसौदा तैयार हो चुका है और इस पर जल्द ही समझौता संपन्न होने वाला है।

सिसेल्स

राष्ट्रपति रेने की 27 वर्ष की कार्यावधि के पश्चात पूर्व उप-राष्ट्रपति जेम्स एलिक्स माईकल ने 14 अप्रैल 2004 को सिसेल्स के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। जोसफ बेल्मोंट को नए उप-राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। भारत ने वर्ष के दौरान सिसेल्स को

50,000 यू एस डॉलर मूल्य की एच आई वी/एड्स एंटीरिट्रोवायरल दवाई दानस्वरूप दी। सिसेल्स एक शैक्षिक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा (मई-जून) किया जिससे उच्च शिक्षा के लिए सिसेल्स के छात्रों को भारत भेजने से पहले विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं का पता लगाया जा सके। भारतीय रक्षा कार्मिक और स्थानीय एस पी डी एफ ने 8 से 18 नवम्बर तक दूसरी बार एक 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 'ब्लैक पैरोट' किया, जिसमें तख्ता पलट और आतंकवाद विरोधी कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया था। सिसेल्स ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों अर्थात् आई सी ए ओ परिषद का चुनाव,प्रशासन और बजट प्रश्न संबंधी संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में भारतीय उम्मीदवार का पुनः निर्वाचन, 2005-07 की अवधि के लिए इकोसॉक, यू पी यू का चुनाव, में भारत का समर्थन किया और 59वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूनिवर्सल रियलाईजेशन ऑफ द राईट्स ऑफ पीपुल्स टू सेल्फ-डिटरमिनेशन विषय पर पाकिस्तान की संकल्पना के विरूद्ध अपना मत दिया।

मॉरीशस

मॉरीशस के विदेश मंत्री जया कृष्ण कुट्टारी ने 28 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते समय इस बात पर बल दिया कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को एक पुनर्गठित यू एन सुरक्षा परिषद के प्रति व्यापक प्रतिनिधित्व के आधार पर बेहतर प्रतिबद्धता दर्शाने की जरूरत है और उन्होंने यह दोहराया कि भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने के लिए पूरी तरह योग्य है। मि0 जया कृष्ण कुट्टारी ने डब्ल्यू टी ओ के महानिदेशक के पद के लिए भारतीय नेताओं को अपनी अभ्यर्थिता से अवगत कराने के लिए 4-9 नवम्बर,2004 को भारत का दौरा किया और इसके लिए भारत का समर्थन मांगा। उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात की और सामयिक तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

श्रीमती सोनिया गांधी, संसद सदस्य और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष, ने 29-30 नवम्बर,2004 को मॉरीशस का एक अत्यंत सफल दौरा किया। उसके कार्यक्रम की सबसे प्रमुख घटना मॉरीशस में राजीव गांधी साईंस सेंटर का उद्घाटन करना था, जिसे भारतीय सहायता से स्थापित किया गया है। वे सर अनिरूद्ध जगन्नाथ,मॉरीशस के राष्ट्रपति तथा ; प्रधान मंत्री माननीय पॉल रेमंड बेरेंजर से भी मिलीं, जिन्होंने उनके सम्मान में एक भोज दिया और वे मॉरीशस में विपक्ष के नेता माननीय डा0 नवीन रामगुलाम से भी मिलीं। प्रवासी भारतीय मामले राज्य मंत्री, श्री जगदीश टाईटलर ने नवम्बर,2004 को मॉरीशस का दौरा किया। उन्होंने भारतीय पी आई ओ संगठनों की सभा को संबोधित किया और उन्हें जनवरी,2005 में प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय वायु सेना के वायुयानों ने मॉरीशस कोस्ट गार्ड और मॉरीशियन स्पेशल मोबाईल फोर्स के हेलीकॉप्टरों और वायुयानों के साथ मिलकर 4 अक्तूबर,2004 को मॉरीशस के मॉन च्वाइसी बीच के ऊपर वायु प्रदर्शन किया। मॉरीशस की जनता के सामने उच्च क्षमता वाले यंत्रों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित इस वायु प्रदर्शन को 100,000 से अधिक व्यक्तियों ने देखा। मॉरीशस के प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों और अन्य राजनयिक सदस्यों ने भी इस वायु प्रदर्शन को देखा।

मॉरीशस और भारत के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनोमिक कॉपरेशन एंड पार्टनर शिप एग्रीमेंट (सी ई सी पी ए) तैयार करने के लिए बनाए गए संयुक्त अध्ययन समूह ने नवम्बर,2004 को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। मॉरीशस और भारत के बीच पर्यटन परिवहन और वायु संपर्क के क्षेत्र में सितम्बर,2004 में महत्वपूर्ण विकास हुए। मॉरीशस के पर्यटन मंत्री अनिल गायन ने मॉरीशस के पर्यटन स्थलों को बढावा देने के लिए भारत का दौरा भी किया था। भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मॉरीशस सरकार ने एक नई रियायती वीजा व्यवस्था की घोषणा की जिसके तहत् मॉरीशस में अधिक-से-अधिक 15 दिन तक ठहरने वाले भारतीय पर्यटकों को वीजा प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते वे वहां अपने ठहरने पर होने वाले खर्च के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था को दर्शाएं। इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, मॉरीशस सरकार ने दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र के एयर इंडिया को ' फिफ्थ फ्रीडम ' अधिकार देने का निर्णय लिया, जिससे भारतीय विमान को भारत दक्षिण अफ्रीका मार्गों पर मॉरीशस से होकर यात्रियों एवं सामानों को लाने एवं ले जाने की अनुमति हासिल होगी। एयर मॉरीशस ने भी एयर मॉरीशस के यात्रियों द्वारा आगे की यात्राओं हेतु भारतीय कम्पनी के घरेलू नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए भारत के सहारा एयरलाईन्स के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया। इस करार से एयर मॉरीशस की पहुंच बढ़कर भारतीय उपमहाद्वीप के 22 शहरों तक हो गई है।

केन्या

विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढावा देने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसरण में फिक्की और यू.जी.सी. ने12-13 जून,2004 को संयुक्त रूप से 'भारतीय शैक्षाणिक मेला ' का आयोजन किया जिसमें जे एन यू, बी एच यू, सीमबॉयसिस पूणे आदि सहित 18 भारतीय विश्व विद्यालयों और 9 उप कुलपतियों ने हिस्सा लिया।

मि. कपिल सिब्बल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(स्वतंत्र प्रभार) ने इन्टरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिसिएटिव पर होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए 14-18 जून,2004 को केन्या का दौरा किया। वे केन्या के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, प्रो0 जॉर्ज साईटोटी से मिले और केन्या एवं भारत के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी एक समझौता करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर सिद्धांततः सहमति थी। केन्या के विदेश मंत्री, एच.ई.चिराऊ अली म्वाक्वेयरे ने हमारे प्रवासी मामले मंत्री को केन्या आने का निमंत्रण दिया जिसे हमारे प्रवासी मामले मंत्री ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। केन्या के न्याय मंत्री, माननीय मि0 किरायतु मुरूंगी भारत में अपने ट्रांजिट दौरे के दौरान न्याय मंत्री से मिले और प्रेस को बताया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। प्रवासी भारतीय मामले राज्यमंत्री माननीय श्री जगदीश टाईटलर ने प्रवासी भारतीय दिवस 2005 को बढ़ावा देने के लिए 15-17 नवम्बर, 2004 को नैरोबी का दौरा किया। शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन राज्य मंत्री, माननीय कुमारी सैलजा ने शहरी ग्रामीण संपर्क संबंधी अंतर-क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28 सितम्बर -3 अक्टूबर, 2004 को नैरोबी का दौरा किया।

उस्ताद अमजद अली खान और इसके बेटे अमान अली और अयान अली तथा तबला वादक शाफत अहमद खान ने 26 जून को नैरोबी में और 27 जून, 2004 को मोम्बासा में अपना प्रदर्शन किया।

एरीट्रिया

उक्त अवधि के दौरान कोई उच्च-स्तरीय दौरा नहीं हुआ। तथापि, जब उच्चायुक्त राष्ट्रपति और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिले, तो उन्होंने जल्द से जल्द राजनयिक प्रतिनिधिमंडल बनाने की सख्त आवश्यकता पर बल दिया। लगभग 1500 भारतीय शिक्षक/डॉक्टर/विशेषज्ञ एरीट्रिया में विभिन्न विभागों/क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

कांगो में भारत के राजदूत की नियुक्ति के बाद इस वर्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डी आर सी) के साथ संबंधों में तेजी से सुधार हुआ। मंत्रालय ने किंशासा में भारतीय दूतावास को फिर से खोलने का निर्णय लिया। वित्तीय और स्टाफ संबंधी आबंटन के पश्चात इसे जल्द ही कार्यान्वित किया जाएगा। औषधीय, मशीनरी, हीरा, अयस्क और खनिज आदि के क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए अनेक भारतीय कंपनियों ने डी आर सी का दौरा किया जिससे व्यापार और आर्थिक संबंध सुधरते गए। डी आर सी में भारतीय समुदाय की आबादी में पर्याप्त वृद्धि हुई है। डी आर सी के विदेशी मामले मंत्री 1 फरवरी, 2005 को भारत का दौरा करेंगे। ऐसी उम्मीद है कि दौरे के दौरान अनेक समझौते संपन्न होंगे।

पश्चिम अफ्रीका

भारत का पश्चिम अफ्रीका के देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। तथापि इस क्षेत्र के देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा सहयोग कायम करने और अधिक से अधिक नजदीकी स्थापित करने के लिए मंत्रालय ने पश्चिम अफ्रीका के लिए एक नया प्रभाग बनाया। नए प्रभाग के बनने से इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंध को व्यापक प्रोत्साहन देने में मदद मिली है।

एक नई पहल टीम-9, अर्थात् भारत और पश्चिम अफ्रीका के 8 देशों के बीच तकनीकी-आर्थिक सहयोग संबंध की शुरूआत एक मुख्य पहल है जिसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि भारत सामान्य रूप से अफ्रीका और विशेष रूप से पश्चिम अफ्रीका पर विशेष ध्यान दे रहा है। पश्चिम अफ्रीका में भारतीय मिशन को सुदृढ़ किया गया और मंत्रालय ने डी आर कांगो में भारतीय दूतावास को फिर से खोलने का निर्णय लिया।

इस क्षेत्र में भारत की ऊर्जा सुरक्षा की अधिकतर संभावनाएं हैं और मंत्रालय ने इस क्षेत्र में, विशेषकर, अंगोला, नाइजीरिया, कोट-डी आइवरी, मॉरीतानिया और विषुवतरेखीय गिनी में तेल एवं पेट्रोलियम क्षेत्र से संपर्क स्थापित करने में पहल की।

मंत्रालय ने उपयुक्त वित्तीय तंत्र स्थापित करने में भी अगुआई की जो अफ्रीका के साथ हमारे आर्थिक सहयोग के विस्तार में गति प्रदान करेगा। इस संबंध में पश्चिम अफ्रीका के देशों को कई प्रकार के ऋण दिए गए। व्यापार और आर्थिक लेन-देन, जो सीमित थी, में तेजी से वृद्धि हुई और भारतीय कंपनियों को पश्चिम अफ्रीका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

भारत ने पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय (इकोवास) के साथ सघन सहयोग स्थापित किया और नाइजीरिया में भारत के राजदूत को इकोवास का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया। कोट डी' आइवोरी और गिनी को खाद्य सहायता के साथ तकनीकी सहयोग एवं विकास सहायता जारी रही। इस क्षेत्र के देशों को एच आई वी प्रतिरोधी दवाइयां भी भेजी गईं। पश्चिम अफ्रीका के सहेलियन देशों में टिड्डे के कुप्रभाव को रोकने में मदद करने के लिए भारत ने बड़ी मात्रा में कीटनाशक भेजा। इसी प्रकार कांगो गणराज्य को मच्छरदानी उपलब्ध कराई गई।

अंगोला

अंगोला और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों में निरन्तर गर्मजोशी एवं निकटता आई है। अप्रैल, 2004 में अंगोला में लंबे गृह युद्ध की समाप्ति और विगत 2 वर्षों के दौरान इसकी एकजुटता आने से व्यापारियों का भारत से अंगोला के दौरों की संख्या में वृद्धि हुई है और इस प्रकार आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों में प्रगाढ़ता आई है।

वर्ष 2003-04 के दौरान अंगोला को भारत का निर्यात 37.31 मिलियन यू एस डॉलर का था जबकि 2003-04 के दौरान निर्यात बढ़कर 70.55 मिलियन यू एस डॉलर तक हो गया, अर्थात 89.10 ऽ की वृद्धि।

राईट्स लिमिटेड बहुत जल्द ही अंगोला के हुइला क्षेत्र में अंगोलन रेलवे रिहैविलिटेशन प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करेगा। इसके लिए जून,2004 को एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ है। इस परियोजना का वहन अंगोला सरकार को भारत सरकार द्वारा दी गई 40 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण सहायता से किया जा रहा है।

भारत ने भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण सहायता भी प्रदान की है। इस ऋण के एवज में एक प्रतिष्ठित भारतीय कंपनी कृषि मंत्रालय, अंगोला सरकार को कृषि उपकरणों की आपूर्ति करेगी।

टेली कम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल) ने लुआंडा में 24 सितम्बर,2004 को अंगोला के दूर संचार मंत्रालय के साथ एक संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसमें दूर संचार क्षेत्रों में सहयोग के पांच संभावित क्षेत्र शामिल हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शीघ्र ही अपना प्रतिनिधिक कार्यालय लुआंडा में खोलेगा।

मि0 जॉर्ज वैलेंटिम, अंगोला के होटल एवं पर्यटन मंत्री 5-11 जुलाई,2004 तक भारत के दौरे पर थे। अपने दौरे के दौरान, उन्होंने विश्व पर्यटन संगठन की परामर्शदात्री परिषद के 73 वें सत्र में और हैदराबाद में पर्यटन पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के संबंध में हुए सेमिनार में हिस्सा लिया। वे ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिले।

अंगोला विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत इंडियन टेक्निकल इकॉनोमिक कॉपरेशन (आइटेक) कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जा रहे प्रशिक्षण स्लॉटों को लगातार उपयोग कर रहा है। हाल ही में, अध्यक्ष आर ई ए (अंगोलियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्री में से एक) ने नई दिल्ली में 4-10 अक्तूबर,2004 को भारतीय उद्योग महासंघ द्वारा कराए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने के साथ-साथ, अंगोला आने वाले भारतीय व्यवसायियों की संख्या भी बढ़ रही है। अंगोला में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 200 है जबकि कुछ अंगोला के तेल क्षेत्रों में कार्य करते हैं और अन्य व्यवसाय और व्यापार से जुड़े हैं। लुआंडा में भारतीय समुदाय ने 13 नवम्बर,2004 को इंडियन एशोसिएशन ऑफ अंगोला का गठन किया।

बेनिन

बेनिन के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में एक दूतावास खोलने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य, बेनिन भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की अपनी इच्छा जाहिर करते रहे हैं और उन्होंने दक्षिण-दक्षिण सहयोग और उपयुक्त प्रौद्योगिकी में भारत की नेतृत्वात्मक भूमिका को स्वीकार किया है।

कोट डी' आइवरी

कोट डी' आइवरी में संकट से उत्पन्न कठिन परिस्थिति के बावजूद, भारतीय मिशन ने वहां अपना कामकाज जारी रखा। जब पहली बार कोट डी' आइवरी में भारत ने अपना दूतावास खोला तो दोनों देशों के संबंध और अधिक मजबूत हुए। कोट डी' आइवरी के प्रथम राजदूत, मि0 ब्ली लेने ने 29 सितंबर, 2004 को अपना प्रत्यय पत्र प्रस्तुत किया। कोट डी' आइवरी के इन्डिपेंडेंट इलेक्टोरल कमीशन (सी ई आई) के अध्यक्ष, मि0 कैमिल हॉग की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ने 5 सितंबर से 11 सितंबर 2004 तक भारत का दौरा किया। इस शिष्टमंडल को विशेषकर चुनाव और चुनाव बोटिंग मशीन आदि के लिए लोगों के पंजीयन में भारत से सुविज्ञता और अनुभव प्राप्त करने की जरूरत है। सी ई आई के साथ दो समझौते संपन्न हुए - एक निर्वाचन मामले में सहयोग के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ और दूसरा कोट डी' आइवरी में सूचना प्रौद्योगिकी युक्त चुनाव कराने हेतु आपूर्ति और सेवाओं के लिए सी एम सी लिमिटेड के साथ। भारत ने कोट डी' आइवरी को 100,000 यू.एस. डॉलर मूल्य की एंटी-रिट्रोवायरल दवाईयां दान में दी। कोट डी' आइवरी आईटेक कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से शिक्षावृत्ति प्राप्त कर रहा है। वर्ष के दौरान कोट डी' आइवरी कोट आइटेक शिक्षावृत्ति मिली।

जाम्बिया

इस अवधि के दौरान जाम्बिया के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ होते गए है। भारत ने एक सौ हजार डॉलर मूल्य के एण्टी-टिट्रोवायरल ड्रग्स दान में दिए। इन दवाओं की एक खेप भारतीय उच्चायुक्त द्वारा औपचारिक रूप से 8 अप्रैल 2004 को जाम्बिया के स्वास्थ्य मंत्री के सुपुर्द की गई थी।

भारत सरकार ने जाम्बिया को 1979 में दिए गए ऋण और उस पर आए ब्याज को मिलाकर लगभग 3 मिलियन डॉलर की बकाया देयताओं को माफ करने का निर्णय लिया। जाम्बिया के वित्त मंत्री और भारतीय उच्चायुक्त के बीच 9 जुलाई 2004 को आस्थगन करार संपन्न हुआ था। भारतीय संसद के अधिष्ठताओं ने जाम्बिया नेशनल एसेंबली के वक्ता को संसदीय शिष्टमंडल के साथ भारत आने का आमंत्रण दिया। इस आमंत्रण को स्वीकार किया गया तथा यह दौरा 2005 के पूर्वार्द्ध में होने की संभावना है।

जाम्बिया में भारत की आर्थिक मौजूदगी भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए नए निवेशों और उन्हें दिए गए ठेकों से संभली हुई है। जाम्बिया सरकार ने जाम्बिया की सबसे बड़ी कोंकोला तांबे की खानों के पुनरूर्द्धार के लिए मैसर्स वेदांत रिसोर्सेज, मैसर्स स्टर्लाईट इण्डस्ट्रीज ऑफ इंडिया की मूल कंपनी को प्रमुख इक्विटी साझेदार के रूप में चुना है। एक अन्य भारतीय कंपनी, मैसर्स कमानी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को जाम्बिया और नामीबिया के सीमावर्ती शहरों के बीच एक पावर ट्रांसमिशन लाईन लगाने के लिए 11 मिलियन डॉलर का ठेका मिला है। टाटा समूह के अध्यक्ष मि0 रतन टाटा ने लुसाका का दौरा किया और 26 अक्तूबर, 2004 को राष्ट्रपति से मुलाकात की तथा खनन, विद्युत उत्पादन और अंतरण, पर्यटन और ऑटोमोबाईल क्षेत्रों में नए निवेश पर विचार करने पर अपनी सहमति जताई। टाटा समूह ने लुसाका में ताज पामोदजी होटल के नवीकरण में 8 मिलियन यू एस डॉलर का निवेश किया जो कि समूह और जाम्बिया सरकार के बीच संयुक्त प्रयत्न है। मैसर्स वाटर एंड पावर कन्सल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (वैपकॉस) के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दो-सदस्यीय दल ने सिंचाई क्षेत्र में कॉमेसा सचिवालय के साथ भारतीय सहयोग के तौर-तरीके पर चर्चा करने के लिए 15-17 अगस्त,2004 को जाम्बिया का दौरा किया।

घाना

घाना गणतंत्र के राष्ट्रपति माननीय श्री जॉन आग्येकुम कुफूर की 2002 में भारत दौरे तथा अंगूजा में दिसम्बर,2003 को सी एच ओ जी की बैठक की तर्ज पर भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ओर माननीय श्री जॉन आग्येकुम कुफूर के बीच हुई बैठक के उपराँत, भारत-घाना के बीच द्विपक्षीय संबंध, जो इन घटनाओं से काफी सुधरे थे, सभी क्षेत्रों में अनुमानित स्तरों तक सुधरते गए तथ इन संबंधों के मजबूत होने की प्रवृत्ति जारी रही। वर्ष के दौरान किए गए करारों के साथ कुछ मुख्य उपलब्धियों की नीचे संक्षेप में व्याख्या की जा रही है।

भारत के सहयोग से आई सी टी में द इण्डिया-घाना कोफी अन्नान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई थी, जो अब पूरी तरह कार्य कर रहा है और घाना में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को काफी अच्छा प्रदर्शित कर रहा है। अन्य इकॉवास देशों की जरूरतों को पूरा करने की संभावनाएं काफी अधिक हैं। द्विपक्षीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए, घाना के लिए ऋण के दो चरणों (एल ओ सी) पर सहमति हुई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए 15 मिलियन डॉलर ऋण के लिए पहला करार एक्जिम बैंक के साथ संपन्न हुआ और संवितरण जल्द ही किए जाने की संभावना है। दूसरा चरण 27 मिलियन यू एस डॉलर एक्जिम एल ओ सी, जिसकी घोषणा तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा अम्बूजा में उपर्युक्त बैंठकों में की गई थी , इस मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है और इस पर वित्त मंत्रालय का अनुमोदन अभी लिया जाना है। ऋणों के इन चरणों से विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी उपशमन उद्देश्यों को पूरा करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में मदद मिलेगी, जिनमें ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि के संबंध में राष्ट्रपति की विशेष पहल के ट्रेक्टरों की खरीद और परिवहन क्षेत्र के लिए बसों की खरीद शामिल है।

घाना के वरिष्ठ मंत्री, माननीय श्री जे.एच मेन्साह ने टीम-9 की उद्घाटन बैठक में भाग लेने के लिए 1-2 मार्च, 2004 को भारत का दौरा किया। टीम-9 के तहत वित्तपोषण के लिए परियोजनाओं की सूची मंत्रालय को भेज दी गई है। इनमें विद्युत कृषि, रेलवे और औद्योगिकी क्षेत्रों की परियेजानाएं शामिल हैं। अब भारतीय घाना के निजी क्षेत्रों में दूसरे सबसे बड़े विदेशी निवेशक बन गए हैं और भारतीय निजी क्षेत्रों की मौजूदगी घाना में धीरे-धीरे लगातार बढ़ रही है। अनेक भारतीय व्यवसायी इस देश में व्यवसाय भी कर रहे हैं। घाना में अपने-अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करने वाली कुछ भारतीय कम्पनियों के नाम हैं- निट एवं एपटेक (सॉफ्टवेयर कम्पनी) ,टाटा, टेल्को,मारूती, डा0 रेड्डी लैब, कोर केयर हेल्थ इण्डिया आदि। घाना द्वारा लगभग 500 टाटा वाहन खरीदे गए थे। यहां अनेक भारतीय कम्पनियां हैं, विशेषकर औषधीय क्षेत्र में, जिसमें उन्होंने अपने देश के प्रबंधक नियुक्त किए हुए हैं। भारतीय औषधीय उत्पादों का योगदान घाना के औषधि और औषधीय आयात का लगभग 50 ऽ है। भारत के टी सी आई एल ने कॉपर ऐक्सेस नेटवर्क लगाने के लिए घाना दूरसंचार कम्पनी से 50 मिलियन अमरीकी डालर का करार किया था।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग की अपनी नीति के तहत भारत आई.टी.ई.सी./ एस.सी.ए.ए.पी कार्यक्रम के अन्तर्गत घाना के सिविल सर्वेटों के लिए प्रशिक्षण पाठयक्रमों की पेशकश करता रहा है। अप्रैल और नवम्बर,2004 के बीच घानावासियों ने इस वर्ष के 60 प्रशिक्षण सत्रों से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण

प्राप्त किया है। मिशन ने इस वर्ष अतिरिक्त 25 सत्रों के आयोजन का आग्रह किया है क्योंकि मानव संसाधन विकास घाना की सरकार के विकास कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पांच दीर्घावधि छात्रवृत्तियां दी जाती हैं तथा घाना के छात्रों द्वारा इसका उपयोग भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। भारत तथा घाना का दौरा करने वाले उच्च-स्तरीय सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के शिष्टमंडलों की संख्या में 2004-05 में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इनमें मंत्री, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, संसद सदस्य आदि शामिल हैं।

भारत तथा घाना के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। यह भारत के घाना के साथ द्विपक्षीय व्यापार के कारण हुआ है जिससे व्यापार में काफी वृद्धि हुई है और भारत का निर्यात (2003-04 में 65 ऽ से अधिक) 2004-05 तक जारी रहने की संभावना है। कुछ हद तक ये परिणाम प्रगतिशील व्यापार संवर्द्धन एवं वाणिज्यिक प्रयास के लिए श्रेयस्कर हो सकते हैं, ऐसे प्रयास जिन्हें मिशन स्तर पर शुरू किया गया था। भारतीय कम्पनियों ने विश्व बैंक आदि द्वारा वित्तपोषित बड़ी अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं पर बोली को भी बढ़ाया है तथा इस संबंध में मिशन सहायता कर रहा है।

भारत के लिए सामरिक महत्व की कुछ पहलें की जो रही हैं। पेट्रोलियम क्षेत्र में, पेट्रोलियम का पता लगाने, विकास तथा उत्पादन में सहयोग करने के लिए ओ.एन.जी.सी.(विदेश) तथा घाना राष्ट्रीय पेट्रोलियम कम्पनी के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है। अनुप्रवाह पेट्रोलियम क्रिया-कलापों में भारतीय तेल कम्पनी और घाना तेल कम्पनी के बीच सहयोग के लिए वार्ता हो रही है। भारत में इस्पात उद्योग के लिए घाना से मैगनीज की आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। घाना में हीरे की खुदाई में भारत के रत्न एवं जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा भावी निवेश का मामला विचाराधीन है। भारतीय स्टेट बैंक ऐकरा में एक शाखा खोलने का प्रक्रम कर रहा है।

गिनी-बिसाऊ

गिनी-बिसाऊ के साथ संबंध विशेषकर उस समय पनपे जब वे नई पहल टीम-9 का भाग बने। बिसाऊ गिनी विदेश मंत्री महामहिम श्री जॉस जोआओं सिल्वा मांटेरो ने टीम-9 की बैठक के उद्घाटन के अवसर में भाग लेने के लिए 1 मार्च, 2004 को भारत का दौरा किया। आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई और विभिन्न भारतीय कम्पनियों ने व्यापार अवसरों को तलाशने के लिए गिनी-बिसाऊ का दौरा किया। कुछेक परियोजनाओं पर करार किया गया। गिनी-बिसाऊ ने एफ एस आई द्वारा कराए गए 36 वें पी सी एफ डी में भाग लेने के लिए एक आई. टी. ई.सी. स्लॉट का लाभ उठाया।

गिनी

गिनी के साथ संबंध अभी भी मैत्रीपूर्ण हैं। गिनी ने भारत में अपना नया अवैतनिक वाणिज्य दूत (कान्सुल) नियुक्त किया है। भारत ने गिनी को 2000 टन चावल तथा 1000 टन चीनी दान में दिया। इसके अतिरिक्त, 100,000 अमरीकी डालर मूल्य की एंटी रिट्रोवाइरल औषधि भी दान में दी थी।

मॉरीटानिया

राजदूत के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय पेट्रोलियम इण्डिया इंटरनेशल(पी.आई.आई.) शिष्टमंडल ने नोयूधीबो में सोमिर रिफाइनरी के पुनर्वास तथा संचालन पर वार्ता करने, नेशनल आयरन और माइनिंग कम्पनी (सनिम) के लिए विस्फोटों की आपूर्ति तथा मॉरीटानिया में तेल अन्वेषण की सम्भावना का पता लगाने के लए मॉरीटानिया का दौरा किया। शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति माओया सिद्धि उल्द अहमद तया से भेंट की तथा जल एवं ऊर्जा मंत्री, श्री साद बुच कामरा तथा खनन एवं उद्योग मंत्री, श्री जेदानी ओल्द हमीदा से भी भेंट की। मॉरीटानिया सरकार ने भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र में अपने पेशवरों के लिए प्रशिक्षण में भी रूचि दिखाई। मॉरीटानिया ने आई टी प्रशिक्षण के लिए दो आई.टी.ई.सी. स्लॉटों का लाभ उठाया। मॉरीटानिया जल बोर्ड के महानिदेशक को भारत के अध्ययन दौरे पर आंमत्रित किया गया।

नाइजीरिया

भारत वर्ष 2004-05 में नाइजीरिया के साथ अपने बेहतर द्विपक्षी संबंधों को बढ़ा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबेसाँजो, जो अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष और सी एच ओ जी एम के भी अध्यक्ष हैं, के 2-3 नवम्बर, 2004 को नई दिल्ली के दौरे ने भारत-नाइजीरिया संबंधों को और अधिक प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति ओबेसाँजो ने माननीय प्रधान मंत्री के साथ द्विपक्षी संबंधों ,अफ्रीका में शांति और सुरक्षा तथा संयुक्त राष्ट्रों के सुधारों पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि भारत यू.एन. सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए वास्तविक उम्मीदवार है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने भारत सरकार द्वारा नाइजीरिया मशीन टूल्स को दी गई सहायता की सराहना की। उन्होंने अफ्रीकन विकास की नई भागीदारी के तहत भारत की पहल की भी सराहना की, जिसके अंतर्गत भारत अफ्रीकी देशों को 200 मिलियन अमरीकी डालर देगा। राष्ट्रपति ओबेसाँजो ने आश्वासन दिया कि नाइजीरिया भारत को सीधे और अधिक कच्चा

तेल देगा। उन्होंने भारतीय कंपनियों को तेल अन्वेषण तथा उत्पादन की बोलियों में भाग लेने और विद्युत सृजन तथा एल पी जी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। श्रीमती सोनिया गांधी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा भी राष्ट्रपति ओबेसाँजो से मिली।

इसी समय, भारत सरकार के 5 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान के तहत नाइजीरिया मशीन टूल्स के पुनरूद्धार के लिए 2001 में करार हुआ था तथा इसी वर्ष एच एम टी (I) द्वारा भेजी गई सभी मशीने नाइजीरिया मशीन टूल्स को प्राप्त हुई। संयुक्त सचिव (एम इ आर), विदेश मंत्रालय ने प्रगति की समीक्षा करने के लिए अप्रैल, 2004 में नाइजीरिया का दौरा किया। अपनी तरफ से नाइजीरिया ने प्रतिपक्ष वित्तपोषण का एक हिस्सा रिलीज किया तथा आगे प्रगति हो रही है। श्री एम.एस. श्रीनिवासन, अपर सचिव, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल, जिसमें भारतीय तेल निगम के वरिष्ठ कार्यकारी भी शामिल थे, ने 11-13 अगस्त, 2004 को नाइजीरिया का दौरा किया तथ कच्चे तेल की 40,000 बी पी डी आपूर्ति के लिए करारनामे की शर्त के नवीकरण के संबंध में चर्चा की।

10 सितम्बर, 2004 को भारतीय तेल निगम ने तेल रिफाइनरि लगाने के लिए नाइजीरिया में इडो स्टेट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस रिफाइनरि की क्षमता प्रति वर्ष लगभग 9 मिलियन टन होने की संभावना है तथा अंतिम निवेश 1.5 बिलेलियन अमरीकी डालर का आर्डर होने की संभावना है। इडो स्टेट प्रतिनिधियों तथा आई.ओ.सी. के बीच आगे की बातचीत 29-30 नवम्बर, 2004 को नई दिल्ली में हुई थी। रक्षा मामले में, इंडियाज नेशनल डिफेंस कालेज का एक दल, जिसमें 14 अधिकारी शामिल थे, 17 से 20 मई 2004 तक नाइजीरिया के अध्ययन दौरे पर गया जबकि 15 नाइजीरिया आर्म्ड फोर्स आफिसरों ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

सेनेगल

विदेश मंत्री महामहिम श्री शेख तिदियाने गाडिओ 8-11 सितम्बर, 2004 को भारत के दौरे पर आए थे। मंत्री गाडियों माननीय विदेश मंत्री, श्री नटवर सिंह के साथ-साथ माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम, माननीय संचार तथा आई.टी. मंत्री, श्री दयानिधि मारन और प्रधानमंत्री के माननीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री जे.एन. दीक्षित से मिले। भारतीय उद्योग परिसंघ ने मंत्री गाडिओ के लिए व्यापार बैठक आयोजित की। उन्होंने भारतीय विश्व मामला परिषद् में नेपड, टीम-9 तथा भारत और अफ्रीका के सहयोग संबंधी एक सम्मेलन को भी संबोधित किया। संयुक्त वक्तव्य जिसे, दौरे के अंत में जारी किया था, में यह सहमति हुई कि सेनेगल में जनवरी, 2005 में द्विपक्षी संयुक्त समिति बैठक के दूसरे सत्र का आतिथेय होगा। आर्थिक सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष द्विपक्षी निवेश संवर्धन एवं सुरक्षा करार तथा दोहरे करारोपण से बचने के करार पर हस्ताक्षर करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने पर सहमत हुए। भारत सेनेगल को भारत से 350 बसें लेने के लिए ऋण देने पर भी सहमत हुआ। यह भी सहमति हुई कि भारत ट्रैक्टर बनाने के संयंत्र की स्थापना में मदद करेगा, इसके लिए सेनेगल को भारत से ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपस्करों को प्राप्त करने के लिए पहले ही 15 मिलियन अमरीकी डालर देने की पेशकश की गई है। सेनेगल सरकार के आग्रह पर यह सहमति हुई कि माननीय विदेश मामले मंत्री 2005 में सेनेगल का दौरा करेंगे।

सेनेगल के पर्यटन मंत्री श्री उस्मान मासेक नदाए ने हैदराबाद के पर्यटन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। वह भारत-सेनेगल के संयुक्त उद्यम उद्योग चिमिक्ते डू सेनेगल के संबंध में माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से भी मिले। डी टी ए ए बातचीत का पहला दौर 30 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2004 तक नई दिल्ली में चला। भारत के एजिम बैंक तथा सेनेगल के वित्त मंत्री के बीच 15 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण करार पर 10 दिसम्बर, 2004 को मुम्बई में हस्ताक्षर हुए थे। सेनेगल आई टी ई सी कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहा है। अप्रैल-नवम्बर, 2004 के दौरान सेनेगल द्वारा नौ आई टी ई ए छात्रवृत्तियां प्राप्त की गई थीं।

सेनेगल सरकार के आग्रह पर मैसर्ज एच एम टी (1) ने अतिरिक्त उपस्कर और अभियंता भेजे ताकि दाकर में भारत द्वारा स्थापित 4.5 मिलियन अमरीकी डालर के उद्यमिता एवं तकनीकी विकास केन्द्र को अद्यतन बनाया जा सके। सेनेगल सरकार के आग्रह पर सेनेगल के मक्का उद्योग को अद्यतन बनाने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकियों संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आई टी ई सी के अंतर्गत भारतीय मक्का विशेषज्ञ भेजा गया था। 20 मार्च से 5 अप्रैल, 2004 तक सृष्टि स्कूल आफ आर्ट एण्ड डिजाइन, बंगलौर तथा फ्यूचर अकादमी, लंदन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'समकालीकरण' कार्यक्रम के तहत फरूत मीडिया सेंटर से पांच-सदस्यीय सेनेगल शिष्टमंडल ने बंगलौर का दौरा किया।

2004-06 अवधि के लिए तीन वर्षीय भारत-सेनेगल सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर सेनेगल की संस्कृति मंत्री, श्रीमती सेफितो नदाए पिओप तथा राजदूत ने 30

सितम्बर, 2004 को दाकर में हस्ताक्षर किए। महात्मा गांधी के 135 वें जन्मदिवस के अवसर पर मंत्री दिओप ने चांसरी परिसर में महात्मा गांधी की आवक्षमूर्ति का उद्घाटन किया। उन्होंने शेख अंता दिओप यूनिवर्सिटी, दाकर में महात्मा की फोटो की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी जनता के लिए 27 अक्टूबर से 12 नवम्बर, 2004 तक खुली रही थी। दाकर विश्वविद्यालय में '' 21वीं सदी में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता' पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था। 31 अक्तूबर को दाकर विश्वविद्यालय के सभा भवन में ' मेकिंग आफ द महात्मा' फिल्म भी दिखाई गई थी।

बुर्किना फासो

बुर्किना फासो भारत को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, आधारभूत सुविधाओं का विकास, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास, खनन, औषधीय, कृषि के क्षेत्रों तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में अपने विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। कुछ प्रमुख विकास कार्यों तथा करारनामों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें शामिल हैं-

बुर्किना फासो के विदेश मामले एवं क्षेत्रीय सहयोग मंत्रालय के क्षेत्रीय सहयोग मंत्री श्री टी.जीन.डी. डीयू सोमदा टीम-9 संबंधी बैठक में भाग लेने के लिए 29 फरवरी से 2 मार्च, 2004 तक भारत के दौरे पर आए। टीम-9 पहल के अंतर्गत वित्तपोषण करने वाली परियोजनाओं की सूची अनुमोदन के लिए मंत्रालय भी भेजी गई है। बुर्किना फासो के विदेश मामले एवं क्षेत्रीय सहयोग मंत्री श्री युसूफ ओड्रागो द्विपक्षी और आपसी हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जुलाई, 2004 में भारत आए। बुर्किना फासो ने उप-सहारा अफ्रीकी देशों के लिए एच आई वी एड्स हेतु ए आर वी (एंटी-रिट्रोवायरल) औषधियों, सामान्य औषिधियों, चिकित्सा उपस्करों के आयात करने तथा भारत से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अलग से ऋण (1.5 मिलियन अमरीकी डॉलर) मुहैया कराने की भारत सरकार की प्रस्तावित पहल का लाभ उठाने की भी इच्छा जाहिर की।

सितम्बर,2004 में इस मिशन ने अफ्रीकन यूनियन के एकस्ट्रा-ओर्डेनरी शिखर सम्मेलन, जो ओगादोगू में आयोजित किया जा रहा था, में भाग लेने के लिए भारत के विशेष दूत श्री सलमान खुर्शीद के बुर्किना फासो के दौरे की व्यवस्था की। विदेश मामले एवं क्षेत्रीय सहयोग मंत्री, श्री युसूफ ओड्रागो आपसी हितों के द्विपक्षी मुद्दों पर चर्चा करने के लि श्री सलमान खुर्शीद से मिले। श्री खुर्शीद ने नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष (तथा पूर्व प्रधानमंत्री) श्री रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरी से भेंट की। मिशन ने यू एन ईकोसोक के लिए भारत की उम्मीदवारी हेतु समर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ 25 अफ्रीकी देशों के शिष्टमंडलों के नेताओं के साथ बैठकें भी करवाई थी, जिससे अफ्रीकी देशों से पुरजोर समर्थन प्राप्त हुआ और इससे ईकोसोक चुनावों में भारत को सफलता प्राप्त करने में मदद मिली। निदेशक (एशिया प्रशांत महासागर तथा कैरेबियन), श्री पायबी फर्मिन ग्रेगोरे के नेतृत्व में बुर्किना फासो के विदेश मामले एवं क्षेत्रीय सहयोग मंत्रालय से एक शिष्टमंडल ने 22 मार्च,2004 को भारतीय उच्चायुक्त, अकरा का दौरा किया ताकि द्विपक्षी मुद्दों पर चर्चा की जा सके। इसमें बुर्किना फासो विदेश मामले मंत्री के भारत दौरे का आग्रह, टीम-9 सहयोग, कूटनीति, आई टी, रक्षा, पत्रकारिता आदि के क्षेत्रों में बुर्किना फासो के कार्मिकों के प्रशिक्षण की सम्भाव्यता तथा ओगादोगू में संयुक्त आयोग के तीसरे सत्र को कराना भी शामिल था।

2003-04 में व्यापार तथा भारत से बुर्किना फासो तक के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है तथा 2004-05 के आकलनों से पता चलता है कि 2004-05 में भी इस क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। 2004-05 में द्विपक्षी व्यापार तथा बुर्किना फासो के लिए भारतीय निर्यात में सकारात्मक रवैये से व्यापार के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

टोगो

भारत तथा टोगो के बीच द्विपक्षी संबंध बाधारहित तथा मैत्रीपूर्ण बने हुए हैं। भारत के विशेष दूत, श्री सलमान खुर्शीद सितम्बर, 2004 में ओगादोगू में ए यू के एकस्ट्रा-ओर्डेनरी शिखर सम्मेलन के टोगो शिष्टमंडल से मिले। आमतौर पर टोगो यू एन तथा ईकोसोक की उम्मीदवारी के समर्थन के लिए हमारे आग्रह का पक्षधर रहा है। तथापि, कोई प्रमुख क्रिया-कलाप नहीं हुआ है। 2003-04 में वाणिज्यिक क्रियाकलाप में थोड़ी बहुत तेजी आई थी किन्तु व्यापार का स्तर विगत वर्ष जैसा ही रहा तथा टोगो के लिए भारत के निर्यात में विगत वर्ष की अपेक्षा गिरावट आई है। टोगो स्वास्थ्य, कृषि तथा शिक्षा और मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण में भारत की सहायता चाहता है।

नाइजर

भारत तथा नाइजर के बीच के राजनैतिक संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। 2003-04 में दोनों देशों के बीच कोई महत्वपूर्ण दौरा नहीं हुआ है। 26 नवम्बर,2004 को नाइजर के राष्ट्रपति ने अपनी कुछ विकासात्मक परियोजनाओं के लिए निपैड (एन ई पी ए डी) वित्तपोषण प्राप्त करने में नाइजर की रूचि के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री को संदेश भेजा था। नाइजर ने टीम-9 पहल का हिस्सा बनने के प्रति भी अपनी ईच्छा जाहिर

की। व्यापार संबंध बढ़ रहे हैं। निमेय में इंटरनेशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फार द सेमी-ऐरिड ट्राफिक्स कार्यालय ने कुछ टाटा बसें तथा छोटी बसें खरीदी हैं।

नाइजर सरकार को धान के नमूने दिए गए। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के आई सी ए आर तथा नेशनल एग्रोनोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ नाइजर के बीच करार हो गया है किंतु हमारे द्वारा दिए गए विषय के संबंध में नाइजर की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य (कार)

भारत तथा मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बीच के द्विपक्षी संबंध 1998 से ही स्थिर बने हुए हैं। कार का पूर्ववर्ती (मनोनीत) राजदूत अपना प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया था। साथ ही, लगभग तीन वर्ष बीत चुके हैं और वर्तमान राजदूत (मनोनीत) के संबंध में करारनामा कार प्राधिकारियों द्वारा सूचित नहीं किया गया है। इस प्रकार, द्विपक्षी संबंधों में कोई नई प्रगति नहीं हुई है तथा रिपोर्ट में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। कार की प्रतिक्रिया के उल्लिखित कारणों में से एक कारण मार्च,2003 में तख्ता पलटना है जिसमें कार के पूर्व सेनाध्यक्ष, जनरल फ्रैंनकोसी बोजिजी द्वारा राष्ट्रपति फीलिक्स को हटाया गया था। इन कारणों की वजह से मिशन के सम्प्रेषण तथा प्रत्यय-पत्र को प्रस्तुत करने आदि जैसे मुद्दों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने में बंगुई में प्राधिकारियों को कुछ समय लगा।

केप वेर्दे

भारतीय नौसैनिक बेड़ा आई एन एस-ताबर अपनी पहली समुद्री यात्रा करते हुए 26-29 मई,2004 को मिनदेलो, केप वेर्दे पहुंचा। किसी भी भारतीय नौसैनिक बेड़े की केप वेर्दे की यह पहली यात्रा थी। केप वेर्दे के प्राधिकारियों ने आवश्यक सैन्यतंत्र सहायता देने तथा आवश्यक बैठकें आयोजित करने में सहायता की।

माले

माले के साथ संबंध विशेषकर उस समय पनपे जब नई पहल टीम-9 का भाग बने। माले के विदेश मंत्री ने टीम-9 की उद्घाटन बैठक में भाग लेने के लिए 1-2 मार्च,2004 को भारत का दौरा किया। माले ने कपास उत्पादन और प्रसंस्करण तथा लघु सीमेंट संयंत्रों को लगाने में भारतीय निवेशों को आमंत्रित करने की ईच्छा जाहिर की। माले ने टीम-9 के संयंत्र के तहत ट्रैक्टर असेम्बली यूनिट लगाने की भी ईच्छा जाहिर की। इस संबंध में उन्होंने भारतीय निर्यातकों से आग्रह किया कि वे माले में ट्रैक्टर असेम्बली प्लांट के लिए व्यवहार्य अध्ययन कराएं। एच एम टी (1) यह अध्ययन कराने के लिए सहमत हो गया है।

गाम्बिया

भारत ने राज्य (मंत्री) विदेश मामले के गाम्बियान सचिव को जनवरी,2005 में भारत आने का नियंत्रण दिया। इस दौरे का उद्देश्य राष्ट्रपति अलहाजी याहया अज जामेह के भारत के सरकारी दौरे की तैयारी के बारे में चर्चा करना है। गाम्बिया ने एस एम ई, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण और आई टी क्षेत्रों में भारतीय सहयोग का आग्रह किया। गाम्बिया को एफ एस आई के पी सी एफ डी कोर्स के लिए एक सहित तीन आई टी ई सी स्लॉटों का लाभ मिला। गाम्बिया में भारतीय समुदाय बढ़ रहा है और अब इसकी संख्या 250 हो गई है। मुख्य रूप से वे खुदरा व्यापार तथा रेस्तरां कारोबार करते हैं, हालांकि उन्होंने कृषि और मूंगफली तेल रिफाइनरी में काफी निवेश किया है।

चाड

नई दिल्ली में मार्च,2004 में शुरू की गई टीम-9 की पहल का चाड में काफी जोर-शोर से स्वागत किया गया। संयुक्त सचिव (पश्चिम अफ्रीका), श्री ई बरवा ने पहल पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए अप्रैल, 2004 में एन जमेना का दौरा किया तथा चाड के उप प्रधानमंत्री के साथ-साथ चाड के सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की। वर्ष के दौरान नोडल मंत्रालयों में विभिन्न कर्मचारियों को चुना गया था और वे पहल के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाओं की देखरेख कर रहे हैं। भारत ने पहले चाड को उपहार स्वरूप 5000 टन चावल दिए जो इस वर्ष वहां पहूंचे। प्राधिकारियों, विशेषकर सूडान के दारफर क्षेत्र से आए शरणार्थियों ने इसको सराहा।

सियरा लिओन

सियरा लिओन के साथ मधुर संबंध हैं। सियरा लिओन ने आग्रह किया कि भारत उनकी अर्थव्यवस्था को फिर से सबल बनाने में सहायता करे। वहां कठिन परिस्थितियों के बावजूद सियरा लिओन ने आई टी ई सी छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया। वर्ष के दौरान उन्होंने 8 स्लॉट प्राप्त किए।

साओ टोम एण्ड प्रिंसिप (एस टी पी)

एस टी पी के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण बने हुए हैं। जून,2004 में एस टी पी के सरकारी दौरे के दौरान भारत का राजदूत मानव संसाधन तथा पर्यावरण ; स्वास्थ्य ; कृषि ; ग्रामीण विकास तथा मत्स्य-पालन मंत्रियों से मिला और द्विपक्षी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। एस टी पी के सम्मानित सदस्यों ने भारत के साथ राजनैतिक,आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों

को मजबूत करने की ईच्छा जताई। एस टी पी निरन्तर आई टी ई सी स्लॉटों का उपयोग कर रहा है।

इक्वेटोरियल गिनी

इक्वेटोरियल गिनी के साथ संबंध निरन्तर बढ़े हैं। आर्थिक सहयोग, जो इससे पहले नगण्य था, में वृद्धि हुई है। इक्वेटोरियल गिनी में तेल क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में अनेक भारतीय काम कर रहे हैं। टीम-9 पहल को इक्वेटोरियल गिनी में सराहा गया था। अप्रैल,2004 में संयुक्त सचिव (पश्चिम अफ्रीका) श्री ई.बरवा ने पहल पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एन' जमेना का दौरा किया तथा विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ वार्ता की। राष्ट्रपति कर्नल टेडोरो ओबियांग ग्वेमा बसागो, जिन्होंने पहल का स्वागत किया, ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने हाइड्रोइलैक्टिक पावर स्टेशनों को लगाने, जल प्रबंधन और उपचारी संयंत्रों, लघु उद्योगों के विकास आदि में भारत की सहायता मांगी। भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों ने परियोजनाओं का पता लगाने और व्यापारिक संबंध बनाने के लिए इक्वेटोरियल गिनी जाना शुरू कर दिया है।

कांगो गणराज्य

नजदीकी संबंध बनाने के लिए भारत ने कांगो गणराज्य में अपना पहला अवैतनिक कान्सुल जनरल नियुक्त किया है। कांगो सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र, पर्यावरण और वन क्षेत्रों में भारत की सहायता मांगी। भारत ने अपनी मानवता सहायता योजना के भाग के रूप में 200,000 मच्छरदानियां भी दान में दी। कांगो गणराज्य ने सक्रियता से भारतीय आई टी ई सी स्लॉटों का उपयोग किया। आर ओ सी रक्षा शिष्टमंडल ने 29 जुलाई से 4 अगस्त,2004 तक भारत का दौरा किया तथा हमारे रक्षा मंत्रालय के साथ वार्ता के दौरान आर ओ सी की रक्षा जरूरतों की सूची सौंपी।

गैबोन गणराज्य

भारत तथा गैबोन के बीच द्विपक्षी संबंधों में तेजी आ रही है। वर्ष 2003 में गैबोन में भारत के अवैतनिक कान्सुल जनरल की नियुक्ति तथा बाद में भारत में गैबोन के अवैतनिक कान्सुल की नियुक्ति से आपसी बातचीत में सहायता मिली। गैबोन सरकार ने अपने स्वास्थ्य तथा छोटे/मध्यम औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और गैबोन में भारतीय व्यावसायियों की नियुक्ति के लिए भारत की सहायता मांगी। गैबोन आई टी इ सी स्लॉटों का भरपूर उपयोग कर रहा है।

इकोवास

पश्चिम अफ्रीकी देशों के साथ नजदीकी संबंध बनाने के अपने प्रयासों की दिशा में भारत ने परामर्श और बातचीत तंत्र बनाने के लिए पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय (इकोवास) के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। 13 अक्तूबर,2004 को नाइजीरिया के उच्चायुक्त, श्री आतिश सिन्हा प्रेक्षक हैसियत के साथ (इकोवास) को प्रत्यायित किए जाने के लिए भारत के पहले स्थायी प्रतिनिधि बने। इकोवास कार्यपालक सचिव, डॉ0 मोहम्मद अबस चम्बस ने उच्चायुक्त सिन्हा का प्रत्यय-पत्र प्राप्त किया और इसके बदले एक पत्र सौंपा जिसमें लिखा था कि नियुक्ति विकास पहल को प्रोत्साहित करेगी और परियोजनाओं का मूल उद्देश्य पश्चिम अफ्रीकी लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उप क्षेत्र में समेकन की प्रगति में तेजी लाएगी।ꣳ उन्होंने आशा जताई कि इससे भारत- इकोवास संबंध और गहरे होंगे तथा इससे संबंधों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

■■

यूरोप

7

यूरोप ।

यूरोप तथा यूरोपीय संघ के एक-एक देश के साथ भारत के संबंध वर्ष के दौरान लगातार मजबूत होते रहे। उच्चतम स्तर समेत यात्राओं के नियमित आदान-प्रदान से अन्योन्यक्रियाएं हूई जिससे द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने तथा उनमें विविधता लाने की परस्पर इच्छा प्रदर्शित हुई। भारत ने इंग्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनी के साथ नीतिगत संबंध बनाए और यूरोप के अन्य अनेक देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए जिसका लक्ष्य विस्तृत क्षेत्र में और अधिक सशक्त द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। नवम्बर 2004 में हेग में आयोजित भारत-यरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों में एक मील का पत्थर था क्योंकि इसने एक बड़े क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिक प्रतियोगी के रूप में भारत के बढ़ते कद को मान्यता देते हुए भारत-यरोपीय संघ नीतिगत भागीदारी का शुभारम्भ किया। यूरोप के एक-एक सदस्य देश के साथ विचारों के आदान प्रदान से सार्वभौमिक प्रभाव के विभिन्न मुद्दों के संबंध में समान समझ परिलक्षित हुई। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बहस के संबंध में भारत यूरोपीय संघ के अनेक सदस्य देशों से सार्थक समर्थन जुटाने में कामयाब रहा। भारत और जर्मनी, एक नीतिगत प्रयास में, विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए सहमत हो गए ।

आर्थिक महत्व, यूरोप के देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों का आधार बना हुआ है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की सम्भाव्यता की बढ़ती मान्यता के चलते प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के खास क्षेत्रों में वृहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन सम्पन्न करना चाहते हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूहों के प्रतिनिधित्व में बड़े यूरोपीयन देशों के साथ नागरिक संस्थाओं के साथ संवाद ने बहु-आयामी संबंधों को मजबूत करने में योगदान दिया ।

यूरोपीय संघ

वर्ष 2004 भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए एक लाभकारी वर्ष रहा है (यूरोपीय संघ की सदस्यता 15 से 25 सदस्य देशों तक बढ़ गई है)। यूरोपीय संघ ने अनुकूल भागीदारी के लिए भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों का दर्जा बढ़ाया। भारत उन पांच अन्य देशों में शामिल हो गया जिनके साथ यूरोपीय संघ के इस प्रकार के विशेष संबंध हैं। 5वां भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच उच्चतम स्तर पर वार्षिक संस्थागत राजनैतिक संवाद श्रृंखला में अद्यतन है - यूरोपीय संघ की डच प्रेसीडेंसी के अधीन 8 नवम्बर 2004 को हेग में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया और विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री जे.एन. दीक्षित ने उनकी सहायता की। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व डच प्रधान मंत्री तथा मौजूदा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डा. जन पीटर बाल्केन्डे द्वारा किया गया और इसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष डा. रोमानो प्रोडी, सामान्य विदेश एवं सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि श्री जेवीयर सोलना, यूरोपीयन आयोग के व्यापार आयुक्त श्री पास्कल लेमी और डच विदेश मंत्री डा. बर्नार्ड बोट शामिल थे। शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक अनुकूल साझीदारी की शुरूआत की गई। इसमें ऐसा कार्यक्रम बनाया गया जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई, बहुपक्षता की भूमिका, पारस्परिक हित की क्षेत्रीय घटनाओं और आर्थिक एवं व्यापारिक मामलों के संबंध में दोनों पक्षों के बीच सहयोग की समीक्षा जैसे सार्वभौमिक मुद्दों सहित भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों का सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब सम्मिलित

हो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मोर्चे पर संबंधों को बढ़ाने की सम्भावना, विशेषकर गेलिलियो परियोजना में भारत की भागीदारी और आईटीईआर परियोजना में भारत की अभिरूचि के बारे में दोनों पक्षों के बीच संरचना करार पर प्रस्तावित हस्ताक्षर किए जाने के परिप्रेक्ष्य में बल दिया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने एक एनर्जी पैनल तथा एक पर्यावरण मंच स्थापित करने का भी निर्णय लिया और भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के सम्पूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संयुक्त कार्रवाई योजना बनाने के लिए सहमत हुए। दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक संबंधों पर एक संयुक्त घोषणा और एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य भी जारी किया ।

राजनैतिक शिखर सम्मेलन के बाद दोनों पक्षों की ओर से मुख्यकारी अधिकारियों की गोलमेज बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने गोलमेज बैठक को संबोधित किया और आर्थिक सुधारों के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने, निवेश के लिए भारत में उभरते नए अवसरों पर नजर डालने के लिए यूरोपीय कंपनियों को आमंत्रित किया।

वर्ष के दौरान यूरोपीय संसद के साथ अन्योन्यक्रिया जारी रही। एमईपी श्री जॉन कुशनाहन के नेतृत्व में यूरोपीय संसद का एक तदर्थ प्रतिनिधिमण्डल 20-24 जून 2004 तक नई दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर की यात्रा पर आया। दक्षिण एशिया का एक प्रतिनिधिमण्डल और अध्यक्ष नीना गिल के नेतृत्व में ईपी का एक सार्क प्रतिनिधिमण्डल 1-6 नवम्बर को भारत की यात्रा पर आया। इस प्रतिनिधिमण्डल ने, विदेशी मामलों संबंधी लोक सभा स्थायी समिति, राज्य सभा सदस्यों, पूर्व गृह मंत्री श्री एल.के. आडवाणी, श्री एन.एन. वोरा, भारत-यूरोपीय संघ गोलमेज के सह-अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों, एफआईसीसीआई और सीआईआई के साथ बैठकों में भाग लेने के अलावा विदेश मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा पर्यावरण मंत्री से भी मुलाकात की। चार भारतीय सांसदों का एक दल, विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों संबंधी आईपीयू सम्मेलन में भाग लेने के लिए नवम्बर के अन्त में ब्रुसेल्स की यात्रा पर गया ।

विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह 13-15 सितम्बर 2004 तक ब्रुसेल्स की यात्रा पर गए और सीएसएफपी के उच्च प्रतिनिधि जेवियर सोलना, पूर्व विदेश संबंध आयुक्त क्रीस पैटन और उसके उत्तरवर्ती अधिकारी सुश्री बेनिटा फ्रेरो बाल्डनर, डच वित्त मंत्री बर्नार्ड बोट (उनकी यूरोपीय विदेशी मामलों संबंधी परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से) तथा बेल्जियम के विदेश मंत्री श्री कारेल डे गूच से मिले। विदेश मंत्री ने उनके साथ हित-चिन्ता के अनेक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की ।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक अभिरुचि के पर्याप्त मामले हैं। यूरोपीय संघ (25 राष्ट्रों के एक समूह के रूप में) भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और भारत के कुल निर्यात में उसका हिस्सा 24 प्रतिशत से भी अधिक है। वर्ष 2003 में भारत का यूरोपीय संघ को निर्यात 13.30 बिलियन यूरो और आयात 14.20 बिलियन यूरो रहा जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2003 में भारत, यूरोपीय संघ को निर्यात करने वाले 19 सबसे बड़े देशों में से था और उसने यूरोपीय संघ द्वारा किए गए कुल आयात में 1.35 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा किया। दूसरी ओर भारत यूरोपीय संघ के उत्पादों का 16वां सबसे बड़ा आयातक देश था यूरोपीय संघ के सार्वभौमिक निर्यात में 1.46 प्रतिशत हिस्सा भारत का था। भारत-यूरोपीय संघ भारत के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का एक सबसे बड़ा स्रोत है। वर्ष 1991 से 2003 के बीच, संचित वास्तविक आवक यूरोस्टेट डाटा के अनुसार लगभग 6.2 बिलियन यूरो (5.6 बिलियन अमरीकी डॉलर) रही। यूरोपीय संघ से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अति महत्वपूर्ण स्रोत इंग्लैण्ड, जर्मनी तथा नीदरलैण्ड हैं और उनके बाद फ्रांस, इटली और बेल्जियम आते हैं ।

भारत-यूरोपीय संघ के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी संरचना करार ने दोनों पक्षों के आर्थिक प्रतियोगियों एवं अन्वेषकों का ध्यान आकर्षित करने में वृद्धि की है। मार्च 2004 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री वी.एस. राममूर्ति ने इण्डिया-ईसी स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक में भाग लेने के लिए ब्रुसेल्स की यात्रा पर गए एक प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया जिसके दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत-ईसी सहयोग कार्यक्रम 2004-2006 तथा एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्ष,

नेनो-प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य तथा खाद्य के गुणसूत्र, भू-तल परिवहन (वाहन क्षेत्र) तथा स्थायी विकास (प्राकृतिक आपदा शमन) के क्षेत्रों में वर्ष 2004-05 के दौरान 4 कार्याशालएं संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए सहमत हुए। संयुक्त गतिविधियों तथा परियोजनाओं को, यूरोपीय संघ के वर्ष 2002-2006 के लिए अन्वेषण तथा प्रौद्योगिकी विकास (आरटीडी) की छठी संरचना में सहायता दी जाएगी। भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक 10 सितम्बर 2004 को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। सूचना समिति संबंधी यूरोप-भारत सहयोग मंच 2004 का आयोजन 24-26 मार्च 2004 को नई दिल्ली में किया गया ।

भारत और यूरोप के बीच सिविल सोसाइटी वार्ता वर्ष के दौरान जारी रही। भारत-यूरोपीय संघ गोलमेज की सातवीं और आठवीं बैठकें क्रमशः श्रीनगर में जून 2004 में और लन्दन में दिसम्बर 2004 में आयोजित की गई। 'पर्यटन को बढ़ावा देने' 'व्यापार तथा स्थायी विकास को प्रोत्साहित करने' के लिए द्विपक्षीय सहयोग तथा सिविल सोसाइटी इन्टरनेशनल फोरम पर सातवें दौर में चर्चा की गई। गोलमेज की आठवीं बैठक की सह-अध्यक्षता यूरोपीय संघ की ओर से यूरोपीय आर्थिक तथा सामाजिक समिति (ईईएससी) की अध्यक्षा सुश्री ए.एम. सिगमुन्द द्वारा तथा भारत की ओर से श्री एन.एन. वोरा द्वारा की गई। अन्य मुद्दों के साथ-साथ इसमें यूरोपीय संघ तथा भारत में श्रम संबंधों और शिक्षा तथा प्रशिक्षण में सहयोग के बारे में चर्चा की गई ।

भारत को दी जाने वाली यूरोपीय संघ विकास सहयोग सहायता के केन्द्र बिन्दु आमतौर पर पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र रहे हैं। शिक्षा संबंधी इसके कार्यक्रम के दूसरे चरण में यूरोपीय आयोग ने, 42 जिलों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए परिकलित सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए 200 मिलियन यूरो की वचनबद्धता की है। यूरोपीय आयोग ने, कन्टरी सट्रेटजी पेपर फॉर इण्डिया 2002-2006, जिसके अधीन उसने इस अवधि के लिए 225 मिलियन यूरो की वचनबद्धता की है, में स्पष्ट रूप से भारत के साथ अपने संबंधों के लिए एक नई विकास सहयोग नीति का मसौदा तैयार किया है। क्षेत्रीय संकल्पना के स्थान पर अब एक 'राष्ट्र-भागीदारी' संकल्पना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत यूरोपीय आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चयन किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों पक्षों ने वर्ष के दौरान राज्य भागीदारी कार्यक्रम संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय आयोग ने दो नए कार्यक्रम आरम्भ किए हैं :- 14 मिलियन यूरो की लागत के साथ व्यापार एवं निवेश विकास कार्यक्रम तथा 33 मिलियन यूरो की लागत के साथ छात्रवृत्ति कार्यक्रम। भारत-यूरोपीय आयोग छात्रवृत्ति कार्यक्रम के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर 7 जनवरी 2005 को ब्रुसेल्स में हस्ताक्षर किए गए ।

सीमा शुल्क संबंधी सहयोग करार, जिस पर अक्तूबर 2003 में नई दिल्ली में पिछले शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे, अनुसमर्थित किया गया और यह 1 नवम्बर 2004 से लागू हो गया। दोनों पक्षों के बीच भारत-यूरोपीय संघ समुद्री करार के संबंध में वार्ता के पहले दौर का आयोजन सितम्बर में नई दिल्ली में किया गया ।

इंग्लैण्ड

भारत और इंग्लैण्ड के संबंध बहुत घनिष्ठ बने रहे। वर्ष भर लगातार उच्च स्तरीय द्विपक्षीय परामर्शों से विविध क्षेत्रों में सहयोग को समेकित करने तथा उसमें प्रगति करने में सहायता मिली है। प्रधान मंत्री की 19-20 सितम्बर को लन्दन की यात्रा के दौरान इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में कहा कि कई वर्षों के बाद आज के संबंध सम्भवतः सबसे अधिक मजबूत हैं। यह ऐसा संबंध है जो वास्तव में मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। दोनों प्रधान मंत्रियों ने संयुक्त घोषणा जारी की जिसका शीर्षक था - इण्डिया-यूकेः टूवर्डस ए न्यू एण्ड डाइनेमिक पार्टनरशीप, जिसमें व्यापक अनुकूल साझेदारी के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ तथा विस्तृत बनाने की योजनाएं निर्धारित की गई हैं। संयुक्त घोषणा ने अनुकूल आर्थिक संबंधों को मजबूत करने तथा भारत-ब्रिटिश आर्थिक तथा वित्तीय संवाद के लिए मंत्रालय के नेतृत्व में एक संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति के गठन के लिए आधार प्रदान किया। प्रधान मंत्री ने जलपान के समय आयोजित चुनिन्दा ब्रिटिश फर्मों के मुख्य कार्यकारियों की बैठक को

संबोधित किया और भारतीय मूल के श्रमिक नेताओं के साथ भी बैठक की। विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी प्रधानमंत्री के साथ गए थे ।

विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह पूर्व में जून 2004 में इंग्लैण्ड की यात्रा पर गए और वहां के विदेश मंत्री जैक स्ट्रा से मिले जिसके साथ उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया। अन्य अनेक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं सम्पन्न की गई जिनमें आर्थिक तथा वाणिज्यिक मुद्दों की संभावनाएं सुदृढ़ हुई तथा उनमें वृद्धि हुई। वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने 8-9 अक्तूबर को लन्दन में एक कार्यक्रम में भाग लिया जिसका शीर्षक था 'पैसेज टू इण्डिया' जिसमें अनेक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा सम्भावित निवेशकों ने भाग लिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ जून और अक्तूबर में अपनी लन्दन की यात्राओं के दौरान वहां की व्यापार मंत्री सुश्री पेटरिसिया हेविट से मिले तथा द्विपक्षीय हितों एवं विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अक्तूबर में एफआईसीसीआई द्वारा आयोजित सम्मेलन 'इन्वेस्ट इण्डिया' का उद्घाटन भी किया। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल सितम्बर में यात्रा पर गए और अपने समकक्षी श्री अलीस्टेयर डार्लिंग से मिले। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 अक्तूबर को लन्दन में एक 'इन्क्रेडिबल इण्डिया इवनिंग' आयोजित की गई जिसमें पर्यटन मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी ने भाग लिया। लन्दन में आयोजित विश्व पर्यटन बाजार में विभिन्न राज्यों के लगभग 18 प्रतिनिधिमण्डलों ने भाग लिया। हरियाणा तथा सिक्किम के प्रतिनिधिमण्डलों का नेतृत्व मुख्यमंत्रियों द्वारा किया गया और कुछ प्रतिनिधिमण्डलों का नेतृत्व राज्य के पर्यटन मंत्रियों द्वारा किया गया। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन ने सितम्बर में इप्सविच स्थित ब्रिटिश संचार प्रयोगशालाओं की यात्रा की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री कपिल सिब्बल लन्दन में हाऊस ऑफ कॉमन्स में एड्स से संम्बद्ध सर्वदलीय संसदीय दल को संबोधित करने के लिए अक्तूबर में लन्दन की यात्रा पर गए। स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती पानावाका लक्ष्मी नवम्बर में लन्दन में अपने समकक्षी मंत्री श्री जॉन इटन से मिली और स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की सम्भावनाओं पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने अपने संबंधित राज्यों में निवेश आकर्षित करने के लिए रोड शो आयोजित किए। भारत की ओर से हाल ही की अन्य उच्चस्तरीय यात्राओं में, लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री सुश्री कुमारी शैलजा द्वारा की गई यात्राएं शामिल थी ।

इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में वहां के उप-प्रधानमंत्री जॉन प्रैसकोट, रक्षा सचिव जियोफ्रे हून, शिक्षा एवं कौशल राज्य मंत्री श्री डेविड मिलिबैंड, केबिनेट मंत्री तथा पर्यावरण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सुश्री मारग्रेट बैकेट, स्थायी अंडर सेक्रेटरी सर माइकल जे, पीटर लुफ एमपी के नेतृत्व में सीपीएफआईएन सदस्यों, संवैधानिक कार्य विभाग के संसदीय अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेविड लम्मी, सर केविन टेबिट, केसीबी, सीएमजी, रक्षा संबंधी परमानेन्ट अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अन्तर्राष्ट्रीय विकास मंत्री श्री हिलेरी बेन, अन्तर्राष्ट्रीय विकास कनिष्ठ मंत्री श्री ग्रेथ थॉमस, तथा उत्तरी आयरलैण्ड में आर्थिक तथा शिक्षा मंत्री श्री बेरी गार्डीनर द्वारा भारत की यात्रा की गई ।

इंग्लैण्ड, अमरीका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा और यूरोप में सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत और इंग्लैण्ड के बीच वस्तुओं और सेवाओं का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2003 के दौरान 5 बिलियन पौण्ड से काफी अधिक रहा। जनवरी और सितम्बर 2004 के बीच वस्तुओं के व्यापार में भारत के पक्ष में 3.29 बिलियन पौण्ड पर होते हुए मामूली वृद्धि दर्ज की गई। इंग्लैण्ड के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजार के रूप में ऊपर उठकर 15वें स्थान पर पहुंच गया। इंग्लैण्ड, भारत में सबसे बड़ा संचित निवेशक और 1991 के बाद तीसरा सबसे बड़ा निवेशक बना हुआ है। भारत, परियोजनाओं की संख्या के संबंध में इंग्लैण्ड में आठवां सबसे बड़ा निवेशक और एशिया में जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। इंग्लैण्ड में भारतीय कंपनियों की कुल संख्या इस समय 480 है। प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर और व्यापार एवं उद्योग स्टेट सेक्रेटरी ने, इंग्लैण्ड के लिए बेहतर आर्थिक लाभों की ओर संकेत करते हुए ब्रिटिश कंपनियों द्वारा ऑफसोर-आऊटसोर्सिंग का सुस्पष्ट समर्थन किया ।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर लंदन में संयुक्त रूप से प्रैस को सम्बोधित करते हुए, 19-20 सितम्बर 2004।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, जर्मनी के चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर से मिलते हुए, नई दिल्ली, 6-7 अक्तूबर 2004।

हवाई सेवा संबंधी वार्ता, नागगरिक उड्डयन मंत्रालय और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच सितम्बर में लन्दन में आयोजित की गई और इस सहमति के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई कि दोनों पक्षों द्वारा एक वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सीधी उड़ानों की संख्या प्रति सप्ताह 19 से बढ़ाकर 40 कर दी जाएं और भारत में गन्तव्य स्थानों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए। एन्यूवल सीआईआई-सीईओ मिशन जून में लन्दन की यात्रा पर गया। आऊटसोर्सिंग पर तीसरा फाइनेंशियल टाइम्स-नास्सकॉम वार्षिक सम्मेलन नवम्बर में लन्दन में आयोजित किया गया ।

भारत के लिए विकास सहायता के इंग्लैण्ड सरकार के कार्यक्रम, विश्व भर में अधिकतम बने हुए हैं। ब्रिटिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग ने वर्ष 2004-05 के दौरान भारत में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 250 मिलियन पौण्ड वितरित करने की योजना बनाई है। इंग्लैण्ड की ओर से अनेक राष्ट्रीय गतिविधियों और चार केन्द्रीकृत राज्यों (आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल) में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए सहायता पहुंचाई जा रही है। अक्तूबर 2004 में इंग्लैण्ड ने, चार वर्ष में 190 मिलियन पौण्ड की वचनबद्धता के साथ भारत सरकार के सर्वशिक्षा अभियान का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सहायता की घोषणा की ।

फ्रांस

भारत और फ्रांस के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा स्थायी हैं। परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर नियमित और संरचित परामर्शों का दौर वर्ष 2004 में जारी रहा। प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री जे.एन. दीक्षित ने 23 अगस्त 2004 को पेरिस में आयोजित रणनीतिक संवाद के 12वें दौर में भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया। फ्रांस की ओर से, फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार गौरडॉल्ट-मोन्टेग्ने द्वारा नेतृत्व किया गया। बातचीत के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। श्री दीक्षित फ्रांस के राष्ट्रपति जैकस चिराक और फ्रांस के विदेश मंत्री माइकेल बारनीयर से भी मिले। फ्रांस के विदेश मंत्री माइकेल बारनीयर 27-28 अक्तूबर को भारत की यात्रा पर आए और प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री और विपक्ष के नेता से मिले। विदेश मंत्री ने शिष्टमण्डलीय स्तर की वार्तालाप का नेतृत्व किया जिसमें पारस्परिक हित के अनेक मुद्दे सम्मिलित थे। पर्यटन संबंधी संयुक्त कार्यदल की छठी बैठक 2 अप्रैल 2004 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, दोनों पक्षों के बीच वर्ष भर लगातार विचारों का आदान प्रदान किया जाता रहा। भारत-फ्रांस उच्चस्तरीय रक्षा समिति की बैठक का सातवां दौर रक्षा सचिव स्तर पर 17-19 नवम्बर 2004 तक पेरिस में आयोजित किया गया। इस संवाद तंत्र-प्रणाली के अधीन स्थापित तीन उप-समितियों की बैठकें भी आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त दोनों देशों की संशस्त्र सेनाओं के बीच विचार विमर्श का कार्यक्रम चलता रहा जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी स्तर पर एक दूसरे के यहां यात्राएं हुई। भारत-फ्रांस अनुसंधान मंच की तीसरी बैठक 18-21 अक्तूबर तक पेरिस में आयोजित की गई जिसका उद्देश्य रक्षा संयुक्त उद्यम के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना था ।

यह वर्ष भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में निरन्तर प्रगति का साक्षी रहा है जो वर्ष 2003-04 में कुछ-कुछ भारत के पक्ष में रहते हुए 2.5 बिलियन यूरो तक पहुंच गया। वर्ष के दौरान, ऊर्जा, सड़क, शहरी विकास और खनिज अन्वेषण एवं विकास संबंधी संयुक्त कार्यदलों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार करने के लिए बैठकें की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ, पर्यटन मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री सुबोध कान्त सहाय द्वारा की गई यात्राओं ने आर्थिक क्षेत्र में उच्चस्तरीय अन्योन्यक्रिया कायम रखने के लिए योगदान किया। भारतीय उद्योग संघ द्वारा प्रायोजित उच्चस्तरीय सीआईआई-सीईओ प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा, फोयर डे पेरिस, प्रेट-ए-पोर्टर, केन्नस वाटर सिम्पोजियम, सलोन इन्टरनेशनल डे आई एलिमेन्टेशन (एसआईएएल) तथा चमड़े और फैशन परिधानों के लिए बायर-सैलर मीट्स जैसे व्यापार मेलों तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संगोष्ठियों में भारत की भागीदारी तथा भारतीय कृषि खाद्य क्षेत्र में व्यापार के अवसरों ने दोनों देशों के बीच व्यापार की अन्योन्यक्रिया को बढ़ावा दिया ।

पांचवें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त प्रैस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए, द हेग, 8 नवम्बर 2004।

राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, इटली के राष्ट्रपति श्री कार्लो अजेग्लियो क्यिपी की भारत यात्रा के दौरान उनके सम्मान में आयोजित रात्रि भोज। (12-16 फरवरी 2005)। राष्ट्रपति के दाईं ओर श्रीमती फ्रैंका क्यिम्पी, इतालवी राष्ट्रपति की पत्नी और उनके बाईं ओर श्रीमती गुरशरन कौर, प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की पत्नी।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग की गति को निरन्तर बनाए रखा। अन्तरिक्ष के क्षेत्र में स्थापित की गई बड़ी द्विपक्षीय परियोजना, मेगा-ट्रोपिक्यूस उपग्रह विकास कार्यक्रम है जिसके संबंध में आईएसआरओ (इसरो) और सीएनईएस के बीच नवम्बर 2004 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस उपग्रह को अब एक भारतीय लांचर से वर्ष 2008-2009 में छोड़ा जाना निर्धारित किया गया है। अंतरिक्ष से संबंधित एक आईएसआरओ-सीएनईएस संयुक्त कार्यदल का गठन भी किया गया है। 16 सितम्बर को परमाणु ऊर्जा विभाग और कॉमिशारियेट एएल एनर्जी एटोमिक (सीइए) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। परमाणु ऊर्जा संबंधी भारत-फ्रांस संयुक्त समिति का दूसरा सत्र 8-11 नवम्बर 2004 तक मुम्बई में आयोजित किया गया। भारतीय रेलवे और फ्रैंच रेलवे के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 30 जनवरी 2004 को पेरिस में हस्ताक्षर किए गए ।

भारत-फ्रांस मंच के समन्वयकों की बैठक 3 मई 2004 को पेरिस में आयोजित की गई। दूतावास के सहयोग से प्रतिष्ठित केन्द्र पॉम्पीडाऊ द्वारा आयोजित एक भारतीय फिल्मोत्सव 'डिड यू से बॉलीवुड' बहुत सफल रहा। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2004-05 के तहत 16 आईसीसीआर छात्रवृत्तियां फ्रांस के नागरिकों को दी गई। आईएसीपीएआर की औद्योगिक अनुसंधान समिति की पांचवीं बैठक 16 और 17 दिसम्बर 2004 को मुम्बई में आयोजित की गई। आईसीएमआर और आईएनएसईआरएम के संयुक्त कार्यदल की चौथी बैठक 24 मार्च 2004 को पेरिस में आयोजित की गई। सीईएफआईपीआरए की विज्ञान परिषद की 33वहीं बैठक 3 और 4 मई को ग्रनोबल में आयोजित की गई ।

जर्मनी

चांसलर श्रोएडर वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीय अन्योन्यक्रिया के एक भाग के रूप में 6-7 अक्तूबर 2004 को भारत की यात्रा पर आए। उनके साथ शिक्षा तथा अनुसंधान की संघीय मंत्री सुश्री एडेलगार्ड बुल्माहं, एक उच्चस्तरीय सरकारी शिष्टमण्डल तथा अग्रणी जर्मन कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का एक 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल भी आया। उन्होंने राष्ट्रपति जी, उप-राष्ट्रपति से मुलाकात की और प्रधान मंत्री के साथ प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय बातचीत की। विदेश मंत्री चांसलर श्रोएडर से मिले। प्रधान मंत्री के साथ प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय बातचीत के समय चांसलर ने भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए गहरी रुचि व्यक्त की थी जैसा कि 21वीं सदी में भारत-जर्मन साझीदारी में विचार किया गया है। भारत-जर्मन 'साइंस सर्कल', जो बेवसाइट के माध्यम से दोनों देशों के अनुसंधान संस्थानों तथा वैज्ञानिकों को जोड़ता है, का चांसलर द्वारा उद्घाटन किया गया। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग तथा मैक्स प्लैंक संस्थान द्वारा वैज्ञानिक सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता के संबंध में जर्मनी तथा भारत दोनों के विचार एक समान थे और दोनों ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक दूसरे की उम्मीदवारी के समर्थन को दोहराया। दोनों पक्षों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार (इस समय 5.02 बिलयन यूरो) को दुगुना करने का निर्णय लिया ।

जर्मनी के विदेश मंत्री जोसका फिशर पहले 14 जुलाई 2004 को भारत की यात्रा पर आए और प्रधान मंत्री से मिले। विदेश मंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय बातचीत का नेतृत्व किया जिसमें एक अनुकूल प्रयास में भारत तथा जर्मनी दोनों विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए सहमत हुए थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे के संयुक्त समन्वयित प्रस्ताव के महत्व को दोहराया। वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम के निमंत्रण पर जी-20 संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जर्मनी के वित्त मंत्री आइचल 14-15 अक्तूबर को भारत की यात्रा पर आए। दोनों मंत्री द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में वृद्धि करने के लिए संगठित प्रयास करने तथा द्विपक्षीय व्यापार, जो इस समय 5.8 बिलियन यूरो है, को दुगुना करने के लिए सहमत हुए। 20-21 नवम्बर 2004 को वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री वाई.वी. रेड्डी ने बर्लिन में आयोजित जी-20 मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्री ने 22 नवम्बर 2004 को फ्रैंकफोर्ट में निवेशकों के एक समूह को सम्बोधित किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित

ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिन्युएबल इनर्जी बॉन (1 से 4 जून 2004) संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री आर.सी. लाहौटी ने 15-21 अगस्त तक बर्लिन में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विधि संघ सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। भारत के मुख्य न्यायाधीन ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून संबंधी पूर्ण सत्र की सह-अध्यक्षता की। 10-11 नवम्बर को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री ओमप्रकाश चौटाला हरियाणा में पर्यटन तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ म्युनिख की यात्रा पर गए। माननीय अप्रवासी भारतीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जगदीश टाइटलर 10-12 अक्तूबर 2004 तक जर्मनी की यात्रा पर गए और अप्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों से मिले ।

विदेश सचिव श्री शशांक ने, 31 मार्च - 1 अप्रैल 2004 को बर्लिन में आयोजित अफगानिस्तान संबंधी तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। विदेश सचिव ने जर्मन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जरगेन च्रोबोग के साथ भी चर्चा की। रक्षा सचिव श्री अजय प्रसाद ने 4-8 अप्रैल 2004 को बर्लिन तथा म्यूनिख के लिए थलसेना, वायुसेना तथा नौसेना के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। जर्मनी की संयुक्त संचालन कमाण्ड के कमाण्डर ले.जनरल फ्रेडरिक रिचमैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल 10-17 अगस्त तक भारत की यात्रा पर आया। बवारियन न्यायमंत्री डा. बीटमार्क 31 अग्रस्त - 6 सितम्बर तक भारत की यात्रा पर आए ।

बेल्जियम

बेल्जियम के साथ भारत के संबंध हार्दिक तथा मैत्रीपूर्ण बने रहे। विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह 12-14 सितम्बर 2004 तक ब्रुसेल्स की यात्रा पर गए और बेल्जियम के विदेश मंत्री श्री कारेल डे गूच के साथ विचारों का विस्तारपूर्वक आदान-प्रदान किया जिसमें द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मुद्दे सम्मिलित थे। पारस्परिक हित के कोंसली मुद्दों के संबंध में एक तदर्थ संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बेल्जियम, वर्ष 2003 के लिए लगभग 6 बिलियन यूरो के द्विपक्षीय व्यापार कारोबार के साथ यूरोपीय संघ के अन्दर भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। बेल्जियम-भारत वाणिज्य मण्डल ने 'इण्डिया टार्गेट 2005' नामक संगोष्ठी के साथ 8 नवम्बर 2004 को अपनी स्वर्ण जयन्ती मनाई जिसमें बेल्जियम के एचआरएच प्रिंस फिलिप ने उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ाई ।

लक्जमबर्ग

लक्जमबर्ग के साथ भारत के संबंध हार्दिक व मैत्रीपूर्ण बने रहे। द्विपक्षीय दोहरे कर निदान करार पर वार्ता आरम्भ करने के लिए भारत और लक्जमबर्ग के अधिकारियों के बीच चर्चाएं आयोजित की गई। लक्जमबर्ग को 1 जनवरी 2005 से 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता मिली। वर्ष 2005 में भारत के लिए एक व्यापार शिष्टमण्डल की तैयारी में लक्जमबर्ग के वाणिज्यिक मण्डल के साथ वार्ता आयोजित की गई ।

नीदरलैण्ड

भारत और नीदरलैण्ड के संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बने रहे। इस वर्ष की विशेषता, यूरोपीय संघ की डच द्वारा अध्यक्षता के दौरान 8 नवम्बर 2004 को हेग में आयोजित पांचवां भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व प्रधान मंत्री द्वारा किया गया और अपनी यात्रा के दौरान हेग जाने और रानी वीटरीक्स से मिलने का अवसर निकाला। विदेश मंत्री ने डच विदेश मंत्री डा. बर्नार्ड आर.बोट के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ डच के अपने समकक्षी सुश्री करियन वान जेनिप से मिले ।

व्यापार तथा निवेश में वर्ष के दौरान संतोषजनक वृद्धि हुई। भारत के पक्ष में 1.8 बिलियन अमरीकी डॉलर की द्विपक्षीय व्यापार की प्रमात्रा तथा भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दोनों के संबंध में नीदरलैण्ड भारत के 7 शीर्ष भागीदारों में बना रहा। एक 17 सदस्यीय संयुक्त सीआईआई/एफआईसीसीआई व्यापार प्रतिनिधिमण्डल, 8 नवम्बर को भारत-यूरोपीय संघ व्यापार अन्योन्यक्रिया के समय नीदरलैण्ड की यात्रा पर गया। कोंसली क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रगति, निजी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के हेग सम्मेलन के अधीन विदेशी सार्वजनिक

दस्तावेज के लिए विधिककरण की आवश्यकता को समाप्त करते हुए हेग सम्मेलन में सम्मिलित होने का भारत का निर्णय था। इस समिलन से जन्म तथा विवाह प्रमाण-पत्रों जैसे भारतीय दस्तावेजों की, नीदरलैण्ड तथा हेग सम्मेलन के अन्य सभी सदस्य देशों में उनके उपयोग से पहले विधिककरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी ।

पुर्तगाल

भारत तथा पुर्तगाल ने 31 दिसम्बर 2004 को राजनयिक संबंधों की पुनःस्थापना की 30वीं जयन्ती मनाई। इस अवसर पर राष्ट्रपति जी और पुर्तगाल के राष्ट्रपति डा. जार्ज सेम्पाओ के बीच और विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री डा. एन्टोनियो विक्टर मार्टिन्स मॉन्टेयरी के बीच, मैत्री गठबंधन और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की परस्पर इच्छा दोहराते हुए बधाई संदेशों का आदान-प्रदान किया गया। द्विपक्षीय संबंधों की उल्लेखनीय बात उच्च स्तरीय यात्राओं का नियमित रूप से आदान-प्रदान है। शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कुमारी शैलजा 17-20 सितम्बर 2004 को पुर्तगाल की यात्रा पर गई और सामाजिक सुरक्षा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा शहरी, स्थानीय प्रशासन, आवास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री से मुलाकात की तथा दो सामाजिक आवास परियोजनाओं का दौरा किया। अप्रवासी भारतीय कार्य राज्य मंत्री श्री जगदीश टाइटलर 7 अक्तूबर 2004 को लिसबन की यात्रा पर गए और मुम्बई में आयोजित किए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारी में भारतीय राष्ट्रिकों के संघों तथा भारतीय मूल के लोगों के साथ चर्चा की ।

भारतीय नौसेना पोत आईएनएस टाबर रूस के कालिनिनग्रेड से मुम्बई तक की अपनी प्रथम यात्रा के दौरान चार दिनों (18-21 अप्रैल 2004 तक) के लिए लिसबन में रूका ।

भारत-पुर्तगाल द्विपक्षीय व्यापार भारत के पक्ष में 166 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा। व्यापार संवर्द्धन गतिविधियों के भाग के रूप में भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन ने लिसबन (26 जून-4 जुलाई 2004) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में भारत की भागीदारी के संबंध में समन्वय कार्य किया जिसमें लगभग 40 कंपनियों ने भाग लिया। विला डो कोन्डा के मेयर के आमंत्रण पर भारत ने 27वें पुर्तगाली राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में (24 जुलाई-8 अगस्त 2004) में विषय-वस्तु देश के रूप में भाग लिया। हस्तशिल्प संबंधी निर्यात संवर्द्धन परिषद, जिसने भारत की भागीदारी के संबंध में समन्वय कार्य किया, ने एक रंग-बिरंगा और आकर्षक विषय-वस्तु मण्डप स्थापित किया जो अंततः प्रदर्शनी का केन्द्र बिन्दु बन गया ।

स्पेन

स्पेन, यूरोपीय संघ में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। समाजवादी गठबंधन के प्रधान मंत्री जोस रोडरीग्यज जेपेटेरो की नई सरकार के साथ हमारे संबंध हार्दिक एवं घनिष्ट बने रहे। वर्ष 2004 के दौरान महत्वपूर्ण यात्राएं सम्पन्न हुई। पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती रेणुका चौधरी 5-8 अक्तूबर तक स्पेन की यात्रा पर गई। पेरिस स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालय द्वारा आयोजित रोड शो को संबोधित करने के अलावा राज्य मंत्री (पर्यटन) ने स्पेन के उद्योग, पर्यटन एवं वाणिज्य मंत्री श्री जोस मान्टीला एग्यूलेरा से भेंट की। पारस्परिक देशों के उत्सव आयोजित करने, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान आरम्भ करने जैसे द्विपक्षीय मुद्दों तथा होटल श्रृंखला तथा बुनियादी ढांचा निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। राज्य मंत्री (अप्रवासी भारतीय कार्य) श्री जगदीश टाइटलर 5-7 अक्तूबर को स्पने की यात्रा पर गए और स्थानीय भारतीय समुदाय से अन्योन्यक्रिया की। इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध विशेष तौर पर मजबूत हुए। वर्ष 2003-04 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार सार्थक रूप से भारत के पक्ष में 1.25 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। संबंधित निर्यात संवर्द्धन परिषदों के सहयोग से मिशन द्वारा महत्वपूर्ण निवेश संवर्द्धन कार्यक्रम तथा चमड़े और परिधान क्षेत्र में बायर-सैलर मीट्स आयोजित की गई ।

भारतीय संस्कृति तथा परम्परा में स्पेनवासियों की बढ़ती अभिरुचि, पर्यटन में वृद्धि तथा भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति अति उत्साहित प्रतिक्रिया प्रमाणित होती है। स्पेन से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या इस वर्ष के अंत तक 38000 के आंकड़े तक पहुंच जाने की संभावना है। सांस्कृतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कठपुतली उत्सव नवम्बर में स्पेन के उत्तर में आयोजित किया गया। भारत इस उत्सव में एक

विषय वस्तु देश था जिसमें अन्य विभिन्न भारतीय कलाओं और पाक-प्रणाली का चित्रण भी शामिल किया गया था। कासा.डे.ला.इण्डिया (भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र) की स्थापना की हमारी पहलकदमी को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला जिसमें महानिदेशक (आईसीसीआर) भी पधारे जिन्होंने, आईसीसीआर की ओर से कासा डे.ला. इण्डिया को 50,000 अमरीकी डॉलर का चैक प्रदान किया ।

राष्ट्रमण्डल

राष्ट्रमण्डल महाचिव श्री डॉन मैक किन्नन, चोगम 2005 से पूर्व शासन प्रमुखों के साथ परामर्श करने के लिए अक्तूबर 2004 में भारत की यात्रा पर आए। वे प्रधान मंत्री व विदेश मंत्री से मिले और माल्टा में अगली चोगम बैठक के प्रारूप सहित राष्ट्रमण्डल संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के तकनीकी सहयोग में इस प्रकार वृद्धि की जाए ताकि इससे भारत का बढ़ता हुआ कद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबिम्बित हो। भारत राष्ट्रमण्डल के बजट में पांचवां सबसे बड़ा अंशदाता बना हुआ है और इसने न्यूयार्क स्थित राष्ट्रमण्डल के लघु राष्ट्र कार्यालय के लिए अपने वार्षिक अंशदान को बढ़ाकर 35000 अमरीकी डॉलर करने का निर्णय लिया है। भारत सीएफटीसी के लिए 7,20,000 जीबीपी के वार्षिक अंशदान के साथ सबसे बड़ा अंशदाता भी बना हुआ है। भारत ने, सीएमएजी तथा पर्यटन संबंधी समिति और गवर्नरों के राष्ट्रमण्डलीय बोर्ड की कार्यकारी समिति तथा राष्ट्रमण्डल संघ सहित महत्वपूर्ण राष्ट्रमण्डल निकायों अपनी सक्रिय सदस्यता जारी रखी और इसकी बैठकों में सक्रिय भागीदारी की। वर्ष 2004 के दौरान भारत ने राष्ट्रमण्डल की प्रत्यायन समिति की अध्यक्षता की जो चोगम 2005 में भागीदारी के लिए राष्ट्रमण्डल के लिए गैर-सरकारी संगठनों के प्रत्यायन की अनुशंसा करने के लिए गठित की जाती है।

यूरोप II

भारत के परम्परागत तौर पर यूरोप स्र्स्र् प्रभाग के उन 29 देशों के साथ मैत्रीपूर्ण तथा स्थायी संबंध रहे हैं जो मार्च 2004 में अस्तित्व में आया था। समीक्षाधीन वर्ष इस क्षेत्र के आर्थिक-राजनैतिक ज्यामिति में युगान्तरीय परिवर्तनों का साक्षी रहा है। 2 अप्रैल 2004 को सात पूर्वी यूरोपीय देश अर्थात बुल्गारिया, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया तथा स्लोवेनिया उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में सम्मिलित हो गए। एक महीने बाद, यूरोपीय संघ का विस्तार किया गया ताकि उसमें पूर्व तथा दक्षिण के दस और सदस्य राष्ट्रों को सम्मिलित किया जा सके। वर्ष के अन्त तक यूरोपीय संघ ने निर्णय लिया कि बुल्गारिया तथा रोमानिया 2007/2008 में इस निकाय में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय संघ ने क्रोएशिया तथा तुर्की के साथ एक्सेशन वार्ता आरम्भ करने का भी निर्णय लिया। यूरोपीय संघ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तथा निवेश का स्रोत होने के नाते वर्तमान परिवर्तनों का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ा ।

अल्बानिया

भारत तथा अल्बानिया ने वर्ष 2004 के दौरान एक दूसरे की राजधानियों में अवैतनिक महा कोंसलों की नियुक्ति की है।

आस्ट्रिया

विदेश राज्य मंत्री श्री राव इन्द्रजीत सिंह ने जुलाई 2004 में आस्ट्रिया के स्वर्गीय राष्ट्रपति थॉमस क्लेस्टिल की राष्ट्रीय अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए आस्ट्रिया की यात्रा की। निर्धारत कार्यक्रमों के अलावा मंत्री आस्ट्रिया के नए राष्ट्रपति, चांसलर तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की ।

वर्ष के दौरान द्विपक्षीय कार्यक्रमों में, माननीय विदेश मंत्री तथा आस्ट्रिया के विदेश मंत्री के साथ ब्रुसैल्स में सितम्बर 2004 के आरम्भ में बैठकें, अगस्त 2004 में थलसेनाध्यक्ष की यात्रा, अगस्त 2004 में आंध्र प्रदेश के मंत्रिमण्डलीय प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा तथा विएना में नवम्बर 2004 के अन्त में सम्पन्न विदेशी कार्यालय परामर्शो का तीसरा दौर भी सम्मिलित हैं ।

जबकि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणीशंकर अय्यर की सितम्बर 2004 में विएना की यात्रा बहुपक्षीय परिप्रेक्ष्य में थी फिर भी उन्होंने आस्ट्रिया के अपने समकक्षी के साथ द्विपक्षीय सम्भावनाओं पर भी चर्चा की ।

सितम्बर 2004 में, नागरिक उड्डयन मंत्री ने आस्ट्रिया की एयरलाइनों के अनुरोध पर उनकी दिल्ली के लिए वर्तमान उड़ानों के अतिरिक्त विएना-मुम्बई उड़ाने संचालित करने की सशर्त अनुमति प्रदान की ।

बोस्निया-हर्जेगोविना

पर्यटन राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी ने 29 अक्तूबर से 1 नवम्बर 2004 तक बोस्निया हर्जेगोविना की सरकारी यात्रा पर गई जिसके दौरान गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा उनका स्वागत किया गया ।

भारत ने, बोस्निया हर्जेगोबिना के टुल्जा केन्टोन के बाढ़ पीड़ितों के लिए 50000 अमरीकी डालर (लगभग 22 लाख रुपए) की मानवीय सहायता की दो खेपें भेजी ।

बुल्गारिया

बुल्गारिया के विदेश मंत्री डा. सोलोमन पास्सी 28 जुलाई 2004 को भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आए जिसके दौरान उनके साथ विदेश उप-मंत्री, प्रतिरक्षा उप-मंत्री तथा कृषि उप-मंत्री और बुल्गारिया की संसद के कुछ सदस्य भी थे। इस यात्रा के दौरान वहां के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श किया; शिष्टाचार के लिए उन्होंने राष्ट्रपति जी तथा रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। यात्रा पर आए बुल्गारिया के विदेश मंत्री ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की सदस्यता के लिए बुल्गारिया का समर्थन दोहराया और आतंकवाद के संबंध में स्थिति के समन्वय में रुचि व्यक्त की। विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत तथा बुल्गारिया के विदेश मंत्रालय के राजनयिक संस्थान के बीच परस्पर सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए ।

आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-बुल्गारिया संयुक्त आयोग का 15वां सत्र 17-20 नवम्बर 2004 तक दिल्ली में आयोजित किया गया। बुल्गारिया के कृषि तथा वन मंत्री श्री मेहमद डिक्मे ने बुल्गारिया के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया जिसमें आर्थिक उप-मंत्री, परिवहन एवं संचार उप-मंत्री और युवा एवं खेल उप-मंत्री भी सम्मिलित थे। माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। संयुक्त व्यवसाय परिषद का सत्र भी आयोजित किया गया ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-बुल्गारिया संयुक्त समिति का तीसरा सत्र 1-2 नवम्बर 2004 को आयोजित किया गया। इसकी सह-अध्यक्षता बुल्गारिया के शिक्षा एवं विज्ञान मंत्री प्रो. कामेन वेलेव तथा भारत के सचिव (विज्ञान एवं प्रौद्योगिक) प्रो. वी.एस. रामामूर्ति ने की। इस सत्र के दौरान 2005-07 तक की अवधि के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए ।

भारत तथा बुल्गारिया ने सरकारी संदेशों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के आदान-प्रदान के द्वारा द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयन्ती का स्मरणोत्सव मनाया।

क्रोएशिया

अन्तर्राष्ट्रीय अवैध मादक तथा साइकोट्रोपिक पदार्थों, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा संगठित अपराध पर रोक लगाने संबंधी भारत-क्रोएशिया संयुक्त समिति की पहली बैठक 8-9 सितम्बर 2004 को जगरेब में आयोजित की गई ।

6 वर्षों के अन्तराल के बाद, भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन ने 80वें वार्षिक जगरेब अन्तर्राष्ट्रीय शरद मेला 2004 में 14 भारतीय कंपनियों की भागीदारी की व्यवस्था की ।

साइप्रस

साइप्रस के विदेशी मामलों के स्थायी सचिव श्री सोटोस जैरिव्योस विदेश कार्यालय परामर्शों के दूसरे दौर के लिए 4-7 नवम्बर 2004 को भारत की यात्रा पर आए। सचिव (पश्चिम) ने श्रीमती शशी यू. त्रिपाठी ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया। श्री जैक्योस ने माननीय विदेश मंत्री के साथ एक शिष्टाचार बैठक भी की और उन्हें साइप्रस के विदेश मंत्री श्री जॉर्ज लेकोवो की ओर से एक निमंत्रण पत्र सौंपा। वे नाशकॉम के अध्यक्ष से भी मिले ।

चैक गणराज्य

कन्द्रीय पर्यावरण तथा वन राज्य मंत्री श्री नामोनारायण मीणा ने मोन्ट्रीयल प्रोटोकॉल के बाद बहुपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए 25-27 नवम्बर 2004 को प्रेग की यात्रा की ।

भारत-चैक गणराज्य संयुक्त समिति का 6वां सत्र 16-17 दिसम्बर 2004 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी सह-अध्यक्षता चैक के उद्योग एवं व्यापार उप-मंत्री श्री मिरोस्लेव सोमोल तथा भारत की ओर से वाणिज्य सचिव श्री एस.एन. मेनन द्वारा की गई ।

गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर की आवक्ष मूर्ति के उद्घाटन तथा भारतीय फिल्मोत्व सहित वर्ष 2004 के दौरान प्रेग में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

डेनमार्क

डेनमार्क के विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार मंत्री श्री हल्गे सेन्डर ने 25-29 अक्तूबर 2004 तक भारत की यात्रा की जिसके दौरान जीव-प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। डेनमार्क के उप-प्रधानमंत्री श्री बेन्डटसन भी 12-17 अक्तूबर 2004 तक भारत की यात्रा पर आए जिसके दौरान उन्होंने दादरी (उ.प्र.) में एक इण्लैण्ड कॉन्टेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। डेनमार्क की संसद की विदेशी मामलों संबंधी समिति के एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 3-8 नवम्बर 2004 तक भारत की यात्रा की जिसके दौरान उसने भारत की विदेशी मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया ।

फिनलैण्ड

फिनलैण्ड के विदेशी आर्थिक संबंधों के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री पेक्का लिन्टू ने 7-10 जून 2004 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा का सदुपयोग, भारत के विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों तथा दिल्ली, बंगलौर और चेन्नई में भारतीय व्यापार के अधिपतियों के साथ विचारों के व्यापक आदान प्रदान के लिए किया गया। फिनलैण्ड के विदेश कार्यालय में निदेशक (एशिया एवं प्रशान्त) श्री पेक्का मेत्सो भी नवम्बर 2004 में द्विपक्षीय विचार विमर्श के लिए भारत की यात्रा पर आए ।

इस अवधि के दौरान भारत तथा फिनलैण्ड के द्विपक्षीय संबंध हार्दिक मैत्रीपूर्ण तथा किसी भी प्रकार के द्विपक्षीय मतभेद रहित रहे। भारतीय वायुसेना बैण्ड के एक 75 सदस्यीय दल हमीना टैटू अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक संगीत उत्सव में भाग लेने के लिए 1-8 अगस्त तक फिनलैण्ड की यात्रा पर गया ।

ग्रीस

13 से 29 अगस्त 2004 के दौरान एथेन्स में आयोजित 28वें ओलम्पिक खेलों में 80 से अधिक भारतीय एथलिटों ने भाग लिया। मेजर आर.एस.राठौर ने निशानेबाजी प्रतिस्पर्द्धा में रजत पदक जीता। युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री सुनील दत्त के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल ने ओलम्पिक की अवधि के दौरान एथेन्स की यात्रा की। इसके बाद 17 से 28 सितम्बर 2004 के दौरान एथेन्स में ही आयोजित पैरालम्पिक्स में भारत के देवेन्द्र ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता जबकि राजेन्द्र सिंह ने पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता ।

हंगरी

हंगरी के राष्ट्रीय सांस्कृतिक दाय मंत्री श्री इस्तवान हिल्लर ने 22-25 नवम्बर 2004 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने माननीय सूचना, प्रसारण एवं संस्कृति मंत्री श्री जयपाल रेड्डी के साथ नई दिल्ली में हंगेरियन संस्कृति सप्ताह का उद्घाटन किया ।

हंगरी के प्रधानमंत्री के अन्तर्राष्ट्रीय नीति संबंधी मुख्य सलाहकार डा. अन्द्रास बलोघ ने पंचशील संबंधी संगोष्ठी में भाग लेने के लिए 17-27 नवम्बर 2004 तक भारत की यात्रा की ।

सचिव (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन) श्री लक्ष्मी चन्द ने आर्थिक सहयोग संबंधी संशोधित करार पर हस्ताक्षर करने के लिए 29 मार्च 2004 को हंगरी की यात्रा की ।

शिक्षा संबंधी भारत-हंगरियन संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक 2-4 नवम्बर 2004 तक बुडापेस्ट में आयोजित की गई।

भारत के ज्ञान आधारित उद्यमों ने वर्ष के दौरान दो नई स्थापनाएं खोल कर हंगरी में अपनी मौजूदगी को सुदृढ़ करना जारी रखा ।

माल्टा

14-16 अक्तूबर 2004 तक अपनी माल्टा की यात्रा के दौरान विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (यूरोप - ख्ख्र) ने माननीय विदेश मंत्री की ओर से निमंत्रण पत्र सौंपने के लिए माल्टा के विदेश मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की ।

माल्दोवा

माल्दोवा के वाणिज्य मण्डल के प्रतिनिधिमण्डल ने नवम्बर

2004 में नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार सम्मिलित होने के लिए भारत की यात्रा की थी।

नार्वे

विदेश मंत्री श्री जेन पीटरसन 6 जुलाई 2004 को भारत की सरकारी यात्रा पर आए जिसके दौरान उन्होंने माननीय विदेश मंत्री के साथ विचारों का व्यापक आदान प्रदान किया। दोनों विदेश मंत्रियों ने सहयोग के एक संयुक्त आयोग की स्थापना करने के लिए एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए। यात्रा पर आए नार्वे के विदेश मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ भी विचार विमर्श किया ।

नार्वे के राज्य सचिव श्री विदार हेल्गेसेन ने 11 से 15 अक्तूबर 2004 तक भारत की सरकारी द्विपक्षीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान राज्य सचिव ने विदेश राज्य मंत्री श्री राव इन्द्रजीत सिंह के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह से भी मुलाकात की। नार्वे के विकास सहयोग संबंधी राज्य सचिव श्री ओलाव क्जोरवेन ने भी 7-8 सितम्बर 2004 को भारत की सरकारी यात्रा की जिसके दौरान वे विदेश राज्य मंत्री श्री इ. अहमद और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. एम.एस. आहलुवालिया से मिले ।

पोलैण्ड

मार्शल ऑफ पोलिस सेज्म, श्री जोसफ ओलेस्की 9 दिसम्बर 2004 से भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। माननीय लोक सभा अध्यक्ष से मिलने के अलावा यात्रा पर आए श्री ओलेस्की का राष्ट्रपतिजी, उप-राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री द्वारा भी स्वागत किया गया ।

रक्षा मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी 30 अक्तूबर 2004 से पोलैण्ड की तीन दिवसीय यात्रा पर गए जिसके दौरान उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा रक्षामंत्री सहित पोलैण्ड के गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ उपयोगी विचार विमर्श किया। इस वर्ष के दौरान रक्षा अधिकारियों द्वारा भी अनेक द्विपक्षीय यात्राएं की गई ।

भारत तथा पोलैण्ड ने, सरकारी संदेशों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आदान प्रदान कर द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयन्ती का स्मरणोत्सव मनाया।

पोलैण्ड के यूरोपीय संघ में अधिमिलन के बाद भारत ने एक नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पोलैण्ड के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श आरम्भ किया। वर्ष के दौरान अनेक व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों ने भी पोलैण्ड की यात्रा की ।

रोमानिया

माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन ने 19-22 सितम्बर 2004 तक बुखारेस्ट में आयोजित विश्व डाक संघ के 23वें सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। सम्मेलन के कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने रोमानिया की अपनी समकक्षीय सुश्री एडरीयाना टिकाऊ के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।

रक्षा सचिव श्री अजय प्रसाद के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने 8 से 10 अप्रैल 2004 तक बुखारेस्ट की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमण्डल ने कार्यकारी रक्षामंत्री श्री जॉर्ज क्रिस्टीयन मायर से मुलाकता की। इस प्रतिनिधिमण्डल ने रक्षा राज्य सचिव जॉज मटाचे तथा आर्थिक एवं वाणिज्य राज्य सचिव जनरल डा. डेसीबल लिना के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया ।

भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.वी. रेड्डी ने 12वें वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय न्याय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 19 से 21 मई 2004 तक बुखारेस्ट की यात्रा की ।

रोमानिया सरकार के विशेष प्रतिनिध होहेनजोलरन वेरिनजेन के राजकुमार राडु और उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी मारगरिटा ने, महाराष्ट्र के राज्यपाल के निमंत्रण पर 7 से 21 नवम्बर 2004 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश राज्य मंत्री श्री राव इन्द्रजीत सिंह से मुलाकात की ।

भारत-रोमानिया व्यापार में प्रभावशाली उन्नति हुई जो वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए 119 मिलियन अमरीकी डालर के आंकड़े तक पहुंच गया। रोमानिया के साथ व्यापार तथा निवेश सहयोग में समन्वय तथा संवर्द्धन के लिए बुखारेस्ट में एक 'रोमानिया के भारतीय व्यापार गठबंधन' की स्थापना

की गई। अप्रैल 2004 के अन्त में बुखारेस्ट तथा ब्रासोव में एक बड़ी भारतीय कपड़ा प्रदर्शनी आयोजित की गई ।

मध्य यूरोप के हिन्दी विद्वानों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन जुलाई 2004 में ट्रांसाइलवानिया-मीरक्युरियासियुक के सेपीएटिया-हंगेरीयन विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया ।

सर्बिया तथा मॉन्टेनेग्रो (एससीजी)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास राज्य मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने 27-30 अक्तूबर 2004 तक सर्बिया मॉन्टेनेग्रो की सरकारी यात्रा की। राज्य मंत्री (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), सर्बिया एवं मॉन्टेनगब्रो के राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री और सर्बिया गणराज्य के विज्ञान मंत्री से मिले थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी एक द्विपक्षीय करार पर भी हस्ताक्षर किए गए ।

पर्यटन राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी ने 1-4 नवम्बर 2004 तक सर्बिया एवं मॉन्टेनेग्रो की सरकारी यात्रा की । उन्होंने 'भारतीय उत्सव के दिन' समारोह का उद्घाटन किया और एससीजी के विदेश मंत्री और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध मंत्री तथा सर्बिया के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के साथ बैठकें की। इस यात्रा के दौरान भारत और सर्बिया गणराज्य के बीच पर्यटन सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

एससीजी के विदेश मंत्रालय के सहायक मंत्री (अन्तर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग) श्री दुसान क्रनोगोरसेविक ने 2 दिसम्बर 2004 को भारत-एससीजी विदेश कार्यालय परामर्श के चौथे दौर के संबंध में भारत की यात्रा की। भारत की ओर से सचिव (पश्चिम) श्रीमती शशी यू. त्रिपाठी ने अध्यक्षता की। यात्रा पर आए एससीजी उच्च पदाधिकारी विदेश राज्य मंत्री श्री राव इन्द्रजीत सिंह से भी मिले ।

स्वीडन

स्वीडन के रक्षा आयोग के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 2-7 नवम्बर 2004 तक भारत की यात्रा की। इस पहली यात्रा के दौरान इस प्रतिनिधिमण्डल का रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया ।

स्वीडन के विदेश मंत्री श्री हेंस डाहलग्रेन ने, सचिव (पश्चिम) श्रीमती यू. त्रिपाठी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ विदेश कार्यालय परामर्श के लिए भारत की यात्रा की। उन्होंने माननीय विदेश मंत्री को, गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर को भेंट किए गए उस नॉबल मैडल की दो प्रतिकृतियां भेंट की जिसे इस वर्ष आरम्भ में विश्व भारती संग्रहालय से चोरी कर लिया गया था ।

स्वीडन के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक (व्यापार नीति) श्री लार्स ऑलोफ लिंडग्रेन ने अक्तूबर 2004 में भारत में आए एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। श्री लिंडग्रेन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से मिले ।

स्लोवाक गणराज्य

माननीय राष्ट्रपति जी के निमंत्रण पर स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति डा. इवान गेसपारोविक ने 11 दिसम्बर 2004 को भारत की पांच दिवसीय राजकीय यात्रा आरम्भ की। उनके साथ स्लोवाक की प्रथम महिला मैडम सिलविया गेसपारोविकोवा, आर्थिक, रक्षा तथा विदेश राज्य मंत्री और एक बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमण्डल था। डा. गेसपारोविक माननीय राष्ट्रपति जी से मिले और माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ प्रतिनिधिमण्डल स्तर की बातचीत की। उन्होंने शिष्टाचार के नाते माननीय उप-राष्ट्रपति, विदेश मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से भी मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम तथा लघु उद्योग में सहयोग से संबंधित तीन द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। स्लोवाक राष्ट्रपति के भारत में अन्य कार्यक्रमों में महान स्लोवाक नेता श्री अलेक्जैण्डर डबकेक के नाम से नई दिल्ली में सड़क का नामकरण करना तथा नई दिल्ली और मुम्बई में शीर्षस्थ मण्डलों को संबोधित करना सम्मिलित था। स्लोवाक राष्ट्रपति द्वारा भारत की पहली राजकीय यात्रा होने के कारण इस यात्रा से परम्परागत द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत होने और उनके भावी विकास के लिए नीति का विकास करने का अवसर सृजित होने की सम्भावना थी ।

आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग संबंधी भारत-स्लोवाक संयुक्त समिति का पांचवां सत्र 18-19 अक्तूबर 2004 के दौरान ब्रातीसलावा में आयोजित किया गया। इस सत्र की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश व्यापार के महानिदेशक द्वारा तथा स्लोवाक की ओर से व्यापार एवं ग्राहक संरक्षण के महानिदेशक द्वारा की गई। वर्ष 2003-04 में द्विपक्षीय व्यापार 27 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा ।

स्लोवेनिया

व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-स्लोवेनियन संयुक्त समिति का पांचवां सत्र 21-22 अप्रैल 2004 को लजूबल्जाना में आयोजित किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव श्री जी.के. पिल्लै ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया और स्लोवेनिया की ओर से आर्थिक मंत्रालय में विदेश आर्थिक संबंधों के राज्य मंत्री श्री रेनाटा विटेज ने नेतृत्व किया ।

स्विटरलैण्ड

रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर, स्विटजरलैण्ड के रक्षा, खेल तथा नागरिक संरक्षण संबंधी फैडरल कॉऊंसलर एवं उप-राष्ट्रपति श्री सैमूअल सचमिड 27 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2004 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए। यह स्विटजरलैण्ड के रक्षा मंत्री द्वारा की जाने वाली भारत की पहली सरकारी यात्रा थी। रक्षा मंत्री के साथ व्यापक चर्चा के अलावा यात्रा पर आए गण्यमान्य व्यक्ति का राष्ट्रपति जी द्वारा भी स्वागत किया गया ।

भारत-स्विस संयुक्त आयोग का नौवां सत्र 8 दिसम्बर 2004 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दोनों प्रतिनिधिमण्डलों का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव श्री अभिजीत सेनगुप्ता और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के प्रमुख, राजदूत जोरग रेडिंग द्वारा किया गया। द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में नियमित प्रगति दर्ज की गई और यह पिछले वर्ष 3.75 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया ।

तुर्की

तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव जनरल सुकरू सारीसिक 4-9 अप्रैल 2004 तक भारत की यात्रा पर आए और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्रा, सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष एडमिरल माधवेन्द्र सिंह, थलसेनाध्यक्ष जनरल एन.सी.विज, विदेश सचिव श्री शशांक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सहायक श्री सतीश चन्द्र से मिले। इस यात्रा से दोनों पक्षों को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और साझा हित के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने में सहायता मिली और इससे अपनी-अपनी सुरक्षा तथा भू-नीति संबंधी वातावरण को परस्पर बेहतर तरीके से समझने में योगदान मिला ।

सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष एडमिरल माधवेन्द्र सिंह 10-15 मई 2004 तक तुर्की की यात्रा पर गए और अपने समकक्षी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल ओजकोक तथा तुर्की की सशस्त्र सेनाओं के अन्य उच्चाधिकारयों से बहुत सकारात्मक बातचीत की ।

भारतीय नौसेना के दो पोतों - आईएनएस गंगा तथा आईएनएस शक्ति - की 30 मई 2004 को इस्तान्बुल की चार दिवसीय सद्भावना यात्रा से द्विपक्षीय प्रतिरक्षा सहयोग को प्रोत्साहन मिला। सात वर्षों में इस प्रकार की यह पहली यात्रा थी ।

आतंकवाद पर काबू पाने संबंधी संयुक्त कार्यदल की तुर्की के साथ पहली बैठक 1 और 2 जून 2004 को आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में अपर सचिव श्रीमती मीरा शंकर द्वारा किया गया और तुर्की के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व आसूचना एवं अनुसंधान के महानिदेशक राजदूत के. इकवेट तेजकेन द्वारा किया गया तथा तुर्की के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व महानिदेशक आसूचना एवं अनुसंधान के महानिदेशक एम्बेसडर के.एकवेट तेजकन द्वारा किया गया ।

आर्थिक मंत्रालयों के भारत-तुर्की संयुक्त कार्यदल का पहला सत्र 6-7 अक्तूबर 2004 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बैठक के दौरान, द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य, मौजूदा 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 2009 तक 2 बिलियन अमरीकी डॉलर निर्धारित करने पर सहमति जताई गई। संयुक्त कार्यदल ने सहयोग बढ़ाने के लिए खाद्य तथा खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, कपड़ा, मोटर वाहन, इलैक्ट्रॉनिक्स, औषध निर्माण, पर्यटन, हाइड्रोकार्बन्स, सूचना प्रौद्योगिकी, जीव-प्रौद्योगिकी, रेलवे तथा चमड़ा सहित अनेक क्षेत्रों की पहचान की ।

तुर्की के लिए भारत का निर्यात 2004 में पहली बार 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर को पार कर गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान के 37 विशेषज्ञों ने आईटैक फैलोशिप का लाभ उठाया। तुर्की में आयोजित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खाद्य उत्सवों तथा फिल्म प्रदर्शनों से द्विपक्षीय व्यक्तियों से व्यक्तियों के संबंधों को बढ़ावा मिला। तुर्की से भारत आने वाले यात्रियों की संख्या में भी लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

■■

अमरीका

8

संयुक्त राज्य अमरीका

वर्ष 2004-05 के दौरान भारत-अमरीका संबंधों में गहन क्रियाकलाप जारी रहे जो गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में थे । दोनों पक्षों ने भारत और अमरीका के बीच सामरिक भागीदारी स्थापित करने के अपने संकल्प को दोहराया । दोनों पक्षों में संबंध को और व्यापक, गहन तथा सुदृढ़ बनाने की वचनबद्धता है । यह बात भारत सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम और जून 2004 में संसद में दिये गये राष्ट्रपति के भाषण में परिलक्षित होती है । नवम्बर, 2004 में राष्ट्रपति बुश के दुबारा चुने जाने के साथ ही अमरीकी सरकार ने भारत और अमरीका के बीच सामरिक भागीदारी को और ठोस बनाने की वचनबद्धता व्यक्त की ।

दोनों पक्ष सामरिक मसले, रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शांति-रक्षा, सायबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, अंतरिक्ष, ऊर्जा एवं पर्यावरण इत्यादि सहित आपसी हित के अन्य मसलों पर विस्तृत बातचीत कर रहे हैं । दोनों पक्षों के बीच सभी स्तरों पर क्रियाकलाप चल रहा है । जून 2004 में विदेश मंत्री की वाशिंगटन यात्रा और 7-8 जुलाई, 2004 तक आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक के दौरान विदेश मंत्री कॉलिन पावेल के साथ उनकी बातचीत से राजनैतिक स्तर पर प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुए । अमरीकी पक्ष से 13-14 जुलाई 2004 तक अमरीकी विदेश उप-मंत्री ने भारत-अमरीकी संबधों के सतत् विकास की पुष्टि के लिए भारत की यात्रा की । जून 2004 में नई दिल्ली में हुई रक्षा नीति दल की बैठक और जून 2004 में बंगलौर में हुई भारत-अमरीकी अंतरिक्ष सम्मेलन से सकारात्मक संदेश मिले ।

प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा

संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के अवसर पर 21 सितम्बर, 2004 को प्रधानमंत्री ने न्यूयार्क में राष्ट्रपति बुश से मुलाकात की। संयुक्त वक्तव्य "अमरीका-भारत भागीदारीः सहयोग और विश्वास" में उन्होंने कहा कि "आज से पहले द्विपक्षीय संबंध इतने घनिष्ठ कभी नहीं थे " और इससे भारत-अमरीका सामरिक भागीदारी के और विकास की दिशा निर्धारित हुई । बैठक के दौरान राष्ट्रपति बुश ने इस बात पर बल दिया कि भारत के साथ हमारा संबंध महत्वपूर्ण और संभावनाओं से परिपूर्ण है । प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि हमार द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की हमारी वचनबद्धता से शांति, समृद्धि और आतंकवाद मुक्त पर्यावरण के निर्माण में सहायता मिलेगी । उन्होंने सामरिक भागीदारी के अगले कदम के चरण-I को क्रियान्वित करने, जिसमें इसरो मुख्यालय को वाणिज्य विभाग की प्रतिबंधित इकाइयों की सूची से हटा लिया गया है, को सहयोग और विकास के एक नये युग की शुरूआत माना । विस्तारित रक्षा सहयोग को बढ़ते हुए संबंधों का एक अभिन्न पहलु माना गया ।

दोनों नेताओं में अपनी साझी वैश्विक चिंताओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया और इस बात पर सहमत हुए कि विश्व को सुरक्षित स्थान बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है । उन्होंने आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई और व्यापक विनाश के हथियारों और चलाये जाने की प्रणाली के प्रसार का मुकाबला करने में मिलकर कार्य करने के महत्व को स्वीकारा । वे इस बात पर सहमत हुए कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करने वाली नीतियों से उनकी आर्थिक भागीदारी व्यापक और संवर्द्धित होगी । इस उद्देश्य के लिए दोनों नेताओं ने विश्व व्यापार संगठन की दोहा विकास कार्यसूची सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों तथा अमरीका-भारत आर्थिक वार्ता और उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग दल जैसे द्विपक्षीय प्रयासों के जरिए सहयोग संवर्द्धित किये जाने पर बल दिया ।

विदेश सचिव ने अमरीकी प्रशासन में अपने समकक्षों के साथ चर्चा करने के लिए 16-18 सितम्बर, 2004 तक वाशिंगटन डी सी का दौरा किया । उन्होंने विदेश विभाग, व्हाइट हाउस और पेंटागन में बैठकें कीं । विदेश सचिव और अंडर सेक्रेटरी मार्क ग्रोसमैन के साथ विदेश कार्यालय

परामर्श एवं एशियाई सुरक्षा वार्ताएं की गयीं । विदेश सचिव की अमरीकी प्रशासन के उच्चाधिकारियों, मनोनीत विदेश मंत्री कोंडोलिजा राइस, उप रक्षा मंत्री पाउल वोल्फोविच, उप विदेश मंत्री रिचर्ड आर्मिटेज, एवं वाणिज्य, आर्थिक एवं कृषि मामलों के अंडर सेक्रेटरी एलन लारसन के साथ उपयोगी बैठकें हुईं । विदेश मंत्री ने रक्षा अंडर सेक्रेटरी डगलस फीथ, वाणिज्य अंडर सेक्रेटरी केनेथ जस्टर और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्टीव हेडले के साथ भी मुलाकात की । इन बैठकों से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मसलों पर विचारों का व्यापक उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान हो पाया । अमरीका ने भारत-अमरीकी संबंधों के प्रति अपनी मजबूत वचनबद्धता को दोहराया। विदेश सचिव ने 18-19 नवम्बर, 2004 तक वाशिंगटन डी सी में हुई एच टी सी जी की तीसरी बैठक के लिए उद्योग-सरकार के एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया । इस बैठक के दौरान उद्योग-सरकार सत्र में डेटा प्रायवेसी और रक्षा प्रौद्योगिकी और सरकार-सरकार सत्र में सामरिक व्यापार और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के संबंध में चर्चा की गयी । इस बैठक में दोनों पक्षों के औद्योगिक और सरकारी प्रतिनिधियों ने व्यापक भागीदारी की । पूर्ण अधिवेशन में लगभग 100 भागीदार थे ।

भारत ने व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार रोकने के प्रस्तावों को प्रतिपादित करने के लिए 11 फरवरी, 2004 के राष्ट्रपति बुश की पहल का स्वागत किया । हमारे द्विपक्षीय वार्ता तंत्र के एक भाग के रूप में अपर सचिव (यू एन) और संयुक्त सचिव (ए एम एस) ने 22 नवम्बर, 2004 को वाशिंगटन में सामरिक स्थायित्व पर सहायक मंत्री स्टीफन रडमेकर और प्रसार मसलों पर सहायक सचिव सुसान बर्क के साथ बातचीत की । रक्षा मंत्री रोनाल्ड रम्सफील्ड ने 8-9 दिसम्बर, 2004 तक भारत का दौरा किया और उन्होंने प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ मुलाकात की । हमारे रक्षा सहयोग की परिधि को बढ़ाने में स्पष्ट रूप से रूचि ली गयी।

रक्षा मसलों पर होने वाली वार्ताओं का पर्यवेक्षण रक्षा नीति समूह जैसे संस्थागत ढ़ाचे द्वारा किया जाता है जिसने 1-2 जून, 2004 तक की बैठक में अपनी चर्चा जारी रखी । इसमें हमारे संबंधों के तीन पहलुओं, रक्षा आदान-प्रदान, रक्षा आपूर्ति और तकनीकी सहयोग पर एक अलग द्विपक्षीय समूह द्वारा बातचीत की जाती है । सैन्य आदान-प्रदान और अभ्यास नियमित रूप से होते हैं जिनके अपने आयाम हैं । 2004 में होने वाले प्रमुख अभ्यास हैं, 15-13 जुलाई, 2004 तक अलास्का में को-ऑपरेटिव कोप थंडर (वायु सेनाओं के बीच), 12-31 जुलाई, 2004 तक हवाई के युद्ध अभ्यास, 5-15 सितम्बर, 2004 तक लेह में बैलेंस इरोक्विस अभ्यास/बज्र प्रहार अभ्यास (सेनाओं के बीच), 5-10 अक्टूबर, 2004 तक मालाबार अभ्यास और 6-24 अक्टूबर तक फ्लैश इरोक्विस अभ्यास (नौसेनाओं के बीच) ।

16 नवम्बर, 2004 को अमरीकी रक्षा विभाग ने अमरीकी कांग्रेस को पाकिस्तान को बेचे जाने वाले सैनिक उपकरणों के प्रस्ताव की अधिसूचना अमरीकी कांग्रेस को दी जिसमें निम्नलिखित शामिल थे : आठ पी- 3 सी ओरियन समुद्री निगरानी विमान, छह फलांक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम और 2000 टी ओ उब्ल्यू-2 ए फ्लाय टू बाय प्रक्षेपास्त्र (मूल्य 1.2 बिलियन अमरीकी डालर) । पाकिस्तान को दिये गये हथियारों के पैकेज के संबंध में भारत की गहरी चिंता से अमरीकी सरकार को उच्च-स्तर पर अवगत कराया गया । यह भी बताया गया कि जारी भारत-पाकिस्तान वार्ता, जो एक नाजुक मोड़ पर है, पर पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं । साथ ही कहा गया कि ऐसे समय में जब भारत-अमरीका संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं, और भारत में अमरीका को एक सामरिक भागीदार के रूप में देखा जाता है, इस कदम से भारत में अमरीका के प्रति सकारात्मक भावना और सद्भावना पर दुष्प्रभाव पड़ेगा । अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अमरीका भारत के साथ अपने संबंधों को महत्वपूर्ण मानता है और राष्ट्रपति बुश इसे आगे बढ़ाने के लिए निजी तौर पर प्रतिबद्ध हैं । जहाँ तक भारत-पाकिस्तान संबंधों का प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ अमरीका का शस्त्रों की आपूर्ति का संबंध है परन्तु यह भारत-पाकिस्तान वार्ता का पक्षधर है । वह सीमा-पार आतंकवाद से जुड़ी बातों पर भी नजर रखेगा ।

जनवरी 2000 में स्थापित आतंकवाद का मुकाबला से संबद्ध संयुक्त कार्यदल एक-दूसरे की चिंताओं को और समझने के लिए एक उपयोगी तंत्र है । 31 अगस्त - 1 सितम्बर, 2004 तक नई दिल्ली में आयोजित जे डब्ल्यू जी सी टी की छठी बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की वर्तमान प्रवृत्तियों और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की गयी

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश के साथ, न्यूयार्क, 21 सितम्बर 2004।

NYSE
New York Stock Exchange
New York
Stock Exchange

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में भाषण देते हुए, 22 सितम्बर 2004।

। दोनों पक्षों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में विधि प्रवर्त्तन, विधायी, वित्तीय और अन्य उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान किया (त्त) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की (त्त्त) आतंकवाद का मुकाबला करने के बहु-पक्षीय प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया ।

अमरीका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और अमरीका के भागीदारों की सूची में हमारा स्थान 18वां है । कैलेण्डर वर्ष 2004 के प्रथम नौ महीनों में तिजारती माल और पण्यों का कुल व्यापार 15.91 बिलियन अमरीकी डालर (पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.56 बिलियन अमरीकी डालरों से 17 प्रतिशत अधिक) । इस अवधि के दौरान अमरीका को हमारे निर्यात में 26 प्रतिशत (9.95 बिलियन से 11.54 बिलियन अमरीकी डालर) की वृद्धि हुई । अमरीका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का हमारा सबसे बड़ा स्रोत है जिसका योगदान जनवरी 1991 और मार्च 2004 के बीच अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 21 प्रतिशत है । अमरीका को सेवाओं का हमारा निर्यात प्रति वर्ष 6 बिलियन अमरीकी डालरों से अधिक का है । दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए तीन उपाय किये गये-सामरिक भागीदारी में अगला कदम, उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग दल और उच्च-स्तरीय आर्थिक वार्ता ।

सामरिक भागीदारी में अगले कदम से चार क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाये जाने के लिए राजनैतिक दिशा मिली - नागरिक अंतरिक्ष, नागरिक नाभिकीय ऊर्जा, दोहरे उपयोग की मदें और मिसाइल रक्षा । सहयोग के ये क्षेत्र अनेक आपसी कदमों से आगे बढ़ेंगे । जनवरी, 2004 से दोनों सराकरों ने एन एस एस पी के प्रथम चरण को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य किया है । इसमें शामिल हैं प्रसार चिंताओं के समाधान और निर्यात नियंत्रण का सुनिश्चय । इन उपायों से अमरीका निर्यात लाइसिंग नीतियों में संशोधन करने में सक्षम हो पाया जससे व्यवसायिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और सुरक्षित नाभिकीय संयंत्रों के विद्युत संयत्रों में कतिपय निर्यात हो सकेगा । इसरो मुख्यालय को वाणिज्य मंत्रालय की इकाइयों की सूची से हटा दिया गया । एन एस एस पी के प्रथम चरण का पूरा किये जाने की घोषणा विदेश सचिव की अमरीका की यात्रा के दौरान 17 सितम्बर, 2004 को दिये गये एक संयुक्त वक्तव्य में की गयी । तदनुरूप दो बैठकें-पहली नई दिल्ली में 28 अक्टूबर को और इसरी 18 नवम्बर को वाशिंगटन में की गयीं जिसमें अगले चरण में जाने के मार्गों का अन्वेषण किया गया ।

भारत और अमरीका के बीच उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह की बैठकें जारी रहीं जिनकी अध्यक्षता विदेश सचिव और अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने की । यह समूह दोहरे उपयोग की मदों के व्यापार को बढ़ाने के तरीकों का अन्वेषण करता है और रक्षा, नई प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर जोर देता है । एच टी सी जी की तीसरी बैठक 18-19 नवम्बर, 2004 तक वाशिंगटन में हुई जिसमें डेटा प्रायवेसी और रक्षा प्रौद्योगिकी उद्योग-सरकार सत्र में मुख्य विषय-वस्तु थी जबकि सरकार-सरकार सत्र में सामरिक व्यापार और व्यापार सहजता महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे । एच टी सी जी की स्थापना के बाद से दोहरे उपयोग की वस्तुओं के अनुमोदित उपयोग सहित भारत और अमरीका के बीच उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है । भारत के लिए अमरीकी दोहरे उपयोग के लाइसेंसों की संख्या वित्तीय वर्ष 2002 में 423 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2003 में 619 और वित्तीय वर्ष 2004 में 912 हो गयी । लागत की दृष्टि से भी यह व्यापार वित्तीय वर्ष 2002 में 28.78 मिलियन से बढ़कर 2004 में 90.06 मिलियन अमरीकी डालर हो गया । लाइसेंस अनुमोदन दर दो वर्षों की अवधि में बढ़कर 84 प्रतिशत से 90 प्रतिशत हो गया ।

नवम्बर 2001 में अमरीकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री के बीच हुई सहमति के फलस्वरूप भारत-अमरीका आर्थिक वार्ता का गठन किया गया । 2004 में दोनों सरकारें योजना आयोग के उपाध्यक्ष को सह-अध्यक्ष मनोनीत करने और विदेश सचिव को उनका डेपुटी तथा दूसरे पक्ष से अमरीकी राष्ट्रपति के आर्थिक नीति सहायक को सह-अध्यक्ष और आर्थिक, वाणिज्यिक और कृषि मामलों के अंडर सेक्रेटरी को उनका डेपुटी मनोनीत किया । इसे बातचीत से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इसे केन्द्रित और प्रभावी बनाया जा सके । भारत-अमरीकी साइबर सुरक्षा मंच की दूसरी बैठक 8-10 नवम्बर 2004 तक वाशिंगटन में हुई । पूर्ण एवं कार्यकारी समूह के सत्रों के परिणामस्वरूप अच्छी कार्ययोजना बनी ।

कनाडा

दिसम्बर 2003 में प्रधान मंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री पाउल मार्टिन ने भारत के साथ राजनैतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने की कनाडा की वचनबद्धता को दोहराया । भारत और कनाडा दोनों में 2004 में आम चुनाव हुए और पूरे वर्ष कनाडा ने विदेश नीति समीक्षा का कार्य जारी रखा । कनाडा के आम चुनाव में हाउस ऑफ कॉमंस में रेकार्ड संख्या में भारतीय मूल के लोक निर्वाचित हुए । इनमें शामिल थे : उज्जल दोसांज, गुरबक्श सिंह मल्ही, रूबी धल्ला, नवदीप सिंह बेंस (सभी लिबरल पार्टी से), और गुरमत ग्रेवाल एवं नीना ग्रेवाल, दीपक ओभराई और रहीम जफर (कंजरवेटिव पार्टी से) । उज्जल दोसांज 39 सदस्यीय पाउल मार्टिन मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और उनके पास महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग है । अनेक भारतीय-कनाडियाई प्रांतीय संसदों के लिए भी चुने गये ।

जून, 2004 में कनाडा में हुए आम चुनावों के पश्चात प्रधान मंत्री पाउल मार्टिन ने हमारे प्रधान मंत्री के लिए शुभकामना संदेश लेकर कनाडा के कैबिनेट मंत्री हर्ष धारीवाल को भारत में विशेष प्रतिनिधि के रूप में भेजा । श्री धारीवाल को प्रधान मंत्री के दूत के रूप में चुना जाना कनाडा के राजनैतिक जीवन में भारतीय-कनाडियन समुदाय की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है ।

आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध छठे भारत-कनाडियाई संयुक्त कार्यदल की बैठक 13 मई, 2004 को ओटावा में हुई । बैठक में सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मसलों पर सहयोग आगे बढ़ाने और सुव्यवस्थित करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की गयी । इससे इस क्षेत्र में एक-दूसरे की चिंताओं और क्षमताओं को समझने का अवसर मिला । व्यापक चर्चाएं हुईं । दोनों पक्षों ने इस दल को अत्यंत उपयोगी और सहयोग के एक क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जो उत्तरोत्तर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रासंगिक होता जा रहा है । अभी भारत और कनाडा के दृष्टिकोण में समानता है कि आतंकवाद की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है ।

भारत और कनाडा इस वर्ष सक्रिय रूप से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संवर्द्धन में लगे रहे । 1 जनवरी 2004 से 31 अगस्त, 2004 तक कनाडा को भारतीय निर्यात 1035 मिलियन कनाडियन डालरों का हुआ और कनाडा से निर्यात 510 मिलियन अमरीकी डालरों का हुआ । भारत-कनाडा द्विपक्षीय व्यापार 1997-98 में 848.73 मिलियन अमरीकी डालरों से 2003-2004 में 1350.47 मिलियन अमरीकी डालरों तक पहुंच गया अर्थात पांच वर्षों की अवधि में 59.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस अवधि के दौरान हमारा निर्यात 77 प्रतिशत तक और आयात 40 प्रतिशत तक बढ़ गया । पिछले 5 वर्षों से व्यापार संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में रहा है । कनाडा को किये जाने वाले मुख्य भारतीय निर्यात हैं कपड़े और वस्त्र, रत्न और आभूषण, कार्बनिक रासायन, लौह एवं इस्पात, कॉफी, चाय और अन्य खाद्य उत्पाद । कनाडा से किये जाने वाले मुख्य निर्यात हैं लकड़ी की लुगदी, न्यूजप्रिंट, टेल्कॉम और विद्युत उपकरण, विमानन से जुड़े उपकरण, उर्वरक और रासायन ।

कनाडा की अनेक कंपनियों ने भारत में साफ्टवेयर विकास और इलेक्ट्रानिक घटक सुविधाओं के साथ आई टी और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में भारत में अपनी मजबूत स्थिति बना ली है । उसी प्रकार वित्तीय सेवा क्षेत्र में पर्याप्त गतिविधियाँ हुई हैं जिसके तहत स्कौटिया बैंक और डुंडी बैंकोर्प नेटवर्कों, बिरला सन लाइफ संयुक्त उपक्रम, टी डी-वाटरहाउस और टाटा फाइनान्स एवं लोम्बार्ड-आई सी आई सी आई भागीदारी स्थापित हुई । भारतीय साफ्टवेयर कंपनियों द्वारा कनाडा में निवेश एक अन्य प्रवृत्ति है । इनमें शामिल हैं - इन्फोसिस, सत्यम, विप्रो एवं टाटा कंसल्टेंसी जिनके कार्यालय कनाडा में हैं । बिरला ने एक लुगदी कारखाना स्थापित कया है ।

अभी दोनों सरकारें द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन एवं संरक्षण करार पर बातचीत कर रही हैं । इस संबंध में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के एक शिष्टमंडल ने 27-29 सितम्बर, 2004 तक नई दिल्ली का दौरा किया । वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक चार-सदस्यीय शिष्टमंडल ने 26-29 अक्टूबर 2004 तक किम्बरले प्रक्रिया पूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए ओटावा का दौरा किया ।

क्यूबेक सरकार के एक 19 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 1-2 नवम्बर, 2004 तक नई दिल्ली का और 4-5 नवम्बर, 2004 तक मुम्बई का दौरा कया । इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय कंपनियों के साथ वाणिज्यिक बातचीत करना और वर्ष 2006 के आरंभ में क्यूबेक के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के लिए शुरूआती कार्य करना था । मानितोबा प्रांतीय सरकार के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य विकास प्रभाग के दो-सदस्यीय सरकारी शिष्टमंडल ने भारत में वाणिज्य परिसंघों

के साथ चर्चा करने के लिए 15-19 नवम्बर, 2004 तक भारत का दौरा किया ।

वर्ष 2004 में कनाडा के किसी व्यक्ति को पहली बार पद्‌मश्री पुरस्कार दिया गया । यह पुरस्कार भूतपूर्व संसद सदस्य, संघीय मंत्री एवं प्रमुख शिक्षाविद तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता माननीय फ्लोरा मैकडोनाल्ड को दिया गया । 30 जून, 2004 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में श्री फ्लोरा मैकडोनाल्ड को "पद्‌मश्री" प्रदान किया गया ।

ओटावा के मुख्य सामुदायिक संगठन भारत-कनाडा एसोसिएशन और संसद सदस्य श्री दीपक ओभराई ने 16 नवम्बर 2004 को ओटावा के संसद में छठा वार्षिक दीपावली समारोह संयुक्त रूप से मनाया । प्रधान मंत्री पाउल मार्टिन ने समारोह में भाग लिया और कनाडा के विकास तथा इसे सच्चे अर्थों में बहु-सांस्कृतिक समाज बनाने में भारतीय-कनाडियाइयों के योगदान का उल्लेख किया । इसके अतिरिक्त संसद में अनेक विपक्षी दलों के नेताओं और बड़ी संख्या में सांसदों और सीनेटरों ने दीपावली समारोह में भाग लिया ।

तीन वर्षों के अंतराल के पश्चात विदेश कार्यालय परामर्श सचिव (पश्चिम) और कनाडा के उप-विदेश मंत्री श्री पीटर हारडर के बीच 16-17 दिसम्बर, 2004 को किये जाएंगे । अंतिम परामर्श अप्रैल 2001 में हुए थे ।

कनाडा के प्रधानमंत्री 18 जनवरी, 2005 को भारत आने वाले हैं । आशा की जाती है कि वर्ष 2005 में दोनों देशों के बीच क्रियाकलाप को और बढ़ाया जाएगा ।

लातिन अमरीका और कैरीबिया

वर्ष 2004 में लातिन अमरीकी क्षेत्र के साथ भारत सरकार के संबंध और सुदृढ़ हुए । इस क्षेत्र में हमारी नीति की मुख्य विषय-वस्तु विद्यमान संबंध को संवर्द्धित करना, राजनैतिक वार्ता और सहयोग के लिए एक तंत्र बनाना तथा व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देना है । क्षेत्रीय समूहों के साथ संरचना करार किये गये हैं । ये हैंः मरकोसर समूह के देशों के साथ, कैन (अनदियन समुदाय) के साथ राजनैतिक वार्ता और सहयोग कैरिकॉम के साथ परामर्श, सहयोग और समन्वय पर एक स्थायी संयुक्त आयोग, मध्य अमरीकी देशों के समूह (सीका) के साथ राजनैतिक परामर्श तंत्र ।

अर्जेन्टिना

अनेक सरकारी दौरों और व्यापार शिष्टमंडलों की यात्राओं से भारत के साथ अर्जेन्टिना के सौहार्दपूर्ण संबंधों का पता चलता है । सितम्बर/अक्टूबर 2004 में आयोजित नमस्ते-कोनोसिएन्डो ला इन्डिया नामक महोत्व आयोजित किया गया जिसमें एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी, फीचर फिल्म, "भारतीय महिलाओं" पर फैशन शो, शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रम, गायन, भारतीय लोक गीत/सामयिक नृत्य और थियेटर प्रस्तुतियाँ शामिल की गयीं । प्रतिष्ठित सान मार्टिन थिएटर में अप्रैल 2004 में एक भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया ।

ब्राजील

जनवरी 2004 में राष्ट्रपति लूला की भारत यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को मिली गति इस वर्ष भी जारी रही । वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने जून, 2004 में ब्राजील का दौरा किया और वे ब्राजील के विदेश मंत्री सेल्सो एमोरिम, विदेश व्यापार मंत्री लुइज फर्नान्डो फुरलान से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की । प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 21 सितम्बर, 2004 को संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से मुलाकात की । भारत और ब्राजील के बीच व्यापार वर्ष 2003 से अधिक के स्तर पर हो जाने की संभावना है । अक्टूबर, 2004 में भारत और ब्राजील के बीच हवाई सेवा करार संपन्न किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

कोलंबिया

द्विपक्षीय यात्राएं हमारे घनिष्ट संबंधों की विशेषता रही । द्विपक्षीय संबंधों के लिए कोलंबिया के उप मंत्री श्री केमिलो रयेस ने विदेश कार्यालय परामर्शों के लिए मई 2004 में नई दिल्ली का दौरा किया । सितम्बर, 2004 में विदेश राज्य मंत्री श्री राव वीरेन्द्र सिंह ने कोलंबिया का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों की समीक्षा की । राष्ट्रपति अल्वारो यूरिब ने राष्ट्रपति जी को कोलंबिया यात्रा का निमंत्रण दिया जिसे सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है । भारत से कोलंबिया को हुआ निर्यात 41.8 प्रतिशत बढ़कर 102.6 मिलियन अमरीकी डालरों का हो गया । भारतीय वस्त्र प्रदर्शनी आयोजित की गयी और चेमोक्सिल शिष्टमंडल ने कोलंबिया का दौरा किया । भारतीय

कंपनी को 32 मिलियन अमरीकी डालरों के मूल्य के इंधन इथनोल के निर्माण के लिए संयंत्र और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति का ठेका मिला ।

क्यूबा

भारत-क्यूबा संबंध घनिष्ट और मैत्रीपूर्ण रहे । भारत से गैर-पारंपरिक ऊर्जा, बायोमास, पवन ऊर्जा उत्पादन, चीनी से सहः उत्पादन, लघु पन-बिजली उत्पादन एवं सौर ऊर्जा पर अनेक भारतीय वैज्ञानिक शिष्टमंडलों की यात्राओं से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला । वर्ष 2004-2005 के लिए अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रोतोकोल संपन्न किया गया । ओ एन जी सी विदेश लि0 ने मैक्सिको खाड़ी के क्यूबाई ई ई जेड क्षेत्र में भूगर्भीय एवं भूंकप आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए मार्च 2004 में क्यूबा का दौरा किया ।

क्यूबा के विदेश उप-मंत्री श्री मेनुअल एगुलेरा ने जेनेवा में होने वाले मानवाधिकार सम्मेलन से जुड़े मसलों पर चर्चा करने के लिए मार्च 2004 में दिल्ली का दौरा किया । वर्ष 2004-05 में आइटेक के अंतर्गत सभी तीस स्थानों का उपयोग किया गया । सेना खेल संस्थान ने भारतीय बाक्सिंग परिसंघ के कोचों के अतिरिक्त मुक्केबाजों, भारोत्तोलको और गोताखोरों के प्रशिक्षण के लिए क्यूबा के कोचों की भर्ती की है । विदेश उप मंत्री श्री जोस मेनचेरो ने दिसम्बर 2004 में दिल्ली का दौरा किया और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की ।

डोमिनिकन रिपब्लिक

विदेश राज्य मंत्री श्री इन्द्रजीत सिंह ने सितम्बर, 2004 में डोमिनिकन रिपब्लिक का दौरा किया और राष्ट्रपति फर्नान्डेज, उप-राष्ट्रपति राफेल अलबूकर और विदेश मंत्री कार्लोस ट्रोंकोसी मोराल्स से मुलाकात की । डी आर सरकार ने राजनयिक रिश्तों को आगे बढाते हुए नई दिल्ली में दूतावास खोलने की अपनी ईच्छा जतायी । इसने व्यापार बढ़ाने तथा आई टी, भेषज, अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया और बहुपक्षीय मंचों पर भारत के साथ मिलकर कार्य करने का प्रस्ताव किया ।

इक्वाडोर

इक्वाडोर ने नई दिल्ली में पुनः अपना आवास खोलने पर सहमति व्यक्त की और भारत से पेट्रोलियम उद्योग और भेषज उत्पादों में भारतीय विशेषज्ञता के लिए उत्सुकता दिखायी है । गुआयाक्विल में वस्त्र प्रदर्शनी आयोजित की गयी । दिसम्बर, 2004 तक इक्वाडोर के तीन राष्ट्रिकों ने भारत में आइटेक प्रशिक्षण प्राप्त किया । भारत ने क्विटो को इबेरोअमेरिकन राजधानी घोषित किये जाने के अवसर पर आयोजित समारोहों में आनन्द शंकर जयन्त के नेतृत्व में एक भरतनाट्टयम बैले मंडली के साथ भाग लिया जिसने अक्टूबर, 2004 में क्विटो के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

मैक्सिको

हमारे संबंध विकसित और संवर्द्धित होते रहे । मैक्सिको के विदेश मंत्री डा0 लुई अर्नेस्टो डेरबेज ने जून 2004 में वाशिंगटन में विदेश मंत्री के साथ बैठक की । अगस्त, 2004 में उनके साथ एक शिष्टमंडल भारत आया जिसने विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री और अन्य के साथ मिलकर द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के संबंध मं चर्चा की । अर्थव्यवस्था उप-मंत्री सुश्री मारिया डेल रोसियो रूइज चावेज ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग के मार्गों का पता लगाने के लिए अगस्त, 2004 में नई दिल्ली, बंगलौर और हैदराबाद का दौरा किया । अक्टूबर 2004 में भारतीय चुनाव आयोग के एक शिष्टमंडल ने मैक्सिको का दौरा किया जिसके दौरान सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया । मैक्सिकन कांग्रेस के परिसर में मैक्सिकन चैम्बर ऑफ डेपुटीज (निचला सदन) में भारत-मैक्सिको मैत्री समूह का उद्घाटन बैठक नवम्बर, 2004 में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया । सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध संवर्द्धित होते रहे।

वर्ष 2004 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में उत्साहवर्धक विकास जारी रहा । मैक्सिको को भारतीय निर्यात 2003 के 397.75 मिलियन अमरीकी डालरों की तुलना में सितम्बर, 2004 तक 609.4 मिलियन अमरीकी डालरों तक पहुंच गया अर्थात 53.2 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । उसी प्रकार मैक्सिको से भारत के निर्यात में इसी अवधि के दौरान 324.3 मिलियन अमरीकी डालरों से 365.7 मिलियन अमरीकी डालर तक की वृद्धि हुई । इस प्रकार 2004 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 1बिलियन अमरीकी डालरों के आंकड़ों को पार करके 1.2 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाने की आशा है जो इस क्षेत्र किसी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार का सबसे बड़ा आंकड़ा है । अनेक व्यापार संवर्द्धन

उपाय किये गये जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, क्षमताओं एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता और मैक्सिको से यात्राओं की व्यवस्था करना।

उरूग्वे

उरूग्वे के विदेश मंत्री ने सितम्बर, 2004 में भारत का दौरा किया और विदेश कार्यालय परामर्शों में भाग लिया । उन्होंने रिलायंस, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऑफ इन्डिया, नास्कोम बायोटेक तथा आई-फ्लेक्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात की ।

वेनेजुएला

मई 2004 में वेनेजुएला में विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित हुए । वेनेजुएला के विदेश मंत्री श्री जेसस अर्नाल्डो पेरेज ने सितम्बर, 2004 में भारत का राजकीय दौरा किया और विदेश, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पर्यावरण एवं वन मंत्रियों तथा शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन राज्य मंत्री के साथ चर्चाएं कीं । वेनेजुएला के ऊर्जा और खनन मंत्री राफेल दारियो रमिरेज ने सितम्बर में अपने भारतीय समकक्ष से मुलाकात की । अंतरिक्ष अनुसंधान और सहयोग, आई टी सहयोग के अन्य क्षेत्र हैं ।

मध्य अमरीका (सीका)

वर्ष 2004 के दौरान मध्य अमरीका के सात देशों यथा कोस्टारिका, बेलिज, अल-सल्वोडार, ग्वाटेमाला, होडुंरास, निकारागुआ तथा पनामा के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण संबंधों ने नये चरण में प्रवेश किया । वर्ष 2004 में सीका विदेश मंत्रियों की भारत यात्रा के दौरान भारत और सीका राज्यों के सदस्यों के बीच राजनैतिक सहयोग के लिए तंत्र की स्थापना हेतु एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । विदेश राज्य मंत्री श्री राव इन्द्रजीत सिंह की सीका महासचिव डा0 ओस्कर सांतामारिया और उनकी टीम के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें सीमा सदस्य देशों के साथ बहु-फलकीय सहयोग विकसित करने की भारत की रूचि को दोहराया गया । सीका महासचिव, जो पहले भी भारत आये थे, ने आई टी, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, अवसंरचना परियोजनाएं, पर्यावरण मसले, पर्यटन इत्यादि सहित अन्य मसलों पर भारत के साथ सहयोग का वादा किया और भारत तथा सीका के बीच नियमित संपर्कों का प्रस्ताव किया । इससे द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दृष्टि से भारत के संबंधों को गति मिलेगी ।

ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और पनामा में इस अवधि के दौरान कार्य ग्रहण करने वाली नयी सरकारों ने भारत के साथ संबंध बढ़ाने में अपनी रूचि दिखायी है, विशेषकर मानव संसाधन विकास में भारतीय अनुभवों के संदर्भ में । इस क्षेत्र के साथ आर्थिक संबंध बढ़ते रहे और 2003-04 के दौरान 164.89 मिलियन अमरीकी डालरों का द्विपक्षीय व्यापार हुआ जो वर्ष 2002-03 के 149 मिलियन अमरीकी डालरों से 12 प्रतिशत अधिक है । भारतीय वाणिज्य और उद्योग इंजीनियरिंग सामानों, ऑटोमोबाइल पुर्जों, रासायनों, भेषजों और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नये क्षेत्रों में बढ़ रहा है । वीजा आवेदनों की संख्या से यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । आइटेक के अंतर्गत प्रशिक्षण में सहयोग और आगे बढ़ा।

पनामा

विदेश राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने राष्ट्रपति मार्टिन टोरिजोस की नई सरकार के सपथ ग्रहण समारोह में सितम्बर, 2004 में भाग लिया और राष्ट्रपति की ओर से मैत्री संदेश सौपा । उन्होंने उप-राष्ट्रपति एवं विदेश मंत्री सैमुअल लेविस नवारो और उप मंत्री रिकार्डो डुरान के साथ मुलाकात की और आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने तथा वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर सहमति हुई । वर्ष 2003-04 में पनामा को भारतीय निर्यात बढ़कर 49.4 मिलियन अमरीकी डालर से 54.44 मिलियन अमरीकी डालर हो गया ।

अल सल्वाडोर

विदेश मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने अल-सल्वाडोर के विदेश मंत्री के निमंत्रण पर सितम्बर 2004 में अल सल्वाडोर का दौरा किया । उन्होंने उप-राष्ट्रपति अना विल्मा डी इस्कोबार और विदेश मंत्री फ्रांसिसको इस्तेबान लेनिज के साथ मुलाकात की और आई टी, भेषज, कृषि तथा इंजीनियरिंग सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी हित के मसलों पर चर्चा की । सल्वाडोर पक्ष ने भारतीय कंपनियों को निवेश का निमंत्रण दिया । हालांकि अल सल्वाडोर के साथ द्विपक्षीय व्यापार सीमित है परन्तु इसमें 2002-03 में 4.9 मिलियन अमरीकी डालरों से 2003-04 में 7.64 अमरीकी डालरों की वृद्धि हुई ।

ग्वाटेमाला

ग्वाटेमाला के साथ व्यापार में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2002-03 में 20.54 मिलियन अमरीकी डालरों से बढ़कर 2003-04 में 26.36 मिलियन अमरीकी डालर हो

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, कनाडा के प्रधान मंत्री श्री पॉल मार्टिन की भारत यात्रा के दौरान मुलाकात करते हुए, 17-18 जनवरी 2005।

विदेश मंत्री श्री कुं नटवर सिंह ने चिल्ली के राष्ट्रपति डॉ. रिकार्डो लागोस की भारत की यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की, 18-22 जनवरी 2005।

गया । व्यापार की मदें थी आटोमोबाइल और ऑटो कल-पुर्जे तथा भेषज । ग्वाटेमाला-भारत वाणिज्य परिसंघ की स्थापना की गयी ।

कैरिकॉम

भारत ने कैरिकॉम के साथ नियमित राजनैतिक वार्ता किये जाने के लिए एक संस्थागत संपर्क का प्रस्ताव किया जिसके फलस्वरूप परामर्श, सहयोग और समन्वय पर कैरिकॉम-भारत संयुक्त आयोग का गठन हो सका । इसके प्रथम कार्यों से एक है सूचना प्रौद्योगिकी सहित अनेक क्षेत्रों में कैरिकॉम-भारत तकनीकी सहयोग कार्यक्रम का गठन ।

गुयाना

29 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र के 59वें महाधिवेशन को संबोधित करते हुए गुयाना के विदेश मंत्री रूडी इन्सानली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन किया । भारत गुयाना में एक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के प्रति वचनबद्ध है और नवम्बर में गुयाना के राष्ट्रपति भारत जगदेव की उपस्थिति में दो वित्तीय करार संपन्न किये गये । पहला 6 मिलियन अमरीकी डालरों के भारत सरकार के अनुदान से संबंधित था और दूसरा एक्जिम बैंक की 19 मिलियन अमरीकी डालरों की रियायती ऋण श्रृंखला के संबंध में थी ।

इस वर्ष आइटेक कार्यक्रम के अंतर्गत गुयाना के 25 मनोनीत व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया । अभी गुयाना में 7 भारतीय आइटेक विशेषज्ञ हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं । न्यू गुयाना फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन और भारत के सिपला ने सयहोग की सहमति व्यक्त की है जिसके अंतर्गत एन जी पी सी को कच्चा माल, बल्क फोर्मुलेशंस, निर्मित उत्पाद और तकनीकी विशेषज्ञता सिपला द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और इसमें एंटी-रेट्रोवायरल शामिल होगा जिसका उत्पाद एन जी पी सी ने राज्य द्वारा वित्त-प्रदत्त एच आई वी/एड्स उपचार कार्यक्रम के लिए करना आरंभ किया है । भारत ने गुयाना को 16 मिलियन गुनाया डालरों की कृषि-प्रसंस्करण गाड़ियाँ दी ।

हैती

भारत ने सितम्बर, 2004 में हैती में आये हरीकेन जीन के पीड़ितों के लिए दवाएं खरीदे जाने हेतु 10,000 अमरीकी डालरों का उपहार दिया । वाणिज्य शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया और व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ाने के मार्गों का अन्वेषण किया ।

जमैका

भारत और जमैका के संबंध घनिष्ट और मैत्रीपूर्ण रहे । भारत ने तुफान से हुई तबाही के आलोक में जमैका को 200,000 अमरीकी डालरों के मूल्य की राहत सामग्री भेजी । भारत ने जलापूर्ति और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भारत से सेंट्रीफूगल पंप आपूरित किये जाने के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालरों की ऋण श्रृंखला दी । लघु उद्योगों के लिए मशीन और उपकरण और डेयरी तथा इंजीरियरिंग फाउन्ड्री के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 2 मिलियन अमरीकी डालरों की एक अन्य ऋण श्रृंखला दी । कैरीबियाई समुदाय और साझे बाजार के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में जमैका ने भारत-कैरिकॉम वार्ता तंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी ।

दी बहामास (सह-प्रत्यायन)

जुलाई 2004 में दी बहामास के लिए सह-प्रत्यायन वाशिंगटन डी सी के हमारे मिशन से किंग्सटन मिशन को स्थानांतरित कर दिया गया । भारत ने तूफान से हुई तबाही के बाद बहामास को राहत आपूर्ति दी ।

सूरीनाम

भारत और सूरीनाम के बीच संबंध संवर्द्धित होते रहे । भारत ने 161 के बी बिजली प्रसारण लाइन के निर्माण के लिए सूरीनाम को 16 मिलियन अमरीकी डालरों की एक रियायती ऋण श्रृंखला दी जिसका निष्पादन भारतीय कंपनियों मैसर्स पी ई सी और एल एण्ड टी द्वारा किया जाएगा । सूरीनाम की विदेश मंत्री सुश्री मारिया इ0 लीवेंस ने भारत-सूरीनाम संयुक्त आयोग में भाग लेने के लिए नवम्बर में भारत का दौरा किया । भारत कृषि, वन, ऊर्जा, रक्षा और आई टी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति किये जाने के लिए नई ऋण श्रृंखला उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ ।

त्रिनिडाड एण्ड टोबैगो

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत और त्रिनिडाड एण्ड टोबैगो के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे । आर्थिक और वाणिज्यिक संपर्कों को बढ़ाने पर बल दिया गया । भारतीय माल और सेवाओं के निर्यात को वित्त-पोषित करने के लिए जून 2004 में 8 मिलियन अमरीकी डालरों की ऋण श्रृंखला

आरंभ की गयी । द्विपक्षीय व्यापार में प्रति वर्ष 30 प्रतिशत की दर से वृद्धि होती रही । त्रिनिडाड एण्ड टोबैगो डायस्पोरा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण देश है । डायस्पोरा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन और हिंदी कक्षाएं आयोजित की गयीं । त्रिनिडाड एण्ड टोबैगो के राष्ट्रपति प्रो0 जार्ज मैक्सवेल रिचड्स ने नवम्बर 2004 में भारत की निजी यात्रा की और राष्ट्रपति से मुलाकात की ।

■■

9

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन

महासचिव द्वारा "संयुक्त राष्ट्र के लिए अवसरों और कठिनायों का वर्ष " के रूप में वर्णित इस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने संमर्थन और संसाधनों के अभाव के बावजूद अनेक कठिन कार्य सम्पादित किये । हालांकि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और प्रासंगिकता की जांच चलती रही, यह वर्ष महासचिव के उच्च-स्तरीय पैनल द्वारा नई सदी में सामुहिक सुरक्षा के लिए व्यापार रूपरेखा का प्रस्ताव करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ समाप्त हुआ । संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान, कोट डी आइवरी, हैती, कोसोवो, लाइबेरिया, सूडान, तिमोर लेस्ते और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सहित विश्व के विभिन्न भागों में चुनौतीपूर्ण शांति-रक्षा और शांति-निर्माण मिशनों में शामिल रहा ।

संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों, स्वास्थ्य, महिला और बाल, जनंसख्या, सतत् विकास, विकास के वित्त-पोषण, मानवीय गतिविधियाँ और विकास से जुड़े अन्य क्षेत्रों में अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं । भारत ने संयुक्त राष्ट्र में होने वाली चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा और विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देते हुए महत्वपूर्ण विवादास्पद मसलों पर सर्वसम्मति लाने में समर्थ हुआ । भारत को 2005-07 की अवधि के लिए एशियाई गुट से सर्वाधिक मतों से आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया ।

महासभा का 59वां सत्र

महासचिव द्वारा गठित खतरों, चुनौतियों और परिवर्तनों से संबद्ध उच्च-स्तरीय पैनल की रिपोर्ट दिसम्बर, 2004 मे प्रकाशित होने से पूर्व 50वें सत्र का आयोजन किया गया था । राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर 'विधिसम्मत शासन' को मजबूत बनाने पर ही महासचिव ने आम बहस में आधे से अधिक समय लगा दिया । 59वें सत्र ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर निरंतर बल दिया, काहिरा में जनसंख्या और विकास पर 1994 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की 10 वर्षीय समीक्षा समारोह आयोजित की और सहस्त्राब्दि घोषणा के क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा के लिए 2005 में उच्च-स्तरीय पूर्ण बैठक के तौर-तरीकों, फारमेट और आयोजन पर महासचिव की रिपोर्ट पर आधारित निर्णयों और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों को स्वीकार किया ।

प्रधान मंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने 59वें सत्र में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और महासभा में अपने संबोधन में उन्होंने बहुवाद के प्रति भारत की वचनबद्धता की पुष्टि की। प्रधान मंत्री ने स्थायी एवं अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद की सदस्यता का विस्तार करके संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सही मायनों में एक प्रातिनिधिक इकाई बन सके । प्रधान मंत्री ने विश्व समुदाय में अपने कद और भूमिका के अनुरूप कोई भी जिम्मेदारी उठाने की भारत की इच्छा भी व्यक्त की । उन्होंने आतंकवाद तथा व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार से उत्पन्न चुनौतियों को भी रेखांकित किया । प्रधान मंत्री ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और अमरीका के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षाओं की बैठक में भी भाग लिया । प्रधानमंत्री की संयुक्त राष्ट्र कार्यसूची के मसलों पर चर्चा की गयी ।

विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह संयुक्त राष्ट्र के 59वें सत्र के लिए प्रधानमंत्री के साथ गये । विदेश मंत्री ने रूसी परिसंघ, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, थाइलैंड, चीन और बंगलादेश के अपने समकक्षों के साथ बैठकें की । उन्होंने अरब लीग के महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष परामर्शदाता से भी मुलाकात की । विदेश मंत्री ने समूह चार (भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान) के मंत्रियों के साथ और भारत-खाड़ी सहयोग परिषद तथा आई बी एस ए (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) के साथ विचार विमर्श किया । उन्होंने खतरों, चुनौतियों और परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उच्च-स्तरीय पैनल के सदस्यों के साथ भी मुलाकात की ।

विदेश राज्य मंत्री श्री ई अहमद ने महासभा में "सुरक्षा परिषद की सदस्यता बढ़ाने और इससे जुड़े मसलों में न्यायोचित प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर रिपोर्ट " और "आर्थिक, सामाजिक और संबंधित क्षेत्रों में प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों के परिणामों का एकीकृत और समन्वित क्रियान्वयनः जनसंख्या और विकास से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की दसवीं वर्षगांठ " जैसे दो मदों पर महासभा में वक्तव्य दिया । राव इन्द्रजीत सिंह ने "अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी " की रिपोर्ट पर महासभा में भाषण दिया ।

भारत ने 59वें सत्र में आम बहस की शुरूआत की पूर्व संध्या पर दो विशेष कार्यक्रमों में भाग लिया । पहला कार्यक्रम था

तंजानियाँ और फिनलैंड के राष्ट्रपतियों की सहः अध्यक्षता में वैश्वीकरण के सामाजिक आयामों पर विश्व आयोग की रिपोर्ट को 20 सितम्बर को औपचारिक रूप से आरंभ करना । प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह के संदेश का पाठ इस अवसर पर पढ़ा गया । 20 सितम्बर को ब्राजील के राष्ट्रपति के पहल पर भूख और गरीबी उपशमन पर एक बैठक थी जिसमें ब्राजील, चिलि, फ्रांस और स्पेन ने भाग लिया ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता

इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी को अनेक देशों से समर्थन मिला । तीन प्रमुख आकांक्षियो-ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ भारत की आपसी सहमति हुई । जनवरी माह में ब्राजील के राष्ट्रपति की, जुलाई में जर्मनी के विदेश मंत्री और अगस्त में जापान के विदेश मंत्री की भारत यात्राओं के दौरान इस वर्ष यह घोषणा की गयी । उल्लेखनीय है कि ये आकांक्षी अब मिलकर कार्य करेंगे । ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान के नेताओं के बीच 59वें संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के अवसर पर न्यूयार्क में 21 सितम्बर, 2004 को यह दोहराया गया । इस समूह ने सुरक्षा परिषद के सुधार की आवश्यकता पर बल दिया ताकि इसे और प्रातिनिधिक, वैध और प्रभावी बनाया जा सके । उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के रूप में उन देशों को शामिल करना आवश्यक है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करने की अपनी जिम्मेदारियों को निभाने मे सक्षम है । वे इस बात पर भी सहमत हुए कि अफ्रीका को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए ।

संयुक्त राष्ट्र के 59वें महाधिवेशन की आम बहस के दौरान अपने भाषणों में अनेक नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संस्थागत सुधार की आवश्यकता, सुरक्षा परिषद के विस्तार, नये स्थायी सदस्यों को शामिल किये जाने और इस संबंध में भारत की पात्रता का उल्लेख किया ।

आगामी महीनों में संयुक्त राष्ट्र में इस मसले पर बहस गरमाने की आशा है । भारत इन चर्चाओं में भाग लेगा और इस बात पर ध्यान देगा कि किस प्रकार सर्वोत्तम तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुधार और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की उम्मीदवारी के उद्देश्य प्राप्त किये जाएं ।

महासभा और सुरक्षा परिषद में राजनैतिक मसले

सुरक्षा परिषद

वर्ष 2004-05 में भारत ने सुरक्षा परिषद की सार्वजनिक बैठकों में अफगानिस्तान मध्य पूर्व, तिमोर-लेस्ते, आतंकवाद और सामान्य देशों में व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार और संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा कार्रवाइयों, न्याय और विधिसम्मत शासन एवं महिलाओं तथा शांति और सुरक्षा जैसे विषयों पर अनेक वक्तव्य दिये ।

महा-सभा

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें पूर्ण सत्र में राजनैतिक और सामरिक महत्व के सभी मसलों पर वक्तव्य दिये जिनमें संगठन के कार्य, सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट, न्यायोचित प्रतिनिधित्व, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट, फिलीस्तीनी प्रश्न, मध्य पूर्व की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर इसका प्रभाव तथा युद्ध से तबाह हुए अफगानिस्तान में शांति, सामान्य स्थिति लाने और उसके पुनर्निर्माण के लिए आपात अंतर्राष्ट्रीय सहायता शामिल हैं ।

आतंकवाद

सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 (2001) के अनुसरण में गठित आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध सुरक्षा परिषद की समिति ने क्रियान्वयन की एक सक्रिय योजना का पालन किया जिसमें आतंकवादियों के वित्त-प्रवाह को रोकने के लिए उपयुक्त विधायी रूपरेखा और उपायों को जगह दी गयी थी । भारत ने अभी आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विधायी और अन्य उपायों का ब्यौरा देने वाले चार रिपोर्ट प्रस्तुत किये हैं । वर्ष 2004.05 में भारत ने सुरक्षा परिषद में तीन अवसरों पर "आतंकवादी कृत्यों से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा " विषय पर वक्तव्य भी दिये ।

26 मार्च, 2004 के प्रस्ताव 1535 स्वीकार किये जाने के साथ ही सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1373 के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए सी टी सी की क्षमता बढ़ाने के लिए तथा अपने कार्यों के लिए अपनी क्षमता निर्माण जारी रखने के लिए आतंकवाद-रोधी समिति कार्यकारी निदेशालय की स्थापना की । इसने सदस्य राज्यों के साथ अपनी बातचीत में अपनी सक्रिय भूमिका ग्रहण करने, प्रस्ताव 1373 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने, सदस्य राज्यों को तकनीकी सहायता देने तथा अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने की इच्छा भी परिलक्षित की ।

सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव 1566 (8 अक्टूबर, 2004) पारित किया जाना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आतंकवाद के सभी स्वरूपों में सभी आतंकवादी कृत्यों की भर्त्सना की गयी है और सदस्य देशों से आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय तथा नाभिकीय आतंकवाद के कृत्यों के दमन से संबद्ध अभिसमय के प्रारूपों को शीघ्र पारित किये जाने का भारत ने स्वागत किया जिसे हम आतंकवाद का मुकाबला किये

जाने पर विद्यमान बहुपक्षीय सहयोग और सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1267 (1999) और 1373 में प्रतिपादित आदर्शों का तार्किक विस्तार मानते हैं ।

शांतिरक्षा

अभी भारत संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियानों में सैनिकों का योगदान देने वाले सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है । अभी भारत जारी 16 संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियानों में 8 के लिए अपने सैनिकों का योगदान दे रहा है - कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन (मोनुक), लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (अनफिल), इथोपिया और इरीट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन (अनमी) और कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में एक विशाल नागरिक पुलिस घटक (अनमिक) । भारत ने बुरूंडी और कोट डी आइवरी में संयुक्त राष्ट्र मिशनों को सैन्य कार्मिक और सिएरा लियोन तथा साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में पुलिस अधिकारी भी उपलब्ध कराये हैं । भारत सूडान के आगामी संयुक्त राष्ट्र मिशन (अनमिसुद) को वायु सेना पुलिस की एक टुकड़ी सहित पैदल बटालियन, विशेष और समर्थकारी संसाधन भी उपलब्ध करायेगा ।

भारतीय अभी फील्ड और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में दो वरिष्ठ पदों पर हैं । जनरल रणधीर कुमार मेहता को 29 जनवरी, 2005 को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के शांतिरक्षा कार्रवाई विभाग में सैन्य परामर्शदाता जैसे प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया है ।

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा केन्द्र की स्थापना सितम्बर, 2000 में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से की गयी जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनिवार्यताओं और अनुसंधान को पूरा करना था । इस वर्ष इस केन्द्र ने अनेक शांतिरक्षा कार्यक्रम आयोजित किये । "एशिया पैसेफिक पीस आपरेशंस-लेसंस लर्न्ड" सेमिनार का सहःप्रायोजन 19-23 अप्रैल, 2004 तक सी यू एन पी के द्वारा आपदा राहत और मानवीय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केन्द्र के साथ किया गया । सेमिनार में 15 देशों से और भारत से 35 भागीदारों ने भाग लिया ।

सी यू एन पी के ने कनिष्ठ अधिकारियों और सैन्य पर्यवेक्षकों को संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा के लिए एकीकृत प्रशिक्षण देने के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कैप्सुलों का आयोजन किया । इन कैप्सुलों में कुल 26 विदेशी अधिकारियों और 57 भारतीय अधिकारियों ने भाग लिया । कुछ विकासशील देशों की भागीदारी का वित्त-पोषण भारत सरकार ने किया । 11-12 अक्टूबर, 2004 तक "फ्यूचर ऑफ पीस आपरेशंस-इम्प्लीकेशंस ऑफ इन्डिया" विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें 68 सैनिक एवं नागरिक कार्मिकों ने भाग लिया । जनवरी 2005 में आयोजित होने वाले यू एन लाजिस्टिक्स एण्ड स्टाफ ऑफिसर्स कैप्सुल में 15 विदेशी और 20 भारतीय अधिकारी भाग लेंगे ।

भारत शांतिरक्षा के संबंध में अमरीका और यू के के साथ द्विपक्षीय बातचीत कर रहा है । शांतिरक्षा से संबद्ध भारत-यू के संयुक्त कार्य दल की चौथी बैठक सी यू एन पी के, नई दिल्ली में 23-25 नवम्बर, 2004 तक हुई । इस बैठक में शांतिरक्षा की उदीयमान चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया तथा शांतिरक्षा के विभिन्न वैचारिक और प्रचालनात्मक आयामों पर एक-दूसरे के दृष्टिकोणों को समझा गया । अनुभावों और विचारों का आदान-प्रदान किये जाने के अतिरिक्त यह संयुक्त कार्यकारी दल शांतिरक्षा की संयुक्त कार्रवाइयों की योजना कार्यकारी दल शांतिरक्षा की संयुक्त कार्रवाइयों की योजना बनाने और संस्थागत कार्रवाइयों की पहचान करने का एक मंच भी है । इस रूपरेखा के अंतर्गत "प्रशिक्षक को प्रशिक्षण" पर सेन्ट्रेक्स, यू के के राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शांतिरक्षा कार्रवाइयों में भाग लेने वाले भारतीय पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया । शांतिरक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए अनुदेशकों का आदान-प्रदान करने सहित द्विपक्षीय सहयोग के अन्य पहलों की पहचान की गयी है ।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन

भारत ने 17-19 अगस्त, 2004 तक दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित गुट-निरपेक्ष आंदोलन के -ज्ख्ज्वें सम्मेलन में भाग लिया। विदेश राज्य मंत्री ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया । सम्मेलन में डरबन घोषणा पारित की गयी जिसमें बहुपक्षबाद को सुदृढ़ बनाने की नाम की वचनबद्धता और संयुक्त राष्ट्र की प्रमुखता की पुष्टि की गयी । मंत्रिस्तरीय सत्र में सम्मेलन की विषय-वस्तु "21वीं सदी में बहुपक्षवाद की चुनौतियाँ" पर चर्चा की गयी । अपने वक्तव्य में श्री राव इन्द्रजीत सिंह ने गुट-निरपेक्षता और बहुपक्षवाद के बीच अभिन्न संबंधों का उल्लेख किया । उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुधार की आवश्यकता, संयुक्त राष्ट्र के विकास और बढ़ावा संबंधी पहलुओं, जो नियामक पहलुओं से भिन्न है, पर बल दिया । उन्होंने बड़े विकासशील देशों में क्षमताओं को एकत्र करने की आवश्यकता पर बल दिया और इस संबंध में कुछ ठोस सुझाव दिये ।

भारत ने पुत्राजय, मलेशिया में 13 मई, 2004 को फिलीस्तीन से संबद्ध नाम समिति की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया जिसमें मलेशिया के नेतृत्व में एक मंत्रिस्तरीय शिष्टमंडल गठित किया जाएगा जो चतुष्क, (संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अमरीका और रूस) और पाँच स्थायी सदस्यों से बातचीत

बाएं से दाएं: प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, जापानी प्रधानमंत्री जुनिचीरो कोइजुमी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासिओ लुला द सिलवा और जर्मनी के उपचांसलर जोस्का फिशर, जी-4 की बैठक के दौरान, न्यूयार्क, 21 सितम्बर 2004।

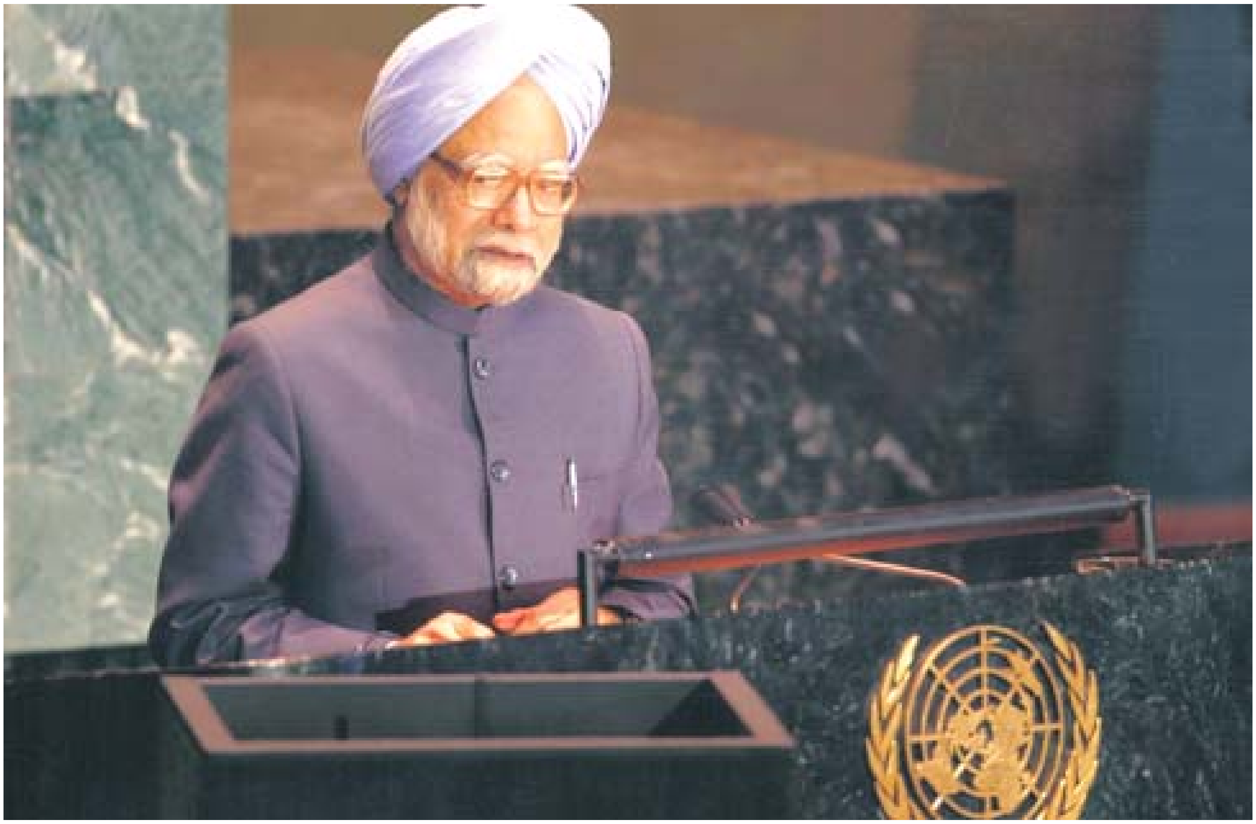

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें सत्र को सम्बोधित करते हुए, न्यूयार्क, 23 सितम्बर 2004।

करके मध्य पूर्व वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी । फिलीस्तीनी आंदोलन के साथ अपनी सहानुभूति को दोहराते हुए मानवीय स्थिति तथा शांति प्रक्रिया में बाधा पर चिंता व्यक्त करते हुए बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया गया कि वह कब्जा किये गये क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति सुनिश्चित करे और संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा मिशन स्थापित करे, संयुक्त राष्ट्र के अगले महाधिवेशन के दौरान फिलीस्तीन पर विशेष बैठक बुलाये तथा अंतर्राष्ट्रीय जनमत को एकजुट करे । भारत ने महासभा द्वारा 5 अगस्त, 2004 को नाम प्रस्ताव "अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख भूमिका की पुष्टि " पारित किये जाने का समर्थन किया ।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक 22 सितम्बर 2004 को 59वें संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के दौरान आयोजित की गयी । भारत ने "21वीं सदी में खतरों और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार " विषय पर बैठक के दौरान हुई चर्चा में भाग लिया । शिष्टमंडलों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुधार से संबंधित सामग्रियाँ खतरों, चुनौतियों और परिवर्तनों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उच्च-स्तरीय पैनल को सौंपी गयी ।

मध्य पूर्व

इस वर्ष मध्य पूर्व की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र में लगातार बहस चलती रही । अधिग्रहित पूर्वी जेरूसेलम और शेष फिलीस्तनी भूक्षेत्र की स्थिति पर महासभा का दसवाँ आपातकालीन विशेष सत्र पुनः 16-20 जुलाई 2004 तक के लिए बुलाया गया जिसमें "अधिग्रहित फिलीस्तीनी क्षेत्रों में दीवारों के निर्माण के विधिक परिणामों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के परामर्शों पर विचार किया जाना था । भारत ने बैठक में एक वक्तव्य दिया और उस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विचारों को स्वीकारा गया । प्रस्ताव के पक्ष में 150, विरोध में 6 मत पड़े जबकि 10 दिशों ने भाग नहीं लिया।

29-30 नवम्बर, 2004 को महासभा में मध्य पूर्व और फिलीस्तीनी प्रश्न को विचारार्थ कार्यसूची में रखा गया था । भारत सहित अनेक देशों ने इस मदों पर चर्चा में भाग लिया । राष्ट्रपति अराफात की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकतर वक्ताओं ने संबंधित पक्षों से हिंसा समाप्त करने और 'चतुष्क' योजना के क्रियान्वयन के जरिए राजनैतिक वार्ता बहाल करने का आह्वान किया । अनेक शिष्टमंडलों का विचार था कि फिलीस्तीनी प्राधिकार में होने वाले चुनाव और इजराइल की मुक्ति योजना से ऐसे अवसर मिलने की संभावना है जिसमें दोनों देश साथ-साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रह सकें । भारत ने "मध्य-पूर्व की स्थिति " विषय पर सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भी भाग लिया ।

इराक

संक्रमणकालीन प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता किये जाने के इराकी शासी परिषद और अनन्तिम गठबंधन प्राधिकार के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत लखदर ब्राहिमी ने फरवरी और अप्रैल 2004 में इराक का दौरा किया और राजनैतिक परिवर्तन की व्यापक योजना तैयार की । 8 जून, 2004 को सर्वसम्मति से पारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1546 में इराक में राजनैतिक परिवर्तन के लिए ब्राहिमी द्वारा दी गयी समय-सीमा का समर्थन किया गया और कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र को इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए जैसा कि इराकी सरकार ने अनुरोध किया है ।

उपर्युक्त योजना के पहले कदम के रूप में 30 जून, 2004 को इराकी शासी परिषद भंग किये जाने के साथ ही इराकी अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाल ली । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इराकी अंतरिम सरकार को पूर्ण सत्ता सौंपे जाने और कब्जा किये जाने का स्वागत किया । 14 जुलाई 2004 को अमरीका में पाकिस्तान के राजदूत श्री अशरफ जहांगीर काजी को इराक में महासचिव का विशेष दूत मनोनीत किया गया । ब्राहिमी योजना का दूसरा कदम अगस्त, 2004 के मध्य में पूरा किया गया जब संयुक्त राष्ट्र ने एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि राष्ट्रीय सम्मेलन के गठन को सहज बनाया जो नीति मामलों पर इराकी अंतरिम सरकार को सलाह देगा । संयुक्त राष्ट्र ने संक्रमणकालीन सरकार के चयन के लिए 31 जनवरी, 2004 को आयोजित प्रत्यक्ष राष्ट्रीय चुनावों को आयोजित करने में सीमित सहायता भी दी । संयुक्त राष्ट्र ने एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के गठन, विधायी रूपरेखा तैयार करने के लिए तकनीकी तैयारी, मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कार्मियों के प्रशिक्षण में सहायता की । चुनावों के बाद नये संविधान का प्रारूप तैयार किया जाएगा और इसके अनुमोदन के लिए जनमत संग्रह कराया जाएगा तथा उसके बाद 31 दिसम्बर, 2005 तक संवैधानिक तौर पर चुने गये स्थायी इराकी सरकार का गठन किया जाएगा ।

इराकी राजनैतिक हस्तांतरण के लिए समय सीमा तय करने के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1546 द्वारा आई आई जी के अनुरोधों के आधार पर एम एन एफ गठित किये जाने का प्रादेश देते हुए; एम एन एफ और आई आई जी के बीच "सुरक्षा भागीदारी " का समर्थन करते हुए तथा आई आई जी की इच्छानुसार इराक में एम एन एफ को निर्धारित एक वर्ष से अधिक रखकर बहु-राष्ट्रीय सेनाओं की स्थिति

तथा इराकी सरकार के साथ इसके संबंधों का भी निर्धारण कर दिया गया । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1546 में इराक विकास निधि को वितरित किये जाने तथा खाद्य के लिए तेल कार्यक्रम सहित आर्थिक शक्तियों के पूर्ण हस्तांतरण को भी शामिल किया गया था ।

अतः युद्ध के तत्काल बाद की अपनी सीमित भूमिका से आरंभ करके संयुक्त राष्ट्र इराकी राजनैतिक परिवर्तन प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाने लगा । हालांकि संयुक्त राष्ट्र से बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया जा रहा है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1546 के तहत आवश्यक प्रादेश भी प्राप्त हैं, कठिन सुरक्षा स्थिति के कारण इसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ है और वस्तुतः इसकी भूमिका सीमित ही है । हालांकि संयुक्त राष्ट्र को इराक के मामलों में पुनः शामिल किया गया है, यह देखा जाना शेष है कि यह हस्तांतरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों में कितनी बड़ी भूमिका निभा पाता है ।

भारत ने सर्वसम्मति से पारित किये गये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1546 का स्वागत किया और इराकी अंतरिम सरकार के प्रति समर्थन को पूर्ण सत्ता के पारदर्शी हस्तांतरण की दिशा में पहला कदम माना । इस बात पर गौर करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है, आशा की जाती है कि संयुक्त राष्ट्र इराक की आगामी परिस्थितियों में केन्द्रीय भूमिका निभायेगी । भारत के विचार में यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता है कि इराकी जनता के लिए सुरक्षा और सामान्य स्थिति बहाल की जाए और इराक के साथ भारत के लोगों के ऐतिहासिक एवं दीघावधिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत ने राजनैतिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के कठिन कार्यों में इराक को मदद करने की अपनी वचनबद्धता रोहरायी । भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित "इराक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष सुविधा " के जरिए इराक की मानवीय और पुनर्निर्माण संबंधी आवश्यकताओं के लिए 30 मिलियन अमरीकी डालरों के अनुदान की घोषणा की । जून, 2004 में भारत ने इराक में चुनाव सहायता के लिए अपने योगदान को निर्धारित करने में रूचि दिखायी । तदनुरूप भारतीय चुनाव आयोग और संयुक्त राष्ट्र के बीच 29 अगस्त, 2004 को चुनाव सहायता पर हुए समझौता ज्ञापन के अनुसरण में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और अन्य सबंधित क्षेत्रों में इराक को सहायता और आई आर एफ एफ के जरिए 5 मिलियन अमरीकी डालरों की सहायता का प्रस्ताव किया है । इसमें 2.5 मिलियन अमरीकी डालरों की राशि संयुक्त राष्ट्र इराक न्यास कोष में इराकी चुनावों के लिए निर्धारित की गयी है ।

अफगानिस्तान

संयुक्त राष्ट्र में भारत एक मजबूत, एकीकृत संप्रभु और स्वतंत्र अफगानिस्तान का समर्थन करता रहा । 8 दिसम्बर, 2004 को संयुक्त राष्ट्र ने चर्चा हेतु दो मसलों को उठायाः "अफगानिस्तान की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर इसका प्रभाव " और "युद्ध-ग्रस्त अफगानिस्तान में शांति, सामान्य स्थिति बहाल करने और पुनर्निर्माण के लिए आपातकालीन अंतर्राष्ट्रीय सहायता "। भारत सहित अनेक देशें ने इन कार्यसूची मदों पर वक्तव्य दिये । अफगानी जनता को सफल लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राष्ट्रपति करजई को लोकतांत्रिक रूप से अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुनने पर बधाई देते हुए भारत ने देश की कमजोर सुरक्षा स्थिति के संबंध में सावधान भी किया, विशेषकर जारी आतंकवादी गतिविधियों, स्वापक उत्पादन और केन्द्र सरकार को मजबूत बनाने की चुनौतियाँ के संबंध में । सभी वक्ताओं ने परिवर्तन प्रक्रिया में अफगानिस्तान द्वारा की गयी प्रगति पर गौर किया विशेषकर सफलता पूर्वक संविधान पारित करने और चुनाव आयोजित करने के संबंध में । हालांकि अनेक शिष्टमंडलों ने अन्य के साथ-साथ आतंकवादी खतरों, उग्रवादियों की उपस्थिति, स्वापक उत्पादन और अवैध व्यापार तथा आपराधिक गतिविधियों के कारण अफगानिस्तान के समक्ष आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख किया । अनेक शिष्टमंडलों ने समयबद्ध और विश्वसनीय संसदीय एवं स्थानीय चुनाव कराने की आवश्यकता का उल्लेख किया । अफगानिस्तान में सतत् अंतर्राष्ट्रीय रूचि का परिचय देते हुए भारत सहित 145 अन्य सदस्य देशों ने अफगानिस्तान पर महासभा के प्रस्ताव को सहःप्रायोजित किया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया ।

सूचना

सूचना से संबद्ध समिति, जो सार्वजनिक सूचना विभाग की नीतियों और गतिविधियों पर महासभा को अनुशंसाएं करती है, की वार्षिक बैठक अप्रैल - मई 2004 में न्यूयार्क में आयोजित की गयी । संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र रूचि और विवाद का प्रमुख मुद्दा बना रहा । इस बात पर सहमति हुई कि संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र पर किसी भी निर्णय को तब तक के लिए टाल दिया जाए जब तक कि फरवरी, 2004 से ब्रसल्स में कार्यरत क्षेत्रीय सूचना केन्द्र के कार्यों पर समिति को एक विस्तृत रिपोर्ट न उपलब्ध करा दी जाए । अपनी प्रक्रियाओं के अंत में समिति ने "मानवता की सेवा में सूचना " और "संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना गतिविधियाँ एवं नीतियाँ " पर दो प्रस्ताव पारित किये । समिति ने कतर, आइसलैंड, लक्जमबर्ग, मेडागास्कर और केप बर्डे को शामिल करते हुए अपनी सदस्यता संख्या को 102 से बढ़ाकर 107 करने का निर्णय भी लिया । 21 अक्टूबर, 2004 को "सूचना से संबंधित

प्रश्न " कार्यसूची मद पर चर्चा करते समय चौथी समिति द्वारा दो प्रस्तावों और निर्णयों का समर्थन किया गया । तत्पश्चात इन्हें महासभा द्वारा पारित किया गया ।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद

28 जून से 23 जुलाई 2004 तक इकोसॉस का महत्वपूर्ण अधिवेशन न्यूयार्क में आयोजित किया गया । इस वर्ष उच्च स्तरीय खण्ड की विषय-वस्तु थी "2001-2010 के दशक के लिए अल्प विकसित देशों के लिए कार्य-योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में गरीबी उन्मूलन के लिए संसाधन जुटाना और पर्यावरण को जनुकल बनाना " । उच्च-स्तरीय खण्ड के अंत में एक मंत्रिस्तरीय घोषणा पारित की गयी जिसमें अल्प विकसित देशों के लिए क्रियान्वयन योजना के कमजोर क्रियान्वयन की पहचान की गयी, कार्य-योजना में निहित वचनबद्धताओं के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सुशासन की आवश्यकता की पुष्टि की गयी तथा अल्प विकसित देशों के प्रयासों को सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ठोस समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

इकोसॉस ने अल्प विकसित देशों की स्थिति में प्रगति के पश्चात सुगमता से आगे बढ़ाने की नीति तथा केप बर्डे और माल्दीव को अल्प विकसित देशों के समूह से आगे बढ़ाने के विकास नीति समिति की अनुशंसाओं का समर्थन किया और महासभा से इन अनुशंसाओं पर गौर करने का अनुरोध किया।

इकोसॉस ने युद्ध से उबरे अफ्रीकी देशों से संबद्ध इकोसॉस के तदर्थ परामर्शी समूह के कार्यों की समीक्षा की और वर्ष 2005 में होने वाले महत्वपूर्ण सत्र तक गिनि-बिसाउ और बुरूंडी से संबद्ध तदर्थ परामर्शी समूह के प्रादेश को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया । इकोसॉस ने हैती से संबद्ध तदर्थ परामर्शी समूह को पुनः सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और इस समूह को 2005 में होने वाले महत्वपूर्ण सत्र में इकोसॉस के विचारार्थ रखे जाने के लिए हैती के लिए दीर्घावधिक विकास नीति के संबंध में सलाह देने का प्रादेश सौंपा गया ताकि वहाँ सामाजिक आर्थिक प्रगति और स्थायित्व बहाल की जा सके।

इकोसॉस ने कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबद्ध विशेषज्ञों के तदर्थ समूह का उन्नयन करते हुए इसे कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की समिति बनाने और इसके प्रादेश को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जो अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी विचार कर सके कि नये और उदीयमान मसले किस प्रकार कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं तथा आकलन एवं उपयुक्त अनुशंसाएं कर सकते हैं ।

59वीं महासभा

भारत ने दूसरी समिति में सक्रिय भूमिका निभानी जारी रखी । महासभा ने 2005 में होने वाले 60वें सत्र के आरंभ में सभा का उच्च-स्तरीय पूर्ण सत्र बुलाने का निर्णय लिया ताकि उनकी प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों और वैश्विक भागीदारी तथा आर्थिक, सामाजिक और संबंधित क्षेत्रों में बड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों एवं शिखर सम्मेलनों के परिणामों के एकीकृत और समन्वित क्रियान्वयन में हुई प्रगति सहित सहस्त्राब्दि घोषणा में निहित सभी वचनबद्धताओं की पूर्ति के संबंध में की गयी प्रगति की व्यापक समीक्षा की जा सके । इस निर्णय के आलोक में दूसरी समिति में आर्थिक, पर्यावरण और विकास मसलों पर हुए विचार-विमर्श में बड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों एवं शिखर सम्मेलनों के परिणामों के क्रियान्वयन और विकास के लिए संसाधनों के संवर्द्धित प्रवाह की आवश्यकता पर बल दिया गया । शिष्टमंडलों ने इन संवर्द्धित प्रवाहों को संपूरित करने के लिए विकास के वित्त-पोषण के लिए नये संसाधनों की आवश्यकता पर बल दिया । महासभा ने विकास के लिए वित्त-पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए समग्र संरचना के अंतर्गत प्रस्तावों पर विचार करने का निर्णय लिया ।

"अ फेयर ग्लोबलाइजेशनः क्रिएटिंग अपोर्चुनिटीज फॉर आल " शीर्षक से वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व आयोग की रिपोर्ट को शिष्टमंडलों का व्यापक समर्थन मिला। रिपोर्ट को जारी करने के लिए विश्व आयोग के सह अध्यक्षों फिनलैंड के राष्ट्रपति तारजा होलोनेन और तंजानियाँ के राष्ट्रपति बेंजामिन विलियम मकापा द्वारा एक विशेष बैठक आयोजित की गयी । इस अवसर अपने संदेश में प्रधान मंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने इस बात पर बल दिया कि प्रभावी राष्ट्रीय कार्रवाई को सुविधाजनक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की आवश्यकता है ताकि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकें और उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस रिपोर्ट से इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति बन पायेगी । पहली बार महासभा ने वैश्वीकरण और अंतर-निर्भरता के संदर्भ में नीति के महत्व को रेखांकित किया ।

पर्यावरण एवं सतत् विकास मसले

भारत ने सतत् विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत सतत् विकास से संबद्ध उच्च-स्तरीय आयोग के बारहवें सत्र के कार्यों में सक्रिय भागीदारी की । इसे कार्यसूची 21 और जोहान्सबर्ग क्रियान्वयन योजना की समीक्षा और इनके क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करने का कार्य दिया गया । सतत् विकास से संबद्ध बारहवाँ सत्र 14-30 अप्रैल, 2004 तक न्यूयार्क में आयोजित किया गया जिसमें जल जमाव, स्वच्छता और मानव बस्तियाँ बसाने के संबंध में क्रियान्वयन लक्ष्यों के लिए सहमत जोहान्सबर्ग योजना को पूरा करने में विकासशील देशों के समक्ष आयी बाधाओं और चुनौतियों पर

विशेष बल दिया । सी एस डी की उच्च-स्तरीय बैठक 28-30 अप्रैल तक हुई । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सचिव, डा0 प्रदीपो घोष ने सी एस डी - 12 में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया । उन्होंने कहा कि इस बैठक से विकासशील देशों की चुनौतियों का पता चला और उन्होंने राज्य भागीदारों और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों के प्रावधानों सहित क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को स्वीकार करने और मॉनिटर करने तथा विकासशील देशों को आवश्यक प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सी एस डी-12 ने अनेक चुनौतियों की पहचान की जिनमें शामिल हैंः सभी स्रोतों से संसाधन जुटाना, विकासशील देशों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का अन्तरण एवं क्षमता निर्माण । इन पहलुओं पर अप्रैल 2005 में होने वाली सी एस डी-13 के 13वें सत्र में चर्चा की जाएगी जिसमें नीति विकल्पों और व्यावहारिक उपायों पर निर्णय लिये जाएंगे ।

सामाजिक, मानवाधिकार और मानवीय मसले

भारत ने सामाजिक विकास और मानवाधिकार मसलों पर हुई बहस और चर्चा में बढ़ चढकर भाग लिया । महासभा, इकोसॉस और कार्यकारी आयोगों में इन मसलों पर हुई चर्चा में भारत की भागीदारी इस कारण भी हुई कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह एक विकासशील देश है, और यह विधिसम्मत शासन तथा मानवाधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है । भारत ने गैर-सरकारी समिति के नियमित सत्र में सक्रिय भूमिका निभायी ।

मानवाधिकार

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रणाली के प्रति अपनी पारंपरिक वचनबद्धता को ध्यान में रखकर भारत ने प्रमुख मानवाधिकार निकायों-मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण पर उप-आयोग, उनकी उप समितियों और कार्यकारी समूहों में भाग लेना जारी रखा । उप-आयोग में भारत के प्रतिनिधि श्री सोली सोराबजी को 56वें उप-आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया । संबंधित विशिष्ट प्रक्रियाओं और संधि निकायों के साथ रचनात्मक वार्ता की गयी । भारत ने भोजन के अधिकार से जुड़े विशेष रैपोर्टियर द्वारा आपसी सुविधाजनक तिथियों को भरत आने का अनुरोध स्वीकार कर लिया ।

मानवाधिकार आयोग का 60वां सत्र 15 मार्च - 23 अप्रैल, 2004 तक जेनेवा में हुआ । 18 मार्च 2004 को विदेश सचिव ने उच्च-स्तरीय खण्ड को संबोधित किया । भारत ने हमास नेता शेख अहमद यासिन की हत्या से उत्पन्न स्थिति पर, जो आई सी द्वारा बुलाई गयी, विशेष बैठक आयोजित किये जाने के पक्ष में मत दिया ।

भारत ने इस महत्वपूर्ण मसले पर हो रही राजनीति और ध्रुवीकरण के समय प्रमुख और संतुलन की भूमिका निभायी । भारत ने संबंधित प्रस्तवों पर बातचीत में भाग लिया और इन मसलों पर अनेक प्रस्तावों को सह-प्रायोजित करने के अलावे दो द्विवार्षिक प्रस्तावों को आगे बढ़ाया-परामर्शी सेवाओं और तकनीकी सहयोग तथा सहिष्णुता और बहुवाद पर जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया । अन्य शिष्टमंडलों के साथ मिलकर भारत ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों, आतंकवाद का मुकाबला इत्याद जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानिटरिंग तंत्र बनाने के प्रयासों का विरोध किया और कुछ मामलों में सफलता भी मिली ।

आयोग में आतंकवाद बहस का विषय रहा जिसमें भारत ने अपने इस सुस्थापित दृष्टिकोण के आलोक में भाग लिया कि आतंकवादी जीने के अधिकार का हनन करते हैं जो सबसे मौलिक मानवाधिकार है । रचनात्मक बहस और चर्चाओं के जरिए भारत इस मसले पर पारित मैक्सिकन प्रस्ताव में ऐसी कुछ चिंताओं को परिलक्षित करने में सफल रहा जिन पर सर्वसम्मति बनी ।

विकलांगों के अधिकारों और सम्मान के संवर्द्धन एवं संरक्षण से संबद्ध व्यापक एवं अभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर तदर्थ समिति का तीसरा और चौथा सत्र 24 मई से 4 जून, और 23 अगस्त से 3 सितम्बर 2004 तक आयोजित किया गया । कार्यकारी दल द्वारा तैयार किये गये पाठ के प्रारूप के प्रथम अध्ययन में भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

नवम्बर, 2004 में भारत ने बच्चों को बेचे जाने, बाल वेश्यावृत्ति और बाल अशलील साहित्य तथा सशस्त्र संघर्षों में बच्चों को शामिल किये जाने से संबद्ध अभिसमय के वैकल्पिक प्रोतोकोलों पर हस्ताक्षर किया।

अनेक प्रसिद्ध भारतीय महत्वपूर्ण संधि निगरानी निकायों और मानवाधिकार तंत्रों के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे । इनमें शामिल थे : श्री पी एन भगवती (मानवाधिकार समिति के सदस्य), श्रीमती चोकिला अय्यर (आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबद्ध समिति की सदस्य), श्री आर वी पिल्लई (जातीय भेदभाव उन्मूलन समिति के सदस्य), और श्री मिलन कोठारी (पर्याप्त आवास अधिकार पर विशेष रैपोर्टियर) । विकास के अधिकार पर स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में श्री अर्जुन सेनगुप्ता का प्रादेश समाप्त हो गया ।

शरणार्थी, प्रवसन और आपदा नियंत्रण

भारत ने स्थायी समिति की बैठकों और शरणार्थियों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग के अनौपचारिक विचार-विमर्शों और साथ ही उच्चायुक्त की पहल पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया । इसने अक्टूबर, 2004 में यू एन एच सी आर कार्यालय

की कार्यकारी समिति के 55वें वार्षिक सत्र में भाग लिया । भारत ने शरणार्थियों का शरण देने और भाईचारे के सिद्धांतों की अपनी ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख किया । यू एन एच सी आर के साथ अपने क्रियाकलाप में भारत ने विकासशील देशों के हितों से जुडे मसलों को उठाया जिसमें शामिल थे शरणार्थियों के विशाल और मिले-जुले प्रवाह का समाधान और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी । इसने मानवीय सहायता और दीर्घावधिक विकास के बीच संपर्क पर भी बल दिया जो शरणार्थी संरक्षण के निषेधात्मक उपायों के लिए महत्वपूर्ण हैं । भारत ने अपनी स्थायी दृष्टिकोण को दोहराया कि संबंधित देशों की सहमति से ही टिकाऊ समाधान आ सकता है जिसमें यू एन एच सी आर की निष्पक्ष, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ भूमिका हो ।

मानवीय सहायता

भारत ने समूह 77 की ओर से प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता के लिए मानवीय सहायता में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर वार्षिक प्रस्ताव को आगे बढ़ाना जारी रखा । महासभा के 59वें सत्र द्वारा पारित प्रस्ताव में इस विषय पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए संसाधनों और महासचिव के प्रादेशों से जुड़े मसलों पर बल दिया गया । अनेक विकासशील देशों ने इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित करने में भाग लिया। भारतीय शिष्टमंडल ने जनवरी 2005 में कोबे में आयोजित होने वाले आपदा नियंत्रण पर विश्व सम्मेलन की तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभायी ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन पर वैश्विक आयोग

अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन पर वैश्विक आयोग एक वैश्विक पैनल है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के प्रश्न का हल ढूंढ़ने के लिए किया गया है । इसे 9 दिसम्बर, 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के समर्थन से जारी किया गया । मनीला, काहिरा और बुडापेस्ट में क्रमशः भूमध्य क्षेत्र, मध्य पूर्व और यूरोप के लिए एशिया और प्रशांत के संबंध में तीन सुनवाइयाँ हो चुकी हैं । श्रम, गृह और विदेश मंत्रालयों का एक अंतर-मंत्रालयीय शिष्टमंडल जी सी आई एम में भाग लेता रहा है । योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री एन के सिंह जी सी आई एम में भारत के प्रतिनिधि है ।

गंतव्य, उद्गम और पारगमन के एक देश के रूप में भारत वैध और अवैध प्रवसन के बीच अंतर करने की आवश्यकता, वैध उत्प्रवासियों के लिए भेदभाव-रहित नियमों और विनियमों की आवश्यकता और स्वतंत्र व्यवसायिकों तथा संविदा सेवा के प्रवेश के संबंध में विकसित देशों की ओर से और उदार वचनबद्धताओं की आवश्यकता पर इन बैठकों में अपने विचार व्यक्त करता रहा है ।

विशिष्ट निकायः परिचालन गतिविधियाँ

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की परिचालन गतिविधियाँ/संयुक्त राष्ट्र की निधियाँ और कार्यक्रम

भारत ने संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों के कार्यों में महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखा । भारतीय प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ कि ये संगठन राष्ट्रीय विकास योजनाओं और प्राथमिकताओं के अनुसरण में अपने देश द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के साथ समझौता किये बिना गरीबी उन्मूलन और सतत् विकास के अपने प्रयासों में विकासशील देशों को सहायता करने के प्राथमिक प्रादेश पर बल देना जारी रखें । भारतीय शिष्टमंडल ने संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यक्रमों में समानता लाने के प्रयासों का विरोध करने में योगदान दिया । भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें सत्र के दौरान निर्धारित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के विकास की प्रचलानात्मक गतिविधियों की त्रिवार्षिक व्यापक नीति समीक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड)

भारत ने 13-18 जून, 2004 तक ब्राजील के साओ पाउलो में हुए अंकटाड -XI सम्मेलन में भाग लिया । भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने किया । सम्मेलन के दौरान मंत्री महोदय ने पूर्ण सत्र को संबोधित किया और अपने समकक्षों के साथ अनेक द्विपक्षीय बैठकें कीं । सम्मेलन में एक मंत्रिस्तरीय घोषणा-साओ पाउलो सर्वसम्मति- और एक राजनैतिक संदेश-साओ पाउलो की भावना पारित की गयी । सर्वसम्मति दस्तावेज में वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रिया और विकासशील देशों पर इसके प्रभाव पर नीति विश्लेषण उपलब्ध कराया गया । किसी बहुपक्षीय मंच द्वारा प्रकाशित शायद यह पहला दस्तावेज है जिसमें बहुपक्षीय व्यापार और अन्य वार्ताओं के अनुसरण में बढ़ती हुई वचनबद्धताओं के आलोक में विकास उद्देश्यों का पालन करने में विकासशील देशों के समक्ष सीमित नीति विकल्पों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया । अंकटाड-XI सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में एक थी विकासशील देशों के बीच व्यापार अधिमानता की वैश्विक प्रणाली के अंतर्गत वार्ता का तीसरा दौर शुरू किया जाना ।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी)/यू एन हैबिटेट

यू एन ई पी की शासी परिषद/वैश्विक मंत्रिस्तरीय पर्यावरण मंच का आठवां सत्र 27-31 मार्च 2004 तक कोरिया गणराज्य के जेजू द्वीप में आयोजित किया गया । भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व डा0 प्रदीपो घोष सचिव (पर्यावरण एवं वन) ने किया । भारत ने इस बैठक में सक्रिय भागीदारी की । हम तकनीकी समर्थन और क्षमता निर्माण के लिए अंतर-सरकारी

सामरिक योजना पर उच्च-स्तरीय खुले अंतर-सरकारी दल की बैठकों में भी भाग लेते रहे हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

1-17 जून, 2004 तक जेनेवा में आयोजित 92वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठकों में श्रम मंत्री श्री शीश राम ओला ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री शिष्टमंडल के सदस्य थे । अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के बाद हुए शासी निकाय के 290वें सत्र में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व सचिव (श्रम) ने किया । 92वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में फरवरी 2004 में वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व आयोग की वैश्वीकरण पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर विशेष चर्चा की गयी । चर्चा के अन्य मसले मात्सिकी, प्रवसन और मानव संसाधन विकास से संबंधित थे।

विश्व स्वास्थ्य असेम्बली (डब्ल्यू एच ए)

17-22 मई, 2004 तक जेनेवा में हुए 57वें विश्व स्वास्थ्य असेम्बली में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने किया । एच आई वी/एड्स विषय पर विश्व स्वास्थ्य असेम्बली ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की "3 बाय 5 " पहल पर विशेष बल दिया । असेम्बली में स्वास्थ्य के विषय पर अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किये गये जैसे कि "खान-पान, शारीरिक सक्रियता और स्वास्थ्य पर वैश्विक नीति " और "जनन स्वास्थ्य पर नीति " । असेम्बली के दौरान पिछले वर्षों की भांति पारंपरिक भारतीय दवाओं पर एक प्रस्तुती सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें इन दवाओं का निर्माण करने वाली छह कंपनियों ने भाग लिया ।

विश्व मौसमविज्ञान संगठन (डब्ल्यू एम ओ)

भारतीय मौसमविज्ञान विभाग के महानिदेशक डा0 एस के श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने 8-18 जून, 2004 तक डब्ल्यू एम ओ के 56वें सत्र में भाग लिया ।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो)

भारत औद्योगिक विकास बोर्ड, कार्यक्रम एवं बजट समिति इत्यादि सहित यूनिडो की सभी महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेता रहा है । आई डी बी की बैठकों में भाग लेते हुए भारतीय शिष्टमंडल ने यूनिडो की गतिविधियों में भारतीय सरकार की वचनबद्धता को रेखांकित किया । जी-77 और चीन द्वारा दिये गये वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया गया कि भारत यूनिडो के सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्त्ताओं में से एक है । इस बात का भी उल्लेख किया गया कि बदलती हुई वैश्विक अनिवार्यताओं के साथ यूनिडो को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों और उनके अनुप्रयोगों पर बल देना चाहिए ताकि वे एस एम ई की लागत प्रतियोगिता को बढ़ा सकें और अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार बना सकें कि भारत इस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करने में योगदान कर सके । भारत ने यह भी कहा कि सतत् विकास और रोजगार निर्माण की समग्र सामरिक अनिवार्यता के अंतर्गत भारत ने खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण उद्योग, कौशल उन्नयन और लघु पन-बिजली संयंत्रों को यूनिडो के साथ कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है । दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर चर्चा के संदर्भ में भारत ने अन्य विकासशील देशों को बायोमास, लघु पनबिजली एवं अल्प लागत तथा भूकंप रोधी मकान बनाने जैसे क्षेत्रों में सहायता सहित भारतीय प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का प्रस्ताव करके इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कार्य करने की भारत की वचनबद्धता का भी उल्लेख किया गया । अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (अनसिटराल)।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (अनसिटराल)

भारत ने प्रापण, विवाचन और संराधन, परिवहन कानून, इलेक्टानिक वाणिज्य, सुरक्षा हित पर अनसिटराल के कार्य दल के सत्रों में भाग लिया जो अप्रैल-नवम्बर, 2004 तक विएना में आयोजित किये गये थे।

एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (इस्कैप)

आयोग का साठवां सत्र 22-29 अप्रैल, 2004 तक शंघाई में आयोजित किया गया । इस सत्र में दो वरिष्ठ अधिकारियों का सत्र 22-24 अप्रैल, 2004 तक और मंत्रिस्तरीय सत्र 26-28 अप्रैल, 2004 तक हुआ । भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव श्री दीपक चटर्जी ने किया । शंघाई अधिवेशन की मुख्य विषय वस्तु थी "क्षेत्रीय विकास सहयोग को संवर्द्धित करते हुए वैश्वकीरण के युग में चुनौतियों का मुकाबला " । तीन विषयों-गरीबी उपशमन, वैश्वीकरण का प्रबंधन और उद्दीयमान सामाजिक मसलों का समाधान के अतर्गत इस्कैप के कार्यों पर बल देने के महत्व की पुष्टि की गयी । शंघाई घोषणा पारित की गयी ।

स्वापक औषधों से संबद्ध आयोग

भारत ने 15-22 मार्च तक विएना में आयोजित स्वापक औषधों से संबद्ध आयोग के 47वें नियमित सत्र में भाग लिया जिसमें सी एन डी के 48वें सत्र की अध्यक्षता की पुष्टि की गयी । तुर्की के साथ मिलकर भारत ने चिकित्सा उद्देश्यों से अफीम की आपूर्ति और मांग के बीच नाजुक संतुलन बनाये रखने का पारंपरिक अनुरोध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किया । बाद में आस्ट्रेलिया भी इस प्रस्ताव का सह-प्रायोजक बना।

अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक न्याय पर आयोग

भारत ने अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक न्याय के 13वें सत्र, जिसका आयोजन 11-20 मई तक विएना में हुआ, में भाग

लिया और अन्य बातों के साथ-साथ 18-25 अप्रैल, 2005 तक बैंकाक में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के 11वें कांग्रेस की तैयारी पर हुई चर्चा में भाग लिया। इसमें और अन्य गतिविधियों में भारत ने सी सी पी सी जे के भावी कार्यों के लिए आगामी संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस के परिणामों के महत्व पर बल दिया।

समूह - 77

महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा अन्य निकायों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों के लिए विकासशील देशों के दृष्टिकोणों में समन्वय लाने के उद्देश्य से समूह 77 की बैठकें पूरे वर्ष चलती रहीं। 2004 के दौरान कतर ने समूह 77 की अध्यक्षता की। समूह 77 के विदेश मंत्रियों की 28वीं वार्षिक बैठक 30 सितम्बर को न्यूयार्क में हुई जिसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री निरूपम सेन ने भाग लिया। स्थायी प्रतिनिधि ने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में विकासशील देशों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया, विकसित देशों से अपनी वचनबद्धताएं पूरी करने का आह्वान किया, विकास, गैर-पारंपरिक और नये स्रोतो के वित्त-पोषण के संदर्भ में चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए भारत के मजबूत समर्थन को दोहराया।

व्यापार और विकास से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 11वें अधिवेशन की पूर्व संध्या पर समूह की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 11-12 जून, 2004 तक साओ पाउलो में समूह 77 की बैठक हुई। इस अवसर पर पारित मंत्रिस्तरीय घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय और विकास मसलों के समाधान में और विकासशील देशों के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने में इस समूह की भूमिका की पुष्टि की गयी तथा इस समूह, चीन और निर्गुट देशों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने के महत्व पर बल दिया गया। अपने वक्तव्य और चर्चाओं में भारत ने इस बात पर बल दिया कि विकासशील देश अपने विचारों का समन्वय करें और बहु-पक्षीय व्यापार वार्ताओं में संयुक्त स्वर उठायें ताकि इन प्रक्रियाओं को विकासशील देशों के लिए लाभकारी बनाया जा सके। भारत ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग को संवर्द्धित करने की अपनी जारी वचनबद्धता का दोहराया।

उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान

विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह, जो यूरोपीय देशों में भारत के मिशन प्रमुखों की बैठक के संदर्भ में जेनेवा गये थे, ने कार्यकारी मानवाधिकार उच्चायुक्त और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक के साथ मुलाकात की। कार्यकारी मानवाधिकार उच्चायुक्त श्री बर्ट्रेंड रामचरण ने 15 जून, 2004 को जेनेवा में विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने मानवाधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के प्रति भारत की वचनबद्धता को दोहराया और इस विषय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भारत द्वारा दिये जाने वाले महत्व को रेखांकित किया।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक डा0 जुआन समोविया ने 15 जून, 2004 को जेनेवा में विदेश मंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने संगठन में भारत की भूमिका पर चर्चा की। उनकी चर्चा संगठन में भारत की भूमिका और तंजानियाँ एवं फिनलैंड के राष्ट्रपतियों की सह-अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा गठित सतत् विकास आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट "फेयर ग्लोबलाइजेशन,: क्रिएटिंग अपोर्चुनिटीज फॉर ऑल" पर केन्द्रित रही।

यूनिडो के महानिदेश डा0 कार्लोस मगारिनोस ने 15-23 सितम्बर, 2004 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ मुलाकात की और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की। कार्यक्रम विकास एवं तकनीकी सहयोग महानिदेशक श्री अब्दुल जे जे रवेन्डेयर ने 23-30 अक्टूबर, 2004 तक भारत का दौरा किया।

अंतर-संसदीय संघ (आई पी यू)

अंतर-संसदीय संघ की 111वीं असेम्बली 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2004 तक जेनेवा में आयोजित की गयी। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के नेतृत्व में एक 15 सदस्यीय शिष्टमंडल, जिसमें कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री श्री सुरेश पचौरी शामिल थे, ने इसमें भाग लिया। शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध प्रथम स्थायी समिति की प्रारूप समिति का एक सदस्य भारत भी था जिसमें भारत के श्री एम सलीम रैपोर्टियर थे। असेम्बली द्वारा पारित प्रस्ताव और "मानव सुरक्षा" शब्द पर भारत की आपत्तियों को दर्ज किया गया। वर्ष 2005 के लिए अंतर-संसदीय संघ में भारत का योगदान सी एच एफ 56730 था।

चुनाव

भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद में अक्टूबर 2004 में पुनः चुन लिया गया। भारत को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। भारत को महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 190 सदस्यों में से 174 का मत प्राप्त हुआ। भारत को एच आई वी/एड्स से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के लिए निर्विरोध चुन लिया गया। इस वर्ष के दौरान प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र परामर्शी समिति में भारत के उम्मीदवार को चुना गया।

भारत को 28 सितम्बर - 8 अक्टूबर के दौरान मॉंट्रियाल में हुए संगठन के 35वें अधिवेशन के दौरान 2 अक्टूबर को आयोजित

चुनावों में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के लिए चुना गया ।

भारत को 15 सितम्बर - 5 अक्टूबर, 2004 के दौरान रोमानियाँ, बुखारेस्ट में आयोजित संघ की 23वीं कांग्रेस के दौरान सार्वभौमिक डाक संघ की डाक प्रचालन परिषद के लिए चुना गया ।

डा0 अर्जुन सेनगुप्ता को मानवाधिकार तथा नितान्त गरीबी विषय पर स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में मनोनीत किया गया, एक प्रादेश जिसे मानवाधिकार आयोग द्वारा 1998 में दिया गया और जिसे अप्रैल 2004 में मानवाधिकार आयोग के 60वें सत्र में आगे बढ़ाया गया । जुलाई 2004 में इस प्रादेश की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गयी ।

निरस्त्रीकरण

गैर-भेदमूलक और विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण तथा जन-संहार के समस्त हथियारों के वैश्विक उन्मूलन के प्रति भारत की वचनबद्धता इसकी नीतिगत घोषणाओं और राजनीतिक प्रयासों में झलकती रही है। विभिन्न बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय मंचों पर निरस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में भारत का रवैया इन चुनौतियों से निपटने में सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत की गहरी संबद्धता और इसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर आधारित रही है ।

प्रमुख देशों के साथ द्विपक्षीय वार्त्ताएं इस वर्ष होती रही हैं और नाभिकीय अप्रसार तथा निरस्त्रीकरण से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय चिंताओं के साथ भारत की राष्ट्रीय अनिवार्यताओं और सुरक्षा दायित्वों का समन्वित किया जाना भी निर्बाध गति से बढ़ता रहा है ।

क्षेत्रीय स्तर पर, आसियान क्षेत्रीय मंच (ए आर एफ) तथा कॉन्फरेंश ऑन इन्टरएक्शन एंड कॉन्फीडेंश बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया (सी आइ सी ए) के अंतर्गत विश्वास एवं सुरक्षा निर्माण प्रक्रिया और संरचना में भारत की भागीदारी ने बेहतर गति हासिल कर ली है ।

निरस्त्रीकरण मामलों पर भारतीय दृष्टिकोण को प्रचारित करने के उद्देश्य से निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा गया है ।

आसियान क्षेत्रीय मंच

भारत ने आसियान क्षेत्रीय मंच के कार्यों में इसके तत्वावधान में आयोजित विभिन्न बैठकों में भागीदारी कर हिस्सा लिया। भारत ने 30-31 मार्च,2004 को मनीला, फिलीपिन्स में हुई दूसरी इन्टरसेशनल मीटिंग ऑन काउंटर-टेरोरिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राईम्स (आइ एस एम ऑन सी टी-टी सी), मई,2004 में मोकार्ता, इण्डोनेशिया में हुई ए आर एफ सीनियर आफिसियल्स मीटिंग, जिसमें जुलाई में 11वीं ए आर एफ मीनिस्टीरियल मीटिंग हेतु प्रगति एवं तैयारी पर चर्चा हुई, 'मेरीटाईम सिक्यूरिटी' पर इण्डोनेशिया, मलेशिया द्वारा तथा क्वालालम्पुर, मलेशिया में 24-26 सितम्बर, 2004 को संयुक्त राज्य द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, 7-8 अक्तूबर,2004 को कोरिया गणराज्य द्वारा आयोजित' साईबर-सिक्यूरिटी' संगोष्ठी तथा 24-26 अक्तूबर,2004 को नोम-पेन्ह में हुई इन्टर-सेशनल सपोर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन कन्फीडेंश बिल्डिंग मेजर्स (आई एस जी ऑन सी बी एम) में भागीदारी की ।

इण्डोनेशिया ने जकार्ता में 1-2 जुलाई,2004 को 11वीं ए आर एफ मीनिस्टीरियल मीटिंग की मेजबानी की । विदेश मंत्री ने भारतीय शिष्टमंडल की इस वार्षिक बैठक में अगुआई की । समग्र रूप से क्षेत्र में आतंकवाद तथा आतंकवादी धमकी का मामला ए आर एफ की कार्यसूची में छाया रहा । मंत्रियों ने इस संबंध में सदस्य देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की तथा एक "परिवहन सुरक्षा सुदृढ़ीकरण संबंधी वक्तव्य " को अपनाया, जिसमें आतंकवादी धमकियों से परिवहन साधनों को बचाने के लिए सहकारी कार्रवाई का आह्वान किया गया । मंत्रियों ने एक नाभिकीय अप्रसार संबंधी वक्तव्य को भी अपनाया । विदेश मंत्री ने अपने भाषण में किसी दोहरे मानदंड या टालमटोल को अपनाए बिना वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई की आवश्यकता पर बल दिया तथा जन-संहार के हथियारों के प्रसार के साथ इसके संबंधों में खतरों की संभावना को रेखांकित किया ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति में निरस्त्रीकरण मामलों पर सक्रिय भूमिका को निभाना जारी रखा । पहली समिति के 59वें सत्र में, "जन-संहार संबंधी हथियारों को हासिल करने से आतंकवादियों को रोकने संबंधी उपाय " पर भारत के संकल्प को एकबार फिर एकमत होकर स्वीकार कर लिया गया था । भारत ने पहली बार इस संकल्प को 2002 में यू एन जी ए के 57वें सत्र में प्रस्तुत किया था। 59वें सत्र में, इस संकल्प हेतु सह-समर्थकों की संख्या पिछले वर्ष के 17 से बढ़कर 47 हो गई, जिसमें जापान, रूस और ब्रिटेन शामिल हैं । संकल्प में जन-संहार के हथियारों के प्रसार से उत्पन्न खतरे पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की संयुक्त चिंता झलकती है और संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसी वास्तविक सार्वभौमिक एवं लोकतांत्रिक निकाय से एक स्पष्ट वक्तव्य के रूप में इसकी निरन्तर संगतता को बनाए रखा गया है ।

भारत ने वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण पर अपने सैद्धांतिक रवैये की प्रतिबद्धता को दोहराया जो इस दृढ़ विश्वास पर आधारित था कि विश्वस्तर पर शस्त्रों को धीरे-धीरे निचले स्तरों तक लाने से सबको बढ़ती सुरक्षा की गारंटी मिलेगी । भारत को विश्वास है कि इसकी सुरक्षा परमाणु-हथियार-मुक्त-विश्व में बढ़ जाएगी । वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण की इस वचनबद्धता के साथ, भारत ने 1982 में पहली बार शुरू किए गए "परमाणु हथियारों के प्रयोग पर रोक संबंधी अभिसमय" के अपने संकल्प को फिर से प्रारंभ किया । यह संकल्प परमाणु हथियारों की प्रमुखता को घटाने की ओर प्रथम चरण के रूप में, किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी या प्रयोग को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर बातचीत शुरू करने हेतु निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन का आह्वान करता है ।

"परमाणु खतरे को कम करना" संबंधी भारत के संकल्प, जिसे सर्वप्रथम 1998 में लाया गया था, जिसमें परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा करने तथा परमाणु हथियारों के गैरईरादतन एवं आकस्मिक प्रयोग के खतरे को कम करने के लिए तत्काल एवं अनिवार्य कदम उठाए जाने की बात कही गयी है, को भी फिर से प्रस्तुत किया गया ।

"अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका" नामक भारत के संकल्प में हथियारों के दौर में गुणात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है और वास्तविक बहुपक्षीय एवं गैर-भेदमूलक प्रतिक्रिया की आवश्यकता को परिलक्षित किया गया है । भारत ने उन उत्तरदायी देशों को प्रौद्योगिकी अन्तरण पर रोक जारी रखा है जो अप्रसार के उद्देश्यों का समर्थन नहीं करते हैं बल्कि मात्र दण्डात्मक ईरादे को ईंगित करते हैं । पूर्व वर्षों की भांति अधिकांश ने इन सभी संकल्पों को अपना लिया ।

निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन

निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (सी डी), "एकमात्र बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि वार्त्ता निकाय" के तीन सत्र 2004 के दौरान 19 जनवरी- 26 मार्च, 10 मई-25 जून तथा 26 जुलाई-10 सितम्बर को जेनेवा में हुए । सामान्य औपचारिक पूर्ण बैठकों के अलवा, इस वर्ष हुए सम्मेलन में सी डी की विद्यमान कार्यसूची संबंधी मामलों पर अनौपचारिक पूर्ण बैठकों की रूपरेखा तैयार की गई । भारत ने एक कार्य-कार्यक्रम को अपनाने संबंधी सी डी में गतिरोध को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर बातचीत में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। विचार-विमर्शों के दौरान, सी डी हेतु कार्य-कार्यक्रम को सुस्थापित करने में योगदान देने के लिए एक स्वतंत्र और रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया, जो इसके समस्त सदस्य देशों की चिंताओं और प्राथमिकताओं को परिलक्षित करता है।

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग (यू एन डी सी)

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग निरस्त्रीकरण एवं हथियार नियंत्रण से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के अधिदेश के साथ तथा महासभा को सिफारिशें करने के लिए एकमात्र सार्वभौमिक मंच है । यू एन डी सी की महत्वपूर्ण बैठक न्यूयार्क में 5-27 अप्रैल,2004 को हुई थी । आयोग में इसकी कार्य-सूची को नहीं अपनाया जा सका, क्योंकि दो महत्वपूर्ण मामलों पर कोई सहमति नहीं हो पाई थी जिसे इसके विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके । हालांकि गुट-निरपेक्ष दल, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य ने विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसमें विचारों की कोई भिन्नता नहीं थी ।

अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

20-24 सितम्बर,2004 तक अन्तर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के महा-सम्मेलन का 48 वां सत्र चला । इसमें आणविक ऊर्ज आयोग के अध्यक्ष डॉ0 अनिल काकोदकर ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया । पिछले कुछ वर्षों की भांति, रेडियोधर्मी स्त्रोतों के बचावों, सुरक्षा और संरक्षण को सुदृढ़ बनाने संबंधी संकल्प अत्यंत विवादास्पद थे । भारत ने भेदभाव किए बिना एजेंसी के समस्त सदस्य देशों के लिए 'बचाव' संबंधी जी सी संकल्प में एक संतुलित दृष्टिकोण को बनाए रखने का प्रयत्न किया । भारतीय शिष्टमंडल ने परमाणु ईंधन चक्रों और चुनौतियों पर वैज्ञानिक मंच के सफल उपाय में भी योगदान किया । भारत ने आइ ए इ ए की संवर्द्धनकारी भूमिका, विशेष तौर पर, अभिनव परमाणु रिएक्टरों और ईंधन चक्रों (इन्प्रो) संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना पर आई ए इ ए के चल रहे कार्य को समर्थन देना जारी रखा है । इस परियोजना के अंतर्गत आयोजित किए गए 14 विषयगत अध्ययनों में से एक इण्डियन एडवान्स्ड हैवी वाटर रिएक्टर (ए एच डब्ल्यू आर) संबंधी विषयगत अध्ययन था ।

डॉ0 मोहम्मद अल बारादेई ने 13-16 नवम्बर,2004 तक भारत का सरकारी दौरा किया । उन्होंने 15 नवम्बर को मुम्बई में हुए भारतीय परमाणु समाज (इनसैक-2004) के 15वें वार्षिक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया और आणविक ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक की । दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान, उन्होंने विदेश सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा विदेश मंत्री से आपसी हित के विभिन्न मामलों पर चर्चा की,जिसमें शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी की पहुँच को बढ़ावा देने में आइ ए इ ए की भूमिका पर चर्चा भी शामिल थी । चर्चा के दौरान, यह कहा गया था कि परमाणु ऊर्जा हमारे ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण स्थान बनाना जारी रखेगी, जिससे आर्थिक प्रगति की तीव्र गति को बनाए रखने की हमारी मंशा जाहिर हुई । महानिदेशक, आइ ए इ ए ने दृढ़तापूर्वक कहा कि एजेंसी के कार्य ने परमाणु ऊर्जा के

शांतिपूर्ण प्रयोगों के संवर्द्धन और अप्रसार उद्देश्यों में योगदान दोनों को सम्मिलित कर लिया है । उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकीय कौशल और विभिन्न आइ ए इ ए क्रियाकलापों में इसके योगदान की सराहना की ।

भारत ने सुरक्षा संबंधी सलाहकार दल (एडसेक) सहित तकनीकी एवं नीतिगत क्षेत्रों में महानिदेशक, आइ ए इ ए द्वारा गठित कई सलाहकार दलों में भाग लेना जारी रखा और हाल में परमाणु ईंधन चक्र के बहुराष्ट्रीयकरण पर विशेषज्ञ दलों को संघटित किया । भारत ने आइ ए इ ए के 48वें महा-सम्मेलन से पहले अमरीका और रूस द्वारा आयोजित ग्लोबलथ्रीट रिडक्शन इनिसिएटिव (जी टी आर आइ) सम्मेलन में भी भागीदारी की ।

रासायनिक हथियार अभिसमय

भारत ने इस वर्ष के दौरान हेग में रासायनिक हथियार पर रोक संबंधी संगठन (ओ पी सी डब्ल्यू) में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा । भारत रासायनिक हथियार (सी डब्ल्यू सी) का एक मूल राष्ट्र पक्ष है।

भारत को 29 नवम्बर-3 दिसम्बर,2004 तक हेग में हुए सी डब्ल्यू सी के राष्ट्र पक्षों के नौवें सम्मेलन में ओ पी सी डब्ल्यू की कार्यकारी परिषद में फिर से सफलतापूर्वक चुन लिया गया था । भारत वार्त्ताओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया, विशेषकर अभिसमय के अनुच्छेद-ज्रूरू (राष्ट्रीय कार्यान्वयन उपाय) की कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अभिसमय के सार्वभौमिक अनुपालन, में प्रभावी ढंग से सम्मिलित रहा । भारत ने हमारे तथा अन्य विकासशील देशों के चिंता के समस्त मामलों को इस सम्मेलन के दौरान तथा कार्यकारी परिषद की बैठकों में भी उजागर किया ।

भारत ने इस अभिसमय के अंतर्गत अपनी समस्त वचनबद्धताओं को पूरा करना जारी रखा । 1997 में ओ पी सी डब्ल्यू के पास रासायनिक हथियार होने की घोषणा के बाद, ओ पी सी डब्ल्यू निरीक्षणों के अंतर्गत अभिसमय के अधीन अनुमानित विनाश समय-सीमाओं में भारत का विनाश प्रयास काफी आगे बढ़ता जा रहा है । श्री रोगलियो फिरतर, रासायनिक हथियार पर रोक संबंधी संगठन (ओ पी सी डब्ल्यू) के महानिदेशक ने 28 मार्च- 4 अप्रैल 2004 तक भारत का दौरा किया । विभिन्न अंतर्सम्पर्कों में, रासायनिक हथियार अभिसमय (सी डब्ल्यू सी) की सफलता तथा इसके पूर्ण एवं प्रभावी कार्यान्वयन में भारत ने अपनी निरंतर रूचि को फिर से दोहराया था ।

जैविक और विषाक्त हथियार

बी डब्ल्यू सी की राज्य पार्टियों की दूसरी वार्षिक बैठक 6-10 दिसम्बर,2004 को जेनेवा में हुई ताकि निम्नलिखित के संबंध में आम समझ और कारगर कार्य पर चर्चा की जा सके और इन्हें बढ़ावा दिया जा सकेः (त) जैविक और विषाक्त हथियारों के दुरूपयोग के मामले या भयावह महामारी के प्रभाव की जांच करने एवं इन्हें कम करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ावा; (त्त) मानव, पशु और पेड़-पौधों को प्रभावित करने वाली संक्रामक बीमारियों की जांच करने, पता लगाने, एवं इनका समाधान करने और इनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत प्रयासों एवं मौजूदा तंत्रों को सुदृढ़ करना एवं व्यापक बनाना । भारत बी टी डब्ल्यू सी की राज्य पार्टियों की वार्षिक बैठक की इस प्रक्रिया का समर्थक रहा है और इसका मानना है कि ये बैठकें राज्य पार्टियों में विचारों एवं राष्ट्रीय अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से आम समझबूझ को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं । राज्य पार्टियों की बैठक की तैयारी करने की दृष्टि से जेनेवा में 19-30 जुलाई,2004 को विशेषज्ञों की एक बैठक हुई थी । भारतीय शिष्टमंडल ने विशेषज्ञों की बैठक में हुई चर्चा पर सक्रिय रूप से भाग लिया और देश की ओर से विस्तृत अभ्यावेदन दिया ।

विशिष्ट पारंपरिक हथियारों संबंधी अभिसमय

भारत कतिपय पारंपरिक हथियारों के उपयोग, जो अत्यधिक घातक या अत्यधिक विध्वंसक प्रभाव वाला माना जा सकता है, पर निषधों या प्रतिबंधों से संबंधित अभिसमय में अत्यधिक प्रभावशाली पक्ष रहा है तथा भारत ने माईन्स, बूबी ट्रैप्स और अन्य साधनों के उपयोग पर निषेधों या प्रतिबंधों संबंधी संशोधित प्रोटाकॉल-रूरू सहित अपने सभी प्रोटोकॉलों का समर्थन किया है ।

सी सी डब्ल्यू संबधी अभिसमय की राज्य पार्टियों का दूसरा समीक्षा सम्मेलन 2001 में हुआ था, जिसमें दो अलग-अलग कार्य समूहों (क) युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के मुद्दे का समाधान करने वाले तौर-तरीके (ख) एंटी-पर्सोनेल माईन्स के अतिरिक्त अन्य माईन्स, में चर्चा करने के लिए सरकारी विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र समूह बनाने का निर्णय लिया गया था । नाम समूह ने युद्ध के विस्फोटक अवशेष संबंधी कार्य समूह की बैठक के समन्वयक के रूप में, सी डी के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व को नियोजित किया । सी सी डब्ल्यू की राज्य पार्टियों की एक बैठक जेनेवा में 18-19 नवम्बर, 2004 को हुई । बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी विशेषज्ञों का समूह 2005 में अपना काम शुरू करेगा । नाम समूह की सिफारिश से यह भी निर्णय लिया गया कि भारत 2005 में विस्फोटक अवशेष संबंधी कार्य समूह की बैठक को समन्वित करना जारी रखेगा । माईन्स, बूबी ट्रैप्स और अन्य साधनों के उपयोग पर निषेध या प्रतिबंध के संबंध

में सी सी डब्ल्यू संबंधी अभिसमय, के संशोधित प्रोटोकॉल-ख्ख् की राज्य पार्टियों की वार्षिक बैठक भी 17 नवम्बर,2004 को जेनेवा में हुई थी । भारत ने संशोधित प्रोटोकॉल-ख्ख् के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए अपने द्वारा किए गए उपायों और लैंडमाईन्स से रहित विश्व के विजन के प्रति अपनी वचनबद्धता के बारे में बैठक की जानकारी दी ।

भारत एक चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से, जो लैंड माईनों के अव्यवस्थित स्थानांतरण और उपयोग से उत्पन्न गंभीर मानवीय समस्या को दूर करते समय राज्यों की वैध रक्षा जरूरतों को पूरा करती है, एन्टी-पर्सोनेल लैंड माईनों पर भेदभाव रहित, सार्वभौम और वैश्विक प्रतिबंध के उद्देश्यों के प्रति हमेशा से वचनबद्ध रहा है । भारत ने "एन्टी-पर्सनेल माईन्स (ए पी एल) " के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और अंतरण पर निषेध और उनके विनाश संबंधी अभिसमय की राज्य पार्टियों के प्रथम समीक्षा सम्मेलन में एक "प्रेक्षक" के रूप में भाग लिया, जो नैरोबी, केन्या में 29 नवम्बर - 3 दिसम्बर, 2004 को संपन्न हुआ था । भारत ए पी एल के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रति अपनी मानवीय चिंता को व्यक्त करता है । किंतु भारत इस अभिसमय में पार्टी नहीं है, क्योंकि यह देशों की वैध सुरक्षा हितों का ध्यान रख पाने में असफल है जो कि वैध सुरक्षा मानदंडों के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्राप्त और सुपरिभाषित सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप सुरक्षा प्रयोजन के लिए लैंडमाईनों के उपयोग को जरूरी बनाता है ।

लघु अस्त्र और हल्के हथियार

भारत लघु हथियारों के प्रसार और उनके अनुचित कारोबार की समस्या के प्रति अत्यंत सजग है और लघु अस्त्र एवं हल्के हथियारों के अवैध कारोबार के संबंध में जुलाई,2001 में संपन्न संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाए गए प्रोग्राम ऑफ एक्शन (पी ओ ए) के कार्यान्वयन सहित इनके प्रभावी समाधान कि लिए अंतर्राष्ट्रीय खोज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए हमेशा से ही वचनबद्ध रहा है ।

भारत के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 56/24 के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा स्थापित ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स ऑन ट्रेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ इलिसीट स्मॉल आर्मस एंड लाईट वीपन्स की अध्यक्षता की। सरकारी विशेषज्ञों के समूह ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि राज्यों को समय पर एवं विश्वसनीय तरीके से अवैध लघु एवं हल्के हथियारों की पहचान करने एवं इनका पता लगाने में समर्थ बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साधन विकसित करना वांछनीय और व्यवहार्य दोनों है । 2003 में महासभा के 58वें सत्र में इस सिफारिश का समर्थन किया गया ।

समय पर और विश्वसनीय तरीके से अवैध लघु एवं हल्के हथियारों की पहचान करने एवं इनका पता लगाने के लिए एक साधन पर चर्चा करने के लिए एक स्वतंत्र कार्य समूह बनाया गया है । लघु एवं हल्के हथियारों की पहचान करने एवं पता लगाने के संबंध में एक साधन पर चर्चा करने के लिए महासचिव द्वारा बनाए गए स्वतंत्र कार्य समूह का प्रथम महत्वपूर्ण सत्र न्यूयार्क में 14-25 जून, 2004 को संपन्न हुआ। सी डी के राजदूत/ पी आर के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने भावी साधन के विभिन्न घटकों पर तकनीकी प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला तैयार की और इससे समूह में विचार-विमर्श को एक नई दिशा देने में मदद मिली । भारत इस चर्चा की प्रक्रिया में हमेशा जुड़ा रहेगा जो सक्रिय रूप से 2005 में शुरू होगा ।

बाह्य अंतरिक्ष मामले

बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का 47 वां सत्र बियाना में 2 से 11 जून, 2004 को संपन्न हुआ । भारतीय शिष्टमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भारत के योगदान का उल्लेख किया और आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पर एक प्रस्तुतीकरण दिया । भारत ने विभिन्न मुद्दों पर विकसित एवं विकासशील दोनों देशों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग किया और अपने हितों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया एवं इसकी सुरक्षा की । समिति ने कानूनी उप-समिति के 43 वें सत्र, जिसकी बैठक पहले हो चुकी थी, की रिपोर्ट की समीक्षा की एवं इसका समर्थन भी किया ।

एशिया में पारस्परिक संपर्क एवं विश्वासोत्पादक उपायों पर सम्मेलन

एशिया में पारस्परिक संपर्क और विश्वासोत्पादन (सी आई सी ए) संबंधी सम्मेलन पर मंत्रालय की बैठक 22 अक्तूबर, 2004 को अलमाटी, कजाकिस्तान में हुई थी । इस बैठक में विदेश मंत्री ने हमारे शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। भारत के अलावा, चीन, रूस, किर्गीस्तान और ताजिकिस्तान के शिष्टमंडलों का प्रतिनिधित्व उनके विदेश मंत्रियों द्वारा किया गया था । थाईलैण्ड के विदेश मंत्री ने भी इसमें भाग लिया था क्योंकि इस बैठक में थाईलैण्ड को सी आई सी ए का नवीनतम संपूर्ण सदस्य बनाया गया था, इस प्रकार यह सी आई सी ए का सदस्य बनने वाला पहला दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश बन गया है । बैठक में एक "विश्वास निर्माण उपायों की सी आई सी ए सूची " और "सी आई सी ए प्रक्रिया नियमावली " तैयार की गई । सचिवालय की स्थापना से संबंधित पहलुओं पर विचार-विमर्श शिखर सम्मेलन तक के लिए टाल दिया गया था, जो आम सहमति नहीं होने के कारण अब 2006 में आयोजित होगा । विश्वास निर्माण उपायों की सूची में अनेक विश्वास निर्माण उपाय शामिल हैं, जिन्हें सदस्य राज्य अपनी स्वेच्छा से तथा क्रमिक आधार पर लागू कर सकते हैं । इनमें

राजनैतिक सैन्य क्षेत्र, नई चुनौतियां और आशंकाएं तथा सामाजिक, आर्थिक और मानवीय क्षेत्र शामिल हैं । बैठक के अंत में, मंत्रियों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें आतंकवाद, डब्ल्यू एम डी प्रसार, अफगानिस्तान, इराक और मध्य-पूर्व के अनेक मुद्दे शामिल हैं ।

ई ए एम ने पूर्ण बैठक के दौरन अपने भाषण में सी आई सी ए की प्रगति को नोट किया तथा इस बात पर बल दिया कि एशिया और उसके बाहर शांति और समृद्धि एक-दूसरे की शक्तियों के आधार पर सहयोगी दृष्टिकोण निर्माण के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती है । ई ए एम ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि आतंकवाद एक गंभीर चुनौती है और सभी सदस्य राज्यों से एक व्यापक और स्थायी प्रयास के माध्यम से इसे दूर करने की मांग की । उसने यह भी नोट किया कि एशिया की विविधता को ध्यान में रखते हुए, बेहतर सामाजिक और आर्थिक संबंध को प्रोत्साहित किया जाना प्रथम वरीयता होनी चाहिए ।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून और गतिविधियां

संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की छठी (विधायी) समिति

चालू सत्र के दौरान, आम सभा की छठी समिति में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं- राज्यों की जिम्मेवारी, राज्यों और उनकी परिसम्पत्ति के अधिकार क्षेत्र की उन्मुक्ति से सम्बद्ध अभिसमय यूएनसीआईटीआरएएल की रिपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर सम्बन्धी विशेष समिति की रिपोर्ट, आतंकवाद समाप्त करने के उपाय, संयुक्त राष्ट्र तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के सुरक्षा सम्बन्धी अभिसमय के अन्तर्गत विधायी सुरक्षा और मानवजाति की पुनःउत्पादक क्लोनिंग के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय।

इस सत्र के दौरान छठी समिति ने दो विधायी दस्तावेजों को पुनः पारित किया जिनके नाम हैं-राज्यों और उनके परिसम्पत्ति के अधिकार क्षेत्र की उन्मुक्ति से सम्बद्ध अभिसमय और दिवालिया कानून सम्बन्धी विधायी गाइड।

छठीं समिति की सिफारिश पर आम सभा ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क), शंघाई सहयोग संगठन, दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, पूर्वी कैरीबियन राज्यों संगठन और पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों आर्थिक समुदाय को आम सभा में पर्यवेक्षक का पद प्रदान करने का निर्णय लिया।

आम सभा में आईएलसी द्वारा तैयार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कृत्यों के लिए राज्य की जिम्मेवारी संबंधी मसौदा अनुच्छेद पर विचार किया गया। चर्चा के दौरान, मसौदा अनुच्छेदों पर आकस्मिक रूप के तौर पर भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए। कई वक्ताओं ने अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय पर बातचीत करने के लिए पूर्णाधिकारियों का एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाने के पक्ष में कहा। कुछ लोगों ने ऐसे सम्मेलन के लिए प्रारम्भिक कार्य शुरू करने के लिए तदर्थ समिति अथवा कार्यदल स्थापित किए जाने का सुझाव दिया। अन्य वक्ताओं ने सन्देह व्यक्त किया कि क्या अभिसमय में अनुच्छेदों को रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि कुछ प्रावधान पहले ही सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून के एक भाग के तौर पर स्वीकृत किए जाने हैं। इसके बाद विचार-विमर्श को आम सभा के 62वें सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया गया है ताकि राज्यों को मसौदा अनुच्छेदों और इससे सम्बन्धित अड़चनों की विधायी पेंचीदगियों को समझने का अधिकाधिक समय मिल जाए।

राज्यों और उनकी परिसम्पत्ति के अधिकार क्षेत्र की उन्मुक्तियों से सम्बद्ध अभिसमय इस सिद्धांत को मानता है कि राज्यों और उनकी इनटिटी अपने वाणिज्यिक लेने-देने के सम्बन्ध में अन्य देशों के न्यायालयों से अधिकार क्षेत्र की उन्मुक्ति को नहीं प्राप्त करते हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ विधायी दस्तावेज द्वारा संयुक्त राष्ट्र और उनसे सम्बद्ध कार्मिकों की सुरक्षा सम्बन्धी अभिसमय के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना जारी रखने का आम सभा द्वारा निर्णय लिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय अपराध-न्यायालय

रोम सांविधि के अस्तित्व में आ जाने के पश्चात हेग में अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कार्यात्मक हो गया है। इस सांविधि के 139 हस्ताक्षरकर्ता हैं जिसमें से 97 देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है। राज्य पार्टी की सभा ने आपराधिक तत्वों और क्रिया विधि के नियमों को तथा प्रांरम्भिक आयोग द्वारा पूर्व में तैयार किए साक्ष्य को स्वीकार किया है। राज्य पार्टी की असेम्बली ने कोर्ट तथा अपने अभियोजन के लिए 18 न्यायाधीशों का चयन किया है। अभियोजन कार्यालय (ओटीपी) ने हाल ही में अफ्रीका में दो जांच-पड़ताल किए हैं। दो राज्य पार्टियों-उगान्डा गणराज्य और कांगो लोकतंत्र गणराज्य ने मामले को मुख्य अभियोजक मि. मोरेनो ओकाम्यों के पास भेज दिया है। काफी गहन विश्लेषण के पश्चात अभियोजक ने दोनों मामलों में जांच करने का निर्णय लिया है।

मानव क्लोनिंग

मानव क्लोनिंग पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय तैयार करने के लिए जनरल असेम्बली द्वारा जो तदर्थ समिति की स्थापना की गयी थी, वह अभिसमय के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने में असमर्थ

रहीं। राज्यों का एक समूह हर प्रकार की मानव क्लोनिंग पर तुरन्त रोक लगा देना चाहता था। भारत सहित अन्य राज्यों ने पुनःउत्पाद क्लोनिंग पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाकर अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज का विस्तार करने के लिए और कदम-दर-कदम आधार पर थेराप्यूटिक क्लोनिंग सहित हर प्रकार के क्लोनिंग के सम्बन्ध में विधायी दस्तावेज की चर्चा और विस्तार करने, अपने देश में थिराप्यूटिक क्लोनिंग की अनुमति दी जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय करने के लिए राज्यों को स्वतन्त्रता प्रदान करने के प्रस्ताव का समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर सम्बन्धी विशेष समिति

संयुक्त राष्ट्र चार्टर सम्बन्धी विशेष समिति और संगठन की भूमिका को मजबूत बनाने के कई प्रस्तावों अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राज्यों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, न्यासी परिषद, अन्य समितियों आदि के साथ समन्वय आदि अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रख-रखाव, विशेष रूप से प्रतिबंधों से बुरी तरह प्रभावित राज्यों को सहयोग देने के सम्बन्ध में विचार किया गया। वर्षों से भारत का यह दृष्टिकोण रहा है कि प्रतिबंध लगाने संबंधी एक भाग के तौर पर सुरक्षा परिषद को प्रभावित तीसरे राज्यों की प्राथमिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। परिषद को शान्ति स्थापा कार्यवाहियां तथा स्वैच्छिक अंशदान को व्यवहार्य पैमाने के आधार पर इस प्रयोजनार्थ "ट्रस्ट फन्ड " की स्थापना करनी चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय

यह स्मरणीय है कि भारत द्वारा प्रस्तावित मसौदे के आधार पर वर्ष 2000 की छठी समिति के कार्यदल के ढांचे के भीतर अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद सम्बन्धी व्यापक अभिसमय के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है। यद्यपि, सिद्धांततः प्रमुख मसौदा अनुच्छेदों पर सहमति हो गई है, जो बकाया मुद्दे रहते हैं उनमें शामिल हैं-अनुच्छेद 2 (अपराध की परिभाषा) अनुच्छेद 2 बिस (क्षेत्रीय अभिसमयों से पूर्व सम्बन्ध) और अनुच्छेद 18 (राज्य के सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों को शामिल न करना) तथापि, मुख्य बकाया मुद्दा "विदेशी व्यवसायें" के विरूद्ध अभिसमय के कृत्यों को लागू करने से हटाने का प्रस्ताव है।

आईएमओ विधायी समिति

आईएमओ की विधायी समिति के समक्ष एक महत्वूपर्ण कार्यसूची समुद्री नौवहन, 1988 की सुरक्षा के विरूद्ध गैर-कानूनी गतिविधियों का दमन करने के लिए अभिसमय के मसौदा प्रोटोकोल पर विचार करना है। यह पहलकदमी वर्ष 2000 में अमरीका पर 9/11 को हुए आतंकवादी हमले के पश्चात की गयी। अमरीका द्वारा तैयार किए गए मसौदा प्रोटोकोल में उन निगमित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एसयूए अभिसमय को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया है जो अपने आप में आतंकवाद से संबद्ध नही है परन्तु " सुरक्षा पहल के प्रसारण " के समावेशन सहित निरस्त्रीकरण और अप्रसार संबंधी मुद्दों के समावेशन से सम्बन्धित है। भारत ने इन संशोधनों का विरोध किया है और आईएमओ परिषद की बैठक की भांति विधायी समिति के 88वें सत्र के दौरान भी अपना मत व्यक्त किया। भारत ने प्रस्तावित संशोधन कार्य के कार्यक्षेत्र के भीतर विधायी समिति के प्रादेश और नाभिकीय अप्रसार संधि से सम्बन्धित सिद्धान्तों की चर्चा से सम्बन्धित कुछ पहलुओं पर भी अपना मत व्यक्त किया।

महासागर और समुद्री कानून

इस मद के अन्दर संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा किए गए कार्य के अन्तर्गत दोहरे प्रकरणों पर जोर दिया गया। पहला समुद्री कानून 1982 पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के प्रावधानों के साथ राष्ट्रीय विधायन का सामंजस्य और दूसरा, समुद्रीय जैविकीय विविधता की सुरक्षा। इस वर्ष के महासागरीय संकल्प का मुख्य आकर्षण, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर समुद्रीय जैविकीय विविधता के संरक्षण तथा स्थायी उपयोग से सम्बन्धित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए कार्यदल की स्थापना करना है क्योंकि आर्थिक तथा इससे बाहर दोनों क्षेत्रों के विनाशक व्यवहारों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए विशिष्ट विधायी और संभारतंत्रीय चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2006 के प्रारम्भ में कार्यदल की बैठक की तैयारी करते समय सचिवालय इन मुद्दों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

यूएनसीआईटीआरएएल

दिवालिया कानून से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र आयोग के कार्यदल ने इस वर्ष के दौरान मसौदा विधायी गाइड को पारित कर दिया। विधायी गाइड में कोर्ट से बाहर की पुनर्संरचना में महत्वपूर्ण उद्देश्यों वाला विवरण तथा सुदृढ़ दिवालिया व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। सामान्य दिवालिया कानून का निर्माण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य परिसमापन की प्रक्रिया में विभिन्न मामलों की प्राथमिकताओं को सन्तुलित करना है। इस निदेशिका में की गई सिफारिश में नाजुक सन्तुलन को बनाए रखने का प्रयास किया गया है।

परिवहन कानून सम्बन्धी कार्यदल इस समय प्रौद्योगिकीय विकास के कारण व्यावहारिक परिवर्तनों से निपटने के लिए समुद्री तथा अन्य माध्यमों से सामानों की अन्तर्राष्ट्रीय ढुलाई से सम्बन्धित मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने के मद्देनजर नए अभिसमय के लिए बातचीत कर रहा है। यह बहु आयामी स्वरूप का समुद्र द्वारा माल ढोने से सम्बन्धित अत्यन्त प्रभावशाली

अभिसमय होगा। चौदहवें सत्र में, ढुलाई के दौरान माल के नुकसान अथवा क्षति की जिम्मेवारी, ठेके की स्वन्त्रता, विवादों, जो प्रस्तावित अभिसमय के प्रावधानों की व्याख्या अथवा उनको लागू करते समय उत्पन्न हो सकते हैं, से निपटाने के लिए तथा अधिकार क्षेत्र और मध्यस्थता से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा की गयी थी।

अन्तर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन

इस प्रभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (आईएचओ) सम्बन्धी अभिसमय की पुनर्संरचना में भाग लिया। इसके पश्चात, अन्तर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन तथा इसके सामान्य तथा वित्तीय विनियमों को स्थापित करके 1956 के अभिसमय को पुनर्जीवित करने तथा उसे व्यापक बनाने के लिए एक नीतिगत योजनागत कार्यदल (एसपीडब्ल्यूजी) की स्थापना की गयी है। इस वर्ष इस प्रभाग ने एसपीडब्ल्यूजी की टोकियो में हुई 5वीं तथा अंतिम बैठक में भाग लिया। बैठक में लिए गए निर्णय पर आईएचओ की अप्रैल 2005 में होने वाले विशेष सम्मेलन में चर्चा की जाएगी।

एएएलसीओ

वर्ष 2004 का आसियान अफ्रीकन विधायी परामर्शदात्री संगठन (एएएलसीओ) का वार्षिक सम्मेलन बाली में 21-25 जून 2004 तक आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान, संगठन ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के निम्नलिखित कई समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया (त) अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के 55वें सत्र में कार्य सम्बन्धी मामलों पर रिपोर्ट (त्त) अन्तर्राष्ट्रीय अपराध-न्यायालय हाल की गतिविधियां और (त्त्त) जन-वार्ता की अभिव्यक्ति और उनकी अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा। एक दिन के विशेष सत्र में व्यक्तियों विशेष रूप से स्त्रियों तथा बच्चों के अवैध व्यापार (ट्रैफिकिंग) से सम्बन्धित मुद्दों पर गहराई से विचार किया गया।

मुक्त-व्यापार करार

मरकोसर के साथ मुक्त-व्यापार करार के अनुपालन में मूल नियम, सुरक्षा के उपाय विवाद निपटारा क्रियाविधि सम्बन्धी करारें तथा रियायतों के आदान-प्रदान के लिए उत्पादों की दो सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। मूल नियम को अंतिम रूप देने के लिए रियायतों के आदान-प्रदान के लिए उत्पादों की सूचियों को अंतिम रूप देने के लिए, एलडीसी को राजस्व हानि के मुआवजे के लिए तन्त्र, तकनीकी सहयोग का प्रावधान और व्यापार के उदारीकरण कार्यक्रम के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए साफ्टा प्रावधानों के समाधान के लिए साफ्टा के अनुसरण में बातचीत हुई। आलोच्य वर्ष के दौरान बीआईएमएसटीईसी देशों के बीच मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किया गया। आसियान तथा थाईलैण्ड और दक्षिण अफ्रीका कस्टम यूनियन के साथ रूपरेखा करारों और खाड़ी सहयोग परिषद के साथ मुक्त व्यापार सहयोग पर विभिन्न चरणों में विचार किया जा रहा है।

निवेश

सार्क के तत्वाधान में, निवेशों के संवर्धन तथा संरक्षण सम्बन्धी सार्क करार को अंतिम रूप देने के लिए भी इस प्रभाग ने बातचीत में भाग लिया। आलोच्य वर्ष के दौरान, लात्विया तथा उरूग्वे के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन करार पर बातचीत हुई। तथापि, बोस्निया, हर्जेगोविना, अजर्बेजान, सेनेगल, स्लोवाक गणराज्य, पापुआ न्यूगिनी और ट्यूनिशिया के साथ द्विपक्षीय बातचीत विभिन्न चरणों में चल रही है। सार्क मध्यस्थता परिषद, जिसमें निवेश सम्बन्धी तथा क्षेत्र के विधायी विवादों को निपटाने की क्षमता है, की स्थापना करने के लिए जांच-पड़ताल पर ली गयी है और करार पर सार्क शिखर बैठक की आगामी बैठक में हस्ताक्षर किए जाने की सम्भावना है।

निजी अन्तर्राष्ट्रीय कानून

यह प्रभाग, भारत को उनकी एक पार्टी बनाने के उद्देश्य से निजी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के हेम अभिसमयों की जांच कर रहा है। इससे इन अभिसमयों के अन्य राज्य पक्षकारों से कई सिविल कानून के क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में भारतीय न्यायालयों तथा पक्षकारों को मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने विदेशी सार्वजनिक दस्तावेज के लिए वैधीकरण की आवश्कयता, 1961 का उन्मूलन करके हेम अभिसमय के दस्तावेज की अभिप्राप्ति को जमा कर दिया है। सिविल अथवा वाणिज्यिक मामलों, में न्यायिक तथा गैर-न्यायिक दस्तावेजों की विदेश सेवा अभिसमय 1965 और सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों, में विदेशी साक्ष्य लेने सम्बन्धी अभिसमय, 1970 चल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल अपहरण 1980 पर हेम अभिसमय के पक्षकार बनने के मुद्दे पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में विधि तथा संधि प्रभाग की भागीदारी

इस प्रभाग ने सांस्कृतिक तत्वों और कलात्मक अभिव्यक्ति की विविधता के संरक्षण से सम्बद्ध यूनेस्को के प्रारम्भिक मसौदा अभिसमय पर अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बैठक में और पेरिस में आयोजित प्रारूपेण समिति की भी बैठक में तथा एशिया में अपहरण तथा सशस्त्र लूटपाट के दमन करने के लिए टोकियो में हुए क्षेत्रीय सहयोग करार के विस्तारण सम्बन्धी अन्तर्सरकारी विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।

इस प्रभाग ने शांति स्थापना से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा करने तथा सशक्त बनाने के लिए भारत तथा यू.के. के बीच संयुक्त कार्यदल की बैठक, आतंकवाद का दमन करने के लिए भारत

तथा इजराइल के बीच संयुक्त कार्यदल की बैठक और आतंकवाद के प्रतिकार के संबंध में बीआईएमएसटीईसी देशों के कार्यदल की बैठक में भाग लिया।

विधि तथा संधि तथा ने विदेशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां, आपराधिक तथा सिविल मामलों में परस्पर विधिक सहायता से सम्बद्ध करारों को अंतिम रूप देने के लिए द्विपक्षीय बातचीत में भाग लिया। परिणाम स्वरूप, कुवैत, कोरिया गणराज्य, बहरीन, फिलीपीन्स गणराज्य के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए। नेपाल तथा ओमान के साथ संधि के अंतिम रूप दे दिया गया है और दोनों हस्ताक्षर के लिए तैयार हैं। इसके अलावा इजराइल, मलेशिया और सेनेगल के साथ संधि पर बातचीत चल रही है। आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता के संबंध में करारों पर बहरीन, हांगकांग और सिंगापुर के साथ बातचीत की गयी और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है। नेपाल, अजरबेजान, जर्मनी, बुल्गारिया, तुर्कमेनिस्तान, मिस्र तथा मलेशिया के साथ करार सम्पन्न करने के लिए पर बातचीत चल रही है। बहरीन तथा कजाकिस्तान के साथ सिविल मामलों में परस्पर विधिक सहायता से संबंधित करारों को अंतिम रूप दिया गया।

इस प्रभाग ने प्रत्यर्पण के कई अनुरोधों और देशी तथा विदेशी अधिकार क्षेत्रों से प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के अन्य अनुरोधों की जांच की और उन पर विधायी सलाह दी।

इस प्रभाग ने सिन्धु नदी की जल संधि के तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और संगत प्रावधानों को लागू करने के लिए तुलबुल नौवहन परियोजना, बगलिहार परियोजना और किशनगंगा परियोजना से सम्बन्धित मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भाग लिया।

इस प्रभाग ने दोहरी राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में विधायी स्थिति की संगतता तथा भारतीय डायस्पोरा के जमाव को ध्यान में रखते हुए पीआईओ (भारतीय मूल के लोगों) की " दोहरी नागरिकता " नामक योजना देने की जांच की।

इस प्रभाग ने विश्व कस्टम यूनियन, क्योतो प्रोतोकोल के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ विकास तंत्र प्राधिकरण की स्थापना, कीटनाशक तथा रसायनों से सम्बन्धित पीआईसी क्रियाविधियों पर रोटरडम अभिसमय के स्वीकृति से सम्बन्धित मंत्रिमंडल नोट पर मत व्यक्त किए।

इस प्रभाग ने राष्ट्रमंडल, अन्टार्कटिका, निजी अन्तर्राष्ट्रीय कानून पर हेम अभिसमय को स्वीकार करने अन्तर्राष्ट्रीय हेलिंग अभिसमय, संसदीय प्रश्नों, अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, मानवाधिकार, शरणार्थी, 111वें अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय यूनियन की बैठक में भाग लेने के लिए आईएचएल का वक्तव्य, क्षेत्रीय समुद्र तथा भारतीय ईईजेड में तेल अण्वेषण के पर्यावरणीय पहलुओं से सम्बन्धित मामलों पर अपने मत व्यक्त किए। अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्बन्धी विषय पर विभिन्न संसदीय प्रश्नों का भी निपटारा किया।

विभिन्न अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विधिक मुद्दों तथा मामलों विशेषकर भारतीय न्यायालयों के समक्ष लागू करने के लिए राजनयिक संबंधों से सम्बद्ध वीयना अभिसमय, 1961, कोंसली संबंधों से सम्बद्ध वीयना अभिसमय, 1963, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अन्तर्गत पासपोर्ट से संबंधित मामलों, भारतीय सिविल क्रियाविधि संहिता जिसमें भारतीय न्यायालयों में विदेशी सरकार के विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति की आवश्यकता हो, की धारा 86 की जाचं की गई।

आलोच्य वर्ष के दौरान विदेशों के साथ भारत द्वारा कई बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संधियां/करारों पर हस्ताक्षर किए गए/समर्थन किया गया है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्क का सामाजिक चार्टर, आतंकवाद के दमन पर सार्क क्षेत्रीय अभिसमय का अतिरिक्त प्रोतोकोल, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर करार, एशिया तथा प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग द्वारा स्वीकृत किए गए एशियाई राजमार्ग नेटवर्क पर अन्तर्सरकारी करार, तम्बाकू नियन्त्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का रूपरेखा अभिसमय, विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों के लिए वैधीकरण की आवश्यकता का उन्मूलन करने वाला अभिसमय, सशस्त्र संघर्ष में बच्चों को शामिल करने सम्बन्धी बाल अधिकार पर अभिसमय का वैकल्पिक प्रोतोकोल, बाल बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल-अश्लीलता सम्बन्धी बाल अधिकार पर अभिसमय का वैकल्पिक प्रोतोकोल, शामिल हैं। एक विस्तृत सूची परिशिष्ट-X में दी गयी है। वर्ष 2004 के दौरान जारी की गयी पूर्ण शक्तियों वाले दस्तावेज की एक सूची परिशिष्ट-IX पर तथा दस्तावेजों के अनुसमर्थन की एक सूची परिशिष्ट-XI पर दी गयी है।

■■

बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध

10

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से एशिया की अर्थव्यवस्था के साथ अपना एकीकरण (इन्टीग्रेसन) बढाने के अपने प्रयास जारी रखे । भारत ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय समूहों में अन्य विकासशील देशों के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने में भी सक्रिया भूमिका निभायी है। यह "पूवोन्मुख" नीति जिसे 1992 में शुरू किया गया था, को आगे बढ़ाती है।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 29-30 नवम्बर 2004 को वियन्ताने, लाओस में हुई तीसरे भारत-आसियान (एसोसिएशन आफ साउथ ईस्टन एशियन नेसन्स) शिखर बैठक में भारतीय शिष्ट-मंडल का नेतृत्व किया। तीसरे भारत-एशिया (इंडिया-आसियान) शिखर बैठक ने बहुमुखी सम्बन्ध को मजबूत बनाने का काम किया और आसियान के साथ दीर्घावधि भागीदारी का ढांचा भी तैयार किया। शिखर-बैठक में भारत आसियान सम्बन्ध जिनकी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों की जड़े गहरी हैं, को सशक्त बनाने में परस्पर रूचि दिखायी। राजनीतिक, सुरक्षा, तकनीकी तथा आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की परस्पर मंशा भी देखी गई।

शिखर बैठक में " शांति, उन्नति तथा साझी समृद्धि की भारत-आसियान भागीदारी " सम्बन्धी करार किया गया जिससे भारत तथा आसियान के बीच भावी सहयोग के लिए एक दृष्टिकोण स्थापित होता है। दस्तावेज की प्रमुख विशेषताएं और इसके साथ संलग्न कार्रवाई योजना में- संयुक्त राष्ट्र पद्धति को सशक्त बनाने और उसमें सुधारने के लिए सहयोग करने, विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य ऐसे बहुपक्षीय में सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की विपदा से निपटने, और ट्रांसनेशनल अपराध निःशस्त्रीकरण, क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय आधारभूत ढांचे के विकास, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास शामिल हैं । शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री ने आस्ट्रेलिया, चीन, इण्डोनेशिया, जापान, लाओस, सिंगापुर तथा वियतनाम के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

शिखर बैठक में, आसियान नेताओं ने आसियान में विकास के अन्तर को पाटने के लिए भारत द्वारा सीएलएमवी देशों (कम्बोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमा और वियतनाम) को प्रदान किए गए सहयोग की सराहना की । विदेश मंत्री ने वियन्ताने में 27 नवम्बर को भारत के सहयोग से स्थापित उद्यमशील विकास केन्द्र का उद्घाटन किया। इसी प्रकार अन्य सीएलएमवी देशों में उद्यमशील विकास केन्द्र के 2005 तक तैयार हो जाने की आशा है। प्रधान मंत्री ने भारत-आसियान सहयोग निधि, जो 2-5 बिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त अंशदान से भारत-आसियान के बीच सहमत परियोजनाओं को वित्त-पोषित करती है, को पूरा करने की घोषणा की। उन्होंने नवगठित आसियान विकास निधि को सिन्द्धान्ततः अपनी मदद देने के लिए कहा।

तीसरी आसियान-भारत व्यापार शिखर बैठक 19-21 अक्तूबर 2004 को नई दिल्ली तथा चेन्नई में आयोजित की गयी। प्रधान मंत्री ने उद्घाटन भाषण दिया। नई दिल्ली में पर्यटन, आधारभूत ढांचे (सड़क, बन्दरगाह, हवाई अड्डे और शहरी आधारभूत ढांचे) वित्तीय सेवाएं और जैव प्रौद्योगिकी सम्बन्धी तथा चेन्नई में कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण, आईटी एवं आईटीईएस, इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण स्वास्थ्य रक्षा एवं फार्मो पर क्षेत्रीय सत्र आयोजित किए गए। इन सभी सत्रों में व्यापक विचार-विमर्श हुआ ।

प्रथम भारत -आसियान कार रैली को 22 नवम्बर 2004 को गुवाहाटी में प्रधान मंत्री द्वारा झंडी दिखाकर शुरू किया गया। रैली के दूसरे-चरण को 30 नवम्बर 2004 को वियन्ताने में प्रधान मंत्री सहित सभी आसियान नेताओं द्वारा झंडी दिखाकर शुरू किया। रैली 11 दिसम्बर को बातम, इण्डोनेशिया में जाकर सम्पन्न हुई। इस पहलकदमी ने भारत-आसियान सम्बन्धों में व्यापक लोक हित का सृजन किया है और आशा है कि इससे संबंधों में वृद्धि तथा भारत - आसियान के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन तथा जन-जन के बीच सम्पर्क बढ़ेगा।

आलोच्य वर्ष में हमारे पारस्परिक हित अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी अन्तरिक्ष और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-आसियान कार्यात्मक सहयोग का विस्तार देखने को मिला है। सूचना प्रौद्योगिकी के एक आसियान अण्वेषात्मक अध्ययन मिशन ने 30 मार्च से 2 अप्रैल 2004 तक भारत का दौरा

किया। जिन क्षेत्रों में सहयोग की पहचान की गयी उनमें शामिल हैं-साइबर सुरक्षा, आईसीटी मानव संसाधन विकास, असहायों के लिए आईटी परियोजना, ई-वाणिज्य और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वि-मैक्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आसियान-भारत कार्यकारी दल की बैठक 11 जून 2004 को सिंगापुर में हुई। प्रगतिशील सामग्रियों, जैस प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चाएं आयोजित की गयी। 24 मई से 4 जून 2004 तक इंडियन इंस्टीट्यूट आफ रिमोट सेन्सिंग, देहरादून में अन्तरिक्ष में आसियान-भारत सहयोग के प्रथम-चरण के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया गया था । 8 आसियान देशों के प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कोर्स में भाग लिया। प्रारम्भिक चरणों में सहयोग के जिन क्षेत्रों की पहचान की गई उनमें पर्यावरण प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेन्सिंग (आईआरएस) की क्षमता का निर्माण और उपयोग करना है ।

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहलकदमी

बीआईएमएसटी-ईसी के उप-क्षेत्रीय ग्रुपिंग के लिए जुलाई 2004 की उल्लेखनीय घटना 31 जुलाई को बैंकाक, थाईलैण्ड में आयोजित प्रथम बीआईएमएसटी-ईसी शिखर बैठक थी। शिखर बैठक में श्री लंका के राष्ट्रपति और बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमा, नेपाल तथा थाईलैण्ड के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। नेपाल और भूटान ने इस शिखर सम्मेलन में इस समूह में भाग लिया । प्रधानमंत्री ने इस शिखर बैठक में भारतीय शिष्ट-मंडल का नेतृत्व किया। शिखर बैठक से पहले सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और विदेश मंत्रियों की बैठक हुई।

शिखर बैठक के परिणाम स्वरूप ग्रुपिंग का नाम बीआईएमएसटी-ईसी से परिवर्तित होकर बीआईएमएसटीईसी (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के लिए बंगाली की खाड़ी की पहलकदमी) हो गया। शिखर बैठक में जिस घोषणा-पत्र को पारित किया गया उसमें व्यापार और निवेश परिवहन और संचार, पर्यटन, ऊर्जा, मानव संसाधन का विकास, कृषि, मत्स्य पालन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और जन-जन से सम्पर्क के क्षेत्र में सहयोग पर विशेष बल दिया गया है। जनस्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण सामुदायिक विकास, लघु तथा मध्यम उद्यम, निर्माण, पर्यावरण, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, मौसम तथा जलवायु अनुसंधान और प्राकृतिक विनाश प्रशमन तथा प्रबन्धन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गयी। शिखर बैठक में परिवहन तथा संचार के आधारभूत ढांचे का विकास, हाइड्रोपावर और हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं और विद्युत की इन्ट्रा बीआईएमएसटीईसी और प्राकृतिक गैस ग्रिड के महत्व को जोड़ने पर सहमति हुई। शिखर बैठक में बीआईएमएसटीईसी पर्यटन पैकेजों, बीआईएमएसटीईसी ट्रैवेल कार्ड/वीजा की शुरूआत, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और सरहद पार आतंक से निपटने में सदस्य देशों के प्रयासों का समन्वय, सांसदों के विनिमयों का संवर्धन, मीडिया के व्यक्तियों, छात्रों और संकाय, खिलाड़ियों इत्यादि के संयुक्त विकास पर भी सहमति हुई। यह शिखर-सम्मेलन परिवहन तथा संचार अवसंरचना, जल विद्युत और हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं के विकास एवं बीआईएमएसटीइसी के भीतर विद्युत और प्राकृतिक गैस ग्रिडों को परस्पर जोड़ने को महत्व देने पर सहमत हुआ । इस शिखर सम्मेलन में बीआईएमएसटीईसी पर्यटन पैकेजों के संयुक्त विकास, बीआईएमएसटीईसी यात्रा कार्ड/वीजा को लागू करने, अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद एवं परा-राष्ट्रीय अपराध की विपदा को रोकने में सदस्य देशों के प्रयासों का समन्वय करने, संसद सदस्यों, मीडिया के व्यक्तियों, छात्रों और संकाय, खेलकूद के व्यक्तियों आदि के आदान-प्रदान को संवर्धित करने पर सहमति हुई ।

बीआईएमएसटीई के देशों के रेलवे के मुख्य कार्यपालकों की प्रथम बैठक रेल मंत्रालय तथा आसियान परिवहन विकास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा 20-21 सितम्बर 2004 तक नई दिल्ली में आयोजित की गयी । यह बैठक बीआईएमएसटीईसी के सदस्य देशों में रेल नेटवर्क के विकास, ट्रांस-आसियान रेलवे-मार्गों, प्रौद्योगिकियों के सामंजस्य और मानव संसाधन विकास से सम्बन्धित मुद्दों का समाधान निकालने के लिए वर्ष 2001 में नई दिल्ली में हुई विशेषज्ञ दल की बैठक की सिफारिशों के अनुपालन में आयोजित की गयी थी। इस बैठक में मानव संसाधन विकास के उद्देश्य से वास्तविक रूप से क्षेत्रीय सहयोगी प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रतिभागियों ने सरकार से बाहर नए संस्थात्मक प्रबन्ध की स्थापना की सिफारिश की जिसमें पर्याप्त निधि का संग्रह करके सहायता पहुंचायी जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ परिवहन विकास संस्थान ने मुख्य पूंजी के तौर पर 20 लाख रू. का अंशदान करने की पेशकश की है जिसकी प्रतिपूर्ति सदस्य देशों से अंशदान द्वारा तथा बहुपक्षीय निकायों से अनुदानों के द्वारा की जाएगी । भारतीय रेल ने सदस्य देशों के रेलवे कार्मिकों को मुफ्त यात्रा की पेशकश की है। बीआईएमएसटीईसी के देशों के रेलवे के मुख्य अधिकारियों की अगली बैठक म्यांमा में आयोजित की जाएगी।

बीआईएमएसटीईसी के आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक 9-10 दिसम्बर 2004 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी । इस बैठक में संयुक्त कार्यदल द्वारा विचारार्थ विषय और " प्रादेश " को पारित किया गया ।

विदेश मंत्री श्री कुं नटवर सिंह, कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री रोह मू-ह्यून की भारत यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात करते हुए, 4-6 अक्तूबर 2004।

BIMST-EC
31 July 2004
Bangkok, Thailand

बी आई एम एस टी ई सी शिखर सम्मेलन की पहली बैठक के दौरान बाएं से दाएं नेपाल के प्रधान मंत्री, म्यामा के प्रधान मंत्री, श्रीलंका की राष्ट्रपति और थाइलेंड, भारत, भूटान और बंगलादेश के प्रधान मंत्री।

क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआर-एआरसी)

क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 5वीं बैठक 26-27 अगस्त को कोलम्बो में हुई । मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले हिन्द महासागर रिम अकादमी ग्रुप, हिन्द महासागर रिम व्यसाय मंच, व्यापार तथा निवेश से सम्बद्ध कार्यदल और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की बैठकें हुईं । भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री श्री ई.अहमद ने किया । मंत्रिपरिषद की पांचवीं बैठक में परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन की नई संकल्पना पर सहमति हुई । इसमें 5 ‍ऽ प्रस्ताव पर विचार किया गया जिसका तात्पर्य यह है कि कम से कम 5 सदस्य राज्यों की आई.ओ.आर.ए.आर.सी. परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा ।

भारत ने हिंद महासागर रिम व्यवसाय फोरम परियोजना के तौर पर 11-12 अगस्त तक ई-वाणिज्य गोल मेज का आयोजन किया। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने दि ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के सहयोग से 2005 के आरम्भ में ही आपदा प्रशमन और प्रबन्धन पर एक कार्यशाला का आयोजन करेगा। आपदा प्रशमन और प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित करने की भारत की पेशकश को पांचवें मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया । रूचि रखने वाले सदस्य राज्यों के लिए लघु, मध्यम तथा माइक्रो उद्यमों के लिए उद्यमशील विकास पर एक-दूसरी कार्यशाला का भी आयोजन भारत द्वारा किया जाएगा।

भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका

भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रियों की पहली बैठक 25 अक्तूबर 2004 में नई दिल्ली में हुई । बैठक में सहयोग की पहल करने के लिए मुख्य बल दिए जाने वाले 4 क्षेत्रोंः (क) एड्स, टीबी तथा मलेरिया के लिए वैक्सीन का विकास (ख) स्वास्थ्य और कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी को लागू करना (ग) नानो-विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा समुद्र-विज्ञान-विज्ञान की पहचान की गयी थी। यह भी निर्णय लिया गया था कि भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी जबकि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्यदल की बैठक प्रत्येक छः महीने में आयोजित की जाएगी। त्रिपक्षीय आयोग की दूसरी बैठक के लिए विकास और तैयारी की समीक्षा करने के लिए भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका फोकल बिन्दुओं की दूसरी बैठक 29-30 नवम्बर 2004 तक नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी।

मेकांग - गंगा सहयोग

पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और परिवहन तथा संचार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मेकांग-गंगा सहयोग 6 देशों-भारत तथा 5 आसियान देशों नामतः कम्बोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमा थाईलैण्ड तथा वियतनाम द्वारा नवम्बर 2004 में वियतनाम में शुरू की गयी एक पहल है। मेकांग-गंगा सहयोग के अन्तर्गत दिल्ली-हनोई रेल लिंक के एक भाग के तौर पर, जिरीबाम (मणिपुर-मन्डाले (म्यांमा) रेल मार्ग के लिए राइट्स (आरआईटीईएस) लि. द्वारा सितम्बर 2004 में एक सम्भाव्यता अध्ययन शुरू किया गया । संस्कृति में सहयोग के एक भाग के तौर पर भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा मेकांग-गंगा सहयोग के देशों का पारम्परिक वस्त्र संग्रहालय स्याम रीप कम्बोडिया में स्थापित किया जा रहा है।

जी-15

समूह - पन्द्रह (जी-15) के संस्थापक सदस्य के तौर पर, भारत ने जी-15 देशों के मध्य आर्थिक, तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जी-15 परियोजनाओं तथा क्रियाकलापों में सक्रिय भूमिका निभाई । भारत कई जी-15 परियोजनाओं अर्थात सौर ऊर्जा को लागू करने, चिकित्सीय तथा एरोमैटिक संयंत्र के लिए जीन बैंक और सेनेमल में उद्यमशील और तकनीकी विकास केन्द्र (ईटीडीसी) की स्थापना करने में सहयोग कर रहा है। नाइजीरिया मशीन टूल के पुररूद्धार के लिए भारत द्वारा 5 मिलियन अमरीकी डालर की मदद से यह परियोजना पूरी होने वाली है।

आर्थिक सहयोग तथां विकास संगठन

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के साथ भारत की अन्योन्यक्रिया में वर्षों से वृद्धि हो रही है। औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग और आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ने 19-21 अक्तूबर 2004 तथा अन्तर्राष्ट्रीय निवेश पर वैश्विक मंच की मेजबानी की । यह विश्व स्तर पर आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन सदस्यों, गैर-सदस्यों तथा अन्य स्टेक होल्डरों के बीच नीतिगत वार्तालाप का एक खुला मंच है। बैठक में प्रतिभागी सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय निवेश गति के मुद्दे पर अपने विचार रखने की अनुमति दी ।

सार्क

जनवरी 2004 में हुई 12वीं शिखर बैठक में तीन दस्तावेजों, सार्क सोशल चार्टर, आतंकवाद सम्बन्धी एक अतिरिक्त प्रोटोकाल और साफ्टा पर एक ढांचागत करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने सार्क देशों में (भारत के बाहर) में गरीबी उन्मूलन

परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करने की पेशकश की।

12वीं शिखर बैठक में गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी स्वतन्त्र दक्षिण एशियाई आयोग से 12वीं शिखर बैठक में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों के लिए सार्क विकास लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए अपनी भूमिका जारी रखने और 13वीं शिखर बैठक में अपनी वास्तविक तथा व्यापक रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तत्पश्चात माले तथा नई दिल्ली में हुई बैठक में आईएसएसीपीए ने 13वीं शिखर बैठक तक एक कार्य योजना की पहचान किया और यूएनडीपी जैसे बाह्य स्रोतों से वित्त-पोषण की मांग की। भारत 21 दिसम्बर 2004 को आईएसएसीपीए रिपोर्ट लांच करेगा। एक क्षेत्रीय गरीबी प्रोफाइल-2004, जो कि दूसरी ऐसी रिपोर्ट है, में सार्क के सदस्य देशों का आर्थिक संकेतकों का ब्यौरा दिया गया है उसे ढाका में 13वीं शिखर बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

भारत द्वारा प्रस्ताव

जुलाई 2004 में इस्लामाबाद में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव (प्रत्येक प्रस्ताव की स्थिति रिपोर्ट कोष्ठक में दी गयी है) पेश किए।

i) दक्षिण एशियाई संसदीय फोरम का गठन : भारत ने सार्क के अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग के प्रयासों से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दक्षिण एशियाई संसदीय फोरम का गठन किए जाने की मांग की और फोरम की अगली बैठक की मेजबानी की पेशकश की। (भारत बजट सत्र 2005 के दौरान फोरम की बैठक की मेजबानी करेगा)

ii) अर्थव्यवस्था, व्यापार, वित्तीय और मौद्रिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से सम्बन्धित विचारों तथा पहलकदमियों का संवर्धन करने के लिए सार्क सदस्य देशों के वित्त और वाणिज्य मंत्रियों के साथ सार्क उच्च आर्थिक परिषद की स्थापना की गयी। (20-23 नवम्बर 2004 को इस्लामाबाद में हुई चौथी सार्क वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में, बांग्लादेश में होने वाले आर्थिक सहयोग सम्बन्धी समिति की 13वीं बैठक, जिसकी तारीख 2005 में तय की जाएगी, के दौरान अपनी टिप्पणियों को विचारार्थ सचिवालय को भेजने के लिए सदस्य राज्यों को कहा)।

iii) सार्क अवसंरचना कोष का गठन, जिसमें क्षेत्र की प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने के लिए लगभग 10 मिलियन अमरीकी डालर का संग्रह होगा। 20-23 नवम्बर 2004 को इस्लामाबाद में हुई चौथी सार्क वाणिज्य मंत्रियों की बैठक ने यह अनुमोदन किया कि प्रथमतया प्रस्ताव की वैचारिक व्यवहार्यता और संभाव्यता के बारे में सार्क वित्त की सलाह (केन्द्रीय बैकों में गवर्नरों का एक निकाय और सार्क के वित्त सचिव) ली जा सकती है।

iv) सदस्य देशों में राष्ट्रीय समितियों के गठन ने सार्क जिसे सामाजिक चार्टर के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के कार्यक्रमों को मानीटर तथा उनका उपाय करने और सार्क गरीबी उन्मूलन निधि की परियोजनाओं सहित सहयोगी गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं का संवर्धन करने के लिए एक-दूसरे के साथ सम्पर्क करने का प्रादेश दिया गया। (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सार्क समकक्षों के साथ सहयोग के लिए नोडल फोकल प्वाइंट के रूप में पहचान की गयी है)

v) टीबी और एचआईवी/एड्स के लिए सार्क जागरूकता वर्ष के एक भाग के तौर पर, परिषद ने टीबी और/अथवा एचआईवी/एड्स के क्षेत्र में " समर्पित सामुदायिक सेवा " के लिए सार्क युवा पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। भारत ने इस वर्ष सार्क देशों के विशेषज्ञों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं की बैठक की मेजबानी करने की पेशकश की और प्रत्येक सार्क देशों को चिकित्सा वाहन और चल जागरूकता यूनिटें भेजने की पेशकश किया। (इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विदेश मंत्रालय के परामर्श से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) द्वारा एक परियोजना तैयार की जा रही है।

vi) भारत ने सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण की पेशकश की है। (भारत ने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित के लिए प्रथम बैठक आयोजित करने के लिए सार्क सचिवालय से सार्क सदस्य देशों को उपयुक्त तारीख सुझाने (बताने) की पेशकश की है)।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (एसएएफटीए) के लिए बातचीत

साफ्टा को जनवरी से दिसम्बर 2004 के दौरान आयोजित 6 बैठकों से प्रगति देखने को मिली है। संवेदनशील सूची को स्पष्ट करने तथा मूल नियम (रूल्स ऑफ ओरिजिन) के अंतर को कम करने में प्रगति हुई है। फरवरी 2005 में होने वाली बैठक में कम विकसित कन्टैक्टिंग स्टेटों (एलडीसीएस-बांग्लादेश,

भूटान, मालदीव तथा नेपाल) के लिए मुआवजे के तन्त्र पर एक वैचारिक पत्र पर चर्चा की जाएगी। तकनीकी सहयोग के लिए कम विकसित संविदाकारी राज्यों (एलडीसीएस) द्वारा किए गए अनुरोध को भारत, पाकिस्तान तथा श्री लंका द्वारा पूरा किया जाएगा। आशा है कि जनवरी 2006 तक साफ्टा को अस्तित्व में लाने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उन देशों को सक्षम बनाकर सभी मुद्दों को जनवरी 2005 तक हल कर लिया जाएगा। 1 जनवरी 2006 तक साफ्टा अस्तित्व में आ जाने से और वर्ष 2016 तक इसके पूर्ण प्रचालन से, हम 2015 तक कस्टमस यूनियन तथा 2020 तक एसएईयू को कार्यान्वित करने के मुद्देनजर सेवाओं और निवेश जैसे आर्थिक एकीकरण के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने में समर्थ होगें। सार्क उच्च आर्थिक परिषद की स्थापना के लिए जुलाई के मंत्रिस्तरीय बैठक में हमारा प्रस्ताव आर्थिक, व्यापार, वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से सम्बन्धित विचारों तथा पहलकदमियों को आगे बढ़ाने के विचार से किया गया था।

साफ्टा के सहारे 13वीं शिखर बैठक के दौरान व्यापार सुविधा उपायों पर हस्ताक्षर किए जाने की सम्भावना है। ये कस्टम मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहयोग, निवेश का संवर्धन तथा सुरक्षा, सार्क मध्यस्थता परिषद की स्थापना और दोहरे कराधान के परिहार एवं कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहयोग से सम्बन्धित हैं।

■■

तकनीकी सहयोग

11

तकनीकी सहयोग प्रभाग एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, खाड़ी के देश और पेसिफिक तथा कैरीबियन क्षेत्र के छोटे द्वीपों के विकासशील देशों को भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम और अफ्रीका योजना के विशिष्ट राष्ट्र मण्डल सहयोग के अन्तर्गत तकनीकी सहयोग प्रदान करने के प्रशासन के लिए जिम्मेवार रहा है। यद्यपि आइटेक कार्यक्रम अधिक सामान्य है, एससीएएपी अफ्रीका के राष्ट्रमण्डल देशों के लिए सिविलियन प्रशिक्षण है। सभी अन्य कार्यक्रम आइटेक के अन्तर्गत आते हैं। आइटेक और स्कैप के अन्तर्गत 15 देश आते हैं, एरिट्रिया आइटेक भागीदार देशों का नवीनतम भागीदार सदस्य है।

तकनीकी सहयोग कार्यक्रम से भारत को अच्छी प्रतिष्ठा मिली है और इससे मानव कौशल तथा तकनीकी और औद्योगिक उन्नति को बढ़ावा मिला है। वर्ष 2004-05 में आइटेक के लिए 30 करोड़ रू., स्कैप के लिए 5.5 करोड़ रू. तथा आपदा राहत सहायता के लिए 5 करोड़ रू. का बजट-आबंटन किया गया है। आइटेक के निम्नलिखित घटक हैं।

(i) प्रशिक्षण (सिविल तथा सैन्य दोनों)

(ii) उपकरण की आपूर्ति, परामर्शी सेवाएं और सम्भाव्यता अध्ययन जैसी परियोजनाओं और परियोजनाओं से सम्बन्धित सहयोग

(iv) भारतीय विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति

(v) भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों/निर्णयकर्ताओं के अध्ययन दौरे

सिविलयन प्रशिक्षण सहयोग का अत्यन्त लोकप्रिय और अत्यन्त प्रभावशाली साधन है जिसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, शिक्षण शुल्क, जीविका भत्ता, अध्ययन दौरा, बीमारी की हालात में चिकित्सा सहयोग और पुस्तक भत्ता जैसे सभी व्यय विदेश मंत्रालय द्वारा वहन किए जाते हैं। सिविलियन प्रशिक्षण के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा, बैंकिंग वित्त तथा लेखा, औषधि और फार्मासिवटिकल, शिक्षा आयोजना और प्रशासन, अंग्रेजी भाषा, उद्यमशीलता, खाद्य प्रौद्योगिकी, जनशक्ति संसाधन आयोजना, सूचना प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता और जनसंचार, श्रम प्रशासन प्रबन्धन, संसदीय अध्ययन, दूर-संवेदी, ग्रामीण विकास लघु उद्योग, स्तरीकरण, लघु व्यवसाय विकास और वस्त्र प्रौद्योगिकी आते हैं।

जबकि आइटेक/स्कैप कार्यक्रम मूल रूप से द्विपक्षीय हैं, हाल ही में, क्षेत्रीय समूहों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आसियान देशों तथा बीआईएमएसटीईसी देशों को अतिरिक्त प्रशिक्षण स्लाट भी मुहैया कराए गए हैं। पहली बार अफ्रीका संघ को भी प्रशिक्षण स्लाट के लिए निर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त आइटेक/स्कैप के अन्तर्गत अनुमोदित इन देशों के कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश की खासतौर से व्यवस्था करायी गयी है। आइटेक-I योजना में हवाई यात्रा, शिक्षण शुल्क, जीविका भत्ता, चिकित्सा तथा अध्ययन दौरों की सम्पूर्ण लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है जबकि आइटेक-II के अन्तर्गत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की लागत को लाभभोगी देशों द्वारा वहन किया जाता है। स्व-वित्त-पोषण तथा परस्पर योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए भी प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक सहयोग प्रभाग का 3400 व्यक्तियों को सिविल प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है जिसके लिए 30 नवम्बर 2004 तक 2698 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 1007 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है। विदेश मंत्रालय के आइटेक/स्कैप कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी नामित को सिविलियन पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं की सूची अनुबन्ध-I में दी गयी है। अप्रैल-नवम्बर 2004 की अवधि के लिए आइटेक/स्कैप के अन्तर्गत निर्दिष्ट और उपयोग किए गए स्लाटों की देशवार स्थिति अनुबन्ध में दी गयी है। अनुबन्ध-III में वित्त वर्ष 2004-05 के व्यय का विवरण दिया गया है।

भारत रक्षा सेवा के सभी तीनों अंगों को देश की चुनिन्दा राष्ट्रीय डिफेन्स कालेज, नई दिल्ली और नेशनल डिफेन्स सर्विसेज स्टाफ कालेज, वेलिंगटन, तमिलनाडु जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत सुरक्षा और नीतिगत अध्ययन, रक्षा प्रबन्धन, आर्टिलरी, इलेक्ट्रानिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैरीन और एरोनाटिकल इंजीनियरिंग, ऐन्टीमैरीन वार फेयर, हाइड्रोग्राफी, संभार तंत्रीय सहायता और प्रबन्धन और गुणवत्ता युक्त सेवाएं जैसे कई क्षेत्र आते हैं।

45वां नेशनल डिफेन्स कालेज पाठ्यक्रम, नई दिल्ली जनवरी 2005 में शुरू किया जाएगा और इस पाठ्यक्रम में 21 विदेशी अधिकारी भाग लेंगे जिसकी अवधि लगभग एक वर्ष है। स्व-वित्त-पोषण योजना के अन्तर्गत विदेशी प्रतिभागियों से प्रत्येक 30000, अमरीकी डालर लिया जाता है और आइटेक और विशेष सहायता योजना (एसएपी) के अन्तर्गत प्रशिक्षिणर्थियों के लिए तकनीकी सहयोग प्रभाग इतनी ही राशि रूपए में भुगतान करता है । 60वें डिफेन्स सर्विसेज स्टाफ कालेज पाठ्यक्रम विलिंगटन कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु जो मई

2004 में शुरू हुआ था, में 30 विदेशी रक्षा अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 8 अधिकारियों को आइटेक के अन्तर्गत और शेष को स्व-वित्त-पोषण योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की गयी । इसके अतिरिक्त, 2004-05 के दौरान 268 स्लाट (124 थलसेना पाठ्यक्रम, 55 वायुसेना तथा 89 नवसेना पाठ्यक्रम) आबंटित किए गए । रक्षा प्रशिक्षण के लिए 10 करोड़ रू. निर्दिष्ट किया गया है और नवम्बर 2003 के अन्त तक 5.50 करोड़ रू. पहले ही व्यय कर दिए गए है। वर्ष 2004-05 के दौरान रक्षा प्रशिक्षण स्लाट का देशवार विवरण अनुबंध-ख्र्ज पर देखा जा सकता है।

आपदा राहत सहायता

आलोच्य वर्ष 2004-05 के दौरान औषधि-आपूर्ति कुछ देशों की आपदा राहत की मुख्य मद रही हैं। इसके लाभभोगी देश वेलीज, निकारगुआ, एलसल्वाडोर, मध्य अमेरिका (14.461 लाख रू.) स्थित गवाटेमाला, जमैका (90 लाख रू.) ग्रेनाडा (22.5 लाख रू.) हैती (4.5 लाख रू.) सूरीनाम (43 लाख रू.) बहमास (22.5 लाख रू.) और डोमिनिकन गणराज्य (22.5 लाख रू.) है। इसके अतिरिक्त, डीपीआरके को 1.67 करोड़ रू. की कीमत का 1000 मि.ट. चावल प्रदान किया जाता है।

परियोजना और आपूर्ति

कम्बोडिया

भारत के उपराष्ट्रपति के कम्बोडिया के प्रधानमंत्री को वचन दिया था, तदनन्तर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से कम्बोडिया स्थित श्याम रीप में टा प्रोहम मंदिर परिसर के संरक्षण और पुनरूज्जीवन के लिए अप्रैल 2002 में प्रधानमंत्री की कम्बोडिया यात्रा के दौरान दोनों सरकारों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस परियोजना के लिए कुल 19.57 करोड़ रू. का अनुमान लगाया है जिसे 10 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। सीएमई ने प्रथम चरण (2003-04, 2004-05) के 3.5 करोड़ रू. अनुमोदित कर दिया है परियोजना के लिए अनुमानित कुल 19.57 करोड़ रू. की राशि को भी सिद्धांततः अनुमोदित कर दिया है। कार्य प्रगति पर है। चयनित कम्यूनियन पार्षदों के उपयोग के लिए में 1000 साइकिलें देने का निर्णय लिया गया है।

इण्डोनेशिया

इण्डोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति ने फरवरी 2000 में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान जकार्ता में निर्माण क्षेत्र के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का भारत से अनुरोध किया था। अप्रैल 2002 में इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति मेगावती के भारत यात्रा के दौरान इण्डोनेशिया तथा भारत सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । इसकी सम्भाव्यता अध्ययन के पश्चात राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन लि. इस केन्द्र की स्थापना में 308.70 लाख रू. की लागत का अनुमान लगाया इस प्रस्ताव की हमारे एकीकृत वित्त प्रभाग तथा विधि मंत्रालय से अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात इस मंत्रालय तथा एनएसआईसी के बीच करार पर 10.7.03 को हस्ताक्षर किया गया था। स्वीकृति आदेश 14.7.03 को जारी किया गया था। समान राशि की बैंक गारंटी के एवज में प्रथम किश्त (अग्रिम भुगतान) के रूप में 4200,000 रू. पहले एनएसआईसी को रिलीज कर दिए गए हैं। एनएसआईसी ने सभी मशीनें और उपकरण भेज दिए हैं और उक्त कार्य को शुरू करने के लिए 6 विशेषज्ञों की भी प्रतिनियुक्ति कर दिया है।

लाओस

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग पर नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत-लाओस संयुक्त आयोग में की गयी चर्चा के अनुरूप, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, एनआईसी के एक विशेषज्ञ को 5 दिनों के लिए अर्थात 2 से 6 जून 2003 तक, सम्भान्यता का अध्ययन करने के लिए लाओस में प्रतिनियुक्त किया गया। कुल लागत 9.6 करोड़ रू. आएगी और परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। 5.5 लाख रू. की लागत सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। पूर्व में की गयी प्रतिबद्धता के अनुपालन में प्रधानमंत्री की नवम्बर 2004 के दौरे के दौरान भारत-लाओस संघ ऐसोसिएशन को 6.54 लाख रू. की कीमत का श्रव्य-दृश्य उपकरण भेंट किया गया है।

यमन

यमन के प्रतिनिधि के साथ किए गए करार के अनुपालन में अल-खोतवा संस्थान को तेज में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने के लिए 1.9 करोड़ रू. की कीमत का उपकरण भेंट किया जाएगा।

जिम्बाब्वे

भारत सरकार द्वारा जिम्बाब्वे सरकार को समूह-15 सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु तथा मध्यम उद्यमों के विकास का वचन दिया गया और उक्त के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर उद्दिष्ट किया गया है। इसलिए, नए सिरे से सम्भाव्यता अध्ययन करने के लिए एचएमटी (ख्र) के दो विशेषज्ञों को अगस्त 2003 दो सप्ताह के लिए जिम्बाब्वे में प्रतिनियुक्त किया गया था। एचएमटी (ख्र) इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेन्सी होगी।

अध्ययन दौरे

नवम्बर 2004 तक कोई अध्ययन दौरा नहीं किया गया है।

विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति

आलोच्य वर्ष के दौरान भारतीय विशेषज्ञों की मांग में वृद्धि हुई है और विभिन्न देशों में प्रतिनियुक्त विशेषज्ञों की संख्या को दो गुना कर दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किए गए विशेषज्ञ, वास्तुकला, डेरी फार्म, चिकित्सा, सुरक्षा, शहरी योजना, दूर-संवेदी, कृषि, टी.वी. ट्रांसमिशन, डब्ल्यूटीओ मामले, आदि जैसे है। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रतिनियुक्त तथा वे विशेषज्ञ भी जिन्हें पूर्व में ही भेज दिया गया है और जिनकी प्रतिनियुक्त की जा रही है का ब्यौरा अनुबंध-ज में दिया गया है।

■■

निवेश और व्यापार संवर्धन

12

आई.टी.पी. प्रभाग ने अपने प्रकाशन “इंडिया रिलाइबिल बिजनेस पार्टनर-एटरेक्टिव एफ.डी.आई.डेस्टीनेशन” में निहित व्यापक सूचना के लिए अनुपूरक सामग्री का समावेश करने और उसे अद्यतन बनाने हेतु निवेश और व्यापार के संबंध में एक विस्तृत ब्रीफ तैयार किया। यह ब्रीफ विदेश में स्थित हमारे सभी मिशनों को परिचालित किया गया ताकि उन्हें हमारे व्यापार और निवेशों से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों सहित भारतीय अर्थव्यवस्था में अद्यतन गतिविधियों के बारे में सूचना मुहैया की जा सके। भारत में विदेशी निवेश को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की नई नीति के भाग के रूप में, इस प्रभाग ने विख्यात प्रकाशन 'यूरो मनी' के प्रकाशक अपने सहयोगी संगठन के

“इन्वेस्ट इन इंडिया 2004” के संबंध में नवम्बर 2004 के विशेष अंक में चार पृष्ठ का एक “इंडिया इंवेस्टमेंट मेनीफेस्टोƒ सह-प्रकाशित किया।

इस प्रभाग ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बैठकों और अर्थव्यवस्था और निवेश कार्यविधियों के सुधार और उदारीकरण में योगदान देने वाली अन्य नीतिगत बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस प्रभाग ने ऊर्जा मामलों के संबंध में हुई सरकारी और गैर-सरकारी बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रभाग इस बात का समर्थन करता रहा है कि भारत को नीतिगत ऊर्जा सुरक्षा के लिए विदेश में पेट्रोलियम और गैस परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करना चाहिए। प्रभाग ने निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार और उद्योग निकायों, वाणिज्य मंत्रालय तथा भारतीय निर्यात संवर्धन मिशनों के साथ अनोन्यक्रिया की। आई.टी.पी.प्रभाग ने सितम्बर 2004 में पूर्व एशिया में हमारे मिशनों में तैनात वाणिज्यिक प्रतिनिधियों द्वारा चेन्नई, बंगलौर, मुम्बई और दिल्ली में भारतीय व्यापार और उद्योग के साथ परस्पर सहयोग के सत्र आयोजित करने में वाणिज्य मंत्रालय के प्रयासों में सहायता की।

यह प्रभाग भारतीय अर्थव्यवस्था और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा आर्थिक कूटनीति को दिए जा रहे महत्व को मीडिया तथा भारत और विदेश में व्यापार समुदाय को जानकारी देता रहा है। इसके एक भाग के रूप में, भारतीय अर्थव्यवस्था और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने में मिशनों को पहले से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रभाग को अपनी नई वेबसाइट www.indiainbusiness.in की क्षमता के संबंध में सकारात्मक सूचना प्राप्त हुई है। यह वेबसाइट पूर्ण रूप से भारतीय कूटनीति के आर्थिक और वाणिज्यिक पहलुओं के प्रति समर्पित है। इस वेबसाइट को भारत में अवसरों के संबंध में वैश्विक निवेशकों तथा व्यवसायियों के उपयोग हेतु व्यापक और संगत सूचना के साथ लगातार अद्यतन किया जाता है।

भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक देश बनाने को बढ़ावा देने के लिए अपने अभियान के भाग के रूप में आई.टी.पी.प्रभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय निवेश संबंधी वैश्विक फोरम (जी.एफ.आई.आई.) द्वारा प्रायोजित ओ.ई.सी.डी.के आयोजन में और भारत में निवेश के संबंध में अक्तूबर, 2004 में नई दिल्ली में हुई बैठक के आयोजन में वाणिज्य मंत्रालय के प्रयासों में सहायता दी। यद्यपि जी. एफ. आई. आई. का मुख्य विषय

“विकास के लिए निवेश भागीदारियां बनाना” था, तथापि, भारत में निवेश संबंधी बैठक में भारत में निवेश के लिए अवसरों तथा नीति संबंधी चुनौतियों पर मुख्यतः विचार-विमर्श किया गया।

आई.टी.पी.प्रभाग ने विदेश मंत्री के निमंत्रण पर 15 अक्तूबर 2004 को भारत की यात्रा पर आए ओ.ई.सी.डी. के महा सचिव श्री डोनाल्ड जे. जॉनस्टोन की मेजबानी की। अपनी यात्रा के दौरान महा सचिव ने प्रधान मंत्री से भेंट की और ओ.ई.सी.डी. तथा भारत के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने तथा परस्पर सहयोग को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की ताकि विशेष रूप से विकासशील देशों के समक्ष आ रही विभिन्न चुनौतियों से निपटा जा सके।

■■

13

नीति नियोजन एवं अनुसंधान

नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय, जिसे पहले संयुक्त आसूचना समिति के रूप में जाना जाता था, के साथ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसके संबद्ध निकायों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में अवस्थित और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अनुसंधान में विशेषज्ञता रखने वाले क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रों के साथ सम्पर्क के लिए नामिक केन्द्र के रूप में भी काम करता है ।

इस प्रभाग ने भारत के बाह्य संबंधों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सम्मेलन, संगोष्ठियाँ आयोजित करने, शोध पत्र तैयार करने, विद्वानों के आदान-प्रदान और ट्रैक-II कार्यक्रमों के लिए सहायता हेतु देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों में स्थित विभिन्न शिक्षा संस्थाओं/विद्यानों को वित्तीय सहायता भी दी । नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित और संस्थाओं/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/सम्मेलनों/बैठकों/अध्ययन परियोजनाओं की सूची परिशिष्ट- XII पर दी गई है ।

विदेश सचिव की पहल पर नीति नियोजन प्रभाग ने मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश फिर से तैयार करने का काम शुरू किया है । इस सारांश में पिछले महीने के दौरान विश्व के अलग-अलग देशों के साथ भारत के संबंधों का व्यापक परिदृश्य शामिल होता है ।

इस प्रभाग के अनुसंधान अनुभाग ने मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के सम्पादन और प्रकाशन का कार्य जारी रखा है । इस रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर सरकार के मत सहित राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शेष विश्व के साथ भारत के सम्पर्क के संदर्भ में एक कम्पैंडियम का कार्य किया है ।

यह अनुभाग, विदेशी प्रकाशनों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के चित्रण का मामला भी देखता रहा है । अशुद्ध चित्रण के मामलों को आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाने हेतु विदेश में स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से संबंधित सरकारों अथवा प्रकाशक के साथ उठाया गया । देश में आयातित किए जा रहे विदेशी प्रकाशनों में भारत की बाहरी सीमाओं के चित्रण की समीक्षा के लिए भी यह प्रभाग उत्तरदायी रहा है और इस मामले को देख रहे मंत्रालयों को प्रभाग ने अपनी सलाह दी है । प्रभाग ने विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी एजेंसियों को भारत के सर्वेक्षक और रक्षा मंत्रालय के साथ उनके सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए मानचित्र शीटों की आपूर्ति का समन्वय भी किया है । अनुसंधान अनुभाग मंत्रालय के अभिलेखों तक पहुँच के लिए शोध छात्रों से प्राप्त अनुरोधों का निपटारा भी करता है ।

अभिलेख प्रबन्धन अनुभाग

मंत्रालय के अभिलेख प्रबंधन अनुभाग में वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों ही प्रकार की लगभग 5 लाख फाइलें मौजूद हैं । अभिलेख प्रबन्धन अनुभाग संबंधित अधिकारियों/अनुभागों/प्रभागों के पास पुरानी फाइलें नियमित रूप से समीक्षा के लिए भेजता रहा है ताकि इन फाइलों को बनाए रखने अथवा हटा दिए जाने के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा। ऐसी 2164 फाइलों को जलाकर नष्ट किया गया जिनकी आगे आवश्यकता नहीं थी ।

विदेश प्रचार

14

समाचार माध्यमों के साथ मंत्रालय के इंटरफेस के रूप में विदेश प्रचार प्रभाग ने विदेश नीति संबंधी मुद्दों पर भारत के मत को सामने लाने का काम जारी रखा । विभिन्न मुद्दों पर सरकार की चिंताओं और दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से प्रचारित किया गया और नियमित एवं विशेष प्रैस ब्रीफिंग, वक्तव्यों, पृष्ठभूमिक टिप्पणियों, वैबसाइट, श्रव्य-दृश्य सामग्री, विवरणिकाओं और पर्चों आदि के माध्यम से इनका व्यापक प्रसार किया गया ।

विदेश प्रचार विभाग ने भारत के हित साधन के लिए विदेश स्थित मिशनों को नवीन एवं अद्यतन सामग्री उपलब्ध कराके सार्वजनिक राजनय को भी मजबूत किया ।

मई, 2004 में सत्ता में आई नई सरकार की विदेश नीति संबंधी वरीयताओं को प्रचारित करने पर विशेष ध्यान दिया गया । नई सरकार की परिणामी सघन राजनयिक गतिविधियाँ उन उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान से परिलक्षित हुई हैं जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भारत की स्थिति को शब्द देने के उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराए । बिम्सटैक शिखर सम्मेलन के लिए बैंकाक की यात्रा के साथ-साथ प्रधान मंत्री की लंदन यात्रा, संयुक्त राष्ट्र आम सभा के लिए न्यूयार्क की यात्रा, भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए द हेग की यात्रा और भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के लिए वेनेसियान (लाओस) की यात्राओं को राष्ट्रीय और दुनिया के अन्य समाचार माध्यमों में व्यापक प्रचार दिया गया । विदेश प्रचार प्रभाग ने अनेक भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं द्वारा लिए जाने वाले प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के साक्षात्कारों की व्यवस्था की । विश्व के प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों की ओर से जिनमें अन्य के साथ-साथ द टाइम्स, टाईम मैगजीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल, चार्ली रोज शो, फाईनेंशियल टाइम्स, कुमरसेंट, रोसिस्काया गेजिटा और टोरंटो स्टार शामिल हैं, ने प्रधान मंत्री के साक्षात्कार प्रकाशित किए ।

हमारे प्रचार संबंधी प्रयासों में जिन प्रमुख मुद्दों पर हमारा ध्यान केन्द्रित रहा, वे मुद्दे हैं - भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता प्रक्रिया, रणनीतिक साझेदारी में अगले कदमों सहित भारत-अमेरिका संबंध और उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह की बैठकें, अपने पड़ोसियों - भूटान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार तथा रूस और चीन जैसे अन्य बड़े राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, अफगानिस्तान को भारत की सहायता, इराक के बारे में भारत की नीति, फिलिस्तीन को भारत का समर्थन । आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के बारे में भारत के दृष्टिकोण तथा आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा की गई प्रगति पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया ।

प्रवक्ता का कार्यालय

संवाददाताओं के लिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन प्रवक्ता के कार्यालय द्वारा की जाने वाली प्रैस ब्रीफिंग, वक्तव्य और प्रैस विज्ञप्तियाँ रहीं तथा पूरी सूचना के साथ समाचार माध्यमों में प्रसारण सुनिश्चित करने में इन्होंने अत्यन्त प्रभावी भूमिका निभाई । इस संबंध में प्रभाग की दृष्टि प्रतिक्रियाशील और पूर्वगामी दोनों ही प्रकार की रही और इनका अनुसरण करते हुए प्रभाग ने समाचार माध्यमों द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी तथा मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर जानकारी का प्रसार किया । अप्रैल, 2004 से जनवरी 2005 तक की अवधि के दौरान आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा लगभग 150 प्रैस ब्रीफिंग आयोजित की गईं या फिर ब्रीफिंग प्वाइंट जारी किए गए । इसके अलावा इसी अवधि के दौरान 150 से अधिक प्रैस विज्ञप्तियाँ और प्रैस वक्तव्य भी जारी किए गए ।

विदेश मंत्री, विदेश सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष मीडिया ब्रीफिंग संबोधित कीं । अपना पदभार ग्रहण करने के बाद विदेश मंत्री ने विदेश प्रचार प्रभाग में प्रैस ब्रीफिंग आयोजित की । साथ ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा छः महीने का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर प्रैस ब्रीफिंग आयोजित की ।

इस वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक गतिविधि इराक में बंधक बनाए गए भारतीयों के संकट के दौरान मीडिया प्रबंधन के बारे में रही । यह सुनिश्चित किया गया कि इस संकट के दौरान मीडिया को मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले वक्तव्यों के माध्यम से नियमित तौर पर अद्यतन स्थिति की जानकारी मिलती रहे । इन वक्तव्यों को वैबसाइट पर भी हाथों-हाथ प्रदर्शित किया गया और ई-मेल के माध्यम से विभिन्न समाचार संगठनों को भी साथ-साथ ही भेजा जाता रहा ।

सुनामी त्रासदी के बाद भारत के राहत प्रयासों को भी उचित प्रचार दिया गया । आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा की जाने वाली नियमित प्रैस ब्रीफिंग के साथ-साथ विदेश सचिव और एकीकृत सेना कमांड के प्रमुख द्वारा एक संयुक्त प्रैस ब्रीफिंग भी आयोजित की गई । सुनामी के बारे में भारतीय मिशनों को नियमित रूप से अद्यतन जानकारी भेजने का काम भी प्रभाग ने किया ।

वैबसाइट

मंत्रालय की वैबसाइट http://meaindia.nic.in को तुरत फुरत अद्यतन किया जाता रहा और इसके लिए वैबसाइट पर नवीनतम प्रेस विज्ञप्तियाँ, ब्रीफिंग, वक्तव्य, दस्तावेज, रिपोर्टें, संसद में प्रश्नोत्तर, साक्षात्कार और संबंधित लेख तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से प्राप्त प्रचालन एवं शैक्षणिक सामग्री भी प्रदर्शित की गई । हमारे द्वारा जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियों के इलैक्ट्रॉनिक रूपांतर अब मीडिया में सूचना के प्रसार के लोकप्रिय और कम लागत वाले साधन बन गए हैं। अनेक पत्रकार इन इलैक्ट्रॉनिक विज्ञप्तियों को सीधे ही हमारे वैबसाइट से लेते हैं जबकि ये इलैक्ट्रॉनिक विज्ञप्तियाँ प्रभाग के डाटाबेस में पंजीकृत लगभग 200 संपर्क सूत्रों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाती हैं । मंत्रालय की मासिक पत्रिका “इंडिया पर्सपेक्टिव्स” तथा प्रभाग द्वारा तैयार किए जाने वाली श्रव्य दृश्य सामग्री के साथ-साथ विभिन्न अन्य प्रकाशन भी वैबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं । प्रभाग अब प्रैस सम्मेलनों और ब्रीफिंग को सीधे ही वैबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने के लिए इनको डिजीटल रूप देने की प्रक्रिया में है ।

सप्ताह की महत्वपूर्ण गतिविधियों को दर्शाने वाले एम ई ए न्यूजवायर साप्ताहिक पत्र के माध्यम से बुद्धिजीवियों, मत निर्माताओं, विचारकों और विश्व भर के भारत प्रेक्षकों को लक्ष्य करके सामग्री दी जाती रही । मिशनों के लिए विदेश प्रचार प्रभाग में उपलब्ध प्रचार सामग्री के बारे में सूचना के स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु एक इलैक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड भी तैयार किया गया है । इस नोटिस बोर्ड के माध्यम से भारत से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में पेशेवर रूप से लिखे गए लेख मिशनों को उपलब्ध कराए गए ।

मीडिया को सुविधा प्रदान किया जाना

भारत की यात्रा पर आए राज्य प्रमुखों/सरकार प्रमुखों के साथ आने वाले विदेशी मीडिया शिष्ट मंडलों को यंत्रोपकरणों और सम्पर्क के संबंध में सहायता एवं समर्थन जुटाने का काम करने के साथ-साथ विदेश प्रचार प्रभाग ने विदेश यात्राओं पर जाते समय राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और उप राष्ट्रपति के साथ जाने वाले भारतीय मीडिया शिष्टमंडलों को भी इस प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कीं । भूटान, कनाडा, चिली, जर्मनी, मलेशिया, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, रूस, सिंगापुर, स्लोवाकिया और श्रीलंका से आने वाले राज्य/शासन प्रमुखों की यात्राओं के संबंध में भारत की यात्रा पर आए मीडिया प्रतिनिधि मंडलों और भारतीय मीडिया को सक्रिय समर्थन प्रदान किया । प्रभाग ने इस प्रकार की सहायता देने के लिए उन्हें मीडिया सलाह जारी की, प्रैस सम्मेलन/प्रैस संपर्क आयोजित किए , समारोह/बैठक स्थलों तक उनकी पहुँच को सुकर बनाया और उन्हें परिवहन एवं आवास संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराईं। इसी प्रकार की सहायता अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, बल्गारिया, बुर्किना फासो, चीन, कोमरोस, कांगो, क्रोएशिया, फ्रांस, गाम्बिया, जर्मनी, ईरान, जापान, कुवैत, मारीशस, मैक्सिको, म्यांमार, नार्वे, पाकिस्तान, रूस, सेनेगल, श्रीलंका, सूरीनाम, थाईलैंड, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला आदि से आने वाले विदेश मंत्री/ मंत्री स्तरीय यात्राओं के दौरान उपलब्ध कराई गई ।

प्रधान मंत्री की तंजानिया एवं दक्षिण अफ्रीका यात्रा, उप राष्ट्रपति की दक्षिण अफ्रीका यात्रा और प्रधान मंत्री की लाओस, थाईलैंड, नीदरलैंड्स, अमेरिका और यूनाईटिड किंगडम की यात्राओं के दौरान इंटरनेट, टेलिफोन, फैक्स तथा अन्य सुविधाओं सहित मीडिया केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से इस प्रभाग ने मीडिया शिष्टमंडलों के काम में सहायता प्रदान की । इसी प्रकार की सहायता कजाखिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, रूस, स्विटजरलैंड, यूनाईटिड किंगडम, अमेरिका और वियतनाम से आए विदेश मंत्रियों की यात्राओं को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों को प्रदान की गई । इस प्रभाग ने विदेशों में काम करने वाले तथा विदेश की यात्रा पर गए भारतीय पत्रकारों को भी सहायता प्रदान की ।

विदेशी मीडिया प्रतिनिधि

भारत में काम करने वाले लगभग 310 विदेशी समाचार एजेंसियों और मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को अपना काम करने में सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रभाग ने उनकी रूचि के मुद्दों पर नियमित ब्रीफिंग के माध्यम से संगत जानकारी और तारीखों आदि के बारे में सूचना दी । इसके साथ ही उन्हें परिचय दस्तावेजों, वीजा, निवास की अनुमति आदि के मामलों में भी सहायता प्रदान की गई । लगभग 300 विदेशी पत्रकारों को वीजा विस्तार और/अथवा प्रत्यायन की सुविधा प्रदान की गई । मई 2004 में हुए आम चुनावों जिन्हें पूरी दुनिया में अभूतपूर्व और व्यापक कवरेज मिला, के दौरान विदेशों से आए 100 से अधिक पत्रकारों को समाचार संग्रहण, मतदान स्टेशनों तक उनकी पहुँच, प्रत्यायन मामलों आदि में सहायता प्रदान की गई ।

विदेशी मीडिया द्वारा यात्राएँ

विदेश स्थित भारतीय मिशनों के समन्वय से विदेश प्रचार प्रभाग ने विदेशी पत्रकारों की भारत यात्राएँ और भारत में स्थित महत्वपूर्ण संस्थाओं तथा उत्कृष्टता केन्द्रों के साथ उनके सम्पर्क दौरे आयोजित किए । भारत की यात्रा पर आए पत्रकारों के लिए अन्य लोगों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों, विद्वत्जनों , शिक्षाविदों और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं । विदेशी समाचार माध्यमों में भारत के बारे में अधिक सटीक और समसामयिक चित्रण के लिए चलाए जा रहे हमारे बहुमुखी प्रयासों के एक प्रमुख तत्व के रूप में ये यात्राएँ उभर कर सामने आई हैं क्योंकि पत्रकार, भारत की विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में अनूठी और मौके पर प्राप्त जानकारी से लैस होते हैं ।

अप्रैल 2004 से जनवरी 2004 तक की अवधि के दौरान इस प्रभाग ने 50 से अधिक पत्रकारों की भारत यात्रा को सुकर बनाया । इन यात्राओं में शामिल हैं - आस्ट्रेलिया, आजरबैजान, बंगलादेश, कम्बोडिया, क्यूबा, चेक गणतंत्र, मिस्र, हंगरी, मारीशस, मैक्सिको, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपींस,

रूस, स्लोवाकिया, श्रीलंका, सूडान, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, यूनाईटिड किंगडम, अमेरिका आदि देशों से आए वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकों द्वारा भारत की परिचय यात्राएँ। कई वर्षों में पहली बार सात पाकिस्तानी पत्रकारों के एक समूह को दस दिन की यात्रा पर आमंत्रित किया गया । इन यात्राओं का अपेक्षित प्रभाव पड़ा और इनसे भारत के बारे में और इसकी विविध उपलब्धियों के बारे में प्रतिष्ठित विदेशी प्रकाशनों में सकारात्मक चित्रण/कवरेज को बढ़ावा मिला ।

श्रव्य दृश्य प्रचार

भारत की प्राकृतिक एंव सांस्कृतिक धरोहर, अर्थव्यवस्था, सामाजिक परंपराओं आदि का चित्रण करने वाली भिन्न-भिन्न प्रकार की विषय वस्तु पर डाक्यूमेंटरी फिल्म तैयार करने के लिए अलग-अलग देशों से प्रभाग को 325 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए । इनमें से 275 से अधिक प्रस्तावों को प्राप्त होते ही अनुमति दे दी गई । शेष प्रस्तावों को आगे प्रक्रमण के लिए अन्य संबंधित मंत्रालयों, राज्यों एवं अन्य संगठनों के पास भेज दिया गया । अपेक्षा है कि फरवरी और मार्च 2005 के दौरान लगभग 50 प्रस्तावों का निपटारा किया जाएगा ।

डाक्यूमेंटरी फिल्मों को तैयार कराया जाना/प्राप्त किया जाना तथा इनकी आपूर्ति किया जाना, डाक्यूमेंटरी फिल्मों की प्रतियाँ तैयार किया जाना और इन्हें नियमित आधार पर/ अनुरोध प्राप्त होने पर भारतीय मिशनों को प्रेषित किया जाना, डाक्यूमेंटरी फिल्मों की विदेशी भाषा में डबिंग किया जाना, पुरानी डाक्यूमेंटरी फिल्मों और फीचर फिल्मों को भारतीय मिशनों तथा विदेशी सरकारों/संगठनों को भेंट स्वरूप/ उधार दिया जाना, फिल्मों को विदेशी भाषाओं में डब किया जाना और उन पर सबटाइटल दिया जाना, फिल्म समारोह और विदेशों में आयोजित भारतीय फिल्म सप्ताहों में सहभागिता के लिए फीचर फिल्मों का प्रापण और आपूर्ति किया जाना, सांस्कृतिक प्रचार और प्रदर्शनियाँ आयोजित किया जाना आदि जैसी कुछ प्रमुख श्रव्य दृश्य प्रचार गतिविधियाँ भी विदेश प्रचार प्रभाग द्वारा की गईं ।

प्रभाग द्वारा तैयार फिल्मों और डाक्यूमेंटरी फिल्मों का उद्देश्य विदेश में भारत की सकारात्मक छवि के प्रसार का है । यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि ये फिल्में भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक बनें । अप्रैल 2004 से जनवरी 2005 के दौरान 12 डाक्यूमेंटरी फिल्में पूरी की गईं (देखें ऊपर दिया गया विवरण) । "एन इनडिवाइजिबिल यूनिटी", "अनेक रस (भारत और इंडोनेशिया)" , "पत्थर में अमृत" , "मध्य पूर्व में भारतीय मूल के लोग", "भारत आसियान कार रैली", "इंडियन हैरीटेज साइट्स इन अदन", "शांति रक्षक" और जम्मू कश्मीर के बारे में 24 अंकों वाली एक डाक्यूमेंटरी फिल्म तैयार होने और दर्शाई जाने के लिए लगभग तैयार है। कुछ अन्य डाक्यूमेंटरी फिल्में भी तैयार की जाने वाली हैं ।

25 मिनट की एक लघु फिल्म "डेमोक्रेसी इन एक्शन" जिसमें भारत की मतदान प्रक्रिया और इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग अर्थात् इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रयोग का चित्रण किया गया है , मई 2004 में तैयार की गईं । इस फिल्म का प्रयोग हमारे मिशनों द्वारा व्यापक तौर पर किया गया और अनेक देशों में इसे प्रसारित किया गया ।

डाक्यूमेंटरी फिल्में

- भारतीय कविता में कश्मीर
- रूह पंजाब दी
- आत्म चित्रण
- खेल के मैदान का पुनर्निमाण - भारत में बाल श्रम का निवारण
- भारत में रोमांचक खेल
- स्टेप्स एंड स्ट्राइड्स
- भारत एवं आसियान - प्रगति में सहभागी
- भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति
- टाइमलैस फ्रैंडशिप - इंडो अफगान रिलेशन्स
- अ ब्रिज सो नियर - भारत - भूटान संबंध
- लाइफ एनकोडिड - बायोटैक्नोलॉजी - द इंडियन एफर्ट
- इंडियन लिजेंड्स

विदेश प्रचार प्रभाग द्वारा तैयार कराई गई "द सोल कनेक्शन" और "भारत एवं आसियान - प्रगति में सहभागी" नामक डाक्यूमेंटरी फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग अप्रैल और दिसम्बर 2004 में क्रमशः नई दिल्ली में काम करने वाले राजनयिक समुदाय के लिए और कला एवं सिनेमा जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ-साथ विदेशी मीडिया कार्मिकों के लिए आयोजित की गईं । विदेश प्रचार प्रभाग ने जुलाई 2004 में नई दिल्ली में आयोजित छठे सिनेफैन समारोह और गोवा में नवम्बर -दिसम्बर 2004 में आयोजित भारत के 35वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन में भी सहायता प्रदान की ।

भारतीय फीचर फिल्म समारोह/फिल्म सप्ताहों का आयोजन अर्जेंटीना (ब्यूनस आयर्स), आजरबैजान (बाकू), ब्राजील (ब्रासिलिया एवं साओ पालो) , बल्गारिया (सोफिया), चेक गणराज्य (प्राहा), फ्रांस (पेरिस), जमैका (किंगस्टन) , केन्या (नैरोबी), किर्गीजिस्तान (बिश्केक), म्यांमार (यंगून एवं मांडले), पेरू (लीमा), फिलीपींस (मनीला), रूस (मास्को), स्पेन (मेड्रिड), ताईवान (ताईपेई), तुर्कमेनिस्तान (अश्गाबात), अमेरिका (वाशिंगटन, शिकागो), उज्बेकिस्तान (ताशकंद), वेनेजुएला (काराकस) तथा यूगोस्लाविया (बेलग्राद) में किया गया ।

मंत्रालय द्वारा प्राप्त की गई/तैयार कराई गई डाक्यूमेंटरी फिल्मे विदेशी टीवी चैनलों पर गैर वाणिज्यिक प्रसारण के लिए मिशनों में भी भेजी गई । इनमें से कुछ डाक्यूमेंटरी फिल्में बहरीन, भूटान, केन्या, लाओस, मलेशिया, नामीबिया, रोमानिया, तंजानिया और वियतनाम में विदेशी टीवी नेटवर्क पर हमारे

मिशनों के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप दिखाई गईं । इसके अलावा बीटाकैम कैसेटों, सीडी रोम, ऑडियो एवं वीडियो सीडी, डीवीडी तथा कैसेटों के रूप में श्रव्य दृश्य सामग्री भी पुस्तकालय में रखने के लिए और भेंट स्वरूप देने के लिए मिशनों में भेजी गई । भेजी गई सामग्री मिशनों की जरूरतों के अनुरूप थी और इसका चयन भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सावधानीपूर्वक किया गया । श्रव्य दृश्य उपकरणों और अन्य हार्डवेयर जैसे टीवी, वीसीआर, डिश एंटीना आदि के बारे में हमारे मिशनों से तथा मंत्रालय के कार्यालयों से प्राप्त अनुरोधों पर संस्वीकृति के लिए प्रभाग ने प्रस्तावों का प्रक्रमण किया ।

इस अवधि के दौरान भारत में बौद्ध स्थलों एवं कला विरासत के बारे में "द पाथ आफ कम्पेशन" विषय पर एक फोटो प्रदर्शनी बैंकाक, बीजिंग, बेलग्राद, बर्लिन, कोलम्बो, हनोई, मनीला, मास्को (5 सेट), पेरिस, नोम पेन्ह, टोकियो (2 सेट), उलनबातर (2 सेट), वाशिंगटन और यंगून स्थित भारतीय मिशनों में भेजी गई । पुराने गोवा के गिरजाघरों के बारे में "वेला गोवा" नामक एक अन्य फोटो प्रदर्शनी बर्लिन, कोपेन हेगन, डबलिन, लीमा, लिस्बन, मास्को, पेरिस, रोम और सेनफ्रांसिस्को स्थित भारतीय मिशनों को भेजी गई । विदेश प्रचार प्रभाग के श्रव्य दृश्य पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर उपलब्ध ट्रांस्पेरेंट शीटों की प्रतिलिपियाँ तैयार करके मिशनों से अनुरोध प्राप्त होने पर उन्हें भेजी गईं ।

विज्ञान भवन के प्रदर्शनी कक्ष में नवम्बर 2004 में विदेश प्रचार प्रभाग द्वारा पंचशील पर आयोजित एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन विदेश मंत्री ने किया । प्रदर्शनी में नई दिल्ली स्थित विदेशी मिशनों के राजनयिकों सहित भारतीय और विदेशी उच्चाधिकारियों ने हिस्सा लिया । नई दिल्ली में भारत - भूटान मैत्री पर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन मार्च 2005 में किए जाने की योजना पर काम चल रहा है ।

इंडिया पर्सपेक्टिव्स

विदेशों में मंत्रालय के प्रचार संबंधी प्रयासों की ध्वजवाहक पत्रिका के रूप में इंडिया पर्सपेक्टिव्स पत्रिका अपनी भूमिका निबाहती रही । इस पत्रिका का उद्देश्य एक ओर जहाँ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने का है वहीं दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा मानव उद्यम के अन्य संगत क्षेत्रों में भारत द्वारा लगाई गई लंबी छलाँग के बारे में भी उचित जानकारी प्रसारित करने का है । इसका प्रकाशन 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में किया जाता है ताकि यह दुनिया के लगभग हर कोने तक अपनी पहुँच बना सके । इस पत्रिका में विविध क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का चित्रण करने के लिए भारत में जीवन के विभिन्न आयामों को समेटते हुए सावधानीपूर्वक लिखे गए चुनिंदा लेख शामिल किए जाते हैं । देश में विभिन्न गंतव्य स्थलों के बारे में सुन्दरता पूर्ण ढंग से विस्तृत विवरण देते हुए लिखे जाने वाले लेखों द्वारा भारत की व्यापक पर्यटन संभावनाओं का दोहन करने में भी इस पत्रिका से मदद मिलती है । इस पत्रिका का एक लक्ष्य, सधे हुए ढंग से भारत की विदेश नीति संबंधी दृष्टिकोण को सामने लाने का भी है।

विशेष प्रकाशन, विवरणिकाएँ एवं पुस्तकें

प्रकाशित विवरणिकाएँ

- सेलीब्रेटिंग डैमोक्रेसी
- इंडिया - स्क्रिप्टिंग फ्यूचर हिस्ट्रीज (जर्मन एवं बर्मी भाषा में)
- पंचशील
- आम चुनाव 2004
- अफगान्स फर्स्ट - अफगानिस्तान में सक्रिय भारत (जर्मन में)
- ब्रिजिंग द ओशन - सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई
- भारतः एक गतिशील लोकतंत्र

इंडिया पर्सपेक्टिव्स के वर्तमान एवं पुराने अंक इलैक्ट्रॉनिक रूप में पाठकों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। दुनिया भर से पाठकों की प्रतिक्रिया के अनुसार देखा जाए तो हर माह इस पत्रिका की उत्सुकता से प्रतीक्षा की जाती है और इसने अपने लिए एक निश्चित स्थान बना लिया है । अभी भारत ने गुरू ग्रंथ साहब की 400वीं जयंती मनाई है इसलिए दिसम्बर 2004 के अंक में पत्रिका का यह प्रयास रहा है कि समय की कसौटी पर खरे उतरे इस महान ग्रंथ की महत्ता और युक्तियुक्तता पर प्रकाश डाला जाए ।

विदेश प्रचार प्रभाग महत्वपूर्ण मुद्दों एवं घटनाओं के बारे में विशेष प्रकाशन निकालता है । ऊपर दी गई विवरणिकाओं के अलावा बारहवें सार्क शिखर सम्मेलन, प्रथम बिम्सटैक शिखर सम्मेलन (जुलाई 2004), प्रधान मंत्री की लंदन एवं न्यूयार्क यात्रा (सितम्बर 2004) तथा राष्ट्रपति की तंजानिया संघी गणराज्य एवं दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की यात्रा (सितम्बर 2004) के बारे में भी विशेष प्रकाशन अप्रैल 2004 और जनवरी 2005 के बीच निकाले गए ।

हाल ही के वर्षों में पहली बार विदेश प्रचार प्रभाग ने इंडिया टुडे प्लस के सहयोग से एक उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की जिसका शीर्षक है "इंडिया - मूड्स एंड मैमोरीस" । विख्यात व्यक्तियों द्वारा भारत के विभिन्न आयामों के बारे में लिखे गए लेखों वाली इस पुस्तक की तीन हजार प्रतियाँ वितरण के लिए भारतीय मिशनों में भेजी जा रही हैं ।

इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर रघु राय द्वारा लिए गए छाया चित्रों के संकलन वाले एक प्रकाशन "विश्व धरोहर स्थलों के माध्यम से भारत की छवि" की पाँच सौ प्रतिलिपियाँ भी तैयार कराई जा रही हैं ।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों को उनकी जरूरत के आधार पर प्रभाग ने अनेक पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ प्रेषित कीं।

प्रोतोकोल

15

पहले से अधिक संख्या में देश से बाहर की जाने वाली उच्च स्तरीय यात्राओं और बाहर के देशों से भारत की यात्राओं, सम्मेलनों, परिचय पत्र प्रस्तुति समारोहों, राजकीय अतिथि सत्कार और अन्य बहुआयामी समारोहों के काम में प्रोतोकोल प्रभाग लगा रहा । विदेशी उच्चाधिकारियों की बड़ी संख्या में होने वाली यात्राओं को सँभालने की प्रोतोकोल प्रभाग की योग्यता ने भारत की उद्भवशील अंतर्राष्ट्रीय छवि में योगदान किया । प्रोतोकोल मानदंडों एवं मानकों को सुचारू बनाने पर लगातार ध्यान दिया जाता रहा ।

कार्यकाल पूरा होने पर 01 अप्रैल, 2004 से 28 फरवरी, 2005 तक की अवधि के दौरान भारत छोड़कर गए विदेशी राजदूतों/उच्चायुक्तों की सूची

नाम	प्रस्थान की तिथि
महामहिम प्रो. अशीर अताएव, तुर्कमेनिस्तान के राजदूत	03 अप्रैल 2004
महामहिम श्री जइम इनफांते, कोलम्बिया के राजदूत	1 जून 2004
महामहिम डॉ. नूरी अल फितूरी अलमदनी, लीबियाई अरब जम्हीरिया समाजवादी महा गणराज्य के राजदूत	3 जून 2004
महामहिम श्री अलेक्जेंडर एम कदाकिन, रूसी परिसंघ के राजदूत	2 जुलाई 2004
महामहिम वाल्टर गाइजर, स्विट्जरलैंड के राजदूत	20 जुलाई 2004
महामहिम प्रोफेसर मोजिज मोसोंदा, जाम्बिया गणराज्य के उच्चायुक्त	27 जुलाई 2004
महामहिम श्री मोहम्मद लुआफा, मोरक्को साम्राज्य के राजदूत	3 अगस्त 2004
महामहिम श्री अश्कर ओ शकिरोव, कजाकिस्तान गणराज्य के राजदूत	13 अगस्त 2004
महामहिम श्री फिलीप मेक दोना, आयरलैंड के राजदूत	18 अगस्त 2004
महामहिम श्रीमती वीरा बारोइन मेकाडो, ब्राजील संघीय गणराज्य की राजदूत	19 सितम्बर 2004
महामहिम डॉ. सईद एम अल शमशी, संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत	9 अक्तूबर 2004
महामहिम श्री लादेशलाव वोल्को, स्लोवाक गणराज्य के राजदूत	15 अक्तूबर 2004
महामहिम श्री जूलियो फेजलर कार्लसिल, मैक्सिको के राजदूत	31 अक्तूबर 2004
महामहिम श्री मून सोंग मो, लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया के राजदूत	8 नवम्बर 2004
महामहिम सुश्री पेनी वेंसले, आस्ट्रेलिया की राजदूत	21 नवम्बर 2004
महामहिम श्री एनरिक एनकरदूकि, उरूगवे के राजदूत	22 नवम्बर 2004
महामहिम श्री हुआ जून दू, चीनी लोक गणराज्य के राजदूत	24 नवम्बर 2004
महामहिम श्री आरमैन बेबूरशियान, आर्मीनिया गणराज्य के राजदूत	2 दिसम्बर 2004
महामहिम डॉ. इब्रोखीम मावलोनोव, उज्बेकिस्तान गणराज्य के राजदूत	11 जनवरी 2005
महामहिम श्रीमती मैते ई नोआना माशाबानी, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की उच्चायुक्त	22 जनवरी 2005
महामहिम श्री अलीजेन्द्रो गारीदो ए, पनामा के राजदूत	02 फरवरी 2005

01 अप्रैल, 2004 से 28 फरवरी, 2005 की अवधि के दौरान अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले विदेशी राजदूतों/उच्चायुक्तों की सूची

नाम	परिचय पत्र की प्रस्तुति की तारीख
महामहिम श्री मून सोंग मो, कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के राजदूत	7 मई 2004
महामहिम श्री अमादू बोकोम, सेनेगल गणराज्य के राजदूत	7 मई 2004
महामहिम श्री खलफ अब्बास खलफ अल फोदारी, कुवैत राज्य के राजदूत	7 मई 2004
महामहिम श्री चोई जूंग इल चोई, कोरिया गणराज्य के राजदूत	7 मई 2004
महामहिम श्री लूक रोकोवादा, फिजी के उच्चायुक्त	7 मई 2004
महामहिम श्री वुक जूगिच, सर्बिया और मोन्टेनिग्रो के राजदूत	7 मई 2004
महामहिम श्री एंटोनियो आर्मेलिनी, इटली के राजदूत	7 मई 2004
महामहिम श्री हैरी मुत्तुमा कथूरिमा, केन्या गणराज्य के उच्चायुक्त	7 मई 2004
महामहिम सुश्री इंगा एरिक्सन फो, स्वीडन के राजदूत	7 मई 2004
महामहिम अब्बु बकर गरबा अब्दुल्लाहीमिनी नाइजीरिया संघीय गणराज्य के राजदूत	5 अगस्त 2004
महामहिम श्रीमती मिलेना सांतना रमीरेज, वेनेजुएला बोल्वीरियन गणराज्य के राजदूत	5 अगस्त 2004
महामहिम श्री दातो जुलकीफलाई इब्राहिम अब्दुल रहमान, मलेशिया के उच्चायुक्त	5 अगस्त 2004
महामहिम श्री बालमून कुन्ना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राजदूत	5 अगस्त 2004
महामहिम श्री ब्रूनो क्लाउदे फ्रैडरिक रानारिवेलो, मेडागास्कर के अनिवासी राजदूत	5 अगस्त 2004
महामहिम श्री ग्राम चार्ल्स वाटर्स, न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त	29 सितम्बर 2004
महामहिम श्रीमती उषा चाँदनी द्वारिका कनबादी, मारीशस गणराज्य की उच्चायुक्त	29 सितम्बर 2004
महामहिम श्री एस के वालूबिता, जाम्बिया गणराज्य के उच्चायुक्त	29 सितम्बर 2004
महामहिम श्री ईवान नेमेत, हंगरी गणराज्य के राजदूत	29 सितम्बर 2004
महामहिम श्री चारी जी नियाजोव, तुर्कमेनिस्तान गणराज्य के राजदूत	29 सितम्बर 2004
महामहिम श्री केरात ई उमारोव, कजाकिस्तान गणराज्य के राजदूत	29 सितम्बर 2004
महामहिम श्री गिलबर्ट ब्लुलेन, कोट डी आईवरी के राजदूत	29 सितम्बर 2004
महामहिम श्री किरण दाउलिंग, आयरलैंड के राजदूत	29 सितम्बर 2004
महामहिम डॉ. तेमरलेन एलमार ओग्लू काराऐव, आजरबैजान गणराज्य के राजदूत	30 नवम्बर 2004
महामहिम श्री डोमेनिक ड्रैयर, स्विटजरलैंड के राजदूत	30 नवम्बर 2004
महामहिम श्री अलेक्जेंडर इलास्किक, स्लोवाक गणराज्य के राजदूत	30 नवम्बर 2004
महामहिम श्री पैड्रो डी बेयोत गोरी, कोलम्बिया के राजदूत	30 नवम्बर 2004
महामहिम श्री हान चांग ओन, कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के राजदूत	30 नवम्बर 2004
महामहिम लेफ्टिनेट जनरल (सेवानिवृत्त) अम्बारी अब्दुल सत्तार अदम, मालदीव गणराज्य के राजदूत	30 नवम्बर 2004
महामहिम श्री जोश विसेंत दे सा पाइमेन्तेल, ब्राजील संघीय गणराज्य के राजदूत	30 नवम्बर 2004
महामहिम श्री व्याचेस्लाव इवानोविक त्रूविनकोव, रूसी परिसंघ के राजदूत	18 जनवरी 2005
महामहिम श्री अरनेस्टो कार्लोस अलवारेज, अर्जेटीना गणराज्य के राजदूत	18 जनवरी 2005

महामहिम श्री जॉन मैकार्थी आओ, आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त	18 जनवरी 2005
महामहिम श्री रोजेलिया ग्रॉगीलहोम, मैक्सिको के राजदूत	18 जनवरी 2005

महामहिम श्री सून यू ची, चीनी जनवादी गणराज्य के राजदूत 18 जनवरी 2005 उन देशों के नाम जिन्होंने नीचे दी गई तिथियों को दिल्ली में अपने आवासी मिशन खोले

ताजिकिस्तान गणराज्य दूतावास	09 अक्तूबर 2003
फिजी गणराज्य उच्चायोग	02 जनवरी 2004
गयाना गणराज्य उच्चायोग	25 अक्तूबर 2004
मालदीव गणराज्य उच्चायोग	17 नवम्बर 2004
आजरबैजान गणराज्य दूतावास	01 दिसम्बर 2004
लिसोथो साम्राज्य उच्चायोग	जनवरी 2005
एक्वेडोर गणराज्य दूतावास	04 फरवरी 2005

2004 में की गईं यात्राएँ

शासन प्रमुखों/राष्ट्र प्रमुखों/उप राष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर के उच्चाधिकारियों द्वारा की गई राजकीय यात्राएँ

उच्चाधिकारी का नाम	**दिनांक**
महामहिम श्री भरत जगदेव, गयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति	06 से 13 जनवरी 2004
महामहिम शेख खलीफा बिन समान अल खलीफा, बहरीन के प्रधान मंत्री	11 से 19 जनवरी 2004
महामहिम श्री नामबरीन ऐख बायर, मंगोलिया के प्रधान मंत्री	14-19 जनवरी 2004
महामहिम श्री लुई इनाशियो लूला द सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति	25 से 28 जनवरी 2004
महामहिम श्री इयान इलियासकू, रोमानिया के राष्ट्रपति	28 जनवरी से 01 फरवरी 2004
महामहिम श्री गोह चोक तोंग, प्रधान मंत्री, सिंगापुर	8-11 जुलाई, 2004
महामहिम श्री रोह मु ह्यून, कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति	4-6 अक्तूबर 2004
महामहिम श्री गेरहार्ड श्रोडर, जर्मनी के राष्ट्रपति	6-7 अक्तूबर 2004
महामहिम सुश्री हेलेन क्लार्क, न्यूजीलैंड की प्रधान मंत्री	17-20 अक्तूबर 2004
महामहिम सीनियर जनरल थान श्वे, चैयरमेन - म्यांमार	24-29 अक्तूबर 2004
महामहिम श्री इवान गासपरोविक, स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति	11-16 दिसम्बर 2004
माननीय श्री अब्दुला अहमद बदावी, मलेशिया के प्रधान मंत्री	19-23 दिसम्बर 2004
महामहिम श्री रिकार्डो लागोस, चिली गणराज्य के राष्ट्रपति	18-22 जनवरी 2005

शासन प्रमुखों/राष्ट्र प्रमुखों/उप राष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर के उच्चाधिकारियों द्वारा की गई आधिकारिक/कार्यकारी यात्राएँ -

महामहिम श्री गोरान पर्सन, प्रधान मंत्री - स्वीडन की कार्यकारी यात्रा	09-11 जनवरी, 2004
महामहिम पारसबीर विक्रमशाह देव, नेपाल के राजकुमार की शासकीय यात्रा	18 जनवरी से 01 फरवरी 2004
महामहिम श्री अमानी आबीद कारूमे, जंजीबार के राष्ट्रपति	07-12 मार्च 2004
महामहिम श्री आयातुल्ला हाशिमी शाहरूदी, न्यायपालिका के प्रमुख	09-15 मार्च 2005

महामहिम श्री महेन्द्र राजपक्षे, श्रीलंका के प्रधान मंत्री	17-19 जुलाई 2004
माननीय श्री शेरबहादुर देऊबा, प्रधान मंत्री, नेपाल	8 -12 सितम्बर 2004
महामहिम श्रीमती चंद्रिका भंडारनायके, श्रीलंका की राष्ट्रपति	4-7 नवम्बर 2004
महामहिम श्री शौकत अजीज, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री	23-24 नवम्बर 2004
महामहिम श्री आगा खां	24 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2004
महामहिम भूटान नरेश	24-29 नवम्बर 2004
महामहिम श्री ब्लादिमीर वी. पुतिन, रूसी संघ के राष्ट्रपति	03 - 05 दिसम्बर 2004
महामहिम श्री द्रिश जेतु, मोरक्को के प्रधान मंत्री	6-9 दिसम्बर 2004

विदेश मंत्री एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों द्वारा शासकीय यात्राएँ

माननीय जे.के. कोतारी, विदेश मंत्री, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं क्षेत्रीय सहकारिता मंत्री, मारीशस	06-11 जनवरी 2004
मध्य अमेरिकी एकता प्रणाली (एस.आई.सी.ए.) के मंत्री एवं प्रतिनिधियों की यात्रा	01-05 फरवरी 2004
माननीय जेक स्ट्रा, यूनाइटिड किंगडम के विदेशी एवं राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री	05-08 फरवरी 2004
महामहिम श्री सिलवान शालोम, इज्राइल के उप प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री	09-12 फरवरी 2004
महामहिम श्री डॉमनिक डी वेलेपीन, फ्रांस के विदेश मंत्री	12-13 फरवरी 2004
महामहिम श्री दिमीत्रीज रूपेल, स्लोवानिया के विदेश मंत्री	14-18 फरवरी 2004
भारत-यूरोपीय संघ त्रिकोण मंत्रिस्तरीय बैठक (आयरलैंड, नीदरलैंड और यूरोपीय समुदाय के विदेशी मामलों के आयुक्त)	15-16 फरवरी 2004
महामहिम डॉ. एडमंड स्टोयबर, बावेरिया स्वतंत्र राज्य के मंत्री राष्ट्रपति	16-21 फरवरी 2004
टीम-09 (पश्चिम अफ्रीका के विदेश मंत्री)	25 फरवरी से 03 मार्च 2004
ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री (आई.बी.एस.ए. त्रिपक्षीय बैठक)	04-05 मार्च 2004
महामहिम श्री कोलिन एल पावेल, अमेरिका के विदेश मंत्री	15-17 मार्च 2004
माननीय लक्ष्मण कादिर गामार, श्रीलंका के विदेश मंत्री	28-29 अप्रैल 2004
माननीय लक्ष्मण कादिर गामार, श्रीलंका के विदेश मंत्री	29 मई से 02 जून 2004
महामहिम लियोनपो खांदू वांगचुक, भूटान के विदेश मंत्री	7-10 जून 2004
महामहिम डॉ. सुराकियार्थ सथीरथई, थाईलैंड के विदेश मंत्री	8-11 जून 2004
महामहिम श्री जोशका फिशर, जर्मनी के विदेशी मामलों के संघीय मंत्री	13-14 जुलाई और 19-21 जुलाई 2004
महामहिम श्री युसुफ ओद्दिरेगो, बुर्किना फासो के विदेश मंत्री	22-25 जुलाई 2004
महामहिम यू विन ओंग, म्यांमार के विदेश मंत्री	23-25 जुलाई 2004
महामहिम श्री दाई बिंगु, चीन के विशेष प्रतिनिधि	25-30 जुलाई 2004
महामहिम डॉ. कमाल खाराजी, ईरान के विदेश मंत्री	25 - 26 जुलाई 2004
महामहिम डॉ. सोलोमन पासी, बल्गारिया के विदेश मंत्री	27-30 जुलाई 2004
महामहिम सुश्री योरीको कावागुची, जापान की विदेश मंत्री	12-14 अगस्त 2004
महामहिम डॉ. लुई अरनेस्टो दरबेज, मैक्सिको के विदेश मंत्री	12-14 अगस्त 2004

महामहिम श्री सोफ मोहम्मद अल अमीन, कोमोरोस के विदेश मंत्री	22-27अगस्त 2004
महामहिम शेख डॉ. मोहम्मद सबाह अल सलेम अल सबाह, कुवैत के विदेश मंत्री	24-26 अगस्त 2004
महामहिम डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री	31 अगस्त - 03 सितम्बर 2004
महामहिम श्री जीसस अरनाल्डो पैरेज, वेनेजुएला के विदेश मंत्री	01-03 सितम्बर 2004
महामहिम श्री खुर्शीद मोहम्मद कसूरी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री	04-08 सितम्बर 2004
महामहिम डॉ. शेख तिदियान गादियो, सेनेगल के विदेश मंत्री	8-12 सितम्बर 2004
महामहिम श्री सर्गेई वी. लावरोव, रूसी परिसंघ के विदेश मंत्री	8-10 अक्तूबर 2004
महामहिम श्री तांग जिकसुआन, चीन की राज्य परिषद के पार्षद	18-20 अक्तूबर 2004
महामहिम श्री माइकेल बर्नियर, फ्रांस के विदेश मंत्री	27-28 अक्तूबर 2004
महामहिम डॉ. सौदिक एस सफेव, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री	29-31 अक्तूबर 2004
महामहिम श्री एम. मुर्शीद खान, बंगलादेश के विदेश मंत्री	31 अक्तूबर से 02 नवम्बर 2004
महामहिम श्री जयकृष्ण कोतारी, मॉरीशस के विदेश मंत्री	4-9 नवम्बर 2004
महामहिम सुश्री मारिया ई लेवेंस, सुरीनाम की विदेश मंत्री	15-19 नवम्बर 2004
महामहिम श्री अलेक्जेंडर डी जुकोव, रूसी परिसंघ के उप प्रधान मंत्री	18-20 नवम्बर 2004

शासन प्रमुखों/राष्ट्र प्रमुखों/उप राष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर के उच्चाधिकारियों द्वारा की गई ट्रांजिट यात्राएँ -

रोमानिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री इयान इलियासकु की ट्रांजिट यात्रा	05 जनवरी 2004
स्वीडन के प्रधान महामहिम श्री गोरान पर्सन की ट्रांजिट यात्रा	13 जनवरी 2004
रोमानिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री इयान इलियासकु की ट्रांजिट यात्रा	05 फरवरी 2004
पोलेंड के राष्ट्रपति महामहिम श्री अलेक्जेंडर कोआसनिस्की की ट्रांजिट यात्रा	21 फरवरी 2004
पोलेंड के राष्ट्रपति महामहिम श्री अलेक्जेंडर कोआसनिस्की की ट्रांजिट यात्रा	27 फरवरी 2004
महामहिम श्री अब्दुल कादिर बागमल, यमन के प्रधान मंत्री की ट्रांजिट यात्रा (हैदराबाद)	01 अप्रैल 2004
मेडागास्कर के प्रधान मंत्री की ट्रांजिट यात्रा (कोलकाता)	12 मई 2004
महामहिम श्री अज जामेह, गाम्बिया के राष्ट्रपति की ट्रांजिट यात्रा (मुम्बई)	22 मई 2004
महामहिम श्री मुसेवेनी, युगांडा के राष्ट्रपति की ट्रांजिट यात्रा (कोलकाता)	26 मई 2004
महामहिम श्री मुसेवेनी, युगांडा के राष्ट्रपति की ट्रांजिट यात्रा (कोलकाता)	30 मई 2004
महामहिम श्री ओलुसेगन ओबसांजो, नाइजीरिया के राष्ट्रपति की ट्रांजिट यात्रा	2 -3 नवम्बर 2004
चीफ स्टेला ओबसांजो, नाइजीरिया की प्रथम महिला	1-10 दिसम्बर 2004
महामहिम एस आर नाथन, सिंगापुर के राष्ट्रपति	10-20 दिसम्बर 2004

भारत के राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/प्रधान मंत्री की विदेश यात्राएँ

भारत के प्रधान मंत्री की इस्लामाबाद यात्रा (सार्क शिखर सम्मेलन के लिए)	03-06 जनवरी 2004
भारत के उपराष्ट्रपति की दक्षिण अफ्रीका यात्रा	25 अप्रैल से 03 मई 2004
भारत के प्रधान मंत्री की बैंकाक यात्रा - प्रथम बिम्सटैक शिखर सम्मेलन के लिए	29-31 जुलाई 2004
भारत के राष्ट्रपति की तंजानिया एवं दक्षिण अफ्रीका यात्रा	11-18 सितम्बर 2004

भारत के प्रधान मंत्री की लंदन, न्यूयार्क एवं जेनेवा यात्रा	19-27 सितम्बर 2004
भारत के प्रधान मंत्री की नीदरलैंड्स की यात्रा (पांचवें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए)	07-10 नवम्बर 2004
भारत के प्रधान मंत्री की लाओ लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के वेनेसियान की यात्रा	28 - 30 नवम्बर 2004

2005 में की गई यात्राएं

शासन प्रमुख/सरकार के प्रमुख/ उप राष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर द्वारा की गई आधिकारिक यात्राएं

डिग्निटरी	तिथियाँ
महामहिम डॉ. रिकॉर्डो लागोस, चिली के राष्ट्रपति	18-22 जनवरी
महामहिम किंग जिंगमे सिंगे वांगचुक, भूटान के महाराजा	23 से 27 जनवरी
महामहिम श्री कार्लो एजिलियो सियाम्पी, इटली के राष्ट्रपति	12-16 फरवरी
महामहिम डॉ. हेंज फिशर, आस्ट्रिया के राष्ट्रपति	16-22 फरवरी

शासन प्रमुख/सरकार के प्रमुख/ उप राष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर द्वारा की गई आधिकारिक/कार्यकारी यात्राएं

महामहिम पॉल मार्टिन, कनाडा के प्रधान मंत्री	17-18 जनवरी
महामहिम श्री हामिद कर्जेई, अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति	23-25 फरवरी

विदेश मंत्री तथा समकक्ष स्तर द्वारा की गई आधिकारिक यात्राएं

महामहिम श्री सिद्धी मोरो सानेह, गाम्बिया के विदेश राज्य मंत्री	11-13 जनवरी
महामहिम श्री शेख तादियान गादियो, सेनेगल के विदेश मंत्री	21 से 24 जनवरी
महामहिम श्री फ्रेडिरिक मिशेल, बहामा के विदेश मंत्री	26 जनवरी से 01 फरवरी
महामहिम श्री रमजानी बाया, कांगों लोकतांत्रिक गणराज्य के विदेश मंत्री	01 से 04 फरवरी
माननीय जैक स्ट्रा, ब्रिटिश विदेश मंत्री	16-18 फरवरी
महामहिम श्री कमाल खराजी, ईरान के विदेश मंत्री	20-22 फरवरी
महामहिम श्री लक्ष्मण कादिर गामार, श्रीलंका के विदेश मंत्री	24-26 फरवरी

शासन प्रमुख/सरकार के प्रमुख/ उप राष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर द्वारा की गई निजी/ट्रांजिट यात्राएं

महामहिम श्री जुलियस रत्नकुमार अयोध्या, सूरीनाम के उप राष्ट्रपति (प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि)	04-12 जनवरी
महामहिम श्री अनिरूद्ध जगन्नाथ , मारीशस के राष्ट्रपति	10-22 जनवरी
तुर्की के प्रधान मंत्री, (दिल्ली)	06 फरवरी
महामहिम आसि सांगे कोदेन वांगचुक, भूटान की महारानी	06-21 फरवरी

विदेश मंत्री तथा समकक्ष स्तर द्वारा की गई निजी/ट्रांजिट यात्राएं

महामहिम श्री जेन पीटरसन नार्वे के विदेश मंत्री	जनवरी
महामहिम श्री लॉरी चांद, सोलोमन द्वीप समूह के विदेश मंत्री	17-20 जनवरी
महामहिम श्री सादिक एस. सफाऐव, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री	07-08 फरवरी

भारत के राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/ प्रधान मंत्री द्वारा की गई विदेश यात्राएं

शून्यी

■■

पासपोर्ट, वीजा और कोंसली सेवाएं

16

भूमिका

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के माध्यम से और विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों के माध्यम से विदेश मंत्रालय का कोंसल पासपोर्ट और वीजा प्रभाग भारत में आम जनता के साथ, विदेशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा विदेशी नागरिकों के साथ सीधी कार्रवाई करता है। मंत्रालय भारत में पासपोर्ट कार्यालयों के माध्यम से पासपोर्ट जारी करता है और पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है ।

इस समय भारत में 30 पासपोर्ट कार्यालय हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालय कम्प्यूटरीकृत हैं और उनके पास मशीन प्रिंटेड तथा मशीन-रीडेबल पासपोर्ट हैं। पासपोर्ट जारी करने के लिए अनुमति आदेश इलैक्ट्रानिक पद्धति से दिया जाता है। पासपोर्ट से संबंधित समस्त नैमितिक कार्य कम्प्यूटरीकृत हैं जैसे कि नकदी सृजन, सूचकांक की जांच, पासपोर्ट, पते लिखना एवं प्रेषण करना तथा रिकार्ड इलैक्ट्रानिक पद्धति से रखा जाता है। पासपोर्ट आवेदन-पत्रों को स्कैन किया जा रहा है और इनका संचय इलैक्ट्रानिक पद्धति से किया जाता है। जन शिकायत निवारण तंत्र प्रणाली को सुदृढ़ करने के एक भाग के रूप में आवेदकों की सहायता करने तथा साथ ही शिकायतों/फरियादों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए सभी पासपोर्ट कार्यालयों को सुविधा काउण्टर और सहायता डेस्क स्थापित करने के निदेश दिए गए हैं। संयुक्त सचिव (सीपीवी) के निकट पर्यवेक्षण में कोंसल, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग में भी एक जन शिकायत निवारण तंत्र प्रणाली कार्यरत है ।

पासपोर्ट सेवाएं

डाक घरों और जिला कार्यालयों के जरिए विकेन्द्रीकरण

विकेन्द्रीकरण योजना के एक भाग के रूप में जिला स्तरों पर जिला पासपोर्ट कक्ष खोले गए हैं जहां जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पासपोर्ट के आवेदन-पत्र प्राप्त करते हैं और जांच करने के एवं पुलिस से सत्यापन कराने के बाद पासपोर्ट जारी करने के लिए इन्हें संबंधित पासपोर्ट कार्यालय को भेजते हैं। इस समय भारत के 26 राज्यों में लगभग 400 जिला पासपोर्ट कक्ष हैं। जिला पासपोर्ट कक्षों के खुल जाने के फलस्वरूप पासपोर्ट कार्यालयों में भीड़-भाड़ काफी हद तक कम हो गई है। पुलिस से सत्यापन कराने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के अलावा जिला पासपोर्ट कक्ष आवेदकों को राहत भी प्रदान करते हैं, जिन्हें पासपोर्ट कार्यालयों तक पहुंचने के लिए लम्बी यात्रा नहीं करनी पड़ती है। पासपोर्ट के आवेदन-पत्र स्पीड पोस्ट केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए भी प्राप्त किए जाते हैं। इस समय लगभग 215 ऐसे स्पीड पोस्ट केन्द्र हैं जो पासपोर्ट के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार करते हैं ।

क्रियान्वयनाधीन परिवर्तन

बिना बारी के पासपोर्ट जारी करने की 'तत्काल' योजना के फलस्वरूप प्रणाली तात्कालिक आधार पर पासपोर्ट जारी करने की मांग के संबंध में त्वरित प्रतिक्रिया करने में सफल हुई है। वर्ष के दौरान (दिसम्बर 2004 तक) 'तत्काल' योजना के तहत कुल 206915 पासपोर्ट जारी किए गए जिसके परिणामस्वरूप 31.12 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

22 पासपोर्ट कार्यालयों में दूरभाष-पूछताछ प्रणाली उपलब्ध है तथा पासपोर्ट कार्यालय बेंगलूर में टच स्क्रीन पूछताछ किऑस्क प्रायोगिक आधार पर आरम्भ किया गया है ।

पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली की पुनरीक्षा

पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली की पुनरीक्षा संबंधी अन्तर्मंत्रालय समिति ने, जिसकी स्थापना मंत्रिमण्डल सचिवालय में की गई थी, पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को सरल बनाने के लिए कई सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को काफी संख्या में क्रियान्वित किया जा चुका है तथा संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करके शेष सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है ।

आधारभूत संरचना

सरकार ने बेंगलूर, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर और भुवनेश्वर में पासपोर्ट कार्यालयों के लिए भवनों का निर्माण कार्य हाथ में लिया है। इस समय आठ स्थानों पर अर्थात, मुम्बई, चण्डीगढ़, कोचीन, कोझीकोड, अहमदाबाद, हैदराबाद, पटना और पणजी में पासपोर्ट कार्यालयों के भवन विदेश मंत्रालय के स्वामित्व में हैं। छह पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यालय परिसर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं तथा 16 पासपोर्ट कार्यालय किराए के भवनों में हैं। चार पासपोर्ट कार्यालयों अर्थात त्रिचिरापल्ली, गुवाहाटी, जलंधर और मुम्बई के लिए भूमि खरीदने की कार्रवाई भी चल रही है ।

कम्प्यूटीकरण

इस समय सभी 30 पासपोर्ट कार्यालय कम्प्यूटीकृत हैं। सभी

पासपोर्ट कार्यालयों में ई-मेल की सुविधा उपलब्ध है। सभी पासपोर्ट कार्यालयों के लिए वैब पृष्ठ भी सृजित किए गए हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालयों को परस्पर जोड़कर एक व्यापक कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क और संयोजकता के साथ-साथ एक केन्द्रीय प्रक्रिया कक्ष सृजित करने के प्रस्ताव की परिकल्पना की गई है ।

कार्यभार

जनवरी से दिसम्बर, 2004 तक की अवधि के दौरान कुल 3352780 पासपोर्ट जारी किए गए तथा 395598 विविध सेवाएं प्रदान की गई। प्राप्त हुए पासपोर्ट आवेदन-पत्रों/जारी किए गए पासपोर्टों/प्रदान की गई विविध सेवाओं की संख्या और राजस्व एवं व्यय संबंधी आंकड़ों का पासपोर्ट कार्यालय-वार ब्यौरा परिशिष्ट-रूज् में दिया गया है ।

पासपोर्ट फाइलों की स्कैनिंग

पुराने आवेदन-पत्रों को संचित करने के लिए स्थान की कमी और संदर्भ के लिए अथवा न्यायालय संबंधी मामलों के लिए उन्हें शीघ्र पुनः निकालने की कठिनाइयां काफी लम्बे समय से चली आ रही समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए पुराने आवेदन-पत्रों को स्कैन करने और सूचना को सी डी में संचित करने का निर्णय लिया गया था। गैर-योजना व्यय से सम्बद्ध समिति का अनुमोदन प्राप्त किया गया। पुराने पासपोर्ट आवेदन पत्रों को स्कैन करने का काम सभी पासपोर्ट कार्यालयों में पूरा हो गया है ।

पासपोर्ट अधिकारियों का सम्मेलन

26 सितम्बर 2004 को कोचीन में पासपोर्ट अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने आधुनिकीकरण, विकेन्द्रीकरण, लम्बित कार्यों को समाप्त करने, लोक शिकायतों के त्वरित निवारण, कार्यालय भवनों के उचित रख-रखाव और भ्रष्टाचार और लापरवाही को कतई सहन न करने पर बल दिया ।

कोंसली सेवाएं

विदेश स्थित सभी मिशन/केन्द्र विदेशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों को कोंसली सेवाएं प्रदान करते हैं। विदेशों में भारतीयों की मृत्यु के मामलों में शवों/अस्थियों को शीघ्र प्रेषित करने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने, स्थानीय एवं भारतीय प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क करने और मृतक के संबंधियों को स्थिति से अवगत कराए रखने में हमारे मिशनों और केन्द्रों द्वारा तत्परतापूर्वक सहायता प्रदान की गई। जनवरी से नवम्बर 2004 तक की अवधि के दौरान विदेशों में 8909 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। मंत्रालय को विदेशों में 2378 भारतीयों की मृत्यु की सूचना दी गई ।

वीजा सेवाएं

विगत वर्षों में भारतीय मिशनों और केन्द्रों द्वारा वीजा प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अधिकांश मिशन और केन्द्र या तो उसी दिन काउण्टर पर अथवा अधिक से अधिक 48 घंटे के अन्दर वीजा प्रदान कर देते हैं। खाड़ी, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमरीका में मिशनों और केन्द्रों की वीजा एवं पासपोर्ट शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण की एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। पहले उन मिशनों और केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा जिनमें प्रदान की गई सेवाओं की मात्रा अधिक है। इसके आलवा, कोंसल, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) भारत के इस्लामाबाद और लन्दन स्थित उच्चायोगों की वीजा एवं पासपोर्ट शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं ।

कोंसली सत्यापन

वर्ष 2004 के दौरान कोंसल, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग में 5,37,467 दस्तावेजों को कोंसली सत्यापन प्रदान किया गया जिसमें से 232060 वाणिज्यिक दस्तावेज थे। यह सेवा बिना कोई प्रभार लिए उसी दिन प्रदान की जाती है तथा यह सेवा अविलम्ब एवं कुशलतापूर्वक प्रदान की जाती है ।

कोंसली करार - प्रत्यर्पण और पारस्परिक विधिक सहायता कार्यक्रम

संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिए एक विधिक एवं सांस्थानिक ढांचा प्रदान करने के लिए तथा वित्तीय एवं अन्य अपराधों के बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय आयामों के प्रति कार्रवाई करने के लिए अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय करारों के संबंध में वार्ताएं की जा रही हैं ताकि इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास को वैधानिक आधार प्रदान किया जा सके। इन कोंसली करारों में ये शामिल हैं; प्रत्यर्पण संधियां, आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता तथा सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता ।

अक्तूबर 2004 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दो करारों, पत्यर्पण और आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संबंधी संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। अगस्त 2004 में कुवैत के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान पत्यर्पण संधि और आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सरकार और ओमान की सल्तनत के बीच 26 दिसम्बर 2004 की एक प्रत्यर्पण संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए थे ।

प्रत्यर्पण और आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संबंधी संधियों पर बातचीत करने के लिए वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल की यात्रा पर गए। आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि के बारे में बातचीत करने के लिए एक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल सिंगापुर की यात्रा पर गया। विभिन्न कोंसली करारों के संबंध में बातचीत करने के लिए ईरान, हांगकांग, सिंगापुर और कजाकस्तान से सरकारी प्रतिनिधिमण्डल भारत की यात्रा पर

आए। विभिन्न विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों की भारत यात्रा के फलस्वरूप ओमान के साथ प्रत्यर्पण संधि, कजाकस्तान के साथ सिविल मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि, हांगकांग के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि तथा सिंगापुर के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि के मूल पाठों को अन्तिम रूप दिया गया और उन पर सरकारी स्तर पर हस्ताक्षर किए गए ।

आपराधिक और सिविल/वाणिज्यिक दोनों अपराधों के लिए विदेशी सरकारों से प्रत्यर्पण एवं विधिक सहायता हेतु प्राप्त अनुरोधों पर मंत्रालय सक्रिय रूप से कार्रवाई करता है। प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध विभिन्न देशों के साथ सम्पन्न प्रत्यर्पण संधियों अथवा प्रत्यर्पण करारों के तहत हमारी बाध्यताओं से प्राप्त होते हैं। वर्ष 2004 के दौरान विभिन्न जांच एजेंसियों से प्राप्त 14 प्रत्यर्पण अनुरोध विदेशी सरकारों को अग्रेषित किए गए थे। इसी अवधि के दौरान विदेशी सरकारों से भारत को 10 प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त हुए। भारत सरकार ने 2 व्यक्तियों को प्रत्यर्पित किया। विदेशों से भारत को तीन व्यक्ति प्रत्यर्पित किए गए। विदेशी सरकारों से विधिक सहायता के लिए भारत सरकार को 88 अनुरोध प्राप्त हुए तथा आपराधिक मामलों में विधिक सहायता के लिए 37 भारतीय अनुरोध विदेशी सरकार को अग्रेषित किए गए ।

■■

17

प्रशासन और स्थापना

श्री नटवर सिंह ने 23 मई 2004 को विदेश मंत्री के पद का कार्यभार सम्भाला। श्री ई. अहमद और श्री राव इन्द्रजीत सिंह ने भी 23 मई 2004 को विदेश राज्य मंत्री के पद का कार्यभार सम्भाला। श्री श्याम सरन ने 1 अगस्त 2004 को विदेश सचिव के पद का कार्यभार सम्भाला ।

भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों का कारगर ढंग से अनुपालन करने के लिए विदेशों में भारत के राजनयिकों की उपस्थिति में वृद्धि करना आवश्यक होता है। वर्ष के दौरान प्रशासन प्रभाग के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण चुनौती सभी ग्रेडों में पर्याप्त प्रोन्नति के अवर प्रदान करा कर अपने कार्मिकों का मनोबल ऊंचा बनाए रखना थी। मुख्यालय में तथा भारतीय मिशनों/केन्द्रों दोनों में मंत्रालय की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा साथ ही अपने कार्मिकों की आकांक्षाओं संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीति के एक भाग के रूप में प्रशासन प्रभाग ने भारतीय विदेश सेवा की चौथी संवर्ग समीक्षा के साथ-साथ भारतीय विदेश सेवा (ख) की सर्वप्रथम संवर्ग समीक्षा की। भारतीय विदेश सेवा की चौथी संवर्ग समीक्षा के फलस्वरूप भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड - III के 29 पद तथा भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ वेतनमान के और परिवीक्षार्थी रिजर्व के 40 पद सृजित किए जा सके। भारतीय विदेश सेवा (ख) की पहली बार की गई संवर्ग समीक्षा में अवर सचिव के स्तर पर 60 पदों, अनुभाग अधिकारी स्तर पर 94 पदों तथा निजी सचिव स्तर पर 67 पदों को सृजित करने तथा साथ ही समूह 'ग' के आनुपातिक पद कम करने की व्यवस्था की गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय के सक्रिय सहयोग से मंत्रालय दोनों संवर्ग समीक्षाओं के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने और उन्हें समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित करने में भी सफल रहा है ।

सभी स्तरों पर सीधी भर्ती को अनुकूलतम करने के लिए मंत्रालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई अनिवार्य जांच समिति तंत्र-प्रणाली को लागू किया जिसके फलस्वरूप पदों को समाप्त किया गया। प्रशासन प्रभाग ने मंत्रालय में मानव संसाधनों के नियोजन के संबंध में भी व्यापक अध्ययन किए और पदों के उपयुक्त अनिवार्य समापन को ध्यान में रखते हुए मिशनों/केन्द्रों के साथ-साथ मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों दोनों में कार्मिकों के युक्तिसंगत वितरण के लिए अनेक उपाय किए। इस कार्रवाई का उद्देश्य निम्न स्तर पर, विशेष रूप से उच्च श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक स्तर पर, कम होते जा रहे कार्मिकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में अधिक अर्हताप्राप्त वरिष्ठ कार्मिक उपलब्ध करा कर मंत्रालय में उपलब्ध सहायक कार्मिकों को युक्तिसंगत रूप से तैनात करना भी था ।

मंत्रालय द्वारा मुख्यालय में और विदेशों में स्थित 162 मिशनों/केन्द्रों में 3340 अधिकारी एवं कर्मचारी नियोजित किए गए हैं जिसका ब्यौरा परिशिष्ट - I में सारणी में दिया गया है। इनमें भारतीय विदेश सेवा (क) (आइएफएस), भारतीय विदेश सेवा (ख) (आईएफएस - ख), भाषान्तरकार तथा विधि एवं संधि संवर्ग शामिल हैं ।

मंत्रालय में 1 अप्रैल से 30 नवम्बर 2004 तक सीधी भर्ती, विभागीय प्रोन्नतियों और सीमित विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से, जिनमें आरक्षित रिक्त पद भी शामिल हैं, की गई नियुक्तियां परिशिष्ट - II में दी गई हैं ।

परिशिष्ट - III में दी गई सारणी में मंत्रालय के अधिकारियों की भाषा प्रवीणता संबंधी ब्यौरा दिया गया है ।

मंत्रालय ने अपने प्रयास जारी रखे जिनका उद्देश्य नियमों एवं विनियमों का सरलीकरण करके तथा नई प्रौद्योगिकी अपनाकर अधिकतम कार्यकुशलता प्राप्त करना था ।

स्थापना

निर्माण परियोजनाओं और मंत्रालय में कम्प्यूटरीकरण की विशेष ध्यान सुनिश्चित करने के लिए स्थापना प्रभागम में से परियोजना प्रभाग अर ई-गवर्नेंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग नामक दो नए प्रभाग बनाए गए थे। स्थापना प्रभाग, भारत में मंत्रालय के सभी परिसरों को किराए पर लेने और उनके रख-रखाव, विदेशों में परिसरों को किराए पर देने, मिशनों तथा मुख्यालय के कार्यालयों के लिए भत्तों तथा अनुदान के निर्धारण और कार्यालय एवं आवासीय उपस्करों, फर्नीचर तथा कलात्मक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी एक सेवा विभाग ही बना रहा। वर्ष 1998 में आरम्भ की गई वार्षिक सूचकांकन प्रणाली को जीवन-निर्वाह की लागत के प्रति और प्रभावी बनाने के लिए विदेशी भत्तों की प्रत्येक वर्ष 1 अक्तूबर से प्रभावी होने वाली मध्यकालिक समीक्षा प्रणाली आरम्भ की गई थी। सूचकांकन दल ने, अमरीकी डॉलर में मूल्यह्रास से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका, लन्दन और रोम का दौरा किया। इस दल की अनुशंसाओं के आधार पर मंत्रालय ने स्थानीय मुद्रा के

संबंध में सदृश्यमूलक अनुदान तथा कुछ मिशनों में विदेशी भत्तों को संरक्षण प्रदान किया। सदृश्यमूलक अनुदान और विशेष अनुदानों की एक व्यापक समीक्षा विचाराधीन है ।

सीडीओटी द्वारा खाली किए गए अकबर भवन के तलों की मरम्मत करवाई गई थी। इसके एक भाग में प्रवासी मामलों का नया मंत्रालय स्थापित किया जाएगा जबकि शेष भाग मंत्रालय के पास रहेगा। सी-। हटमैन्ट्स, जहां अभिलेख प्रबंधन अनुभाग अवस्थित है, की मरम्मत का काम भी शीघ्र ही आरम्भ किया जाना है ।

कलात्मक वस्तुओं के चयन संबंधी समिति (ओडीए समिति) का पुनर्गठन किया गया था। विदेश सचिव की पत्नी श्रीमती अनिता सरन इस समिति की अध्यक्षा हैं। ओडीए समिति के सदस्य हैं : श्री एस. वर्द्धराजन, पूर्व सचिव (संस्कृति), अध्यक्ष, विशेषज्ञ समिति, राष्ट्रीय संग्रहालय; श्री राजीव लोचन, निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला भवन; डा. सुधाकर शान्ना, सचिव, ललित कला अकादमी; सुश्री पूर्णिमा राय, दिल्ली हस्तकला परिषद; सुश्री जसलीन धर्मीजा, कपड़ा विशेषज्ञ; सुश्री लेखा भगत, बर्तन विशेषज्ञ; श्री दिलीप सिन्हा, संयुक्त सचिव (स्थापना एवं परियोजना), विदेश मंत्रालय (पदेन सचिव के रूप में) ।

परियोजना प्रभाग

विदेश मंत्रालय का परियोजना प्रभाग, भारत तथा विदेश में निर्मित सम्पत्तियों की खरीद तथा निर्माण तथा मरम्मत परियोजनाओं के लिए पूंजी लागत से संबंधित व्यय को नियंत्रित करने वाला एक सेवा प्रभाग है। इसके अतिरिक्त यह प्रभाग, विदेशों में विदेश मंत्रालय के परिसरों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है ।

परियोजनाएं

मंत्रालय, भारत तथा विदेशों में नियोजित परियोजनाओं के तेजी से पूरा करने के काम को उच्च वरीयता देता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्पवत होकर काम कर रहा है। सरकार के स्वामित्व वाले भू-खण्डों पर निर्माण एवं मरम्मत के काम में तेजी लाने के प्रयास बढ़ा दिए गए हैं तथा इन भू-खण्डों का विकास करने तथा व्यवस्थित तरीके से नियोजन एवं निर्माण गतिविधियां आरम्भ करने के काम में वर्ष 2004-2005 के दौरान काफी प्रगति की गई है ।

मंत्रालय ने अबुधाबी मे राजदूतावास परिसर का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अन्य परियोजनाएं भी नियोजन एवं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। वारसा में चांसरी तथा स्टाफ आवासों के निर्माण के लिए और सिंगापुर में उच्चायुक्त के आवास के पुनर्विकास के लिए तथा अबुजा में चांसरी के निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारियों से वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। इन परियोजनाओं के लिए नक्शों को अन्तिम रूप देने और स्थानीय निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने जैसी निर्माण पूर्व गतिविधियां आरम्भ कर दी गई हैं। ब्रासीलिया, काठमाण्डू, इस्लामाबाद, ताशकंद आदि में परियोजनाओं के लिए वित्तीय अनुमोदन का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। ढाका राजदूतावास परिसर के लिए डिजाइन को अन्तिम रूप दे दिया गया है और मंत्रालय परामर्शदाता के साथ एक करार सम्पन्न करने की प्रक्रिया में है जिसके बाद लागत के आंकलन की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी ।

उन परियोजनाओं के लिए, जहां वित्तीय अनुमोदन पहले ही मौजूद हैं, मंत्रालय उनके काम को यथासंभव समय पर पूरा करने के लिए कदम उठा रहा है। बीजिंग में निर्माण परियोजना के लिए प्रथम चरण की निर्माण अनुमति प्राप्त कर ली गई है और द्वितीय चरण के अनुमोदनों के लिए कार्रवाई की जा रही है। ठेकेदारों को संक्षिप्त सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी गई है। मस्कट निर्माण परियोजना, जहां निविदाओं में उद्त लागत अनुमोदित लागत से अधिक हो गई, के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। मास्को में आवास निर्माण परियोजना जो नियोजन के उन्नत चरण में पहुंच गई थी, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भू-खण्ड वापस लिए जाने को दृष्टिगत रखते हुए विलम्बित कर दी गई है और परस्पर स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के प्रयास जारी हैं। जेनेवा में स्थायी प्रतिनिधि के आवास की मरम्मत और 8 एसएएस लन्दन में आवास निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है। टोकियो में सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण और टोकियो में मिशन की अन्य सम्पत्तियों के नवीकरण का काम अभी योजनावस्था में है ।

मारीशस और बहरीन में चांसरी के निर्माण के लिए नए भू-खण्ड अधिग्रहित किए गए थे। हमारी चांसरी के निर्माण के लिए पहले के भू-खण्ड के बदले मारीशस सरकार की नव-विकसित साइबर सिटी में एक भू-खण्ड देने की पेशकश स्वीकार कर ली गई है। बहरीन में न्यू डिप्लोमेटिक एन्कलेव में एक भू-खण्ड उस सम्पत्ति दल के निर्णय के आधार पर खरीदा गया था जिसने जनवरी 2005 में बहरीन का दौरा किया था। कतर के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि दोहा में न्यू डिप्लोमेटिक एन्कलेव में एक भू-खण्ड वर्ष 2005 के मध्य तक आबंटित कर दिया जाएगा ।

भारत में, छात्रावास एवं प्रशासनिक ब्लॉक तथा आवासों सहित विदेश सेवा संस्थान परिसर के निर्माण का काम काफी आगे बढ़ चुका है। इस परिसर से सटा हुआ जमीन का एक अतिरिक्त टुकड़ा अधिग्रहित किया गया है और निर्माण योजनाओं के लिए स्थानीय निकायों से अनुमोदन प्राप्त किए जा रहे हैं। भारत सरकार की ओर से एक उपहार के रूप में, चाणक्यपुरी में बनाया जा रहा एशियाई-अफ्रीका विधिक परामर्शदायी संगठन का मुख्यालय बनकर लगभग तैयार है। कोलकाता में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भवन और लखनऊ में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भवन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। चण्डीगढ़ में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भवन

का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पप्पनकलां, द्वारका में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है और फ्लेटों का आबंटन पहले ही आरम्भ कर दिया गया है ।

चाणक्यपुरी मे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए एक आवासीय परिसर हेतु वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कहा गया है कि वे निर्धारत समय सीमा के अंदर इस परियोजना को क्रियान्वित करें। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्थानीय निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने के काम में लगा हुआ है ।

जवाहर लाल नेहरू भवन परियोजना के डिजाइन और कार्यान्वयन का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। पूर्व में विदेश भवन के नाम से ज्ञात जवाहर लाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय के मुख्यालय के रूप में उपयोग किया जाएगा और यह जनपद तथा मौलाना आजाद रोड के संधिस्थल पर अवस्थित होगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने ही संसाधनों से एक संकल्पना डिजाइन तैयार किया गया है जो सैन्ट्रल विस्टा पर लुटियन के भवनों और अन्य भवनों से वास्तुकलात्मक अनुरूपता से युक्त है और पर्यावरण और आस-पड़ोस के वातावरण के अनुकूल है। चूंकि इस भवन में विदेश मंत्रालय स्थापित किया जाएगा, जहां विदेशी महानुभाव बहुधा आते रहते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है कि यह भवन न केवल मंत्रालय के कार्यकलापों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता हो बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत की महत्ता के परिचायक के रूप में अपनी मौजूदगी का विशेष अहसास भी कराता हो।

जवाहर लाल नेहरू भवन का संकल्पा डिजाइन, दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदित कर दिया गया है जबकि सैन्ट्रल विस्टा समिति तथा अन्य स्थानीय निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रहा है। इसके साथ-साथ इस परियोजना के लिए वित्तीय अनुमोदन भी लिया जा रहा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुमानों के आधार पर, गैर-योजना व्यय संबंधी समिति ने इस परियोजना को 175.57 करोड़ रुपए की लागत पर पूरा किए जाने की स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने संकेत दिया है कि सभी अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद भवन के निर्माण में 40 महीने का समय लगेगा। मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी गई है और मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा कि आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाने के बाद यह परियोजना समय पर पूरी हो जाए ।

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में, निर्माण परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और नियमित आधार पर इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। समुचित अनुवर्ती कार्रवाई और यथा-समय कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से परियोजनाओं की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ।

विदेशों में सम्पत्ति की खरीद

मंत्रालय, विदेशों में निर्मित सम्पत्ति की खरीद करके किराए पर होने वाले सरकारी व्यय को कम करने का प्रयास करता रहा है। भारी-भरकम किराया देने वाले मिशनों की पहचान करके उनसे कहा गया है कि वे खरीद के लिए उपयुक्त सम्पत्तियों का पता लगाएं। खरीद/निर्माण परियोजनाओं संबंधी व्यय हेतु मंत्रालय द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिए जाने से मिशनों को खरीद की सम्भावनओं का पता लगाने में अपेक्षाकृत अधिक सुगमता हो गई है। मंत्रालय का यह प्रयास रहा है कि प्राप्त दस्तावेजों पर तेजी से कार्रवाई की जाए। मार्च 2004 में पनामा मे राजदूत के आवास के लिए सम्पत्ति की खरीद की गई। एक सम्पत्ति दल ने जनवरी 2005 में बुटोनोस सयर्स तथा जार्जटाउन का दौरा किया और दोनों ही स्थानों पर चांसरी और राजदूतावास के लिए आवास की खरीद करने की सिफारिश की। इन खरीदारियों को चालू वित्त वर्ष में ही सम्पन्न करने के दृष्टिकोण से, खरीद से संबंधित विभिन्न औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। अन्य विभिन्न स्टेशनों में सम्पत्ति की खरीद के प्रस्तावों पर मंत्रालय सक्रियतापूर्वक विचार कर रहा है ।

ई-गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी

विदेश मंत्रालय में पहले से चल रहे हार्डवेयर आपूर्ति पक्ष के अलावा ई-गवर्नेंस संबंधी पहलकदमी को दी जा रही महत्ता में वृद्धि होने का पता इस बात से चलता है कि मंत्रालय में ई-गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से एक नया प्रभाग खोला गया है ।

इस अवधि के दौरान विश्वव्यापी स्तर पर एक बड़ी परियोजना प्रारम्भ की गई और उसे पूरा भी कर लिया गया इस परियोजना का नाम है - मानकीकृत ई-मेल पते एवं प्रबंधन की परियोजना। इस परियोजना को कार्यरूप देकर, विदेश मंत्रालय के सभी ई-मेल प्रयोक्ताओं को एकल डोमेन अर्थात user@mea.gov.in के अधीन लाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक मिशन/पोस्ट को भी मानक ई-मेल पहचान प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, सभी अधिकारियों को नाम आधारित स्थायी ई-मेल पहचान दी गई है जिसका प्रयोग कभी भी कहीं भी अभिप्रमाणन के साथ किया जा सकता है।

इसके अलावा, विभिन्न अन्य परियोजनाएं जैसे कि मिशन पासपोर्ट एवं वीजा पैकेज, राजनयिक पहचान पत्र डिजिटलीकरण, संसदीय आवश्वासन प्रबोधन प्रणाली आदि पूरी की गई। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट www.mea.gov.in के डोमेन नाम के अन्तर्गत मानकीकृत कर ली गई है ।

■■

समन्वय

18

समन्वय प्रभाग की तीन शाखाएं हैं अर्थात संसद अनुभाग, समन्वय अनुभाग और छात्र कक्ष ।

संसद अनुभाग

समन्वय प्रभाग विदेश मंत्रालय का संसद से संबंधित सभी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु है; इन कार्यों में प्रश्न-उत्तर, आश्वासन, विदेशी संबंधों पर बहस और संसद के दोनों सदनों में रिपोर्टें प्रस्तुत करना शामिल है। समन्वय प्रभाग विदेश मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठकों का आयोजन भी करता है और विदेश मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य तथा जिन मामलों पर विदेश मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है उनसे संबंधित अन्य संसदीय समितियों के कार्य का समन्वय और देखभाल करता है ।

समन्वय अनुभाग

समन्वय अनुभाग राज्यपालों, लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा उपाध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों के मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, न्यायपालिका के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों आदि द्वारा की जाने वाले यात्राओं के लिए राजनीतिक दृष्टि से अनापत्ति प्रदान करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करता है। विदेश मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद सामान्यतः राजनीतिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करता है। इन पहलुओं में ये शामिल हैं; इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश; यात्रा के लिए राजनीतिक और कार्यात्मक औचित्य; आयोजनकर्ताओं की पृष्ठभूमि और पूर्ववृत्त; तथा हमारे संबंधित मिशन/केन्द्र से प्राप्त सिफारिश। किसी सरकारी अधिकारी को विदेश जाने की अनुमति प्रदान करने से पहले इस मंत्रालय की सिफारिश अनिवार्य है ।

वर्ष के दौरान समन्वय अनुभाग ने विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में विभिन्न भारतीय खिलाड़ियों और खेल-कूद टीमों की भागीदारी के लिए और भारत में विदेशी खेल-कूद टीमों के लिए बड़ी संख्या में अनुमोदन प्रदान करने पर भी कार्रवाई की है ।

वर्ष के दौरान आतंकवाद विरोधी दिवस (21 मई) सद्भावना दिवस (20 अगस्त) और कौमी एकता सप्ताह/दिवस (19-25 नवम्बर) पूर्ण गरिमा के साथ मनाए गए। मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों दोनों में शपथ दिलाई गई ।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करने, विदेशी सहायता/अनुदान स्वीकार करने, विदेशी अंशदान नियंत्रण अधिनियम के तहत अनुमोदन प्रदान करने, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत एमेच्योर डब्ल्यू/टी लाइसेंस प्रदान करने, विदेशों में स्थित भारत विदेश सांस्कृतिक मित्रता और सांस्कृतिक सोसाइटियों के लिए सहायता अनुदान के वास्ते अनापत्ति देने के अनुरोधों पर भी वर्ष के दौरान तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई। इसी प्रकार गैर-अनुसूचित उड़ानों और विदेशी नौसेना पोतों एवं जलयानों द्वारा यात्राओं के लिए कूटनीतिक मंजूरी देने के लिए कार्रवाई की गई ।

छात्र कक्ष

छात्र कक्ष, जो समन्वय प्रभाग का एक भाग है, मेडिकल एवं इंजीनियरी संस्थानों में एमबीबीएस/बीडीएस, इंजीनियरी डिग्री, बी. फार्मेसी और इंजीनियरी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में आरक्षित स्थानों पर विदेशी स्व-वित्त पोषित छात्रों के चयन, नामांकन और प्रवेश के संबंध में कार्रवाई करता है ।

यह कक्ष विभिन्न मेडिकल संस्थानों और अनुसंधान पाठ्यक्रमों में ऐच्छिक प्रशिक्षण सहित इंजीनियरी, भेषज प्रबंधन और अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले विदेशी छात्रों के संबंध में राजनीतिक दृष्टि से स्वीकृति देने के संबंध में भी कार्रवाई करता है ।

यह कक्ष विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्व-वित्त पोषित छात्रों की राजनीतिक स्वीकृति और प्रवेश से संबंधित मामलों के बारे में विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों और संस्थानों के साथ सम्पर्क स्थापित करता है ।

एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शैक्षिक वर्ष 2003-04 में 149 और वर्ष 2004-05 में 164 वैध आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार इंजीनियरी और फार्मेसी में डिग्री/डिप्लोमा के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए वर्ष 2003-04 और 2004-05 में क्रमशः 122 और 126 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करने के अलावा वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमशः 1123 और 1236 आवेदन-पत्रों पर राजनीतिक दृष्टि से अनापत्ति प्रदान करने के लिए कार्रवाई की गई ।

■■

19

अनिवासी भारतीय और विदेशों में भारतीय मूल के लोग

नए अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का सृजन हो जाने के बाद अधिकांश विषय, जिनके संबंध में कार्रवाई इस प्रभाग द्वारा की जा रही थी, नए मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। चूंकि यह प्रभाग अभी विदेश मंत्रालय का ही एक भाग है इसलिए इस प्रभाग द्वारा कुछ विषयों पर पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्रवाई की गई है, जो नीचे दिए गए हैं :-

तीसरा प्रवासी भारतीय दिवस 2005

तीसरा प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी 2005 तक मुम्बई में आयोजित किया गया। अनिवासी भारतीय और विदेशों में भारतीय मूल के लोग प्रभाग में नए गठित किए गए अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की इस समारोह के आयोजन में पूरी सचिवालय सहायता प्रदान की। प्रधान मंत्री ने समारोह का उद्घाटन किया और राष्ट्रपति जी द्वारा 15 प्रतिष्ठित अनिवासी भारतीयों/विदेशों में भारतीय मूल के लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए। इस समारोह से सरकार को प्रवासी भारतीयों की भावनाओं के साथ-साथ उनकी आकांक्षाओं को जानने तथा पारस्परिक लाभ के लिए प्रवासी भारतीयों के साथ कार्रवाई करने के लिए नीति विस्तृत ढांचा तैयार करने का अवसर दिया ।

तीन दिवसीय समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री ने सभी देशों में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को, जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से जाकर परदेस में रहने लगे हैं, दोहरी नागरिकता प्रदान करने की घोषणा की। प्रधान मंत्री की घोषणा के उपरान्त गृह मंत्रालय नागरिकता प्रमाण-पत्र तथा ओआईसी वीजा जारी करने के आवेदन पत्र, फार्म और फार्मेट को सरल बनाने के बारे में कार्रवाई कर रहा है। भारतीय नागरिकता अधिनियम और अनुपूरक नियमों में तदनुसार संशोधन किया जा रहा है और इसे सभी संबंधितों के लिए अधिसूचित किया जाएगा ।

अनिवासी भारतीयों/विदेशों में भारतीय मूल के लोगों से प्राप्त शिकायतें

विचाराधीन अवधि के दौरान इस प्रभाग को अनिवासी भारतीयों/विदेशों में भारतीय मूल के लोगों से भारत में अपनी सम्पत्ति पर गैर कानूनी कब्जे और अतिक्रमण के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए संबंधित राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है। अनिवासी भारतीयों/विदशों में भारतीय मूल के लोगों के साथ भारतीय लड़कियों की असफल और धोखाधड़ी से की गई शादियों के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि समस्याएं गंभीर होती जा रही थी इसलिए उक्त समस्याओं पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों से एक अलग कक्ष स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है। इनमें राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जिसकी रिपोर्ट में समस्या का शीघ्र समाधान चाहने वाली ऐसी महिलाओं की दुर्दशा पर विशेष प्रकाश डाला गया है, परामर्श और विधिक विकल्प उपलब्ध कराना शामिल है ।

■■

विदेश सेवा संस्थान

20

भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों और विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा विदेश सेवा संस्थान ने विदेशी राजनयिकों को प्रशिक्षण देने के अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा विदेशी राजनयिकों के लिए तीन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, विदेशी राजनयिकों के लिए एशिया के बारे में दो उन्नत पाठ्यक्रमों तथा फिलिस्तीनी राजनयिकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कनेडियाई राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम 21-24 मार्च 2005 तक आयोजित किया जाएगा। सेवारत भारतीय राजनयिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ परामर्श करके स्थापित किए गए विदेश सेवा संस्थान के वरचुअल कैम्पस का 27 जुलाई 2004 को विदेश मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। जिन भारतीय राजनयिकों ने सेवा के 18-20 वर्ष पूरे कर लिए हैं उनके लिए संस्थान ने विदेश नीति, सुरक्षा, आर्थिक एवं क्षेत्रीय मामलों के बारे में दो सप्ताह का एक आवासीय मिड-कैरियर मॉड्यूल का भी आयोजन किया है। वर्ष के दौरान विदेश सेवा संस्थान और बुल्गारिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान एवं नामीबिया के विदेश सेवा संस्थानों के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए ।

विदेश सेवा संस्थान ने वर्ष 2004 के दौरान न केवल भारतीय और विदेशी राजनयिकों को प्रशिक्षण देने बल्कि अन्य देशों में अपने समकक्ष संस्थानों के साथ सांस्थनिक संबंध बनाए रखने के लिए भी अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष के दौरान संस्थान के क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :

भारतीय राजनयिकों को प्रशिक्षण

सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए वरचुअल कैम्पस आरम्भ करना

विदेश सेवा संस्थान की स्थापना 1986 में की गई थी, जिसे मूलतः हमारे अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। इस उद्देश्य के अनुसरण में सक्षम अधिकारियों ने सेवारत अधिकारियों के लिए इन्टरनेट पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदित कर दिया। इन्टरनेट आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव इस तथ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था कि हमारे अधिकारी विभिन्न समय सारणियों वाले विश्व के अनेक क्षेत्रों में विभिन्न पदों एवं कार्यों पर अलग-अलग विखरे हुए हैं तथा अलग-अलग समयों पर मुख्यालय में अथवा किसी अन्य मिशन में स्थानांतरण पर अधिकारियों के आने जाने से पर्याप्त संख्या में ये अधिकारी मुख्यालय आधारित प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे ।

सेवाकालीन प्रशिक्षण में अधिकारियों के निम्नलिखित ग्रुपों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगाः

- लक्ष्य ग्रुप - 1 (टीजी - 1) 11-13 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी ।
- लक्ष्य ग्रुप - 2 (टीजी - 2) 18-20 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी ।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम टीजी - 1 में 1992 के बैच के अधिकारियों और टीजी - 2 में 1985 के बैच के अधिकारियों के जुलाई 2004 में शुरू हुआ। ऑन लाइनन प्रशिक्षण में दोनों ग्रुपों के लिए विदेश नीति, सुरक्षा, आर्थिक तथा क्षेत्रीय मसलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। टीजी - 2 कमे अधिकारियों के लिए विदेश सेवा संस्थान ने 3-14 जनवरी 2005 तक नई दिल्ली में दो सप्ताह के एक आवासीय मॉड्यूल का आयोजन किया गया। आवासी मॉड्यूल का उद्देश्य महत्वपूर्ण निर्णय निर्माताओं के साथ अन्योयाक्रिया करके ऑनलाइन शिक्षा को सम्पूर्ण करना है। दो सप्ताह के मॉड्यूल के भाग के रूप में टीजी - 2 के भागीदारों ने भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूर में 'अनुकूल प्रबंधन एवं नेतृत्व' से सम्बद्ध तीन सप्ताह के एक मॉड्यूल में भी भाग लिया ।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण

भारतीय विदेश सेवा के 2003 बैच के 9 प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 जनवरी 2005 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। व्याख्यानों, अन्योन्याक्रियात्मक सेमिनारों के साथ-साथ विभिन्न संस्थानों के दौरों के माध्यम से इस कार्यक्रम में अनेक विषयों को शामिल किया गया। पिछले वर्ष की भांति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मे विदेश एवं सुरक्षा नीति; आर्थिक नीति; अन्तर्राष्ट्ब्य नियम तथा विधिक मसले; प्रेस, संस्कृति एवं सूचना; कोंसली कार्य; कार्यात्यमक कौशल आदि शामिल किए गए। भागीदारों को इन विषयों की गहरी जानकारी उपलब्ध कराने, निकटवर्ती पड़ोस के बारे में उनके ज्ञान मे वृद्धि करने तथा विदेशों में भारतीय मिशनों के कार्य के बारे में उन्हें अवगत कराने की दृष्टि से कार्यक्रम में सार्क क्षेत्र के देशों के तीन अध्ययन दौरे भी शामिल किए गए थे। विदेश सेवा संस्थान ने 10 जनवरी 2005 को भारतीय विदेश

सेवा के 2000 बैच के 16 अधिकारियों के लिए एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है ।

भारतीय पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

विदेश सेवा संस्थान ने 'कूटनीति एवं भारतीय विदेश नीति' के संबंध में भारतीय संवाददाताओं के लिए एक वार्षिक पाठ्यक्रम शुरू किया। पहला कार्यक्रम 31 जनवरी-4 फरवरी 2005 तक आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री श्री के.नटवर सिंह ने किया। इस पाठ्यक्रम में 24 पत्रकारों ने भाग लिया ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

विदेश सेवा संस्थान ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2004 बैच के 92 परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 18 फरवरी 2005 को भारत की विदेश नीति के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया ।

■■

21

राजभाषा नीति का अनुपालन तथा विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार

विदेश मंत्रालय विदेशों में अपने मिशनों/केन्द्रों के साथ-साथ अपने कार्यालयों में हिन्दी के उन्नयन और प्रचार-प्रसार के लिए सभी प्रयास कर रहा है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अलावा यह विदेशों में भी हिन्दी के उन्नय और प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्विपक्षीय संधियां, करार, समझौता ज्ञापन, प्रत्यय पत्र, राष्ट्रपति के अभिभाषण, लोक लेखा समिति के पैराग्राफ, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले संसदीय प्रश्न द्वि-भाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं ।

मंत्रालय की विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की एक सूत्रबद्ध योजना है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में विजिटिंग हिन्दी प्राध्यापकों को नियुक्त करती है। विदेशों में भारतीय मिशन/केन्द्र केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा आयोजित पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी अध्ययन को प्रोत्साहन व सहायता प्रदान करते हैं। वर्ष 2004-05 में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में 100 सीटों में से हिन्दी सीखने के लिए 18 देशों के 43 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। विदेशों में स्थित मिशनों/केन्द्रों के कार्मिकों तथा एयरलाइन्स, बैंकों आदि जैसे संगठनों के अन्य अधिकारियों के बच्चों को हिन्दी सिखाने के लिए एक विशेष योजना के तहत विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति की गई ।

भारतीय मिशनों/केन्द्रों को उनके पुस्तकालयों के लिए और हिन्दी को बढ़ावा देने के कार्य में लगे शैक्षिक संस्थानों तथा विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को भेंट स्वरूप प्रदान करने के लिए हिन्दी शिक्षण सामग्री और भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य इतिहास और दर्शन शास्त्र जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित बाल साहित्य भेजा गया। विदेशों में स्थित मिशनों व केन्द्रों को 15 प्रमुख हिन्दी पत्रिकाएं भी भेजी जा रही हैं। पाठ्य पुस्तकों, शब्द कोशों, ऑडियो विजुअल कैसेटों, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, सी डी - रोम आदि सहित शैक्षिक सामग्री भी नियमित आधार पर भेजी जा रही है। कुछ मिशनों को कम्प्यूटर भेंट किए गए ।

मिशन/केन्द्र स्थानीय संगठनों और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखते हैं और हिन्दी भाषा से संबंधित उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारे कुछ मिशनों/केन्द्रों ने हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी सम्मेलन, साहित्यिक समारोह, हिन्दी निबंध प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया। लन्दन येरेवान और काठमाण्डू जैसे कतिपय भारतीय मिशन हिन्दी पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं। विदेशों में भारतीय संस्कृति के साथ-साथ हिन्दी के शिक्षण और उसे बढ़ावा देने के कार्य में जुटे संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बुडापेस्ट स्थित भारतीय दूतावास को उच्चतर शिक्षा के लिए हिन्दी कक्षाएं जारी करने के लिए 1.75 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। हिन्दी दिवस पर हिन्दी के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न मिशनों को अनुदान दिया गया। लन्दन मिशन ने मंत्रालय की वित्तीय सहायता से 'भारत भवन' पत्रिका प्रकाशित की ।

विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए बुखारेस्ट (रोमानिया) में 1-3 जुलाई 2004 तक एक क्षेत्रीय हिन्दी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 7 राष्ट्रों के 17 विद्वान आमंत्रित किए गए थे। मंत्रालय ने भी इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया। इन देशों के विद्वानों द्वारा सम्मेलन की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई ।

नेपाल मिशन ने विद्यार्थियों के लिए इन्टरमिडिएट स्तर पर 6 छात्रवृत्तियां और स्नातक स्तर पर एक छात्रवृत्ति आरम्भ की। इससे हिन्दी के लिए पड़ोसी देश में अच्छी भावना प्रदर्शित होगी ।

संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को एक भाषा के रूप में लागू कराने के लिए विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। इस संबंध में कतिपय रचनात्मक बैठकें आयोजित करने के फलस्वरूप सभी संबंधितों से सूचना मंगाई गई और समर्थन दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुनिन्दा देशों में भारतीय मूल के लोगों को संगठित करने और संचार माध्यमों का उपयोग करने का प्रस्ताव है। विदेशी प्रचार प्रभाग से पर्याप्त सहायता ली जा रही है और इस विषय पर लेख आमंत्रित किए जा रहे हैं जिन्हें विश्व भर में परिचालित किए जाने पर विचार किया जा रहा है ।

मंत्रालय में सितम्बर 2004 में हिन्दी पखवाड़ा आयोजित

किया गया था। हिन्दी टिप्पण/आलेखन, हिन्दी निबन्ध लेखन, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टंकण और हिन्दी गीत/कविता गायन जैसे विभिन्न प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। विदेशों में स्थित कई मिशनों/केन्द्रों में हिन्दी दिवस मनाया गया जिसके लिए मंत्रालय ने हिन्दी बजट से पर्याप्त अनुदान दिया ।

हिन्दी, विदेश सेवा संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। नए प्रशिक्षुओं को उनके विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सरकार की राजभाषा नीति और इसके कार्यान्वयन (नियमों और विनियमों) के बारे में गहण प्रशिक्षण दिया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 28 जनवरी 2004 को आयोजित की गई। संसदीय राजभाषा समिति ने 14 अगस्त 2004 को पासपोर्ट कार्यालय भोपाल और 27 अक्तूबर 2004 को पासपोर्ट कार्यालय चेन्नई का निरीक्षण किया ।

कई देशों में भाषांतरकारों का एक पैनल बनाया गया है। जब संबंधित देशों के गण्यमान्य व्यक्ति यात्रा पर आते हैं तब यह पैनल मिशन में उपलब्ध रहता है ।

■■

लिंग संबंधी मामले

22

मंत्रालय अपने सभी कार्मिकों के बीच लिंग साम्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला अधिकारियों को चुनौतीपूर्ण पद और कार्यभार स्वीकार करने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं और इस समय 15 महिला अधिकारी विदेशों में राजदूतों/उच्चायुक्तों/स्थायी प्रतिनिधियों/महा कोंसलों के रूप में तैनात हैं। इस समय 15 महिला अधिकारी सचिव स्तर पर कार्यरत हैं तथा इसके अलावा 7 महिला अधिकारी अपर सचिव स्तर पर 24 संयुक्त सचिव स्तर पर और 17 निदेशक स्तर पर कार्य कर रही हैं। महिला अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और युनेस्को जैसे इससे संबंधित संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

विदेश मंत्रालय में विभिन्न संवर्गों में महिला अधिकारियों की तैनाती परिशिष्ट - XIX पर दी गई है ।

कार्य स्थल पर महिला अधिकारियों के शारीरिक शोषण की शिकायतों के निवारण के लिए और राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे संस्थानों/निकायों के साथ समन्वय और अन्योन्यक्रिया के लिए मंत्रालय में एक महिला सैल है। इस सैल के प्रमुख अपर सचिव स्तर के अधिकारी हैं ।

■■

23

सांस्कृतिक संबंध

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (जिसे इसके बाद इसमें 'परिषद' अथवा 'भा.सा.सं. प.' कहा गया है) की औपचारिक स्थापना 1950 में हुई जिसका उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और आपसी समझ-बूझ को स्थापित करना, पुनर्जीवित करना तथा उसे मजबूत करना है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं -

(i) भारत सरकार की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का नियमन;

(ii) प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान;

(iii) सेमिनारों तथा संगोष्ठियों का आयोजन तथा उनमें भाग लेना;

(iv) मंचीय कलाओं और उनकी मंडलियों का आदान-प्रदान;

(v) विदेशों में भारतीय अध्ययन के लिए पीठ एवं प्रोफेसरशिप स्थापित करना और उसे कायम रखना;

(vi) पुस्तकों तथा वाद्ययंत्रों को उपहार स्वरूप प्रदान करना;

(vii) विदेश मंत्रालय की ओर से मौलाना आजाद स्मारक व्याख्यानमाला तथा मौलाना आजाद निबंध प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यक्रमों का वार्षिक आयोजन;

(viii) जवाहर लाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के लिए सचिवालय की व्यवस्था;

(ix) प्रकाशन;

(x) विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र कायम करना तथा विशेष द्विपक्षीय कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना ।

अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों को छात्रवृत्तियां और उनका हित चिन्तन

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के प्रमुख कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप है - विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। परिषद् स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेट स्तर के कार्यक्रमों के साथ साथ इंजीनियरी, फार्मेसी, व्यापार प्रबन्धन, लेखा विधि और प्रबन्धन जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। छात्रवृत्ति कार्यक्रम में विकासशील देशों, खासतौर पर पड़ोसी राष्ट्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है । वर्ष 2004-2005 के दौरान विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परिषद् द्वारा लगभग 1200 नई छात्रवृत्तियों की पेशकश की गई । इस वर्ष छात्रवृत्तियों के उपयोग का प्रतिशत लगभग 60 प्रतिशत रहा है । विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत में 75 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1500 से अधिक विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं ।

विदेशी विद्यार्थियों के सामान्य हित चिन्तन की देखभाल करने के अपने अधिदेश के अन्तर्गत परिषद् ने विद्यार्थी शिविरों का आयोजन किया ताकि विद्यार्थियों को भारतीय जीवन और धरोहर के बहुमुखी पहलुओं से परिचित कराया जा सके । उपर्युक्त अवधि के दौरान सिक्किम/दार्जिलिंग , शिमला/कुल्लू/मनाली तथा नैनीताल/रानीखेत/अल्मोड़ा में एक एक ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किए गए । प्रत्येक शिविर में लगभग 45 विदेशी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया । भारतीय कला और संस्कृति की एक विहंगम तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए परिषद् के अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी स्कन्ध ने भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया । परिषद् के संस्थापक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयन्ती मनाने के लिए वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय छात्र समारोह नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में 7 दिसम्बर, 2004 को मनाया गया ।

अपनी बकाया छात्रवृत्ति के आहरण के लिए दिल्ली में अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थियों को ए.टी.एम. कार्ड जारी करने के परिषद् के प्रस्ताव के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और अब परिषद् इस बात पर विचार कर रही है कि बंगलूर और हैदराबाद में अध्ययन कर रहे आई सी सी आर के अध्येताओं को भी यह सुविधा प्रदान कर दी जाए ।

विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र

विदेशों में भारत की सांझी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने की दृष्टि से परिषद् निम्नलिखित स्थानों पर सांस्कृतिक केन्द्र चला रही है - काहिरा (मिस्र) , बर्लिन (जर्मनी) , पोर्ट लुई (मॉरीशस) , पारामारिबो (सूरीनाम) , जार्ज टाउन (गयाना) , जकार्ता (इण्डोनेशिया) जिसका एक उपकेन्द्र बाली में भी है, मास्को (रूसी परिसंघ) , लंदन (यूनाइटेड किंगडम) , अल्माटी (कजाखिस्तान) , ताशकंद (उजबेकिस्तान) , डर्बन तथा जोहानिसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) , पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद तथा टोबैगो) , कोलम्बो (श्रीलंका) , दुशान्बे (ताजिकिस्तान), क्वाला लम्पुर (मलेशिया) तथा सूवा (फिजी) , जिसका एक उपकेन्द्र लाउतोको में भी है । परिषद् बंगलादेश के ढाका में एक संगीत एवं नृत्य अकादमी का वित्तपोषण भी कर रही है।

सांस्कृतिक केन्द्रों की गतिविधियों में स्थानीय जनता की सांस्कृतिक आवश्यकताएं प्रतिबिम्बित होती है । ये केन्द्र वार्ता, व्याख्यान, दृश्यकलाओं की प्रदर्शनियों , निबंध प्रतियोगिताएं, नृत्य एवं संगीत की प्रस्तुति , नाटकों का मंचन, भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन , समाचार बुलेटिनों का प्रकाशन, समसामयिक मुद्दों पर संगोष्ठियां आदि आयोजित करते हैं । भारतीय संगीत, नृत्य, तबला, योग और हिन्दी की नियमित अध्यापन कक्षाएं कुछ केन्द्रों पर चलाई जाती है । इन केन्द्रों पर पुस्तकालय, वाचनालय और श्रव्य दृश्य सामग्री के संग्रह भी आगन्तुकों के लिए संचालित किए जाते हैं । स्वयं के क्रियाकलापों के आयोजन के अलावा ये सांस्कृतिक केन्द्र विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के समन्वय के लिए भारतीय मिशनों के सहायक की भूमिका भी निभाते हैं । ये केन्द्र स्थानीय नागरिकों खासतौर से विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों, मतनिर्माताओं और सांस्कृतिक हस्तियों के साथ संपर्क विकसित करते हैं ताकि भारत की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत की जा सके ।

विदेशों में भारतीय अध्ययन के अतिथि प्रोफेसर और पीठ

द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों और विदेशों में हिन्दी के प्रचार प्रसार की योजना के अधीन तथा परिषद् के अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद् विदेशों में भारतीय भाषाओं और अन्य संगत विषयों को पढ़ाने के लिए भारतीय अध्ययन पीठों का संचालन करती है । इस समय 19 प्रोफेसर पारामारिबो (सूरीनाम) , बुदापेस्त (हंगरी) , मास्को (रूस) , सियोल (दक्षिण कोरिया) , वारसा (पोलैण्ड-हिन्दी और तमिल के दो पद) , पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद और टोबैगो- हिन्दी और आधुनिक भारतीय इतिहास/दक्षिण एशियाई मामले के दो पद), अंकारा (तुर्की) , सोफिया (बल्गारिया) , बुखारेस्ट (रोमानिया) , बीजिंग (चीन) , मेड्रिड (स्पेन) , बैंकाक (थाईलैण्ड) , पेरिस (फ्रांस) , ओश (किरगिस्तान) , ताशकन्द (उजबेकिस्तान) , ब्रसेल्स (बेल्जियम) तथा मोका (मॉरीशस) में हिन्दी, संस्कृत , तमिल , आधुनिक भारतीय इतिहास , भारतीय सभ्यता का अध्यापन कर रहे हैं । परिषद् ने आधुनिक भारतीय अध्ययन का एक अतिथि प्रोफेसर पोलैण्ड भेजा । भारतविद्या और भारतीय अध्ययन में पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विदेशी केन्द्रों/संस्थाओं को भी परिषद् की ओर से सहायता प्रदान की जाती रही है ।

प्रकाशन

अपने प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद् पाँच भिन्न-भिन्न भाषाओं में नियमित रूप से छः जर्नल प्रकाशित करती है । ये जर्नल हैं - गगनांचल (हिन्दी) , अफ्रीका क्वार्टरली और इण्डियन होराइजन्स (अंग्रेजी) , तकाफत उल हिन्द (अरबी),पीपल्स द ल इण्दिया (स्पेनिश) और रिकोन्त्रे एवेक ल इन्दे (फ्रेंच) ।

इस अवधि के दौरान परिषद् ने “कन्टेम्परेरी रेलीवेन्स ऑफ सूफिज्म” नामक अपने प्रकाशन का अरबी भाषा में एक संस्करण निकाला । परिषद् ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया द्वारा 21 से 29 अगस्त, 2004 तक आयोजित दसवें दिल्ली पुस्तक मेले में भी हिस्सा लिया । परिषद् ने गांधी जयन्ती के अवसर पर हरियाणा के करनाल में आयोजित एक पुस्तक प्रदर्शनी में भी भाग लिया । भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के प्रमुख जर्नल “इण्डियन होराइजन्स” का नवीनतम संस्करण अब एक बिलकुल नए रूप और सज्जा के साथ प्रकाशित किया गया है ।

भेंट

उपर्युक्त अवधि के दौरान भारतीय संस्कृति, कला, वास्तुकला, इतिहास, नृत्य एवं संगीत के बारे में पुस्तकें, कलात्मक वस्तुएं, श्रव्य दृश्य सामग्री , वाद्य यन्त्र आदि निम्नलिखित 29 देशों को विदेश में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से वहां के अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा स्थानीय उच्चाधिकारियों , पुस्तकालयों, संस्थाओं और विद्यालयों को भेंट स्वरूप देने के लिए भेजे - आजरबैजान , बंगलादेश, ब्राजील, ब्रेलग्राद, बेलरूस, कनाडा, चीन, चिली, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया,

कोरिया, किरगीजिस्तान, कजाखिस्तान, लंदन (यूनाइटेड किंगडम), मंगोलिया, मॉरीशस, मलेशिया, नाईजीरिया, न्यूजीलैण्ड, पुर्तगाल, पोलैण्ड, पनामा, अमेरिका, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, उजबेकिस्तान, थाईलैण्ड और जाम्बिया ।

पुस्तकालय

1950 में स्थापित भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के पास मुख्यतः भारतीय इतिहास , कला और संस्कृति के बारे में 50 हजार खण्डों का एक संग्रह है । परिषद् विभिन्न समाचार पत्र और जर्नल भी मंगवाता है। परिषद् के पुस्तकालय का मुख्य आकर्षण है - उर्दू , अरबी और फारसी भाषाओं की 195 दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संग्रह । ये पाण्डुलिपियां और अन्य दुर्लभ पुस्तकें तथा माइक्रोफिल्मों के रोल पुस्तकालय के एक विशेष खण्ड में रखे हैं जिसे "गोशा-ए-आजाद" का नाम दिया गया है । भारत विद्या के शोधकर्ताओं के लिए यह पुस्तकालय एक वरदान है । परिषद् का पुस्तकालय डेलनेट का सदस्य है।

परिषद् का पुस्तकालय मुख्य रूप से शोधकर्ताओं और संगठनों/संस्थाओं को परामर्श एवं अन्तस्पुस्तकालयी पुस्तक ऋण उपलब्ध कराने के साथ साथ संदर्भ पुस्तकालय का काम करता है । इच्छुक शोधार्थियों , आम जनता के लोगों को विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विभाग प्रमुखों के संस्तुतिपत्र के आधार पर अथवा अन्य संगठित पुस्तकालयों की सदस्यता के आधार पर पुस्तकालय का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है । अप्रैल से नवम्बर 2004 तक की अवधि के दौरान लगभग 2000 आगन्तुकों ने परिषद् के पुस्तक संसाधनों का प्रयोग किया ।

पुस्तकालय में उर्दू, अरबी, फारसी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध 125 पाण्डुलिपियों , दुर्लभ पुस्तकों, मौलाना आजाद के भाषणों, मौलाना आजाद व्याख्यानमालाओं, पाण्डुलिपियों की सूचियों को संरक्षण और संवितरण के उद्देश्य से डिजिटल रूप दिया गया है । परिषद् के पुस्तकालय ने भारत के सांस्कृतिक राजनय और मौलाना आजाद की विज्ञान , प्रौद्योगिकी और विकास संबंधी दृष्टि के बारे में हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में शोध के लिए 6 अल्पकालीन पुस्तकालय अध्येतावृत्तियां प्रदान की हैं । परिषद् ने अपनी वेबसाइट को खुद ही नया रूप देने का काम प्रारम्भ किया है।

प्रदर्शनियां

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद् ने महात्मा गांधी की दो और राजीव गांधी की एक आवक्ष मूर्तियां प्राप्त करके क्रमशः ब्यूनसआयर्स , पेरिस और पोर्टलुई में स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए भेजीं ।

परिषद् ने निम्नलिखित 6 बड़ी प्रदर्शनियां भी प्रेषित की - (1) "माई लैण्ड माई पीपुल" नामक फोटोग्राफिक प्रदर्शनी सेसेल्स, जिम्बाबवे और नामीबिया में (2) "सेलेब्रेटिंग वूमेन-अमृता शेरगिल रीविजिटेड" नामक प्रदर्शनी भारत उत्सव के दौरान मंगोलिया और मास्को में तथा उजबेकिस्तान, किरगीजिस्तान, कजाखिस्तान में । (3) "मधुबनी चित्रकला" के बारे में एक प्रदर्शनी स्थायी रूप से प्रदर्शित किए जाने हेतु पोर्ट ऑफ स्पेन में (4) "म्यूराल्स ऑफ इण्डिया" की प्रदर्शनी स्थायी रूप से प्रदर्शन हेतु नेहरू केन्द्र, लन्दन में (5) "इण्डियन डॉल्स एण्ड ड्रेसेस" बेलग्राद में (6) समसामयिक रेखाचित्र प्रदर्शनी पोलैण्ड में और कलेण्डर पर 12 चित्रकलाएं स्थायी रूप से प्रदर्शित किए जाने हेतु नेहरू केन्द्र, लन्दन में ।

इसके अलावा परिषद् ने नई दिल्ली में बाहर से आई दो प्रदर्शनियों अर्थात 9 से 18 सितम्बर, 2004 तक टॉमस पाइसेकी और माईकेल पाईसेकी द्वारा "पोस्टर्स एण्ड सिम्बल्स" नामक स्लोवाक गणराज्य से आयी प्रदर्शनी और 11 से 16 अक्तूबर, 2004 तक किरगिजिस्तान से आई चित्रकला एवं हस्तशिल्प मेला प्रदर्शनी का आयोजन भी किया । परिषद् ने पंचशील की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष आवरण पृष्ठ, स्मारक टिकट और सैशे के मुद्रण का कार्य किया और बाली से ऋषिकेष तक पदमासन के परिवहन की भी व्यवस्था की ।

देश में आने वाले और देश से बाहर जाने वाले विशिष्ट आगन्तुक कार्यक्रम

भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों तथा आपसी समझबूझ को बढ़ावा देने के और सुदृढ़ करने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में परिषद् प्रतिष्ठित आगन्तुक कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्वानों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और कलाकारों के आदान प्रदान के कार्य को सुकर बनाती है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद् ने विश्व के अलग अलग देशों से आए 18 आगन्तुकों / शिष्टमण्डलों की मेजबानी की । अलग अलग विषयों पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं अथवा व्याख्यानों में भागीदारी के लिए विविध क्षेत्रों के 53 विशिष्ट भारतीयों को उनके समकक्षों के साथ सम्पर्क हेतु प्रायोजित किया । उक्त अवधि के दौरान परिषद् ने तीन विदेशी विद्वानों को अभिमुखीकरण अनुदान उपलब्ध कराया ।

सृजनात्मक वार्ता (अवार्ड/संगोष्ठी/विचार गोष्ठियां)

अन्तर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार

राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में अन्तर्राष्ट्रीय समझ बूझ के लिए वर्ष 2003 का जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार 9 जुलाई, 2004 को सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री गोह चोक तोंग को प्रदान किया गया ।

मौलाना आजाद निबन्ध प्रतियोगिता

मौलाना आजाद निबन्ध प्रतियोगिता 2002 के लिए पुरस्कार वितरण का आयोजन 4 सितम्बर 2004 को उप राष्ट्रपति निवास पर किया गया । माननीय उप राष्ट्रपति ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए ।

परिषद् ने “दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का सांस्कृतिक राजनय - चुनौतियां एवं अवसर” नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 3 से 5 जुलाई , 2004 तक करने के लिए भारतीय समुद्र अध्ययन सोसायटी, हैदराबाद को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी और साथ ही “रीविजनिंग मुम्बई” विषय पर एक दो दिवसीय सम्मेलन 29 से 30 अक्तूबर, 2004 तक आयोजित करने के लिए एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुम्बई को भी वित्तीय सहायता प्रदान की ।

मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मारक व्याख्यान

मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मारक 36वां व्याख्यान 14 दिसम्बर , 2004 को लार्ड मेघनाद देसाई द्वारा दिया गया ।

मंचीय कलाएं

उपर्युक्त अवधि के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने दुनिया के सभी महाद्वीपों में फैले 70 देशों में भारत से जाने वाले 64 सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों की यात्राएं प्रायोजित की। इन यात्राओं का प्रायोजन करते समय मंचीय कलाओं के अलावा स्थानीय कलाकारों के साथ कार्यशालाओं और व्याख्यानों का आयोजन करने पर विशेष बल दिया गया । इन शिष्टमण्डलों में युवा कलाकारों और लोक कलाकारों की संख्या काफी अधिक थी ।

जिन प्रमुख समारोहों / कार्यक्रमों में भारतीय मंचीय कलाकार समूह ने हिस्सा लिया उनमें से कुछ इस प्रकार हैं - बंगलादेश में दूसरा सार्क सांस्कृतिक समारोह, अमेरिका के क्लीव लैण्ड में वार्षिक त्यागराज समारोह, पोलैण्ड-साकराल संगीत समारोह, अमेरिका में हैरिटेज इण्डिया समारोह , क्रोएशिया में 2004 का ग्रीष्म कालीन डुब्रोवनिक समारोह , रूस में विश्व चाय समारोह, राष्ट्रकुल के देशों में फैशन प्रदर्शनी , चीन में पंचशील की वर्षगांठ का समारोह , दक्षिण कोरिया में बसन्तोत्सव और ग्वाचेन समारोह , दक्षिण अफ्रीका में ग्राम्स टाउन थिएटर समारोह, गयाना में भारतीय श्रमिकों के आगमन के 150 वर्ष पूरे होने संबंधी समारोह , कैरीबियन में भारतीयों के आगमन के 150 वर्ष पूरे होने संबंधी समारोह, वियतनाम में ह्यू फेस्टिवल और कोलम्बिया में भारत उत्सव , ओसलो में थिएटर उत्सव , कनाडा में भारतीय संस्कृति के दिन नामक समारोह, डबलिन में ओसलिन समारोह, यूनाइटेड किंगडम में एडिनबर्ग समारोह, बेलग्राद में लघु भारत समारोह , स्पेन में तोलोसा अन्तर्राष्ट्रीय कठपुतली - इण्डिया विंडो समारोह , मैक्सिको में सर्वेटिनो समारोह, वेनेजुएला में बार्सिलोना समारोह और भूटान में इमत्रात संस्थापना समारोह ।

भारत के विभिन्न नगरों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पूरी दुनिया के देशों से भारत आने वाले मंचीय कलाकारों/ मण्डलियों की यात्राओं का आयोजन भी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा किया जाता है । इन समूहों की मेजबानी द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के साथ साथ विदेश स्थित भारतीय मिशनों की सिफारिशों के जवाब में तथा भारत स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों/सांस्कृतिक केन्द्रों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर की जाती है । उपर्युक्त अवधि के दौरान परिषद् ने 8 देशों से भारत आए 8 विदेशी सांस्कृतिक समूहों की यात्राओं की मेजबानी की । ये समूह त्रिनिदाद एवं टोबैगो , मिस्र , नेपाल, इण्डोनेशिया, अंगोला, पोलैण्ड और श्रीलंका से वर्तमान सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत और इन कार्यक्रमों के अलावा भी आए । पिछले अनेक वर्षों से परिषद् भारतीय कला मंचन की अपनी “होराइजन” और “रीट्रॉस्पेक्टिव्स” नामक श्रृंखलाओं के अन्तर्गत नई दिल्ली एवं अन्य शहरों में उदीयमान तथा प्रतिष्ठित कलाकारों का प्रदर्शन आयोजित करती रही है । अपनी “रीट्रॉस्पेक्टिव्स” श्रृंखला के अन्तर्गत परिषद् ने पैनल में शामिल प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा प्रदर्शन आयोजित किए । परिषद् ने भारत में रह रहे विदेशी कलाकारों के नृत्य एवं संगीत के प्रदर्शन भी कराए ।

विविध परियोजनाएं

कम्बोडिया सरकार के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई वचनबद्धता के एक हिस्से के रूप में कम्बोडिया के सुविधाहीन एवं दलित समाज के बच्चों के उपयोग हेतु पांच कम्प्यूटर क्योस्कों की स्थापना की है । भारत सरकार की ओर से परिषद् द्वारा किए गए इन प्रयासों का कम्बोडियाई पक्ष की ओर से स्वागत हुआ है । परिषद् को कम्बोडिया में

एक पारम्परिक एशियाई वस्त्र म्यूजियम की स्थापना से जुड़ा काम भी सौंपा गया है । इस परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है जबकि इसके लिए भूमि कम्बोडिया सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है ।

लेखा

वर्ष 2004-2005 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् का अनुमोदित बजट अनुमान 5,590 लाख रूपए का है । अनुमानित प्राप्तियां 40 लाख रूपए की हैं ।

■■

विश्व कार्य संबंधी भारतीय परिषद

भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से विश्व कार्य संबंधी भारतीय परिषद की स्थापना 1943 में की गई थी। देश में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए यह एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित केन्द्र है। राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किए जाने के बाद, आईसीडब्ल्यूए ने अपने अधिदेश के अनुसरण में, क्रियाकलापों का एक ओजस्वी कार्यक्रम आरम्भ किया है। इसका लक्ष्य, अपनी संगोष्ठियों, प्रकाशनों, व्याख्यानों और विशेषीकृत पुस्तकालय के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली की जटिलताओं की मूल समझ की जानकारी प्रदान करना ।

सप्रु हाऊस बिल्डिंग

बहुत सिविल मरम्मत कार्य आरम्भ किया गया और उसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। सप्रु हाऊस को, राष्ट्रीय महत्व के किसी संस्थान को इसमें स्थापित करने के लिए उचित दर्जा दिया जा रहा है। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी और महाराणा रणजीत सिंह ट्रस्ट के अधिकार वाले सप्रु हाऊस बिल्डिंग के भाग को खाली करा लिया गया है। उनके द्वारा खाली किए गए भाग को अनुसंधानरत विद्यार्थियों के लिए उपयोग में लाया जाएगा ।

सहायता अनुदान

आईसीडब्ल्यूए के लिए वर्ष 2004-05 के लिए 1.65 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान का अनुमान लगाया गया और उसे अनुमोदित किया गया ।

प्रकाशन

अपने आवधिक प्रकाशनों, इण्डिया क्वार्टरली और फॉरेन अफयर्स रिपोर्ट के अलावा, परिषद ने विदेश मंत्रालय के पूर्व विदेश सचिव श्री शशांक द्वारा दिया गया भाषण थर्ड अफ्रीका डे नामक अन्य प्रकाशन भी प्रकाशित किया ।

एशिया पेसिफिक में सुरक्षा और सहयोग परिषद, भारत का सचिवालय और अफ्रीका केन्द्र

एशिया पेसिफिक में सुरक्षा और सहयोग परिषद भारत के सचिवालय को सप्रु हाऊस में पुनर्स्थापित किया गया है। (1) 'चीन : दक्षिण पूर्व एशिया में उभरती एक शक्ति' (2) 'बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग' और (3) 'बाली से वियनटिएन तकः इण्डिया-एशियन भागीदारी के लिए रोडमैप' विषयों पर राजदूत ए.एन.राम की अध्यक्षता में संगोष्ठियां आयोजित की गई। 'इण्डोनिशिया में चुनाव' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता जे.एन.यू. के प्रोफेसर एस.डी. मुनी द्वारा की गई। इन संगोष्ठियों में प्रतिष्ठित पत्रकारों और शिक्षाविदों ने भाग लिया ।

पुस्तकालय

मरम्मत, नवीनीकरण, स्थान विस्तार के बाद सप्रु हाऊस के पुस्तकालय को वातानुकूलित किया गया और इसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के लिए एक संदर्भ पुस्तकालय के रूप में उपयोग किए जाने के लिए बेहतर बनाया गया। इस अवधि के दौरान 994 शीर्षकों पर पुस्तकों, धारावाहिकों और जिल्द बंद पत्रिकाओं को शामिल करके इसके विशाल में मौजूदा संग्रह का परिवर्धन किया गया। पुस्तकालय को भारत और विदेशों से 390 शीर्षकों पर अनुसंधान पत्रिकाएं और महत्वपूर्ण दैनिक प्रकाशन प्राप्त हुए। इनमें से 201 शीर्षकों पर विख्यात पत्रिकाओं को अनुसंधानरत विद्यार्थियों के लिए 'समसामयिक ज्ञान सेवा' के एक भाग के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व राजनीति संबंधी महत्वपूर्ण लेखों की लगभग 3700 प्रविष्टियां भारत और विदेश दोनों की अनुसंधान पत्रिकाओं से तैयार की गई। प्रयोक्ताओं के लिए संदर्भ संबंधी सहायता के एक भाग के रूप में आईसीडब्ल्यूए की जुलाई 2003 से सितम्बर 2004 की फॉरेन अफेयर्स रिपोर्ट के खण्ड 2 और 3 में प्रकाशनार्थ समसामयिक घटनाओं संबंधी विषयों की चयन सूचियां तैयार की गई ।

यूनएनडीपी की पूर्ण न्यासी योजना के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयार्क से लगभग 5350 नए दस्तावेज प्राप्त किए और इसके संग्रह में शामिल किए गए। इसी तरह, यूरोपीय संघ और भारतीय सरकार के लगभग 1600 प्रकाशन पुस्तकालय द्वारा प्राप्त किए गए और उन्हें प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, 8 बड़े राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और 4 क्षेत्रीय समाचार पत्रों से 36000 प्रेस किलिपिंग चुनी गई जिसने संग्रह की संख्या को लगभग 2.9 मिलियन तक पहुंचा दिया ।

10,608 से भी अधिक आगन्तुकों ने अपने अनुसंधान कार्य और संदर्भ के लिए पुस्तकालय का उपयोग किया। इस अवधि के दौरान 219 अनुसंधानरत विद्यार्थियों, विषय विशेषज्ञों, पत्रकारों और अन्य को पुस्तकालय के सदस्यों के रूप में

नामांकित किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अनुसंधानरत विद्यार्थियों ने अपने अनुसंधान कार्य के लिए पुस्तकालय सामग्री का उपयोग किया। महत्वपूर्ण विद्यालयों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, मदुरै विश्वविद्यालय, कर्नाटक विश्वविद्यालय, बंगलौर विश्वविद्यालय, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, गुलाब सिंह हिन्दु कॉलेज, बिजनौर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, दिल्ली विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय आदि सम्मिलित थे ।

अफ्रीकी राष्ट्रों के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए पुस्कालय में विशेष रूप से बनाए गए अफ्रीका केन्द्र में महत्वपूर्ण पठन सामग्री को शामिल किया। पुस्तकालय का स्वचलन कार्य प्रगति पर है। इस प्रयोजनार्थ एक पृथक मल्टीमीडिया सेक्सन भी सृजित किया गया है ।

सेमिनार/गोष्ठी/सम्मेलन

आईसीडब्ल्यूए ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अनेक सेमिनार, गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किए। सेनेगल गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम डा. चेख टीडीआने गाडिओ, होहेनजोलर्न-बेरीनगन, रोमानिया के राजकुमार महामहिम रादु द्वारा विशेष भाषण दिए गए। परिषद ने 'पंचशील' संबंधी एक बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किया जिसमें 13 विदेशी और 6 भारतीय प्रतिनिधिमण्डलों ने भाग लिया। विदेश मंत्री श्री के.नटवर सिंह ने सेमिनार का उद्घाटन किया। 'भारत-अफ्रीकी संबंधों में उभरती प्रवृत्तियों' संबंधी एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार भी परिषद द्वारा आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री राव इन्द्रजीत सिंह द्वारा किया गया। सम्पूर्ण सूची अनुबन्ध-। पर दी गई है ।

■■

25

गुट-निरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान तथा सूचना प्रणाली

अनुसंधान तथा सूचना प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों तथा विकास सहयोग में विशेषीकृत नई दिल्ली आधारित विचारक है। अनुसंधान तथा सूचना प्रणाली विदेश मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसके प्रादेश में, समय-समय पर यथा-सन्दर्भित, क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय सहयोग प्रबन्धों सहित बहु-पक्षीय आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दों से सम्बन्धित मामलों पर भारत सरकार के परामर्शदात्री निकाय के रूप में इसका कार्यकरण शामिल है। अनुसंधान तथा सूचना प्रणाली में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देश के विचारकों के बीच प्रभावशाली नीतिगत बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के तौर पर परिकल्पना की जाती है।

वर्ष 2004-05 के दौरान अनुसंधान तथा सूचना प्रणाली के कार्यों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गयी हैं :-

सरकार को मुहैया कराए गए अनुसंधान तथा नीतिगत निवेश

अनुसंधान तथा सूचना प्रणाली ने नीतिगत निरूपण तथा प्रमुख शीर्ष बैठकों के लिए तैयारी तथा वर्ष में हुए अन्य विचार-विमर्श में सहायता प्रदान करने के लिए अनुसंधान अध्ययन कराया। इन अध्ययनों में से कुछ निम्नलिखित हैं :-

- भारत-आसियान सम्मेलन तथा सम्बन्धित घटनाएं : आरआईएस ने आसियान विचारकों, जिन्होंने नवम्बर, 2004 में हुई वियतनामी शिखर बैठक में हस्ताक्षर किए गए भागीदारी करार का आधार तैयार किया, के साथ परामर्श करके आसियान-इंडिया विजन-2020 पर एक दस्तावेज तैयार किया । आरआईएस में आसियान एकोनामिक कम्युनिटी पर नोट सहित शिखर बैठक की तैयारियों में एमईए तथा पीएमओ के निवेशों (इनपुट) को मुहैया कराया है। अक्तूबर, 2004 में नई दिल्ली में हुई भारत-आसियान बिजनेस शिखर बैठक के लिए तैयार करने में पीएमओ को भी इनपुट मुहैया कराए गए थे।
- सार्क मंत्रिस्तरीय बैठक : साफ्टा और इससे परे" सार्क के लिए एक एजेन्डाँ पर एक नोट माननीय विदेश मंत्री भारत सरकार को 17 जुलाई, 2004 को भेजा गया था जिस पर उनके द्वारा ब्रीफिंग मीटिंग बुलाई गई थी।
- सार्क की ढाका शिखर बैठक के लिए तैयारियां : आरआईएस ने सार्क के भावी निदेशों पर दो नीतिगत नोट तैयार किए हैं और इसे एमईए को प्रस्तुत कर दिया है। इसके अलावा, शिखर बैठक की तैयारी सम्बन्धी एक नोट पीएमओ को प्रस्तुत कर दिया गया है।
- एनएएम मंत्रिस्तरीय बैठक डरबन दक्षिण-अफ्रीका, 17-19 अगस्त, 2004 एनएएम की मध्यावधि मंत्रालयी बैठक के लिए इनपुट के लिए क्रमशः 6 अगस्त, 2004 तथा 11 अगस्त, 2004 को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित परिचर्चा बैठकों में आरआईएस ने भाग लिया। तदनन्तर एनएएम के लिए आर्थिक एजेन्डे पर एक नोट 12 अगस्त, 2004 को भेज दिया गया।
- बीआईएमएसटीईसी शिखर-बैठक : बीआईएमएसटीईसी के भावी निदेशों पर संशोधित रिपोर्ट बंगाल की खाड़ी आर्थिक समुदाय को एमईए को मुहैया कराया गया।
- भारत-ब्राजील-दक्षिण-अफ्रीका (आईबीएसए) : विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुरोध पर भारत-ब्राजील तथा दक्षिण-अफ्रीका के बीच सम्भावी आर्थिक भागीदारी पर आरआईएस ने एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार किया।
- भारत-चीन संयुक्त अध्ययन दल : दल के एक सदस्य के तौर पर, डीजी-आरआईएस ने दिल्ली (जुलाई, 2004) तथा बीजिंग (दिसम्बर, 2004) में हुई संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) की बैठकों में भाग लिया। आरआईएस ने विदेश मंत्रालय की ओर से मसौदा भारतीय इनपुट को तैयार करने के अतिरिक्त जेएसजी की मसौदा रिपोर्ट के अध्यायों की ड्राफ्टिंग (मसौदा तैयार करने) में सहयोग प्रदान किया।
- भारत-कोरिया संयुक्त अध्ययन दल : डीजी-आरआईएस की जेएसजी के एक सदस्य के तौर पर नियुक्ति की गयी है और उसने जनवरी, 2005 में नई दिल्ली में हुई दल की प्रथम बैठक में भाग लिया। आरआईएस रिपोर्ट के मसौदा अध्यायों को तैयार करने में भी सहयोग प्रदान कर रहा है।
- अंकटाड XI : आरआईएस ने भारत तथा अन्य विकासशील देशों की घटना की तैयारी में सहयोग प्रदान करने के लिए अंकटाह XI के एजेन्डे पर एक नीतिगत ब्रीफ तैयार किया है।

- डब्ल्यूटीओ/एनएएमए विचार-विमर्श : आरआईएस, चालू डब्ल्यूटीओ विचार-विमर्शों विशेष रूप से नोट सहित नान-एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस (एनएएमए) तथा विश्लेषणात्मक इनपुटों को तैयार करने में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की सहायता करता रहा है। आरआईएस ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न प्रस्तावों के नियमित अनुरूपणों तथा सवेदनशीलता विश्लेषण को मुहैया कराया है।
- तरजीही मूल नियम पर विशेषज्ञ दल : आरआईएस को भारत सरकार, 2004 द्वारा सहित गठित विशेषज्ञ दल के तौर पर माना जाता है और इसे औद्योगिक वर्गीकरण के परिवर्तन के अन्तर्गत न आने वाले उत्पादों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदान किया गया था। आरआईएस ने भारत द्वारा विचार-विमर्श किए जा रहे विभिन्न आरटीए के सन्दर्भ में इनपुट प्रस्तुत कर दिया है और इस विषय पर दल की बैठकों में प्रस्तुतीकरण किया गया है।
- भारत-मकोसर पीटीए : आरआईएस ने भारतीय उत्पादों के संवेदनशील विश्लेषण तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को आपूर्ति किए गए मूल नियमों पर इनपुटों सहित भारत-मरकोसर पीटीए पर चालू विचार-विमर्शों पर सहयोग प्रदान किया है।
- साफ्टा बातचीत : वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार जुलाई, 2004 के लिए साफ्टा मूल नियम सम्बन्धी इनपुट को प्रस्तुत किया गया।
- भारत-थाईलैण्ड एफटीए : आरआईएस ने संवेदनशील मदों की पहचान पर भारत सरकार-अनकटाड अध्ययन के लिए कई पेनल की विचार-विमर्शों पर भाग लिया।
- "व्यापार तथा पर्यावरण " पर अन्तर्मत्रालयी परामर्शदाता दल : आरआईएस को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा संयुक्त रूप से गठित परामर्शदाता दल के एक विशेषज्ञ दल के लिए एक लीड इंस्टीट्यूट के रूप में नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरआईएस में प्रमुख चालू अध्ययनों में सेक्टोरल सहयोग सहित आसियान एकोनोमिक कम्युनिटी का रोड मैप, डब्ल्यूटीओ के हांगकांग मंत्रालयी सम्मेलन के लिए तैयारी के कार्य, क्षेत्रीय व्यापार प्रबन्ध और विकासशील देश, मेकांग-गंगा भागीदारी की सम्भावना, ज्ञान-आधारित उद्योगों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने के लिए अनुकूल एप्रोच, निर्यात-उन्मुख औद्योगीकरण का संवर्धन, निर्यातोम्मुख मैनुफैक्चरिंग की रोजगार सृजन सम्भावना, जैव-प्रौद्योगिकी के लिए जैव-सुरक्षा तथा क्षमता का विकास, शामिल है।

नीतिगत बातचीत, सम्मेलन और परिचर्चा

विकासशील देशों के बीच बौद्धिक बातचीत को प्रोत्साहित करने के अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान आरआईएस ने कई नीतिगत बातचीत, सम्मेलन तथा परिचर्चा का आयोजन किया।

आसियान-इकोनोमिक इन्टीग्रेशन पर उच्च स्तरीय सम्मेलनः न्यू एशिया, टोकियो 18-19 नवम्बर, 2004 का विजन

सासाकावा पीस फाउन्डेशन के सहयोग से ईस्ट आसियान कम्युनिटी, काउंसिल (सीईएसी), टोकियो, चायना स्टेट आफ काउंसिल का विकास अनुसंधान केन्द्र, वैश्विक सुरक्षा अनुसंधान संस्थान (जी-एसईसी), कियो विश्वविद्यालय, टोकियो, मलेशिया आर्थिक अनुसंधान संस्थान (एमआईईआर), कुआलालमपुर के सहयोग से आरआईएस द्वारा उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें एशिया के प्रगतिशील विचारकों के प्रमुखों अथवा वरिष्ठ विशेषज्ञों ने भाग लिया। विस्तृत आसियाना आर्थिक सहयोग के एजेन्डे का संवर्धन करने के लिए आरआईएस द्वारा मार्च, 2003 में नई दिल्ली में आयोजित पूर्व के सम्मेलन में दिए गए सुझाव पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। माननीय श्री कोपची काटो, जापानी डायट के सदस्य ने उद्घाटन भाषण दिया। मशहूर विशेषज्ञ जिन्होंने सम्मेलन को सम्बोधित किया उनमें हैं- ई-सकाकीबारा, आसियान के पूर्व महासचिव, प्रो. झांग जिया ओजी, महानिदेशक, डीआरसी. बीजिंग, डा. एरिक टेव, परिषद सचिव, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की सिंगापुर संस्थान, डा. मोहम्मद आरिफ, कार्यपालक निदेशक, एमटीईआर कुआलालमपुर, राजदूत एम. जुटो, कार्यपालक निदेशक, आईटीओ बैंकाक, प्रो. याचो चाओ चेंग, डीन, शान्सी विश्वविद्यालय, ताइयुआन, चीन, डा. चान-हुंन सोन, वरिष्ठ सहयोगी, केटीईपी, सिओल, प्रो. टी इड, पूर्व उप-मंत्री, ईपीए, जापान, प्रो. ए. सेठ, प्रेसीडेंट जी-एसईसी, टोकियों, प्रो. इटो केनिची, प्रेसीडेंट सीईएसी टोकियो, श्री बी.जे. पान्डा माननीय संसद सदस्य, भारत, राजदूत शशांक, पूर्व विदेश सचिव, भारत, राजदूत एसटी. देवारे, उपाध्यक्ष आरआईएस, डा. नागेश कुमार, डीजी-आरआईएस, श्री राहुल खुल्लर, संयुक्त सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत, डा. राजीव कुमार, मुख्य अर्थशास्त्री सीआईआई, एडीबी के वरिष्ठ अधिकारी, यूएन-एस्कैप और बहुत से अन्य लोग। जापान, एशिया, चीन, भारत तथा कोरिया (जेएसीआईके) के साथ चरणबद्ध तरीके से एक आशियान इकोनोमिक कम्युनिटी को लांच करने सम्बन्धी सम्मेलन में एक विवरण पत्र जारी किया गया।

महासचिव, आसियान, नई दिल्ली 18 अक्तूबर, 2004 द्वारा भारत-आसियान इमिनेन्ट पर्सन्स लेक्चर

आरआईएस ने विदेश मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से 18 अक्तूबर, 2004 को नई दिल्ली में एच.ई. श्री ओग यांग महासचिव, आसियान द्वारा 15वें इंडिया आसियान इमिनेन्ट पर्सन्स लेक्चर का आयोजन किया। एच.ई. श्री ओग-केंग यांग "फोजिंग आसियान इंडिया : 21वीं शताब्दी के लिए

BUSINE
FICCI
CII
Octo
MANMOHAN SINGH
KAMAL NATH

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ, तृतीय भारत-आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में। चित्र में (बाएं से) योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया; महामहिम श्री ओंग केंग योंग, महासचिव, आसियान; फिक्की अध्यक्ष श्री वाई के मोदी और सी आई आई के उपाध्यक्ष श्री वाई सी देवेश्वर भी दिखाई दे रहे हैं।

RIS
Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries
Ministry of External Affairs Government of India
India-ASEAN Eminent Persons Lecture
by
H.E. Mr. Ong Keng Yong
Secretary-General, ASEAN
on
Forging ASEAN-India Partnership for the 21st Century
New Delhi, October 18

भारत-आसियान प्रतिष्ठित व्यक्ति व्याख्यान के अवसर पर बांए से दांएः डा. नागेश कुमार, महानिदेशक आरआईएस; श्री राव इन्द्रजीत सिंह, विदेश राज्य मंत्री; महामहिम श्री ओंग केंग योंग, महासचिव, आसियान और श्री राजीव सिकरी, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय।

भागीदारी " पर अपने मत व्यक्त किए। श्री राव इन्द्रजीत सिंह माननीय विदेश राज्य मंत्री ने इसकी अध्यक्षता किया। डीजी-आरआईएस ने शिष्टमंडल का स्वागत किया और राजदूत राजीव सिकरी सचिव (ईस्ट) एमईए ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

सार्क का क्षेत्रीय सम्मेलनः पश्च-इस्लामाबाद चुनौतियां, नई दिल्ली 31 अगस्त, 2004

इस सम्मेलन को साउथ एशिया सेन्टर फार पालिसी स्टडीज (एसएसीईपीएस) के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन में साफ्टा के कार्यान्वयन की चुनौतियों से सम्बन्धित मुद्दों, ऊर्जा मामलों में सहयोग की सम्भावना तथा गरीबी और सामाजिक मुद्दों पर क्षेत्रीय एप्रोच प्रस्तुत करने के मुद्दों को सम्बोन्धित किया गया। स्वर्गीय श्री जे.एन. दीक्षित, तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जिन्होंने सम्मेलन को सम्बोन्धित किया वे हैं:- श्रीमणि शंकर अय्यर, माननीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री, प्रो. अर्जुन सेन गुप्ता, अध्यक्ष आरआईएस, प्रो. रहमान सोमन, कार्यपालक निदेशक, एसएसीईपीएस, प्रो. मुचकुन्द दुबे, अध्यक्ष सीएसडी, डा. मोहन मान सेनजू, अध्यक्ष आईआईडीएस, काठमान्डु, डा. स्मन केलेगामा, कार्यपालक निदेशक, नीतिगत अध्ययन संस्थान, कोलम्बो, डा. कमल हुसैन, पूर्व विदेश मंत्री बांग्लादेश, डा. अकमल हुसैन, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य और डा. अभिजीत सेन, सदस्य योजना आयोग।

आसियान डेवलमेन्ट के लिए बायो टेक्नोलाजी पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन; नई दिल्ली, 7-8 अप्रैल, 2004

यह सम्मेलन सीआईआई तथा आईयूसीएन के सहयोग से तथा यूनेस्को और बायोटेक्नोलाजी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से आरआईएस द्वारा आयोजित किया गया। श्री के.सी. पन्त, तत्कालीन उपाध्यक्ष योजना आयोग ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को , कई आसियान देशों और बायोटेक्नोलाजी पर कवर सेसन तथा एशिया खाद्य सुरक्षा, प्राथमिकताएं तथा चुनौतियां, बायोटेक्नोलाजी तथा आईपीआर शासन, अन्तर्राष्ट्रीय विकास तथा नीतिगत विकल्पों, ट्रेड लेबलिंग ट्रैसेबिलिटी और बायोसेफिटी प्रबन्धन के मुद्दे, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण तथा बायो-टेक्नोलाजी पर अध्ययन, बायोटक्नोलाजी में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मुद्दों, माडलिटीज और लेसन, देश विशिष्ट अनुभव और बायोटेक्नोलाजी में आसियान क्षेत्रीय सहयोग के लिए विकल्प से सम्बन्धित विषयों को प्रमुख विशेषज्ञों ने सम्बोधित किया और भारत में कृषि बायो-टेक्नोलाजी पर विशेष पेनल की चर्चा किया।

ज्ञान-आधारित उद्योगों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने के लिए नीतिगत एप्रोच पर राष्ट्रीय कार्यशाला, नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2004

यह कार्यशाला वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से आरआईएस द्वारा आयोजित की गयी। श्री राव इन्दर जीत सिंह, माननीय विदेश राज्य मंत्री ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और डा. जार्ज बी. आसफ, निदेशक यूनिडो, नई दिल्ली ने महत्वपूर्ण भाषण दिया। कार्यशाला में आरआईएस फैकल्टी तथा उक्त विषय पर डीएसआईआर परियोजना के एक भाग के तौर पर परामर्शदाताओं तथा नीति-निर्माताओं द्वारा कमेन्ट्री तथा उद्योग की गहन ब्रान्चों की चयनित प्रौद्योगिकी के उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किए गए अध्ययनों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

राष्ट्रीय अभिनव प्रणाली पर संगोष्ठी : चयनित आसियान देशों के अनुभव, नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2005

इस संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रो. अशोक पार्थसारथी, वैज्ञानिक नीति का अध्ययन के केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने किया और डा. सी. जुन यून, निदेशक, प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण एशिया तथा पेसिफिक केन्द्र (एपीसीटीटी), नई दिल्ली द्वारा महत्वूपर्ण प्रस्तुतीकरण किया गया। अन्य प्रस्तुतीकरणों में डा. पतरापांग इन्तराकुमनर्ड, प्रोजेक्ट लीडर, राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (एनएसटीडीए), थाईलैण्ड द्वारा थाईलैण्ड का मामला, डा. बच तान सिंह, कार्यकारी निदेशक राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति और नीतिगत अध्ययन संस्थान (एनआईएसटीपीएसएस), वियतनाम द्वारा वियतनाम फेलो द्वारा भारत का मामला तथा डा. सचिव चतुर्वेदी, फेलो आरआईएस द्वारा सिंगापुर का मामला, प्रमुख थे।

वैश्विक उपस्थिति और नेटवर्किंग को आउट रीच करना

अन्तर्राष्ट्रीय विजिबिलटी और आउटरीच को बढ़ाने के लिए आईआरएस के कार्य के लिए संगत प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में भाग लेने के लिए एक प्रयास किया गया है। इसके एक भाग के तौर पर आरआईएस ने अंकटाड, डब्ल्यूटीओ तथा एनएएम के साथ परामर्शी स्थिति प्राप्त कर लिया है और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्डा को प्रभावित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकों के लिए प्रारम्भिक प्रक्रियाओं में भाग लिया है। बहु-पक्षीय व्यापार विचार-विमर्श पर आरआईएस के कार्य की बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय पहचान के कारण इसे मई, 2004 में जिनेवा में हुई डब्ल्यूटीओ की सार्वजनिक परिचर्चा में महत्वपूर्ण पेनल को सम्बोधित करने के लिए डब्ल्यूटीओ सचिवालय आमंत्रित किया गया।

सहयोगपूर्ण क्रियाकलापों के लिए अन्य नीति विचारकों के साथ नेटवर्किंग को सशक्त बनाने के लिए भी आरआईएस ने कदम उठाए है। मार्च, 2004 में नई दिल्ली में हुई प्रथम बातचीत के अनुपालन में एक नियमित नीतिगत बातचीत के लिए चीन की राज्य सभा के विकास अनुसंधान केन्द्र (डीआरसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। डीआरसी, मलेशियाई आर्थिक परिषद, जापान ने भी उच्च स्तरीय सम्मेलन के टोकियो में आयोजन में आरआईएस के साथ सहयोग किया। संस्थात्मक लिंक स्थापित करने के

लिए आरआईएस ने शान्क्सी अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय, चीन तथा विश्वअर्थशास्त्र एवं राजनीति संस्थान, हनोई, वियतनाम के शिष्टमण्डल का भी आवभगत किया। वर्ष के दौरान तीन पुस्तकों के संयुक्त प्रकाशन और जनवरी, 2005 में द्वितीय आसियान-इंडिया फोरम इन-इंडिया का आयोजन करने के प्रस्ताव के साथ-साथ साउथ ईस्ट आसियान स्टडीज संस्थान (आईएसईएएस) सिंगापुर के साथ सम्बन्ध को और मजबूत बनाया गया। आईपीएस, श्रीलंका, आईटीडी, बैंकाक तथा नीतिगत बातचीत के केन्द्र, ढाका के साथ सम्बन्ध, उनके सहयोग से तैयार की जा रही बीआईएमएसटीईके रिपोर्ट के साथ, मजबूत होने लगे हैं। आरआईएस ने पाकिस्तान विकास आर्थिक संस्थान के साथ लिंक को भी मजबूत बनाया है और उसने अगस्त, 2004 में पाकिस्तान योजना आयोग के आडिटोरियम में इस्लामाबाद में आरआईएस की साउथ एशिया डेवलपमेन्ट एवं को-आपरेशन रिपोर्ट, 2004 को लांच करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया। आरआईएस ने दक्षिण एशिया नीतिगत अध्ययन केन्द्र के साथ सहयोग किया है वर्तमान में उसने सार्क आर्थिक एकीकरण मुद्दे तथा आरआईएस, 2004 रिपोर्ट लांच करने के सम्बन्ध में मई, 2004 में ढाका में संयुक्त सम्मेलन सहित कई संगोष्ठी का मिलकर आयोजन करने के लिए ढाका में अपना मुख्यालय बनाया है। आरआईएस ने एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का संवर्धन करने के लिए संस्थानों तथा विशेषज्ञों के नेटवर्क के तौर पर न्यू-एशिया फोरम को शुरू किया। इस नेटवर्क ने अपनी समर्पित www.newasiaforum.org वेबसाइट का विकास किया है और" न्यू-एशिया मानीटर" एक तिमाही पत्रिका को ठीक पाया है। फोरम वेबसाइट समाचार, एशिया के विकास पहलुओं पर विश्लेषण और प्रलेखन तथा क्षेत्रीय सहयोग और जर्नल, सूचना आदान-प्रदान के लिए एक फोरम, एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्बन्धी संसाधनों तथा विश्लेषण का तीव्रता से समृद्ध खजाना बनती जा रही है।

यूएन-ईएससीएपी ने आरआईएस को, भारत को व्यापार पर एशिया-अनुसंधान नेटवर्क के रूप में निरूपित करते हुए और इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए, संस्थागत सलाहकार बोर्ड (आईएबी) का सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। आरआईएस ने दो अनुसंधान परियोजनाओं को सम्भावित वित्त-पोषण पर चर्चा के अतिरिक्त, एशियन इकोनोमिक को-आपरेशन पर इसको उच्च स्तरीय सम्मेलन के लिए आसियान विकास बैंक (मनीला) के साथ सहयोग किया है और अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (वाशिंगटन) ने मेलबोर्न विश्वविद्यालय तथा एएनयू और बैंकाक के थम्मासाट विश्वविद्यालय सहित खाद्य सुरक्षा परियोजना में चालू सहयोग के अतिरिक्त बीज उद्योग पर एक अध्ययन आरम्भ किया है। कोलम्बो के आईयूसीएन-एशिया क्षेत्र ने एशिया में बायोटेक्नोलाजी पर संयुक्त सम्मेलन का आयोजन करने के अतिरिक्त अनुसंधान सहयोग के लिए आरआईएस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कामनवेल्थ सचिवालय, लन्दन ने भी आरआईएस में एक अध्ययन शुरू किया है। आरआईएस को एशियाई सहयोग वार्ता (एसीडी) के लिए भारत से एकेडमिक आर्म यूनिट के रूप में पदनामित किया गया है और उसने 15-17 दिसम्बर, 2004 को बैंकाक में आयोजित एशियाई सहयोग वार्ता विचारक परिचर्चा पर भाग लिया है।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों तथा विकास नीति अनुसंधान में अनुसंधान फेलोशिप की विजिटिंग

आरआईएस ने एमईए, भारत सरकार के इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक को-आपरेशन (आईटीईसी) प्रोग्राम के साथ विकासशील देशों के अनुसंधानकर्त्ताओं तथा अधिकारियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति अनुसंधान की स्थापना की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आरआईएस प्रत्येक चार महीनों की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष 3 विजिटिंग फेलो प्राप्त करता है। 2004-05 के विजिटिंग फेलो ने जनवरी, 2005 में अपने कार्याक्रम शुरू कर दिए है।

आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण मोड्यूल 23-27 अगस्त, 2004

आरआईएस ने 23-27 अगस्त, 2004 को 2003 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण मोड्यूल की पेशकश की। आरआईएस में अपने ठहराव के दौरान अधिकारियों को बहुपक्षीय क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मंच में व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों में एक ओरिएन्टेशन दिए गए। मोड्यूल की फैकल्टी में आरआईएस के वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य तथा आरआईएस से सम्बद्ध बाहरी चयनित विशेषज्ञ शामिल हैं।

टैरिफ आयोग के अधिकारियों के लिए आरटीए/एफटीए पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

फरवरी-मार्च, 2005 में अपने अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार प्रबन्धनों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए टैरिफ कमीशन द्वारा आरआईएस की एप्रोच की गयी है। यह कार्यक्रम दो सप्ताह से अधिक समय तक चलता है जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार प्रबन्धन और उनके अनुप्रयोगों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दे आते हैं।

आरआईएस प्रकाशन

वर्ष 2004-05 के दौरान आरआईएस ने सात पुस्तकें प्रकाशित की है, इस अवधि के दौरान दो नीतिगत ब्रीफ तथा 18 चर्चा पत्र (अनुबन्ध देखें) जारी किए। आरआईएस डायरी के 4 प्रकाशनों के अतिरिक्त साउथ एशिया इकोनोमिक जर्नल तथा बायोटैक्नोलाजी एण्ड डेवलमेन्ट रिविव प्रत्येक के दो-दो प्रकाशनों का संस्करण किया गया। आरआईएस संस्करणों को अब इसके वेबसाइट ण्द्यद्र:/ध्ध्ध्.द्धत्द्म.दृद्धश्र्.त्द से डाउनलोड किया जा सकता है

बजट

आरआईएस ने विदेश मंत्रालय (एमईए) से 2004-05 के दौरान 137 लाख रूपए की बजटीय सहायता प्राप्त की है।

■■

पुस्तकालय

26

अनुसंधान कार्य में सहायता के लिए मंत्रालय के पुस्तकालय में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण और समृद्ध स्रोत सामग्री उपलब्ध है जिसमें एक लाख से अधिक पुस्तकों के साथ साथ मानचित्रों, माइक्रोफिल्मों और सरकारी दस्तावेजों का विशाल संग्रह शामिल है। परिषद् में 600 से अधिक पत्र पत्रिकाएं प्राप्त होते हैं और इनका रख रखाव किया जाता है। पुस्तकालय में अपना एक कम्प्यूटर सिस्टम है जिसमें एक सर्वर के साथ 7 पर्सनल कम्प्यूटर और 8 टर्मिनल शामिल हैं जिनमें से कुछ में हिन्दी में भी डाटा प्रविष्टि और डॉटा प्राप्ति की सुविधा है। विदेशी मामलों और समसामयिक विषयों पर पुस्तकालय में सी डी रोम वर्क स्टेशन और सी डी रोम डाटा बेस हैं। पुरस्तकालय में एक रंगीन स्केनर (ओ सी आर क्षमता के साथ साथ चित्रों के भण्डारण और निकासी की सुविधा सहित), एक माईक्रोफिल्म/फिश रीडर प्रिंटर, सादा कागज फोटो कॉपियर होने के साथ साथ एक वी टी आर तथा रंगीन मॉनीटर और डैस्क टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक लेजर प्रिंटर भी है। इससे पुस्तकालय / प्रभाग के प्रकाशनों एवं दस्तावेजों का बेहतर प्रस्तुतीकरण संभव हुआ है।

प्रलेखन/ग्रन्थ सूची सेवाओं के साथ साथ अन्य पुस्तकालय प्रचालनों एवं सेवाओं को एक समेकित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रयोग करके कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। 1986 के बाद से पुस्तकालय में प्राप्त (और 1986 से पहले के प्रकाशन जो सक्रिय उपयोग में हैं) सभी पुस्तकों, मानचित्रों, दस्तावेजों और चुनिंदा पत्रिकाओं में छपे लेखों के बारे में जानकारी, पटियाला हाउस स्थित मुख्य पुस्तकालय के प्रत्येक टर्मिनल / कम्प्यूटर के माध्यम से आन लाइन उपलब्ध है। मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों में कार्य कर रहे हमारे अधिकारीगण विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय की वेबसाइट http://mealib.nic.in पर इण्टरनेट के माध्यम से पुस्तकालय के डाटाबेस को देख सकते हैं।

पुस्तकालय की इण्टरनेट सुविधाएं आगन्तुक प्रयोक्ताओं जिनमें शोध छात्र और विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी शामिल हैं, को धीरे धीरे उपलबध कराई जा रही हैं। पुस्तकालय अब उस पूछताछ पर भी ध्यान देता है जो पुस्तकालय की वेबसाइट देख रहे प्रयोक्ताओं द्वारा अथवा ई-मेल के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा की जाती है। इन सवालों के उत्तर तुरन्त प्रतिक्रिया स्वरूप, जहां कहीं भी संभव होता है वहां ई-मेल के माध्यम से दिए जाते हैं।

पुस्तकालय में प्राप्त होने वाले सभी नए दस्तावेजों अर्थात पुस्तकों, मानचित्रों, माईक्रोफिल्मों, पत्र पत्रिकाओं के चुनिन्दा लेखों को पुस्तकालय के कम्प्यूटर सिस्टम में फीड किया जाता है ताकि विदेशी मामलों के बारे में एक डाटाबेस तैयार हो सके। इस डाटाबेस का और सी डी डाटाबेस का प्रयोग करके पुस्तकालय समसामयिक जागरूकता सेवाएं और संदर्भिका एवं शोध सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके अलावा पुस्तकालय निम्नलिखित का भी नियमित रूप से प्रकाशन करता है -

- अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर चुनिन्दा लेखों की एक सूची- फारेन अफेयर्स डाक्यूमेन्टेशन बुलेटिन।
- पुस्तकालय में शामिल किए गए प्रकाशनों की एक संक्षिप्त विवरणिका - रीसेन्ट एडीसन्स

सी डी रोम प्रकाशन

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से पुस्तकालय ने विदेश मंत्रालय की वर्ष 1948 से वर्ष 1998-99 तक की वार्षिक रिपोर्टों और वर्ष 1955 से अगस्त 1999 तक के विदेशी मामलों संबंधी रिकार्ड का एक सम्पूर्ण सी डी रोम रूपान्तर प्रकाशित किया है। इन सी डी पर उपलब्ध जानकारी विभिन्न प्रकार की खोजों के संयोजन से अर्थात किसी निश्चित शब्द या शब्द समूह को खोजकर प्राप्त की जा सकती है। यह सी डी रोम रूपान्तर 01 जनवरी, 2000 तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर तैयार किया गया था। यह सी डी पटियाला हाउस नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के मुख्य पुस्तकालय में देखी जा सकती है। इसके संशोधित/अद्यतन संस्करण के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आशा है कि इसे अगले वर्ष जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय में पुस्तकालय के सभी उपांगों को संभालने वाला समेकित पुस्तकालय प्रबन्धन सॉफ्टवेयर लिबसिस लगाया गया है। लिबसिस, मार्क प्रणाली का अनुगमन करते हुए छपी और बिना छपी दोनों प्रकार की सामग्री के लिए उपयोगी है। इस सॉफ्टवेयर में मार्क प्रारूप जैसे मानक विनिमय प्रारूप में सामग्री को संजोने / प्राप्त करने की सुविधा है। बूलियन प्रचालकों का प्रयोग करते हुए लिबसिस में शब्द आधारित मुक्त पाठ खोज की सुविधा है। डाटाबेस को अद्यतन बनाने से पूर्व पहले से भंडारित सामग्री को ऑन लाइन अद्यतन बनाने की सुविधा भी इस सॉफ्टवेयर में है।

शोध छात्रों सहित सभी पुस्तकालय प्रयोक्ताओं को सी डी रोम डाटाबेस सहित विभिन्न डाटाबेस तथा विदेशी मामलों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रणाली (एफ ए आई आर एस) में जाकर पुस्तकालय की वेबसाइट देखने अथवा नई दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित पुस्तकालय में ऑन लाइन कम्प्यूटर आधारित सूचना तक पहुँच बनाने की सुविधा है। शोध छात्रों सहित सभी पुस्तकालय प्रयोक्ताओं को फोटो कॉपी करने और कम्प्यूटर प्रिंट आउट निकालने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

हाल ही में पुस्तकालय ने एक आभासी पुस्तकालय की स्थापना की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से नेट पर उपलब्ध महत्वपूर्ण लेखों के सम्पूर्ण पाठ उपलब्ध कराना भी शुरू किया गया है और इस संबंध में उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

कल्याण

27

विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के सामान्य हित चिन्तन का काम कल्याण प्रभाग करता है । इस कार्य में शामिल है - एम बी बी एस / इंजीनियरी / डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तथा केन्द्रीय विद्यालयों में विदेश मंत्रालय के कोटे के अन्तर्गत उनके बच्चों की शिक्षा तथा साउथ ब्लॉक , अकबर भवन एवं पटियाला हाउस में स्थित कैंटीन सेवाओं का प्रबंधन । कल्याण संबंधी अन्य सेवाओं में शामिल हैं - विदेश मंत्रालय के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों की तकलीफों को दूर करने की व्यवस्था जिसमें उनके आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर रोजगार दिए जाने के मामलों की संस्तुति करना , विवादों के मामले में और सामान्य सेवाओं के मामले में पुलिस एवं स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाना , विदेश स्थित मिशनों और मुख्यालयों में मनोरंजन क्लबों की स्थापना के लिए अनुदान सहायता देना । सांप्रदायिक सौहार्द , स्टाफ बेनिफिट फण्ड , रेड क्रास, तथा सशस्त्र सेना झण्डा दिवस आदि जैसे दिवसों के संबंध में भी कल्याण प्रभाग सभी व्यवस्थाएं करता है ।

वर्ष 2004-2005 के दौरान दो आश्रितों को विदेश मंत्रालय में अनुकम्पा आधार पर अवर श्रेणी लिपिक के नियमित पदों पर और एक आश्रित को दैनिक मजदूरी आधार पर नियुक्त किया गया । विदेश मंत्रालय के सभी कार्यालयों में दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्ति में विदेश मंत्रालय के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वरीयता दिए जाने की एक अभूतपूर्व नीतिगत पहल की गई है । रात के समय विदेश से लौटने वाले परिवारों के लिए एक सुरक्षित परिवहन सेवा शुरू की गई है । तनाव प्रबंधन के क्षेत्र में मुख्यालय में "आर्ट ऑफ लिविंग" कार्यक्रम चलाया गया तथा विदेश में कार्य कर रहे विदेश मंत्रालय के कार्मिको के लाभार्थ विदेश स्थित मिशनों में तनाव प्रबन्धन के बारे में प्रश्नों सहित एक दस्तावेज परिचालित किया गया है। भारत की यात्रा पर आए राजनयिकों और अन्तर्राष्ट्रीय आगन्तुकों के साथ साथ अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तथा पेशेवर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए साउथ ब्लॉक में एक समानान्तर कैटरिंग आउटलेट स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है ।

■■

परिशिष्ट I

वर्ष 2004-2005 के दौरान मुख्यालय में और विदेश स्थित मिशनों/पोस्टों में संवर्ग संख्या (वाणिज्य मंत्रालय प्रदत्त बजट वाले पदों और रोक रखे गए/बाह्य संवर्गीय पदों सहित)

क्र.सं.	संवर्ग/पद	मुख्यालय में पद	मिशनों में पद पद	योग
1.	ग्रेड-I	4	22	26
2.	ग्रेड-II	5	20	25
3.	ग्रेड-III	35	118	153
4.	ग्रेड-IV	37	99	136
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ वेतनमान	48	132	180
6.	(I) कनिष्ठ वेतनमान	1	20	30
	(II) परिवीक्षा रिजर्व	27	-	27
	(III) अवकाश रिजर्व	15	-	15
	(IV) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	19	-	19
	(V) प्रशिक्षण रिजर्व	7	-	7
	भारतीय विदेश सेवा (ख)			
7.	(I) ग्रेड-I	43	100	143+60*
	(II) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	6	-	6
8.	(I) ग्रेड-II/III	99	178	274+94*
	(II) अवकाश रिजर्व	30	-	30
	(III) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	16	-	16
	(IV) प्रशिक्षण रिजर्व	25	-	25
9.	(I) ग्रेड-IV	203	407	610
	(II) अवकाश रिजर्व	60	-	60
	(III) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	55	-	55
10.	(I) ग्रेड-V/VI	250	193	443
	(II) अवकाश रिजर्व	60	-	60
	(III) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	14	-	14
11.	(I) ग्रेड-II साइफर संवर्ग (साइफर सहायक)	49	143	192
	(II) अवकाश रिजर्व	24	-	24
12.	(I) निजी सचिव	35	199	234
	(II) अवकाश रिजर्व	14	-	14
13.	(I) निजी सहायक	130	195	325
	(II) अवकाश रिजर्व	33	-	33
	(III) प्रशिक्षण रिजर्व (हिन्दी)	10	-	10
	(IV) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	12	-	12
14.	आशुलिपिक (ग्रेड-III)	17	77	94
15.	भाषान्तरकार संवर्ग	6	27	33
16.	एल एण्ड टी संवर्ग	14	1	15

(* संवर्ग समीक्षा के परिणामस्वरूप सृजित/घटाए गए पद)

(** निजी सचिव से संबंधित आँकड़ों में वे 60 पद शामिल हैं जो प्रधान निजी सचिव के रूप में उन्नत किए गए हैं। प्रधान निजी सचिव के इन 60 पदों में से 22 पदों को आगे वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में उन्नत कर दिया गया है।)

परिशिष्ट II

विदेश मंत्रालय में अप्रैल से नवम्बर 2004 तक विभिन्न समूहों में सीधी भर्ती , विभागीय पदोन्नति और सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से की गई भर्ती तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के द्वारा भरी गई आरक्षित रिक्तियों के बारे में आँकड़े ।

समूह	**पदों की कुल संख्या**	**पदों की संख्या**			**अनारक्षित**
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
समूह-क	82	14	6	6	56
समूह-क (संवर्ग बाह्य)	1	1	-	-	-
समूह-ख	346	56	21	1	268
समूह-ग	30	11	2	3	14
समूह-घ	1				1
योग	**460**	**82**	**29**	**10**	**339**

परिशिष्ट III

30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों का भाषावार विवरण (श्रेणी-I से भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ वेतनमान तक)

भाषा	**अधिकारियों की संख्या**	**भाषा**	**अधिकारियों की संख्या**
अरबी	88	थाई	2
भाषा इंडोनेशिया	13	तिब्बती	2
चीनी	56	तुर्की	6
फ्रेंच	70	डच	1
जर्मन	30	गोरखाली	1
इतालवी	5	स्वीडिश	1
जापानी	24	मलय भाषा	1
किशवाहिली	8	हंगेरियन	1
नेपाली	3	वियतनामी	1
पर्सियन	21	वर्मी	1
पुर्तगाली	17	मंदारिन	1
रुसी	75	उक्रेनी	1
सर्वो क्रोएशियन	3	कजाख	1
सिंहली	2	हेब्रयु	3
स्पेनी	59		

परिशिष्ट IV

1 जनवरी , 2004 से 30 नवम्बर, 2004 तक पासपोर्ट कार्यालयों में तत्काल योजना सहित पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों और जारी किए गए आवेदनों की संख्या, प्राप्त विविध आवेदन पत्रों की संख्या और प्रदत्त सेवाओं की संख्या के साथ साथ राजस्व (तत्काल योजना के अधीन प्राप्त राजस्व सहित) और व्यय के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण -

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/ पासपोर्ट कार्यालय का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या	प्राप्त विविध आवेदनों की संख्या	दी गई विविध सेवाएं	तत्काल योजना के अन्तर्गत जारी पासपोर्ट	तत्काल योजना के अन्तर्गत राजस्व	कुल राजस्व	कुल व्यय
अहमदाबाद	214443	235335	17895	19129	7130	8991000	223777698	28635772
बंगलूर	170826	167010	28620	28418	10421	13051500	186016217	22930889
बरेली	44680	41989	3256	3202	1519	2281000	47278899	8541252
भोपाल	53519	43970	4913	4873	3199	4273000	57478750	5453458
भुवनेश्वर	26594	20987	1986	1963	1150	1538000	48293740	7478470
चण्डीगढ़	204326	184987	24525	22225	7168	10376000	233409010	22685557
चेन्नै	230529	216367	29240	26299	22735	32810000	273633931	26797069
कोचीन	176339	177863	34810	34620	15754	22020800	202075031	23146142
दिल्ली	207773	158258	32280	31515	16024	29103700	235239387	44808025
गाजियाबाद	49831	40280	6178	6023	2618	3853600	52779867	5410259
गुवाहाटी	18978	18055	1431	649	2184	3643000	23724000	3508246
हैदराबाद	273128	284753	33060	32292	23927	46088800	413615858	32104067
जयपुर	136424	106091	9170	6592	6183	7896500	145411946	16695741
जालंधर	168418	166425	18076	17402	1032	2001825	189702537	19319598
जम्मू	14250	11206	899	869	463	642500	16142080	3028782
कोलकाता	115006	114542	12611	12388	3595	5053400	124373517	13571022
कोझिकोड	238217	237355	24236	23811	23802	33745500	284480096	24313113
लखनऊ	161051	133238	10114	9432	1985	2796000	158518793	24256675
मुम्बई	228982	218355	29063	28261	8914	15960000	240410545	50305451
नागपुर	26215	24515	1889	1757	2437	3120500	29099300	3690337
पणजी	23515	23913	7903	7780	2187	3167500	30825996	4643352
पटना	71366	53901	3181	3084	658	870000	67563900	7825316
पूना	62426	60009	8305	8231	5082	6458500	68859185	8738149
रांची	19525	15277	1734	1469	1294	1722800	21390600	2822167
श्रीनगर	12020	10585	933	919	430	589300	13072069	5321697
सूरत	69798	61820	5441	5029	2473	3117600	70957870	*
ठाणे	87686	79072	8766	8657	4529	6710500	94115910	**
त्रिची	222368	261803	20937	19307	10581	14785000	278581040	26302129
त्रिवेन्द्रम	121765	119594	22804	21534	15359	21599000	152265994	14962055
विशाखापट्टनम	65832	65225	8072	7868	2082	3003700	73825785	7175366
योग	**3515830**	**3352780**	**412328**	**395598**	**206915**	**311270525**	**4056919551**	**464470156**

* व्यय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद के व्यय में शामिल है क्योंकि एलओसी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद के साथ संयोजित है।

* व्यय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुम्बई के व्यय में शामिल है क्योंकि एलओसी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद के साथ संयोजित है।

परिशिष्ट V

वर्ष 2004-05 के दौरान विदेश मंत्रालय का वित्त

वर्ष 2004-05 के वित्तीय अनुमान में विदेश मंत्रालय के लिए बजट आबंटन 3640.69 करोड़ रूपए का है जो कि 2003-04 के बजट अनुमान की तुलना में 6.77 प्रतिशत की अर्थात् कुल 230.69 करोड़ रूपए की वृद्धि दर्शाता है। 2004-05 के लिए संशोधित बजट अनुमान में भी 6.71 प्रतिशत की अर्थात् कुल 244.31 करोड़ रूपए की वृद्धि की गई है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान विदेश मंत्रालय का व्यय और बजट का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

वर्ष	वास्तविक व्यय (करोड़ रूपए में)	प्रतिशत अंतर
2000-2001	2488.85	शून्य
2001-2002	2624.55	5.45
2002-2003	3253.79	23.98
2003-2004	3344.91	2.8 प्रतिशत
2004-2005 (बजट अनुमान)	3640.69	8.84 प्रतिशत
2004-2005 (संशोधित अनुमान)	3885.00	6.71 प्रतिशत

परिशिष्ट VI

2004-2005 के बजट में सैक्टर वार प्रमुख आबंटन

सैक्टर	करोड़ रूपए में
विदेश मंत्रालय सचिवालय	118.30
राजदूतावास एवं मिशन	896.26
पासपोर्ट एवं उत्प्रवास	159.98
विशेष राजनयिक व्यय	841.01
तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	1326.39
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अंशदान	61.50
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को अनुदान	57.50
विदेशी सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	298.88
अन्य	125.18

2004-2005 के बजट में सैक्टर वार प्रमुख आबंटन

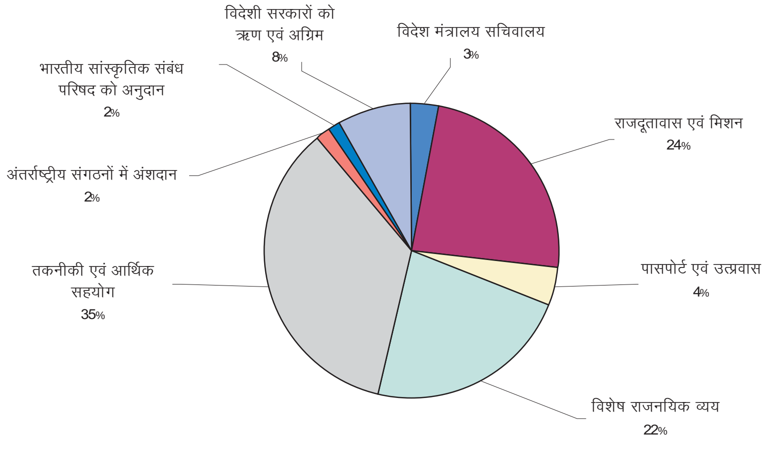

परिशिष्ट VII

भारत का सहायता कार्यक्रम

चालू वित्त वर्ष में हमारे सहायता एवं ऋण कार्यक्रमों के मुख्य लाभार्थी निम्नलिखित हैं -

देशों को ऋण एवं सहायता	**करोड़ रूपए में**
भूटान	768.65
बंगलादेश	3.30
नेपाल	66.17
श्रीलंका	15.30
मालदीव्स	3.20
म्यांमार	6.21
अफ्रीकी देश	106.84
अन्य (विकासशील देशों सहित)	356.72

भारत का सहायता कार्यक्रम

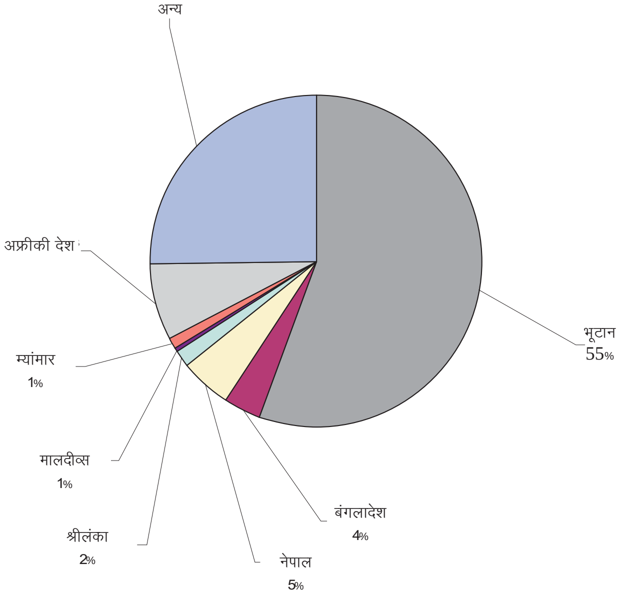

3.1 भारत की कुल बजटीय सहायता का 55 प्रतिशत हिस्सा भूटान को सहायता के रूप में दिया जाता है। भारतीय सहायता कार्यक्रमों के अन्य प्रमुख प्राप्तकर्ता देशों में शामिल हैं - अफ्रीकी देश-8 प्रतिशत, नेपाल-5 प्रतिशत, श्रीलंका-2 प्रतिशत और अन्य देश - 30 प्रतिशत ।

3.2 भारत सरकार ने बंगलादेश और भूटान की सरकारों को ऋण उनकी विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिए हैं । वर्ष 2004-05 के दौरान बंगलादेश की सरकार और भूटान को दिए गए ऋण की राशि क्रमशः 18.87 करोड़ रूपए और 280.00 करोड़ रूपए है ।

4. विदेश मंत्रालय का बजट तत्वतः एक योजनेतर बजट है । फिर भी, वर्ष 1996-97 से मंत्रिमंडल के अनुमोदन से एक योजना बजट शीर्ष स्थापित किया गया है । इस शीर्ष के अंतर्गत भारत सरकार के भूटान को सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत भूटान सरकार के अनुरोध पर परियोजना सहायता के एक हिस्से के रूप में भूटान में शुरू की गई विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरतों की पूर्ति की जाती है । भूटान में इस समय पूरी की जा रही ताला जल विद्युत परियोजना एक प्रतिष्ठापूर्ण और महत्वपूर्ण परियोजना है । योजना लेखा शीर्ष के अंतर्गत वित्त पोषित की जा रही अन्य दो परियोजनाएँ भी भूटान में ही हैं अर्थात पुनातशांगसू और दुंगसम सीमेंट संयत्र।

5. चालू वित्त वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में अनुमानित व्यय 120.80 करोड़ रूपए का है जो कि मंत्रालय के कुल अनुमानित राजस्व व्यय का लगभग 3 प्रतिशत बैठता है । विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों एवं पोस्टों पर कुल अनुमानित व्यय 866.33 करोड़ रूपए तक का होने की आशा है जो कि मंत्रालय के कुल राजस्व व्यय का लगभग 25 प्रतिशत है ।

6. पासपोर्ट एवं वीजा शुल्कों तथा अन्य प्राप्तियों से विदेश मंत्रालय का राजस्व 1117.20 करोड़ रूपए का होने की संभावना है । यह अनुमान है कि पासपोर्ट शुल्क का हिस्सा इसमें से लगभग 520 करोड़ रूपए का, वीजा फीस का हिस्सा 575 करोड़ रूपए का और अन्य प्राप्तियाँ 22.20 करोड़ रूपए की रहेंगी ।

परिशिष्ट VIII

विदेश मंत्रालय के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

वैट के रिफंड का दावा करने में विलम्ब के कारण हुई परिहार्य हानि - अक्तूबर 1999 से मई 2001 तक राजदूत के निवास की मरम्मत के संबंध में अदा किए गए वैट के रिफंड का दावा करने में भारत के उच्चायोग लंदन द्वारा विलंब करने से 2.44 करोड़ रूपए की हानि हुई ।

(लेन देन लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ - 2004 की रिपोर्ट संख्या 2 का पैरा 2.1)

लंदन में उच्चायुक्त के अस्थायी आवास को किराए पर लेने पर हुआ परिहार्य व्यय - भारत के उच्चायुक्त के आवास के लिए, दूतावास के उनके आवास की भावी मरम्मत को देखते हुए 47 सप्ताह के लिए अस्थायी आवास किराए पर लेने के परिणामस्वरूप 1.71 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

(लेन देन लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ - 2004 की रिपोर्ट संख्या 2 का पैरा 2.2)

भारत के राजदूतावास, रोम के अधिकारियों को अनुचित लाभ - बार-बार की गई लेखा परीक्षा टिप्पणियों के बावजूद रोम स्थित मिशन में भारत आस्थानी स्टाफ के बच्चों को दोपहर का भोजन एवं परिवहन सुविधा देने पर अस्वीकार्य भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1998 से मार्च 2003 तक स्टाफ को 79.26 लाख रूपए का अवांछित लाभ हुआ ।

(लेन देन लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ - 2004 की रिपोर्ट संख्या 2 का पैरा 2.4)

रिक्त आवास को अनुचित रूप से बनाए रखना - माले स्थित भारतीय उच्चायोग ने जनवरी, 2001 से दिसम्बर 2002 तक की दो साल की अवधि के लिए रिक्त पट्टा आवास अपने पास बनाए रखा जबकि इसके लिए केवल 90 दिन की अवधि की अनुमति थी । इसके कारण किराए के भुगतान पर 39.71 लाख रूपए का अनुचित व्यय हुआ ।

(लेन देन लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ - 2004 की रिपोर्ट संख्या 2 का पैरा 2.8)

रिक्त संपत्ति के निबटान में विलंब - मार्च 1994 में अदन में खाली कर दिए गए एक भवन का निबटान करने में विदेश मंत्रालय ने विलंब किया जिसके कारण इसकी हालात खराब होती गई । मंत्रालय ने इस भवन को पट्टे पर देने के मिशन के प्रस्ताव पर अनुमोदन देने में भी विलंब किया जिसके परिणामस्वरूप राजकोष पर 16.96 लाख रूपए की हानि सहनी पड़ी ।

(लेन देन लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ - 2004 की रिपोर्ट संख्या 2 का पैरा 2.10)

माली की मजदूरी का अनियमित भुगतान - मस्कट स्थित भारत के राजदूतावास ने मिशन के प्रमुख को माली की मजदूरी के खाते में 5.74 लाख रूपए की अनियमित प्रतिपूर्ति की यद्यपि राजदूत के आवास के किराए में बगीचे की देखभाल की लागत भी शामिल थी और इस बगीचे की देखभाल वास्तव में मकान मालिक द्वारा की गई थी ।

(लेन देन लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ - 2004 की रिपोर्ट संख्या 2 का पैरा 2.13)

परिशिष्ट IX

जनवरी 2004 से मार्च, 2005 के दौरान अन्य देशों के साथ संपन्न अथवा नवीकृत की गयी संधियों अभिसमय/करार ।

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार इत्यादि के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/प्रवेश/स्वीकृती जामा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
बहुपक्षीय				
1.	सार्क का सामाजिक चार्टर	4.1.2003		4.1.2004
2.	आतंकवाद के दमन पर सार्क क्षेत्रीय अभिसमय पर अतिरिक्त प्रोतोकोल	4.1.2004		4.1.2004
3.	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर करार	4.1.2004		4.1.2004
4.	एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा बैंकाक में पारित एशियाई उच्च-मार्ग नेटवर्क पर अंतर- सरकारी करार	27.4.2004		
5.	तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन संरचना अभिसमय			
6.	मरकोसर और भारत गणराज्य के बीच संरचना करार			
7.	विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों को विधिक रुप देने की आवश्यकता को समाप्त करने से संबद्ध अभिसमय, 1961		26.10.2004(क)	14.7.2005
8.	(क) सशस्त्र संघर्षों में बच्चों को शामिल करने के संबंध में बच्चों के अधिकारों से संबद्ध अभिसमय पर अतिरिक्त प्रोतोकोल; और (ख) बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बाल अशलील साहित्य के संबंध में बच्चों के अधिकारों से संबद्ध वैकल्पिक प्रोतोकोल	15.11.2004		
9.	भारत और खाड़ी के अरब देशों की सहयोग परिषद के सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग पर संरचना करार			
10.	टीम-9 देशों (बुरकीना फासो, चाड, कोट डी आइवरी, इक्वाटोरियल गुयाना, घाना, गिनी बिसाउ, माली ....की सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन)			

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार इत्यादि के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/प्रवेश/स्वीकृती जामा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
द्विपक्षीय				
	अफगानिस्तान			
1	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय के एफ एस आई और अफगानिस्तान संक्रमणकालीन इस्लामिक राज्य के बीच आपसी सहयोग पर समझौता ज्ञापन	1.9.2004		1.9.2004
	आर्मीनिया			
2	भारत गणराज्य की सरकार और आमीनियाँ गणराज्य की सरकार के बीच निवेशों के संवर्द्धन और संरक्षण पर करार	23.5.2003	13.8.2004	
	बहरीन			
3	भारत गणराज्य की सरकार और बहरीन साम्राज्य के बीच निवेशों के संवर्द्धन और संरक्षण पर करार	13.01.2004	6.8.2004	
4.	भारत गणराज्य की सरकार और बहरीन साम्राज्य के बीच प्रर्त्यपण संधि			
5.	भारत गणराज्य की सरकार और बहरीन साम्राज्य के बीच नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक सहयोग पर करार	13.01.2004	21.10.2004	
6.	भारत गणराज्य की सरकार और बहरीन साम्राज्य की सरकार के बीच आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता पर करार			
	ब्राजील			
7.	ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग करार ।	27.01.2004		
8.	ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर करार ।	27.01.2004		

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार इत्यादि के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/प्रवेश/ स्वीकृती जामा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
9.	भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य के बीच राजनयिक और सरकारी/ सेवा पासपोर्टधारकों के लिए वीजा अनिवार्यता में छूट से संवद्ध करार।	27.01.2004		
10.	वर्ष 2004-05 के लिए भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	27.01.2004		
11.	वर्ष 2004 के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और ब्राजील अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग कार्यक्रम	27.01.2004		
	बुल्गारिया			
12	भारत गणराज्य और बुल्गारिया गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि	23.10.2003		
13.	भारत सरकार और बुल्गारिया गणराज्य के बीच युवा मामलों और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर करार	23.10.2003		23.10.2003
14.	इलेक्ट्रोनिक्स और कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्द्धन परिषद और बुल्गारिया एसोसिएशन ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी के बीच समझौता ज्ञापन	23.10.2003		23.10.2003
15.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान और बुल्गारिया गणराज्य के विदेश मंत्रालय के राजनयिक संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन।	28.07.2004		28.7.2004
	क्यूबा			
16	भारत गणराज्य के भारतीय मानक और क्यूबा गणराज्य के राष्ट्रीय मानक ब्यरो के बीच मानकीकरण, प्रामाणीकरण और सूचना के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	28.7.2004		28.7.2004
	चेक गणराज्य			
17	भारत गणराज्य की सरकार और चेक गणराज्य की सरकार के बीच रक्षा सहयोग पर करार	21.10.2003		

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार इत्यादि के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/प्रवेश/स्वीकृती जामा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
18.	यूरोपीय समुदाय और भारत गणराज्य की सरकार के बीच सभा शुल्क मामलों में सहयोग पर यूरोपीय समुदाय करार ।	29.11.2003		
	फ्रांस			
19	भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच प्रतयर्पण संधि	04.01.2003	15.04.2004	
20.	भारत- फ्रांस गणित संस्थान की स्थापना से संबद्ध समझौता ज्ञापन	25.09.2004		25.09.2004
21.	फ्रेंच राष्ट्रीय रेलवे और भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	30.1.2004		31.1.2004
	हंगरी			
22	भारत गणराज्य और हंगरी गणराज्य के बीच निवेशों के संवर्द्धन और संरक्षण पर करार	3.11.2003	20.02.2004	
23.	भारत गणराज्य और हंगरी गणराज्य के बीच दोहरे कराधान के परिहार और आयकर पर राजकोषीय वचन पर रोक से संबद्ध करार	3.11.2003		
24.	भारत गणराज्य और हंगरी गणराज्य के बीच रक्षा सहयोग पर करार	3.11.2003		
25.	भारत गणराज्य और हंगरी गणराज्य के बीच राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा उन्मुक्ति से संबद्ध करार	3.11.2003		
26.	भारत गणराज्य और हंगरी गणराज्य के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	3.11.2003		3.11.2003
	इंडोनेशिया			
27	भारत गणराज्य की सरकार और इंडोनेशिया गणराज्य के बीच अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध समझौता ज्ञापन	2.7.2004		2.7.2004

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार इत्यादि के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/प्रवेश/स्वीकृती जामा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
	इजराइल			
28	भारत गणराज्य की सरकार और इजराइल राज्य की सरकार के बीच पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग पर करार	9.9.2003	7.5.2004	
	इरान			
29	भारत गणराज्य और इरान इस्लामी गणराज्य के बीच टिकटों के संयुक्त मसले पर करार।	जुलाई , 2004		जुलाई, 2004
	इटली			
30	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य और इटली गणराज्य के बीच करार ।	28.11.2003	7.5.2003	
	कजाकिस्तान			
31	भारत गणराज्य के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कजाकिस्तान गणराज्य के उद्योग और व्यापार मंत्रालय के बीच सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की रुपरेखा के अंतर्गत समझौता ज्ञापन	15.09.2004		15.09.2004
	कोरिया			
32	भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि	5.10.2004		
33.	आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता पर भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य के बीच संधि	5.10.2004	4.11.2004	
	कुवैत			
34	भारत गणराज्य और कुवैत गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि	25.8.2004		
35.	भारत गणराज्य और कुवैत गणराज्य के बीच आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता पर करार ।	25.08.2004		
36.	भारत-कुवैत सामरिक परामर्शी समूह की स्थापना पर समझौता ज्ञापन	25.08.2004		25.08.2004

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार इत्यादि के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/प्रवेश/स्वीकृती जामा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
	लाओ पी डी आर			
37	भारत गणराज्य और लाओ लोकतांत्रिक जन गणराज्य के बीच दवाओं की मांग में कमी और स्वापक औषधों एवं मन प्रभावी पदार्थों की तस्करी में कमी लाने में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	6.11.2002	23.1.2004	
	मंगोलिया			
38	मवेशी स्वास्थ्य और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य और मंगोलिया गणराज्य के बीच करार	15.1.2004		
39.	भारत गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और मंगोलिया सरकार के शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान मंत्रालय के बीच जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग प्रोतोकोल ।	15.01.2004		15.01.2004
40.	भारत गणराज्य की सरकार के अंतरिक्ष विभाग और मंगोलिया सरकार के अवसंरचना मंत्रालय के बीच अंतरिक्ष, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में सहयोग पर करार ।	15.1.2004		15.01.2004
	मोरक्को			
41	भारत गणराज्य की सरकार और मोरक्को साम्राज्य के बीच हवाई सेवाओं के संबंध में करार।	7.12.2004		
42.	ऊर्जा के क्षेत्र में भारत गणराज्य और मोरक्को साम्राज्य के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	7.12.2004		7.12.2004
43.	भारत गणराज्य और मोरक्को साम्राज्य के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	7.12.2004		7.12.2004
	मोजाम्बिक			
44	भारत गणराज्य और मोजाम्बिक गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों के बीच स्वास्थ्य और दवाओं के क्षेत्र में सहयोग पर करार	22.02.2004		22.02.2004
45.	भारत गणराज्य और म्यामां गणराज्य के बीच रेलवे के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	27.7.2004		27.7.2004

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार इत्यादि के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/प्रवेश/स्वीकृती जामा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
46.	भारतीय मानक ब्यूरो और नेपाल मानक एवं मौसम विज्ञान ब्यूरो नेपाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग करार	9.9.2004		9.9.2004
47.	भारत - नेपाल रेल सेवा करार			
	नार्वे			
48	सहयोग पर संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए भारत गणराज्य और नार्वे साम्राज्य के बीच करार	6.7.2004		6.7.2004
49.	रेल संचार पर भारत और पाकिस्तान के बीच करार	21.1.2001		21.1.2004
50.	भारत			
	फिलीपींस			
51	भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपींस गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि	12.3.2004	3.5.2004	
	पोलैंड			
52	भारत गणराज्य की सरकार और पोलैंड गणराज्य की सरकार के बीच संगठित अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग पर करार।	17.2.2003	21.10.2004	
	रोमानियॉ			
53	राजनयिक पासपोर्टधारकों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था पर सहयोग के लिए भारत-रोमानियाँ के बीच करार	31.1.2004		31.1.2004
54.	भारत गणराज्य और रोमानियाँ गणराज्य के बीच पादप संरक्षण और पादप स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग पर करार।	31.1.2004		
55.	रोमनियां के टेलीविजन और दूरदर्शन के बीच समझौता ज्ञापन।	31.1.2004		31.1.2004
56.	रोमानियां के ब्रोडकास्टिंग और आकाशवाणी के बीच समझौता ज्ञापन।	31.1.2004		31.1.2004
	सबिर्या और मोंटनेगरो			
57	भारत गणराज्य की सरकार और सर्बिया और मोंटनेगरो की मंत्रि - परिषद के बीच वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग पर करार	28.10.2004		

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार इत्यादि के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/प्रवेश/स्वीकृती जामा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
58.	पर्यटन करार			
	सिंगापुर			
59	वर्ष 2004-07 के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच कला, धरोहर, अभिलेख और पुस्तकालय के क्षेत्र में करार।	19.10.2004		19.10.2004
	स्लोवेनियाँ			
60	भारत गणराज्य की सरकार और स्लोवेनियां गणराज्य की सरकार के बीच दोहरे करों कराधान से परिहार और आयकर के राजकोषीय वचन पर रोक के लिए करार	13.1.2003	30.8.2004	
	दक्षिण अफ्रीका			
61	दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	15.09.2004		15.9.2004
	श्रीलंका			
62	भारत गणराज्य की सरकार और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	23.1.2004		23.01.2004
63.	भारत गणराज्य के लधु उद्योग मंत्रालय और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	27.1.2004		27.1.2004
	सूरीनाम			
64	कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन	17.3.2003		
	सूडान			
65	भारत गणराज्य की सरकार और सूडान गणराज्य की सरकार के बीच निवेशों के संवर्द्धन और संरक्षण पर करार	2.10.2003	23.1.2004	
	स्विटजलैंड			
66	भारत गणराज्य की सरकार और स्विस संघीय परिषद के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग पर करार	10.11.2003	6.8.2004	

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार इत्यादि के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/प्रवेश/स्वीकृती जामा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
	सीरिया			
67	भारत और सीरिया के बीच कृषि में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	15.11.2003		
68.	भारत गणराज्य और स्विस परिसंघ के बीच आपदा की स्थिति में सहयोग पर करार।	10.11.2003	20.2.2004	
	थाइलैंड			
69	भारत गणराज्य की सरकार और थाइलैंड साम्राज्य के बीच आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता पर संधि	8.2.2004	18.03.2004	
	त्रिनिडाड एंड टोबैगो			
70	भारत गणराज्य की सरकार और त्रिनिडाड एंड टोबैगो गणराज्य की सरकार के बीच राजनैतिक, आर्थिक , वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर करार	5.2.2003	18.3.2004	
	यूनाइटेड किंगडम			
71	भारत गणराज्य की सरकार और यूनाइटेड किंगडम सरकार के बीच अवैध अप्रवासियों की वापसी से संबद्व समझौता ज्ञापन	30.1.2004		30.1.2004
	उक्रेन			
72	भारत गणराज्य और उक्रेन के बीच गोपनीय सूचनाओं के संरक्षण के संबंध में करार ।	12.8.2003	7.4.2004	
73.	भारत गणराज्य और उक्रेन के बीच प्रत्यर्पण संधि	3.10.2002	26.5.2004	
	उजबेकिस्तान			
74	भारत गणराज्य की सरकार और उजबेकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच भारत-उजबेक सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने के संबंध में समझौता ज्ञापन	29.10.2004		29.10.2004
	जाम्बिया			
75	भारत और सीरिया के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	21.4.2003		

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार इत्यादि के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/प्रवेश/ स्वीकृती जामा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
	वेनेजएला			
76	भारत के विदेश सेवा संस्थान और वेनेजुएला के विदेश सेवा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन	2.10.2004		
	यमन			
77	भारत गणराज्य की सरकार और यमन गणराज्य की सरकार के बीच निवेशों के संवर्द्धन एवं संरक्षण पर करार	3.10.2002	10.2.2004	10.2.2004

परिशिष्ट X

जनवरी 2004 से दिसम्बर 2004 की अवधि के दौरान पूर्ण शक्तियां जारी किये जाने से संबंधित दस्तावेज

क्र.सं.	अभिसमय/संधि	पूर्ण शक्तियों की तारीख
1.	भारत गणराज्य के लघु उद्योग मंत्रालय और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन संपन्न किये जाने के लिए श्री बी एस मिन्हास, सचिव(एस एस आई) लघु उद्योग मंत्रालय को पूर्ण शक्तियां ।	13.01.2004
2.	भारत गणराज्य की सरकार और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन संपन्न किये जाने के लिए श्रीमती रति विनय झा, सचिव, पर्यटन विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय को पूर्ण शक्तियां ।	21.01.2004
3.	एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा बैंकाक में पारित एशियाई उच्च-मार्ग नेटवर्क पर अंतर- सरकारी करार संपन्न किये जाने के लिए श्री दीपक चटर्जी, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग को पूर्ण शक्तियां ।	26.04.2004
4.	भारत गणराज्य और सर्बिया और मोंटनेगरो के मंत्रिपरिषद के बीच वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग पर करार संपन्न किये जाने के लिए श्री कपिल सिबल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को पूर्ण शक्तियां ।	24.09.2004
5.	भारत सरकार और सैन मारिनो गणराज्य के बीच कोंसली संबंधों को बढ़ाकर राजनयिक संबंधों तक करने के लिए करार संपन्न किये जाने हेतु श्री हिमाचल सोम को पूर्ण शक्तियां ।	04.11.2004
6.	संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी निरूपम सेन को निम्नलिखित संपन्न किये जाने के लिए पूर्ण शक्तियां और प्राधिकार (क) सशस्त्र संघर्षों में बच्चों को शामिल करने पर बच्चों के अधिकारों से संबद्ध अभिसमय पर वैकल्पिक प्रोतोकोल(ख) बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृति और बाल अशलील साहित्य के संबंध में बच्चों के अधिकारों से संबद्ध अभिसमय पर वैकल्पिक प्रोतोकोल ।	04.11.2004

परिशिष्ट XI

जनवरी, 2004 से दिसम्बर 2004 की अवधि के दौरान जारी किये गये अनुसमर्थन / प्रवेश दस्तावेज

क्र.सं.	अनुसमर्थन/प्रवेश दस्तावेज	अनुसमर्थन / प्रवेश जारी करने की तिथि
1.	तम्बाकु नियंत्रण से संबद्ध विश्व व्यापार संगठन का संरचना अभिसमय	22.01.2004
2.	निवेशों के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बहरीन साम्राज्य के बीच करार	06.08.2004
3.	भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण करार	15.04.2004
4.	निवेशों के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और हंगरी गणराज्य के बीच करार	20.02.2004
5.	भारत गणराज्य की सरकार और इजराइल राज्य के बीच पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में सहयोग पर करार	07.05.2004
6.	भारत गणराज्य की सरकार और इटली गणराज्य के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग पर करार	07.06.2004
7.	भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपींस गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि	03.05.2004
8.	भारत गणराज्य की सरकार और सूडान गणराज्य की सरकार के बीच निवेशों के संरक्षण और संवर्द्धन पर करार	23.01.2004
9.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और स्विस संघीय परिषद के बीच करार	06.08.2004
10.	आपदा की स्थिति में सहयोग पर भारत गणराज्य और स्विस परिसंघ के बीच करार	20.02.2004
11.	भारत गणराज्य की सरकार और थाइलैंड साम्राज्य के बीच आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता पर करार	18.03.2004
12.	भारत गणराज्य की सरकार और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो गणराज्य की सरकार के बीच राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर- सरकारी आयोग के संबंध में करार ।	18.03.2004
13.	भारत गणराज्य और उक्रेन के बीच गोपनीय सूचना के आपसी संरक्षण पर करार	07.04.2004
14.	भारत गणराज्य और उक्रेन के बीच प्रत्यर्पण संधि	26.05.2004
15.	भारत गणराज्य की सरकार और स्लोवेनिया गणराज्य की सरकार के बीच दोहरे कराधान के परिहार तथा आयकर के वित्तीय वचन पर रोक के संबंध में करार	30.08.2004

परिशिष्ट XI

क्र.सं.	अनुसमर्थन/प्रवेश दस्तावेज	अनुसमर्थन/प्रवेश जारी करने की तिथि
16.	भारत गणराज्य की सरकार और आर्मेनियाँ गणराज्य की सरकार के बीच निवेशों के संवर्द्धन और संरक्षण पर करार	30.08.2004
17.	भारत गणराज्य की सरकार और लाओ लोकतांत्रिक जन गणराज्य के बीच औषघों की मांग में कमी और मादक द्रव्यों तथा मनः प्रभावी पदार्थों एवं संबंधित मामलों पर आपसी सहयोग से संबद्ध करार	23.01.2004
18.	भारत गणराज्य की सरकार और पोलैंड गणराज्य की सरकार के बीच संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग पर करार	21.10.2004
19.	भारत गणराज्य की सरकार और बहरीन साम्राज्य के बीच सम्मनों की तामील, न्यायिक दस्तावेजों, आयोगों, निर्णयों के निष्पादन और विवाचनों से संबद्ध नागरिक और व्यवसायिक मामलों में न्यायिक सहयोग पर करार	21.10.2004
20.	भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य के बीच आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता पर संधि	04.11.2004
21.	भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य के बीच प्रर्त्यपण संधि	24.11.2004
22.	भारत गणराज्य और कुवैत राज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि	09.12.2004
23.	भारत गणराज्य और कुवैत राज्य के बीच आपराधिक मामलों में विधिक सहायता पर करार	03.12.2004
24.	भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच आपसी विधिक सहायता और सिविल मामलों में निर्णयों की मान्यता एवं प्रवर्तन पर करार ।	07.12.2004
25.	भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता पर संधि	07.12.2004

परिशिष्ट XII

नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक रूप से वित्त प्रदत्त संस्थाओं / गैर- सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित/चलाये गये सम्मेलन/सेमिनारों/बैंकठ/अध्ययन परियोजनाएं ।

क. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान हुआ व्यय

क्र.सं.	कार्यक्रम	संस्थान	राशि (रूपए में)
1.	मार्च 1947 में हुए प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन के उपलक्ष्य में 2007 में एक समारोह सम्मेलन का आयोजन फाइल सं. एफ(II) 12 (12)/2004	एशोसिएशन फॉर एशियन यूनियन	56,250/-
2.	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन, मौलिक अनुसंधान कार्यों का प्रकाशन और मुद्रण, व्याख्यानों का आयोजन इत्यादि। फा. सं. एफ(II) 12 (16)/2004	भारतीय अध्ययन केन्द्र बीजिंग विश्वविद्यालय	5,00,000/-
3.	मुस्लिम देशों के संबंध में भारत की नीति परियोजना। सं. एफ(II) 12 (16)/2004	ओ आर एफ एशियाई अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	3,00,000/-
5.	पश्चिम और मध्य एशिया पर व्याख्यान तथा अनुसंधान बैठके आयोजित करने का इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेस्ट एंड सेन्द्रल एशियन स्टडीज (राजदूत एम.एच.अंसारी) फाइल सं0 एफ(II) 12 (19)/2004	इंडियन एसोसएशन ऑफ बेस्ट एंड सेन्ट्रल एशियन स्टडीज	1,50,000/-
7.	27-29 जनवरी, 2004 तक" शिष्ट्रवाद, अंतराष्ट्रीयवाद और भारतीय डायस्पोरा" पर आयोजित सेमिनार की कार्यवाहियों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना। फाइल सं0 एफ(II) 12 (21)/2003	भारतीय डायस्पोरा और सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र हेमचन्द्रचार्या, उत्तरी गुजरात, पाटन	37,500/-
8.	हिस्पेनिज्म एंड लूसो- बाजीलियन स्टडीज, फ्लैशबैंक फ्राम दी प्रजेन्ट पर बी इंटरनेश्नल सम्मेलन की कार्यवाहियों का प्रकाशन (शेष भुगतान) फाइल सं0 एफ(II) 12 (68)/2003	स्पेनिश अध्ययन केन्द्र, जे एन यू	16,680/-
9.	जून, 2004 में द्वितीय भारत- सर्बिया मोंटनेगरो वार्ता में भागीदारी फाइल सं0 एफ(II) 12 (12)/2004	नीति अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली	1,39,500/-
10.	नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर 7वां एशियाई क्षेत्रीय सेमिनार (शेष भुगतान) फाइल सं0 एफ(II) 12 (54)/2002	यूनाटेड स्कूल्स इंटरनेश्नल, नई दिल्ली	12,500/-

परिशिष्ट XII

क्र.सं.	कार्यक्रम	संस्थान	राशि (रूपए में)
11.	डा0 आदेश पाल का आस्ट्रेलिया और फिजी का शैक्षिक दौरा फाइल सं0 एफ(रूस) 12 (38)/2004	हेमचन्द्राचार्य, उत्तरी गुजराज विश्वविद्यालय, पाटन	41, 380/-
12.	एशिया में बृहत्तर राजनैतिक आर्थिक प्रवृत्तियाँ विषय पर संयुक्त सेमिनार में भागीदारी (शेष भुगतान) फाइल सं0 एफ(रूस) 12 (54)/2004	सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली	75,285/-
13.	तीन मानवधिकार अभिसमयों पर रिपोर्ट की तैयारी" परियोजना फाइल सं0 एफ(रूस) 12 (25)/2004	आई एस आई एल, नई दिल्ली	4,11,400/-
14.	" मध्य एशिया में परिवर्तन : राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक विकास के आयाम" पर मार्च, 2004 में आयोजित सेमिनार में हुए व्यय का भुगतान । फाइल सं0 एफ(रूस) 12 (73)/2004	मुम्बई विश्वविद्यालय	50,000/-
15.	भारत- अमरीका सैन्य कानूनों के आदान-प्रदान का आयोजन 1-3,मार्च, 2004 फाइल सं0 एफ(रूस) 12 (19)/2004	यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीच्यूशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	18,215/-
16.	" एशिया में वृहत्तर राजनैतिक - आर्थिक प्रवृत्तियाँ" विषय पर संयुक्त सेमिनार में भागीदारी फाइल सं0 एफ(रूस) 12 (54)/2004	सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली	75,285/-
17.	फिजी में जातीय संघर्ष : भारतीय डायस्पोरा के समक्ष समायोजन की चुनौतियाँ । फाइल सं0 एफ(रूस) 12 (61)/2004	डा0 अम्बा पांडे जे एन यू	3,966/-
18.	पाकिस्तानी समकक्ष के साथ ट्रैक -II वार्ता के अगले दौर का आयोजन । फाइल सं0 एफ(रूस) 12 (8)/2004	भारत- पाकिस्तान नीमराना पहल, नई दिल्ली	2,60,385/-
19.	पाकिस्तानी समकक्ष के साथ ट्रैक -II वार्ता के अगले दौर का आयोजन । फाइल सं0 एफ(रूस) 12 (18)/2004	भारत- पाकिस्तान नीमराना पहल, नई दिल्ली	2,60,385/-
20.	सामरिक भागीदारी की रुपरेखा बनाने के लिए भारत- आस्ट्रेलिया संयुक्त अध्ययन । फाइल सं0 एफ(रूस) 12 (85)/2004	डा0 सी राजा मोहन, प्रोफेसर, दक्षिण एशियाई अध्ययन केन्द्र जे एन यू	12, 500/-
21.	हिस्पेनिज्म एंड लूसो- बाजीलियन स्टडीज, फ्लैशबैंक फ्राम दी प्रजेन्ट पर बी इंटरनेशनल सम्मेलन की कार्यवाहियों का प्रकाशन (अंतिम भुगतान) फाइल सं0 एफ(रूस) 12 (68)/2004	स्पेनिश अध्ययन केन्द्र, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज, लिटरेचर एंड कल्वर स्टडीज, जे एन यू	
22.	मार्च 2004 में" दक्षिण एशिया में घरेलू संघर्ष - भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर प्रभाव" पर सेमिनार और मोनोग्राफ का प्रकाशन (अंतिम भुगतान) फाइल सं0 एफ(रूस) 12 (36)/2004	अंतराष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, पांडिचेरी वि. पांडीचेरी ।	25,750/-

परिशिष्ट XII

क्र.सं.	कार्यक्रम	संस्थान	राशि (रूपए में)
23.	" नये युग में भारत की विदेश नीति की चुनौतियाँ" पर अक्तूबर, 2004 में सेमिनार (75%) फाइल सं0 एफ(ख्ख) 12 (15)/2004	एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर उत्तरांचल	56,250/-
24.	मार्च 2004 में वैकूवर में आयोजित दूसरी कनाडा-भारत वार्ता में भागीदारी (अंतिम भुगतान) फाइल सं0 एफ(ख्ख) 12 (78)/2004	नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	48,200/-
25.	शांति की खोज में" भारत-पाकिस्तान संबंध" पर सेमिनार/ अंतिम भुगतान) फाइल सं0 एफ(ख्ख) 12 (4)/2004	विद्या प्रसारक मंडल, मुम्बई	1,14,592/-
26.	5-7 नवम्बर, 2003 तक फ्योदोर आई त्यूतचेव की दो सौंवी वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" रुसी और भारतीय साहित्य में पंरपराएं और दार्शनिक कविता पर अंतरर्राष्ट्रीय सम्मेलन (अंतिम भुगतान) फाइल सं0 एफ(ख्ख) 12 (12)/2004	रुसी अध्ययन केन्द्र जे एन यू	9,120/-
		कुल	**24,65,025/-**

ख. पहले से अनुमोदित परियोजनाओं के लिए जारी की जाने वाली राशि

क्र.सं.	कार्यक्रम	संस्थान	राशि (रूपए में)
1.	शिप एंड ओसन फाउन्डेशन, टोक्यो के शिष्टमंडल के साथ दूसरी वार्ता की मेजबानी	हिंद महासागर अध्ययन सोसायटी, नई दिल्ली	73,000/-
2.	तीन मानवधिकार अभिसमयों पर रिपोर्ट की तैयारी रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों के हवाई किराये सहित।	आइ एस आई एल, नई दिल्ली	4,11,400/- + 1,25,000/- 5,36,000/-
3.	डा0 श्यामली घोष द्वारा चीन और दक्षिण एशिया : बंगलादेश - चीन संबंध" परियोजना	आई डी एस ए, नई दिल्ली	1,77,480/-
4.	सामारिक भागीदारी को रुपरेखा बनाने के लिए भारत, आस्ट्रेलिया संयुक्त अध्ययन के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट की तैयारी।	डा0 सी राजा मोहन	12,500/-
5.	" पोखरण -II के बाद भारत का परमाणु राजनय : इसके सरकारी और सार्वजनिक चेहरे" परियोजना।	ओ आर एफ सुरक्षा अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली।	2,95,000/-
6.	" दक्षिण एशिया में घरेलू संघर्ष : भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर प्रभाव" पर सेमिनार	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	26,000/-

परिशिष्ट XII

क्र.सं.	कार्यक्रम	संस्थान	राशि (रूपए में)
7.	" भारत और आसियान एशिया" सेमिनार	जे एन यू, नई दिल्ली	65,000/-
8.	सेमिनार" हाइड्रोइंड - 2004"	राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय, देहरादून	50,000/-
9.	दूसरी कनाडा- भारत वार्ता	सी पी आर, नई दिल्ली	48,200/-
10.	परियोजन" पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बातचीत का पुनर्निधारण"	सामरिक और क्षेत्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय, जम्मू	5,00,000/-
11.	जैव - आतंकवाद और जैव रक्षा" पर सम्मेलन	शांति एवं संघर्ष अध्ययन विश्वविद्यालय, जम्मू	5,00,000/-
12.	ट्रैक-II भारत- श्रीलंका वार्ता का दूसरा दौरे	आई आई सी, नई दिल्ली	61,600/-
13.	अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन मौलिक अनुसंधान कार्यो का प्रकाशन और मुद्रण इत्यादि जैसी विशेष परियोजनाओं को चलाना ।	भारतीय अध्ययन केन्द्र, बीजिंग विश्वविद्यालय	5,00,000/-
14.	चीन राज्य परिषद के विकास अनुसंधान केन्द्र के साथ ट्रैक -II वार्ता	आर आई एस, नई दिल्ली	60,000/-
15.	" भारत और नया यूरोप" सेमिनार	भारतीय राजनयिक संघ, नई दिल्ली	15,500/-
16.	भारत युगोस्लाविया वार्ता	सी पी आर, नई दिल्ली	40,000/-
17.	" फ्योदोर आई प्यूतचेव की दो सौवीं वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" रुसी और भारतीय साहित्य में पंरपराएं और दार्शनिक कविता" पर सेमिनार	जे एन यू, नई दिल्ली	18,750/-
18.	परियोजना" मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताएं : भारत पर प्रभाव	रुसी, मध्य एशियाई एवं पूर्वी यूरोपीय अध्ययन केन्द्र जे एन यू	37,500/-
19.	अंतर्राष्ट्रीय कानून पर चुनिंदा लेखों बाले पुस्तक का प्रकाशन	आई एस आई एल, नई दिल्ली	12,500/-
20.	परियोजना" अरब विश्व में अमरीका विरोधी भावना और भारत किस प्रकार इससे लाभ ले सकता है" ।	डा0 मंजुश्री सिंह	5,000/-
21.	" मध्य पश्चिम और मध्य एशियाई देशों की भाषा, परंपराएं और समाज" विषय पर सेमिनार	पंजाब विश्वविद्यालय	30,000/-
22.	" साहित्य कला और फिल्मों में परिलक्षित क्रांति के 25 वर्ष के बाद का इरान" परियोजना ।	ओ आर एफ एशियाई अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	37,500/-
23.	" अप्रवासी भारतीयों को प्रभावित करने वाले निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून" परियोजना	आई एस आई एल, नई दिल्ली	6,00,000/-
		कुल	**27,26,530/-**

परिशिष्ट XIII

अप्रैल से अक्तूबर 2003 तक की अवधि के लिए व्यय का विवरण (आईटैक एवं स्कैप कार्यक्रम)

मेजर/माइनर लेखा शीर्ष	2004-05 में आबंटित सीटों कुल संख्या	30.11.2004 की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षुओं की संख्या	30.11.2004 की स्थिति के अनुसार किया गया कुल व्यय	2004-05 में बजट अनुदान
मेजर लेखा शीर्ष-3605, 17-आईटेक कार्यक्रम, 17.00.32-अंशदान	2145	793	26.31 करोड़ रूपए	30.5 करोड़ रूपए
मेजर लेखा शीर्ष-3605, 19-स्कैप कार्यक्रम, 19.00.32-अंशदान	611	214	2.89 करोड़ रूपए	5.5 करोड़ रूपए

परिशिष्ट XIV

आईटेक/स्कैप योजना (2004-2005) के तहत नामित विदेशी व्यक्तियों का 'ख' तथा 'ग' श्रेणी के पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थानों की सूची

क्र संख्या	संस्थान का नाम	नगर (संस्थान)
1.	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज	हैदराबाद
2.	ऐप्टेक लिमिटिड	मुम्बई
3.	भारतीय मानक ब्यूरो	नई दिल्ली
4.	संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो	नई दिल्ली
5.	केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान	हरियाणा
6.	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्था	मैसूर
7.	केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान	हैदराबाद
8.	केन्द्रीय टूल डिजाइन संस्थान	हैदराबाद
9.	केन्द्रीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान	कर्नाटक
10.	केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन	नई दिल्ली
11.	सी-डैक	मोहाली (चंडीगढ़)
12.	सी एम सी लिमिटिड	नई दिल्ली
13.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	नई दिल्ली
14.	भारत का उद्यमिता विकास संस्थान	गुजरात
15.	द्रव नियंत्रण शोध संस्थान	केरल
16.	मानव बसाव प्रबंधन संस्थान	नई दिल्ली
17.	भारतीय जन संचार संस्थान	नई दिल्ली
18.	भारतीय उत्पादन प्रबंध संस्थान	उड़ीसा
19.	भारतीय दूर संवेदी संस्थान	देहरादून
20.	जन साधन संस्थान	नई दिल्ली
21	राजकीय लेखांकन एवं वित्त संस्थान	नई दिल्ली
22.	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान	नई दिल्ली
23.	अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान	नई दिल्ली
24.	अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र	कोलकाता
25.	जे आई एस इंजीनियरिंग महाविद्यालय	कोलकाता
26.	नरूला प्रौद्योगिकी संस्थान	कोलकाता
27.	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो	नई दिल्ली
28.	राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान	पूना
29.	राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान	नई दिल्ली
30.	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यापार विकास संस्थान	नोएडा

परिशिष्ट XIV

क्र संख्या	संस्थान का नाम	नगर (संस्थान)
31	राष्ट्रीय भेषजी शिक्षा एवं शोध संस्थान	पंजाब
32	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान	हैदराबाद
33	राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान	हैदराबाद
34	एन आई आई टी लिमिटिड	नई दिल्ली
35	डाक प्रशिक्षण केन्द्र	कर्नाटक
36	गुट निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों हेतु शोध एवं सूचना प्रणाली	नई दिल्ली
37.	राइट्स	हरियाणा
38.	सीबिट	नई दिल्ली
39.	दक्षिण भारत वस्त्र शोध संघ	कोयम्बटूर
40	टाटा इन्फोटेक	नई दिल्ली
41	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	चेन्नई
42	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान	उत्तर प्रदेश
43	जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र	रूड़की

परिशिष्ट XV

आईटैक तथा स्कैप के अंतर्गत सिविलियन प्रशिक्षण स्लॉट का आबंटन तथा उपयोग (2004-05)

देश	स्लॉट	कुल शामिल हुए	कुल शामिल हुए	देश	स्लॉट	कुल शामिल हुए	कुल शामिल हुए
ITEC							
अफगानिस्तान	100	102	80	ग्रेनादा	5	7	5
अल्जीरिया	12	9	9	गयाना	35	51	35
अंगोला	21	16	3	होन्डुरस	7	3	2
एंटीगुअन भरमूदा	7	7	3	हंगरी	2	2	1
अर्जेन्टीना	3	3	1	इण्डोनेशिया	88	119	71
आरमीनिया	60	86	63	ईरान	15	18	13
आजरभैजान	10	9	6	ईराक	125	121	78
भंगलादेश	120	108	56	इवोरी कोस्ट	40	56	34
भेलारूस	10	12	10	जार्डन	5	8	4
भेलीज	7	10	6	कजाखिस्तान	60	41	27
भेनिन	10	4	3	किरिभाती	2	2	1
भूटान	80	43	32	कोरिया डी पी आर	10	10	6
भोलीभिया	3	1	0	किरगीजिस्तान	65	50	38
भोस्निया	2	1	0	लाओस	60	74	42
ब्रुनेई दारूसलाम	10	1	0	लातविया	4	4	3
भल्गारिया	10	17	5	लेभनान	2	3	2
भुरूंडी	5	1	0	लाईभीरिया	10	2	2
कम्भोडिया	60	67	47	लिथवानिया	10	7	6
कोलम्भिया	20	21	13	मकदूनिया	4	0	0
डोमिनिक राष्ट्रकुल	5	4	1	मेडागास्कर	15	9	4
कोस्टारिका	7	4	3	मलेशिया	23	10	7
क्यूभा	38	38	36	मालदीव्स	20	33	19
जिभौती	10	0	0	माली	3	1	1
डोमिनिक गणराज्य	5	1	1	मारीतानिया	2	2	1
पूर्वी तिमोर	20	6	2	मैक्सिको	13	15	5
इक्वाडोर	5	4	2	मालदोवा	2	1	1
मिस्र	13	13	9	मंगोलिया	50	34	29
अल्सलवाडोर	7	9	9	मोरक्को	5	5	2
एरीट्रिया	5	5	4	म्यांमार	130	134	101
एस्टोनिया	25	24	19	नेपाल	80	30	24
इथोपिया	30	46	27	निकारागुआ	7	5	3
फीजी	30	29	13	ओमान	55	70	53
जार्जिया	35	33	23	पलाऊ	2	1	1

परिशिष्ट XV

देश	स्लॉट	कुल शामिल हुए	कुल शामिल हुए
फिलिस्तीन	30	55	19
पनामा	15	15	10
पापुआ न्यू गिनी	10	29	9
परागुवे	2	3	2
पेरू	8	6	6
फिलीपीन्स	35	46	16
पोलैण्ड	3	4	3
साउटोम गणराज्य	2	2	0
रोमानिया	10	13	9
रूस	100	123	77
रवांडा	10	4	0
सेनेगल	20	14	10
स्लोवाक गणराज्य	5	7	4
सोलोमन द्वीप समूह	7	6	2
श्रीलंका	120	93	75
सूडान	70	120	52
सूरीनाम	20	20	14
सीरिया	40	37	30
ताजिकिस्तान	100	43	30
थाईलैण्ड	90	53	39
टोगो	2	2	2
टोंगा	10	6	6
त्रिनिदाद एवं टोभैगो	20	19	9
ट्यूनिशिया	10	7	5
तुर्की	50	76	40
तुर्कमेनिस्तान	32	36	32
युक्रेन	10	13	8
उरूग्वे	5	12	6
उजभेकिस्तान	109	113	77
वनौतू	5	2	0
वेनेजुएला	5	5	5
वियतनाम	100	144	90
यमन	30	31	25
योग		**2821**	**1819**
स्कैप			
भोट्सवाना	25	20	18
भुरकिनाफासो	10	2	2
केमरून	5	4	3
कोमोरोस	5	0	0
गेभन	5	6	1
गाम्भिया	10	10	4
घाना	60	80	55
केन्या	53	69	39
लिसोथो	30	19	16
मलावी	5	11	3
मारीशस	40	49	31
मोजाम्भीक	20	50	17
नामीभिया	50	48	38
नाइजर	5	1	0
नाईजीरिया	53	58	29
सेशेल्स	20	22	18
सीएरा लियोन	15	9	8
दक्षिण अफ्रीका	100	93	64
स्वाजीलैण्ड	5	4	0
तंजानिया	75	73	54
उगाण्डा	30	32	23
जाम्भिया	45	31	23
जिम्भाभवे	50	67	39
योग		758	494

परिशिष्ट XVI

अप्रैल से नवम्बर 2004 तक की अवधि के दौरान विभिन्न देशों को आबंटित सैन्य प्रशिक्षण स्लॉट की संख्या आईटैक/सैप के अन्तर्गत

क्र.सं.	देश	थल सेना	नौ सेना	वायु सेना	डीएसएससी	एनडीसी	योग
आईटैक/सैप के अन्तर्गत							
1.	बंगलादेश	6	19	5	0	1	31
2.	भूटान	0	0	0	1	1	2
3.	बोट्सवाना	3	0	0	0	0	3
4.	कम्बोडिया	3	2	4	0	0	9
5.	मिस्र	0	0	0	0	1	1
6.	इथोपिया	0	0	0	1	0	1
7.	घाना	3	2	1	0	0	6
8.	इण्डोनेशिया	2	3	4	0	1	10
9.	कजाखिस्तान	4	0	0	1	0	5
10.	केन्या	3	3	0	0	0	6
11.	किरगिजिस्तान	4	0	0	0	0	4
12.	लाओ	2	0	4	0	0	6
13.	लिसोथो	3	0	0	0	0	3
14.	मलेशिया	2	3	3	0	0	8
15.	मालदीव्स	0	0	0	0	1	1
16.	मॉरीशस	14	9	5	0	0	28
17.	मंगोलिया	3	0	0	1	0	4
18.	म्यांमार	19	3	2	1	1	26
19.	नेपाल	0	0	0	2	1	3
20.	नाईजीरिया	3	4	2	0	0	9
21.	सेशैल्स	4	5	0	1	0	10
22.	श्रीलंका	0	0	0	3	2	5
23.	सीरिया	0	0	0	1	1	2
24.	सूडान	0	0	0	1	0	1
25.	ताजिकिस्तान	6	0	0	0	0	6
26.	तंजानिया	3	2	0	1	0	6
27.	थाइलैण्ड	0	0	0	0	1	1
28.	उगाण्डा	3	0	0	0	0	3
29.	उजबेकिस्तान	2	0	0	0	1	3
30.	वियतनाम	10	4	0	0	1	15
		102	**69**	**30**	**14**	**13**	**218**

परिशिष्ट XVI

क्र.सं.देश		थल सेना	नौ सेना	वायु सेना	डीएसएससी	एनडीसी	योग
एस एफ एस के अधीन							
1.	आस्ट्रेलिया	0	0	0	1	0	1
2.	बोट्सवाना	22	0	14	1	0	37
3.	चिली	0	0	0	0	1	1
4.	फ्रांस	3	0	0	0	1	4
5.	जर्मनी	0	0	0	0	1	1
6.	ईरान	0	1	0	0	0	1
7.	केन्या	0	0	6	0	0	6
8.	कुबैत	0	1	0	0	0	1
9.	जापान	0	0	0	1	0	1
10.	मलेशिया	1	1	0	1	1	4
11.	नाईजीरिया	3	20	0	1	1	25
12.	कोरिया गणराज्य	0	0	0	1	0	1
13.	सिंगापुर	0	1	0	1	1	3
14.	दक्षिण अफ्रीका	0	2	0	1	0	3
	योग	**29**	**26**	**20**	**8**	**6**	**89**
अदल बदल							
1.	बंगलादेश	0	0	0	3	0	3
2.	यूनाइटेड किंगडम	0	0	0	3	1	4
3.	अमेरिका	0	0	0	2	1	3
	योग	**0**	**0**	**0**	**8**	**2**	**10**

परिशिष्ट XVII

नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में तैनात आईटैक विशेषज्ञों की सूची

क्र.सं.	देश	विशेषज्ञ का नाम	क्षेत्र	दिनांक से	दिनांक तक
1.	लाओस	मेजर अशोक झा	अंग्रेजी एवं सैन्य युक्तियों का शिक्षण	19.9.2001	दिसम्बर, 2004
2.	लाओस	मेजर संदीप नौटियाल	अंग्रेजी एवं सैन्य युक्तियों का शिक्षण	19.9.2001	दिसम्बर, 2004
3.	जाम्बिया	कर्नल यू के गुरूंग	भारतीय सैन्य सलाहकार दल	3.1.2004	2.1.2006
4.	जाम्बिया	ले.कर्नल रघु	श्री निवासन भारतीय सैन्य सलाहकार दल	3.1.2004	2.1.2006
5.	जाम्बिया	ले.कर्नल रघु	श्री निवासन भारतीय सैन्य सलाहकार दल	3.1.2004	2.1.2006
6.	जाम्बिया	विंग कमान्डर वीआर चौधरी	भारतीय सैन्य सलाहकार दल	3.1.2004	2.1.2006
7.	गयाना	डॉ. वी सी माथुर	समूह नियोजन		1.1.2005
8.	गयाना	श्री सी डी बनर्जी	डिजिटल प्रौद्योगिकी	1.9.2002	31.8.2005
9.	सेशैल्स	कमान्डर पी पोखरियाल	नौ सेना सलाहकार	जनवरी 2003	जनवरी,2005
10.	जमैका	श्री के के तिवारी	ढलाई विशेषज्ञ	11.2.2002	10.6.2005
11.	नामीबिया	श्री आर के दुबे	गणित के व्याख्याता	1.3.2003	1.3.2005
12.	लाओस	ले. कर्नल विवेक शर्मा	अंग्रेजी भाषा शिक्षक	मार्च, 2003	मार्च, 2006
13.	लाओस	मेजर एस एस मैनी	अंग्रेजी भाषा शिक्षक	अप्रैल, 2003	अप्रैल, 2006
14.	जमैका	श्री के मोहन	डेयरी फार्मिंग	मई, 2003	मई, 2005
15.	गयाना	डॉ. आर पी एस खरब	सब्जी बीज विशेषज्ञ	जून, 2003	जुन, 2005
16.	गयाना	डॉ. ए मुर्गन	दुग्ध विपणन	जुलाई, 2003	जुलाई, 2006
17.	गयाना	श्री मुकुल गुप्ता	नगर नियोजक	अगस्त, 2003	अगस्त, 2005
18.	मॉरीशस	श्री ए के गुप्ता	वास्तुकार	जुलाई, 2003	जुलाई, 2005
19.	लिसोथो	मेजर संजय कुमार मौर्य	सर्जिकल विशेषज्ञ	अगस्त, 2003	अगस्त, 2005

परिशिष्ट XVII

क्र.सं.	देश	विशेषज्ञ का नाम	क्षेत्र	दिनांक से	दिनांक तक
20.	लिसोथो	मेजर ए के गुप्ता	भारतीय सेना प्रशिक्षण दल	अगस्त, 2003	अगस्त, 2005
21.	लिसोथो	मेजर पवन ढल	भारतीय सेना प्रशिक्षण दल	अगस्त, 2003	अगस्त, 2005
22.	लिसोथो	मेजर नीरज गुसाई	भारतीय सेना प्रशिक्षण दल	अगस्त, 2003	अगस्त, 2005
23.	लिसोथो	मेजर प्रभात गिद्दा	भारतीय सेना प्रशिक्षण दल	अगस्त, 2003	अगस्त, 2005
24.	लिसोथो	मेजर विजय मनराल	भारतीय सेना प्रशिक्षण दल	अगस्त, 2003	अगस्त, 2005
25.	लिसोथो	मेजर संजय मोहला	भारतीय सेना प्रशिक्षण दल	सितम्बर, 2003	सितम्बर, 2005
26.	लिसोथो-दूसरा बैच		मेजर जे एस मिनहास प्रशिक्षण दल	भारतीय सेना सितम्बर, 2003	सितम्बर, 2005
27.	लिसोथो	मेजर हरप्रीत सिंह	भारतीय सेना प्रशिक्षण दल	सितम्बर, 2003	सितम्बर, 2005
28.	लिसोथो	मेजर एन के ओहरी	भारतीय सेना प्रशिक्षण दल	सितम्बर, 2003	सितम्बर, 2005
29.	इथोपिया	श्री जे एम गुप्ता	विदेश व्यापार विशेषज्ञ	अक्तूबर, 2003	जनवरी, 2005
30.	सेशैल्स	ले. कर्नल एल वीआर सिंह	सैन्य सलाहकार	अक्तूबर, 2003	अक्तूबर, 2005
31.	लिसोथो	ब्रिगेडियर पदम बधवार	सुरक्षा सलाहकार, आई ए टी टी	नवम्बर, 2003	फरवरी, 2005
32.	सेशैल्स	डॉ. जगत राम	नेत्र विशेषज्ञ	नवम्बर, 2003	नवम्बर, 2005
33.	गयाना	श्री सी एच रंगाराव	टी वी प्रसारण इंजीनियर	दिसम्बर, 2003	दिसम्बर, 2005
34.	लिसोथो	सीएचएम लक्ष्मारेड्डी	भारतीय सेना प्रशिक्षण दल	दिसम्बर, 2003	अगस्त, 2005
35.	लिसोथो	सीएचएम बी देवराय	भारतीय सेना प्रशिक्षण दल	दिसम्बर, 2003	अगस्त, 2005
36.	लिसोथो	हवलदार विधान मैक	भारतीय सेना प्रशिक्षण दल	दिसम्बर, 2003	अगस्त, 2005
37.	लिसोथो	सीएचएम सायमन के जॉन	भारतीय सेना प्रशिक्षण दल	दिसम्बर, 2003	अगस्त, 2005
38.	लिसोथो	हवलदार ए के भारती	भारतीय सेना प्रशिक्षण दल	दिसम्बर, 2003	अगस्त, 2005

परिशिष्ट XVII

क्र.सं.	देश	विशेषज्ञ का नाम	क्षेत्र	दिनांक से	दिनांक तक
39.	मॉरीशस	श्री के पी सिंह	परिमाण सर्वेक्षक	26 अगस्त, 2004	अगस्त, 2005
40.	मॉरीशस	श्री पी के सिंह	परिमाण सर्वेक्षक	26 अगस्त, 2004	अगस्त, 2005
41.	मॉरीशस	श्री दीपक ठाकुर	परिमाण सर्वेक्षक	26 अगस्त, 2004	अगस्त, 2005
42.	मॉरीशस	श्री एन के सिंह	सिविल इंजीनियर	26 अगस्त, 2004	अगस्त, 2005
43.	मॉरीशस	श्री ए के रस्तोगी	सिविल इंजीनियर	सितम्बर, 2004	सितम्बर, 2005
44.	मॉरीशस	श्री राकेश सिंहल	नौकरशाहों के लिए प्रशिक्षक	जुलाई, 2004	जुलाई, 2005
45.	मॉरीशस	श्रीमती नन्दिता हजारिका	नौकरशाहों के लिए प्रशिक्षक	जुलाई, 2004	जुलाई, 2005
46.	मॉरीशस	श्रीमती सेतु राम लिंगम	नौकरशाहों के लिए प्रशिक्षक	अगस्त, 2004	अगस्त , 2004
47.	मॉरीशस	श्री राजेश कुमार	वास्तुकार	नवम्बर, 2004	नवम्बर, 2005
48.	मॉरीशस	श्री पी एस नेगी	वास्तुकार	नवम्बर, 2004	नवम्बर, 2005
49.	मॉरीशस	श्री राजेश के कौशल	वास्तुकार	नवम्बर, 2004	नवम्बर, 2005
50.	मॉरीशस	श्री बी के चक्रवर्ती	वास्तुकार	नवम्बर, 2004	नवम्बर, 2005

परिशिष्ट XVIII

आपद राहत सहायता

वर्ष 2004-05 के दौरान अल्प विकसित देशों को दी गयी आपदा राहत की सामग्रियों में भेषजों की आपूर्ति प्रमुख थी ।

क्र.सं.	देशों के नाम	मद	राशि (रू.)
1.	मध्य अमरीका के 4 देश अल सल्वाडोर, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, बेलिज	दवाओं की आपूर्ति	14,46,10.71
2.	डी पी आर के	1000 मीट्रिक टन गेहूँ, चावल का दान	1,67,10,000.00
3.	सूरीनाम	एच आई वी / एड्स दवाओं, कीटनाशकों, मच्छरदानियों की आपूर्ति	43,00,000.00
4.	जमैका	दवाओं की आपूर्ति	90,00,000.00
5.	ग्रेनडा	दवाओं की आपूर्ति	22,50,000.00
6.	हैती	दवाओं की आपूर्ति	4,50,000.00
7.	डोमिनिक गणराज्य	दवाओं की आपूर्ति	22,50,000.00
8.	बहामास	दवाओं की आपूर्ति	22,50,000.00
	कुल		373.54 लाख रू0

वर्ष 2004-05 के दौरान आपदा राहत सहायता के लिए कुल बजट अनुदान 5.1 करोड़ रू0 है।

परिशिष्ट XIX

लिंग से संबंधित आंकड़े

संवर्ग	कुल संख्या	महिला अधिकारियों की संख्या	कुल संख्या में उनका प्रतिशत
भारतीय विदेश सेवा	618	80	13
भारतीय विदेश सेवा (ख)	2674	359	13
एल एण्ड टी	15	2	13
भाषान्तरकार	33	6	18
पुस्तकालय संवर्ग	14	3	21

परिशिष्ट XX

अप्रैल 2004 से लेकर आई सी डब्ल्यू ए द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/सम्मेलनों/गोलमेज वार्ताओं का विवरण

क्र.	दिनांक	विषय	सहभागी
1.	23.4.2004	ट्रांस अटलांटिक संबंधों का भविष्य विषय पर संगोष्ठी	राजदूत वी के ग्रोवर , प्रो. बलवीर अरोड़ा, जे एन यू, प्रो. वरूण साहनी जे एन यू, श्री एम के रसगोत्रा, पूर्व विदेश सचिव
2.	5.5.2004	लातिन अमेरिकी एकता और भारत विषय पर संगोष्ठी	महामहिम श्री जार्ज हेन, चिली के राजदूत, प्रो. आर नारायणन, जे एन यू, प्रो. अब्दुल नाफी, जे एन यू, प्रो. आर एल चावला, जे एन यू, राजदूत एम पी एम मेनन
3.	7.5.2004	चीन-दक्षिण पूर्व एशिया की एक उद्‌भवशील शक्ति विषय पर संगोष्ठी	प्रो. मनोरंजन मोहन्ती, आई सी एस , प्रो. स्वर्ण सिंह , जे एन यू, श्री सुजीत दत्ता, आई डी एस ए, डॉ. जी वी सी नायडू, आई डी एस ए , राजदूत ए एन राम
4.	2.6.2004	तृतीय अफ्रीका दिवस पर व्याख्यान	श्री शशांक, विदेश सचिव, महामहिम श्रीमती एम ई कोना मासाबानी दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की उच्च आयुक्त, महामहिम मेजर जनरल चार्ल्स डिक्शन डैक्सू पी नमोलोह , नामीबिया गणराज्य के उच्च आयुक्त
5.	15.6.2004	पंचशील और समसामयिक विश्व विषय पर विचार गोष्ठी	राजदूत सी वी रंगनाथन
6.	13.7.2004	पश्चिम एशिया में धर्म और राज्य निर्माण विषय पर व्याख्यान	प्रो. डेविल एस टॉमस (अमेरिका) राजदूत एस के भूटानिया,
7.	28.7.2004	इण्डोनेशिया में इलैक्ट्रॉनिकी विषय पर संगोष्ठी	डॉ. शंकरी सुन्दर रामन, जे एन यू, डॉ. जी वी सी नायडू, आई डी एस ए , डॉ. उदय भानु सिंह, आई डी एस ए , प्रो. एस डी मुनि, जे एन यू
8.	10.9.2004	भारत और अफ्रीका के बीच नीपैड टीम संबंध विषय पर व्याख्यान	महामहिम डॉ. शेख तायिदियान गादियो, सेनेगल गणराज्य के विदेश मंत्री, श्री शशांक , पूर्व विदेश सचिव,
9.	24.9.2004	कराची विदेश संबंध आर्थिक मामले एवं विधि संबंधी परिषद् के पाकिस्तान से आए प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक	पाकिस्तान से सहभागी - चीफ जस्टिस सेवानिवृत्त सईद उज्जमा सिद्दिकी, डॉ. मंसूर आलम , श्री लियाकत मर्चेंट , डॉ. ए एस नासिर, डॉ. श्रीमती शाहीन सलाउद्दीन , श्रीमती मर्चेंट, श्री अहसान मुख्तार जुबैरी, श्री सलाहुद्दीन अहमद भारत से सहभागी - डॉ. सईदा हमीद , जस्टिस ए एम अहमदी , राजदूत एस के सिंह , श्री सलमान हैदर , राजदूत मुहम्मद हमीन अन्सारी, श्री इन्द्र महलोत्रा , प्रो. सुरेश शर्मा, श्री सिद्धार्थ वरद राजन, सुश्री मोनिका मोहता, सुश्री सुभा राजन
10.	29.9.2004	परमाणु मुद्दा और जापान विषय पर व्याख्यान	महामहिम श्री यासकुनी इनोकी , जापान के राजदूत, राजदूत अर्जुन असरानी ,
11.	13.10.2004	बंगाल की खाड़ी क्षेत्र (बिम्सटैक) के देशों में आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग-चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी	प्रो. एस डी मुनि , जे एन यू, डॉ. मनोज जोशी , हिन्दुस्तान टाइम्स , प्रो. पी वी राव, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, रियर एडमिरल राजा मेनन, यू एस आई आई , डॉ. मनमोहिनी कॉल , जे एन यू, राजदूत ए एन राम ,
12.	16.11.2004	यूरोपीय संघ में शामिल होने की राह पर रोमानिया विषय पर व्याख्यान	महामहिम राजकुमार रादू ऑफ होरेन्जोलेन वैरिन्जिन , रोमानिया

परिशिष्ट XX

क्र.	दिनांक	विषय	सहभागी
13.	18.11.2004	पंचशील के पचास वर्ष-वास्तविक बहुपक्षीयता पर आधारित एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	श्री के नटवर सिंह , विदेश मंत्री, श्री सी एम भण्डारी, अपर सचिव, (पी पी एण्ड आर) विदेश मंत्रालय श्रीमती जूलिया जौली जोनर, अफ्रीकी संघ , प्रो. मारिया रेनी क्यूरा सिविलकाय, अर्जेन्टीना, श्री लियू शूकिंग, चीन , श्री जिया जीझी , चीन , डॉ. इन्द्रस बालोग, हंगरी, डॉ. साबाम सैजियान , इण्डोनेशिया, श्री न्योन्त तिन , म्यामार , डॉ. बी बी थापा, नेपाल, डॉ. मुबासिर हसन, पाकिस्तान, प्रो. मारिया क्रिष्तोफ ब्रिस्की, पोलैण्ड, डॉ. किशोर महबूबानी, सिंगापुर, सुश्री एलिजाबेथ सिदिरोपोलस , दक्षिण अफ्रीका, पो. कुसुमा सितवोंगसे, थाईलैण्ड, प्रो. वी आर चन्द्र शेखर राव, सेवानिवृत्त, हैदराबाद, डॉ. जी गोपकुमार , केरल विश्वविद्यालय, डॉ. चन्द्रिका सिंह नागालैण्ड विश्व विद्यालय, सेवा निवृत्त राजदूत एस के भूटानी, प्रो. मनोरंजन मोहन्ती, आई सी एस , राजदूत सी दास गुप्ता , सेवानिवृत्त
14.	19-20.11.2004	भारत अफ्रीकी संबंधों में नवोद्भूत प्रवृत्तियां विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	श्री राव इन्द्रजीत सिंह , विदेश राज्य मंत्री, प्रो. एच सी नारंग ए एस ए, प्रो. ए के दुबे, ए एस ए , प्रो. जेड एम खान, जे एम आई, डॉ. विनीता रे, जे एम आई, प्रो. राजन हर्ष , हैदराबाद, प्रो. वी एस सेठ मुम्बई, प्रो. सेवानिवृत्त सुशीला अग्रवाल, राजस्थान, डॉ. जगदीश शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय, श्री ई बैरवा , संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय, डॉ. ए एस शाहिद, दिल्ली विश्वविद्यालय , प्रो. के मैथ्यूज, इथोपिया, डॉ. सुरेश कुमार , दिल्ली विश्वविद्यालय , डॉ. अपराजिता विश्वास, मुम्ब्ई, श्री मोआम्बा शिवांगू , कांगो डॉ. निवेदिता रे, आई डी एस ए , श्री सुनील खोसला, विश्व बैंक, डॉ. मुहम्मद अजहर, अलीगढ़, प्रो. गिरिजेश पन्त , जे एन यू, डॉ. एस एन मालाकार , जे एन यू , सुश्री रूचिता बेरी, आई डी एस ए , डॉ. बुल बुल धर जेम्स, जे एम आई, बी पी ढाका, पी एच डी , सी सी आई , डॉ. पार्वती वासुदेवन, मुम्बई विश्वविद्यालय, डॉ. शिप्रा शर्मा, सी आई आई, डॉ. महेन्द्र साहू , मुम्मई विश्वविद्यालय, प्रो. आर एल चावला जे एन यू, प्रो. क्रिस दे वैत , दक्षिण अफ्रीका, प्रो. कुसुम अग्रवाल, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रो. हरीश नारंग , जे एन यू, सुश्री नन्दिनी सेन , दिल्ली विश्वविद्यालय डॉ. हेस्तर द्यू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका, डॉ. गौहर रजा , सी एस आई आर, प्रो. ऊषा शुक्ला दक्षिण अफ्रीका, डॉ. वीना शर्मा, अफ्रीका क्वार्टरली, प्रो. अजय दुबे, जे एन यू, डॉ. मुहम्मद मूसी जे एम आई, श्री सुरेन्द्र कुमार जे एन यू, श्री अरविन्द कुमार यादव जे. एन. यू. श्री विधान पाठक , जे एन यू, श्री रजनीश गुप्ता , जे एन यू, सुश्री बसबी गुप्ता, जे एन यू, महामहिम श्री अब्दल महमूद, अब्दल हलीम मुहम्मद, सूडान गणराज्य का दूतावास, सेवानिवृत्त प्रो. दलीपसिंह दिल्ली विश्वविद्यालय
15.	24.11.2004	बाली से वेनेसियान तक - भारत आसियान सहभागिता के लिए रोडमैप विषय पर संगोष्ठी	प्रो. एस डी मुनि, जे एन यू , प्रो. सी राजामोहन, जे एन यू, डॉ. नागेश कुमार, आर आई एस , राजदूत ए एन राम,

परिशिष्ट XXI

आर आई एस द्वारा आयोजित चुनिन्दा सम्मेलन/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां

एशियाई विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आर आई एस/आई यू सी एन/सी आई आई का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली, 7-8 अप्रैल, 2004

सार्क शिखर सम्मेलन के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में एस ए सी ई पी एस/सी पी डी/आर आई एस की संगोष्ठी और दक्षिण एशिया विकास एवं सहयोग रिपोर्ट , 2004 को जारी किया जाना, ढाका 18 मई, 2004

अंकटाड xi की कार्यसूची के बारे में संगोष्ठी, नई दिल्ली, 4 जून, 2004

भारत के निर्यात का अल्पकालिक पूर्वानुमान-तौर तरीकों संबंधी मुद्दे विषय पर तकनीकी संगोष्ठी, नई दिल्ली 6 जुलाई, 2004

निर्माण उद्योग में उत्पादकता के बारे में व्यापारिक खुलापन के प्रभाव-लागत प्रकार्य दृष्टिकोण विषय पर संगोष्ठी , नई दिल्ली, 7 जुलाई , 2004

विश्व व्यापार संगठन के जुलाई फ्रेम वर्क विषय पर संगोष्ठी, नई दिल्ली, 6 अगस्त , 2004

ज्ञान आधारित उद्योगों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत बनाने की सामारिक दृष्टि के बारे में आर आई एस/डी एस आई आर की राष्ट्रीय कार्यशाला, नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2004

दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्ट, 2004 पर पी आई डी ई/आर आई एस की संगोष्ठी, इस्लामाबाद, 18 अगस्त, 2004

सार्क-इस्लामाबाद के बाद की चुनौतियां विषय पर आर आई एस/एस ए सी ई पी एस का क्षेत्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2004

भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका आर्थिक सहयोग पर विचार मंथन, नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

ब्रिटिश अध्यक्षता के अधीन जी-8 के लिए कार्यसूची विषय पर संगोष्ठी , नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2004

आसियान के महासचिव द्वारा भारत आसियान प्रतिष्ठित व्यक्ति व्याख्यान, नई दिल्ली 18 अक्तूबर, 2004

एशियाई आर्थिक एकता - विजन आफ ए न्यू एशिया, विषय पर उच्चस्तरीय सम्मेलन, टोकियो , 18-19 नवम्बर, 2004

बाली से वेनेसियान- भारत आसियान सहभागिता के लिए रोड मैप विषय पर आइ सी डब्ल्यू ए/सी एस सी ए पी की संगोष्ठी , नई दिल्ली , 24 नवम्बर, 2004

ट्रिप्स व्यवस्था और आवश्यक दवाईयों की सुलभता विषय पर संगोष्ठी, नई दिल्ली 3 दिसम्बर, 2004

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रणाली- चुनिन्दा एशियाई देशों के अनुभव विषय पर संगोष्ठी, नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2005

आर आई एस प्रकाशन

पुस्तकें

एशियाई आर्थिक समुदाय की ओर - विजन आफ ए न्यू एशिया, 2004 - श्री नागेश कुमार द्वारा संपादित और दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से प्रकाशित

श्री राजेश मेहता और श्री जे जार्ज (दोनो संपादक) द्वारा फूड सेफ्टी रेग्यूलेशन कन्सर्न एण्ड ट्रेड , द डेवलपिंग कन्ट्री पर्सपेक्टिव , 2005 नई दिल्ली, मैकमिलन

आर आई एस तथा आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क, 2004, द्वारा प्रकाशित आसियान इण्डिया विजन 2020 - वर्किंग टुगेदर फार ए शेयर्ड प्रॉसपरिटी

बिम्सटैक की भावी दिशाएं - बंगाल की खाड़ी आर्थिक समुदाय की दिशा में - आई पी एस कोलम्बो, आई टी डी बैंकाक और सी पी डी ढाका के परामर्श से आर आई एस द्वारा प्रकाशित , 2004

राजेश मेहता तथा पूजा अग्रवाल द्वारा - विश्व व्यापार संगठन और भारतीय लघु उद्योग । भारतीय अति लघु एवं लघु तथा मध्यम उपक्रम संघ (एफ आई एस एम ई) तथा विकास आयुक्त का कार्यालय , लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित 2004

जैव प्रौद्योगिकी एवं विकास - एशिया के लिए चुनौतियां और अवसर - सचिन चतुर्वेदी और एस एन राव । दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान सिंगापुर तथा आर आई एस द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित

वैश्वीकरण के दौर में भारत आसियान भागीदारी - प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विचार (द्वितीय संस्करण) । दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान सिंगापुर तथा आर आई एस द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित

आर आई एस के नीतिगत ब्रीफ

#13 अंकटाड xi और इक्कीसवीं शताब्दी के लिए विकास वार्ता

#14 ऑयल शॉक तथा अमेरिका की ब्याज दरों में चक्रीय व्यतिक्रम - एशिया पर प्रभाव आर आई एस के विचार विमर्श दस्तावेज

परिशिष्ट XXI

भूमिका के सन्दर्भ में व्यापार उदारीकरण के लिए एक व्यवहार्य मार्ग तैयार करना - इन्द्र नाथ मुखर्जी

#85 राम उपेन्द्र दास द्वारा - इण्डस्ट्रियल रिस्ट्रक्चरिंग एण्ड एक्सपोर्ट कम्पेटीटिवनेस आफ द टेक्सटाइल्स एण्ड क्लोदिंग सेक्टर इन सार्क इन द कन्टेक्स्ट आफ एम एफ ए फेज आउट ।

#84 राजेश मेहता और पारूल माथुर द्वारा - इण्डियाज एक्सपोर्ट बाई कन्ट्रीज एण्ड कमोडिटीज - आन द एस्टीमेशन आफ ए फोरकास्टिंग मॉडल यूजिंग पैनल डाटा

#83 विजय कुमार कौल द्वारा - स्ट्रेटेजिक एप्रोच टू स्ट्रेन्थनिंग द इण्टरनेशनल कम्पेटीनिवनेस इन नॉलिज बेस्ड इण्डस्ट्रीज- इण्डियन कैमिकल इण्डस्ट्री

#82 नीलम सिंह द्वारा - स्ट्रेटेजिक एप्रोच टू स्ट्रेन्थनिंग द इण्टरनेशनल कम्पेटीनिवनेस इन नॉलिज बेस्ड इण्डस्ट्रीज - द केस ऑफ इण्डियन ऑटोमोटिव इण्डस्ट्री।

#81 एम पद्मसुरेश द्वारा - स्ट्रेटेजिक एप्रोच टू स्ट्रेन्थनिंग द इण्टरनेशनल कम्पेटीनिवनेस इन नॉलिज बेस्ड इण्डस्ट्रीज- नॉन इलैक्ट्रिकल मशीनरी इण्डस्ट्री ।

#80 आराधना अग्रवाल द्वारा - स्ट्रेटेजिक एप्रोच टू स्ट्रेन्थनिंग द इण्टरनेशनल कम्पेटीनिवनेस इन नॉलिज बेस्ड इण्डस्ट्रीज- द इण्डियन फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्री ।

#79 कम्प्लीमेंट्रीज एण्ड पोटेन्शियल्स आफ इण्ट्रारीजनल ट्रांसफर्स आफ इनवेस्टमेन्ट्स - टेक्नोलॉजी एण्ड स्किल्स इन एशिया - सैकत सिन्हा राय द्वारा ।

#78 टुवार्ड्स फार्मेशन आफ क्लोज इकोनॉमिक कोआपरेशन एमंग एशियन कंट्रीज - एस के मोहन्ती , संजीव पुरोहित और सैकत सिन्हा राय द्वारा

#77 ट्रांजेक्शन कॉस्ट्स एज बैरियर्स टु इकोनॉमिक इण्टीग्रेशन इन एशिया-एन एम्पाईरिकल एक्सप्लोरेशन - प्रबीर डे द्वारा

#76 ट्रांसफार्मिंग डिजिटल डिवाइड इन टु डिजिटल डिवीडिंड- द रोल आफ साउथ साऊथ कोआपरेशन इन आई सी टीज - के जे जोसेफ द्वारा

#75 ट्रांसपोर्ट कोआपरेशन इन बिम्सटैक - इश्यूज एण्ड वे फारवर्ड - प्रबीर डे द्वारा

#74 डब्ल्यू टी ओ मार्केट एक्सेस नेगोशिएशन्स एण्ड इण्डियन स्माल स्केल इण्डस्ट्री - राजेश मेहता और पूजा अग्रवाल द्वारा ।

#73 आसियान इण्डिया इकोनॉमिक रिलेशन्स - करेन्ट स्टेटस एण्ड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स - राहुल सेन, मुकुल जी असेर और रामकृष्ण एस राजन द्वारा

#72 नेशनल इनोवेशन सिस्टम्स एण्ड इण्डियाज आई टी कैपेबिलिटी - आर देयर एनी लैसन्स फार आसियान न्यू कमर्स - नागेश कुमार और के जे जोसेफ द्वारा

#71 मॉनीटरी कोआपरेशन इन साऊथ एशिया - पोटेन्शियल एण्ड प्रॉस्पेक्ट्स -श्वेता चमन सक्सेना और मिर्जा अलीम बेग द्वारा ।

#70 इण्डिया-आसियान कोआपरेशन इन इनफारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजीज - इश्यूज एण्ड प्रॉस्पेक्ट्स - के जे जोसेफ और गोविन्दन परायल द्वारा ।

जर्नल

1. साऊथ एशिया इकोनॉमिक जर्नल (खण्ड - 5 संख्या -1) जनवरी-जून, 2004
   साऊथ एशिया इकोनॉमिक जर्नल (खण्ड - 5 संख्या

   2) जुलाई -दिसम्बर, 2004
2. एशियन बायोटेक्नोलॉजी एण्ड डेवलपमेंट रिव्यू , खण्ड - 6 संख्या-2 , मार्च, 2004

   एशियन बायोटेक्नोलॉजी एण्ड डेवलपमेंट रिव्यू , खण्ड - 6 संख्या-3 , जुलाई, 2004
3. न्यू एशियन मॉनीटर , खण्ड -1 संख्या 2, जुलाई, 2004

   न्यू एशियन मॉनीटर , खण्ड -1 संख्या3, अक्तूबर, 2004

   न्यू एशियन मॉनीटर , खण्ड -2 संख्या1, जनवरी, 2005

समाचार पत्रक

- आर आई एस डायरी - खण्ड -2 संख्या -2 , अप्रैल , 2004
- आर आई एस डायरी - खण्ड -2 संख्या -3 , जुलाई, 2004
- आर आई एस डायरी - खण्ड -2 संख्या -4 , अक्तूबर , 2004
- आर आई एस डायरी - खण्ड -3 संख्या -1 , जनवरी, 2005

संक्षिप्त रूप

एएएलसीओ	एशियाई अफ्रीकी विधिक परामर्शी संगठन
एसीडी	एशियाई सहयोग वार्ता
एसीएस	केरिबियाई राज्यों का संघ
एजीपीएल	वास्तविक भू स्थिति रेखा
एपीएसईसी	एशिया प्रशांत सुरक्षा सम्मेलन
एआरएफ	आसियान क्षेत्रीय मंच
एएसईएएन	दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ
बीडीआर	बंगला देश राइफल
बीआईएमएसटी	बंगलादेश, भारत , म्यांमा, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग
बीआरपीपीए	द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार
बीओओटी	बिल्ड आन आपरेट ट्रांसफर
बीएसएफ	सीमा सुरक्षा बल
सीएएम	अदीन देशों का समुदाय
सीएआरआईसीओएम	केरिबियाई समुदाय
सीएएसएस	चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी
सीबीएम	विश्वासोत्पादक उपाय
सीडी	निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध सम्मेलन
सीईसीए	व्यापक आर्थिक सहयोग करार
सीईपी	सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम
सीएचओजीएम	राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक
सीएचआर	मानवाधिकार आयोग
सीआईसीए	एशिया में अन्योन्यक्रिया और विश्वासोत्पादक उपायों से सम्बद्ध सम्मेलन
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीएलएमवी	कम्बोडिया, लाओस, म्यांमा, वियतनाम
सीओएमईएसए	पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका समुदाय
सीपीपीसीसी	चीनी लोक राजनीति परामर्श समिति
सीएससीएपी	एशिया प्रशांत में सुरक्षा और सहयोग परिषद
सीयूएनपीके	संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यवाहियों हेतु केन्द्र
डीएई	परमाणु ऊर्जा विभाग
डीपीसी	जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ
डीपीआरके	कोरिया प्रजातांत्रिक लोक गणराज्य
ईसीजीसी	निर्यात ऋण् गांरटी निगम
ईपीजी	प्रतिष्ठित व्यक्तियों का दल
एफआईसीसीआई	भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ
एफआईईओ	भारतीय निर्यात संगठनों का परिसंघ
एफओसी	विदेश कार्यालय परामर्श
एफएसआई	विदेश सेवा संस्थान
जीसीसी	खाड़ी सहयोग परिषद
जीएमईएफ	सार्वभौमिक मंत्रीस्तरीय पर्यावरण मंच
जीओआई	भारत सरकार
आईसीआरसी	अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति
एचओपी	केन्द्र प्रमुख
एचओएम	मिशन प्रमुख
जीओआई	भारत सरकार
जीएसओएमआईए	सैन्य सूचना से सम्बद्ध सामान्य सुरक्षा करार
एचएएल	हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लिमिटेड
एचआईपीसी	अत्याधिक ऋण ग्रस्त गरीब देश
एचटीसीजी	उच्च प्रौद्योगकी सहयोग दल
आईबीपीएफ्	भारत ब्रिटेन संसदीय मंच
आईबीएसए	भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका
आईसीसीआर	भारतीय सांस्कृतिक सम्बद्ध परिषद
आईसीडब्ल्यूए	इंडियन कांउसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स
आईएफएस	भारतीय विदेश सेवा
आईआईजी	भारतीय विद्रोही गुट
आईटीईसी	भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग
आईटीपीओ	भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन
जेईसी	संयुक्त आर्थिक आयोग
जेआरसी	संयुक्त नदी आयोग
जेएसजी	संयुक्त अध्ययन दल
जेटीसी	संयुक्त व्यापार समिति
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्य बल
केएलओ	काम्तापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन
एलएसी	वास्तविक नियंत्रण रेखा
एलसीए	हल्के लड़ाकू विमान
एलओसी	नियंत्रक रेखा
एलटीटीई	लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम
मार्कोसुर	दक्षिण कोण्य देशों का बाजार
एमएलएटी	परस्पर विधिक सहायता संधि
एमएनएनए	प्रमुख गैर नाटो सहयोगी
एमओएनयूसी	कांगो प्रजातांत्रिक गणराजय में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एनएएम	गुट निरपेक्ष आंदोलन

नाटो	उत्तरी प्रशांत संधि संगठन
एनडीसी	राष्ट्रीय रक्षा कालेज
एनईपीएडी	बाडोलैंड राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक मंच अफ्रीका के विकास के लिये नयी भागीदारी
एनआरआई	अप्रवासी भारतीय
एनएससीएस	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
ओडीए	सरकारी विकास सहायता
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
पीसीएफडी	विदेशी राजनयिकों के लिये व्यवसायिक पाठ्यक्रम
पीआईएफ	प्रशांत द्वीप समूह मंच
पीकेओ	शांति कार्यवाहियां
पीआइओ	भारतीय मूल के लोग
पीएलए	पीपील्स लिबरेशन आर्मी
पीएलओ	भारतीय मूल के लोग
पीटीए	अधिमानी व्यापार करार
आरआईटीईएस	रेल इंडिया टेक्नीकल इक्नोमिक्स सर्विस
आरओके	कोरिया गणराज्य
एसएएआरसी	क्षेत्रीय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई संघ
एसएडीसी	दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय
साप्ता	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र
साप्ता	दक्षिण एशिया अधिमानी व्यापार करार
एसएटीटीए	दक्षिण एशियाई यात्रा और पर्यटन प्रदर्शनी
स्काप	अफ्रीकी योजना के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता
आईबीपीएफ	भारत ब्रिटेन संसदीय मंच
पीसीडी	निति आयोजन, कौंसली एवं समन्वय डायस्पोरा
एएनए	एशिया, उत्तरी अफ्रीका
ईआर	आर्थिक संबंध
ईएए	यूरोप, अफ्रीका, अमरीका
एलएसी	लाटिन अमरीकी देश
एसआईसीए	मध्य अमरीकी एकीकरण प्रणाली
एसपीडीसी	राज्य शांति और विकास परिषद
टीसीसी	सैन्य योगदानकर्ता देश
टीसीआईएन	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड
टीम	अफ्रीका भारत आंदोलन के लिए तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण
उल्फा	असम में युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट
यूएनएएमआई	इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन
यूएनसीओपीयूओएस	वाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोग संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति
यूएनडीसी	संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग
यूएनजीए	संयुक्त राष्ट्र महासभा
यूएमएचसीआर	विस्थापितों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त
यूएनआईएफआईएल	लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल
यूएनएमईई	इथियोपिया और एरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन
यूएनएमआईके	कसोवो में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम प्रशासन मिशन
यूएनओडीसी	नशीली दवा और अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय
यूएसआई	भारत का संयुक्त सेवा संस्थान
डब्ल्यूएसआईएस	सूचना सोसायटी संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन
डब्ल्यूएसएसडी	स्थायी विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन